(1)

# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3 ] षष्टम् विधान सभा के तृतीय सत्र का 18वां दिवस [संख्या 15



शुक्रवार,

दिनांक 17 मार्च, 1978

[ विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारंभ हुई । ]

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वर दयाल ! प्रश्न संख्या 311 ।

चौमूं में मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत

311. श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालतों में मुकदमों की कुल कितनी संख्या है और मुंसिफ मजिस्ट्रेट की कितनी अदालतें हैं ?

(2) पुलिस स्टेशन, चौमूं व पुलिस स्टेशन, गोविन्दगढ़ के क्षेत्राधिकार के जयपुर स्थित मुंसिफ मजिस्ट्रेट की सम्बन्धित अदालत में दीवानी एवं फौजदारी कितने मुकदमे विचाराधीन हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय देने के लिए चौमूं नगर में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की अदालत स्थापित करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

विधि मंत्री (श्री सूर्य नारायण चौधरी): (1) राजस्थान में मुंसिफ मजिस्ट्रेटों की अदालतों में दिनांक 31-12-77 को विभिन्न प्रकार के मुकदमों की कुल संख्या 3, 13, 644 थी। मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों के कुल 241 न्यायालय हैं ।

(2) पुलिस स्टेशन, चौमूं व गोविन्दगढ़ के क्षेत्राधिकार से प्रस्तुत जयपुर स्थित मुंसिफ मजिस्ट्रेट के संबंधित न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की संख्या निम्न प्रकार है :—

| अदालत | चौमूं | गोविन्दगढ़ |
|---|---|---|
| 1. फौजदारी मुकदमे | 779 | 136 |
| 2. दीवानी मुकदमे | 160 | 40 |

(3) चौमूं में मुंसिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित करने बाबत सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन

(श्री सूर्य नारायण चौधरी)

नहीं है। कुछ मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेटों के नये न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। चौमूं में न्यायालय भवन आदि की उपयुक्त व्यवस्था की जानकारी लेने के बाद वहां पर भी न्यायालय स्थापित करने पर विचार कर लिया जाएगा।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि एक न्यायालय खोलने के लिए कम से कम मुकदमों की संख्या कितनी होनी चाहिए ? चौमूं का जहां तक सवाल है वहां के लोग बिल्डिंग देने को तैयार हैं। तो क्या मंत्री महोदय यह स्पष्ट करेंगे कि भवन की व्यवस्था कर देने पर वहां न्यायालय खोल दिया जाएगा ?

श्री सूर्य नारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक न्यायालय खोलने के लिए मुकदमों की संख्या और भवन की व्यवस्था का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में कोई नीति प्रतिपादित नहीं की गई है। जो सुझाव प्रश्न के रूप में माननीय सदस्य ने दिए हैं, निश्चित रूप से उच्च न्यायालय से विचार-विमर्श करके नीति निर्धारित कर दी जाएगी। इसके साथ ही चौमूं में न्यायालय स्थापित करने का प्रश्न है, उसमें भी राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय से निश्चित रूप से विचार-विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा। जैसा मूल उत्तर में बताया है, कोई भवन इत्यादि उपलब्ध हो तो राजस्थान सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि मेरे से इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर लें।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : नई कोर्ट्स खोलने के बारे में राज्य सरकार का क्या विचार है ?

एक माननीय सदस्य : मुकदमों की संख्या को देखते हुए क्या सरकार कोई नीति निर्धारित करने का विचार कर रही है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि 3 लाख 13 हजार 644 मुकदमे पेंडिंग हैं वेरियस कोर्ट्स में। तो क्या आप खुद इस बात को महसूस नहीं करते हैं कि मुकदमों की संख्या को देखते हुए राजस्थान में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स की संख्या कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार कोर्ट्स की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है जिससे लोगों को सस्ता, सुलभ और जल्दी न्याय प्राप्त हो सके ?

श्री सूर्य नारायण चौधरी : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय से निरन्तर परामर्श जारी है। हमारी भी यह इच्छा और आकांक्षा है कि लोगों को न्याय सस्ता, सुलभ और शीघ्र मिले। मैं यह मानता हूं कि मुकदमों की संख्या को देखते हुए न्यायालयों का गठन होना चाहिए और उनकी संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। परन्तु आपके सामने इसके फाइनेंशियल इम्पलीकेशन्स भी मौजूद हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति यहां तशरीफ ला रहे हैं। उनके साथ विचार-विमर्श करने के लिए एक अजेन्डा तैयार है जिसमें न्यायालयों के विस्तार करने की भी बात है। मैं सदन के माननीय सदस्यों को यह

(श्री सूर्य नारायण चौधरी)
विश्वास दिलाना चाहता हूं, विशेष कर उन माननीय सदस्यों को जो इसमें रूचि रखते हैं, इसमें उनको कान्फीडेन्स में लेकर सारी चीजें जल्दी से जल्दी करने की कोशिश की जाएगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार एक तरफ तो कह रही है इसके फाइनेन्शियल इम्पलीकेशन्स भी हैं और दूसरी तरफ कह रही है कि हाई कोर्ट से बात की जाएगी। यह दोनों चीजें एक साथ कैसे सम्भव हैं? हाई कोर्ट की ओर से मुकदमों के हिसाब से कोर्ट खोलने के लिए एक क्राइटेरिया ऑलरेडी बनाया हुआ है कि इतने मुकदमों पर कोर्ट होनी चाहिए। हाई कोर्ट तो तैयार है। आप फाइनेन्शियल इम्पलीकेशन्स की बात कह कर मामला अटका रहे हैं। हाई कोर्ट का तो क्राइटेरिया फिक्स है उसके हिसाब से आप कोर्ट खोल दीजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं विधि मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा, प्रश्न के जवाब में उन्होंने यह कहा है कि हम चीफ जस्टिस से कन्सलटेशन कर तय करेंगे। जहां तक मेरा अनुभव है, मैं समझता हूं इसमें कन्सलटेशन की इतनी जरूरत नहीं है जितनी कि इसकी कि आप इसके लिए बजट प्रोविजन रख दें कि इस साल 11, 12, 15 मुन्सिफ कोर्ट्स और खुलेंगी। इसके लिए प्रति वर्ष बजट में प्रावधान किया जाए तो मेरे ख्याल से हाई कोर्ट को इसमें कतई दिक्कत नहीं है। वह तो खुश होगी कि इतनी कोर्ट्स और खुल रही हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): एक मुन्सिफ मजिस्ट्रेट।

(व्यवधान)

इस साल के बजट में कोई ऐसा प्रावधान है जिसके आधार पर आप यह कह सकें कि इतने मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाएंगे? यह बता दीजिए।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : 11 नये न्यायालय खोलने का प्रस्ताव है।

श्री मूलचन्द डागा : कब तक खोलने का प्रस्ताव है? वर्ष के अन्त में या प्रारंभ में? यह बता दीजिए।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : सुविधानुसार और समयानुकूल खोल दिए जायेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह 11 कोर्ट्स खोलने के लिए बजट में कोई प्रावधान है या नहीं है? यह कोर्ट्स आप खोलने जा रहे हैं परन्तु बजट प्रॉविजन है ही नहीं। फिर ये 11 कोर्ट्स कौनसी हैं जिनको कि आप खोलने का विचार कर रहे हैं?

श्री सूर्य नारायण चौधरी : अलग से प्रश्न पूछ लीजिए। बता दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा: इस साल कितना बजट रखा है? बजट में प्रॉविजन नहीं है। यह गलत कहा गया है कि प्रोविजन है। कोई प्रॉविजन नहीं है।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : जिन स्थानों पर ये खोले जाएंगे, उनके नाम बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, कमाल की बात कह रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बजट में प्रॉविजन नहीं है । आप स्वयं बता दें कि कहां से खोल देंगे ? नाम भी आप नहीं बता रहे हैं कि कहां-कहां पर खोलेंगे ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विधि मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर स्थित डिस्ट्रिक्ट मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, जिला जयपुर के न्यायालय में केवल मात्र चौमूं और गोविन्दगढ़ थानों के मुकदमे विचाराधीन हैं । इसके अलावा एडीशनल मुंसिफ कोर्ट-2 में भी विचाराधीन हैं । मैं यह कहना चाहूंगा कि जब बजट में प्रावधान नहीं है तो चौमूं में न्यायालय स्थापित नहीं हो सकता है इसलिए मेरा निवेदन है कि अलहदा न्यायालय वहां पर खोलने की आवश्यकता नहीं है केवल मात्र यह जो न्यायालय जयपुर में है वह चौमूं कर दिया जाए । इसके लिए बजट की भी आवश्यकता नहीं होगी । क्या मंत्री महोदय मेरे सुझाव पर विचार करेंगे ?

श्री सूर्य नारायण चौधरी : मैं आपसे सहमत हूं और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस पर विचार किया जाएगा ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा माननीय सदस्यों की भावनाओं के साथ-साथ अपनी भावना को सम्मिलित करते हुए कि यह जो बेकलॉग ऑफ पेन्डिंग केसेज है, यह बहुत रेपिडली बढ़ता जा रहा है । Justice delayed justice denied. मन्त्री महोदय इसके बारे में कदम उठायेंगे, ऐसी मेरी आशा है ।

एक माननीय सदस्य : ऐसा ही हो ।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवराजसिंह !

तहसील बस्सी व चाकसू की
अधूरी सड़कें

312. श्री शिवराजसिंह (बस्सी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

तहसील बस्सी व चाकसू, जिला जयपुर में अकाल राहत व कैश प्रोग्राम के तहत पड़ी अधूरी सड़कें, जिन पर कुछ पक्की सड़कें भी बन चुकी हैं, को पूरा कराने का क्या राज्य सरकार का विचार है ? यदि हां, तो उनको कब तक पूरा कराया जायेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री जयनारायण पूनिया) : अकाल राहत व कैश में बनी तमाम सड़कों को पूरा कराने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में विचार किया जा सकता है ।

श्री शिवराजसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि नई सड़क पर कंकर डाले हुए हैं इसलिए वह बन सकती है ।

श्री मूलचन्द डागा : जो काम नहीं करना है, उसका क्या यही एक उत्तर है कि उस पर छठी पंचवर्षीय योजना में विचार हो सकता है । कोई प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर यही देते हैं । छठी पंचवर्षीय योजना में विचार करने का जवाब देते हैं ।

श्री टीकमचन्द कान्त (जालोर) : जालोर के अन्दर कुछ रोड बनी हुई हैं, उनके बारे में अभी निर्णय का क्या कोई प्रश्न नहीं है ?

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, राहत कार्यों में बनी सड़कों पर मिट्टी डाली है। जो सड़कें बिगड़ गई हैं, उनके कारण मार्ग अवरुद्ध हो रहा है तो या तो डाली जाय या मिट्टी हटाई जाय।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, छठी पंचवर्षीय योजना के अन्दर आप कितनी राशि का प्रावधान करेंगे ? कितना वर्क करेंगे ? इतना पता तो चले। यह तो वेग रिप्लाई है।

श्री मूलचन्द डागा : अभी तो आपका रोलिंग प्लान है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह रोलिंग प्लान है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

जोधपुर जिले में सीमेन्ट की कमी

313. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीमेन्ट की राज्य के कुछ जिलों में कमी के क्या कारण हैं ?

(2) जोधपुर जिले में सीमेन्ट की कमी दूर करने के लिए नये स्टॉकिस्ट हर तहसील में क्यों नहीं मुकर्रर किये जा रहे हैं ? किस आधार पर ये स्टॉकिस्ट मुकर्रर किये जाते हैं ?

(3) सीमेन्ट के नये कारखाने राज्य में कहां-कहां स्थापित किये जा रहे हैं ?

(4) राज्य में कौन-कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी बाजार में कमी रहती है ? उनकी सुचारू वितरण व्यवस्था कैसी की जाने की है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री ( श्री जयनारायण पूनिया ) : (1) राज्य की मांग से कम सीमेन्ट प्राप्त होने से कमी रहती है।

(2) स्टॉकिस्ट की नियुक्ति सीमेन्ट फैक्ट्रीज द्वारा की जाती है। लाइसेन्स इस विभाग द्वारा दिया जाता है।

(3) अभी कोटा जिले में मोडक नया कारखाना स्थापित किया जा रहा है।

(4) बाजार में सीमेन्ट के अतिरिक्त किसी अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सीमेन्ट की बहुत कमी है। क्या इसी तरह से यह कमी रहेगी ? आपने यह बताया, अध्यक्ष महोदय, जो स्टॉकिस्ट हैं, उनको लाइसेंस उद्योग विभाग देता है। यह कम्पनियां बदमाशी करती हैं। आखिर इसी वजह से करप्शन बढ़ता है। इसके बारे में सरकार क्या निर्णय लेगी कि सभी जगह बराबर कोटा पहुंचाया जाये ?

श्री टीकमचन्द कान्त : जालोर का कोटा कम कर दिया गया है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्या यह सही है कि समूचे राजस्थान में सीमेन्ट की कमी है ?

# Page No 6

(6)



(श्री प्रद्युम्नसिंह)
यदि हां, तो कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ? दूसरी बात, क्या यह सही है कि जो कोटा आ रहा है, उससे गवर्नमेन्ट अपने वर्क के लिए स्टॉक करती जा रही है काश्तकारों को नहीं दे रही है ?

श्री अध्यक्ष : श्री एच. एन. शर्मा !

श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) : राज्य की मांग से सीमेन्ट कम प्राप्त होता तो जो कमी होती है, उसकी पूर्ति करने के लिए राज्य सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : सीमेन्ट की लोगों की मांग है उसके हिसाब से कमी कितनी है ? उसकी पूर्ति कब की जाएगी ?

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : सीमेन्ट की कितनी डिलीवरी हुई है ? यह बताया जाये ।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा ) : मन्त्री महोदय यह बतायें कि कितने स्टॉकिस्ट्स हैं जो कि असेंशियल कमोडिटीज एक्ट की धारा 3/7 के अंतर्गत कन्विक्टेड हैं और ब्लैक लिस्ट में हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : सब जानते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

एक माननीय सदस्य : क्या मन्त्री महोदय को यह पता है कि सीमेन्ट ईंटों से बनाते हैं या पत्थर से बनाते हैं ?

श्री ईश्वरचन्द्र : जो धारा 3/7 असेंशियल कमोडिटीज एक्ट में कन्विक्ट हुए हैं, उनमें क्या सीमेन्ट के स्टॉकिस्ट नहीं हैं ? इस बारे में सरकार के पास कोई जानकारी है ?

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 80% जनता गांवों में रहती है । 80% जनता के लिए गांवों में क्यों नहीं सीमेन्ट जाती है ? गांवों में किसानों को बेरे बनाने के लिये क्यों नहीं सीमेन्ट दी जाती है ?

श्री अध्यक्ष : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है । इतने सप्लीमेंट्री पूछ लिये गये हैं । मन्त्री महोदय को उत्तर तो देना चाहिए । फिर सप्लीमेन्ट्री पूछ सकते हैं । मन्त्री महोदय उत्तर दें ।

श्री रतन लाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेन्ट्री पूछने के लिए ये स्वयं हमें आगे करते हैं । वह स्वयं उत्तर दे दें तो प्रश्न ही नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मेरे कक्ष में पधारने का कष्ट करने की कृपा करेंगे । मैं आप से कुछ कहूंगा, आपके आचरण के सम्बन्ध में ।

श्री जयनारायण पूनिया : यह बात सर्वविदित है कि इन दिनों राजस्थान में ही नहीं समूचे देश में सीमेन्ट की कमी महसूस की जा रही है । बल्कि भारत सरकार इस कमी को दूर करने के लिए विदेशों से भी काफी मात्रा में सीमेन्ट का आयात कर रही है । राज्य सरकार द्वारा पूरा प्रयत्न किया जा रहा है कि आवश्यकता को देखते हुए अधिक से अधिक मात्रा में सीमेन्ट का आवण्टन भारत सरकार से प्राप्त किया जाये ताकि सरकारी कार्यों एवं जनता के निजी कार्यों के लिए इसकी आवश्यकता-

(श्री जयनारायण पूनिया)
नुसार उपलब्धि कराई जा सके। इस सम्बन्ध में यह भी कहना उचित मानता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने यह मामला निजी तौर पर भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्री महोदय से अपने स्तर पर लिया एवं उन्हें अर्द्ध शासकीय पत्र भी समय-समय पर लिख कर वस्तुस्थिति से अवगत कराया।

श्री मूलचन्द डागा : यह तो अपने डिपार्टमेन्ट का लिखा हुआ पढ़ रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : स्टेटमेन्ट दे रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पढ़ने दें। अभी नये हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (विधि मन्त्री) : पुराने तो उधर बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप पढ़िये स्टेटमेन्ट।

श्री जयनारायण पूनिया : अध्यक्ष महोदय, 1978 में 2,85,000 टन सीमेन्ट की डिमाण्ड की थी। 1,50,000 टन का अलॉटमेन्ट हुआ और 95,483 टन उपलब्ध हो सका।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री सारस्वत।

श्री खेतसिंह राठौड़ : प्रश्न तो मैंने किया है, श्रीमान्।

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के जो कारखाने सीमेन्ट के स्थित हैं, उनमें जो उत्पादन होता है उसका कितना प्रतिशत राजस्थान के लिए आवंटित किया जाता है और क्या उसमें राजस्थान को प्राथमिकता दी जाती है?

श्री जयनारायण पूनिया : अध्यक्ष महोदय, सीमेन्ट का अलॉटमेन्ट केन्द्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि सीमेन्ट का कोटा आपका कम हुआ है तो देश में जितना उत्पादन होता है उसके मुकाबले में आपकी ज्यादा कटौती तो नहीं कर ली गई है? दूसरी बात, प्रत्येक जिले की जो आपने कटौती की है वह किस अनुपात से की है? खास तौर से पाली और जालोर में सीमेन्ट बहुत कम मिल रहा है। वहां पर इसका ब्लेक होता है। इसलिये यह बताने की कृपा करें। तीसरा निवेदन यह है कि सीमेन्ट के कारखाने जो बढ़ाने की बात थी, पाली जिले के सेंदड़ा या सोजत के लिए जो प्रस्ताव था उसका क्या हुआ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब आने दीजिये।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो लिखित उत्तर दिया है वह तो कोई बात नहीं किन्तु यह बताने का कष्ट नहीं किया कि गांवों के अन्दर शहरों के अनुपात में सीमेन्ट मिल रहा है या नहीं।

श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर) : सीमेन्ट की कमी का कारण क्या है?

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : जवाब आने दीजिये, अध्यक्ष महोदय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप एक सप्लीमेन्ट्री पूछ चुके हैं । दूसरा पूछ लीजिये ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां): मैं यह निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको स्थगित कर दिया जाय ।

मैं यह जानकारी चाहूंगा कि काश्तकारों के लिए सीमेन्ट का कोटा किस प्रकार से निर्धारित किया गया है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन चाहूंगा, यह तो मान लिया कि प्रोडक्शन कम हुआ और सीमेन्ट की कमी है । आपने यह भी आश्वासन दे दिया कि मुख्य मन्त्रीजी प्रयत्नशील हैं । वह तशरीफ भी ले आये हैं और अब आगाह कर देंगे कि उन्होंने किस प्रकार से प्रयत्न किया और उत्पादन की कमी को कैसे पूरा किया जायगा लेकिन आपके अलॉटमेन्ट का क्राइटेरिया क्या है, डिस्ट्रिक्ट-वाइज अलग-अलग है या पॉलिटिकल ग्राउण्ड पर है ? इसका क्या कारण है कि कुछ जिलों में तो सीमेन्ट की कमी नहीं है और कुछ में बहुत कमी है, किसी जिले में पचास रुपये में एक बोरी बिक रही है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : सीमेन्ट एक जिले से दूसरे जिले में जाकर ब्लैक किया जाता है ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, आपको उत्तर देना है तो दें ।

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि सीमेन्ट की कमी है, उत्पादन भी कम हुआ है और अलॉटमेन्ट भी कम हुआ है । राजस्थान में जो सीमेन्ट मिल रहा है उस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की, मैं निवेदन कर दूं कि अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में ज्यादा कटौती की गई हो, ऐसी बात नहीं है । मैं भारत सरकार के मंत्रीजी से मिला हूं और यह भी अवगत करा दिया है कि राजस्थान कैनाल के लिए विपत्ति खड़ी हो रही है, चालीस हजार टन सीमेन्ट कल ही अलॉट कराई है, कल ही एक अधिकारी को मन्त्रीजी के पास भेजा है । मैं भी जा रहा हूं और इस बारे में चर्चा करूंगा । राजस्थान के निर्माण कार्य में गतिरोध उत्पन्न नहीं हो और पब्लिक को भी सीमेन्ट मिलता रहे इसके लिए पूरा प्रयत्न किया जा रहा है । जितनी कमी पूरी की जा सकती है उसकी चेष्टा की जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : लेकिन आपकी नीति क्या है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत: जिले में वितरण की प्रणाली वही है जो भूतपूर्व सरकार ने बनायी थी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : No more supplementary.

Next question. श्री ईश्वरचन्द्र!

श्री सूर्य नारायण चौधरी : यह डिबेट हो रही है या सवाल उठाये जा रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
सरकार द्वारा बनाई गई नीति में कोई कमी पाते हैं तो उसको निश्चित रूप से दुरस्त करेंगे ।

श्री शंकरलाल : किसी जिले में ज्यादा सोमेन्ट दे रहे हैं श्रीर कहीं बहुत कटौती कर रहे हैं, नीति की बात नहीं, यह क्यों हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन । श्री ईश्वरचन्द्र !

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : काश्तकारों के लिए निर्धारित कोटा होना चाहिए ! पहले होता था वह भी नहीं मिल रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्तर पर्याप्त है, अगर भूतपूर्व सरकार की नीति में आवश्यकता होगी तो वर्तमान सरकार संशोधन करेगी ।

(व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन (बड़ी सादड़ी) : कटौती करने में भेद-भाव बरता गया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

नेक्स्ट क्वेश्चन । श्री ईश्वरचन्द्र !

मुफ्त कानूनी सहायता पर व्यय की गई राशि

314. श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा): क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में सन् 75,76,77 में मुफ्त कानूनी सहायता पर राज्य सरकार ने कितना व्यय किया है तथा कितने लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की गई ?

(2) क्या राज्य सरकार मुफ्त कानूनी सहायता की कोई नई योजना बना रही है ?

(3) क्या राज्य सरकार ने मुफ्त कानूनी सहायता के लिये बजट में कोई प्रावधान रखा है ? यदि हां, तो झालावाड़ जिले को कितनी राशि आवंटित की गई है ?

विधि मंत्री (श्री सूर्य नारायण चौधरी) : (1) राज्य सरकार ने 1975-76, 1976-77 व 1977-78 के बजट में 5-5 लाख रुपये का प्रावधान रखा था । सन् 1975-76 में यह प्रावधान वर्ष के अन्त के करीब स्वीकृत होने के फलस्वरूप उस साल 104 विधिक सहायता समितियों को आवंटित की गई राशि में से कुछ भी खर्च नहीं हुआ । सन् 1976-77 में सभी 104 विधिक सहायता समितियों, जिनको कि 5 लाख रुपये के बजट प्रावधान में से 2-2 हजार रुपये की राशि आवंटित की गई थी, द्वारा उसमें से पूरे वर्ष में करीब 50 हजार रुपये की राशि खर्च हुई थी ।

श्री ईश्वरचन्द्र : कितनी ?

श्री सूर्य नारायण चौधरी : पचास हजार ।

श्री ईश्वरचन्द्र : कोई गरीब लेता ही नहीं है ?

(व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण चौधरी : सुनो, सुनो, आप सुनो । यह बीस सत्री कार्यक्रम के

(श्री सूर्य नारायण चौधरी)
अन्तर्गत है, इसलिये कह रहा हूं, सुनो।

(व्यवधान)

सन् 1977–78 के बजट में भी इन सभी समितियों को दो-दो हजार रुपये की राशि आवंटित की गई है, तथा दिसम्बर, 1977 तक कुल 22,500 रुपये खर्च हुए हैं। अब तक कुल 1,258 गरीब व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की है।

श्री मूलचन्द डागा : आपने परिवर्तित बजट में रकम कम कर दी है।

श्री अध्यक्ष : आप उत्तर पूरा सुन लीजिये।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : (2) जी हां। योजना विचाराधीन है।

(3) जी हां, राज्य सरकार ने सन् 1977–78 के बजट में 5 लाख रुपये का प्रावधान रखा है। इस राशि में से झालावाड़ जिले को 3 विधिक सहायता समितियों को कुल 6,600 रुपये की राशि आवंटित की गई है।

श्री ईश्वरचन्द्र : खण्ड (2) के जवाब में आपने कहा कि योजना विचाराधीन है। अगर थोड़ी-सी उस योजना की आउट लाइन्स बता दें तो मेहरबानी होगी।

दूसरा आपने कहा कि रुपया खर्च नहीं हुआ। तो इसके क्या कारण हैं? कारण यह है कि जो प्रक्रिया आपने सहायता देने के लिये बनाई है वह इतनी गलत और कठिन है कि किसी गरीब आदमी को मदद नहीं दी जा सकती। यह प्रक्रिया माननीय श्री खेतसिंह ने बनाई थी जो केवल प्रचार के लिये थी। क्या आप ऐसी स्कीम बनाने का विचार रखते हैं जिसका इन्टेन्शन प्रचार न होकर वास्तव में गरीब को मदद देने का हो?

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमारे समय में 50 हजार खर्च हुआ था और आपने केवल 22 हजार खर्च किया है। इससे साफ मालूम होता है कि आप गरीबों के कितने हामी हैं।

श्री मूलचन्द डागा : पिछली सरकार ने सन् 1977-78 के लिये बजट में 5 लाख रुपये की राशि मंजूर की थी, लेकिन आपने परिवर्तित बजट में पांच लाख को घटा कर 50 हजार कर दिया। इसका क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो दिलाइये।

श्री अध्यक्ष : उत्तर आ गया है, माननीय सदस्य।

नेक्स्ट। श्री लालूदास!

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि योजना है। तो यह स्पेसिफिक सप्लीमेंट्री है कि क्या योजना है? इसका जवाब तो दिलाइये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री लालूदास!

कोटड़ा महाद सड़क का कार्य

315. श्री लालूदास (फलासिया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या कोटड़ा से महाद, जिला उदयपुर कच्ची सड़क बनी हुई है? यदि हां, तो राज्य सरकार इसे कब तक पक्की सड़क बना देगी?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जयनारायण पूनिया) : जी हां। कोटड़ा से महाद कच्ची सड़क है। इस सड़क को पक्की बनाने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है। कोटड़ा से महाद करीब 39 किलोमीटर है जो 26 किलोमीटर ग्रेवल व 13 किलोमीटर फेयर वेदर है। इस सड़क को पक्का बनाने का छठी पंचवर्षीय योजना में विचार किया जायेगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या यह सही है कि वर्षा काल में सारी सड़क खराब हो जाती है और लोगों को बीस मील पैदल आना पड़ता है ? ऐसी मुसीबत होते हुए भी आप इस पर छठी पंचवर्षीय योजना में विचार करना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, कोटड़ा उदयपुर से 80 मील की दूरी पर पंचायत समिति और तहसील का केन्द्र है। मेरा निवेदन है कि यह सड़क जल्दी से जल्दी पूरी की जाये ताकि उदयपुर का कोटड़ा से सम्पर्क जोड़ सकें।

एक माननीय सदस्य : जो विचाराधीन है, उन्हें तो लें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री श्योपत सिंह मकासर (हनुमानगढ़) : मंत्री महोदय ने कहा कि छठी पंचवर्षीय योजना में इसके लिये प्रावधान रखा जायेगा। तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपकी पांचवीं पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई है ?

विधि मंत्री (श्री सूर्य नारायण चौधरी): पांचवीं तो खतम हो गई। 1-4-78 से छठी शुरू हो जायेगी।

घाटोली कस्बे में पशु चिकित्सालय

316. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहरथाना) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत वर्ष जुलाई माह में घाटोली कस्बे में जो पशु चिकित्सालय खोला गया था और जहां पर 15 दिन के लिये डाक्टर एवं स्टाफ पहुंच गया था, उसे अकारण किन कारणों से बंद करने का राज्य सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया ?

(2) क्या राज्य सरकार पुनः उक्त पशु चिकित्सालय को चालू करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुपालन मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा इस मामले म पुनः विचार हेतु स्थगन आदेश जारी किये गये थे। इसी कारण यह चिकित्सालय बन्द किया गया।

(2) चिकित्सालय को पुनः स्थापित करने हेतु राज्य सरकार ने दिनांक 23-2-78 को आदेश जारी कर दिये हैं।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा: माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि खोला क्यों था और फिर बन्द क्यों किया ?

श्री दिग्विजय सिंह : पूर्व सरकार ने जल्दी में पशु चिकित्सालय खोलने के आदेश दिये थे उन पर पुनः विचार करके 23-2-78 को आदेश दे दिये गये हैं, इस कस्बे में पशु चिकित्सालय खोलने के।

श्री कौशल किशोर जैन : ग्राम उत्थान की योजना सरकार ने बन्द कर दी, उसके कारण अनेक स्थानों पर पशु चिकित्सालय बन्द हो गये। मेरा निवेदन है कि उन स्थानों पर पुनः पशु चिकित्सालय खोलने की व्यवस्था की जाये।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है, घाटोल के पशु चिकित्सालय में कोई डाक्टर नहीं पहुंचा है।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं आश्वासन देता हूं कि यदि डाक्टर नहीं पहुचा है तो जल्दी पहुंचा दिया जायेगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : गत सरकार ने जो पशु चिकित्सालय खोले थे, उन में से जनता पार्टी ने जहां से जनता पार्टी के विधायक जीत कर आये हैं, वहां तो वापस खोल दिये और जहां से कांग्रेस के विधायक जीत कर आये हैं, वहां बन्द कर दिये।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय श्री खेतसिंह को तो इसलिये दुःख है कि ओसियां में खोल दिया गया और उनके यहां नहीं खोला।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) : आपने जो 50 नये चिकित्सालय खोले हैं, क्या यह सही है कि वह सारे के सारे वहीं खोले गये है जहां से जनता पार्टी के विधायक जीत कर आये हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : भयंकर पक्षपात।

श्री दिग्विजय सिंह : यह गलत है।

कई माननीय सदस्य : तो आप बताइये।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह सब सम्पतरामजी ने घोटाला किया था। 50 में से 5 चिकित्सालय भी कांग्रेसी विधायकों के क्षेत्रों में नहीं खोले गये हैं। आप 5 भी ऐसे स्थान नहीं बता सकते।

कई माननीय सदस्य : घोर पक्षपात।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह बात नहीं चलने देंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : तीस साल में ऐसा पक्षपात नहीं हुआ जो इन्होंने किया है।

(व्यवधान)

घोर पक्षपात। घोर पक्षपात।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तानाशाही जनता पार्टी की किसी भी कीमत पर नहीं चलने दी जायेगी।

(व्यवधान)

विधि मंत्री (श्री सूर्य नारायण चौधरी): अध्यक्ष महोदय, तानाशाही तो इन्दिराजी की थी।

( व्यवधान )

यह क्या हो रहा है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : होने दीजिये, मंत्री महोदय थोड़ी देर। 15 मिनट में सब जोश ठण्डा हो जायेगा। आप चिन्ता नहीं करें। मैं वाकिफ हूं इस सदन से।

( व्यवधान )

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इसमें घोर पक्षपात हुआ है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, ऐसा घोर पक्षपात तो हमने पिछले तीस सालों के हमारे शासन में भी नहीं किया था।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट प्रश्न। श्री बालचन्द आर्य !

पुराने जागीरदारों को पेन्शन

3·17. श्री बालचन्द आर्य (डग) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में पुराने जागीरदारों को कोई पेन्शन दी जाती है? यदि हां, तो किस किसको? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य के जिला झालावाड़ के सुनेल कस्बे के जागीरदार को अब तक पेन्शन नहीं मिलने के क्या कारण हैं? अब उन्हें कब तक पेन्शन मिलनी प्रारम्भ हो जायेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री पुरुषोत्तम मंत्री): (1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बालचन्द आर्य : क्यों ? मंत्री महोदय, जबाब दें। अगर आपको उन्हें पेन्शन नहीं देनी है

(व्यवधान)

तो फिर आप जागीरदारों को पेन्शन देने वाले डिपार्टमेन्ट को समाप्त क्यों नहीं कर देते हैं या फिर आप उनको पेन्शन दो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। स्थान ग्रहण करें। ऐसे व्यवधान में आप क्या उम्मीद करते हैं ? इसमें तो कोई नहीं सुन सकता है, न मैं सुन सकता हूं और न आप।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है तो मंत्री जी जबाब क्यों नहीं देते हैं।

श्री अध्यक्ष : जब मंत्री महोदय ने कह दिया कि प्रश्न ही नहीं उठता तो प्रश्न ही नहीं उठता। मंत्रीजी का कहना ही पर्याप्त है।

नेक्स्ट प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं। मदनसिंहजी बीच में बोल रहे हैं पता नहीं क्या बात है। I fail to understand.

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : जागीरदारों को कोई पेन्शन नहीं चाहिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट प्रश्न। श्री रणमलसिंह

# Page No 14

(14)



डो. पी. ए. पी. के अन्तर्गत चूरू में कार्य

318. श्री रणमलसिंह (सीकर) : क्या भेड़ व ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पिछले वर्ष अगस्त-सितम्बर में डी. पी. ए. पी., चूरू ने कन्टूर फरों का टेन्डर श्री हरलालसिंह के नाम मन्जूर किया था ? यदि हां, तो टेन्डर मन्जूर होने के 20 दिन तक कितनी वर्षा प्रति दिन चूरू में हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि परियोजना अधिकारी ने वर्षा न होने का बहाना बना कर ठेकेदार से कार्य नहीं कराया ?

(3) क्या उक्त ठेकेदार की प्रतिभूति राशि अब तक जमा है ? यदि हां, तो क्या इस ठेकेदार से इस वर्ष काम करवाया जावेगा ?

राज्य मंत्री भेड़ व ऊन (श्री नन्दलाल): (1) जी हां। टेन्डर मन्जूर होने के 20 दिन तक चूरू में हुई वर्षा की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह सही है कि बरसात के मौसम की समाप्ति निकट होने के कारण परियोजना अधिकारी ने ठेकेदार से कन्टूर फरों पर का कार्य नहीं करवाया।

(3) जी हां। निविदायें दिनांक 31-10-70 तक ही प्रभावशील होने के कारण उनके आधार पर इस वर्ष इस ठेकेदार से कार्य करवाना सम्भव नहीं होगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में चर्चा नहीं करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, सुनाई नहीं दे रहा है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, अब सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। स्थगित प्रश्नों को ले लें नहीं तो वह रह जावेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं स्थगित प्रश्न 15 मिनट पहले ले लूंगा। अभी वह समय नहीं आया है। अगर मैं 15 मिनट पहले से स्थगित प्रश्न नहीं लूं तो आप मुझे याद दिला दें। अभी तो एक मिनट बाकी है।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, बीच बीच में व्यवधान करने से हम लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न बिला वजह, बिना उत्तर दिये रह जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट प्रश्न। श्री बजरंगलाल।

राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वकीलों को भुगतान

319. श्री बजरंग लाल शर्मा (बनी पार्क) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 20 मार्च, 1977 के बाद 14 अगस्त 1977 तक कितने वकीलों को कितनी-कितनी फीस का भुगतान किया गया ?

(2) उक्त वकीलों के नाम मय

# Page No 15

(15)



(श्री बजरंग लाल शर्मा)
उनको दी गई फीस की कुल राशि दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

कृषि मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (1) विपणन बोर्ड द्वारा 20 मार्च, 1977 के बाद 14 अगस्त, 1977 तक दो वकीलों को 12,000 हजार तथा 550 रुपये फीस का भुगतान किया गया।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री बजरंग लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मन्त्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या कृषि विपणन बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष, जो कि एक कांग्रेसी थे, ने किसी भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मन्त्रीजी को निगम के केस के लिये एक बहुत बड़ी फीस दी थी और यही कारण था, जैसा कि माननीय सदस्य श्री कौशल किशोरजी जैन ने यहां पर बताया, उन्हें निगम के अध्यक्ष पद पर 6 साल से अधिक समय तक रहने दिया ?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है। इसके बावजूद मैं जानकारी कर लूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। कृपया शान्त रहें। स्थान ग्रहण करें।

श्री बजरंग लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस केस की पुख्ता खबर है। कृषि विपणन बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री नाहर ने एक बड़ी लम्बी चौड़ी फीस उस वकील को दी। यही कारण था कि उन्हें 6 साल और 8 महीने तक बोर्ड के अध्यक्ष पद पर रहने दिया। अध्यक्ष महोदय, आप मन्त्री महोदय को पिन डाउन करने दीजिये to know the truth because it concerns the propriety of the behaviour of a Central Minister. इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया कृषि मन्त्रीजी बतायें, क्या उनकी जानकारी में यह बात नहीं है कि बोर्ड से बड़ी लम्बी फीस श्री नाहर द्वारा एक केन्द्रीय राज्य मन्त्रीजी को बतौर फीस के दी गयी थी ?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं जानकारी कर लूंगा।

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह पहली बार मालूम हुआ कि श्री नाहर ने इतनी बड़ी धनराशि किसी वकील को निगम के कार्य के लिये दी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह कौनसी बड़ी बात है, आपने राम जेठमलानी और खण्डालवाला को कौनसी बड़ी फीसें नहीं दी हैं ? यह कौनसी बड़ी बात है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस संबंध में मुझे पहले जानकारी अध्यक्ष महोदय ने नहीं दी थी कि इतनी बड़ी तादाद में रुपये दिये गये हैं। लेकिन उनको इतने अर्से तक इसलिये रखा कि फीस अधिक दी यह सही नहीं है।

Page No 16

(16)



श्री बजरंग लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरी पुख्ता जानकारी है । वह फीस उन्हें इसलिये दी गयी ताकि वह इस पोस्ट पर कन्टीन्यू करते रहे । मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि नाहर साहब ने अध्यक्ष पद पर अपने को बनाये रखने के लिये बोर्ड से फीस उन वकील साहब को दी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, स्थगित प्रश्न तीन अगर समाप्त हो जायें तो वापस हमारे प्रश्न ले लें ।

श्री अध्यक्ष : अगर तीन प्रश्न हो जायेंगे और समय रहा तो मैं आपके प्रश्न ले लूंगा, अन्यथा नहीं ।

श्री शंकरलाल : नहीं तो फिर उन बचे हुए प्रश्नों को स्थगित मान लिया जाय, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : श्री नवरंग सिंह ! .

राजस्व अभियान एवं इस पर व्यय की गई राशि

13. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ---

(1) राज्य में राजस्व अभियान में कितने मामलों का मौके पर निर्णय लिया गया तथा कितने मामले पेंडिंग रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि राजस्व अधिकारियों की लापरवाही के कारण कुछ मामले पेंडिंग रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक इन मामलों का निर्णय होने की आशा है ?

(3) इस राजस्व अभियान पर राज्य सरकार का कितना धन खर्च हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

राजस्व मंत्री (श्री पुरुषोतम मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न को स्थगित करने के लिये निवेदन किया है ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह क्या ? स्थगित प्रश्न स्थगित नहीं हो सकता ।

श्री अध्यक्ष : जब सूचना नहीं मिल सकी है पर्याप्त तो प्रश्न स्थगित करना ही पड़ेगा । वह पुनः स्थगित किया जा सकता है ।

नेक्स्ट । श्री मूलचन्द डागा !

जयपुर को 250वीं वर्षगांठ समारोह पर व्यय की गयी राशि

15. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर की 250वीं वर्षगांठ समारोह पर आज दिन तक कुल कितनी-कितनी राशि किन-किन आयोजनों पर व्यय की गयी और किन-किन आइटमों पर और राशि व्यय करने की आयोजना है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(श्री मूलचन्द डागा)

(2) क्या सरकार ने 250वीं वर्षगांठ मनाने की कोई योजना बनाई थी ? यदि हां, तो कब और उसको मनाने के लिये कौन-कौन से साधन और मशीनरी है ?

राज्य मन्त्री, वित्त (श्रीमती विद्या पाठक): (1) जयपुर की अढाई शती समारोह पर आज तक विभिन्न आयोजनों पर किये गये व्यय की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। अब और किन-किन आयोजनों पर किया जाना है इसके बारे में समिति ने कोई निर्णय नहीं लिया हैं ।

(2) जी हां, राज्य सरकार ने 30 दिसम्बर, 1976 को दो समितियां, ऑर्गेनाईजिंग कमेटी एवं एग्जीक्यूटिव कमेटी, का गठन कर इस समारोह को मनाये जाने का निर्णय लिया था । इन समितियों का पुनर्गठन 1 सितम्बर, 1977 को किया गया। समारोह को मनाने के लिये एक्जीक्यूटिव ने 22 उप-समितियों का गठन किया जो समारोह के विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों की देख-रेख करती है । पर्यटन विभाग ने अपने बजट में से जयपुर अढ़ाई शती समारोह समिति को रुपये 7.50 लाख दिये हैं जो विभिन्न कार्यक्रमों पर व्यय किये जाने के लिये हैं ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री मूलचन्द डागा: यह आपने जो उत्तर दिया है वह पर्याप्त नहीं है। आपने तीन लाख का खर्चा बताया। मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि किन-किन समितियों की कौन-कौन सी तारीख को मीटिंग हुई और कौन-कौन से आइटम उसके सामने थे ? मुझे मालूम हुआ है जो आपका रिकार्ड है, श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, उसके अनुसार सभापति थे वे विदेश चले गये, कर्नल भवानी सिंहजी इसके वाइस चेयरमेन बनाये गये वे विदेश चले गये। फिर उसके बाद किस किस समिति ने किस-किस की अध्यक्षता में कार्य किया ? भविष्य में क्या प्लान है इसका? वह किस आधार पर बना ? क्या रामचन्द्रजी कासलीवाल, जो इसके सचिव थे, ने कहा था कि 15 करोड़ रुपये हम अढ़ाई शती पर खर्च करेंगे और उसके लिये हम सरकार से अनुदान के रूप में मांग करेंगे । क्या यह सत्य है, श्रीमन् ? क्या प्रोग्राम इसका आपने बनाया ? मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आपकी योजनायें किन आधारों पर बनी हैं ? क्या-क्या कमेटीज कौन-कौन सी तारीख को बनीं और कौन-कौन सी योजना के अन्दर बनीं ? क्या यह सही है कि श्रीमती गायत्री देवी ने अपने बयान में साफ कहा है कि यह सारा तमाशा है, न हमसे पूछा गया और न हमसे राय ली गयी ? इस योजना में उनका सहयोग नहीं है। तो ये जो समितियां हैं इनका किस-किस प्रकार का प्लान है ? क्या-क्या प्लान बनाये गये और कितने खर्चे की संभावना है ?

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक कासलीवाल साहब को माननीय सदस्य के द्वारा कोट किया गया है इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। यह सही है कि राजस्थान सरकार ने 7।। लाख रुपया अनुदान के रूप में इसके लिये दिया। इसके अलावा डोनेशन लेकर, जन सहयोग लेकर जो भी आयोजन का कार्यक्रम है उसको पूरा किया जा सकता है ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह सही है कि अढ़ाई शती के सम्बन्ध में जो योजनाएं बनायी ग ी है उसके आधार पर जयपुर शहर के अन्दर स्थायी काम कि जावेंगे, शहर की नालियों, ड्रेनेज, सीवेज सिस्टम, रोड्स आदि के सम्बन्ध में काम किये जावेंगे लेकिन एक भी काम पूरा नहीं हुआ? महरबानी करके आप पूरी बात बताइये। किन साधनों के अभाव को पूरा करने के लिये यह धनराशि खर्च की थी?

एक माननीय सदस्य : 7।। लाख में से कितना खर्च किया ?

श्री मूलचन्द डागा : 3 लाख खर्च कि े। जो खर्चा किया वह मुशाअरा और नाच में खर्च कर दिया।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी रूप रेखा दो बार बनी। पहले इसकी कमेटी बनी। फिर दुबारा दूसरी कमेटी फॉर्म की गई। जहां तक कार्यक्रम का सम्बन्ध है वह 18 नवम्बर से 3 दिसम्बर तक मनाया जाना था।

(व्यवधान)

पूरे साल आगामी 18 नवम्बर तक मनाया जाना था, यह बात सही है और अभी साल भर पूरा नहीं हुआ है।

श्री अब्दुल अजीज : क्या यह राजाओं के प्रभाव को उभारने की बात नहीं है? जबकि जनता सरकार किसानों और पिछड़े वर्ग की हिमायती अपने आपको मानती है? दूसरी तरफ राजाओं की प्रतिभा को बढ़ाया जा रहा है।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अढ़ाई शती का ध्येय क्या था? क्या प्रिन्सिपल्स थे इसके? वे प्रिन्सिपल्स पूरे हुए या नहीं? जयपुर के लिये ही क्यों योजना बनायी गयी? दूसरे शहरों के लि े, जो इससे भी अधिक प्राचीन हैं, कोई योजना क्यों नहीं बनायी गयी?

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्या डूंगरपुर के लिये भी कोई ऐसी योजना बनायी जायेगी? वह प्राचीन नगर है। यहां तो सब बाहर से आये हुए हैं बाहर का सारा समाज है। इसलिये मैं आपको पूछना चाहता हूं...

(व्यवधान)

क्या डूंगरपुर के लिये भी ऐसी योजना बनायी जावेगी?

(व्यवधान)

जयपुर के लि े ही यह क्यों बनायी गयी? जयपुर की अढ़ाई शती ही क्यों मनायी जाय, दूसरे शहरों की क्यों नहीं? राजस्थान में और भी प्रिन्सिपल सिटीज हैं, क्या उनमें भी समारोह मनाये जावेंगे?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब दिलवाइये। सरकार ढीली हो जाती है।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर पिंक सिटी के नाम से मशहूर है।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं यह मानकर चलता हूं कि गूंगी और बहरी सरकार है और जवाब नहीं दे रही है।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन्, एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। कितनी राशि खर्च हो गयी, कितनी राशि और खर्च की जावेगी और क्या प्लान है ? कौनसी कमेटियां गठित की गईं ? किसी प्रश्न का सरकार की ओर से उत्तर नहीं दिया जा रहा है। यह पूछा कि 250वीं वर्षगांठ मनाने की कोई योजना बनाई थी? यदि हां, तो कब और उसको मनाने के लिये कौन-कौन से साधन और मशीनरी है? इसका भी कोई जवाब नहीं। इनका जवाब दें। इवेजिव रिप्लाई दिया गया है वह गलत है। किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : जयपुर के राजघराने की पॉलिटिक्स के कारण...

(व्यवधान)

डूंगरपुर अति प्राचीन है उसका समारोह क्यों नहीं मनाया जाय ?

श्री रघुनाथ विश्नोई: उदयपुर में महाराणा प्रताप हुए थे। वहां की वर्षगांठ मनायी जानी चाहिये थी।

श्री मदन सिंह दांता : यह जयपुर के घराने का प्रश्न ही नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक-एक माननीय सदस्य बोलें तो कुछ समझ में तो आये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे ...

(व्यवधान)

श्री मदन सिंह दांता : आप बाड़मेर की व्याख्यायें करते हैं...

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : क्या यह बताने का कष्ट करेंगे कि भूतपूर्व सरकार ने किस आधार पर 250वीं वर्षगांठ मनायी?

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि हमें इस एप्रिहेन्शन और फोबिया से बाहर आना होगा कि इसकी योजना राजा-महाराजाओं को एप्लाई करने के लिए है। इसकी योजना पिछली सरकार ने बनायी थी। वह बजट प्रोविजन और फिजिबिलिटी को देख कर बनायी होगी। पहले ही भूतपूर्व मंत्री एवं अन्य लोगों की विदेश यात्रा हो चुकी थी, इसको कान्फ्रेंसेज हो चुकी थीं और इसकी वाइड पब्लिसिटी हो चुकी थी। उसी को पर्यटन प्रोत्साहन के हित में कन्टीन्यू करना उचित समझा गया है और इसीलिये यह कन्टीन्यू है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : झीलों की नगरी उदयपुर के लिये आपका विचार क्या है ?

श्रीमती विद्या पाठक : इस तरह का कोई प्रस्ताव आयेगा, बजट प्रावधान होगा तो विचार किया जा सकेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह क्या उत्तर हुआ?

श्री मूलचन्द डागा : कृपया प्रश्न का उत्तर दिलवाइये। कितनी धनराशि खर्च करनी है ?

श्री अध्यक्ष : जो भी धनराशि है वह खर्च की जावेगी।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : No reply has been given, Sir.

श्री अध्यक्ष : जो उत्तर दिया वह पर्याप्त है या नहीं, यह तो विचार का प्रश्न है । आप अपनी विचारधारा से चलते हैं । मैं मंत्री महोदया को मजबूर नहीं कर सकता । इससे अधिक उत्तर नहीं है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप डाइरेक्शन दे सकते हैं । स्पेसिफिक सप्लीमेन्ट्री पूछा है उसका जवाब देना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : मैं कुछ नहीं कहूंगा । मुझे कानूनन अधिकार नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन्, इसमें खर्चा बताया है । आपने लिखा है, 14,852 रुपया तो व्यवस्था पर व्यय है और कार्यालय व्यय है 33,916 रुपया । मैंने आपसे यह पूछा, कौनसी कमेटी है, कौन इसका चेयरमैन है और किस आधार पर खर्च किया है ? मेहरबानी करके बतायें कि 33,916 रुपये में कौनसा कार्यालय चल रहा है, कौन से पेड सर्वेन्ट्स हैं, कौन काम कर रहे हैं ? इतने समय में 33,916 रुपया कैसे उड़ा लिया और 18 हजार रुपया मकान किराया कैसे दे दिया ? यह जवाब दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ लिया । आपने रिपीट भी कर लिया ।

Now next question, श्री ओंकारलाल चौहान !

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 2 मार्च, 1978)

कोटा जिले में भूमि का आवंटन

20. श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

कोटा जिले में जून, 1977 से अब तक किस-किस जगह बंजड़ भूमि व सीलिंग की भूमि का राज्य सरकार द्वारा आवंटन किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

राजस्व मंत्री (श्री पुरुषोत्तम मंत्री) : कोटा जिले में जून, 1977 से अब तक जो बंजड़ भूमि व सीलिंग भूमि आवंटन की गई है, उसकी सूचियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ) ।

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूची माननीय राजस्व मन्त्री जी ने दी है उसमें सीलिंग की भूमि का कहीं जिक्र नहीं है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि सिर्फ छठे और सातवें महीने में अलॉटमेंट हुआ है, आठवें महीने के अंदर अटरू तहसील और छीपाबड़ोद तहसील में अलॉटमेंट का कार्य क्यों नहीं हुआ ? क्या मंत्री महोदय इसका कारण बताने की कृपा करेंगे ?

श्री शंकरलाल (जैतारण) : सीलिंग की भूमि का इसलिए अलाटमेंट नहीं हुआ कि राजा और महाराजाओं से लेकर भूमि अलॉट नहीं करना चाहते हैं ।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले में जून, 1977 से अब तक अनकमाण्ड क्षेत्र में 3595 बीघा बंजर भूमि का आवंटन किया गया, यह गलत है इसके अलावा अतिरिक्त जिलाधीश कोटा

(श्रीपुरुषोतम मन्त्री)
द्वारा 605 व्यक्तियों को 1503 बीघा भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आवंटित की गयी।

श्री शंकरलाल : तो कुल कितनी जमीन प्राप्त हुई सीलिंग से ?

श्री ओंकारलाल चौहान : प्रश्न यह था कि दो महीनों में भूमि का आवंटन हुआ और आठवें महीने में अटरू और छीपाबड़ौद तहसील में कोई भूमि का आवंटन नहीं हुआ। जो आपने सूची दी है उसके अन्दर इसका कहीं उल्लेख नहीं है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं कि आठवें महीने में अटरू और छीपा बड़ौद तहसील में आवंटन क्यों नहीं हुआ ? अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों को यह सुविधा क्यों नहीं दी, इसका कारण बता सकते हैं ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अटरू तहसील और छीपा बड़ौद तहसील में क्यों नहीं अनुसूचित जाति और जन-जाति को जमीन दी गयी, इसका कारण तो मेरे पास इस समय नहीं है। माननीय सदस्य मुझसे बात कर लें। इसका कोई समाधान निकाल लेंगे।

श्री ओंकारलाल चौहान : क्या यह माना जाये कि कोई भूमि आवंटन नहीं की गयी अटरू और छीपा बड़ौद तहसील में ?

श्री शंकरलाल : सीलिंग से कुल कितनी जमीन प्राप्त हुई ?

श्री पुरुषोतम मंत्री : यह तो नया प्रश्न है। इसके लिए अलग से प्रश्न दे दें।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय का यह जवाब है कि आप मुझसे मिल कर जवाब ले लें तो अब यह उनका प्रश्न नहीं रहा, बल्कि हाउस का हो गया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

## अकाल राहत कार्यों पर व्यय की गई राशि

58. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

राज्य में अकाल राहत कार्यों पर अब तक किस-किस वर्ष में कितना-कितना खर्चा किया गया ? वर्षवार आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

राज्य में वर्ष 1966-67 से लेकर 1976-77 तक अकाल राहत कार्यों पर खर्चा किया गया उसका वर्षवार विवरण निम्न है:-

| वर्ष | | अकाल राहत कार्यों पर व्यय ( रु. लाखों में ) |
|---|---|---|
| 1966-67 | .. | 1021.44 |
| 1967-68 | .. | 704.32 |
| 1968-69 | .. | 895.04 |
| 1969-70 | .. | 5118.98 |
| 1970-71 | .. | 3222.19 |
| 1971-72 | .. | 102.50 |
| 1972-73 | .. | 749.95 |
| 1973-74 | .. | 4175.62 |
| 1974-75 | .. | 194.26 |
| 1975-76 | .. | 740.91 |
| 1976-77 | .. | 52.09 |

Page No 22

(22)



(अकाल राहत मंत्री)

उपरोक्त व्यय 289 (पूर्व मद 64) प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में दी जाने वाली राहत की मद के अन्तर्गत सहायता विभाग द्वारा किया गया है।

लघु उद्योग निगम द्वारा 1975-76 में की गई खरीद

59. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

राजस्थान लघु उद्योग निगम (Rajasthan Small Industries Corporation) द्वारा वर्ष 1975-76 में कुल कितना सामान क्रय किया गया जिसमें से जोधपुर संभाग से कितना और जयपुर संभाग से कितना किया?

उत्तर

| वर्ष 1975-76 में राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा किया गया कुल क्रय | जयपुर संभाग से क्रय |
|---|---|
| 84,89,000.00 | 38,30,057.00 |
| | जोधपुर सम्भाग से क्रय |
| | 2,23,584.00 |

विश्वकर्मा तथा बाईस गोदाम औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर के उद्योग

60. श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल, जयपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) एशिया में सबसे बड़े कहे जाने वाले जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र तथा जयपुर के ही बाईस गोदाम में कुल कितनी औद्योगिक इकाइयां पंजीकृत हुई हैं? इनमें कितनी इकाइयों में उत्पादन शुरू हो गया है? शेष इकाइयों में कब से उत्पादन प्रारम्भ कर दिया जायगा।

(2) क्या यह सही है कि दोनों औद्योगिक क्षेत्रों में कुछ औद्योगिक इकाइयां किन्हीं कारणों से बन्द पड़ी हुई हैं? यदि हां, तो इनके बन्द होने का कारण तथा इनकी क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इन कारखानों में राज्य सरकार की कितनी पूंजी लगी है? क्या राज्य सरकार इन बन्द पड़े कारखानों को चालू करायेगी? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में 328 एवं बाईस गोदाम औद्योगिक सम्पदा में 101 इकाइयां पंजीकृत हैं। विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में 221 इकाइयां तथा बाईस गोदाम औद्योगिक सम्पदा में 95 इकाइयों द्वारा उत्पादन शुरू किया गया है। विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में शेष 97 एवं बाईस गोदाम औद्योगिक सम्पदा में 6 इकाइयों में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर रखा है एवं उनके द्वारा दो वर्ष की निर्धारित अवधि में उत्पादन शुरू करने की संभावना है।

(2) विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में 41 इकाई एवम् बाईस गोदाम औद्योगिक सम्पदा में 7 इकाई विभिन्न कारणों से बन्द हैं, जिनकी क्षेत्रवार बन्द होने के कारण सहित सूची संलग्न है।

(उद्योग मंत्री)

(3) बाईस गोदाम औद्योगिक सम्पदा की 3 इकाइयों में राज्य सरकार की गृह निर्माण में 55,024/- रुपये की पूंजी लगी हुई है। विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किया गया मार्जिन मनी ऋण के रूप में दो इकाइयों में 36,860 रुपये लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त इन रुग्ण इकाइयों में राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम का सैड निर्माण के रूप में राशि रु. 10,40,000 लगी हुई है। एवं राजस्थान वित्त निगम की 15,24,695/- रुपये ऋण के रूप में लगे हुए हैं। इन रुग्ण इकाइयों को पुनः जीवित करने के सम्बंध में भारत सरकार के निदेशानुसार राज्य में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है जिसके उद्योग सचिव अध्यक्ष थे व लघु उद्योग सेवा संस्थान भारत सरकार, जयपुर के निदेशक सदस्य सचिव हैं, इस कमेटी ने निर्णय लिया है कि जो इकाइयां कार्यशील पूंजी के सम्पदा अथवा अर्थ-व्यवस्था की वजह से बन्द है उन इकाइयों को जिन बैंकों ने ऋण दिया है उनके तकनीकी स्टाफ द्वारा पूर्ण विवरण सहित सर्वेक्षण कराया जाकर तथा सर्वेक्षण के आधार पर जो कमियां पाई जायं उनको दूर करने के लिये सम्बन्धित बैंक व सरकारी विभाग एवं राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा इन कमियों को पूरा कराया जाकर इन्हें पुनः जीवित करने का प्रयास किया जावेगा।

( सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें। )

### बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ सड़क का कार्य

61. श्री नाथूलाल (घाटोल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ सड़क का कार्य अधूरा है? यदि हां, तो सड़क कब तक डामर की हो जावेगी?

(2) इसे अब तक अपूर्ण क्यों छोड़ा गया ?

उत्तर

(1) इस सड़क की कुल लम्बाई 84 कि. मी. में से 64 कि. मी. बन चुकी है और केवल 20 किलोमीटर का कार्य बाकी है।

(2) अपूर्ण छोड़ने का प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि कार्य हर वर्ष धनराशि के उपलब्धि के अनुसार कराया जा रहा है।

### लघु उद्योग निगम द्वारा 1976-77 में की गई खरीद

62. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राजस्थान लघु उद्योग निगम (Rajasthan Small Industries Corporation, द्वारा वर्ष 1976-77 में कुल कितना सामान क्रय किया गया जिसमें से जोधपुर संभाग से कितना और जयपुर संभाग से कितना किया ?

(उद्योग मंत्री)

उत्तर

| वर्ष 1976-77 में राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा किया गया कुल क्रय | जयपुर संभाग से क्रय | जोधपुर संभाग से क्रय |
|---|---|---|
| 70,22,000.00 | 41,26,911.00 | 1,18,092.00 |

श्रीजी की मोरी जयपुर स्थित विभाग के मकान का बेचान

63. श्री मनफूल राम (केशरीसिंह पुरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्रीजी की मोरी जयपुर में पी. डब्ल्यू. डी. की प्रोपर्टी संख्या 94 थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि कि इस में रह रहे किरायेदार को खाली कराकर श्री ताराचन्द जैन, स्टोर कीपर फर्नीचर, पी. डब्ल्यू. डी. को किराए पर दिया गया था ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों वश और यह प्रोपर्टी श्री ताराचन्द जैन को 1969 में बेच दी है ? अगर हां, तो कितने रुपये में बेच दी है ? तथा इसकी नीलामी की गयी अथवा नहीं ? क्या नीलामी की सूचना सभी को दी गयी थी? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) इस प्रोपर्टी में कितनी जमीन बेचान करते समय थी और इसमें कितने कमरे व अन्य मकानात थे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) उक्त प्रोपर्टी का श्री ताराचन्द जैन कितना किराया देते थे ? इन्हें क्या क्या सुविधाएं थीं एवं कमरों की संख्या कितनी थी ? श्री जैन के किराएदार होने के बाद इस पर कितना पैसा खर्च किया गया ?

(5) उक्त प्रोपर्टी जहां है उधर की जमीन का 1969 में अनुमानित भाव क्या था ?

(6) क्या यह भी सही है कि मोहल्ले वालों की ओर से राज्य सरकार के पास कोई शिकायतें इस तरह की प्राप्त हुई हैं जिसमें उक्त प्रोपर्टी के बेचने में भी पी. डब्ल्यू. डी. के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण श्री जैन को सस्ते भाव पर बेचान की गयी तथा इसमें अनियमितता बरती गयी गयी है ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) मकान सं. पी. 94 श्रीजी की मोरी खाली होने की अवस्था में श्री ताराचन्द जैन को नियमानुसार किराये पर दिनांक 12-9-59 को आवंटन किया गया था। किरायेदारों को राजकीय निर्धारित मूल्य पर नजूल सम्पत्ति बेचने के नियम हैं। तदनुसार राज्य सरकार की स्वीकृति संख्या एफ. 1 (28) पी. डब्ल्यू./ए. एस. । वेल. 6/डी. 1446 दिनांक 26-6-69 द्वारा इस मकान को श्री तारा चन्द जैन को 6,540 रु. में बेचा गया जो उस समय का मूल्यांकन था। नीलामी के बजाय निर्धारित मूल्यांकन पर नियमानुसार किरायेदार को यह मकान विक्रय किया गया।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) मकान में तीन कमरे, दो स्टोर, रसोई, लेट्रीन, बाथरूम तथा खुला चौक था जिसका कुल एरिया 178.22 वर्ग गज था।

(4) नियमानुसार किराया इनके वेतन से वसूल किया जाता था। जो सुविधाएं साधारणतया किरायेदार को मिलती हैं वे ही इन्हें प्राप्त थीं। कमरों की संख्या पैरा (3) में वर्णित हैं। विक्रय से पूर्व यह मकान विभागीय मैन्टीनेंस लिस्ट में होने के कारण इसकी मरम्मत आदि होती रही है।

(5) सन् 1969 में नगर परिषद् जयपुर द्वारा जमीन दर रु. 15/- प्रति वर्ग गज इस क्षेत्र की चौकड़ी पड़ता दरों में निर्धारित थी। मूल्यांकन इसी आधार पर किया गया था।

(6) इस सम्बन्ध में कुछ नागरिकों की एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी विभागीय जांच की जा रही है।

ट्राइबल एरिया में घोषित क्षेत्र

64. श्री भूरा लाल (गोगुन्दा): क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि झाडोल, कोटडा, गोगुन्दा को राज्य सरकार ने विधान सभा चुनाव की दृष्टि से अनुसूचित जन-जाति को दो भागों में बांट दिया (झाडोल-गोगुन्दा) परन्तु अभी हाल ही में झाडोल-कोटडा को ट्राइबल एरिया घोषित कर दिया, मगर गोगुन्दा तहसील को ट्राइबल एरिया में न घोषित करने के क्या कारण हैं जब कि वहां की 60 प्रतिशत जनता आदिवासी है?

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन भारत सरकार परिसीमन आयोग, नई दिल्ली द्वारा उनके परिसीमन आदेश सं. 44 के द्वारा किया गया है न कि राज्य सरकार द्वारा। उदयपुर जिले की फलासिया, कोटड़ा एवं गोगुन्दा तहसीलों को फलासिया एवं गोगुन्दा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में इस प्रकार से सम्मिलित किया गया है:-

| | |
|---|---|
| फलासिया (अनुसूचित जन-जाति विधान सभा क्षेत्र) | फलासिया तहसील कोटडा तहसील का भाग (महरपुर आर. आई. सी.) व कोटडा आर. आई. सी. के पटवार सर्किल मांडवा, बीकराली सामोली व झेड़ को छोड़कर। |
| गोगुन्दा (अनुसूचित जाति विधान सभा क्षेत्र) | गोगुन्दा तहसील कोटड़ा तहसील का भाग (मेरपुर आर. आई. सी.) व कोटडा आर. आई. सी. के पटवार सर्किल मांडवा, बीकराली सामोली व झेठ। |

गोगुन्दा तहसील को "ट्राइबल सब प्लान एरिया में" सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि गोगुन्दा तहसील की आबादी वर्ष 1971 की जनसंख्या के अनुसार 83175 है जिसमें 30962 व्यक्ति जन-जाति के है। इस प्रकार से 37.23% जन-

(चुनाव मंत्री)
संख्या इस तहसील की जन-जाति की है। ट्राइबल सब प्लान एरिया में वे ही क्षेत्र सम्मिलित किये गये है जिनमें जन-जाति के व्यक्तियों की जनसंख्या 50% है।

जालोर जिले की सहकारी समितियों का कार्य

66. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि जिला जालोर में सहकारिता के क्षेत्र में संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं? अगर नहीं, तो किस-किस क्षेत्र में क्या-क्या प्रगति हुई है?

(2) क्या यह भी सही है कि क्रय-विक्रय समितियों के क्षेत्र में एवं उपभोक्ता भण्डार योजनाओं के तहत जालोर में संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है? अगर हां, तो क्यों? भविष्य में इसके बारे में राज्य सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है?

(3) क्या यह भी सही है कि सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में जालोर में संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है? अगर हां, तो क्यों? अगर नहीं, तो किस क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है? क्या यह संतोषजनक कही जा सकती है? भविष्य में इसकी प्रगति के लिये सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये जावेंगे?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियां जालोर में संतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रही हैं? अगर हां, तो क्यों? इस बारे में कब तक राज्य सरकार द्वारा प्रगति के लिये क्या कदम उठाये जावेंगे? अनुसूचित जाति एवं जन-जाति सदस्यता भर्ती राज्य सरकार की नीति के अनुसार क्या की जा सकी है? अगर हां, तो कितने प्रतिशत? अगर नहीं, तो क्यों? कब तक पूरी प्रतिशत भर्ती की जा सकेगी?

(5) क्या यह भी सही है कि कृषि सहकारी समितियों के विकास के क्षेत्र में जालोर सबसे पीछे रहा है? अगर हां, तो इसके क्या कारण थे? भविष्य में इस बारे में सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाये जावेंगे?

उत्तर

(1) जिला जालोर में सहकारिता के क्षेत्र में की गई प्रगति का विवरण परिशिष्ट (अ) में अंकित है।

(2) क्रय-विक्रय समितियों द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा परिशिष्ट 'ब' में अंकित है।

उपभोक्ता भंडारों के क्षेत्र में इस जिले में प्रगति संतोषप्रद नहीं है, कारण संलग्न परिशिष्ट 'स' में अंकित कर दिये गये हैं।

उपभोक्ता आंदोलन में सुधार लाने की दृष्टि से निम्न कार्यवाही की जा रही है :-

1. सिरोही जालोर सहकारी उपभोक्ता भंडार में वित्तीय स्थिति सुधारने पर जिले एवं अन्य स्थानों पर शाखाएं स्थापित कर दी जायेगी।

2. प्रारम्भिक उपभोक्ता भंडार जो निष्क्रिय हैं उनका पुनर्गठन अथवा नवीनीकरण किया जायगा। जो प्राथमिक उपभोक्ता भंडार सक्षम इकाई नहीं होगी उनको अवसायन में लिया जायेगा।

(सहकारिता मंत्री)

(3) जी नहीं, प्रगति का ब्यौरा परिशिष्ट 'द' में अंकित है।

(4) यह सही नहीं है जालोर जिले को ग्राम सेवा सहकारी समितियां सन्तोषजनक रूप से काम कर रही हैं। इन समितियों का ब्यौरा परिशिष्ट 'क' में अंकित है। अनुसूचित जाति / जन-जाति के सदस्यों को ग्राम सेवा सहकारी समिति का सदस्य बनने हेतु किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। एसे लोग आवेदन की तिथि से ही सहकारी समिति के सदस्य बन जाते हैं एवं प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति को प्रति वर्ष दिये गये ऋणों का कम से कम 1|3 भाग कमजोर वर्ग के लोगों के लिए देना आवश्यक है। कमजोर वर्ग के लोगों में अनुसूचित जाति/ जनजाति के लोग भी सम्मिलित है। अब तक जालोर जिले के 36 प्रतिशत ऐसे लोगों को ग्राम सेवा सहकारी समिति का सदस्य बनाया जा चुका है।

(5) यह सही है कि भूमि सहकारी समितियों के क्षेत्र से जालोर जिला पिछड़ा हुआ है। इस वर्ग की सहकारी समितियों में प्रगति न होने के कारण निम्न रहे हैं—

1. समितियों के सदस्यों का कार्यक्षेत्र छोड़कर दिया जाना।

2. सहकारी भंडार के सदस्यों में समिति के कार्य के प्रति रुचि का अभाव।

3. कृषि सहकारी समितियां, जो सक्षम इकाई नहीं पाई जावेगी, को अवसायन में लाया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

पंचायत समिति उमरेन को सार्वजनिक कुए बनाने के लिये दी गई राशि

67. श्री गंगा सहाय (कठूमर): क्या पंचायत राज एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पंचायत समिति, उमरेन, जिला अलवर को गत 5 वर्षों में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लोगों के लिये सार्वजनिक कुए बनाने हेतु कितनी धनराशि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई ? किन-किन गांवों में कितने कुए बने हैं, कितने कुए पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने अधूरे पड़े हैं और किस कारण से अधूरे पड़े हुए हैं ? अब तक इनमें कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ? विवरण देते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा पंचायत समिति, उमरेन, जिला अलवर को गत 5 वर्षों में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लोगों के लिये सार्वजनिक कुए बनाने हेतु कोई धन राशि स्वीकृत नहीं की गई थी। पंचायत समिति को सार्वजनिक पेयजल कूपों के निर्माण हेतु वर्ष 1972-73, 1975-76 एवं 1976-77 में प्राप्त कुल 41,070 की राशि राज्य सरकार से प्राप्त हुई थी जिसमें से 13,410 रुपये की राशि 19 सार्वजनिक पेयजल कूप अनुसूचित जाति के मोहल्लों में बनाने के लिए दी गई थी। उनमें से 11 पेयजल कूप पूर्ण हो चुके हैं तथा 8 पेयजल कूप अपूर्ण हैं। ये कार्य पंचायत समिति द्वारा अपेक्षित धनराशि स्वीकृत नहीं करने से अपूर्ण हैं। अब तक इन पेयजल कूपों पर 13,410 रुपये की राशि का व्यय हो चुका है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें।)

# Page No 28

250



पिपहेरा ग्राम में सेवारत ग्राम सेवक

68. श्री जगदीशसिंह (धौलपुर) : क्या पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री प्रयागसिंह, ग्राम सेवक (VLW) ता. 25-4-72 को धौलपुर सब-डिवीजन के पिपहेरा ग्राम में सेवारत था और उसको छुट्टी के दौरान ही 27-5-72 को ट्रान्सफर करके रिलीव कर दिया गया और आज तक उसको न ट्रान्सफर की जगह पर लिया गया और न धौलपुर में लिया गया ? यदि हां, तो क्या आज भी श्री प्रयाग सिंह सरकारी नौकरी में है ? अगर हां, तो कहां और किस पद पर ? अगर नहीं, तो क्यों ? अनियमितता यदि हुई है तो उसके लिये कौन अधिकारी दोषी है ?

(2) क्या यह सही है कि इस कर्मचारी के साथ ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । श्री प्रयागसिंह दिनांक 25-4-72 को दोनारी मुख्यालय पंचायत समिति, धौलपुर में ग्राम सेवक के पद पर नियुक्त थे । इनका स्थानान्तरण दिनांक 21-4-72 को पंचायत समिति घाटोल, जिला बांसवाड़ा में किया गया था । इन्होंने स्थानान्तरण आदेश की अवहेलना करने के उद्देश्य से दिनांक 25-4-72 से 7-5-72 व 8-5-72 से 31-5-72 की अवधि के अवकाश के प्रार्थना-पत्र दिये थ जिन्हें विकास अधिकारी, पंचायत समिति, धौलपुर ने अस्वीकृत कर दिये थे । विकास अधिकारी, धौलपुर ने दिनांक 29-5-72 को श्री प्रयागसिंह, ग्राम सेवक को इनके ड्यूटी पर गैर हाजिर रहने की स्थिति में ही उनको पंचायत समिति से कार्यमुक्त करके पंचायत समिति, घाटोल में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त कर दिया था । श्री प्रयागसिंह तब से ही अपनी ड्यूटी से जान-बूझकर गैर हाजिर हैं, और इन्होंने स्थानान्तरण आदेश की पालना में पंचायत समिति, घाटोल में अपनी उपस्थिति कभी भी नहीं दी है । स्थानान्तरण के आदेश की अनुपालना में श्री प्रयागसिंह को उनकी अनुपस्थिति में कार्यमुक्त करने व श्री प्रयागसिंह के जान-बूझकर अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर रहने सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराई जा रही है ।

(2) जी हां । विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रूपवास में श्री प्रयागसिंह का पंचायत समिति, धौलपुर में स्थानान्तरण हो जाने पर दिनांक 16-12-69 को श्री प्रयागसिंह के ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने की स्थिति में ही पंचायत समिति, रूपवास से कार्यमुक्त किया गया था । कारणों की जांच कराई जा रही है ।

झुन्झुनूं जिला परिषद् को दी गई राशि

69. श्री मालाराम (खेतड़ी) : क्या पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झुन्झुनूं जिला परिषद् को गत कार्यकाल में कितनी धनराशि विकास कार्य व अन्य कार्यों हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई ? वर्षवार विगत सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) जिला परिषद् द्वारा इस

(श्री मालाराम)

राशि का किस-किस कार्य के लिये कहां-कहां पर उपयोग किया गया ? क्या यह कार्य जन उपयोगी भी साबित हुए या नहीं ?

उत्तर

(1) झुन्झुनूं जिला परिषद् के गत कार्यकाल में कुल 11,05,392/- रुपये की धनराशि विकास कार्यों हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई थी। वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जिला परिषद् द्वारा उक्त राशि का उपयोग जिन-जिन कार्यों के लिए व जहां-जहां किया गया है उनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। ये समस्त कार्य जन-उपयोगी साबित हुए हैं या इनमें से कोई जन-उपयोगी साबित नहीं हुए हैं, उसकी अभी तक जांच नहीं कराई गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

पंचायत समिति नादोती द्वारा विभिन्न कार्यों के लिये दी गई राशि

70. श्री मूलचन्द (बौंसा), श्री कुंजी लाल (बामनवास): क्या पंचायत राज एवं विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) पंचायत समिति, नादोती, मुख्यालय बामनवास (सवाई माधोपुर) ने अपनी निजी आय से गत तीन वर्षों में कितनी-कितनी धनराशि बिना विभागीय स्वीकृति किन-किन कार्यों के लिए किन-किन व्यक्तियों को दी ? कृपया वर्षवार पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि दी गयी अधिकांश राशि का अभी तक उपयोग नहीं किया गया ? यदि हां, तो कितनी राशि का किन-किन व्यक्तियों द्वारा किस-किस कार्य के लिये उपयोग नहीं किया गया ? पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि जिन कार्यों के लिये उक्त धनराशि दी गई थी वे कार्य पंचायत समिति के विषय से बाहर के हैं। उनका पूर्ण होना सम्भव नहीं है ? यदि हां, तो ऐसे कार्यों की स्वीकृति देने का क्या औचित्य था ?

(4) क्या राज्य सरकार इस प्रकार से मनमाने गलत ढंग से पंचायत समिति कोष का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी तथा दी गयी धनराशि की उन लोगों से वसूली की जायेगी ? यदि हां, तो कब और कैसे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति ने ऐसी कोई भी राशि गत तीन वर्षों में किसी भी व्यक्ति को नहीं दी है जिसके लिये नियमानुसार विभागीय स्वीकृति अपेक्षित थी। पंचायत समिति द्वारा स्वीकृत राशि की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। जिन मामलों में उपयोग नहीं हुआ है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) इस बाबत जांच कराई जा रही है।

(4) इस बाबत जांच पूर्ण होने पर

(पंचायत राज एवं विकास मंत्री)
जांच प्रतिवेदन के आधार पर दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही शीघ्र की जावेगी एवं नियमानुसार वसूली की कार्यवाही भी शीघ्र की जावेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें।)

जालोर जिले में डेयरी विकास एवं पशुपालन विकास का कार्य

71. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि जिला जालोर में डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम के तहत डेयरी विकास एवं पशुपालन विकास के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं रखा है एवं न कोई योजना हाथ में ली गई है? अगर हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि रानीवाड़ा प्राइवेट डेयरी भी अच्छी तरह कार्य नहीं कर रही है एवं पशुपालन का सारा कार्य ठप्प हो गया है? अगर हां, तो राज्य सरकार इस बारे में क्या सोच रही है एवं निकट भविष्य में पशुपालन विकास के लिये राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या योजनाएं हाथ में ली जावेंगी?

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार द्वारा पशुओं के उपचार हेतु भी कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है? क्या यह भी सत्य है कि पशुओं की बीमारियों की रोकथाम हेतु पर्याप्त मात्रा में जिला जालोर में पशु अस्पतालों में दवाएं भी नहीं दी गई हैं? अगर हां, तो क्यों? अगर नहीं, तो कहां-कहां पर क्या-क्या बजट दिया है?

(4) जिला जालोर में उन्नत पशुओं की नव ब्रीड्स के विकास हेतु अब तक विभाग द्वारा क्या-क्या किया गया एवं भविष्य में राज्य सरकार क्या करने जा रही है?

(5) जिला जालोर में उन्नत पशुओं के फार्म अब तक क्यों नहीं लगाये गये एवं भविष्य में कहां-कहां पर क्या ब्रीड्स के फार्म लगाये जावेंगे?

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले में भेड़ एवं ऊन विकास की भी पूरी गुंजाइश है? अगर हां, तो इस बारे में राज्य सरकार ने अब तक क्या-क्या कदम उठाये हैं? भविष्य में कब तक क्या-क्या कदम उठाये जावेंगे?

उत्तर

(1) जी हां। क्योंकि जालोर जिले में डेयरी के सघन विकास हेतु भारत सरकार ने मैसर्स आइडियल प्राइवेट लि. कम्पनी को 25-3-1970 को एक औद्योगिक लाइसेन्स दे दिया अतः राज्य सरकार ने डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत इस जिले में कोई कार्यक्रम नहीं लिया। डी. पी. ए. पी. के तहत उन्हीं जिलों में कार्यक्रम लिया गया जहां पर निजी क्षेत्र में कोई भी ऐसी संस्था विस्तृत रूप से कार्य नहीं कर रही थी। राज्य सरकार द्वारा डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत कार्यक्रम केवल केन्द्र सरकार की अनुमति से ही लिया जाता है।

(2) यह सही है कि रानीवाड़ा प्राइवेट डेयरी अच्छी तरह कार्य नहीं कर रही है परन्तु यह सही नहीं है कि इससे पशुपालन का सारा कार्य ठप्प हो गया है। निकट भविष्य में पशुपालन विकास हेतु कोई योजना नहीं है।

(3) जी नहीं, पशुओं की चिकित्सा

# Page No 31

(31)



(पशुपालन मंत्री)
हेतु जालोर जिले में दस पशु चिकित्सालय, एक पशु औषधालय, तीन चल-पशु चिकित्सा इकाई एवं एक सुरक्षा चौकी कार्यरत है। वर्ष 1977-78 में जिला पशुपालन अधिकारी, जालोर और सिरोही को दवाइयां और औजार खरीदने हेतु रुपये 47,000/- का बजट आवंटित किया गया है। उक्त संस्थाओं द्वारा 2,19,285 टीके लगाये, 18,949 पशुओं का इलाज किया गया, 13,478 पशुओं के लिये दवाई वितरित की गई एवं 5,877 पशुओं का बधियाकरण किया गया।

(4) राज्य की नीति के अनुसार यह दायित्व आइडियल रानीवाड़ा का है। फिर भी विभाग द्वारा उन्नत नस्ल के सांड वितरित किये गये है।

(5) ब्रीड्स के फार्म लगाये जाने हेतु आवश्यक सुविधायें जिला जालोर में उपलब्ध न होने से फार्म नहीं लगाये गये एवं न ही निकट भविष्य में लगाये जाने की सम्भावना है।

(6) जी हां। राज्य सरकार द्वारा भेड़ व ऊन विभाग के अन्तर्गत भेड़ व ऊन विकास हेतु निम्न कार्य किये जा रहे हैं:-

जालोर में जिला भेड़ व ऊन अधिकारी का कार्यालय स्थित है। 5 भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र कार्यरत हैं। इनके द्वारा भेड़ों में स्वास्थ्य सेवाएं एवं प्रसार कार्य किया जाता है।

जिले में भेड़ विकास हेतु नवीन पशुपालन कार्यक्रम के अन्तर्गत सीमांत कृषक एवं कृषि श्रमिकों के लाभार्थ योजना कार्यरत है।

गत तीन वर्षों की जिले के अन्तर्गत प्रसार कार्यों की प्रगति निम्न प्रकार रही है :-

| कार्यक्रम | |
|---|---|
| 1. मेढों का बधियाकरण | 26,015 |
| 2. भेड़ों को दवा पिलाई गई | 9,06,507 |
| 3. भेड़ों का इलाज किया गया | 95,716 |
| 4. भेड़ों के टीके लगाये गये | 1,88,925 |

सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिक हेतु योजना के अन्तर्गत गत दो वर्षों में जिले में निम्न प्रगति की गई है :—

विवरण:

| | |
|---|---|
| 1. ऋण स्वीकृत किये गये : | |
| अ- इकाई | 247 |
| ब- राशि (लाख रु. में) | 5.87 |
| 2. अनुदान स्वीकृत किये गये : | |
| अ-इकाई | 95 |
| ब- राशि लाख रु. में | 0.86 |
| 3. भेड़ इकाई—क्रय : | |
| अ- इकाई | 95 |
| ब- ऋण लाख रु. में | 1.82 |
| स-अनुदान लाख रु. में | 0.86 |

वर्ष 1977-78 में 160 एवं वर्ष 1978-79 में 350 लघु एवं सीमान्त कृषकों को भेड़ इकाई उपलब्ध कराने के अतिरिक्त सामान्य स्वास्थ्य आवरण (Health Coverage) 350 एवं इलाज करने पर विचार किया जा रहा है।

सूरतगढ़ सब-यार्ड की दुकानें

72. श्री हरचन्दसिंह (पीलीबंगा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सूरतगढ़ सब-यार्ड में स्थित

(श्री हरचन्दसिंह)

दुकानों के पिड पक्के बनाने हेतु कृषि मन्डी, उपज समिति, पीलीबंगा द्वारा 1-1 हजार रुपये की सब्सिडी दुकानदारों को दी गई ? अगर हां, तो कितने दुकानदारों को दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त सभी दुकानदारों ने पिड पक्के बनवा लिये हैं? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या कृषि मन्डी उपज समिति पीलीबंगा ने सन् 1972 से 1974 तक पुलिया बनाने हेतु अग्रिम राशि व्यवस्थापक मण्डल के सदस्यों को दी ? अगर हां, तो किन-किन सदस्यों को कितनी-कितनी रकम दी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या उक्त तमाम पुलियाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या आपातकाल के दौरान पांच सूत्री कार्यक्रम के तहत पीलीबंगा कृषि मन्डी उपज समिति में भी वृक्षारोपण करवाया गया ? अगर हां, तो कितने वृक्ष लगवाये और अब उन पर कितना खर्च हुआ ? उनमें से कोई वृक्ष अब मौके पर मौजूद भी है या ?

उत्तर

(1) जी हां ! 22 दुकानदारों को यह सब्सिडी दी गई थी। इनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) 20 दुकानदारों द्वारा पिड बनाये जा चुके हैं तथा दो के बाकी है जिन्हें शीघ्र बनवाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां, जिन सदस्यों को जितनी अग्रिम राशि दी गई उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) तमाम पुलियाओं का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। जिन व्यक्तियों ने पुलियाओं का निर्माण नहीं करवाया है उन्हें मण्डी समिति द्वारा नोटिस दिये गये है तथा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। जहां-जहां पर सदस्यों द्वारा पुलिया बनाई गई हैं उनका नक्शा मांगा गया है जिससे सहायक अभियन्ता द्वारा उनकी प्रामाणिकता की जांच की जा सके।

(5) जी हां। समिति द्वारा 100 वृक्ष लगवाये गये तथा उनके चारों ओर ईंटों की बाढ़ बनाई गई। इन पर 3,803/- का व्यय किया गया। यार्ड की मिट्टी सख्त होने से यह पनप नहीं पाये और सूख गये।

### शूकर प्रजनन केन्द्र

73. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राज्य में शूकर प्रजनन केन्द्र कितने और कौन-कौन से जिलों में खोले गये हैं ? प्रत्येक केन्द्र पर भवन, मशीनों आदि उपकरणों में राज्य सरकार की कितनी धनराशि लगी हुई है ? अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन व भत्ते पर प्रति वर्ष कितना खर्चा होता है और कितनी आमदनी प्रति वर्ष इन केन्द्रों से होती है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

राज्य में शूकर प्रजनन केन्द्र एक है जो अलवर जिले में अलवर में ही स्थित है। इस केन्द्र के भवन पर चार लाख, मशीन एवं उपकरणों पर 2,70,634/-रुपया व्यय हुआ है। अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर खर्च एवं आमदनी की सूची

(पशुपालन मंत्री)
क्रमशः 'क', 'ख' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

मरु विकास बोर्ड की उपलब्धियां

74. श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) मरु विकास बोर्ड के गठन के बाद क्या उपलब्धियां हुईं और आज तक इस पर कितना खर्चा केन्द्र एवं राज्य सरकार का हो चुका है ?

(2) राज्य सरकार इसके व्यावहारिक प्रश्न को सफल बनाने को क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) राज्य स्तरीय मरुस्थल विकास मण्डल का गठन दिनांक 12-1-76 को मरु क्षेत्रों के विकास के लिये नीति सम्बन्धी दिशा का निर्देश देने और मरुस्थल विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन का पुनर्विलोकन करने हेतु किया गया था। इस पर अभी तक कोई व्यय नहीं किया गया है।

(2) मण्डल को अधिक व्यावहारिक रूप देने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

मुर्गीपालन केन्द्र, टौंक

75. श्री अजीत सिंह (टौंक): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि टौंक शहर में स्थापित मुर्गीपालन केन्द्र को फिर से चालू करने पर राज्य सरकार विचार कर रही है ?

(2) विभाग घाटे के कारण इसे नहीं चलाना चाहता तो क्या इस मुर्गीपालन केन्द्र को किराये पर मुर्गीपालकों की सहकारी समिति को दिया जा सकता है ? यदि हां, तो किन-किन शर्तों पर ?

(3) क्या मुर्गीपालकों को इस फार्म के चालू न रहने से सही अण्डों का अभाव रहता है ? क्या राज्य सरकार इस पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी हां। राजकीय कुक्कुट शाला, टौंक के बंद हो जाने से क्षेत्र में मुर्गीपालन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। टौंक फार्म के पुनःस्थापन एवं कुक्कुट उत्पादन क्रय-विक्रय सहकारी समिति के पुनर्गठन संबंधी प्रस्ताव तैयार किया जा रहे हैं।

ग्राम आलनियावास की चरागाह की भूमि

76. श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) ग्राम आलनियावास, तहसील डेगाना, जिला नागौर में चरागाह हेतु मवेशियों के लिये कितनी भूमि आरक्षित है ?

(2) चरागाह हेतु आरक्षित भूमि का विवरण, उसका खसरा नम्बर, जमीन, रकबा चरागाह हेतु कब किस तारीख को घोषित की गई व उसका उपयोग क्या किया जा रहा

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)
है, का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) ग्राम आलनियावास, तहसील डेगाना, जिला नागौर में मवेशियों के लिये 1035 बीघा 10 बिस्वा भूमि आरक्षित है ।

(2) वांछित सूचना संलग्न है ।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें ।)

बामनवास तहसील का भवन

77. श्री कुन्जी लाल (बामनवास): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बामनवास तहसील भवन और तहसील के अन्य क्वार्टर आदि आवश्यक मरम्मत के अभाव में दिनों दिन खण्डित होते रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि तहसील क्षेत्र की चारदीवारी नहीं होने के कारण सारे तहसील कम्पाउन्ड में जानवरों की भीड़ व गन्दगी का ढेर लगा रहता है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार तहसील के कार्यालय भवन, क्वार्टरों की मरम्मत व तहसील के चारों ओर दीवार बनवायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है ।

(2) तहसील भवन की चारदीवारी नहीं है जिसके कारण तहसील कम्पाउण्ड में जानवरों का आना-जाना बदस्तूर बना रहता है जिसके फलस्वरूप गंदगी हो जाती है । जहां तक मरम्मत व दीवार बनाने का प्रश्न है इसके लिए जिलाधीश द्वारा राजस्व मण्डल को मरम्मत हेतु प्रस्ताव भेज दिया गया है । यहां से फंड आवंटन होने पर मरम्मत करायी जाएगी । जहां तक चारदीवारी का प्रश्न है जिलाधीश को इसके भी प्रस्ताव भेजने के लिए लिख दिया गया है ।

तहसील नागौर का भवन

80. श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार तहसील नागौर के भवन को, जो अन्य जिला प्रशासन के भवनों से 1 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है, को नीलाम करना चाहती है ?

(2) क्या राज्य सरकार तहसील नागौर के लिए नया भवन जिलाधीश कार्यालय में या पास में बना रही है ?

(3) क्या तहसील का पुराना भवन नीलाम करने से नया बनाये जाने वाले भवन से ज्यादा कीमत आ जायेगी ?

उत्तर

(1) तहसील भवन को नीलाम करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ?

(2) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(3) इस बारे में अभी कोई तकनीकी राय नहीं ली गई है क्योंकि कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री श्योपत सिंह मकासर, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 14 मार्च को गोपाल इन्डस्ट्रीज कोटा के एक लोटू मजदूर कार्यकर्त्ता की हत्या के विषय में,

(2) सर्वश्री खेतसिंह, शंकरलाल व मूलचन्द डागा, सदस्य विधान सभा की ओर से भू-जल विभाग, जोधपुर के कुछ कर्मचारियों को नौकरी से हटाने और उक्त विभाग के ड्रिलिंग कर्मचारी एसोसियेशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल व अनशन करने की घटना के विषय में,

(3) सर्वश्री रामनारायण चौधरी, बुलाराम, नरपतराम व वृद्धिचन्द जैन, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान के पॉलि-टेक्निक छात्रों में तकनीकी शिक्षकों के सत्या-ग्रह से उत्पन्न असन्तोष के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

विशेषाधिकार भंग प्रश्न

राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित लेख

मैंने कल सदन को सूचित किया था कि माननीय सदस्य श्री मूलचन्द डागा ने जिस विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना दी है उसको प्रस्तुत करने के लिए मैंने अपनी अनुमति प्रक्रिया के नियम 157 के अन्तर्गत प्रदान नहीं की है।

श्री डागा ने मेरी व्यवस्था के पश्चात् यह आग्रह किया कि इस संबंध में उनकी बात सुनी जाये।

वे कल मुझसे मेरे चेम्बर में मिले और अपने प्रस्ताव के समर्थन में उन्होंने मेरे समक्ष कुछ तथ्य प्रस्तुत किये। यद्यपि संसदीय परम्पराओं में यह साधारण प्रक्रिया है कि आसन अपने ही विनिश्चय का पुर्नानिरीक्षण करे, सामान्यतया आसन द्वारा दिये गये निर्णयों में कोई परिवर्तन अथवा संशोधन नहीं किया जाता है किन्तु संसदीय कार्यवाहीं में ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि यदि कोई माननीय सदस्य पीठासीन अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्णय के किसी बिन्दु पर स्पष्टीकरण चाहें अथवा आसन से उस पर पुर्नविचार के लिए अनुरोध करें तो ऐसे अवसर आये हैं जब आसन ने अपनी व्यवस्था पर पुर्नविचार करके उसमें संशोधन किये हैं।

श्री डागा ने मेरे समक्ष जो तथ्य रखे तथा अपने कथन के पक्ष में जो मुद्दे प्रस्तुत किये उनको दृष्टिगत रखते हुए मैंने अपने कल के निर्णय पर पुर्नविचार किया है। मैं श्री डागा के तर्क से सहमत हूं कि प्राइमा फेसी यह मामला विशेषाधिकार की परिधि में आता है।

अतः अपने पूर्व के निर्णय पर विचार के बाद मैंने प्रक्रिया के नियम 157 के अन्तर्गत श्री डागा के प्रश्न पर अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। इस प्रश्न को विधिवत रूप से सदन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कल की कार्य सूची में सम्मिलित कर लिया है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय

(श्री श्योपतसिंह मकासर)
अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मुझे खेद इस बात का है कि जब हम ....

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मार्गो के राष्ट्रीयकरण के बारे में आपको एक स्थगन प्रस्ताव दिया था ....

श्री अध्यक्ष : किसके बारे में ?

श्री रामकरण सिंह : जो राष्ट्रीयकरण हो रहा है उसके बारे में दिया है। परसों का दिया हुआ आज तक नहीं मिला.....

श्री अध्यक्ष : मुझे सूचना नहीं है ।

श्री रामकरण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सचिवालय में जो सूचना कार्यालय है वहां दिया हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : मैं प्राप्त कर लूंगा । माननीय सदस्य श्री श्योपतसिंह !

श्री श्योपतसिंह मकासर : स्थगन प्रस्ताव का जबाब देना या उसको कार्यवाही करना तो अलग बात है, जिन मिनिस्टरों के महकमों से संबंध रखने वाले स्थगन प्रस्ताव हों, या विषय हों उन पर अगर...

(व्यवधान)

शुरू करता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में बोलें । चर्चा करने की नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है । कल मुख्य मंत्री ने भी इस ओर ध्यान आकर्षित किया था, मेरी भी सहमति है । जो परम्परा सदन की है वह भंग नहीं होनी चाहिये । नियमों के उपरान्त कन्वेंशन्स हैं । कन्वेंशन्स के अनुसार बड़ी-बड़ी मुख्य-मुख्य बातें हैं उनसे सरकार को अवगत करा दीजिये ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं ऐसा ही करूंगा ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (विधि मंत्री) : एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि जिस मामले में पुलिस इन्वेस्टीगेशन चल रहा हो और जुडिशियल कोर्ट के सामने आने वाला हो उस पर अगर सदन में चर्चा उठाई जाये तो निश्चित रूप से यह सदन के नियमों के अन्तर्गत नहीं होगा । मैं चाहूंगा कि इस दृष्टि को देखते हुए जो व्यवस्था है. ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : अगर तफतीश हो रही है तो बोल सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : एक हद तक मेरी सहमति है । जब तक विपक्ष का सहयोग आसन को प्राप्त नहीं होगा तब तक इस संबंध में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता । अगर मंत्री महोदय चाहते हैं तो अन्य दलों के नेताओं से मिल लें और बैठ कर इस संबंध में चर्चा कर लें ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे विधि मंत्री महोदय...

श्री अध्यक्ष : परम्पराओं के अनुसार चलिये ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय विधि मंत्री महोदय को यह मालूम ही नहीं कि चालान अदालत में हो गया या नहीं

# Page No 37

(37)



(श्री श्योपतसिंह मकासर)
हुआ है। कयास के आधार पर यह बात कह रहे हैं ....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अन्डर रूल्स स्पीकर की.....

श्री अध्यक्ष : चालान हो गया है, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : हम कानून की पालना करते हुए.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : I don't know. मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : ऐसे मामलों पर, जो कोर्ट में विचाराधीन हैं, इस सदन में विचार किया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष : जो कोर्ट में विचाराधीन मसले हैं, उन पर चर्चा सदन में नहीं हो सकती ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं विधि मंत्री की बात को समझता हूं। वे चाहते हैं कि हमारी हुकूमत में कोई भी आदमी किसी तरह का जुल्म करे, उस जुल्म की बात यहां पर न आ पाये। कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। मैं इस विषय की तरफ, माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जनता पार्टी की हुकूमत बनने के साथ और दौरान इमर्जेन्सी जनता पार्टी के नेताओं के साथ एक लम्बे अर्से तक जुल्म के शिकार रहने का मौका मिला। इस पार्टी की नीति भी इसी बात पर आधारित है। हम जुल्म के शिकार साथ-साथ रहे हैं। इसलिये हमारा दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न होते हुए भी कुछ हद तक हम साथ चल सकते हैं। मगर एक बड़ी परेशानी जनता पार्टी के सामने आई है, उस परेशानी को मैं जानता हूं क्योंकि मेरी पार्टी उस परेशानी को भुगत रही है। सबसे ज्यादा परेशानी यह है कि जनता पार्टी के कुछ घटक हैं जिनकी बाहर शक्ल अलग है और जनता पार्टी के अन्दर उनकी शक्ल अलग है। आर.एस.एस. जो जनता पार्टी का संगठन नहीं है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह विषय पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं विषय पर ही बोल रहा हूं।

श्री मूलचन्द डागा : यह भारतीय मजदूर संघ की बात कर रहे हैं ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : भारतीय मजदूर संघ जनता पार्टी का घटक नहीं है लेकिन जनता पार्टी के नेताओं का आशीर्वाद लेकर पिछले 8 महीनों में बी. एम. एस. ने लगातार, जबसे जनता पार्टी की सरकार बनी हर क्षेत्र के अन्दर अपना रोब गालिब करने की गुंडाई तरीके से हावी होने की कोशिश की है। जैसे त्रिपाठी की मिसाल आपके सामने है। भीलवाड़ा की घटना पहली घटना नहीं है। बी. एम. एस. के लोगों ने की....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जनता पार्टी के नेताओं के आशीर्वाद से इस घटक द्वारा कोटा के अन्दर 14 तारीख को घटना हुई। मैं खबरदार कर देना चाहता हूं जनता पार्टी के नेताओं को कि उस घटक का जनता पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। जनता पार्टी के नेताओं से आशीर्वाद पाकर

# Page No 38

(38)



(श्री श्योपतसिंह मकासर)

इस तरह की घटनायें उसके द्वारा की जा रही हैं। मैं जिक्र करना चाहता हूं कि गोपाल इण्डस्ट्रीज के एक कार्यकर्ता को 14 तारीख रात्रि को कतल कर दिया गया। किस तरह कतल किया गया? उसके अन्दर साजिश है। मैं गृह मंत्री को जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके कन्टेन्ट्स बताना चाहता हूं। उसका सर चकनाचूर कर दिया गया। यह रात के 9 बजे की घटना है। अकेला ड्यूटी पर जा रहा था। उस वक्त रात को उसे इसलिये मारा गया कि बी. एम. एस. के संगठन का वहां पर असर कमजोर है, जहां सीटू का असर है। वहां अपना प्रभाव जमाने के लिये यह किया गया। नितांत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि मंत्रिमण्डल के एक मंत्री हैं उनकी जानकारी में है। प्रोटेक्शन दिया जा रहा है उनको,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मुल्जिमानों को। सरकार की जिम्मेदारी है, गृह मंत्रीजी की जिम्मेदारी है····

श्री शंकरलाल : मंत्री का नाम बताओ, वरना सभी मंत्रियों के ऊपर एलीगेशन है।

श्री मूलचन्द डागा : कोटा के मंत्री हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं कहना चाहूंगा, गृह मंत्रीजी, अगर इस तरह की राजनैतिक हत्यायें शुरू हो गई प्रदेश में तो बड़ी मुश्किल होगी, बड़ी परेशानी होगी। हम तो तीस साल परेशानी में रहे, मगर परेशानी हुकूमत करने वालों को ज्यादा होती है। जो रास्ता कांग्रेस ने अपनाया उस तरह के रास्ते पर मत जाइये····

श्री मूलचन्द डागा : कांग्रेस ने यह तरीका कभी नहीं अपनाया···

श्री श्योपतसिंह मकासर : हम तो भुक्तभोगी हैं भाई।

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : इनकी मौजूदगी में चाकू छुराबाजी हुई है। मैं यह आरोप लगाता हूं। आप जब परियोजना में भाषण देने गये थे तो सी. पी. आई. के लोग खुद चाकूबाजी को बढ़ावा दे रहे थे····

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपको कहना चाहिये था····

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इनकी मौजूदगी में चाकू छुराबाजी हुई है। आज ये आरोप नहीं लगा सकते हैं इस प्रकार का···

श्री श्योपतसिंह मकासर : कोई बी.एम. एस. का है क्या?

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : अपने दिल पर हाथ रख कर कह दीजिये, आपके सामने चाकूबाजी हुई या नहीं? आप थे मौजूद।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है····

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं राइट है बोलने का, सुन लें।

Page No 39

(39)



श्री श्योपतसिंह मकासर : जो रावत भाटा से माननीय सदस्य आये हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं...

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

मंत्रिमंडल के सदस्य पर आरोप

श्री शंकरलाल (जैतारण) : व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं उसमें मंत्रिमंडल के किसी सदस्य का नाम आया है कि उन्होंने पनाह दी। यह बात गम्भीर बात है। वह कौन मन्त्री है ? यह सदन के माननीय सदस्य जानना चाहेंगे। उसके बिना सारे मंत्रिमंडल के सदस्यों पर आरोप आता है। इस प्रकार का आरोप लगे और जनता पार्टी की सरकार चुप बैठी रहे। ऐसा कौनसा मंत्री है, उनको बताना चाहिये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न और है...

श्री मूलचन्द डागा : One point of order has already been raised and a decision has not been given by the Chair. Therefore there cannot be another point of order.

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक व्यवस्था के प्रश्न पर दूसरा व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं उठ सकता।

श्री मूलचन्द डागा : There cannot be a point of order on another. How can you raise a point of order unless the one is decided by the Chair.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न व्यवस्था का उठाया है वह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

माननीय प्रद्युम्न सिंहजी, स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य श्योपतसिंहजी से मेरा निवेदन है मोटे-मोटे मुद्दों को ही आप रखें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मोटे-मोटे मुद्दे ही हैं, ये रखने नहीं देते हैं।

चर्चित प्रश्न पर स्थगन प्रस्ताव

श्री सूर्यनारायण चौधरी : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन, सर।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट में समाप्त करें। मुझे सहयोग दें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हां, बिलकुल सहयोग दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, वह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन, सर।

श्री अध्यक्ष : Yes।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : कल के दिन इस सदन में श्रम मंत्रालय की मांग थी, यह प्रश्न कल तक उत्पन्न हो चुका था....

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह इनफार्मेशन का कोई पॉइन्ट है क्या ?

# Page No 40

(40)



श्री मूलचन्द डागा : But the Chair is on legs.

श्री सूर्यनारायण चौधरी : ये सारे मुद्दे मालूम हैं -सीटू और बी. एम. एस. के, जो कुछ भी हैं, कल मालूम थे। निश्चित रूप से मैं निवेदन करूंगा एडजोर्नमेंट मोशन का अर्थ हुआ करता है..

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह गृह मंत्री जी से ताल्लुक रखता है। यह लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन का सवाल है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अब यह प्रश्न उठ ही नहीं सकता है। मैं इस पर व्यवस्था चाहूंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : ये मंत्री हैं? पॉइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन माननीय मंत्रीजी ने उठाया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पॉइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन माननीय मंत्रीजी ने उठाया है उस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि सदन की कार्यवाही परम्परागत रूप से चल रही है और परम्परा के विपरीत नहीं चल रही है। मैं नम्रतापूर्वक यही निवेदन करूंगा कोई घटना हुई है और कोई हत्या हुई है तो उसके मोटे-मोटे मुद्दों पर ही बोलें और घटकवाद को छोड़ दें।

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि रावतभाटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, जिस समय मैं भाषण दे रहा था, उस समय झगड़ा हुआ। मैं यह बता दूं कि माननीय सदस्य उस समय वहीं मौजूद थे। झगड़ा हुआ तब माननीय सदस्य वहां से भाग गये। यह तो मैं ही था जो वहां पर रहा...

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आरोप बिलकुल निराधार है।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, मेरी भी बात सुन लीजिये।

श्री एच. एन. शर्मा : इन्होंने सी.पी. आई. के कार्यकर्ताओं को भड़काया। दो आदमियों से चाकू के वार करवा रहे थे। उसके बाद तो दो ग्यारह हो गये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं तो आपको बचाकर लाया हूं। इस तरह से काम चलने वाला नहीं है...

(व्यवधान)

वे भाग गये मैंने छुड़वाया उनको ......

श्री एच.एन. शर्मा : मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि श्योपतसिंहजी ने रावतभाटा में चाकू चलवाये। मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करता हूं ये भी चाकूबाजी में शामिल थे। इनकी गिनती भी उसमें करनी चाहिये।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, एक लेटेस्ट इन्फार्मेशन आई है। जिस समय चाकूबाजी चल रही थी तो दोनों माननीय सदस्य वहां थे। यह इन्क्वायरी की बात है।

(श्री मदनसिंह दांता)
यह नोट कर लीजिये कि दो माननीय सदस्य वहां मौजूद थे ।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : This is in the F.I.R. This is a written document.

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय श्योपतसिंहजी वहां भाषण करने गये थे । भाषण के समाप्त होने के तुरन्त बाद सी. पी. आई. के कार्यकर्ताओं से चाकूबाजी करवाई । चाकूबाजी करवाने के बाद नो दो ग्यारह हो गये । चाकूबाजी में इनका पूरा पूरा हाथ था ।

श्री मदनसिंह दांता : यह इनक्वायरी का विषय है ।

श्री एच. एन. शर्मा : इन्होंने भाषण से मजदूरों में आग पैदा कर दी और इतनी उत्तेजना फैला दी कि मजदूरों ने आक्रमण किया । इनकी मौजूदगी में आक्रमण किया । भाषण देकर इन्होंने भड़काया ..

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : भाषण देकर उत्तेजना तो इन्होंने फैलाई ..

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपको भी भड़का दूं क्या मैं ?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : पाइन्ट ऑफ आर्डर ।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक राजनैतिक हत्या के बारे में चर्चा शुरू की और...

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कह तो दूं । बात तो पूरी ही नहीं होने देते.....

श्री अध्यक्ष : यह बहुत विवादास्पद प्रश्न है, माननीय सदस्य । सत्तारूढ़ पक्ष आपको बोलने नहीं दे रहा है । इस अशान्त वातावरण में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मुझे आप अपनी बात तो कहने दें ।

श्री मूलचन्द डागा : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर । मैं आपका ध्यान रूल 272 की तरफ दिलाना चाहता हूं...

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के एम. एल. एज. जिस तरह से हल्ला मचा कर बोलने नहीं दे रहे हैं, बहुमत के आधार पर जिस तरह से अल्पमत को बोलने से रोक रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके बारे में आप व्यवस्था करें । प्रजातंत्र का महत्व इसी बात में है कि अल्पमत को भी अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिले । अल्पमत को भी अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार है । जब अल्पमत कोई बात कहता है तो उसे मेजोरिटी के आधार पर दबाने की कोशिश की जाती है, लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है । यह बहुत गंभीर मसला है ।

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)
अगर कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द हो तो उसका आप प्रोसीडिंग्स से एक्सपंज करवा सकते हैं They have no right to interfere and they should not be allowed to....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं कुछ सुन पाऊं तो कहूं ।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं एक ही बात कहना चाहता हूं । मैंने जैसा अभी निवेदन किया, जिस मर्डर की चर्चा की, यह राजस्थान के अन्दर.....

श्री टीकमचन्द कान्त (जालोर) : क्या इस हाउस को दूषित राजनैतिक प्रचार का साधन बना सकते हैं ? ..

(व्यवधान)

क्या हाउस को दूषित राजनैतिक प्रचार का साधन बनाया जा सकता है ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : It is a high drama of politics.

श्री बजरंगलाल शर्मा : एक व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न व्यवस्था के वातावरण के अन्दर हो सकता है । क्या मैं 15 मिनट के लिए इस सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दूं ? माननीय सदस्य क्या यह चाहते हैं ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत वातावरण में सुन लीजिए ।

श्री बजरंग लाल शर्मा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य रामकृष्ण दास गुप्ता ने यह कहा You are non-sense. यह स्पष्ट तौर पर कहा है । इन्कार भी नहीं करेंगे ये कि इन्होंने नहीं कहा...

श्री मदनसिंह दांता : किस को कहा है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : I say it is fantastic non-sense—Fantastic non-sense Fantastic non-sense is not un parliamentary. I say non-sense, non-sense, non-sense, non-sense.

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : मेहरबानी करके मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए । मैं यह व्यवस्था चाहता हूं, यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने नोनसेन्स किसको कहा ? जनता पार्टी के विधायक जब बोल रहे थे तब इन्होंने नोनसेन्स कहा । पहले मैं इस बात का उत्तर चाहता हूं । आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या किसी माननीय सदस्य को किसी दूसरे सदस्य को या सदस्यों के समुदाय को नोनसेन्स कहने का हक है ? माननीय सदस्य ने जो नोनसेंस कहा वह इन्होंने किसी सदस्य विशेष को कहा या सबको कहा, पूरे समुदाय को कहा है ? यह तो तय हो जाना चाहिए ।

श्री मदनसिंह दांता : बात को कहा है, आपको नहीं ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : किसी को भी कह सकते हैं । आप यह फर्मा दीजिए ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को लेकर सदन में उत्तेजना पैदा हुई । अभी जिस मर्डर का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उल्लेख किया जा रहा है, मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उसकी जांच हो रही है। कुछ अरेस्ट भी हुए हैं, और आप विश्वास रख कर चलिये कि जांच में जो भी दोषी पाये जायेंगे, उनको निश्चित रूप से दण्ड मिलेगा, इसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा, जैसा माननीय सदस्य रामकृष्णदासजी ने कहा कि माननीय सदस्य बोलने नहीं देते। मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर हाउस की गरिमा है, उस गरिमा को हम सब को मिल कर बना कर रखना चाहिए तभी हाउस की गरिमा भी रहेगी और लोकतंत्र का विकास होगा। मैं ज्यादा इस संबंध में विवाद में नहीं पड़ना चाहता, इतना ही कहूंगा कि अपोजीशन को अपनी बात कहने का अधिकार है। व्यवस्था के अन्दर आप जो कुछ कहना चाहें कहें, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, हम सुनेंगे और जो कुछ भी उत्तर होगा उससे आपको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। उत्तेजना का वातावरण नहीं बने, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : उत्तेजना तो आपकी तरफ से होती है। सत्ता पक्ष की ओर से होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी कई बार कहा है कि सत्ता पक्ष की ज्यादा जवाबदारी है, आपका बिजनेस है, आपको व्यवस्था रखनी चाहिए। एक न एक बात पर विवाद खड़ा कर देते हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : गुलाबचन्दजी कटारिया जब बोल रहे थे तो रामकृष्णदासजी गुप्ता ने नोनसेंस कहा है। या तो वे अपने शब्द वापस लें या इस पर उचित कार्यवाही करें। माननीय नेता महोदय ने कहा है कि आपकी भी जिम्मेदारी है, यह आपका दायित्व है कि इस सदन के सदस्यों की गरिमा को कोई ठेस नहीं पहुंचाई जावे। इसलिए कृपा करके रामकृष्णदासजी गुप्ता को कहें कि वे अपने शब्द वापस लें या आप व्यवस्था दें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : I have all respects for the Members...

श्री अध्यक्ष : मैं प्रोसीडिंग्स देखे बिना व्यवस्था देने में असमर्थ हूं। नोनसेंस शब्द का प्रयोग हो सकता है लेकिन जिस कन्टेक्स्ट में प्रयोग हुआ है यदि वह आपत्तिजनक है तो मैं देख कर व्यवस्था कर दूंगा। नोनसेंस शब्द अनपार्लियामेंट्री हो, ऐसी बात नहीं है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता I have already said..

श्री बजरंगलाल शर्मा : फेंटास्टिक नोनसेंस कहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री श्योपतसिंहजी, आपको जो कुछ कहना हो कह दीजिए दो मिनट में।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं तो एक ही बात कह रहा हूं कि राजस्थान के अन्दर राजनैतिक वातावरण में राजनैतिक हत्याओं का दौर शुरू हुआ है, वह सब पर लागू होगा, मेरे तक ही सीमित नहीं रहेगा। आज लोग बौखला रहे हैं, सुनते ही नहीं हैं। यह जाहिर करता है कि कहां तक इनके पाप इनके सिर पर चढ़ कर बोल रहे हैं। ऐसी बात मत होने दीजिए। यह तो हो नहीं सकता कि एक को एक गज से नापें और दूसरे को

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

दूसरे गज से नापें। सवाल इस बात का नहीं है कि मेरी पार्टी की मेजोरिटी नहीं है या सीट् की मेजोरिटी नहीं है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का एक ही सदस्य हूं इसलिए इजाजत नहीं देंगे? गिनती ये फैसले नहीं हुआ करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि राजनैतिक वातावरण शांत हो, कारखानों में मजदूर काम करें, जिस संगठन की ताकत हो उस संगठन को बढ़ने का मौका मिले और सही परम्पराओं का पालन हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही मांग करता हूं कि इस हत्या के लिये जो भी जिम्मेदार हैं उनको गिरफ्त में लेना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिये ताकि भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आप और आप माननीय सदस्य, शंकरलालजी या खेतसिंहजी दोनों में से कोई भी बोल लें।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : दोनों बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप तय कर लें कि पहले कौन बोलेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मैंने एक स्थगन प्रस्ताव इस बारे में दिया है कि भू-जल विभाग के चार सौ कर्मचारियों को नोटिस दे दिए गए हैं और उन्हें सर्विस से अलग करने के लिए.......

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। चूंकि इस विषय में सदन में काफी चर्चा हो चुकी है इसलिये मैं भी दो शब्द अर्ज करना चाहूंगा....

श्री श्योपतसिंह मकासर : किस विषय में ?

श्री सम्पतराम : इसी विषय में जिस पर अभी चर्चा हो चुकी है।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : इस संबंध में मैं भी कुछ कहना चाहता हूं....

श्री सम्पतराम : यह वास्तव में बड़े दुःख की बात है कि मजदूर तबके में किसी भी प्रकार का टेन्शन हो, आपस में तनाव हो। हम जो मजदूर वर्ग में काम करना चाहते हैं, वह चाहे इधर बैठने वाले माननीय सदस्य हों या उधर बैठने वाले माननीय सदस्य हों, हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि मजदूरों का वेलफेयर हो, उनकी बहबूदी हो, उनकी तरक्की हो। उसमें जितना भी गवर्नमेन्ट का सहयोग हो सकेगा, वह करेगी।

मैं दूसरे पहलू पर निवेदन करना चाहूंगा जिस पर आज सदन में चर्चा हुई है। कोई भी पार्टी हो, किसी भी दल से प्रभावित हो, जब इस प्रकार के हीनियस आफेन्सेज हो जाते हैं तो गवर्नमेंट को, उसके किसी महकमे को बीच में आना पड़ता है। उसके सामने एक ही दृष्टिकोण रह जाता है कि दलगत राजनीति से ऊंचा उठ कर कार्यवाही करें और जो व्यक्ति निर्दोष हैं उनको न्याय दें और जो कोई भी व्यक्ति दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें। इस मामले में ही 3-4 मुलजिम गिरफ्तार हो गये हैं। एक कोई गन भी बरामद हुई है और चाकू भी बरामद हुआ है। लोग अरेस्ट भी हुए हैं। इसलिए मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजनैतिक प्रभाव है नहीं, और कोई प्रभाव इस प्रकार की बातों में होगा नहीं, सही इन्वेस्टीगेशन होगा और संबंधित व्यक्तियों का चालान

(श्री सम्पतराम)
होगा इसमें किसी को कोई शक नहीं करना चाहिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया, एक स्थगन प्रस्ताव इस बारे में दिया है कि भू-जल विभाग के 400 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया जा रहा है। भू-जल विभाग में 300 ब्लास्टिंग यूनिट्स हैं और 50 के करीब रिग्स हैं। ब्लास्टिंग यूनिट्स की रेट प्राइवेट लोगों से बहुत ज्यादा होने की वजह से आज-कल जितने कुए काश्तकार खुदवाते हैं वे प्राइवेट यूनिट्स से खुदवाते हैं। वे काम सस्ता करते हैं इसलिए उनसे काम करवाते हैं और आपके भू-जल विभाग की ब्लास्टिंग यूनिट्स से काम नहीं करवाते हैं। उनकी रेट्स में और इनकी रेट्स में 70 पैसे और एक रुपये का फर्क है। प्राइवेट वाले 60 पैसे चार्ज करते हैं तो आपका विभाग एक रुपया चार्ज करता है। इस वजह से यह हालत हो गई कि 300 यूनिट्स में से 100 यूनिट्स बेकार हैं। उनको काम नहीं मिल रहा है। काम नहीं मिलता है इस वजह से आपने तय किया है कि यूनिट्स को कम कर दिया जाय, इसी प्रकार बोरिंग में भी प्राइवेट एन्टरप्राइजर्स आते रहते हैं और प्राइवेट लोग बोरिंग करते हैं। आपकी रेट बोरिंग की बहुत ज्यादा आती है। करीब-करीब 50 पर्सेन्ट कम में प्राइवेट पार्टीज बोरिंग कर देती हैं तो फिर सरकारी महकमे से कौन बोरिंग करायेगा। इसलिए खास तौर से निवेदन है कि आप अपनी रेट्स को रिवाइज कीजिये। अगर आपने कर्मचारियों को कम किया तो सारे विभाग के कर्मचारी हड़ताल कर देंगे। इससे जितने भी काश्तकारों के वर्क, डी.पी.ए.पी. के वर्क चल रहे हैं वे सफर होंगे। इसलिए इस समस्या को गम्भीरता से लेना चाहिए। विभाग अपनी रेट्स प्राइवेट पार्टीज की रेट्स की तुलना में काम करके मार्केट में आये।

दूसरा निवेदन यह है कि जिन लोगों को नोटिसेज दिये हैं उनको नौकरी से नहीं हटाकर वापस लगायें ताकि इस विभाग के अन्दर जो अशान्ति फैली हुई है, वह दूर हो।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस संबंध में स्थगन प्रस्ताव दिया था। मैं निवेदन कर रहा था कि यह प्रस्ताव बेरोजगारों को रोजगार देने का नहीं है। ये सारे कर्मचारी ऑल रेडी पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं। जैसा कि माननीय खेतसिहजी ने कहा है, 400 लोगों को नौकरी से अलग कर रहे हैं और केवल इसलिए कर रहे हैं कि मशीनों से बोरिंग और ड्रिलिंग की जो रेट है वह रेट ज्यादा है। दूसरे प्राइवेट लोग हैं जिनके पास बोरिंग और ड्रिलिंग की मशीनें हैं, वे लोग सस्ती रेट पर काम करते हैं। सरकारी मशीनरी पड़ी रहती है तो सरकारी कर्मचारियों का दोष नहीं है। या तो आप रेट कम करिये और अगर रेट कम नहीं करते हैं तो उनको दूसरी नौकरी पर लगाइये। आप उनको निकालने का नोटिस कैसे दे सकते हैं।

मैं निवेदन करूंगा कि भू-जल विभाग की ड्रिलिंग कर्मचारी एसोसियेशन की ओर से जो पर्चा निकाला गया है उसमें बताया गया है कि दिनांक 13-3-78 से 19-3-78 तक भूख हड़ताल और 20-3-78 से आमरण अनशन पर बैठेंगे और काम रोको हड़ताल करेंगे। मैं यह पर्चा सदन की मेज पर रखता हूं।

(श्री शंकरलाल)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इन कर्मचारियों की सब मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके निर्णय ले। साथ ही जो नोटिस आपने उनको दिये हैं उन्हें तुरन्त वापस ले। यह उनकी वाजिब मांग है। आप उनको नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं। या तो अपनी मशीनों की रेट कम करें या उन कर्मचारियों को दूसरी जगह पर लगायें। अगर उनको आप नौकरी से निकाल देंगे तो वह लोग और हम लोग, जो उनका समर्थन कर रहे हैं, धरना देंगे। उनकी बड़ी वाजिब मांग है। इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में कहना चाहूंगा कि उनको नौकरी से निकालने के नोटिसेज वापस लें।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह घोषणा की है कि 5,30,000 आदमियों को रोजगार देगी, और बार-बार यह घोषणा करती है कि हम बेरोजगारी को मिटाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर जब कर्मचारी लोग नम्रतापूर्वक उनके अधिकारियों से जाकर मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं तो सरकार व अधिकारी उनके साथ में जो रवैया अख्त्यार करते हैं उससे उन लोगों में बेचैनी पैदा होती है और लोग बार-बार भूख हड़ताल पर बैठते हैं। अगर सरकार नम्रता की भाषा और प्रार्थना करने की भाषा को भी नहीं मानती है तो फिर कौन सी भाषा को माननी है। लोग धरने पर बैठ जाते हैं या प्रदर्शन करते हैं तो शक्ति का अपव्यय होता है। मैं चाहता हूं कि बैठ कर आप बात कर लें, निर्णय ले लें और घोषणा कर दें तो अच्छा होगा। उन्होंने अपनी 22 सूत्री मांगें दी हैं, उनमें से कई मांगें उनकी बड़ी वाजिब हैं। उनको रविवार की छुट्टी नहीं मिलती है, इन्डिपेन्डेन्स डे की छुट्टी नहीं मिलती है। उनकी सारी मांगों पर, मैं प्रार्थना करता हूं, विचार किया जाय ताकि वह कर्मचारी हड़ताल वगैरह न करें। जो मुख्य अभियंता हैं उनको बुलाकर बात करके उन्हें सन्तोष दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह स्थगन प्रस्ताव, जो प्रस्तुत किया गया है, के बारे में विचार सुन कर मुझे काफी अफसोस भी हुआ है। अफसोस इस बात का कि माननीय सदस्य श्री शंकरलालजी अच्छी तरह जानते हैं कि अन्डरग्राउण्ड वाटर बोर्ड की रेट्स को लेकर इस सदन में भी कई बार चर्चाएं हुई हैं। जिस समय चर्चा हुई तबसे सरकारी पक्ष, भूतपूर्व सरकार की ओर से बार-बार यह कहा गया कि अगर रेट घटा देते हैं तो किसी प्रकार भी इकोनोमिक नहीं होता है। यह प्रश्न कई बार सदन में आ चुका है और इस पर विवाद हो चुका है, उसके बावजूद सरकार ने मजबूरी बताई। उसकी कुछ यूनिट्स को कम करने से अगर किसी प्रकार से ओवरहैड एक्सपेन्डीचर कम करें तो रेट्स कम हो सकती हैं अदरवाइज रेट्स के कम होने का सवाल नहीं है। इस प्रश्न पर आपने जिज्ञासा दिखाई है तो नये सिरे से विचार कर लेंगे कि ओवरहैड चार्जेज को किस प्रकार से कम किया जा सकता है। प्राइवेट कम्पीटीटर्स के मुकाबले में रेट्स पर विचार किया जाय, इस बारे में जितनी आपकी चिन्ता है उतनी ही चिन्ता हमको है। इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करेंगे। परन्तु मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि ओवरहैड चार्जेज जितने कम करेंगे उतनी रेट्स कम होंगी लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्डीचर को जब कम करेंगे तभी ओवर हैड चार्जेज कम होंगे।

आज ब्लास्टिंग यूनिट्स कम होती हैं तो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
जो लोग वहां पर काम में लगे हुए हैं उनको नेचूरली रिट्रेन्च करके सरप्लस घोषित करके दूसरी जगहों पर लगाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक तरफ तो आप कहते हैं कि ओवर हैड एक्सपेन्डीचर कम किया जाय और दूसरी तरफ जब ब्लास्टिंग के चार्जेज को कम करने के लिए कुछ लोगों को रिट्रेंच करते हैं तो आप कहते हैं कि उनको रिट्रेंच नहीं किया जाय। तो दोनों बाते एक साथ नहीं चल सकती हैं। अगर ओवरहैड एक्सपेन्डीचर को कम करना पड़ेगा तो खर्चा कम करना पड़ेगा। मैं इस बात को मानता हूं कि सर्विस से निकलने पर लोगों को दुःख होगा। जो माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की है इस सारे प्रश्न को देख कर जो उचित निर्णय होगा वह करेंगे।

यह कहा गया कि सरकार किस प्रकार की भाषा सुनती है? सरकार जन-भाषा सुनती है। उस पर धमकी की भाषा का असर नहीं होता है। जन-भाषा में जिस प्रकार की लेंग्वेज होती है उसमें हमने सरकारी कर्मचारियों की बातें पहले भी सुनी हैं। धमकी की भाषा हम नहीं सुनते हैं। ऐसी स्थिति में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि सरकारी कर्मचारियों को धमकी देने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। उनकी वाजिब मांगों को मंजूर करते हैं। आजकल फिस्कल रेस्ट्रेन्ट सब जगह ज्यादा है। वित्तीय स्थिति जैसी है उसको हमने बिगाड़ दिया हो यह बात नहीं है। यह थर्टी ईयर्स की लीगेसी है। इस लीगेसी से निकलने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। इस आधार पर मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं पर असन्तोष है तो उस असन्तोष का बैठकर निराकरण करने को तैयार हैं। आप भड़कायें नहीं और उत्तेजनात्मक कार्यवाही करने के लिए उनको प्रेरित न करें।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि विचार करेंगे यह तो ठीक है लेकिन यह जो उत्तेजना फैलाने की बात कही है यह राजनीति से प्रेरित बात है और बार-बार यह कहते हैं यह गलत है। मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग क्या इनको नियमों के अनुसार अलग कर सकते हैं? कल ही आप बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे थे, लेकिन आज रोजगार में लगे हुए जो लोग हैं उनको निकालने की बात करते हैं। प्राइवेट मशीनरी जिस रेट पर चल सकती है उस रेट पर सरकारी मशीनरी क्यों नहीं चल सकती है? इसको क्यों नहीं देखते हैं। माननीय मुख्य मन्त्रीजी, आप उनको नहीं निकाल सकते हैं। अगर निकालेंगे तो आपकी खुद की घोषणाओं, लोकतान्त्रिक सिद्धान्त, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात के खिलाफ होगा, और उनकी हड़ताल वाजिब होगी। हड़ताल वाजिब होने पर हम उसका समर्थन करेंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं उधर के लोग भी इस वाजिब मांग का समर्थन करेंगे। इस पर आप गंभीरता से विचार करें। आप विचार कर निर्णय लें और इनको न निकालें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप बोलना चाहते हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन: अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर पांच पालिटेक्निक स्कूल्स हैं और उनमें 250 लेक्चरार हैं। जब से

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जो लेक्चरार हैं उनके वेतनमान बढ़ाए जाएं और राज्य सरकार ने भी यह निर्णय ले लिया है कि जो कॉलेजेज हैं, उनके लेक्चरार के वेतनमान बढ़ा दिए जाएं किन्तु इन पॉलिटेक्निक लेक्चरार के वेतनमान नहीं बढ़ाये जब कि पहले इनके वेतनमान आर्ट्स के लेक्चरार से ज्यादा थे। इससे उनमें भी असन्तोष पैदा हो गया। इस असन्तोष के कारण उन्होंने सत्याग्रह करना शुरू कर दिया। इसके कारण यह स्थिति पैदा हो गई है कि वे विद्यार्थियों को पढ़ाते नहीं हैं। जो एग्जामिनेशन जनवरी, 1978 में होने वाला था, वह नहीं हुआ है। जो पार्ट टाइम परीक्षाएं होती थी, वे परीक्षाएं उनकी रुकी हुई हैं। कक्षाएं अच्छी तरह से चल नहीं रही हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों की पढ़ाई में बहुत बाधा हो रही है। यह स्थिति पैदा हो सकती है कि उनकी परीक्षा न हो। इस प्रकार उनका एक साल बेकार हो जाए और वे डिप्लोमा प्राप्त न कर सकें यह स्थिति, श्रीमान, पैदा हो सकती है। यह जो वेतनमान का प्रश्न है, इसको राज्य सरकार सुलझावे, जैसे भी आप उचित समझें सुलझावें ताकि यह स्थिति न पैदा हो कि विद्यार्थी का साल खराब हो। यह जो प्रश्न है इसको आप हल करें। इन विद्यार्थियों का जीवन, केरियर खराब न हो, इस प्रकार का सरकार कदम उठावे।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान में पॉलिटेक्निक छात्रों की समस्याओं के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। मान्यवर, 1 तारीख से 17 तारीख तक स्थगन प्रस्ताव पर बराबर आपकी तरफ से यह व्यवस्था दी जा रही है कि राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है, एक भी स्थगन प्रस्ताव के बारे में आपके पास राज्य सरकार ने जानकारी नहीं भेजी है जिसके फलस्वरूप आप एक भी स्थगन प्रस्ताव के बारे में उचित व्यवस्था नहीं दे सके हैं। आपने सारे स्थगन प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजे हैं। इस सत्र का आधा समय व्यतीत हो चुका है किन्तु आज तक एक भी स्थगन प्रस्ताव की जानकारी नहीं मिली है। इसलिए मुझे भय है कि हमने जो स्थगन प्रस्ताव आपको प्रस्तुत किए हैं, जिनके बारे में आप राज्य सरकार से जानकारी चाह रहे हैं, सत्र का आधा समय तो निकल चुका है तो फिर कैसे आप इनके बारे में व्यवस्था देकर सदन में चर्चा उठाने की अनुमति दे सकेंगे ?

मान्यवर, राजस्थान के अन्दर जो पॉलिटेक्निक स्कूल हैं, उनके तमाम लेक्चरारों ने सत्याग्रह कर रखा है। वे अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर स्कूल, कॉलेज में जाकर बैठ जाते हैं। कक्षाएं नहीं चलाते हैं। पढ़ाई नहीं हो रही है। दिसम्बर की परीक्षा स्थगित हो गई है। जनवरी की परीक्षा स्थगित हो गई है। अब यह नहीं मालूम कि ये परीक्षाएं कब होंगी ? उनका भविष्य क्या है ? उनमें गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के लड़के पढ़ रहे हैं। मां-बाप पेट काट कर, अपने वस्त्रों में कमी करके, अपनी अन्य आवश्यकताओं में कमी करके कालेजों में लड़कों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। वहां पर लेक्चरार उनको नहीं पढ़ाते हैं। यह एक विचित्र विडम्बना की स्थिति पैदा हो गई है। इस कारण से वहां पर असन्तोष बहुत गहरा हो गया है। कल ही डाइरेक्टर, टेक्निकल एजूकेशन, जोधपुर अजमेर गये थे। अजमेर के अन्दर उनका घेराव हुआ। पांच घंटे तक उनका घेराव होता रहा। ऐसी भयंकर

(श्री रामनारायण चौधरी)
स्थिति पैदा हो गई। डाइरेक्टर, टेक्निकल एजूकेशन कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे पाये कि वे क्या कदम उठाने जा रहे हैं। इसलिए, मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के हजारों नौनिहालों का, युवकों का, जो वहां पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, यह साल बरबाद हो रहा है। एक साल का उनका खर्चा बेकार जाएगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस मामले में व्यवस्था करें। सरकार क्या सोच रही है? इन अध्यापकों को वेतनमान दें या न दें, यह आपके देखने की बात है। यदि उनकी बात वाजिब है तो उसको मान लिया जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने देश के लेक्चरार के बारे में जो सुझाव दिए हैं, उसके बारे में आपकी क्या नीति है? पहले जो आर्ट्स और साइन्स के लेक्चरार थे, उनकी ग्रेड्स इनसे कम थीं। पॉलिटेक्निक के लेक्चरार की ग्रेड्स ज्यादा थीं। इसलिए इस पर सरकार को शीघ्र निर्णय करना चाहिए ताकि लड़कों का भविष्य खराब न हो। आपने, मान्यवर, यह व्यवस्था दी है कि आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। परन्तु यह जानकारी राज्य सरकार आपको कब तक दे देगी? आज तक सत्र में जितने भी स्थगन प्रस्ताव पेश किये गये हैं उनके बारे में सरकार ने कोई जानकारी आपको नहीं भेजी है। यह स्थिति है। मैंने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, माननीय वृद्धिचन्द जैन, माननीय दुला-रामजी स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, उनकी स्थिति यह न हो जाय कि सदन का सत्रावसान हो जावे और वे स्थगन प्रस्ताव जानकारी के अभाव में आपके सचिवालय में ही पड़े रहें। इसलिये, मान्यवर, आप इस पर कोई न कोई व्यवस्था दें, सरकार को आगाह करें। कब तक; कितनी अवधि में स्थगन प्रस्तावों की जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त हो जाय, निश्चित रूप से समय की एक सीमा निर्धारित की जानी चाहिये, 24 घंटे, 40 घंटे, 32 घंटे, 15 दिन में जानकारी नहीं आयेगी राज्य सरकार से तो फिर स्थगन प्रस्ताव देने का कोई औचित्य नहीं रहता है, मान्यवर।

श्री दुलाराम (रायसिंह नगर): अध्यक्ष महोदय, मैंने कई स्थगन प्रस्ताव पेश किये मगर मुझे दुःख है कि आज तक सरकार की तरफ से एक का भी जवाब नहीं आया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने नारे तो खूब लगाये हैं किसानों के लिए मगर आज गंगानगर का किसान लूटा जा रहा है। जब कपास बिक जाएगी उसके बाद आप यहां पर जवाब देंगे तो मैं यह मानूंगा कि आपका रवैया, इस सरकार का रवैया किसान-विरोधी है। किसानों को राहत दिलाने के लिए यह सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर सकेगी। मान्यवर, कपास बिक गई या बिक जाएगी तब तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा। जो अधिकारी हैं, वे मोनोपोली कर लेंगे, उसके बाद मंत्री महोदय जवाब देंगे और यह देंगे कि खरीद बन्द थी इसलिए भाव गिर गए। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जो फसल बाकी है उसको खरीदा जाए। मार्च के आखिर तक यह बिक जाएगी। फिर इसका इस संबंध में व्यवस्था कब होगी? मुझे दुःख है कि मुख्य मंत्रीजी सदन में नहीं हैं। वे स्वयं किसान हैं। इसका जवाब क्यों नहीं आता है? सरकार क्यों इस प्रश्न पर मौन रह जाती है? अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि परसों यहां पर गंगानगर के जिलाधीश आए हुए थे। मेरी जानकारी के अनुसार मंत्रीजी को उन्होंने जवाब दिया है। परन्तु मंत्रीजी उस जवाब

(श्री दुलाराम)

को जानबूझकर इस सदन में लाना नहीं चाहते हैं। मेरा यह आरोप है, अध्यक्ष महोदय, इस सरकार पर कि वह जानबूझकर किसानों को दबाना चाहती है। किसानों का माल कम भाव पर बिकने के कारण उनको नुकसान पहुंच रहा है। किसानों को बचाने के लिए जल्दी कार्यवाही की जाए। फसल बिक जाएगी उसके बाद गवर्नमेंट क्या जवाब देगी ? खरीद बंद कर दी है इसलिए भाव कम हो गये। भाव ठप्प हो गये।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पांच पॉलिटेक्निक हैं। उनके प्राध्यापक वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने घोषणा की है कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की सिफारिश के आधार पर लेक्चरार के वेतनमान बढ़ाए जायेंगे। इन 250 शिक्षकों का वेतनमान आप क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पहले जो घाटा है, उसमें दो करोड़ का घाटा और ज्यादा जुड़ जाएगा। मेरा निवेदन है सरकार से कि इन छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ न हो। उनके साथ अन्याय न हो। मजबूर होकर उनको हड़ताल न करनी पड़े। मुझे इस संबंध में एक पत्र प्राप्त हुआ है। अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो इनको मजबूरन हड़ताल करनी पड़ेगी, एजीटेशन करना पड़ेगा और सरकार के खिलाफ सारे कालेजों की हड़ताल करानी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि वह आज ही इसकी घोषणा करें कि जिस तरह से अन्य अध्यापकों के वेतनमान सरकार ने बढ़ाए हैं उसी तरह से इन 250 अध्यापकों के भी वेतनमान बढ़ाएगी।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन। श्री हरजीराम बुरडक!

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजा एवं पुनः स्थापन की अनुदान की राशि दिलाने सम्बन्धी याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित दो याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं --

(क) पिड़ावा कस्बे में मुंसिफ-मजिस्ट्रेट कोर्ट की स्थापना करने सम्बन्धी।

(ख) ग्राम नहराबाद, तहसील पचपहाड़ का तुरन्त विद्युतीकरण कराने सम्बन्धी।

समिति का प्रतिवेदन
जन लेखा समिति का पहला, दूसरा व तीसरा प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री औंकारलाल चौहान।

श्री औंकार लाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं जन लेखा समिति 1977-78 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :--

(1) विनियोग लेखे 1972-73 में बताये गये दत्तमत अनुदान तथा प्रभृत विनियोगों में अतिरेक के मामलों पर समिति का पहला प्रतिवेदन।

(श्री ओंकारलाल चौहान)

(2) विनियोग व वित्त लेखे 1971-72 व वर्ष 1971-72 के लेखों पर अंकेक्षा प्रतिवेदन से सम्बन्धित वित्त (व्यय) विभाग विषयक मामलों तथा विनियोग व वित्त-लेखे 1972-73 व वर्ष 1972-73 से सम्बन्धित आबकारी, उद्योग, उपनिवेशन, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा, वाणिज्यिक कर, सहकारिता एवं सिंचाई विभाग विषयक मामलों पर समिति का दूसरा प्रतिवेदन।

(3) जन लेखा समिति के दसवें प्रतिवेदन (चौथी विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों के परिपालन हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर समिति का तीसरा प्रतिवेदन।

खेतड़ी में महिलाओं के साथ घटी घटना

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन् आपकी सेवा में तीन दिन पहले एक एडजोर्नमेन्ट मोशन खेतड़ी में महिलाओं के साथ घटी घटना के सम्बन्ध में दिया गया था। वह जानकारी के लिए भेजा गया था। आज हिंदुस्तान के सभी पत्रों में उस घटना की चर्चा हुई है। हमारे अधिकारियों के होते हुए भी कोई लड़की वापस नहीं लौट सकी है।

श्री अध्यक्ष : इस पर सदन में चर्चा तो हो चुकी है।

श्री मूलचन्द डागा : नहीं, श्रीमन्, गृह मन्त्रीजी ने कहा था कि जांच कराके उत्तर देंगे।

श्री अध्यक्ष : क्या फिर उठाना है?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमने निवेदन किया था। राज्य सरकार के पास आप जो स्थगन प्रस्ताव जानकारी के लिए भेजते हैं, उनमें से एक की भी जानकारी आज तक राजस्थान सरकार ने नहीं भेजी है। आसन की गरिमा का ख्याल नहीं रख कर वस्तु स्थिति की जानकारी नहीं देते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप राजस्थान सरकार को ताड़ना दीजिए। माननीय डागा साहब ने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है, उस स्थगन प्रस्ताव को भी आपने सरकार के पास जानकारी के लिए भेजा है। उसकी जानकारी आ गई होती तो हमारे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का सिर नीचा करने वाला काम खेतड़ी में किया गया है, उस पर वक्तव्य दिया जाता। लेकिन सरकार ने स्थगन प्रस्ताव की कोई जानकारी नहीं दी है। मैंने कल स्थगन प्रस्ताव दिया था इस मामले में, जैसा आपने फर्माया था, मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। लेकिन स्थगन प्रस्ताव ऑलरेडी सरकार के पास भेजा गया है।

श्री अध्यक्ष : जानकारी आ जानी चाहिए थी।

श्री रामनारायण चौधरी : सरकार को ताड़ना तो दीजिए। आपकी बात भी नहीं मानते हैं। अगर ऐसा किया गया तो हमारी मर्यादाएं टूट जायेंगी। न इनको परम्परा का ख्याल है, न आसन की गरिमा का ख्याल है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा होगा तो व्यवस्था की जाएगी। ज्यादा होगा तो ताड़ना दी जाएगी। अभी आवश्यकता नहीं है।

श्री शीशराम ओला (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, यह खेतड़ी की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उन लड़कियों को तीन दिन गायब रखा गया है।

कई माननीय : सदस्य शेम! शेम!

श्री शीशराम ओला : इसके बारे में सरकार उदासीन है। राजस्थान वीर भूमि है। यहां पर इस प्रकार की लज्जाजनक घटनाएं हों।

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल गलत बयान दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है।

श्री ईश्वरचन्द्र : मैं निवेदन करना चाहता हूं.....

(व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : उत्तर जल्दी आना चाहिए था। यह समाज की मर्यादा का प्रश्न है।

श्री ईश्वरचन्द्र : व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैं स्वयं चिन्तित हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : सरकार को इस बात का ख्याल नहीं है।

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से .....

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपने इन्सानियत खो दी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। माननीय मन्त्री महोदय को सुनें।

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ दिनों से मैं बराबर देख रहा हू, माननीय सदस्य इस प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सदन के माननीय सदस्य सरकार से जानकारी की आशा करते हैं तो कायदे और कानून को देखना भी आपका काम है। आप सदन में सरकार को कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हू। माननीय रामनारायणजी स्वयं भी मन्त्री रहे हैं, वे जानते हैं, कायदे और कानून हैं। सरकार को नोटिस मिलता है।

श्री रामनारायण चौधरी : उस घटना की कोई बात नहीं कह रहे हैं। आप क्या जानकारी दे रहे हैं....

(व्यवधान)

मैं तो इस आसन से जानकारी प्राप्त कर रहा हूं। आपके पास जानकारी सरकारी से आई है ?

श्री ईश्वरचन्द्र : यह सब इन्दिरा कांग्रेस के दिमाग की उपज है।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सदन की मर्यादा की रक्षा के लिए विराजे हुये हैं। आप सरकार को आदेश देते हैं, सरकार से जानकारी चाहते हैं। आपकी व्यवस्थाओं का सरकार ध्यान नहीं रखती है। इस सदन की गरिमा को गिराया जा रहा है। सन् 1952 से, अध्यक्ष महोदय, आप इस सदन के सदस्य रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बोले जा रहे है। माननीय सदस्य।

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय चौधरी साहब बोलते हैं तो मेरा कर्त्तव्य हो जाता है कि मैं बैठ जाऊं। सारी बात सुनता हूं। वह हुक्म दें तो नहीं, लेकिन मैं आपके माध्यम से बैठ सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय, एक प्रकार की हवा बनाई जा रही हैं। वह इस बात को जानते हैं कि इस प्रकार की जानकारी करने के लिए सरकार को कितना समय चाहिए। अगर सरकार की तरफ से कुछ लैप्सेज रहे हैं तो उसके लिए कहा जा सकता है।

दूसरे बात बार-बार खेतड़ी के बारे में कही जा रही है कि उसके बारे में सरकार से सूचना मांगी गई है। स्थगन प्रस्तावों के बारे में कोई भी विभाग हो, उससे सूचना मिलती रहती है।

झुंझुनूं से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 26-2-78 को खेतड़ी नगर में सायंकाल 7 बजे से 10 बजे तक श्री गोपाल जोशी नाम के एक व्यक्ति ने एक 'जूनियर महमूद नाइट' नाम से फिल्म स्टार शो का आयोजन किया। इस आयोजन की स्वीकृति श्री जोशी ने उप-दण्डनायक, खेतड़ी नगर से दिनांक 31-1-78 को प्राप्त की थी।

उस दिन दीनबन्धु टाकीज के बाहर शामियाना लगाकर जूनियर महमूद एवं पार्टी द्वारा कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया जाना था जिसमें करीब 3,400 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था थी। उस रात्रि को करीबन 2,000 व्यक्ति, जिनमें मर्द, औरत और बच्चे शामिल थे, इस शामियाने में बैठे थे। शामियाने के बाहर काफी अधिक भीड़ एकत्रित हो गई। लोगों ने शामियाने में बिना टिकट अन्दर प्रवेश करने की चेष्टा की, परन्तु पुलिस के पूर्ण प्रबन्ध की वजह से वह प्रवेश नहीं पा सके। जिस पर भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। जिससे पुलिस व आर. ए. सी. के मुलाजिमानों को चोटें आईं। इस बीच भीड़ ने लाइट का कनेक्शन काट दिया जिससे प्रोग्राम को बीच में ही रोक देना पड़ा। लाइट का प्रबन्ध करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन लाइट ठीक नहीं हुई। चूंकि भीड़ अधिक थी अतः सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने शामियाना में औरतों व बच्चों को उसी प्रांगण में स्थित दीनबन्धु टाकीज के हॉल में सुरक्षित घुसा दिया। उस समय मौके पर एस.डी.एम., उप-पुलिस अधीक्षक, खेतड़ी, मय एक इन्सपेक्टर, तीन सब-इन्सपेक्टर व करीब 115 जवान आर. ए. सी. के उपस्थित थे। उन्होंने भीड़ को तितर-बितर कर दिया और स्त्रियों व बच्चों को सुरक्षित उनके स्थान पर पहुंचाया। इस पथराव से 4 पुलिस कर्मचारियों के मामूली चोटें आईं। भीड़ जाते समय कुछ कुर्सियां भी अपने साथ ले गई बताई। थाना प्रबन्धक, खेतड़ी नगर ने इस घटना के बारे मे अभियोग संख्या 10 दिनांक 26-2-78 धारा 353/332/336/379 आई.पी.सी. तत्काल पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ कर दिया है। अभी तक मुकदमा अनुसंधानाधीन है। अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

दिनांक 7-3-78 को नवभारत टाइम्स में श्री हरजीत सहगल, फरीदाबाद द्वारा सम्पादक नवभारत टाइम्स के नाम से पत्र में यह प्रकाशित करवाया, कि इस घटना में मां, बेटियों व बहनों की इज्जत लूटी गई तथा घर तक जाने के लिये

( श्री सम्पतराम )

उनके शरीर पर पेटीकोट तक न था तथा कुछ कुंआरी लड़कियां गुम हो गईं जो दूसरे दिन शाम को वापस आईं। इस समाचार पर पर पुलिस ने तफतीश की तो इस प्रकार की कोई घटना घटित होना नहीं पाया गया और ना ही पुलिस में इस प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

श्री शीशराम ओला : यह झूठ और गलत है, मंत्री महोदय। मैं बताना चाहूंगा कि जानबूझकर लाइट ...

श्री अध्यक्ष : इस तरह की चर्चा का तो कोई अन्त नहीं है, माननीय सदस्य आप दो मिनट बोल लें।

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि जानबूझकर 9 बजे लाइट बन्द की गई। डी. एस. पी. और एस. डी. एम. को भी दबोच लिया गया। फिर भी यह कहा गया कि ऐसी चीज नहीं हुई। वहां पर पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं थी, । लड़कियों को घरों तक नंगा जाना पड़ा। वहां पर उनके रिश्तेदार आंख मींचकर खड़े हो गये। इतना गन्दा और गलत तरीके का कार्य शायद आजादी के बाद तीस वर्षों में कभी नहीं हुआ। शायद यह पहला केस है। आपकी रिपोर्ट सही है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो आप दे दीजिये। आप समझिये, यह असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने व्यवस्था को भंग किया और इतना गलत और घृणित कार्य किया। आपने बिना जांच कराये यह जवाब दिया कि पुलिस के पास यह रिपोर्ट आई। वहां से सारा सामान ले गये। तम्बू और कुर्सियां भी नहीं छोड़ी। झुंझुनूं में जन–जीवन का रहना कठिन हो गया है, समाज की मर्यादा टूट गई है इसलिए मेहरबानी करके आप इसकी दुबारा जांच कराइये। अगर मेरी बात गलत होगी तो मैं माफी मांग लूंगा।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा): सारे समाज में राजनीति घुसाते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य जो फर्मा रहे हैं वह भी सही है। माननीय गृह मंत्रीजी ने जो वक्तव्य पढ़ा इससे यह प्रमाणित होता है कि वहां पर अव्यवस्था फैली, बिजली काटी गई। देशबन्धु टाकीज में महिलाओं को इकट्ठा किया गया। वहां पर गड़बड़ हुई और उनको बेइज्जत किया गया। वहां से घसीट कर उनको बाहर लाया गया। उनको पुलिस का या और किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं था। वे भी उनके साथ थे। गृह मंत्रीजी ने कहा कि जांच कराई है। पुलिस ने मौके का मुआयना किया तो पेटीकोट के चिथड़े, चूड़ियां, कानों के रिंग, कपड़े, इस तरह का दस किलो वजन का सामान मिला। आप रिकार्ड में देख लें। जो उन्होंने सामान बरामद किया वह रिकार्ड में नहीं दिखाया गया जब कि दस किलो वजन का सामान बरामद किया गया। इससे यह प्रमाणित होता है जैसा इन्होंने कहा कि स्त्रियां, बच्चों और महिलाओं को देशबन्धु टाकीज में पहुंचाया गया, उनको घर नहीं पहुंचाया गया। हमारी बहन-बेटियों की इज्जत लूटी गई। यह जो काण्ड हुआ, यह रविन्द्र सरोवर काण्ड से भी घृणित है। मैं निवेदन करता हूं कि इसकी जांच करवाई जावे। आप थानेदार और डी. एस. पी. की रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दें, वे खुद वहां मौजूद थे। वहां पर असामाजिक तत्व खड़े हुए थे। इस प्रकार का नंगा नाच हिन्दुस्तान में सरोवर काण्ड, जो कलकत्ता में हुआ था,

(श्री रामनारायण चौधरी)
बाद देखने को, सुनने को और पढ़ने को नहीं मिला ।

श्री मूलचन्द डागा : यह बात सही है, रिकवरी लिस्ट बताती है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, खेतड़ी के प्रसंग में कई माननीय सदस्यों ने जानकारी दी है, गृह मंत्रीजी ने तथ्यात्मक स्टेटमेंट पेश किया है। बहन-बेटियों की इज्जत लूटी जाय इसकी चिन्ता सबको है। बहन-बेटी मेरी हो या किसी की भी हो, अगर इस प्रकार की घटना होती है तो निश्चित ही खेदजनक घटना है। इस घटना के बाद इस प्रकार का वातावरण खेतड़ी में रहा कि किसी व्यक्ति ने इस प्रकार की शिकायत नहीं की। उसके बाद एक मंत्रीजी भी वहां गये। अगर कोई शिकायत होती तो कोई भी निश्चित रूप से शिकायत कर सकते थे। नवभारत टाइम्स में न्यूज लेटर छपा, उसके बाद इस प्रकार की जानकारी मिली है.....

श्री रामनारानण चौधरी : नवज्योति में भी...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसके पहले नहीं थी...

श्री श्योपतसिंह मकासर : कोई भी आया हो, डेपूटेशन या शिष्टमण्डल ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत: कोई नहीं आया। माननीय सदस्यों ने तीन-चार दिन पहले जिस समय जानकारी दी उसके बाद में मैंने आदमी भेजे और जानकारी की। मालूम हुआ कि इस प्रकार की घटना नहीं हुई, महिलाओं की इज्जत नहीं लूटी गई है। मैं आप सबको विश्वास देना चाहता हूं कि महिलाओं की इज्जत लुटे और हम यहां बैठे रहें, इस बात के लिए नहीं बैठे हैं । चूंकि आपने प्रसंग उठाया है इसलिए इस मामले की एडीशनल आई. जी. (सी.आई.डी.), क्राइम्स द्वारा जांच कराई जाएगी। जो प्रतिवेदन आएगा, उसकी आपको जानकारी करा देंगे। शीशरामजी कह रहे हैं कि अमुक महिला को नंगा किया गया। यदि वह नाम बता देंगे तो उन महिलाओं की भी जांच की जाएगी लेकिन इस प्रसंग से ऐसा वातावरण न बनाया जाए जिससे आतंक की स्थिति पैदा हो। हम जांच कराने के लिए तैयार हैं जैसा कि आपने सुझाव दिया। अब एडीशनल आई. जी. जांच करेंगे और जो परिणाम निकलेंगे, जो दोषी होंगे, निश्चित रूप से उन पर ध्यान दिया जाएगा और कार्यवाही की जाएगी ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : रिपोर्ट सदन में पेश की जाए ।

श्री शीशराम ओला : वहां इज्जत के मारे महिलाओं ने रिपोर्ट नहीं कराई, आई. जी. साहब जायेंगे तो मैं स्वयं भी जाऊंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत :एडीशनल आई. जी. आप से भी जांच कर लेंगे, रामनारायण-जी चौधरी से भी जांच कर लेंगे और भी कोई सदस्य..

श्री श्योपतसिंह मकासर : वह रिपोर्ट सदन में पेश होनी चाहिए ।

श्री सुभाषचन्द आर्य (सूरजगढ़) : जहां घटना घटी है, वह मेरा क्षेत्र हैं और मुझे जानकारी है। शीशरामजी जो कहते है वह सहा गलत कहते हैं। ये कहते हैं कि बहन-

(श्री सुभाषचन्द आर्य)
बेटियों की इज्जत लूटी गई है यह बिल्कुल गलत है ।......

(व्यवधान)

मुख्य मंत्री महोदय, हमारी बहन बेटियां......

(व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि जो वे कहते हैं यह सही हो और मेरी बात गलत हो तो मैं त्याग-पत्र दे दूंगा ।

श्री सुभाषचन्द्र आर्य : श्री शीशरामजी के खुद के गांव अरडावता के छात्रावास में रहने वाली अध्यापिकाओं के साथ अन्याय हो रहा है। उनको समय पर वेतन नहीं मिलता है और उन्हें बार-बार परेशान किया जा रहा है जिसकी तत्काल जांच कराई जावे ।

(व्यवधान)

सारी बातें झूठी हैं ।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य । आय-व्ययक..

(व्यवधान)

अब चर्चा नहीं होगी। स्थान ग्रहण करें ।

श्री शीशराम ओला : जो मुझ पर आरोप लगाए हैं उन्होंने, वह गलत तरीके से...

श्री अध्यक्षः इन आरोपों और प्रत्यारोपों का अंत नहीं आएगा। आपके पक्ष की बातें सुनीं । अन्य माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा उसको भी सुन लिया जाय ।

श्री शीशराम ओला: मेरे पर व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं ।

श्री मालाराम (खेतड़ी): जो खेतड़ी में घटना घटी है, आई. जी. (एन्टी करप्शन) को सारी बात बता दूं । वहां किसी आदमी ने यह रिपोर्ट नहीं दी कि हमारी बेइज्जती हुई है। किसी की कड़ी कटी है बाकी किसी की बेइज्जती नहीं हुई ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आखिर इसका कोई अंत भी होगा ?

श्री दुलाराम (रायसिहनगर) : मैंने बीकानेर की चर्चा सदन में उठाई थी। मुझे खेद है....

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें । यह कोई विषय नहीं है।

श्री दुलाराम : कोई जवाब नहीं आया । यह राष्ट्र का अपमान है। हम जिनको नेता मानते हैं, उनकी मूर्ति का चश्मा तोड़ा है। आप इसका जवाब आज तक नहीं दे सके । यह सारे देश के लिए कलंक की बात है। एक राष्ट्र के नेता का अपमान हुआ है, उसके बाद जुलूस निकले हैं । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस विषय पर आप आज ही जवाब दें । वह हरिजन नेता हैं। गृह मंत्री इस पर अपनी रिपोर्ट दें ।

श्री सम्पतराम ( गृह मंत्री) : यह प्रश्न पहले भी आया था । जब यह प्रश्न आया था तो मैंने एस.पी. को इस बारे में टेलीफोन किया था कि आप जांच करायें । अब नियमा-

(श्री सम्पतराम)
नुसार जांच के ग्रादेश में कर देता हूं। जो जांच के नतीजे ग्रायेंगे, वे बता दूंगा।

श्री दुलाराम : मुझे दुःख है, ग्रादेश ग्रब देंगे। ग्रब ग्रादेश देंगे कि नियमानुसार कार्यवाही की जाए। राष्ट्र के नेता का अपमान हुग्रा इतने दिन पहले ग्रौर ग्राप ग्राज ग्रादेश देंगे ग्रौर ग्रब एस.पी. कार्यवाही करेंगे? वहां एस. पी., डी. वाई.एस.पी. मौजूद हैं, कोतवाली इन्चार्ज मौजूद हैं, कितने दुःख की बात है, लज्जा की बात है कि गृह मंत्री ग्राज ग्रादेश देंगे।

एक माननीय सदस्य : जो ग्रकाल राहत कार्य चालू हुए हैं उसमें लोग काम के लिए इंतजार कर रहे हैं, किन्तु सरकार से जवाब नहीं ग्राता। कई लोग भूखे मर रहे हैं। मजदूर इसी इंतजार में बैठे हैं कि उनके पास दूसरा काम ग्रा जाए।

श्री दुलाराम : वे भूखे मर रहे हैं। कम से कम गृह मंत्री उनके खाने की व्यवस्था करें, यह घोषणा कर दें।

एक माननीय सदस्य : पी.डब्ल्यू.डी. के ग्रधिकारी पक्षपात कर रहे हैं। मजदूरों के ऊपर भयंकर ग्रत्याचार किया जा रहा है। मजदूर भूखे मर रहे हैं, ग्राप तुरंत कलेक्टर को आदेश दें।

श्री रामकरण सिंह : ग्राज नवज्योति में समाचार ग्राया है। 6-7 दिन पहले मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था कि सुगम शिक्षा समिति के ग्रध्यापक, जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, को पीटा गया है, मारा गया है। वह मान्यता प्राप्त स्कूल है। ग्रध्यक्ष के ग्रादेशों को नहीं मान रहे हैं, ग्रराजकता फैल रही है। सिविल लाइन्स में कांड हुग्रा जहां मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्यपाल ग्रौर ग्राप जैसे सज्जन रहते हैं। यह ग्रराजकता का प्रतीक है। इस तरह की ग्रराजकता सिविल लाइन्स में हुई, जीप में गुंडे गये ग्रौर ग्रध्यापकों को मारा, यह सब ग्राज नवज्योति ग्रखबार में ग्राया है। इससे पहले मैंने स्थगन प्रस्ताव भी दिया। ग्रध्यक्ष महोदय, वहां पर लोगों को पीटा गया है। जो व्यक्ति स्कूल चलाता है वह इतना कलाकार हो सकता है ग्रौर इस तरह की हरकतें कर सकता है, ग्रध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही ग्रशोभनीय ग्रौर शर्मनाक है। ग्रगर इन लोगों की इस तरह की हरकतों को नहीं रोका गया तो, ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रराजकता फैल जायगी। इस तरह नग्न ग्रौर ग्रर्ध-नग्न घटनायें हो रहीं हैं इनको तुरन्त रोका जाना चाहिये। ग्रगर इनको नहीं रोका गया तो ग्रराजकता फैल जायेगी।

### मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य ग्रौर सफाई व 2 मंत्री परिषद की प्रस्तुति

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राय-व्यय बजट। माननीय श्री त्रिलोकचन्द जैन !

श्री त्रिलोकचन्द जैन (चिकित्सा मंत्री): ग्रध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य ग्रौर सफाई के संबंध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 46,40,06,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री महबूब ग्रली !

श्री महबूब ग्रली (राज्य मंत्री, जन सम्पर्क): ग्रध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

S.O.



(श्री महबूब अली)
मांग संख्या 2 मंत्री परिषद के संबंध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 38,20,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ।

श्री मूलचन्द डागा : यह सारा नॉन प्लान एक्सपेन्डीचर है ।

मांग संख्या पर 26 व 2 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय-

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशन पोल, जयपुर) व श्री बजरंग लाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर):

1. जयपुर नगर में नया महिला और जिला अस्पताल अभी तक न खोले जाने पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण), श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) व श्री ओम प्रकाश शर्मा (बून्दी):

2. परिवार नियोजनार्थ गंदे साहित्य के वितरण तथा गंदे पोस्टर्स लगाये जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

3. परिवार नियोजन के कारण उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये ।

4. ग्रामों में चिकित्सा क्षेत्र में सरकार की असफलता से हुई कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

5. रोगों के बचाव और नियन्त्रण करने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली):

6. कोटपूतली क्षेत्र के लिये चिकित्सा विभाग पूरी लापरवाही बरत रहा है, जिसकी वजह से काफी असंतोष है, इस पर चर्चा के लिये ।

7. स्वास्थ्य संस्थाओं में दवाइयों, सामान की कमी पर विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इस पर चर्चा के लिये ।

8. कोटपूतली क्षेत्र में रोगियों को लाने वाले जाने की विभाग द्वारा लापरवाही की जा रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

9. तहसील कोटपूतली में पावटा प्रागपुरा में डिस्पेंसरी को अस्पताल बनाने में विभाग की उपेक्षा पर चर्चा के लिये ।

10. सवाई मानसिंह अस्पताल में रोगियों के साथ डॉक्टरों द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने पर चर्चा के लिये ।

11. प्रस्तावित डिस्पेंसरी व एडपोस्ट आज तक भी नहीं खोले गये, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

12. माली पंचायत समिति, माण्डल में डिस्पेंसरी खुलवाने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) :

13. आबू रोड व भीनमाल में रेफरल अस्पताल बनाए जाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) :

14. बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए नए तरीके अपनाने हेतु चर्चा के लिये ।

15. संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु नए साधन जुटाने की चर्चा के लिये ।

16. अस्पतालों में बीमारों की तादाद के हिसाब से दवाइयां उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

17. मकराना में मरीजों की तादाद के मुताबिक सर्जीकल सामान व सर्जन लगाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) व श्री विजयसिंह नदेरा (बांदीकुई) :

18. दौसा-बांदीकुई अस्पताल को रेफरल अस्पताल बनाने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

19. जोधपुर जिले के गांवों की दूरी ज्यादा होने से प्रत्येक गांव में चिकित्सा व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये ।

20. जोधपुर जिले में बारह ही मास मच्छरों के कारण हुई गांवों में बीमारी की रोकथाम हेतु चर्चा के लिये ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

21. ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा की कमी के संबंध में चर्चा के लिय ।

22. ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सालयों में दवाइयों की कमी के संबंध में चर्चा के लिय ।

23. जालसू नामक आयुर्वेद चिकित्सालय को वहां से हटा कर जालसू स्टेशन पर स्थानान्तरित कर देने के संबंध में चर्चा के लिये ।

24. जाखेड़ा, तहसील डेगाना के आयुर्वेद चिकित्सालय को 'ए' श्रेणी में बदलने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री रामदेव चौधरी (मूण्डवा) :

25. नागौर चिकित्सालय को अपग्रेड करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

26. नागौर जिला चिकित्सालय में महिला चिकित्सक की कमी के संबंध में चर्चा के लिये ।

27. ग्रामीण चिकित्सालयों में दवाओं की कमी पर चर्चा के लिये ।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) :

28. चिकित्सा निदेशालय में फैले हुए कुप्रबन्ध के बारे में चर्चा के लिये ।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

29. पंचायत के हर हैडक्वार्टर पर चिकित्सा सुविधा दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

30. धामनिया में वर्षों से जनता ने चिकित्सालय का भवन बना लिया है सो चिकित्सा सुविधा देने बाबत चर्चा के लिये ।

31. गुढ़ा बिजोलिया में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने बाबत चर्चा के लिये ।

(श्री रामकरण सिंह)

32. मेडिकल रिएम्बर्समेन्ट विधायकों सहित सब ही राज्य कर्मचारियों का बन्द कर दिया जाय, ताकि ग्रामीणों को दवा मिल सके, इस पर चर्चा के लिये।

33. विधायकों को मेडिकल सुविधा ग्राम जनता की तरह ही मिलनी चाहिये और मेडिकल रिएम्बर्समेन्ट नहीं होना चाहिये, इस पर चर्चा के लिये।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) :

34. चिकित्सालय, भीम को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. बरार एवं देवगढ़ प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. बारह हजार की आबादी वाले देवगढ़ नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को शीघ्र रेफरल अस्पताल के रूप में क्रमोन्नत किया जाय, इस पर चर्चा के लिये।

37. उपखण्ड, भीम के केन्द्र में स्थित अस्पताल में शीघ्र महिला चिकित्सक की सेवा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. कुआथल व बार गांवों में अस्पताल तथा इसरमंड व बगड़ गांवों में एडपोस्ट स्थापित करने के जिला प्रशासन के प्रस्तावों की क्रियान्विति पर चर्चा के लिये।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) :

39. जोधपुर में अस्पतालों की व्यवस्था ठीक कराने पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

40. बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में राजकीय अस्पताल में विभाग द्वारा रोगियों के लिये तुरन्त नई एम्बुलेन्स गाड़ी की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. बाड़मेर जिले में टी. बी. के रोगियों की संख्या अधिक होते हुए और एक दानदाता द्वारा 75,000 रुपये की राशि टी. बी. अस्पताल के भवन निर्माण में योगदान देने के उपरान्त भी राज्य सरकार द्वारा भवन निर्माण की स्वीकृति दिलाने में उदासीनता बरते जाने के विषय पर चर्चा के लिये।

42. बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में 100 रोगी शैय्याओं को बढ़ा कर 150 रोगी शैय्याएं कराने पर चर्चा के लिये।

43. राजस्थान प्रान्त के राजकीय अस्पतालों, शहरों, कस्बों में जहां भी स्थापित हैं, में कोटेज वार्डों के किराये की एक समान रूप से 20 रुपये दर होने से कस्बों की जनता कोटेज वार्डों का लाभ नहीं उठा सकती, अतः असंतोष व्याप्त है. इस पर चर्चा के लिये।

44. फर्जी मेडिकल बिल की रिएम्बर्समेन्ट प्रवृत्ति को रोकने में चिकित्सा विभाग द्वारा नवीन प्रणाली अपनाये जाने पर चर्चा के लिये।

45. बाड़मेर जिले के राजकीय अस्पताल, बाड़मेर एवं जिले के विभिन्न

(श्री वृद्धिचंन्द जैन)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप-केन्द्रों में औषध निरीक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक, रेडियोलोजिस्ट, लेब0 टेक्निशियन, मेकेनिक, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, डेन्टल टेक्निशियन, पोस्ट ग्रेजुएट पेथोलोजी, मेल नर्स प्रथम, मेल नर्स द्वितीय, वरिष्ठ लिपिक, टीकाकार, प्रसविका, वाहन चालक के कई पद काफी अर्से से रिक्त होने के कारण जिले के प्राथमिक एवं स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों का प्रबन्ध सुचारु रूप से नहीं होने के कारण जिले की जनता में गहरा असन्तोष है, इस विषय पर चर्चा के लिये ।

46. विभाग द्वारा बाड़मेर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उपकेन्द्रों में स्टाफ के लिये मकान की पर्याप्त व्यवस्था न कराने के विषय पर चर्चा के लिये ।

47. ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में सरकार द्वारा घोर उपेक्षा किये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये ।

48. एम्बुलेन्स गाड़ियों के किराये की दर बड़े शहर और कस्बों (टाउन्स) में एक समान है जो उचित नहीं है, अतः उचित एवं न्यायप्रद किराया तय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

49. बाड़मेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने में विभाग द्वारा उदासीनता की नीति अपनाने के विषय पर चर्चा के लिये ।

50. बाड़मेर जिले के कवास, बाटाडू एवं बैसाला ग्राम में डिस्पेंसरी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हरजी राम बुरड़क (लाडनूं) :

51. पर्याप्त संख्या में औषधालय नहीं खोलने पर चर्चा के लिये ।

श्री भैरव लाल कालाबादल (खानपुर) :

52. चिकित्सालय खानपुर में दवाओं के अभाव एवं बाहर से आने वाले मरीजों के लिए पर्याप्त बिस्तरों के अभाव पर चर्चा के लिये ।

53. चिकित्सा सुविधा न होने से ग्राम खंडी और नूरजगाड़र वाड़ा में कम्पलीट डिस्पेंसरी खोले जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री अजीतसिंह (टोंक) :

54. बीमा योजना चिकित्सा सेवा में सुधार करने के संबंध में अधिक धन प्राप्त कर मजदूरों को राहत दिलाने बाबत चर्चा के लिये ।

55. टोंक पंचायत समिति में 2 डिस्पेंसरी व 2 एडपोस्ट खुलवाने बाबत चर्चा के लिये ।

56. घटिया व नकली दवाइयाँ बेचने व रखने वालों को पकड़ने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये ।

57. टोंक सहादत होस्पिटल में दवाइयों की उचित व्यवस्था व स्थान के अभाव पर चर्चा के लिये ।

(श्री अजीतसिंह)

58. मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री माधोसिंह (रेवदर):

59. रेवदर विधान सभा क्षेत्र को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से उपेक्षित रखने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) :

60. राज्य सरकार की निर्धारित नीति से जहां कम डिस्पेंसरी व एडपोस्ट हैं, वहां डिस्पेंसरी व एडपोस्ट शीघ्र खुलवाने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री नारायण सिंह (मालपुरा) :

61. राज्य में चिकित्सा सुविधा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री रतना राम चौधरी (रानीवाड़ा) :

62. गांवों में दस-दस माइल पर स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोले जावें तथा पूरी दवाइयों की सप्लाई की जावे इस पर चर्चा के लिये ।

63. स्वास्थ्य उपकेन्द्र व प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में दवाइयों की भारी कमी है, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) :

64. भरतपुर जिले में चिकित्सा का अभाव, अस्पतालों की दयनीय दशा एवं उपकरणों की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) :

65. गत सरकार द्वारा मंजूरशुदा डिस्पेंसरी व फर्स्ट-एड सैन्टर न खोलने पर चर्चा के लिये ।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) :

66. पिड़ावा में पिछले 10 माह से डाक्टर की व्यवस्था न होने बाबत चर्चा के लिये ।

67. चिकित्सा सुविधा एवं उपकरण तथा दवाइयां उचित रूप में उपलब्ध न होने की चर्चा के लिये ।

68. पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में एक्स-रे की मशीन व अस्पतालों के अभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

69. ग्राम सिरफोई, तहसील पिड़ावा में चिकित्सालय निर्माण कराने में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

70. डाक्टरों के भौतिकवादी रवैये एवं ग्रामोन्मुख न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

71. भैवानी मंडी में रेफरल अस्पताल की मंजूरी न दी जाने के कारणों की चर्चा के लिये ।

72. हरिजनों को विशेष चिकित्सा सुविधा देने की विभाग द्वारा योजना नहीं बनाने पर चर्चा के लिये ।

73. राजकीय चिकित्सालय, पिड़ावा में अतिरिक्त शैय्याएं एवं भवन विस्तार न करने की चर्चा के लिये ।

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) :

74. देश के 40 प्रतिशत बालकों के स्वास्थ्य को उचित व्यवस्था नहीं है, इस पर चर्चा के लिये ।

75. ग्रामीण महिलाओं के लिये प्रसूति गृहों के अभाव पर चर्चा के लिये ।

76. संक्रामक रोगों की रोकथाम के वास्ते पिछड़े ग्रामों के बालक एवं महिलाओं के वास्ते सेनेटोरियम एवं उचित दवा वितरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

77. ग्रामीण, पिछड़े, वनवासी, गिरिवासी, ट्राइवल क्षेत्र शाहाबाद-किशनगंज में स्वास्थ्य सेवाओं की नितान्त कमी एवं मोबाइल यूनिट एवं सर्जीकल कैम्प्स और आई कैम्प्स की व्यवस्था हेतु चर्चा के लिये ।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) :

78. राजस्थान के गांवों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में भेदभाव पर चर्चा के लिये ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :

79. जिला जालोर में चिकित्सा सुविधाओं के बारे में एवं चिकित्सालयों में पर्याप्त स्टाफ शीघ्र तैनात करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

80. स्वास्थ्य केन्द्रों पर व उप-स्वास्थ्य केन्द्रों पर पूरे स्टाफ न होने बावत चर्चा के लिये ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

81. बालेसर (जिला जोधपुर) में रेफरल हास्पिटल खोलने बाबत तथा पंचायत समिति, बालेसर में व सेखाले में डिस्पेंसरी खोलने की चर्चा के लिये ।

श्री राम नारायण चौधरी (मण्डावा) :

82. ग्राम लादूसर पंचायत समिति, अलसीसर में एडपोस्ट डिस्पेंसरी खोले जाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री सूरज पाल सिंह (भीनमाल) :

83. भीनमाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को रेफरल अस्पताल के रूप में क्रमोन्नत करने बाबत चर्चा के लिये ।

84. ग्राम जुझाणी में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने हेतु चर्चा के लिये ।

85. भीनमाल तहसील के ग्राम बाली में चिकित्सा स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने बाबत चर्चा के लिये ।

86. भीनमाल तहसील के ग्राम दासपां में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा डिस्पेंसरी खोलने बाबत चर्चा के लिये ।

87. ग्राम तिलोड़ी में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने बाबत चर्चा के लिये ।

88. ग्राम मेघलवा, तहसील जालोर में चिकित्सा उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री रघुनंदन व्यास (सिरोही) :

89. सिरोही जिले में फूंगनी गांव में आयुर्वेदिक औषधालय की स्थापना कराने हेतु चर्चा के लिये ।

(श्री रघुनन्दन व्यास)

90. सिरोही अस्पताल में सफाई के अभाव में फैल रही बीमारी की चर्चा हेतु ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) :

91. चिकित्सा निदेशालय में फैले भ्रष्टाचार, अनियमितताओं व गलत स्थानान्तरण के बारे में चर्चा के लिये ।

श्री उगमराम मेहता (ब्यावर) :

92. ब्यावर क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये चर्चा के लिये ।

श्री करतार सिंह (किशनगढ़) :

93. किशनगढ़ की पर्याप्त जनसंख्या को देखते हुए यज्ञनारायण अस्पताल को क्रमोन्नत करने के बारे में चर्चा के लिये ।

94. किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के फलस्वरूप व्याप्त जन-असंतोष पर चर्चा के लिये ।

95. रूपनगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को रेफरल अस्पताल बनाये जाने के बारे में चर्चा के लिये ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर):

96. तहसील सांचोर में अपर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था एवं चिकित्सालयों के भवनों की मरम्मत कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

97. ग्रामीण क्षेत्रों में जिला जालौर में संक्रामक रोगों की रोकथाम के बारे में सरकार की घोर उपेक्षा की चर्चा के लिये ।

श्री समरथ लाल (राजगढ़) :

98. राजस्थान राज्य के घनी आबादी वाले एरियाज में आयुर्वेदिक औषधालय एवं डिस्पेन्सरियों के अत्यन्त अभाव के क्रम में चर्चा के लिये ।

श्री हरलाल सिंह खर्रा (सीकर) :

99. ग्राम सिहोडी में पच्चीस हजार की लागत से चिकित्सा भवन बनाने पर भी वहां एड-पोस्ट नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

100. ग्राम जयतुसर, जिला सीकर की आबादी 6 हजार से भी अधिक होने पर भी चिकित्सा सुविधा नहीं होने से जनता की परेशानी पर चर्चा के लिये ।

101. ग्राम नाथुसर नागल, जिला सीकर की आबादी 6 हजार से अधिक होने पर भी वहां चिकित्सा सुविधा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

102. ग्राम झाडली, जिला सीकर की आबादी करीब दस हजार के होते हुए भी चिकित्सा सुविधा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

103. ग्राम महरौली, जिला सीकर में भू. पू. सरकार द्वारा डिस्पेन्सरी खोलने पर भी आज तक डिस्पेन्सरी चालू नहीं करने से, जबकि ग्रामवासियों द्वारा भवन भी बना दिया गया है, उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

# Page No 65

(65)



श्री समरथ लाल (राजगढ़) :

104. राजगढ़ (अलवर) अस्पताल में बेड्स बढ़ाये जावें, इस पर चर्चा के लिये।

105. राजगढ़ (अलवर) अस्पताल की एक्स-रे की मशीन पिछले 6-7 साल से खराब पड़ी हुई है उसे ठीक कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

106. नीमला, बखेरी, भूड़ा, परवंण, आदि ग्रामों में आयुर्वेदिक औषधालय एवं डिस्पेन्सरी खुलाने हेतु चर्चा के लिये।

107. एम. बी., बी. एस. डाक्टरों को राजस्थान राज्य में समुचित स्थान न मिलने पर, राज्य के खर्च पर अन्य राज्यों में जाकर नौकरी की तलाश करने के क्रम में चर्चा के लिये।

108. ग्राम बकेली (अलवर) में आयुर्वेदिक औषधालय खुलाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भंवर लाल पेरा (नसीराबाद) :

109. नसीराबाद नगर के राजकीय चिकित्सालय को बी श्रेणी के चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाकर वहां एक दाईखाना अविलम्ब खोले जाने हेतु चर्चा के लिये।

110. नसीराबाद क्षेत्र के कम से कम इस वर्ष दस अन्य ग्रामों में यथा बाघसुरी, लामाना, गोवा, प्यारा, झड़वासा, बोरखाड़ा डाल, कानपुरा, लीडी, नायू कलां में चिकित्सालय खोले जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर-पश्चिम) :

111. पालबिचला और गढ़ी (जोन्स गंज) में संक्रामक रोगों की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) :

112. ग्रामीण चिकित्सा योजना के प्रभाव-मेडिकल कालेजों में चिकित्सा स्तर के ह्रास पर चर्चा के लिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

113. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सोमेसर (जोधपुर) में स्टाफ क्वार्टर न होने से स्टाफ की कमी रहने बाबत चर्चा के लिये।

114. सुदूर लगे डाक्टरों को दो वर्ष बाद अच्छे स्थानों पर लगाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

115. बैमाली में डिस्पेन्सरी प्रारंभ कराने बाबत चर्चा के लिये।

116. शिवपुर व ऊमरी में एडवोस्ट जिसकी स्वीकृति पहले हो गई थी प्रारंभ कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जमवारामगढ़) :

117. जमवारामगढ़ की चिकित्सा की दृष्टि से उपेक्षा करने तथा ग्रामीण चिकित्सा विकास हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरीशकुमार शर्मा (रामगंजमंडी) :

118. तहसील लाडपुरा एवं रामगंज-मंडी क्षेत्र में चिकित्सालय की व्यवस्था नहीं के बराबर है और कई गांवों में सफाई नहीं है, गंदगी भरी है आदि पर चर्चा के लिये।

श्री एच.एन. शर्मा (डेग) :

119. डॉक्टरों को उचित भवन व्यवस्था की सुविधा, हर डिस्पेन्सरी तथा रेफरल अस्पताल में कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :

120. राजकीय अनुदान का संस्थाओं द्वारा परिवार नियोजन के नाम पर गबन किया गया, उस पर चर्चा के लिये।

121. उदयपुर के से. 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 गोवर्धन विलास, सवीना आदि में डिस्पेन्सरी नहीं होने से उत्पन्न कठिनाई के बारे में चर्चा के लिये।

122. चिकित्सा भत्ता वेतन के साथ जोड़ देने के संबंध में चर्चा के लिये।

123. टी.बी. हॉस्पिटल में बाहर से आने वाले मरीजों के संबंधियों के ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर-पूर्व) :

124. अजमेर नगर में चिकित्सा सुविधा के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा) :

125. वर्तमान बजट में बूंदी जिले की अवहेलना करने तथा नैनवारदेई में लेडी डॉक्टर एवं अन्य डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

126. केशवराय पाटन, लाखेरी, कापरेन में महिला चिकित्सक की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये।

127. केशवराय पाटन में ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र स्थापित कराने हेतु चर्चा के लिये।

128. ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा, आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा का ह्रास, चिकित्सालय में मरीजों के साथ भेद-भाव बरतने पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

129. जोधपुर जिले के गांव बिसलपुर में मेडीकल डिस्पेन्सरी नहीं होने से जनता को होने वाली परेशानी पर चर्चा के लिये।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) :

130. जोधपुर के अस्पतालों में दवाइयों के दुरुपयोग, सफाई की अवहेलना और डॉक्टरों के समय पर नहीं आने से उत्पन्न बीमारों की समस्याओं पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (नोहर) :

131. चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार तथा सुधार हेतु चर्चा के लिये।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहरथाना) :

132. चिकित्सालयों में डॉक्टरों की कमी, औषधियों के अभाव एवं नर्सों की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री टीकमचन्द कान्त (जालोर) :

133. जालोर विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) :

134. हाड़ोती क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं को विशेषकर महिला चिकित्सकों की सुविधा बढ़ाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनूं) :

135. मलेरिया की रोकथाम एवं डी.डी.टी. छिड़कने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

136. अस्पतालों में छोटी से छोटी आवश्यक दवाइयों की उपलब्धि न होने पर चर्चा के लिये।

श्री रावतराम आर्य (डग) :

137. प्रत्येक पंचायत केन्द्र पर आयुर्वेदिक औषधालय खोलने बाबत चर्चा के लिये।

138. गांवों में प्रशिक्षित दाइयों की नियुक्ति कराने बाबत चर्चा के लिये।

139. गांव सालासर में मेडीकल डिस्पेन्सरी खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

140. सांडवा, छापर, चूरू अस्पतालों में दवाइयों की कमी, डाक्टरों व अन्य कर्मचारियों का मरीजों के साथ दुर्व्यवहार एवं अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) :

141. राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सालय खोलने में प्राथमिकता दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

142. चिकित्सालयों में गरीबों के लिये मुफ्त दवाइयों की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री श्रवण लाल (हिण्डौन) :

143. ग्रामीण जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में सरकार की लापरवाही पर चर्चा के लिये।

144. ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य डॉक्टरों एवं अन्य कर्मचारी उपलब्ध नहीं कराये जाने में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिये।

श्री नरपतराम बरवड़ (सुरसागर) :

145. सुरसागर क्षेत्र में चिकित्सा के भयंकर अभाव को पूरा करवाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) :

146. नवलगढ़ की डिस्पेन्सरी में मरीजों की संख्या को देखते हुए विस्तार किये जाने पर चर्चा के लिये।

147. झुन्झुनूं के जेतान अस्पताल में व्याप्त अनियमितता व हो रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

148. मुकुन्दगढ़ सरकारी डिस्पेन्सरी में एक्स-रे मशीन चालू करवाने पर चर्चा के लिये।

149. परशुरामपुरा, जिला झुन्झुनूं में डिस्पेन्सरी को चालू कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी (मावली) :

150. ईन्टाली में डिस्पेन्सरी नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल, जयपुर) :

151. जयपुर नगर में बालकों के लिए

# Page No 68

(68)



(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
अलग से अस्पताल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :

152. खाद्य सामग्री में मिलावट रोकने के लिये कोई कदम नहीं उठाने पर चर्चा के लिये।

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम) :

153. सवाई माधोपुर जिले में चिकित्सा की सुविधाओं की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री हरचन्दसिंह (पीलीबंगा) :

154. लिखमीसर में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोला जावे व ढाबा जाखड़ वाली ऐटा भोपालपुरा में एडपोस्टें खोली जायें, इस पर चर्चा के लिये।

श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर) :

155. आज भी कुम्हेर क्षेत्र में एक प्राइमरी हेल्थ सेन्टर तथा एक डिस्पेन्सरी है, आयुर्वेद औषधालय तथा स्वास्थ्य केन्द्र भी बहुत कम है, बाढ़ के दिनों कई-कई माह तक चिकित्सा सहायता न मिलने से बड़ी जन-हानि उठानी पड़ती है, अतः इस क्षेत्र में विशेष चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

156. नोनेरा, बिनायका, जलोदा खातियान, जलोदा तेजाजी, चाणदा खुर्द तथा केशोपुरा एवं छापोल में चिकित्सालय खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

157. पीपल्दा क्षेत्र के इन्द्रगढ़, खातोली तथा मांगरोल में जच्चाखाना खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

158. अस्पतालों में दवाओं, बैड्स तथा आवश्यक औजार अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

159. पीपल्दा क्षेत्र के इटावा, इन्द्रगढ़, मांगरोल तथा खातोली अस्पताल में लेडी डॉक्टर की आवश्यकता की चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) :

160. बांसवाड़ा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व डिस्पेन्सरियों में डॉक्टरों के अभाव पर चर्चा के लिये।

161. बांसवाड़ा जिला में चिकित्सा विभाग द्वारा जिले के कुओं में दवाई न डालने तथा दवाखानों में गरीब को मुफ्त दवा नहीं देने बाबत चर्चा के लिये।

162. बांसवाड़ा जिले में गढ़ी पंचायत समिति में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित बाल विकास परियोजना में शिशु विशेषज्ञ (डॉक्टर) की नियुक्ति नहीं होने पर चर्चा के लिये।

163. बांसवाड़ा जिले के आयुर्वेदिक औषधालयों में समय-समय पर औषधियां नहीं पहुंचने व स्वीकृत बजट से कम पहुंचने पर चर्चा के लिये।

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) :

164. दांता ग्राम में स्टाफ भेजने, दांता में लेडी डॉक्टर लगाने, डांसरोली में नई डिस्पेन्सरी खुलवाने तथा दांता में 'सी' क्लास हॉस्पिटल बनाने हेतु चर्चा लिये।

# Page No 69

(69)



श्री जगदीशसिंह (धौलपुर) :

165. बाड़ी (धौलपुर) में 30 बैडस हॉस्पिटल की स्वीकृति दी जावे व धौलपुर क्षेत्र में अस्पताल खोले जावें, इस पर चर्चा के लिये।

श्री कोमल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :

166. एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक औषधालयों में नर्स की व्यवस्था न होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

167. एलोपैथी तथा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में वेतनमानों की असमानता दूर करने हेतु चर्चा के लिये।

डॉ. गंगासहाय (कठूमर) :

168. जिला आयुर्वेदिक कार्यालय में सुयोग्य स्टॉफ की कमी के कारण होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

169. एलोपैथी, होमियोपैथी एवं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों के वेतनमान में अन्तर से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री रंगजी (सपोटरा),

श्री उमरावसिंह गूजर (महुवा) :

170. करणपुर, लांगड़ा तथा कुड़गांव में स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराने में सरकार की शिथिलता पर चर्चा के लिये।

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) :

171. लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में राजकीय डिस्पेन्सरी तथा औषधालय खोलने की असफलता पर चर्चा के लिये।

172. गांवों में मलेरिया के उन्मूलन पर सरकारी योजनाओं की असफलता पर चर्चा के लिये।

173. गांवों में डी. डी. टी. के छिड़काव में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवराज सिंह (बस्सी):

174 तहसील बस्सी व चाकसू के चिकित्सालयों में दवाइयों के अभाव व नये चिकित्सालय खोलने की व्यवस्था करवाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री बत्तीलाल मीना (टोडाभीम),

श्री कुंजीलाल (बामनवास):

175. बामनवास एवं टोडाभीम विधान सभा क्षेत्रों में चिकित्सालय सम्बन्धी सुविधाओं की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री शीशराम ओला (पिलानी) :

176. ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था करने में सरकार की उदासीनता की चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) :

17 चिकित्सा सस्ती, सुलभ, समुचित और प्रमोन्मुखी तथा दरिद्रों को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री निर्मलकुमार सकलेचा (झालरापाटन):

178. झालावाड़ जिले के प्रति चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये पर चर्चा के लिये।

# Page No 70

(70)



श्री गोपाल सिंह (खण्डेला),

श्री हरिसिंह (फुलेरा)

श्री गुलचन्द्र कासलिया (दौसा),

श्री अयूब खां (तिजारा),

श्री जीतमल जैन (अलवर):

179. राज्य के अस्पतालों में नॉर्म के अनुसार नर्सों की संख्या कम होने पर चर्चा के लिये।

180. अलवर के जनरल हॉस्पिटल को 'ए' श्रेणी का अस्पताल घोषित किया जावे, इस पर चर्चा के लिये।

श्री उमराव सिंह गूजर (महुवा),

श्री रंगजी (सपोटरा):

181. ग्राम महुवा के तहसील हैड-क्वार्टर में 20 बैड्स का अस्पताल खोलने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल शर्मा (डूंगरगढ़):

182. चिकित्सा व्यवस्था में सुधार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अचलाराम (बेसूरी):

183. मारवाड़ ग्राम में चिकित्सालय की स्वीकृति हेतु तथा सादड़ी मारवाड़ के अस्पताल को क्रमोन्नत करने व रानी स्टेशन पर जनाना अस्पताल खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रतनगढ़):

184. चूरू जिले के चिकित्सालयों में डॉक्टरों के अभाव एवं इनमें व्याप्त अव्यवस्था तथा रोगी शय्याओं में वृद्धि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

185. मेडिकल डायरेक्टोरेट में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के सम्बंध में चर्चा के लिये।

186. चिकित्सा व्यवस्था में सुधार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाऊलाल जोशी (दीगोद):

187. रसायन शालाओं में [illegible] की जाने वाली औषधियों में हुई अनिय[illegible]तता पर एवं आयुर्वेद अनुसंधान शाला में कोई अनुसंधान नहीं हुआ, इसकी समुचित व्यवस्था करने के संबन्ध में चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार):

188. सवाई माधोपुर तथा खण्डार क्षेत्रों के अस्पतालों को पुरुष डॉक्टर एवं महिला डॉक्टरों की कमी एवं अकस्मात निरीक्षण के अभाव में बीमारों के प्रति लापरवाही तथा औषधियों की कमी की चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह यादव (बानसूर):

189. राजस्थान की ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध [illegible] के लिये योजना के विषय में चर्चा के लिये।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला),

श्री अयूब खां (तिजारा),

श्री हरिसिंह (फुलेरा),

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

190. राज्य के चिकित्सालयों में मुफ्त दवा रोगियों को नहीं मिल पाने पर चर्चा के लिये ।

श्री हजारीमल सारण (सरदारशहर) :

191. चिकित्सा सेवाओं के विस्तार एवं सुधार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) :

192. चिकित्सा की समुचित व्यवस्था के अभाव पर चर्चा के लिये ।

193. चिकित्सा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं धांधली पर चर्चा के लिये ।

194. संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु समुचित व्यवस्था और सही परिकल्पना के अभाव पर चर्चा के लिये ।

श्री बालकृष्ण थानवी (फलोदी) :

195. फलोदी तहसील के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में समुचित रूप से चिकित्सा की व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन) :

196. कपासन तहसील में चिकित्सा की समुचित व्यवस्था करने हेतु तथा गिरवा तहसील में चिकित्सा सुविधा प्राप्त कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री बालचन्द्र मार्ग (डग) :

197. गांव वालों को चिकित्सा को परेशानी आती है वहां व्यवस्था करने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री नाथूराम (बागीदौरा) :

198. चिकित्सा विभाग की भवन निर्माण की नीति को शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तित कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बड़ी सादड़ी) :

199. चित्तौड़गढ़ रेफरल अस्पताल को क्रमोन्नत कर 150 बैड्स की स्वीकृति दिलाये जाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) :

200. चिकित्सा सुविधाओं के लिये नीति निर्धारित करने एवं अव्यवस्था दूर करने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :

201. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सुदृढ़ एवं समुन्नत करने पर चर्चा के लिये ।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (मावली) :

202. ग्रामीण क्षेत्रों को बजाय शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा पर अधिक एवं असन्तुलित व्यय होने पर चर्चा के लिये ।

203. मावली ग्राम में प्रसूति गृह खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

204. मावली क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु अस्पताल व दवाखाने खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री राम प्रसाद लड्ढा (भाण्डल),

# Page No 72

(72)



श्री भेरूलाल बैरवा (शाहपुरा):

205. शाहपुरा में हॉस्पिटल के अधूरा कार्य को पूर्ण कराने में विभाग की असफलता तथा रेफरल हॉस्पिटल में क्रमोन्नत हो, इस पर चर्चा के लिये।

206. शाहपुरा हॉस्पिटल में डॉक्टर की तुरन्त नियुक्ति हेतु चर्चा के लिये।

207. कोठीया, कनेछन कलां में डिस्पेन्सरी खुलाने बाबत चर्चा के लिये।

208. आयुर्वेद औषधालय राजियास, उम्मीदपुरा, अम्बाघोडा में खुलाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल):

209. औषधालयों में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति और निर्धन व्यक्तियों को दवाइयों की सुविधा देने बाबत चर्चा के लिये।

210. जिला स्तरीय चिकित्सालयों में सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधायें व विशेषज्ञ उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

211. औषधालयों को निजी भवनों से हटाकर नक्शे के अनुसार भवन बनवाकर उसमें चलाने पर चर्चा के लिये।

212. सभी डिस्पेन्सरियों में ए. एन. एम. की पोस्ट कायम कराने बाबत माण्डल व राजाजी का केड़ा पं. स., माण्डल के तहत रखवाने हेतु चर्चा के लिये।

213. चिकित्सालयों में डॉक्टरों व स्टाफ की व्यवस्था जनसंख्या व दैनिक उपस्थिति के अनुसार हो क्राइटेरिया के आधार पर नहीं, इस पर चर्चा के लिये।

214. बागोर पंचायत समिति, मांडल में लेडी डॉक्टर की नियुक्ति कराने बाबत चर्चा के लिये।

215. औषधालयों में बजट के अनुसार समय पर दवाइयां उपलब्ध हों व अधिक दवाइयां उपलब्ध कराई जावें इस पर चर्चा के लिये।

216. आयुर्वेदिक औषधालय भवनों के निर्माण में जनसहयोग व सरकारी अंशदान की स्पष्ट नीति निर्धारण कराने हेतु चर्चा के लिये।

217. एडपोस्ट डिस्पेन्सरी में हर जगह प्रथम श्रेणी मेल नर्स को ही रखा जावे, इस पर चर्चा के लिये।

218. भीलवाड़ा हॉस्पिटल में आये दिन टिटनिस की बीमारी होती है उसकी स्थाई रोकथाम बाबत चर्चा के लिये।

219. किड़ीमाल में आयुर्वेदिक औषधालय खुलाने बाबत चर्चा के लिये।

220. भगवानपुरा में डिस्पेन्सरी खुलाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़):

221. उन डॉक्टरों को उसी स्थान पर यथासम्भव रखा जावे जहां उनकी पत्नी हो, ताकि टिक कर काम कर सके, इस पर चर्चा के लिये।

222. मेट्रिक पास लड़कों को प्राथमिक उपचार (फस्ट एड) की शिक्षा के कैम्प

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
स्थापित कर साधारणसा अलाउन्स देकर पंचायत के हेडक्वार्टर पर स्वास्थ्य सेवा प्रारम्भ करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री शिवनारायण (थानागाजी) :

223. ग्राम गोर्धनपुरा, तहसील राजगढ़ उप-केन्द्र स्वास्थ्य अथवा आयुर्वेदिक औषधालय खोलने पर चर्चा के लिये।

224. थानागाजी एवं नारायणपुर चिकित्सालयों में प्रथम श्रेणी मेल नर्स के नये पद सृजन कराने हेतु चर्चा के लिये।

225. ग्राम थेवर, तहसील राजगढ़ में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

226. थानागाजी निर्वाचन क्षेत्र में बल्देवगढ़ एवं अजयगढ़ एडपोस्ट चिकित्सालयों पर ए. एन. एम. लगाने हेतु चर्चा के लिये।

227. थानागाजी मुख्यालय पर एक महिला चिकित्सक का नया पद सृजन कराने एवं 10 शय्याएं बढ़ाने पर चर्चा के लिये।

228. ग्राम मुंडावरा, तहसील थानागाजी में एडपोस्ट चिकित्सालय खोलने पर चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

229. सहायक निदेशक, मलेरिया तथा उनके अधीन कर्मचारियों का फिक्सेशन करने का झूठा आश्वासन देने पर भी कोई कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये।

230. दौसा में आयुर्वेदिकऔषधालय के अभाव पर चर्चा के लिये।

231. दौसा मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र में साधनों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

232. दौसा अस्पताल में एक्स-रे की सही सुविधा के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर) :

233. वैद्यों के वेतनमानों में परिवर्तन की आवश्यकता पर तथा वैद्यों के द्वारा एलोपैथी दवाओं के प्रयोग पर रोक लगाने तथा पुष्कर में आयुर्वेदिक कॉलेज खुलाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं):

234. राजस्थान के चिकित्सालयों में दवाओं व औजारों के अभाव, गरीब जनता को चिकित्सा का समुचित लाभ नहीं मिलने पर चर्चा के लिये।

235. चौमूं क्षेत्र में चिकित्सालयों के अभाव व चौमूं चिकित्सालय को क्रमोन्नत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

236. चौमूं क्षेत्र में मातृ शिशु कल्याण केन्द्रों एवं चिकित्सकों का अभाव होने के सम्बन्ध में तथा कालाडेरा व सामोद में चिकित्सक पदों के अभाव की चर्चा के लिये।

श्री मेगराज पंवार (चूरू) :

237. गांवों में खोले गये एडपोस्ट तथा सब-सेन्टरों में स्टाफ लगाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

# Page No 74

(74)



(श्री मेघराज ंवार)

238. गांव सोमासी, तहसील चूरू में सन् 66 से अब तक पी. एच. का सेन्टर न खोले जाने बाबत चर्चा के लिये।

239. गांव ल्होसना बडा में खोली गई डिस्पेन्सरी में डॉक्टर न भिजवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

240. सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की कमी से जनता को होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

241. मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रमों की असफलता पर चर्चा के लिये।

242. डेडराज भरतिया अस्पताल के अधूरे कार्य को पूरा कराने तथा डॉक्टरों के लिये आवास-गृह निर्माण कराने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

243. डेडराज भरतिया जनरल अस्पताल में दांतों के डॉक्टर को दांत बनाने के औजार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा हेतु।

श्री मंजूर अली (सवाई माधोपुर) :

244. ग्राम पीलवा व गंगवाडा में आयुर्वेद औषधालय खोले जाने बाबत चर्चा के लिये।

245. ग्राम डुब्बी में एडपोस्ट खोले जाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़):

246. सवाई मानसिंह अस्पताल में बर्न यूनिट खोलने बाबत चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र पाल सिंह (आसीन्द) :

247. आसीन्द में रेफरल हॉस्पिटल खुलवाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल परमार (डूंगरपुर),

श्री नत्थीसिंह (लक्ष्मणगढ़) :

248. डूंगरपुर जनरल अस्पताल में दवाई के अभाव के कारण बीमारों तथा खासतौर पर गरीबों का इलाज नहीं करने बाबत चर्चा के लिये।

249. डूंगरपुर जनरल अस्पताल में लम्बे समय से दांतों के डॉक्टर की व्यवस्था नहीं, इससे उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

250. डूंगरपुर जनरल हॉस्पिटल में चीफ मेडिकल अधिकारी की मोनोपोली से जन साधारण की चिकित्सा में भारी बाधा उत्पन्न होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रतन लाल वर्मा (भिनाय),

श्री सुभाष चन्द्र (सूरजगढ़),

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़),

श्री हरिकृष्ण (नदबई):

251. ग्रामीण क्षेत्रों में बीमारी के इलाज का कोई साधन नहीं है, जहां अस्पताल व औषधालयें हैं, वहां दवाये नहीं हैं, इस पर चर्चा के लिये।

श्री असलम अली खां (फतेहपुर),

श्री नत्थी सिंह (लक्ष्मणगढ़),

श्री हनवन्त सिंह राणावत (बाली),

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर),

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा),

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रतनगढ़),

श्री हरिकृष्ण (नदबई),

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सुरतगढ़) :

252. ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित चिकित्सालयों की व्यवस्था कराये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री किशन सिंह भाटी (जैसलमेर) :

253. पिछड़े क्षेत्रों में जन सेवाओं का व्यापक प्रसार एवं चल चिकित्सालय स्थापित कराने तथा जनसंख्या की शर्त हटाने बाबत तथा अधिक निःशुल्क दवाइयां वितरण करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री मेघराज पंवार (चूरू) :

254. चूरू के डेडराज भरतिया अस्पताल में डॉक्टरों एवं अन्य स्टाफ की कमी के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

255. सिकराय निर्वाचन क्षेत्र में अभी तक स्वीकृत किए गए सब-सेन्टर व एड-पोस्ट डिस्पेन्सरीज को चालू न किए जाने पर चर्चा के लिये।

256. सिकराय निर्वाचन क्षेत्र में डिस्पेन्सरीज व औषधालयों में डॉक्टरों व कर्मचारियों की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) :

257. पाली जिले की प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर पर एलोपैथिक व आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी),

श्री गोविन्द सिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़) :

258. इमारत की कमी व डॉक्टर की कमी से बूंदी चिकित्सालय की हालत बड़ी शोचनीय है, इस पर चर्चा के लिये।

259. बून्दी के चिकित्सालय में मरीजों को होने वाली असुविधा एवं बिस्तरों की कमी तथा डॉक्टरों के अनुचित व्यवहार पर चर्चा के लिये।

260. बूंदी क्षेत्र में डाणी, नमाना प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री आलम अली खां (फतेहपुर) :

261. फतेहपुर एस. डी. ओ. क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

262. बाड़मेर जिले में चर्म रोग, खुजली, एक्जिमा आदि का प्रकोप करीब 8 माह से बढ़ रहा है, जिसकी माकूल चिकित्सा की आवश्यकता के विषय पर चर्चा के लिये।

श्री सुखलाल सेंणचा (रायपुर) :

263. पाली जिले के कुशालपुरा एवं

(श्री सुखलाल सेणचा)
बर पर शीघ्र एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने बाबत चर्चा के लिये ।

264. प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में एक साथ दो डाक्टरों के आपस में रहने से झगड़े पैदा होने की स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री हजारीमल सारण (सरदार-शहर ) :

265. सरदारशहर राजकीय अस्पताल में चिकित्सकों के अभाव से व्याप्त अव्यवस्था बाबत चर्चा के लिये ।

श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर-पश्चिम) :

266. सरकार द्वारा योगासन एवं प्राकृतिक चिकित्सा के व्यापक प्रसार हेतु कॉलेज खोले जावें और उच्च स्तर के वैद्य एवं योगी तैयार किये जावें, इस पर चर्चा के लिये ।

267. यूनानी कॉलेज खोलकर अच्छे हकीमों का निर्माण किया जावे, इस पर चर्चा के लिये।

268. आयुर्वेद कॉलेज खोल कर अधिक वैद्य एवं उप-वैद्यों की पढ़ाई की व्यवस्था कर सब अस्पतालों में वैद्यों और उप-वैद्यों की पूर्ति की जावे, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री सुखलाल सणचा (रायपुर) :

269. पाली जिले के व्यापारियों द्वारा खाद्य पदार्थों में की जा रही मिलावट को रोकने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये ।

श्री जगतार सिंह कंग (करणपुर):

270. गंगानगर जिले के पदमपुर कस्बे में महिला डॉक्टरों के अभाव तथा उपचार के लिए बाहर जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये ।

271. गंगानगर जिले के अस्पतालों की खराब हालत पर चर्चा के लिये ।

श्री दुला राम (रायसिंह नगर) :

272. रायसिंह नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में हुई अनियमितताओं के बारे में चर्चा के लिये ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल, जयपुर),

श्री मूलचन्द डागा (पाली),

श्री बजरंग लाल शर्मा (बनीपार्क) :

273. मेल नर्सों को फीमेल नर्सों की भांति पदोन्नत नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये ।

274. राजस्थान नर्सिंग कॉलेज में मान्यता प्राप्त न होने एवं उसमें अयोग्य स्टॉफ लगाये जाने पर चर्चा के लिये ।

275. रेल की भांति बसों (रोडवेज) में भी नर्सिंग स्टॉफ को कन्सेशन दिलाने में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

276. मेल नर्सों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने एवं प्रशिक्षण की सीटें बढ़ाने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

277. नर्सिंग स्टॉफ का 20-20 वर्षों

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
से स्थाई करण न किये जाने व डी. पी. सी. की बैठकें न होने पर चर्चा के लिये।

278. सेवारत कर्मचारी एवं उनके बच्चों का जो जनरल नर्सिंग के प्रशिक्षणार्थी के रूप में चयन किया जाता है उनके कोई नियम न होने पर चर्चा के लिये।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत):

279. जयपुर में स्थित मेडिकल कॉलेज को ही पोस्ट ग्रेजुएट संस्थान न बनाकर शेष मेडिकल कॉलेजों में स्पेशलाइजेशन-वाइज बंटवारे हेतु चर्चा के लिये।

280. राज्य सरकार की सेवा में उपलब्ध विशेषज्ञ चिकित्सकों का उनके विशेष ज्ञान क्षेत्र में पूर्ण व सही उपयोग करने हेतु चर्चा के लिये।

281. चिकित्सकों के ट्रान्सफर में व्याप्त धांधली व निश्चित नीति के अभाव पर चर्चा के लिये।

282. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित चिकित्सा केन्द्रों पर भ्रमण चिकित्सालयों की स्थापना हेतु चर्चा के लिये।

283. चिकित्सालयों में एक्स-रे प्लेट्स के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

284. चिकित्सकों की प्राइवेट प्रेक्टिस के कारण चिकित्सालयों में उनकी कार्य-कुशलता पर प्रभाव पड़ता है, इस पर चर्चा के लिये।

285. टी. बी. क्लिनिक्स में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री गणेश लाल बैरागी (हिण्डोली):

286. बून्दी के अस्पताल की स्थिति सुधारने तथा क्षेत्र में नये अस्पताल खोलने, डाक्टरों एवं नर्सों की समुचित व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गोपाल सिंह (आहोर):

287. ग्राम बाला व ऊण में आयुर्वेद औषधालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

288. आहोर नगर में महिला डॉक्टर की नियुक्ति पी. एच. सी., आहोर में नितान्त आवश्यक होने पर भी नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

289. ग्राम भाद्राजून में औषधालय (एलोपैथिक) भवन बन जाने पर भी औषधालय नहीं खोला गया है, उस विषय में चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा):

290. प्रदेश में चिकित्सा सुविधा के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली),

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर):

291. 20 से 25 वर्ष तक की सेवा पूर्ण करने पर भी पुराने कम्पाउण्डर्स की कोई पदोन्नति नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री मनीराम (तारानगर):

292. तारानगर अस्पताल तथा शिशु कल्याण केन्द्र, तारानगर में दवाइयों की कमी के संबंध में चर्चा के लिये।

Page No 78



श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

293. विधायक निवास स्थित डिस्पेंसरी में कार्यरत मेल नर्सों को मकान किराया एवं शहरी भत्ता नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये ।

294. विधायक निवास स्थित डिस्पेंसरी में मेल नर्स की नियुक्ति नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री शंकर लाल (जैतारण) :

295. पाली नगर में समुचित व्यवस्था न होने से स्वास्थ्य को भयंकर खतरा उत्पन्न होने पर चर्चा के लिये ।

296. जैतारण क्षेत्र में चिकित्सा की समुचित व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये ।

297. जैतारण क्षेत्र में गांव मोहराई और निम्बोल में एडपोस्ट खोलने पर चर्चा के लिये ।

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़):

298. सूरतगढ़ कस्बे में पीने के पानी की पाइप लाइन हरिजनों के मोहल्ले में नहीं डालकर बिना स्वीकृति के दूसरे मोहल्लों में डालने की विभाग की धांधली पर चर्चा के लिये ।

299. लक्ष्मणगढ़ (सीकर) क्षेत्र में औषधालयों एवं चिकित्सालयों के अभाव पर चर्चा के लिये ।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) :

300. सी. एम. एण्ड एच. ओ., जयपुर के कार्यालय की संस्थापन शाखा में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये ।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) :

301. आमेर विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा का अभाव तथा उपलब्ध चिकित्सा सुविधा त्रुटिपूर्ण है, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री हरलाल सिंह खर्रा (सीकर) :

302. पांच हजार से अधिक की आबादी पर समुचित चिकित्सा की व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये ।

वैद्य श्री गोविंद सहाय (गंगापुर) :

303. आयुर्वेद चिकित्सकों का वेतन 750 रुपये से शीघ्र 1350 रुपये किये जाने पर चर्चा के लिये ।

304. सवाई माधोपुर जिले में गंगापुर अस्पताल को रेफरल बनाने पर चर्चा के लिये ।

305. सवाई माधोपुर जिले में गंगापुर सिटी सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है फिर भी वहां लेडी डॉक्टर नहीं है, उसके बारे में चर्चा के लिये ।

306. सवाई माधोपुर जिले में गंगापुर सिटी अस्पताल में सफाई के लिये हरिजन की नियुक्ति पर चर्चा के लिये ।

307. सवाई माधोपुर जिले में गंगापुर सिटी अस्पताल में एक्स-रे मशीन का न होना तथा वहां की जनता की परेशानी पर चर्चा के लिये ।

(वैद्य श्री गोविन्द सहाय)

308. गंगापुर सिटी अस्पताल में कम्पाउण्डर तथा नर्स की कमी पर चर्चा के लिये ।

309. आयुर्वेद औषधालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पर चर्चा के लिये ।

310. सवाई माधोपुर जिले में कई औषधालयों में वैद्यों का तीन माह का वेतन रोके जाने के संबंध पर चर्चा के लिये ।

311. आयुर्वेद विभाग में निदेशक का पद कई माह से रिक्त है; उससे विभाग में अनियमितता तथा सही कार्य न चलने पर चर्चा के लिये ।

312. आयुर्वेद निर्माणशालाओं में सही ढंग से औषधियों का न बनने पर तथा सही औषधियों का वितरण सही न होने पर चर्चा के लिये ।

313. आयुर्वेद औषधियों की सही खरीद न होने तथा रसायनशालाओं में सही निर्माण न होने पर चर्चा के लिये ।

314. आयुर्वेद कॉलेज, जयपुर में छात्रावास का अभाव तथा सिर्फ 56 छात्रों को ही रहने की व्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

315. सवाई माधोपुर जिले में नये औषधालय खोलने पर आवश्यक विचार किया जावे, इस पर चर्चा के लिये ।

316. सवाई माधोपुर जिले के छोटे गांवों में चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में भेदभाव पर चर्चा के लिये ।

317. आयुर्वेद चिकित्सकों का वेतन बढ़ाने पर चर्चा के लिये ।

318. ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य चिकित्सकों के अभाव तथा विभाग द्वारा बरती जाने वाली ढिलाई पर चर्चा के लिये ।

319. राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की प्रगति में बाधक समस्याओं का शीघ्र निवारण कर राज्य सरकार उचित व्यवस्था करें, इस पर चर्चा के लिये ।

320. आयुर्वेद कॉलेज, जयपुर के छात्रावास का शीघ्र विस्तार किया जावे जिससे छात्रों के रहने की समुचित व्यवस्था हो सके, इस पर चर्चा के लिये ।

321. गंगापुर सिटी आयुर्वेद औषधालयों को 'ए' श्रेणी बनाने पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) :

322. ग्राम बिजूसर के अस्पताल को वर्तमान सरकार द्वारा बन्द किये जाने के वैमनस्यपूर्ण आदेश पर चर्चा के लिये ।

श्री माणकचन्द सुराणा (लूणकरणसर) :

323. राजस्थान में चिकित्सा सुविधाओं के धीमे प्रसार से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये ।

324. राजस्थान के अस्पतालों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये ।

325. रेगिस्तानी इलाकों में डिस्पेंसरीज के अभाव पर चर्चा के लिये ।

श्री रणजीत सिंह राठौड़ (ओसियां) :

326. गांवों में चिकित्सा सुविधा के अभाव व गांवों में रहने वालों को दवाई आदि देने में भेदभाव के बरताव पर चर्चा के लिये ।

327. विभाग द्वारा दवाइयों व अन्य सामान की खरीद में किए गए घोटालों के संबंध में चर्चा के लिये ।

328. मलेरिया विभाग के कर्मचारियों को भत्ता आदि नहीं दिये जाने व उनके साथ भेदभाव बरतने पर चर्चा के लिये ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल, जयपुर):

329. सवाई मानसिंह अस्पताल में बच्चा मेडिकल वार्ड में अतिरिक्त बिस्तरों की संख्या में वृद्धि करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

330. 1979 वर्ष में आयोजित होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में शिशु चिकित्सा संस्थान एवं जिला-स्तर पर कनिष्ठ विशेषज्ञ (जूनियर स्पेशियलिस्ट) के पद पर नियुक्ति के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री चिरंजी लाल गर्ग (पुष्कर) :

331. मैनेजर एवं जिला आयुर्वेद अधिकारियों के पद रिक्त रहने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

332. आयुर्वेद विभाग के निदेशक का पद गत जुलाई से रिक्त पड़ा हुआ है, इस पर चर्चा के लिये ।

333. आयुर्वेद फार्मेसी में आवश्यकता से अधिक कच्ची औषधियों का क्रय करने पर चर्चा के लिये ।

मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक मंत्री परिषद् के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय—

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल, जयपुर),

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) :

1. राजस्थान के मंत्रियों पर होने वाले व्यय में कमी किये जाने और सचिवालय में मन्त्रियों से मिलने आने वाली जनता को अधिक सुविधाएं दिये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

श्री विजयसिंह नदेरा (बांदीकुई) :

2. मंत्री परिषद् के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले अनावश्यक यात्रा आदि के बाबत चर्चा के लिये ।

श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

3. मंत्रिमण्डल के सदस्यों द्वारा किये जाने वाले टेलीफोन, यात्रा, दैनिक भत्ता, मोटर व्यय तथा उन पर होने वाले अन्य व्यय का त्रैमासिक ब्यौरा विधान-सभा सदस्यों को उपलब्ध कराने के बारे में चर्चा के लिये ।

4. सरकारी गाड़ियों का उपयोग मंत्री द्वारा केवल सरकारी काम के प्रयोजन लेने हेतु चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण) :

5. मंत्रि-परिषद् के सदस्यों द्वारा निजी कार्यों हेतु सरकारी वाहनों का दुरुपयोग रोकने हेतु चर्चा लिये ।

6. मंत्रि-परिषद् के सदस्यों के निवास पर लगे दूरभाष के दुरुपयोग को रोकने हेतु चर्चा के लिये ।

7. मन्त्रियों को दिये जाने वाले सत्कार भत्ते के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

8. मंत्रि-परिषद् के सदस्यों से वसूल न होने वाले ऋण के अपलेखन के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

9. मंत्रि-परिषद् पर भारी खर्चे को कम किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. मंत्रि-परिषद् के सदस्यों द्वारा अपने विभाग के केसेज का निपटारा करने में व निर्णय लेने की अक्षमता पर चर्चा के लिये ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर):

11. मंत्रि-परिषद् द्वारा आम जनता की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने में घोर उपेक्षा करने पर चर्चा के लिये ।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) :

12. राज्य सरकार के संबंधित मन्त्रियों को भेजी गई अनुसूचित जाति, जन-जाति एवं कमजोर वर्ग की शिकायतों की सुनवाई न किये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

13. मन्त्रि-परिषद् द्वारा आम जनता की शिकायतों का तुरन्त निराकरण करने बाबत व विधायक द्वारा बताई गयी समस्याओं का निराकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

14. वाहनों व अन्य खर्चों के अम्बार कमी की जाय, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) :

15. मंत्रि-परिषद् के सदस्यों द्वारा सादगी नहीं बरतने पर चर्चा के लिये ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :

16. मंत्रि-परिषद् पर अपव्यय रोकने को आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हरीशकुमार शर्मा (रामगंज मण्डी) :

17. मंत्रि-परिषद् की कार्य पद्धति पर चर्चा के लिये ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

18. मंत्रियों के वैभवपूर्ण आचरण तथा अन्य सुविधाओं में कटौती की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री विठ्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहरथाना) :

19. मंत्रिगण विधायकों के क्षेत्रीय विकास की अवहेलना करते हैं एवं पत्रों का उत्तर नहीं देते, इस पर चर्चा के लिये ।

(82)



श्रीमती सुमित्रासिंह (झुन्झुनू) :

20. (मन्त्रि-परिषद् में आवश्यक तालमेल की कमी पर चर्चा के लिये ।

श्री रावतराम आर्य (सुजानगढ़):

21. जनता सरकार के मंत्रिगणों को बड़े बंगले एवं अन्य विलासपूर्ण (Luxurious) सुविधाओं के त्याग से खर्चा कम कर आदर्श कायम करना चाहिये, इस बारे में चर्चा के लिये ।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) :

22. मंत्रि-परिषद् सादगी को अमली जामा पहनाने में असमर्थ रही, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) :

23 मन्त्रियों की शान-शौकत पर किये जा रहे अपव्यय पर चर्चा के लिये ।

24 मन्त्रिमंडल के निर्णयों की पालना नहीं होने पर चर्चा के लिये ।

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम) :

25. मंत्रि-परिषद् द्वारा विधायकों से तालमेल रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) :

26. मन्त्रियों का खर्चा व वैभवपूर्ण रहवास में परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा (झालरापाटन) :

27. प्रत्येक मंत्री को जिला मुख्यालय पर नहीं जाने के संबंध में एवं नागरिकों द्वारा जो शिकायतें या आवेदन-पत्र दिए जाते हैं उन पर गौर नहीं करने के संबंध पर चर्चा के लिये ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल, जयपुर) :

श्री अयूब खाँ (तिजारा),

श्री जगदीश सिंह (धौलपुर) व

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

28. राजस्थान सरकार के वर्तमान मंत्री एव भूतपूर्व राजस्व मंत्री द्वारा जिलों के पुनर्गठन की घोषणा किये जाने के उपरान्त भी अभी तक पुनर्गठन नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री गोपाल सिंह (खंडेला),

श्री अयूबखां (तिजारा),

श्री हरिसिंह (फुलेरा) व

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

29. राज्य मंत्रि-परिषद् पर होने वाले व्यय पर चर्चा के लिये ।

श्री बजरंग लाल शर्मा (गलतापोल, जयपुर) :

30. मंत्रि-परिषद् पर होने वाले भारी अपव्यय पर चर्चा के लिये ।

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

31. मंत्रि-परिषद् की कार्य-प्रणाली में समुचित सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शोपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) :

32. सचिवालय व्यवस्था को खतम कर विभागीय कार्यों के कार्यालय मंत्री के घरों पर ही रखने हेतु चर्चा के लिये।

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी) :

33. मंत्रि-परिषद् के खर्च में कटौती की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द आर्य (डग) :

34. सभी मंत्रियों को प्रेषित शिकायतों का मंत्रियों द्वारा उत्तर नहीं दिये जाने एवं असभ्य व्यवहार किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

35. मन्त्रियों पर होने वाले पूरे खर्च पर नियंत्रण तथा मोटरों का उपयोग केवल मंत्री ही करें, इस पर चर्चा के लिये।

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा) :

37. मंत्रियों और उनकी सुविधाओं पर व्यय में कटौती करने पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (मावली) :

37. मन्त्रियों के खर्चों पर 'सीमा बांधो' नीति के प्रतिपालन व सादगी से रहने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

38. मन्त्रियों के चरित्र तथा आचरण में सादगी, सरलता और सच्चाई प्रकट होनी चाहिये तथा यदा-कदा उन्हें बसों में सफर करना चाहिये, इस पर चर्चा के लिये।

श्री आर० डी० यादव (चोमू) :

39. मन्त्रि-परिषद् के सदस्यों द्वारा मंत्री कक्षों में, वातानुकूलित कमरों में अपव्यय की रोकथाम की चर्चा के लिये।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) :

40. मन्त्रियों एवं राज्य मन्त्रियों में बढ़ते हुये खर्चे को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय),

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़),

श्री सुभाषचन्द्र (सुरजगढ़) व

श्री हरीकृष्ण (नदबई) :

41. मंत्रिगण ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक दौरे करें और अधिकारियों से सही काम लें, इस पर चर्चा के लिये।

श्री आलमअली खां (फतेहपुर),

श्री नरपतसिंह (लक्ष्मणगढ़),

श्री हनवंतसिंह (बाली),

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर),

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा),

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रतनगढ़),

श्री हरीकृष्ण (नदबई),

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) व

श्री सुभाषचन्द्र (सूरजगढ़) :

42. मंत्रि-परिषद् पर होने वाले व्यय पर कटौती किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) :

43. मंत्रि-परिषद् के सदस्यों को सादगी मूलक आचरण अपना कर तथा जन-प्रतिनिधियों का सलाहकार मण्डल बनाकर उनके सहयोग से कार्य करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय):

44. मंत्रि-परिषद् पर होने वाले अनावश्यक व्यय में कमी किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

45. लालफीताशाही पर नियंत्रण करने में मंत्रिमंडल की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री हजारीमल सारण (सरदारशहर) :

46. मंत्रि-परिषद् पर होने वाले खर्चे को घटाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

47. मंत्रियों के बंगलों पर जल और विद्युत् पर होने वाले अनावश्यक खर्चे पर चर्चा के लिये।

48. मंत्रिमण्डल पर यात्रा व्यय, चिकित्सा व्यय, मकान किराया भत्ता आदि पर आयोजना भिन्न में हुए खर्चे की बढ़ोत्तरी पर चर्चा के लिये।

49. मंत्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदान की राशि में वृद्धि और उसका गलत ढंग से उपयोग किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरलाल (जैतारण) :

50. मंत्रि-परिषद् के सदस्यों के अलोकतांत्रिक व्यवहार पर चर्चा के लिये।

51. मंत्रि-परिषद् में मरुप्रदेश का प्रतिनिधित्व न होने के कारण क्षेत्र की अवहेलना पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपलदा) :

52. मंत्रियों पर किये जाने वाले कई मदों में खर्चे अनावश्यक है, इस पर चर्चा लिये)।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

53. मंत्रियों को दी जाने वाली डिस्क्रिशनरी धनराशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

54. मंत्रियों को दी जाने वाली डिस्क्रिशनरी धनराशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रणजीतसिंह राठौड़ (ओसियां) :

55. मंत्रि-परिषद् के सदस्यों के रहन-सहन पर किये जा रहे अनावश्यक खर्चे पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 26 व 2 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल): अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम चिकित्सा की मांग के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में जो सवाई मानसिंह अस्पताल है वह एशिया में मशहूर है। इस अस्पताल में आज जो पानी जा रहा है वह गटर का पानी जा रहा है। इस प्रकार मालूम होता है जैसे कोई फैक्ट्री में वह पानी जा रहा हो। सारा का सारा गन्दी बस्ती का पानी इस अस्पताल में जाता है। अस्पताल में जो लोग भर्ती हैं उनके काम यह पानी आता है।

इसके अलावा जो वहां पर नया प्लान्ट होना चाहिये था, वह भी नहीं है। सवाई मानसिंह अस्पताल की बहुत ही हालत खराब है। एअर कन्डीशन आज पिछले पांच वर्षों से खराब पड़ा हुआ है, उसके बदले में कूलर ही काम में लाया जाता है। वहां पंखों की कोई व्यवस्था नहीं है। एक तरफ तो हम हमारे सचिवालय को एअर कन्डीशण्ड बनाने जा रहे हैं दूसरी तरफ हजारों की तादाद में बेचारे सवाई मानसिंह अस्पताल में बिना पंखों के, बिना एअर कंडीशन के पड़े रहते हैं। वहां न केवल मरीजों के रिश्तेदार और मरीज ही तकलीफ में होते हैं बल्कि हमारे सदन के माननीय सदस्य भी वहां पर बीमार होकर जा सकते हैं। वह अपने परिवार वालों के लिये भी वहां पर जा सकते हैं। स्वयं भी तो बीमार पड़ सकते हैं

(व्यवधान)

मेरा निवेदन है कि वहां पर मरीजों के लिये एअर कन्डीशन लगना चाहिये।

इसके अलावा जो वहां पर लोहे की टंकी है उसका भी लोहा गला हुआ है, उसकी खराब हालत है। इसी प्रकार आप वहां पर मुर्दाखाने की हालत जाकर देखें, बहुत खराब हालत है। वहां पर सड़ान की बदबू आ रही है।

इसके साथ-साथ, अध्यक्ष महोदय, बच्चों के लिये तो यहां कोई अस्पताल है नहीं। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में एक बच्चों का वार्ड बना दिया गया है जिसमें पंखों या कूलर का नाम नहीं। बेचारे बच्चे गर्मी में सिसकते रहते हैं। उनके साथ जो भी उनके रिश्तेदार रहते हैं उनकी हालत बहुत खराब है। गर्मी में वे सिसकते रहते हैं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि एक जांच समिति बनायी जाय जो वहां की सारी स्थिति को देखे और बाद में अपने सुझाव दे।

सबसे पहले मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि सवाई मानसिंह अस्पताल को एअर कन्डीशन्ड किया जाय। इसके अलावा थोड़ा मैं, अध्यक्ष महोदय, वहां के ऑपरेशन थ्येटर के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। एक तो आज वहां पर एअर कन्डीशनर खराब पड़ा है, दूसरे ऑपरेशन थ्येटर में पंखों की पूरी व्यवस्था नहीं है। कई बार जब बिजली चली जाती है, ऐसे समय ऑपरेशन होते हैं तो हालत बहुत ही खराब हो जाती है और मरीजों की मृत्यु होने का खतरा बना रहता है। मेरा निवेदन है कि वहां पर डीजल सेट बिजली के लगाये जायं। आज स्थिति यह है कि वहां पर कोयले की चिमनी चलती रहती है। भोमियाजी की छतरी के पास वह क्षेत्र ऐसा दिखाई देता है मानो वह कोई कारखाना हो और बॉयलर में कोयले झोंके जा रहे हैं।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

वहां धुआं उठता रहता है। इसके लिये मेरा निवेदन है कि वहां पर बिजली के डीजल सेट का इन्तजाम किया जाय और बिजली की पूर्ण व्यवस्था की जाय। नहीं तो, अध्यक्ष महोदय, कभी ऑपरेशन करते वक्त बिजली चली जाती है, तो मरीज के जीवन-मरण का प्रश्न बन जाता है। आज वहां पर एक नहीं हजारों मरीज आते हैं। इसलिये इसकी ओर राज्य सरकार विशेष रूप से ध्यान दे।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान में कोई दन्त चिकित्सा का कॉलेज नहीं है। यह आवश्यक है कि दंत ,चिकित्सा का कॉलेज खोला जाय। दांतों का विभाग है उसमें जो मशीन है वह बेकार पड़ी है। मैंने पिछले सदन में भी, अध्यक्ष महोदय, इस ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। पर राज्य सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।

इसके अलावा, पिछले साल सवाई मानसिंह अस्पताल में लाखों रुपये की खरीद की गयी थी, जिसमें स्टील के बर्तन, थालियां कटोरियां, कूलर वगैरह खरीदे गये थे। उसमें काफी घोटाला हुआ था। उसकी तो खैर जांच हो रही है और जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसको राज्य सरकार दण्ड देगी या उसके खिलाफ कार्यवाही सरकार करेगी। पर यह काम में आने वाली स्टील की थालियां और कटोरियां, गर्म भोजन भेजने के लिये जो ट्रोली वगैरह लाखों रुपये का व्यय करके खरीदी हैं वह आखिर किस काम आती है? वह कहां गयी? इसका कोई पता नहीं चलता। कांग्रेस राज्य में घोटाला होता था, तो कोई खास बात नहीं थी, लेकिन अब तो कुछ कार्यवाही होनी चाहिये। आखिर जनता पार्टी की सरकार में तो जनता को आराम मिलना चाहिये।

इसके साथ-साथ, अध्यक्ष महोदय, जो मुर्दावाहन अस्पताल में है वह भी खराब पड़ा हुआ है। लाश सड़ती रहती है उसके लिये कोई वर्कशॉप नहीं है। वह जब भी खराब होती है तो जनता को दिक्कत होती है। सरकार को चाहिये कि अपना वर्कशाप वहां रखे ताकि मुर्दावाहन खराब हो जाय, तो उसे जल्दी ही ठीक कराया जा सके।

इसी तरह वहां पर कपड़ों का कोई इंतजाम नहीं है, इसमें सुधार होना चाहिये। इसके अलावा एक्स-रे मशीन है उसकी हालत खराब है। अगर कोई बायोलोजिकल जांच करानी हो, थूक की जांच करानी हो, खून की जांच करानी हो या स्टूल टेस्ट कराना हो, तो कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। यह व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। लोग बाहर से अपने पैसों से जांच कराते हैं। पैसे वाले तो बाहर जांच करा लेते हैं पर बेचारे गरीब आदमी परेशान होते हैं और बिना टैस्ट के मरते भी हैं। इसलिय खून, थूक, स्टूल और यूरिन टैस्ट की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिये। वैसे वहां पर एक बेड के ऊपर 60 रुपया खर्च किया जाता है, पर वह किसी के काम का नहीं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन सभी की जांच की मशीनों के लगाने के साथ-साथ एक्स-रे प्लान्ट भी नया लगाने की व्यवस्था करें। इसके अलावा, वहां पर एक मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट होना चाहिये। सवाई मानसिंह अस्पताल में अभी तक फुल टाइम ट्रेन्ड कोई भी सुपरिंटेंडेंट नहीं है। जिनको मेडिकल अस्पताल में सुपरिटेन्डेन्ड के पद पर लगाया

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

गया है वह अधिकारी प्रशिक्षित नहीं है। इसके अलावा, उनको पार्ट टाइम लगाया गया है। इसके लिये मेरा सुझाव है कि सवाई मानसिंह अस्पताल में फुल टाइम ट्रेन्ड सुपरिन्टेन्डेन्ट की नियुक्ति करने की राज्य सरकार कार्यवाही करे।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस अस्पताल के लिये एक सलाहकार समिति बनायी जाय जो कि जनता की समस्या को ध्यान में रखते हुए जनता के भले के लिये कार्य करे।

इसके अलावा रेडियोग्राफर के वेतनमान के बारे में भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। इस संबंध में कई बार राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है, पर पिछली सरकार ने मेरे बार-बार निवेदन करने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। अब वर्तमान सरकार तो कम से कम रेडियोग्राफर के वेतनमान में सुधार करे।

मेल नर्सेज के प्रमोशन के चान्सेज नहीं हैं, फीमेल नर्सेज के चान्सेज प्रमोशन के अधिक होने के कारण मेल नर्सेज के भी प्रमोशन के रास्ते खोले जाने चाहिये। इसके अलावा राजस्थान नर्सिंग कॉलेज जो है वह आज रिकग्नाइज नहीं होने से भी लोगों को दिक्कत आ रही है, उसकी ओर भी ध्यान दिया जाय। इसके अलावा, वर्षों से मेल और फीमेल नर्सेज स्थायी नहीं हुई हैं, उन्हें स्थायी किया जाय।

इसके अलावा, वहां पर एक स्थिति यह भी है कि उन लोगों को पंखे के नीचे के बेड्स दिये जाते हैं जो लोग वहां पर काम करने वाले लोगों को टिप्स देते हैं। दूसरे लोगों को ऐसे बेड्स दिये जाते हैं जिन पर वे गर्मी में सड़ते रहते हैं।

मेरा निवेदन यह है कि हर जगह पंखों की व्यवस्था की जाय। मरीजों के लिये अगर कोटेज की कमी हो तो कोटेजेज के ऊपर और कमरे बनाये जा सकते हैं।

इसके अलावा मैं थोड़ा बच्चों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। हम 1979 में अन्तर्राष्ट्रीय बच्चों का वर्ष मनाने वाले हैं। पिछले वर्ष 29909 आउटडोर में पेशेन्ट्स आये थे और 3234 इन्डोर पेशेन्ट्स रहे थे। इसके अलावा 31039 आउटडोर पेशेन्ट्स आये। बच्चों के लिये 50 बेड्स हैं। बच्चों के वार्ड में बहुत ही सफोकेशन रहता है। वहां पर बीमार को देखने जाने वाला खुद बीमार हो जाता है। ऐसी हालत है कि आप पांच मिनट भी खड़े नहीं रह सकते हैं। इसके लिये मेरा निवेदन है कि जयपुर में बच्चों के लिये अस्पताल अलग से खोला जाय और महिलाओं के लिये अलग अस्पताल बनाया जाय। जयपुर में एक जिला अस्पताल बनाया जाय। अभी जो महिला अस्पताल है उसमें सिर्फ 250 सीट्स हैं, उनको बढ़ाया जाय।

इसके अलावा राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर में कोई दंत कॉलेज नहीं है। राजस्थान में एक दन्त कॉलेज खोला जाय जैसा कि दूसरे प्रान्तों में बम्बई वगैरह में है। इसके अलावा यहां पर दांतों की एक मशीन खराब पड़ी हुई है। ई.एस.आई., जयपुर और सवाई मानसिंह अस्पताल में एक-दो डॉक्टर हैं। अगर इमर्जेन्सी में जरूरत पड़ जाय तो लोगों को बहुत दिक्कत होती है। डॉक्टर लोग भी निर्धारित समय पर ही अस्पताल आते हैं

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
दांत का दर्द तो ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, जो किसी भी वक्त किसी के भी हो सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय और एक दंत कॉलेज यहां पर खोला जावे। कई स्थानों पर लाखों रुपयों के उपकरण पड़े हुए हैं। लाखों रुपयों के इन्स्ट्रूमेन्ट्स पड़े हुए हैं। वह किसी उपयोग में नहीं आ रहे हैं। कारण यह है कि उन स्थानों पर दांतों के डाक्टर की पोस्ट नहीं है। इसलिये आप उन जगहों पर जहां दांतों के डॉक्टर नहीं हैं वहां पर पोस्ट दें।

सवाई मानसिंह अस्पताल में आपने पे क्लिनिक की व्यवस्था की है। पिछली सरकार ने इसको शुरू किया था। आज हम स्थिति यह देखते हैं कि मरीज आते हैं, सात-सात दिन तक पड़े रहते हैं। जो व्यवस्था पिछली सरकार ने चालू की थी उसको डॉक्टरों के हित में, मरीजों के हित में समाप्त किया जाना बहुत जरूरी है।

जयपुर में एक व्यवस्था और चालू की हुई है जो किसी जगह नहीं है। पिछली सरकार ने यह व्यवस्था की कि सरकारी कर्मचारियों के लिये सहकारी दुकानों से ही दवाई खरीदी जा सकती है और उसका रिएम्बर्समेंट हो सकता है अन्यथा नहीं। दूसरी जगह पर इस प्रकार की कोई पाबन्दी नहीं है। यदि कोई आमेर में खरीदे तो उस पर कोई पाबन्दी नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सम्पूर्ण राजस्थान में एक-सी व्यवस्था होनी चाहिये। जब अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, तो हमारे राज्य में क्यों हो ?

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान होम्योपैथिक बोर्ड बना हुआ है। राजस्थान होम्योपैथिक कॉलेज भी है, लेकिन आज उसकी कोई मान्यता नहीं है। परीक्षा का कोई केन्द्र भी नहीं है। इसलिये राजस्थान होम्योपैथिक कॉलेज को मान्यता मिलनी चाहिये और परीक्षा की व्यवस्था भी यहां पर की जानी चाहिये।

इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि होम्योपैथिक विभाग को आयुर्वेदिक विभाग के साथ मिला रखा है, इससे बड़ा अन्याय और होम्योपैथी के साथ क्या हो सकता है? इसलिये मेरी मांग है कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथी के अलग-अलग विभाग होने चाहिये जिससे इनका इसी रूप में विकास हो सके और सही व्यवस्था हो सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेडिकल डॉक्टर्स के ट्रान्सफर्स के संबंध में भी निवेदन करना चाहूंगा। मेडिकल कमिश्नर और डाइरेक्टर ट्रान्सफर करते हैं। सरकार को ट्रान्सफर्स के सम्बन्ध में कोई सही नीति निर्धारित करनी चाहिये।

इसके साथ-साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेदिक विभाग में दवाइयों के टेण्डर के सम्बन्ध में भयंकर घोटाले होते हैं। जो टेण्डर पद्धति इस समय लागू की हुई है उसके अन्तर्गत भयंकर घोटाले हैं। जिस किसी को लाभ पहुंचाना होता है, उसको लाखों रुपयों का लाभ पहुंचा दिया जाता है और जिसको हानि पहुंचानी होती है तो उसको हानि पहुंचा दी जाती है। इसलिये इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। कुछ लोगों की कमेटी बैठाकर रोटेशन प्रणाली के अनुसार टेण्डर दिये जायें तो राजस्थान में जो लाखों रुपयों के घोटाले होते हैं, व नहीं होंगे।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

टी. बी. अस्पताल की भी हालत सुधारने की आवश्यकता है।

लोक स्वास्थ्य के विषय में भी निवेदन करना चाहूंगा। परिवार नियोजन स्वेच्छा से होना चाहिये, इसमें किसी को कोई गिला नहीं है। लेकिन परिवार नियोजन के नाम पर जो अश्लीलता है उसको समाप्त करने की आवश्यकता है। जब 11 बजे पलंग पर सोये होते हैं, विविध भारती से प्रचार होता है, प्रसारण होता है वह बंद होना चाहिये। इसका भारतीय जनता पर अच्छा असर नहीं पड़ता है। $10\frac{3}{4}$ बजे रात को सोने के समय इस प्रकार का प्रचार हो, क्या यह कोई अच्छी चीज है? राष्ट्र-गीत की जगह परिवार नियोजन का प्रचार कोई शोभा की बात नहीं है। यह पिछली सरकार के द्वारा चलाया हुआ था। इसको बन्द किया जाना चाहिये।

इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगा कि पी.एच.सी. की हालत में सुधार होना चाहिये। डॉक्टर्स पी.एच.सी. पर नहीं होते हैं। आप डॉक्टर्स की भर्ती नहीं करेंगे? क्यों? आपरेशन का वहां पर कोई प्रबन्ध नहीं, उपकरण हैं नहीं, फिर प्राइमरी हैल्थ सैन्टर खोलने से क्या फायदा? उसका क्या उपयोग है? यदि उनसे लोगों की आवश्यकतायें पूरी नहीं होती हैं तो ऐसे पब्लिक हैल्थ सैण्टर्स खोलने से क्या फायदा है?

लोक स्वास्थ्य के संबंध में यह भी कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने यह कहा था कि छः महीने में किसी का चालान नहीं किया जावेगा। यह जनता के स्वास्थ्य के साथ एक खिलवाड़ था। जो लोग मिलावट करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिये और जो पिछली सरकार ने आदेश दिये थे उनको जन स्वास्थ्य के हित में आपको तत्काल हटा देना चाहिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, और भी बोलने वाले हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मलेरिया वाले मलेरिया की रिपोर्ट नहीं भेजते हैं। रक्त की रिपोर्ट समय पर नहीं आती है। इस तरह के विभाग से क्या लाभ है? मलेरिया की रोकथाम के लिये पूरी तरह से कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

### व्यवस्था का प्रश्न

#### कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये समय निर्धारण

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मलेरिया की पूरी रोकथाम होनी चाहिये और रक्त की रिपोर्ट बराबर समय पर आनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अनुशासन हो नहीं है।

(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इन सारी बातों का जबाब देना चाहिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

(श्री खेतसिंह)

(व्यवधान)

... पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं हाउस के पजेशन में हूं। जब तक माननीय अध्यक्ष महोदय कहेंगे, मैं बोलूंगा।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप नियमों का पालन कीजिये।

एक माननीय सदस्य : आप भी बिराजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या का क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इस सदन को चलाने के नियम हैं। संसदीय नियमों की पालना करनी चाहिये। व्यवस्था के नाम पर यह कहना चाह रही थी कि पहले बोलने वाले वक्ता को तो काफी समय दे दिया जाता है और फिर पीछे बोलने वालों को समय कम मिलता है और पांच-सात मिनट में ही घंटी बजा दी जाती है। इसलिये टाइम निश्चित कर दीजिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सबके लिये एक ही बात होनी चाहिये। यह सही बात है।

श्री शंकरलाल : सत्ता पक्ष वाले भी यही बात कह रहे हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : रात भर क्यों बैठें ?

श्री नवनीत पालीवाल : निश्चित समय सबके लिये हो जाय, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है।

एक माननीय सदस्य : महिलाओं को विशेष मौका दिया जाना चाहिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पहले भी हाउस में यह परम्परा रही है कि दस-पांच इधर से बोल जाते थे और 10-15 उधर से बोल जाते थे। डिमाण्ड पास हो जाती थी। अब ऐसा नहीं होता है। रोज रात के 12 बजते हैं। जिन्होंने कट मोशन्स दिये हैं, उनमें पहला नाम गिरधारीलालजी भार्गव का, दूसरा नाम बजरंगलालजी शर्मा का और तीसरा नाम श्रीमती उजला अरोड़ा का होता है। हमको ज्यादा बोलने का मौका मिलना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : पहले कट मोशन देने वाले का पहला नम्बर होता है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : पहले देने वालों के नाम पहले नम्बर पर आते हैं। मेरे बोलने के बाद व्यवस्था लागू करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इस संबंध में शासन पक्ष और विपक्ष को बैठकर निर्णय करना चाहिए कि चर्चा किस तरह से हो। जहां तक शासन का संबंध है, मेरे पास कटौती प्रस्ताव जिस क्रम के अनुसार आते हैं, उसके अनुसार मुझे नाम बोलने होंगे। आप दूसरी व्यवस्था चाहते हैं तो आपस में बैठ कर निर्णय कर लेना चाहिए और तय कर लेना चाहिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय समय निश्चित करने की बात है....

श्री शंकरलाल : सरकार की ओर से भी कह रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : दस-बारह मिनट से अधिक न बोलें, 15 मिनट बोलें तो क्षम्य हैं। जघन्य अपराध तो नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सबका समय बांधा जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं निवेदन करूंगा.......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक-दो मिनट में समाप्त करें।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : हम लोग बोलते हैं तो 7 मिनट से अधिक बोलने नहीं दिया जाता।

श्री अध्यक्ष : कट मोशन जिस क्रम में होगा उसी क्रम में मैं लेने के लिये बाध्य हूं। माननीय सदस्य, आपको अधिक समय दिया जावेगा। आपके साथ सहानुभूति है। आप चाहते हैं, दो सत्ता पक्ष से बोलें और दो विपक्ष से बोलें, यह व्यवस्था मुझे मान्य है और उत्तम है।

(व्यवधान)

अभी मैं कोई व्यवस्था नहीं दे सकता।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: मेरे बोलने के बाद व्यवस्था होगी।

श्री अध्यक्ष : जो भी आपके बीच में तय हो और जो क्रम मिलेगा उसके अनुसार ही सदन चलेगा। जो आज का क्रम है उसके अन्दर परिवर्तन करने का कोई कारण नहीं समझता।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था.....

श्री राम रघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, कल भी जो माननीय सदस्य शुरू में बोले, वह काफी समय बोले। जब मेरा नम्बर आया तो केवल 7 मिनट ही मिले और घंटी बजा दी। मेरा निवेदन यह है कि आप जनता पार्टी के लोगों को इतना समय दे देते हैं, वह 20 मिनट बोल लेते हैं....

श्री अध्यक्ष : मैं आसन पर हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई विशेष कठोर नीति नहीं अपनाऊंगा।

श्री नवनीत पालीवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है। मैं सदस्यों के बोलने का जो अधिकार है उस पर कोई आघात नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि यदि हम सदस्य ही, एक-एक जना यदि दो-दो मिनट की बचत कर लें तो 3।। घण्टे का फर्क पड़ता है। इसलिए 5-7 मिनट का टाइम फिक्स कर दें।

श्री अध्यक्ष : सुझाव बहुत उत्तम है। इसकी मैं सराहना करता हूं। लेकिन ताली दो हाथों से बजती है।

श्री शंकरलाल : हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष का ही दोष हो, तो आपको अधिकार है, आप कह सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। मैं सब सुनने के लिये तैयार हूं। पक्ष और विपक्ष को इस संबंध में कोई न कोई बात तय कर लेनी चाहिए। यह आसानी से हो सकती है।

(श्री अध्यक्ष)
इसके अनुसार कार्यवाही चलायेंगे सदन की। सदन आवश्यक है, तत्पश्चात् मेरा है।

(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, पहले इनको बैठाइये।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सचेतक महोदय ने प्रस्ताव रखा है, आप उसके बारे में हाउस की राय जान लीजिए। हम सब सहमत हैं। उससे व्यवस्था ठीक हो जायेगी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय सदस्य, मुझे बोलने दें।

श्री शंकरलाल : ...यह प्रस्ताव सरकारी मुख्य सचेतक का है और सरकार की तरफ से प्रस्ताव है। हम इससे सहमत हैं। आप इस पर सदन की राय और ले लीजिए।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, सरकारी पक्ष और विपक्ष दोनों बैठकर इस बात को आपके चैम्बर में आपके सामने तय कर लें कि कितने टाइम में कौन-कौन बोलेंगे

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, शहर में रहने वाले 5 मिनट और गांव में रहने वाले 10 मिनट बोलें।

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतक महोदय और विपक्ष के एक सदस्य महोदय मुझे चैम्बर में आकर जो व्यवस्था करनी है इसकी सूचना दे दें। मैं उस पर विचार कर लूंगा।

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। लोग बीच में डिस्टरबेंस कर रहे हैं। इस समय को बोलने वाले के समय में जोड़ दिया जाये।

श्री शंकरलाल : आपका भी काट दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री शंकरलाल : पूरा का पूरा समय आपका कटेगा।

श्री सुरेश कुमार : मैं तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य, श्री गिरधारीलालजी भार्गव को भाषण औपचारिक रूप से समाप्त हो तब तक के लिये मौका दूंगा।

मांग संख्या 26 व 2 पर विचार

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री परिषद की एक नई मांग है। प्रथम बार यह मंत्री परिषद की मांग सदन में आई है। शायद कांग्रेस के जमाने में मंत्री परिषद की मांग यहां वाद-विवाद के लिए कभी नहीं आई। मैं मेरी पार्टी को, अध्यक्ष महोदय, इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने सबसे पहले यह विषय ओपन किया है।

इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि जन-प्रतिनिधियों से हमारे जनता पार्टी के मिनिस्टर जितनी आसानी से मिलते हैं उतनी आसानी से मैं समझता हूं कि कांग्रेस के वक्त में कभी भी कांग्रेस के मिनिस्टर नहीं मिलते थे और न जनता के

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
लोगों से मिलते थे । हमारी जनता पार्टी के मिनिस्टर्स आसानी से मिलते हैं और जनता से भी मिलते हैं……

(व्यवधान)

श्री नारायण सिंह (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, इनका समय काट दिया जाये । यह फिर बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री बजरंग लाल शर्मा ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं अभी बोल रहा हूं । मंत्री परिषद् के बारे में अपने विचार रख रहा हूं…

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री गिरधारी लाल भार्गव; एक मिनट ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री परिषद पर डिबेट है इसलिए बोल रहा हूं । दूसरे सदस्य इस से अनजान हैं इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं ।

मैं मंत्री परिषद् के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि उनके पास चाहे जितना काम हो वह धैर्य नहीं छोड़ें और जो आम व्यावहारिक आचरण बने हुए हैं उस प्रकार का आचारण वह बनाये रखें, यह मेरा निवेदन है ।

दूसरे हमारी जनता पार्टी के मिनिस्टर्स ने अपने खर्चे में कमी की है…

श्री रघुनाथ बिश्नोई : कोई कमी नहीं की । यों ही फालतू बोलते हो ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : हर मंत्री के घर पर टेलीफोन पर ताले लगे हुए हैं । मैं ओपन चैलेन्ज के साथ कह सकता हूं कि हमारे मिनिस्टर्स कोई टेलीफोन का दुरुपयोग नहीं करते हैं । यह मैं खुद देखता हूं ।

इसके बाद मंत्री परिषद के सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि हर मंत्री अपने-अपने विभाग पर काबिज हों । अपने विभाग को कंन्चर करें ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह होने वाला नहीं है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : और जो काम करने हों वह अपने स्तर पर ही कर लें और उनको मुख्य मंत्रीजी के ऊपर नहीं टालें । छोटी-मोटी फाइलों को उनके ऊपर नहीं छोड़ें । छोटे-मोटे निर्णय लेने में वह सक्षम हों…

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह सक्षम नहीं हैं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, अब 31 मार्च आने वाली है इस कारण काफी चीजें खरीदी जाती हैं । इस फिजूलखर्ची को रोका जाय । मेरी यह मांग है कि विरोधी दल के नेता की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी जाय जो जांच करे कि इस समय कोई अनाप-शनाप खर्चा तो नहीं हो रहा है ।

इसी प्रकार मेरी पांचवीं मांग यह है कि मोटर गैराज पर कन्ट्रोल बहुत जरूरी है । पेट्रोल की चोरियां होती हैं और

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
टायर-ट्यूब की बहुत चोरियां होती हैं, इन सबको रोका जाय।

एक अन्तिम निवेदन यह है कि बसों की हमारे यहां राज्य में प्राम्प्ट सर्विस हो जाये। ठीक समय पर बसें चलने लग जायें। मैं जनता पार्टी के मिनिस्टर्स से निवेदन करता हूं कि जनता पार्टी के मिनिस्टर्स बसेस में यात्रा करना शुरू कर दें .....

श्री खेतसिंह राठौड़ : मंत्री पद से हटने के बाद करेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यदि वह ऐसा करेंगे और बसेज से यात्रा करेंगे तो पैट्रोल का दुरुपयोग भी नहीं होगा और एक आदर्श होगा। मेरी एक मांग है कि जो सचिव हैं इनको भी कारें देने की आवश्यकता नहीं है।

इसी प्रकार से निवेदन करना चाहूंगा.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आधा मिनट।

हमारे यहां कुर्सी और दरियां बहुत अच्छी-अच्छी होती हैं और टेलीफोन की डोरी के लिए वह दरियां काटी जाती हैं। इससे हमारे यहां 10 करोड़ रुपये की दरियां खराब होती हैं। हमारे यहां विधान सभा भवन में भी दरियां होंगी वह भी टेलीफोन की डोरी के लिये काट दी जाती हैं। मैं समझता हूं कि इसको रोका जाना चाहिए।

इन सारे खर्चों में कटौती हो, यही बात निवेदन करनी थी।

श्री अध्यक्ष : श्री बजरंगलाल शर्मा।

श्री टीकमचन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, बजरंगलालजी भाषण समाप्त होने पर डूंगरपुर का नाम लेंगे, मेहरबानी करके वे यह नाम नहीं लें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : नहीं लूंगा, जालोर का ले लूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भाई गिरधारीलालजी ने जो कुछ कहा, मैं उससे सहमत नहीं हूं। उन्होंने मंत्रिमण्डल को सबसे नीचे रखा है। मैं मंत्रिमण्डल को पहला स्थान दूंगा। जब जनता पार्टी बनी और चुनाव लड़े, चुनाव जीत कर आये तो गान्धीवाद की नीति की घोषणा की थी। हम यह तो अपेक्षा करते हैं कि हमारे मंत्री सादे तरीके से रहें, जिस ढंग से गांधीजी ने रहने को कहा है उस ढंग से रहें। मेरा मानना है मंत्री परिषद की डिमान्ड के पहले एक इस तरह का बयान हो जिसमें कि कम्पेरेटिव स्टडी हो, और वह स्टडी हो कि भूतपूर्व सरकार के मंत्री किस प्रकार रहते थे और हमारे मंत्री किस प्रकार रहते हैं। हमारे मंत्रियों पर मोटर का खर्चा, बिजली का खर्चा, यात्रा भत्ता खर्चा आदि खर्चों को यदि डिमोन्स्ट्रेट कर पायें तो हम देख पायेंगे कि उनमें और इनमें कितना फर्क है। मैं मानता हूं मंत्री परिषद ने अपने आपको सादगी में अवश्य खड़ा किया है लेकिन एक कसौटी पर रखना होगा कि पहले वाले से अच्छे हैं या बुरे। इस आधार पर हम भाई गिरधारीलालजी की तरह पुरजोर शब्दों में नहीं कह पाते हैं कि हमारे मंत्री परिषद के सदस्य गान्धीवाद की तरह जीते हैं और गान्धीवाद

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

की तरह रहते हैं और गांधीवाद की तरह ही आचरण करते हैं। मैं कहता हूं जिन बंगलों में पुराने मंत्री रहते थे आज उन्हीं बंगलों में 1-2 मंत्रियों को छोड़कर सब मंत्रीगण रहते हैं। यदि मैं ईमानदारी और सच्चाई के साथ निवेदन करूं तो हमारे मंत्रियों को कुछ शिकायतें भी अवश्य हैं। अभी मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि हमारे मंत्री नये हैं। इनको बहुत-सी बातें सीखनी हैं – कार ड्राइविंग आदि की बातें भी इन्हें सीखनी हैं...

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपको नाम बताना पड़ेगा वरना पूरा मंत्रिमण्डल बदनाम होता है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मंत्री महोदय का नाम पूछना चाहते है, मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कहना चाहता हूं। मुख्य मंत्रीजी अपने मंत्रियों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, कार ड्राईविंग भी सिखा रहे हैं और सीखते सीखते कार टूट भी जाती है। मेरा निवेदन है कि आपका इतना दुराग्रह ठीक नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं निश्चित रूप से खर्च चाहे हमसे और मांग लें, लेकिन मंत्री परिषद् गान्धीवादी जीवन का आदर्श प्रस्तुत करे। अगर यह नहीं किया गया, तो हमारा मंत्री परिषद् भी उसी तरह का होगा जिस तरह का मंत्री परिषद कांग्रेस के राज्य में था। अगर वही तौर तरीके अपनाते रहे, तो किस तरह से ये अपनी इमेज बना पायेंगे, यह मेरी समझ में नहीं आता है।

मैं एक बात विशेष रूप से मंत्री परिषद् के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, हमारा मंत्री परिषद् शायद अखबार नहीं पढ़ता है, इसलिये कुछ चर्चा इस बारे में करना चाहिये। जबसे राज्य कायम हुआ है शायद किसी अखबार में मुख पृष्ठ पर नहीं छपा, केवल कल के अखबार में छपा था – होशियार रहो, शहर में चोरियां बहुत हो रही हैं, पुलिस के भरोसे मत बैठे रहो नहीं तो मारे जाओगे .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, विश्नोईजी को अकल तो है नहीं, कहते हैं खरीद नहीं सकते। अभी जालोर का नाम लूंगा तो टीकम चन्द-जी कान्त नाराज होंगे। आप बिराजिये तो सही मैं बोलना जानता हूं। आप बिराजो।

तो, अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान पत्रिका ने छापा है – होशियार, खबरदार। जिरह बख्तर पहिन कर घर से निकलो, ऐसा न हो कि कोई चाकू भोंक दे। पुलिस के भरोसे न रहें। तो मेरा निवेदन है इस तरह से अखबारों में छपता है, ऐसा अखबार में छपता है और वह भी ऐसे अखबार में जो हमारी सरकार से सहानुभूति रखने वाला है। पहले मिसेज गान्धी ने गलती की। अखबारों में वस्तु स्थिति को छापने नहीं दिया तो वह चली गई। शायद आज इस तरह से अखबरों में कोई व्यवस्था नहीं है। मैं मंत्री परिषद् को आगाह करना चाहूंगा कि आप भी अपने कर्त्तव्यों को समझें अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान होगा, यह मेरा निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, या तो हमारे मंत्री परिषद के सदस्य अखबार पढ़ते ही नहीं हैं और अगर पढ़ते भी हैं तो नियमितरुप से नहीं पढ़ते हैं...

(2.05 म. प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्री बजरंगलाल शर्मा)
इसलिये मेरा निवेदन है कि मंत्री परिषद के सदस्य अखबार पढ़ा करें ताकि जनता में जो कुछ हो रहा है, उस पर उनकी निगाह रहें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मंत्री परिषद् के सदस्यों के लिये भाई गिरधारीलालजी ने कहा कि स्वच्छ और सीधे सादे हैं। मेरा निवेदन है कि मुख्य मंत्रीजी उनको अभी सिखा रहे हैं। हमारे मंत्री परिषद के पास एक बहुत बड़ी असेट है और वह है माननीय मुख्य मंत्री महोदय के सचिव महोदय, शायद आप सबको उनके बारे में जानकारी नहीं है। सन् 72 के अगस्त से लेकर जब तक राज्य में जो गृह मंत्री रहे वे उनके पास काम करते रहे। इस पीरियड में जो व्यवस्था सीखी और जैसे कन्ट्रोल करना सीखा वह अपने आप में अनोखा है। आज यही कारण है कि राजस्थान पत्रिका को यह छापना पड़ा। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं जितने ऑफिसर्स हैं जिन्होंने भारत में इमर्जेन्सी के वक्त भी काम किया उनके रहते हुये व्यवस्था नहीं कर पाये। यहां पर एक ऐसे स्पेशल सेक्रेटरी रहे हैं मेहता, उनके असिस्टेन्स में हुआ ... (व्यवधान)...उसके बावजूद भी व्यवस्था में गड़बड़ी है जबकि उनका पूरा सहयोग हासिल है। यह नौकरशाही क्यों है?

मान्यवर, जहां तक मंत्री परिषद का सवाल है, हमारे मंत्री सबसे मिलते जुलते हैं और मिलकर संतोष देने की चेष्टा भी करते हैं। अब यह अलग बात है कि तकदीर खराब हो और असन्तोष रहे लेकिन मंत्री परिषद् के मंसूबे अच्छे हैं, इरादे अच्छे हैं। पहले कहीं कोई बात कांग्रेस के मंत्री करते थे, तो जो कुछ कहा करते थे, उसके लिये कह देते थे, ठीक है लेकिन जब-जब भी मैंने मुख्य मंत्री को सुना और जहां-जहां बयान आया उसको देखा, उनके विनम्र बयान आये उन्होंने किसी को छपाया नहीं। कोई गलती भी हो जाती है तो वे उसे मंजूर कर लेते हैं। उनकी इच्छा और मंसूबा हमेशा यही रहता है कि हम चीजों को सुधारना चाहते हैं। आज मंत्री परिषद् के प्रिवेलेज रखे गये हैं, उसको मैं मानता हूं। आज कहीं कोर्डिनेशन की बात भी आती है तो भी उनका कहना हम ठीक करना चाहते हैं। मैं एक निवेदन और कर देना चाहता हूं बहुत बार यह कहा जाता है, कांग्रेस 30 साल में गिरी और वह इसलिये गिरी। उसको फैल होने पर भी काफी मौका मिला। लेकिन आज वह प्रश्न नहीं है। आज जनता के सामने दूसरा आल्टरनेटिव है। वह कांग्रेस गई नहीं, खड़ी है। यह चर्चा अवश्य है कि अब जनता को आल्टरनेटिव दिख रहा है इसलिये जनता इन्तजार नहीं करेगी। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हमारे मंत्री परिषद को अग्नि परीक्षा के पांच वर्ष हैं। यदि हमने अपने इरादों को एक्जीक्यूट नहीं किया, अमल में नहीं लाये तो, कमजोर लोगों के लिये कुछ नहीं किया, यदि उनके आंसुओं को नहीं पोंछा तो इसके नतीजे खतरनाक ही निकलेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अब इन्तजारी का वक्त नहीं है। इसलिये मैंने तेजी से अमल करने की बात कही है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा मंत्री परिषद्

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

अनिश्चय की स्थिति से निकले । आप अन्दाज कीजिये इतने निगम हैं । उनके नॉन–ऑफिसियल्स चेअरमैन की घोषणा करनी है किन्तु आज तक ये निर्णय नहीं कर पाये कि कौनसे निगम में किसको बैठाना है। हमारे यू० आई० टीज० हैं उनके सदस्य जो पुराने एम. एल. एज. थे उनके स्थान पर दूसरे नये एम० एल० एज० सब्स्टीट्यूट करते । दूसरी बॉडीज हैं जैसे स्पोर्ट्स कौंसिल है उसमें भी जो पुराने लोग हैं वह काम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स कौंसिल का काम-काज आज भी काक साहब देख रहे हैं। कितनी अनिश्चित स्थिति के दौर में यह बाडीज चल रही हैं। जरा तेज चलिये ताकि निश्चितता की स्थिति में आये। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम इस बात को भूले हुए हैं, चपरासी और सिपाही का ट्रांसफर अगर गवर्नमेन्ट लेवल से हो तो इसका क्या संकेत है कि स्थिति कहां जायेगी। रुपया लीजिये पर ट्रांसफर पर मत खर्च कर दीजिये। रुपया तो लीजिये पर उसको गलीचों में मत खर्च कीजिये। ऐसे कामों में मत खर्चिये जिससे लोगबाग हमको उसी तरह से थमा दें। मंत्री परिषद् में और भी दिक्कते हैं। मैं यह निश्चित रूप से निवेदन करना चाहूंगा जो दांव पर लगे हुए हैं जो सामने बैठे हुए हैं, रोष जाहिर कर रहे हैं उनका पहले क्या हुआ, वह हाउस देख ले। मान्यवर, कुछ बातों...

श्री उपाध्यक्ष : आप तेज चलिये, इसी चर्चा पर आप इतना टाइम ले चुके हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : चिकित्सा का जहां तक सवाल है मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि यहां एक प्रीमियर इन्स्टीट्यूशन है, एस. एम. एस० हॉस्पिटल लेकिन पिछले कुछ दिनों से महसूस किया जा रहा है कि यहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन इन्स्टीट्यूट कायम किया जाये चंडीगढ की तरह। काबिल प्रोफेसर्स हैं यहां पर। आप पोस्ट ग्रेजुएशन इन्स्टीट्यूट कायम कीजिये।

जहां तक चिकित्सा का प्रश्न है, थोड़ी बात और निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, वह है चिकित्सा विभाग, जो बहुत बड़ी गड़बड़ी कर रहा है। पिछले दिनों मैंने एक प्रश्न उठाया था, मार्च, 77 में फूड इन्सपेक्टर्स की पावर्स ले ली थीं वह आज तक नहीं लौटाई गई। उसके बाद कोई सेम्पल नहीं लिया गया, कोई चालान पेश नहीं किया। यह निश्चित रूप से जनजीवन के साथ, लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ है। स्वास्थ्य मंत्री जी से चाहूंगा अपना उत्तर देते वक्त बतायें, कौनसा कारण था कि फूड इन्सपेक्टर्स को पावर्स नहीं दी गई।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इससे जाहिर होता है अडल्ट्रेशन को मिटाने में हमारी दिलचस्पी नहीं है।

चिकित्सा में चार पद्धति हैं। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी। यूनानी अल्पसंख्यकों की पद्धति है। सरकार उसके लिये कुछ नहीं करती। उसका कोई कॉलेज नहीं है। इसी तरह से आयुर्वेद वाले महसूस करते हैं उनके वेतनमानों में फर्क है। होम्योपैथी की हालत यह है कि बोर्ड बना रखा है। 5 लाख रुपया खर्च हो गया, 1971 से 1978 तक, उसमें दो ही काम हुए। कॉलेजेज का एफीलिएशन हुआ और दूसरा इम्तिहान होल्ड किये।

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

दो साल से 500 विद्यार्थी बैठें हैं उनका इम्तिहान नहीं हो रहा है। यदि यह काम यूनिवर्सिटी को दे दिया जाता जैसे बंगाल में, बिहार में दिया है, तो 15 हजार सालाना खर्च में यह काम हो जाता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जल्दी समाप्त करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : दुनिया में अगर सबसे कठोर दर्द होता है तो दांत का दर्द होता है। Even a philosopher cannot tolerate the pain. दांत की चिकित्सा का सवाल है, मान्यवर, मुझे मालूम हुआ कि यहां तो डेन्टल मेडिकल कॉलेज है नहीं, डेंटल एजूकेशन के लिये लोगों को जाग्रत करना चाहिये कि दांत कैसे स्वच्छ रखें। यहां कोई एजूकेशन की प्रापर व्यवस्था नहीं है। मैंने इस बारे में पत्र भी लिखा....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

है। इस ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

आयुर्वेद का तो हाल यह है कि एक जो निर्देशक बैठे हुए हैं, मंत्री महोदय का हुकम उनकी रद्दी की टोकरी में जाता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर की चिट्ठी आती है तो आर्डर सही है। इस ओर आयुर्वेद मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आयुर्वेद विभाग को सुधारें। उसमें सही व्यक्ति को नियुक्त करें।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं। यहां अभी बात हुई कि 15 करोड़ रुपये की योजना से अढ़ाई शति समारोह के अन्तर्गत जयपुर शहर को स्वच्छ कर दिया जायेगा। इस अढ़ाई शति समारोह के अवसर पर नाच और मुजरे चले इस तरह की हालत जहां पर हो, मान्यवर, उसके बजाय वह पैसा सफाई में खर्च होना चाहिये। दूर दूर से टूरिस्टस आते हैं जयपुर शहर में।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दूसरे मुल्कों में उनके रेडियो से सूचना दी जाती है, यह हिदायत दी जाती है अपने शहर को स्वच्छ रखिये। ऐसा काम मत करिये जिससे शहर मे गंदगी हो। मान्यवर, इस सदन में यह कहना सदन की गरिमा के अनुकूल है या नहीं कि सदन से बाहर जगह-जगह पीक थूक देते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आपका इस बात के लिये आभारी हूं, मुझको समय अधिक दे देते हैं...

श्री रतनलाल वर्मा : खुद खाते हैं दूसरों को शिक्षा देते हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : रतनलालजी वर्मा का मैंने सुबह से पान छुआ नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : काफी समय ले चुके हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : यदि सफाई की व्यवस्था कर दें तो निश्चित रूप से हमारी इमेज बढ़ेगी। गंदगी के नाले बह रहे हैं उनके साथ ही हमारी इमेज बहती जायेगी, कोई रोक नहीं पायेगा। स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि चिकित्सा की मेडिकल की व्यवस्था की तो सब कुछ स्वस्थ होगा और बीमारियां रहीं तो मंत्री परिषद् स्वस्थ नहीं रह पायेगा। मंत्री परिषद् का यहां पर इलाज हो जायेगा। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी माननीय सदस्य बोलें, 7-8 मिनट से अधिक समय न लें।

श्री मूलचन्द सामरिया !

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री परिषद् के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने फर्माया है उनसे मैं इस हद तक सहमत हूं कि मंत्रीगणों में कुछ लोग थोड़े से ऐसे हैं जो कि वास्तव में बहुत ही मिलनसार हैं, उनके पास बड़ी ईजी अप्रोच है लेकिन कुछ मंत्रीगण तो आज भी पब्लिक के लिए वास्तविक रूप से दुर्लभ माने जाते हैं। उनसे मिलना बहुत मुश्किल और परेशानी की बात होती है। जहां तक अन्य बातों का सवाल है, मैं यह निवेदन करूं कि सादगी और रहन-सहन से आदर्श उपस्थित करना चाहिए। मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री परिषद् के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी जोइन्ट होती है, मंत्री परिषद् की जिम्मेवारी संयुक्त होती है, अगर मंत्री परिषद् का कोई भी सदस्य किसी भी बात के लिए सार्वजनिक रूप से घोषणा करता है, या कहता है तो यह माना जाएगा कि यह राजस्थान सरकार की घोषणा है अगर राजस्थान सरकार के किसी मिनिस्टर की घोषणा होने के बाद भी उस पर पूरी तरह से अमल न हो अथवा मंत्री परिषद् के विभिन्न सदस्यगणों की उस पर विभिन्न प्रकार की राय हो, तो मैं यह समझता हूं कि इससे जनता पार्टी की सरकार की, मंत्री परिषद् की इमेज धूमिल होती है। लोगों की निगाह में अविश्वसनीय स्थिति उपस्थिति होती है।

मान्यवर, राजस्थान मंत्रिमंडल में मास्टर आदित्येन्द्रजी जो कि राजस्थान के गांधी के नाम से जाने जाते हैं, बहुत ही अनुभवी, स्वतंत्रता संग्राम में काम किए हुए व्यक्ति, आदर्शवादी, गांधीयन विचारधारा से ओतप्रोत हैं। उन्होंने राजस्थान में जिलों की विभिन्न, असमानता, और लम्बाई-चौड़ाई को देख कर धौलपुर में स्टेटमेंट दिया कि मैं इसको वाजिब मानता हूं कि प्रशासनिक दृष्टि से कुछ नए जिले बनाये जायं। इसी तरह का स्टेटमेंट माननीय वित्त मंत्री महोदय ने दौसा में भी दिया जब वे सैकन्डरी स्कूल के किसी फंक्शन में आए थे। उस समय यह भी फर्माया था कि इसमें वित्तीय साधनों की कमी किसी भी तरह से रास्ते में नहीं आयेगी, मेरी ऐसी मान्यता है। उसके बावजूद मुख्य मंत्री जी ने इसके विपरीत, इसके बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट दिया कि इस बारे में हम विचार भी नहीं कर रहे हैं। इससे एक प्रकार से जनता की निगाह में मंत्री परिषद में मतैक्यता के अभाव, विभिन्न विचारधारा और मनमाने तरीके के स्टेटमेंट देने की धारणा पैदा होती है। इससे मंत्री परिषद् का स्वरूप जनता के सामने यही होगा। आज चीफ मिनिस्टर महोदय, मुख्य मंत्री महोदय इस प्रदेश के वित्त मंत्री और इतने बड़े-बड़े मंत्रीगण कोई बात पब्लिक के सामने अलग-अलग तरीके से कहते हैं तो इससे जनता के सामने एक प्रश्न उठता है कि क्या मंत्री परिषद् के लोगों में अलग-अलग तरीके की विचारधारा है? वे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अथवा उसकी बात को गिराने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं? इससे निश्चित तौर से

(श्री मूलचन्द सामरिया)

मंत्री परिषद् के प्रति लोगों में अविश्वास पैदा होगा। मान्यवर, मैं यह निवेदन करूंगा कि आज जो कुछ मास्टर आदित्येन्द्रजी ने फर्माया है अगर वह चीफ मिनिस्टर के अनुसार सही नहीं है तो किसी मंत्री का स्टेटमेंट किसी जगह पर दिया हुआ किस तरह से सही होगा, उस पर जनता किस तरह से भरोसा करेगी? इसलिए सबसे मुख्य बात तो यह निवेदन करनी है कि मंत्रियों को स्टेटमेंट बिलकुल सोच समझ कर देने चाहिएं। मैं समझता हूं कि मास्टरजी ने सचमुच इतनी उचित और न्यायपूर्ण तरीके की बात कही, उससे अगर चीफ मिनिस्टर महोदय सहमत नहीं थे तो कम से कम चुप रहते और समय का इन्तजार करते तो ज्यादा उपयुक्त होता। इस तरह के स्टेटमेंट से मंत्रियों की साख पब्लिक में गिरेगी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सामरियाजी, आप कृपया अपना भाषण जारी रखें।

श्री मूलचन्द सामरिया : इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो कुछ उन्होंने फर्माया उसकी पूर्ति की जाए। इस बारे में चीफ मिनिस्टर महोदय को अपना स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। जो कुछ वित्त मंत्री ने किन्हीं भी परिस्थितियों में कह दिया, उस डिक्लेरेशन को पूरा किया जाना चाहिए था, जिससे मंत्री परिषद् के सदस्यगणों की साख पब्लिक में बहुत ऊंची होती। शायद इसके जवाब में यह फर्माया जावेगा कि यह उनकी व्यक्तिगत बात थी, मंत्री परिषद् का निर्णय नहीं था। इस तरह का स्टेटमेंट व्यक्तिगत रूप से पब्लिक में देने के कारण गलत धारणायें पैदा होती हैं कि घोषणाओं को पूरा तो कर नहीं सकते। इसलिए बेहतर यह होगा कि वित्त मंत्रीजी ने जो घोषणा की, जिलों के पुनर्गठन की, उसको पूरा कर देना चाहिए, जिससे जनता की इस तरह की धारणा नहीं रहे। एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं।

जहां तक चिकित्सा का प्रश्न है, दौसा में पहले एक जिले का मलेरिया उन्मूलन का ऑफिस था। चूंकि वहां पर सन् 1952 के बाद कांग्रेस का कोई एम. एल. ए. नहीं रहा, इसलिए इसको भी दौसा से हटा दिया। इसी तरह से डी. एम. एच. ओ. जिसको आजकल सी. एम. ओ. कहते हैं, का ऑफिस था। कांग्रेस की सरकार रहने के बावजूद भी कांग्रेस का कोई एम. एल. ए. वहां से नहीं जीता, इसलिए राजनैतिक विद्वेष से उस डी. एम. एच. ओ. के ऑफिस को भी वहां लाकर रख दिया है। आज आप परिवार कल्याण के नाम पर स्वेच्छा से प्रेरित करके परिवार कल्याण की बात तो कहते हैं लेकिन इसको प्रचारित, प्रसारित करने के लिए, देहातों में इसका प्रचार करने के लिए, जो दो कार्यालय हैं, उनमें से एक कार्यालय दौसा में होना बहुत ही जरूरी है।

इसके अलावा, मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे यहां जो भी कोई काम होते हैं, सब बड़े-बड़े शहरों में होते हैं। कॉलेज खोलना हो तो बड़े-बड़े शहरों के अन्दर खोलते हैं। सरकार की तरफ से बिल्डिंग भी बनेगी, सरकार की तरफ से ही सारी सहूलियतें होंगी, तो वह शहरों में होंगी। देहात में एक छोटा-सा स्कूल खोलना होगा, प्राइमरी

(श्री मूलचन्द सामरिया)
स्कूल बनेगा तो भी गांव वालों से कहा जाएगा कि स्कूल की बिल्डिंग बनाओ। यही स्थिति मेडिकल डिपार्टमेंट की है। मेडिकल कालेज यहां पर, एस. एम. एस. हॉस्पिटल यहां पर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल, जनाना हॉस्पिटल सब तरह के हॉस्पिटल यहां पर हैं। उनके सभी काम सरकार की तरफ से होते हैं। देहात में अगर लोग पैसा नहीं देते हैं, अपनी बिल्डिंग नहीं बनाते हैं तो कोई भी सहूलियत सरकार की तरफ से नहीं दी जाती है। हर क्षेत्र में इसी तरह की स्थिति है। शहरों में एक तरफ सौंदर्यीकरण के नाम पर लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं, दूसरी तरफ गांवों में आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं होती है। ठीक इसी तरह से चिकित्सा क्षेत्र में भी देख लीजिए। देहात में मातृ-शिशु कल्याण केन्द्र नहीं होने से, रोगग्रस्त को जीप में लेकर आना पड़ता है, दो तीन सौ रुपये खर्च हो जाते हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो-तीन मिनट और लूंगा।

सुविधाओं के अभाव में, और इतना समय लगने की वजह से बहुत सी माता और बहिनों की मृत्यु हो जाती है जबकि सारा कन्सन्ट्रेशन शहरों में करना चाहते हैं। इसलिए मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि जहां बड़े-बड़े कस्बे हैं वहां पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्थापित करने चाहिए। जयपुर शहर में तो दूसरे और लोगों की देख-रेख में ही डॉक्टर लोग व्यस्त रहते हैं, उनको बहुत कम समय मिलता है। बड़े-बड़े डॉक्टर देखते ही नहीं हैं। देहातों के अन्दर इस तरह की व्यवस्था होगी तभी दबाव कम होगा और गरीब लोगों को, किसानों को आस-पास के क्षेत्र में इस तरह की सहूलियतें मिलेंगी।

एक बात और निवेदन करूंगा। पंचायत चान्दराना में एक यूनानी दवाखाना खोला गया, पंचायत हैड क्वार्टर पर। लोग कहते हैं कि उसका यहां पर कोई उपयोग नहीं हो रहा है। मेहरबानी करके उस यूनानी दवाखाने को दौसा शिफ्ट कर दें और वहां पर आयुर्वेदिक अस्पताल की व्यवस्था कर दें ताकि उसका उपयोग हो सके। यूनानी दवाखाना चान्दराणा, तहसील दौसा में है उसको दौसा शिफ्ट कर दें तो वहां के लोगों को आयुर्वेद औषधालय का लाभ मिल सकेगा और वैद्य आदि के पास भी दौसा में काम रहेगा। आज बड़े-बड़े शहरों में आयुर्वेदिक औषधालय हैं लेकिन हमारे यहां एक भी आयुर्वेदिक औषधालय किसी भी ग्रेड का नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि दौसा 20-25 हजार की आबादी का शहर है, उसके बारे में सरकार को इस तरह से उदासीन नहीं रहना चाहिए। इसी बजट में आप आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की, मैं समझता हूं, स्वीकृति करेंगे।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजय सिंह नबेरा;

(अनुपस्थित)

श्री मनोहरसिंह मेहता!

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : उपाध्यक्षजी, मैं मंत्री परिषद् के बारे में पहले निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री रामकरणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह लिस्ट कौनसी है ? एक लिस्ट में...

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, इनकी बाद में सुनियेगा ।

श्री रामकरणसिंह : क्रम से यह है गिरधारीलाल भार्गव, बजरंगलाल शर्मा, श्रीमती उजला अरोड़ा, गुल मोहम्मद । यह दूसरी कौनसी लिस्ट शुरू हो गई ?

श्री उपाध्यक्ष: आज के लिए जो कटौती प्रस्तावों की है उसी क्रम से बोल रहा हूं ।

श्री अब्दुल अजीज : आप इस लिस्ट में देखिए ।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया अपनी लिस्ट मेरे पास भिजवादें ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री परिषद् के बारे में जितने भी कटौती प्रस्ताव आये हैं अधिकांश इस बात के लिए हैं कि मंत्रियों को सादगी से रहना चाहिए, मोटरों का कम उपयोग करना चाहिए । जब इतने सारे विधायक निवेदन कर रहे हैं तो फिर मान लें । हमारी बात का असर नहीं होता है तो हमको सोचना चाहिए कि कहीं हमारे में तो कोई कमजोरी नहीं है । 1 किलो शक्कर को ब्लेक से बेचने वाला है ऐसे किसी व्यक्ति को जब एक बोरी कन्ट्रोल की शक्कर की मिलती है वह उसका ब्लेक करता है और बड़े-बड़े लोगों से कहता है कि ब्लेक मत करो तो उसका असर नहीं होता है चाहे उसने कम ब्लेक किया हो । कम ब्लेक इसलिए किया है कि उसको कम मिली अगर उसको ज्यादा मिलती तो ज्यादा करता । हम फर्स्ट क्लास का किराया लेते हैं और प्रथम श्रेणी में 12 हजार किलोमीटर रेल से यात्रा की सुविधा लेते हैं । उस पर ध्यान नहीं देते हैं । पहले जब एम. एल. एज. नहीं थे तो मेडिकल रिएम्बर्समेंट का प्रश्न नहीं था, लेकिन अब पूरे परिवार के लिए रिएम्बर्समेंट हो रहा है जबकि गांव के लोगों को दवाएं नहीं मिल रही हैं और वे बिना दवा के मर रहे हैं । जब हम त्याग नहीं कर सकें और मंत्रियों को कहें तो कैसे हमारी बात का असर होगा ? मुझसे कहते हैं कि आपने सैकण्ड क्लास में बैठना शुरू कर दिया है, मेडिकल रिएम्बर्समेंट नहीं लेते हैं और चेयरमन होते हुए भी टेलीफोन नहीं लगाया तो भी आपकी बात क्यों नहीं मानते हैं ? इसलिए नहीं मानते है कि मैं 51 रुपये रोज के लेता हूं । जिस दिन से मैं 51 रुपये से कम लेना शुरू कर दूंगा तो मेरी बात का ज्यादा असर होगा ।

इसमें शक नहीं है कि हमारे मन्त्री ईमानदार हैं, सच्चे हैं लेकिन हमें सोचना चाहिए कि राम को केवल एक बालि वध के अपराध पर लोगों ने बख्सा नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर एक बार ही झूठ बोले थे, एक बार उनसे चूक हुई थी तो लोगों ने बख्सा नहीं, विश्वामित्र से केवल एक बार चूक हुई थी तो लोगों ने बख्सा नहीं । जिसको हृदय में स्थान देते हैं उनकी छोटी-सी चूक को लोग बख्सते नहीं हैं और हृदय से निकाल देते हैं । तो फिर भी भारी दोषों पर भी ध्यान नहीं देते हैं जैसे:—

काली ने देखे कुणी, रिया मोकला लाग ।
धोली चादर ऊपरे, फबे न कालो दाग ।

सफेद चादर पर एक भी दाग होगा तो साफ नहीं लगता है । फिर अगर हम यह मुकाबला करें कि कांग्रेस के वक्त कितना खर्च होता था और अब कितना खर्च होता है, यह न्यायसंगत बात नहीं है ।

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

हमने शपथ खाई है गांधीजी की समाधि के सामने। मिनिस्टर बसों में क्यों न जायं? यहां से जायें तो सिटी बस में जाये। कभी अपने क्षेत्र का दौरा करें तो बसों में बैठकर जायें तो उनको सारी स्थिति मालूम होगी। स्विटजरलैण्ड का राष्ट्रपति जब बस में जा सकता है, क्यू में खड़ा हो सकता है, तो मंत्री बस में क्यों नहीं जा सकते? जनता पार्टी का घोषणा-पत्र है उस लिहाज से मैं आशा करूंगा कि हर तीसरे महीने आप हिसाब दें कि टेलीफोन पर कितना खर्च हुआ है, मोटर पर कितना खर्च हुआ और यात्रा पर कितना खर्च हुआ है? इस तरह से हमेशा हिसाब देंगे तो ठीक रहेगा और सच्चे जनता के सेवक होंगे।

श्री मूलचन्द डागा : हम भी जनता के सेवक हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : हर मंत्री के काम से खुशबू निकलनी चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : मंत्री लोग कान में कन्नोज का इत्र लगा लें तो खुशबू निकलेगी काम से।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैंने काम के लिए कहा है। हर काम से खुशबू निकलनी चाहिए। मेडिकल रिएम्बर्समेंट के बारे में कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की कई पंचायतों में न दवाखाना है और न सड़क है। कई लोग बिना दवा के मरते हैं। आप कम से कम इतना तो करें कि हर पंचायत हैडक्वार्टर पर चाहे किसी तरह का दवाखाना खोल दें, एक मैट्रिक पास आदमी को तीन महीने की ट्रेनिंग देकर फर्स्ट-एड का काम सिखा दें ताकि वह पट्टी तो बान्ध सके...

श्री अब्दुल अजीज : नीम हकीम खतरा-ऐ-जान।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप कृपया सुन लें।

श्री अब्दुल अजीज : आप दवा दिलायेंगे नीम हकीम से?

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैंने फर्स्ट-एड के लिए कहा है। जो बेकार बैठे हैं उनको यह ट्रेनिंग दे दें तो कुछ लोगों को तो जगह मिलेगी। उससे नाइट स्कूल भी चलवा लें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो नौकर हैं चाहे उसको ढाई हजार की तनख्वाह मिलती हो चाहे 150 की तनख्वाह मिलती हो, उसको पूरी सिक्योरिटी है। मेडिकल रिएम्बर्समेंट पूरे परिवार के लिए मिलता है। क्या आप यह बंद नहीं कर सकते हैं? मैं यह भी सुनता हूं कि इसमें दुरुपयोग होता है। कोई झूठा बिल बनाता है, तो उसको फांसी पर लटकाया जाय, डॉक्टर बिल बनाता है तो उस डॉक्टर को फांसी पर लटकाया जाय। यह नहीं होता होगा, ऐसा जघन्य अपराध कोई करता नहीं होगा, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। क्यों देते हैं आप नौकरों को दवा की सुविधा, गांवों में दवा का साधन नहीं है। अगर खुशबू शुरू होगी तो मंत्रियों से शुरू होगी, अगर खुशबू शुरू होगी तो एम.एल.एज. से शुरू होगी, अगर खुशबू शुरू होगी तो अधिकारियों से शुरू होगी, लेकिन कहां हो रही है?

हमारे मुख्य मंत्रीजी संकल्पबद्ध हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने रास्ता गांधीजी का पकड़ा है। ईमानदार हैं इसमें कोई शक नहीं है। भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, लेकिन मिटेगा कैसे, जबकि बहुत से

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
अधिकारी शराब पीते हैं इसको आप बन्द कीजिये और जल्दी से जल्दी शराब पीने वाले अधिकारियों को डिसमिस कीजिये। जो एम.एल.एज. शराब पीते हैं, जो मंत्री शराब पीते हैं उनको पदमुक्त किया जाय, तब यह खुशबू निकलेगी।

एक माननीय सदस्य : कितने मंत्री पीते हैं ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : अगर कोई पीते हों तो बन्द करें। मेरे ख्याल से मंत्री नहीं पीते हैं।

एक माननीय सदस्य : पीते हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : पीते हैं तो गलती करते हैं। इससे जो कांग्रेस की गति हुई है वही हमारी भी होगी। जब भगवान कृष्ण के वंशज भी शराब पीने से बरबाद हो गये तो औरों की तो बिसात ही क्या है।

अब मैं अपने क्षेत्र के कुछ गांवों के नाम बताऊंगा जहां कोई दवाखाना नहीं है, लेकिन क्या करें ? किसके पास जायें। पंचायतों के हैडक्वार्टर पर औषधालय नहीं हैं। कृपा करके मेडिकल रिएम्बर्समेंट का पूरे राजस्थान का खर्चा बचा कर छोटी-छोटी जगहों पर दवाखाने या एड-पोस्ट लगाने की बात करें। इससे लोगों को राहत मिलेगी। हमारे हर काम के ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी। तीन महीने में सब का हिसाब देखें। मैं इतनी ही बात कहकर बैठना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा !

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, हम दो डिमाण्ड्स आज ले रहे हैं। दो नम्बर की डिमाण्ड पर जिसका कटौती प्रस्ताव जिस नम्बर पर आया है उसी क्रम से उसमें लिखा गया है। इसी प्रकार से डिमाण्ड नं. 26 पर जिस प्रकार से कटौती प्रस्ताव आये हैं उसी नम्बर से उसमें लिखे गये हैं। किसी ने 2 नम्बर की डिमाण्ड पर कटौती प्रस्ताव नहीं दिये हैं और 26 नम्बर की डिमाण्ड पर दिये हैं और आप 2 नम्बर की डिमाण्ड की लिस्ट में से नाम क्रम से बोल रहे हैं तो उनका क्या होगा जिनके कटौती प्रस्ताव केवल 26 नम्बर पर हैं ? उनका नम्बर कब आयेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो भी नाम लिये गये हैं कटौती प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए वह एन्टायर्ली पूर्व परिपाटी के अनुसार लिये गये हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि दो डिमाण्ड एक साथ हम ले रहे हैं तो मांग संख्या 2 की जो लिस्ट है उसके हिसाब से ले रहे हैं ? मांग संख्या 26 पर जिनके कटौती प्रस्ताव 1, 2, 3 नम्बर पर आये हैं, मांग संख्या 2 की लिस्ट में उनका कतई नाम नहीं है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है ?

श्री उपाध्यक्ष : दो मांगों पर संयुक्त रूप से चर्चा चल रही है तो मांग पर जिन्होंने कटौती प्रस्ताव जिस क्रम से दिये हैं उसी आधार पर सूची बनाई गई है।

श्रीमती मदन कौर : उपाध्यक्ष महोदय, इनका प्रश्न यह है कि दो डिमाण्ड्स ली जा रही हैं तो दोनों डिमाण्ड पर जिनके कटौती प्रस्ताव हैं उनका क्रम तो ठीक है परन्तु जिनका कटौती प्रस्ताव केवल मांग संख्या 26 पर ही है उनका क्रम कैसे तय किया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आज दो मांगों पर चर्चा की जा रही है, मांग संख्या 2 और मांग संख्या 26। पहले मांग संख्या 2 पर चर्चा के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। मांग संख्या 2 में जिनके नाम आये हैं तो दोनों को संयुक्त रूप से प्राथमिकता देकर चर्चा करने के लिए क्रम बनाया गया है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष, जिस क्रम में मांग संख्या 2 पर जिन माननीय सदस्यों के नाम हैं उनका नम्बर समाप्त होने पर ही 26 नम्बर पर विचार किया जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह संभव नहीं है कि सारी स्थिति को स्पष्ट करूं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले में अगर कोई माननीय सदस्य चर्चा करना चाहें, जानकारी लेना चाहें तो वे चेम्बर में आकर मिल लें। सचिवालय से जानकारी ले लें। पहले कहना चाहें या इस क्रम में संशोधन करना चाहें तो इस समय संशोधन या परिवर्तन करना संभव नहीं है।

श्री रामकरण सिंह : मैं तो आसन से व्यवस्था चाहता था। मेरा मांग संख्या 2 पर कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है। मांग संख्या 26 पर मेरा कटौती प्रस्ताव क्रम संख्या 4 पर है। मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता था कि क्या मांग संख्या 2 के कटौती प्रस्ताव पूरे हो जाने के बाद मांग संख्या 26 के प्रस्तावों को लिया जाएगा या उसके पहले ? पहले 26 पर विचार होगा या नहीं ? इस तरह की व्यवस्था चाहता था।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया बतायें कि आपकी क्रम संख्या सूची में क्या है ?

श्री रामकरण सिंह : मांग संख्या 26 को लिस्ट में चौथे नम्बर पर है।

श्री उपाध्यक्ष : वक्ता महोदय, जो सूची है उसका आप निरीक्षण कर लें। उसके बाद मे उचित व्यवस्था दे दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा !

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि जनता पार्टी ने समग्र क्रान्ति का नारा दिया है। इसलिए इस पार्टी को, विशेष कर जनता पार्टी के मंत्रियों को आदर्श उपस्थित करना चाहिए। जो पिछली परंपराएं चल रही थी वे विलासिता और ऐशो आराम की थी। वे परंपराएं इस समय कतई नहीं चलनी चाहिए और एक आदर्श उपस्थित करना चाहिए।

इसके साथ ही हमें मितव्ययता करनी चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि सिविल लाइन के जो बंगले हैं, मंत्री महोदय उनमें न रहें। जो बड़े-बड़े महंगे दफ्तर किराये पर लिए जाते हैं उनको भी न लिया जाए और केम्पस बनाय जाएं। सिविल लाइन के इन बंगलों में इन दफ्तरों की व्यवस्था की जाए। जो मंत्री महोदय अपने निजी घर में रहते हैं, वे अपने निजी घर में ही रहें। जिनके निजी घर नहीं हैं वे एम.एल.ए. क्वार्टर्स जो बने हुए हैं उनमें रहें। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगी कि पहले की जो परम्परा है, कि जिनके निजी घर थे, वे किराये पर चढ़ा कर सरकारी बंगलों में शिफ्ट हो जाते थे, यह एक संकुचित नजरिया है। मेरा निवेदन है कि जो किराये के मकान में रह रहे हों वे ही सरकारी मकानों में शिफ्ट

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

करें ऐसी परम्परा हम समाज में रखेंगे तो अच्छा रहेगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगी, हमारे मुख्य मंत्री जब विपक्ष में थे तब वे कहा करते थे कि एक ऐसा आदर्श उपस्थित करना चाहिए कि मार्च के महीने में खरीद न हो। इस महीने में अनाप-शनाप खरीद होती है। इस तरीके की खरीद की परम्परा है कि साल भर खरीद नहीं करते हैं और मार्च का महीना आते ही खरीदते हैं। यह गलत है। मेरा निवेदन है कि विपक्ष के जो नेता हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जावे। दोनों पक्ष के विधायक उसमें हों। वे इस पर कन्ट्रोल करें कि चीजों की जो खरीद हो वह गलत न हो। गलत खरीद होती है तो उस अधिकारी को उत्तरदायी बना कर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इससे हमारी धनराशि गलत काम में खर्च नहीं होगी।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो सेक्रेटेरियट में ठंडा-गर्म संयंत्र लग रहा है, वह अविलम्ब रोका जाए। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हर कमरे में दिन में भी ट्यूब लाइट जलती है। यहां सदन में तो अन्धेरा है, इसलिए लाइट की आवश्यकता है। सेक्रेटेरियट के उन कमरों जहां दिन का पूरा-पूरा प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, में भी दिन में ट्यूब लाइट जलती हैं। वह भी एक नहीं कई जलती हैं। इसके बावजूद जो अधिकारी होते हैं उनकी टेबल पर टेबल लैम्प रहता है। वह उसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार हमारी काफी राशि अनाप-शनाप खर्च होती है, इसको रोका जाना चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि इससे दस करोड़ रुपये का खर्च बचाया जा सकता है। ट्यूब लाइट हमारे दफ्तरों में हर कमरे में, चाहे वह अधिकारी का कमरा हो, चाहे मंत्री महोदय का कमरा हो, जलती है। इसी प्रकार इनके कमरों में दरियां रहती हैं। हम लोग सामान्य घरों में रहते हैं। इनके खुद के घरों में दरियां नहीं हैं। ये दरियां ऐसे बिछायी जाती है कि बाद में कट जाती हैं। हर दूसरे वर्ष नई दरियां खरीद कर यहां पर बिछायी जाती हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि...

श्री मूलचन्द डागा : आदर्श की बात है महबूब अलीजी नोट कर लो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह दरियां नहीं खरीदी जाएं।

इसके अलावा माननीय सदस्य मनोहर सिंह जी मेहता ने बात कही है मैं उसका समर्थन करती हूं। मैंने कई बार अस्पतालों में डाक्टरों, दफ्तरों में अधिकारियों, थानों में जो अधिकारी सुरक्षा का काम करते हैं, उन्हें ड्यूटी के टाइम पर शराब पिए हुए धुत्त देखा है। हमारे मंत्री परिषद् का यह कर्तव्य है कि ऐसे लोगों के खिलाफ वह कार्यवाही करें और इसको बंद करने के लिए जल्दी से जल्दी कदम उठायें।

मैं खाद्य सामग्री के संबंध में भी निवेदन करना चाहूंगी। बाजारों में जो चीजें मिल रही हैं, उनका सैम्पल लिया जाना बंद कर दिया गया है। व्यापारी मसालों दालें, आटा, बेसन व अन्य प्रकार के तेलों में मिलावट कर रहे हैं। मैं यह मानती हूं कि मिलावट की चीजें उपलब्ध कराना जहर के बराबर है। हमारे सामान्य नागरिक, जिनको इनका ज्ञान नहीं है बाजार से ये चीजें लेते हैं। इसका दुष्परिणाम कभी-कभी मृत्यु तक हो जाता है।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

इसलिए मंत्री महोदय अविलम्ब स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दें कि वे सेम्पल लेना शुरू करें जिससे बंदिश लग सके और खुले आम जहर का व्यापार रोका जाए।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि स्थानीय लेवल पर नकली दवाइयां बन रही हैं। समय-समय पर इनकी जांच हो तो अच्छा रहेगा। कई कारखाने, फैक्टरियां ऐसी हैं जो गलत, नकली दवाइयां बना रही हैं। श्रीमन् इनकी छानबीन की जा सकती है। जहर शरीर में प्रविष्ट हो जाता है तो उसको निकालना असंभव है। समाज के जनजीवन की रक्षा के लिए दवाइयों की चैकिंग होना भी नितान्त आवश्यक है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय यहां पर बैठे हैं, वे पहले चिकित्सा मंत्री रहे हैं। मेरे क्षेत्र में एक मोती कटला डिस्पेंसरी है। वह 92 बल्लियों पर खड़ी हुई है। उसके लिए पी० डब्ल्यू० डी० ने कह दिया है कि यह बिल्डिंग, यह भवन कभी भी गिर सकता है। इससे वहां एक डर पैदा हो गया है। 92 बल्लियों पर वह भवन टिका हुआ है। कभी भी वहां के डॉक्टर, स्टाफ मरीज मर सकते हैं। तीन हजार रुपया इसके लिए मन्जूर किया गया है। मैं डाइरेक्टर, पुरोहितजी को 6 महीने से ढूंढ रही हूं परन्तु वे कहीं नहीं मिल पाते हैं। उनका कहीं अता-पता नहीं है। ऐसे डाइरेक्टर को बिठाने से क्या फायदा जो अधिकतर दिल्ली ही रहता हो। मैं किसी अधिकारी की व्यक्तिगत आलोचना के पक्ष में नहीं हूं, परन्तु मेरे क्षेत्र के लोग जब दुःखी होकर बार-बार कहते हैं तो मुझे यह बात सदन में कहनी पड़ रही है। मैं मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहती हूं कि वे अपने कर्तव्य पर ध्यान दें। मंत्री महोदय ने पिछले सत्र में यहीं पर कहा था कि सात दिनों में इसका कार्य शुरू हो जाएगा। वे कृपया इस कटौती प्रस्ताव के उत्तर में मुझे यह बतायें कि सात दिन तो क्या छः महीने हो गये, यह कार्य अब तक शुरू क्यों नहीं हुआ है ?

मेरे क्षेत्र के सम्बन्ध में एक निवेदन और करना चाहूंगी। भूतपूर्व मुख्य मंत्री, जोशीजी ने एक अस्पताल का उद्घाटन किया था। उन्होंने उस समय विपक्ष की कड़ी आलोचना की थी कि इस क्षेत्र से विपक्ष का प्रतिनिधि बना हुआ है, इसलिए काम नहीं हुआ है। मैं उस समय जेल में थी। अब हमारी सरकार आई है। परन्तु अभी तक उस अस्पताल में पोस्ट क्रियेट नहीं हुई है। दस बेड का यह अस्पताल है, जो बेकार पड़ा है। न दवाईयों का बजट है .......

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आभारी होऊंगी यदि कुछ समय मुझे और दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बहुत-सी बात कह चुकी हैं। आपके इतने प्रस्ताव नहीं हैं। अब जल्दी समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि एक आचार्य हैं, वह आयुर्वेदाचार्य हैं, भिषगाचार्य हैं, उन्होंने छः महीने तक वेतन न पाने के कारण इस्तीफा दे दिया। मैंने इस संबंध में आयुर्वेद मंत्री महोदय से भी कहा कि दुःख है उसे हटा दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की मेरे क्षेत्र के गांवों में जो व्यवस्था है, उसका मुझे बहुत अफसोस है।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से आपरेशन टेबल पर रोगी को जीवित रखने आदि के लिए जो मशीनें चलती हैं, वह सभी बिजली से चलती हैं। उसके लिए अलग से विद्युत की व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब बिराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसी प्रकार से ब्लड उपलब्ध होने के बारे में निवेदन है, जो गांवों से आते हैं दूसरा कोई उनके साथ में नहीं होता है। उनके लिए ब्लड की व्यवस्था हो। चारपाइयों पर 4 साल पुराने गद्दे रखे जाते हैं। बजट में वह नये दिखाये जाते हैं। ऐसा दुकानों से लाये जाते हैं, जहां 6-6 साल के सड़े गद्दे बेचे जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : समाप्त कर रही हूं।

अस्पतालों की स्थिति को सुधारा जाये। टी.बी. सेनेटोरियम है उसकी व्यवस्था को सुधारा जाये।

होम्योपैथी शिक्षा के लिए कोई बजट नहीं है। पिछली सरकार ने वायदा किया था कि होम्योपैथी कालेज को सरकार ले लेगी। सरकार उस वायदे को पूरा करे।

इसी प्रकार से यूनानी और आयुर्वेद के बारे में भी मैं सुझाव दूंगी। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि गांवों की जो समस्याएं हैं, उनको हल किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब आप बिराज जायें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जब तक व्यवस्था नहीं हो तब तक....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मोबाइल डिस्पेंसरी की व्यवस्था की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, रामकरण सिंह ने अपनी समस्या कही। कुल 55 कटौती प्रस्ताव हैं, जो इस संबंध में प्राप्त हुए हैं। वक्ता महोदय का नाम 53 नम्बर पर है। मेरा ख्याल है, जो नियम है, उसी क्रम से नाम पुकारे जायेंगे।

माननीय श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : श्रीमान् मैंने जनता पार्टी का घोषण पत्र पढ़ा। मुझे इसीलिए उसको याद दिलानी है कि उसमें यह कहा गया था कि हम सच्चाई और सादगी का कड़ाई से पालन करेंगे। कांग्रेस के मंत्री लोग जिस तरीके से रहते थे उस तरीके से हम नहीं रहेंगे। यह आपका 29 सूत्रीय घोषणा-पत्र है। जब यह पढ़ा तो बड़ा आश्वासन मिला लेकिन जब बजट देखा तो मालूम हुआ कि खर्चा बढ़ गया। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं जब बजट बनाया, जिस तरह के बजट के लिये हमारी टीका टिप्पणी करते थे उसी तरह जो बजट 34 लाख 6 हजार का बनता था वह अब 38 लाख का हो गया है। मैं कहना चाहता हूं कि मंत्रिमण्डल पर 4 लाख का खर्चा बढ़ा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अनुदान के लिये बनाया है। आपने कहा है, हमारा पुराना

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
कर्जा रह गया है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्या, बिराज जायें।

श्री मूलचन्द डागा : आपकी गाड़ियों के पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया है। मन्त्रियों के निवास पर जल बिजली का 1 लाख 85 हजार का खर्चा हो गया है। यह खर्चा 1 लाख 85 हजार हो गया फिर भी आपका जो मिनिस्टर सैलेरी का एक्ट है, रूल्स हैं, उसमें कोई संशोधन नहीं है। आपकी घोषणाएं सारी की सारी ऐसी ही हैं। एक मन्त्री अपने पूरे परिवार को लेकर सारे राजस्थान में घूम सकता है। एक मंत्री पर 1 लाख रुपया एक महीने का पड़ता है। एक मिनिस्टर के घर पर 3 गार्डनर, 2 चिपरासी, 4 सेक्रेटरी रहते हैं। मैंने हिसाब लगाया, एक मंत्री पर एक महीने में कम से कम एक लाख रुपया सारे एस्टेब्लिशमेण्ट का खर्चा है। यह जनता सरकार का बजट है इसमें गार्डनर नहीं दिया है, पुलिस कुनिन्दा नहीं दिया है फिर भी इतना खर्चा है। इस खर्चे में से पिछली सरकार ने मकान बनाये हैं। आपने कितने नये मकान बनाये हैं ? आपके मिनिस्टर बनने के बाद कितनी कोठियां बनीं? कितने मंत्री बनाये? पूनिया साहब को बनाया नारे लगे कि हमको मन्त्री नहीं बनाया। जनता पार्टी के खिलाफ नारे लगे हैं। हम तो कहते हैं, गलती हमारी थी। लेकिन भ्रष्टाचार तो रोकना चाहिए था। आपके टेलीफोन का खर्चा बढ़ गया। रूल्स से आपका कितना खर्चा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उसकी फीस बढ़ गई है।

श्री मूलचन्द डागा : कितनी फीस बढ़ गई है ? मैं बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूं

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह बीच में यह क्या बात कर रही है ?

श्री मूलचन्द डागा : यह सारा काम मुख्य मन्त्री पर डालो तो उतना ही ज्यादा मुख्य मन्त्री को खर्चा भी मिलता है। आपको कम खर्चा मिलता है। हमको चाय कम पिलाती हैं, आप।

श्रीमान्, मुख्य मन्त्री का खर्चा पहले से ज्यादा हो गया है। दो लाख रुपया आपने खर्चा बढ़ा दिया है। वह खर्चा करते हैं। आपका खर्चा 75 हजार है। सभी मन्त्रियों का अब 1 लाख 50 हजार हो गया है। ये आंकड़े इस बजट में हैं जो बजट आपने पेश किया है इसके रूल्स बने हुए हैं। आप कहेंगे, हमने बजट के अनुसार खर्चा किया है। लेकिन इस बजट में घाटे के होते हुए भी आपका खर्चा बढ़ गया है। जनता पार्टी जनता के काम करना चाहती है। आदरणीय वित्त मन्त्रीजी का जो भाषण है वह चमत्कार है। यह आदर्श आपको मजबूत रख रहे हैं। आप कहते हैं मन्त्रिमण्डल में भ्रष्टाचार नहीं है। सबसे बड़ी गलती मुख्य मन्त्री ने यह की है कि सारे लोगों को लटकाये रखा। 7 महीने तक मन्त्रियों के घरों पर तबादलों की राजनीति चलती रही। 7 महीनों तक एम. एल. ए. नये नये कपड़े पहन कर कहीं दिल्ली गये, कहीं इधर गये, कहीं उधर गये। 8 महीने बाद मन्त्रिमण्डल बना। उससे काम में शिथिलता आई

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री मूलचन्द डागा)
नया सूट भी सिलवा लिया था भंवरलाल-ने, इन्होंने सोचा था कि शपथ मैं लूंगा ।

श्रीमन्, ऐसी हालत है । मुख्य मन्त्रीजी ने घोषणा की है कि तीन मन्त्री पश्चिम राजस्थान से और पांच पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी लेंगे । उजला बहन, आपका भी नाम सेक्रेटरीज में है । पहले दिन शपथ ली उसी दिन सब मन्त्रियों को शपथ दिलाते लेकिन जनता पार्टी का राज है । अभी लखनऊ में झगड़ा हुआ, मैं उसको बताना नहीं चाहता। एक साथ शपथ लेते, उसके बजाय कुछ मन्त्रियों ने पहले शपथ ली और कुछ मन्त्रियों ने बाद में ली । एक मन्त्री ने उद्योग का काम सीखा। रात-दिन मेहनत की और आठ महीने बाद उसको फेंक दिया । मुख्य मन्त्रीजी चाहते हैं कि कोई सीखे नहीं, बौने बने रहें, कोई कोई मास्टर नहीं बन सके । अब नये चिकित्सा मन्त्री आ गये । सवाई मानसिंह होस्पिटल के मालिक हो गये । उन्होंने चिकित्सा का बजट पेश नहीं किया लेकिन यह विभाग इनके जिम्मे डाल दिया । वित्त मन्त्रीजी बजट देखते नहीं, शराबबन्दी का काम देखते हैं । सारे मन्त्रिमण्डल में भ्रष्टाचार का मतलब रूपया देना और लेना ही नहीं हैं, जनता का काम नहीं करना भ्रष्टाचार है । गिरधारी लालजी ने दाढ़ी बढ़ाई, मालूम नहीं, कब कटायेंगे ? जब बड़े मंत्री बन जायेंगे ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसलिये नहीं बढ़ाई है,सहायता कोष में देने के लिये बढ़ाई है, भ्रष्टाचार तो आपने बढ़ाया था।

श्री ओंकारलाल चौहान : और भी तिगुना हो सकती है ।

श्री मूलचन्द डागा : आपको लेबर मिनिस्टर बनाया था, गलती हो गई । यह जो मन्त्रिमण्डल बनाने का तरीका है यह क्यू में खड़े होने का तरीका है । मुख्य मन्त्री कहते हैं, सचिव बनायेंगे । क्या जरूरत है सचिवों की ? मुख्य मन्त्रीजी ने . . .

श्रीमती सुमित्रा सिंह : डागाजी सचिव नहीं, संसदीय सचिव ।

श्री मूलचन्द डागा : घोषणा की है कि 5 संसदीय सचिव बनायेंगे। क्या करेंगे वे ?

श्री ओंकारलाल चौहान : उनसे शिक्षा लीजिये आप . . . .

श्री मूलचन्द डागा : लेनी पड़ेगी आपसे भी।

श्रीमन्, भ्रष्टाचार का आरोप लगाता हूं मैं मुख्य मन्त्रीजी पर, भैरोंसिंह शेखावत पर, इस बात का कि किसी भी मन्त्री को निष्पक्षता के साथ काम नहीं करने देते।सारे निर्णय केन्द्रित कर लिये हैं और सब मन्त्रियों को बौना बना दिया है । किसी मन्त्री को जवाब देना हो तो मुख्य मन्त्रीजी देंगे दूसरे मंत्री जवाब नहीं दे सकते । यह सारा हिन्दुस्तान सुनता है कि रेडियो पर भी भैरोंसिंह शेखावत प्रसारित होते हैं। क्या सारे मन्त्री कमजोर हैं ? यह मंत्रियों की और पार्टी के सदस्यों की....

श्री खेतसिंह राठौड : तोहीन है ।

श्री मूलचन्द डागा : ये रामप्रसादजी लड्ढा पीछे बैठे हैं, इनको नहीं बनाया मन्त्री ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी, जल्दी समाप्त करिये ।

श्री भंवरलाल ऐरन : जो बोलते हैं, उन्हीं को मन्त्री बना लेते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं एक बात कहना चाहता हूं। मन्त्रिमण्डल जो बनता है यह डिस्क्रिशन जो दे रखा है चीफ मिनिस्टर को, उन्होंने यह ईमानदारी से नहीं यूज किया। यह सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप है मेरा और मैं कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी की इमेज जो आप रखना चाहते थे वह नहीं रही है।

महीने में दौरों का खर्चा देखिये, तीस बार दिल्ली चले गये और सारा खर्चा···

श्रीमती उजला अरोड़ा : जाना पड़ता है, जरूरत थी।

श्री मूलचन्द डागा : जरूरत क्या है ? सेक्रेटेरियट बन्द कर दो ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : घंटी बज गई, डागाजी विराज जाइये।

श्री मूलचन्द डागा : अब दूसरा प्रस्ताव चिकित्सा और स्वास्थ्य पर है। मैं देख रहा हूं कि सवाई मानसिंह हॉस्पिटल की हालत कांस्टीट्यूशन में प्रावधान है कि महिलाओं और पुरुषों में डिस्टिन्क्शन नहीं किया जायगा।

श्रीमति उजला अरोड़ा : नर्सों की बाबत।

श्री मूलचन्द डागा : इनमें डिस्टिन्कशन क्यों है, कान्स्टीट्यूशन में प्रोविजन नहीं है, नर्सों को प्रिफेन्स नहीं दिया जाता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कोर्स में भी दिया जाता है।

श्री मूलचन्द डागा : एक श्रीमन्, राजनारायण जी की नई योजना है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को गांवों में भेजा जायगा पांच-छः महीने की ट्रेनिंग देकर। लोगों को खतरे में डाला जायेगा नीम हकीम खतरा-ए-जान ऐसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता न भेज दें गांवों में···

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सारे हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा ज्यादा और दवाएं कम. इसलिये यह व्यवस्था ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मन्त्री परिषद् के बारे में एक कट मोशन रखा है उसके जरिये राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है कि मन्त्री लोग भाषण तो जनता को बहुत देते हैं लेकिन काम कम करते हैं। जितने भी लोग जबसे मन्त्री बने हैं....

श्री हरीश कुमार शर्मा (रामगंज मंडी): आपने बिगुल तो बजा दिया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उनके आस-पास भीड़ बहुत लगती रहती है। मन्त्रियों को बहुत परेशान किया जाता रहा है। पहले तो सादगी की घोषणा कर दी और खुला दरवाजा जनता को बताया लेकिन अब दो-दो गार्ड लगा दिये। कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है अगर आप काम नहीं करोगे और लोगों को सन्तोष नहीं होगा तो यह ठीक नहीं है। माननीय उपाध्यक्षजी, यह इनकी आदत-सी पड़ गई है, यह कहते हैं कांग्रेस के समय की मशीनरी है जो काम कर रही है, वह मानती नहीं और हमको फेल करना चाहती है। यह कहकर टालते हैं। सारी मशीनरी को डिमोरेलाइज कर रखा है। इस हाउस 15 मिनट तक हो हल्ला होता रहा मकराना के सदस्य के एक सवाल पर। एम. एल. ए. के यहां चोरियां हो जाती हैं, एक-एक महीने में तीन-तीन बार थानेदार के ट्रान्सफर किये

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

जाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं। सम्पतरामजी चुप बैठे हैं। माननीय भैरोंसिंहजी साथ बैठे हुए हैं। यह क्या बात है? जब आप यहां बैठते थे तो क्या-क्या आरोप लगाते थे? अगर कांग्रेस वालों ने कुछ किया है तो जांच कमेटी बिठाओ, छोड़ो मत। पर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपने इंदिरा गांधी के लिए शाह कमीशन बिठाया, लेकिन शाह आयोग का तो बोलना ही बंद हो गया। जनता ने आपको कुर्सी पर इसलिये बिठाया है कि आप काम करो। बाकी हर बात में कहें कि यह तो पिछली सरकार ने किया है, तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? उसका कोई जवाब नहीं है। यह जो मंत्री परिषद् की परिपाटी चली आ रही है, उसके अनुसार हर एक मंत्री को इनडिपेंडेंट कहने का अधिकार है। आप हर अधिकारी, हर कर्मचारी को ऑर्डर देते हैं। आपने ट्रान्सफर का सारा बजट तीन महीने में खर्च कर दिया, फिर कहेंगे कि ट्रान्सफर का बजट नहीं है। इस तरह काम चलने वाला नहीं है। आपको प्रशासनिक मशीनरी पर विश्वास करना पड़ेगा। आप पिछली सरकार को बदनाम करने के लिए हर बात में पहले वाली सरकार की फाइल लायेंगे। पहले वाली सरकार ने कई इन्क्वायरीज करके फाइलें बनाई थीं। आप कौनसी नई इन्क्वायरी करके फांसी लगायेंगे? आप भ्रष्टाचार खतम करने के लिए कटिबद्ध जरूर हों लेकिन जिस ढंग से काम चल रहा है, उसके लिए तांगे वाला या रिक्शा वाला क्या कहता है, आप सुनो तो सही। लोग क्या बोल रहे हैं, यह भूल गए। आप तो सिर्फ कांग्रेस-कांग्रेस कहते जा रहे हैं। जैसे बजरंगलालजी ने कहा, उसकी चिंता मत करो, वह आई।

जनता सरकार के मंत्री लोग कहते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार। मेरे सामने मंत्रीजी बैठे हैं वह सर्वोदयी मंत्री जरूर हैं, लेकिन जितना चाहते हैं उतना काम नहीं कर सकते। हम तो मंत्रियों के पास महीनों से गए नहीं, सदन में जरूर आ जाते हैं। कोई मामला आता है तो उसके लिए कहते भी हैं। यह बहुत ही पिटीएबल कन्डीशन है कि आपने अपना खर्चा कम नहीं किया। कोई उदाहरण तो सरकार का पेश करो। पिछली सरकार ने 30 साल राज किया, फिर भी दनादन दूसरी हवा आ रही है। आपको इस पर विचार करना चाहिए कि क्या खर्चा अपने पर घटाया है?

चिकित्सा पर भी मैंने कटौती प्रस्ताव दिए हैं। मैं जालोर जिले की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जालोर जिले में और विशेषकर सांचोर तहसील में एड-पोस्ट, पी.एच.सी. व डिसपेन्सरीज में पूरा स्टाफ नहीं है। मैंने यह प्रश्न उठाया तो संतोषजनक जवाब मंत्री द्वारा नहीं दिया गया। कहते हैं कि स्टाफ की कमी है लेकिन फैसेलिटीज भी कम हैं और पूरी दवाइयां नहीं। यदि स्टाफ नहीं तो लोगों को कैसे सेटिसफाई करेंगे? हमारे यहां तीन-तीन महीने डाक्टर गैर हाजिर रहते हैं। मलेरिया वर्कर्स को परेशान करना शुरू किया तो छोड़-छोड़ कर भाग गए। वह मलेरिया का एरिया है। ऐसे इलाके में आप धन, पूरा स्टाफ दें और सब सुविधाएं दें। आपको मालूम है कि यह हार्ड एरिया है, अगर कहीं डिस्पेन्सरी हैं तो सुविधायें नहीं, व्यवस्था नहीं। भैरोंसिंहजी ने कहा कि हम फण्ड बना रहे हैं। उन्होंने भी शर्त लगा दी 50 प्रतिशत जन सहयोग की। कहां से गांव वाले देंगे? जहां 50 प्रतिशत जन सहयोग आएगा, वहीं एड

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

पोस्ट्स खोलेंगे, यह क्या है ? यहां जब डिस्पेन्सरीज की बात चली तो मंत्रीजी चुपचाप बैठे रहे। यह क्या अन्याय है, मंत्री बोले नहीं, जवाब नहीं दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया से 50 प्रतिशत से भी ज्यादा लोग पीड़ित हैं। खुजली की बीमारी पानी की वजह से है, पानी बिल्कुल खारा और गंदा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो मेरे कहने का मतलब है कि स्टाफ पूरा नहीं, दवाइयां पूरी नहीं। ऐसे नेग्लेक्टेड एरियाज में जो सुविधायें दे रखी हैं उनकी ओर विशेष ध्यान दें। आपने घोषणा की कि दवाइयां पूरी देंगे। बाजार से दवाइयां मंगानी पड़ती हैं। ऐसे एरियाज में दवाई व स्टाफ का पूरा इंतजाम करना चाहिए। आवागमन के साधनों की भी कमी है, यह तथ्य है। जब शहर के अस्पताल में जाते हैं तो बैड्स नहीं मिलते। जनता सरकार को सोचना चाहिए, जनता सरकार का मतलब सस्ता इलाज। तो आपने कौनसी चीज सस्ती की है, वोट तो मांग लिया। मेडिकल बजट के अन्दर, आपको ग्रेड्स के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। मेडिकल का जो बजट है, यह पुराने आधार पर न दें। जहां कम सुविधायें हैं जैसे सांचौर है एड-पोस्ट्स वगैरह की, वहां पूरी दवाइयां उपलब्ध करायें।

नए मंत्री आए हैं, आपको जनता ने जिताया। पापूलर तो जनता ही बनाती है। मैं तो अपनी सरकार को भी खरी खोटी सुनाता था और आपको भी सुनाता हूं, किसी को बख्सता नहीं हूं। हम तो सिर्फ आपका सहयोग करने के लिए हैं। हम समस्या रखते है, जांच कराना आपका काम है। जालोर जिला पिछड़ा हुआ इलाका है, आप हमारे इलाके के साथ न्याय करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सूरजपाल सिंह।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री परिषद् व चिकित्सा स्वास्थ्य पर मेरे कटौती प्रस्ताव हैं। मंत्रिमंडल के बारे में मेरा कटौती प्रस्ताव यह है कि अनुसूचित जाति व जन-जाति के लोगों की दरख्वास्तें हमारे मंत्रियों के पास भेजी जाती हैं मगर मैंने अमूमन देखा है कि किसी भी मंत्री ने आज तक एक भी पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। यह जनता सरकार शासन में आने से पहले बड़ी-बड़ी बातें करती थी कि जनता की सरकार बनेगी और जनता की बात को सुनेगी। मगर मेरे क्षेत्र में पचासों दरख्वास्तें अनुसूचित जाति व जन-जाति के लोगों ने मंत्रियों को भेजीं। उन पर कार्यवाही करना तो दूर, उन पर किसी तरह का रिमार्क लिखकर किसी संबंधित अधिकारी को भेजने का काम भी इस मंत्रिमंडल ने नहीं किया। यह आप जो जनता को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने की बात करते हैं यह आपकी सिर्फ बातें ही हैं। आप सिर्फ यह कह सकते हैं कि प्रशासन में भ्रष्टाचार है, जुडिशियरी में भ्रष्टाचार है पर आप खुद पहले देखें। जब तक आपके मन्त्री लोग खुद अपने को नहीं सुधारेंगे, जनता की दिक्कतों के बारे में विचार नहीं करेंगे तब तक मैं तो स्पष्ट कहना चाहूंगा कि आपको कोई अधिकार नहीं है यह कहने का कि प्रशासन में भ्रष्टाचार है और जुडिशियरी में भ्रष्टाचार है। पहले इस में बैठने वाले सदस्यों एवं मंत्रियों को

(श्री सूरजपाल सिंह)

प्रेरणा रूप बनना होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि आपको मेरे क्षेत्र के अनुसूचित जाति, जन-जाति वालों ने अर्जियां भेजी हैं शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की पर आपने उन लोगों के एक भी पत्र का और जो भी एप्लीकेशन्स उन लोगों ने आपको भिजवायीं आपने एक भी एप्लीकेशन का जवाब नहीं दिया। इसके अलावा आपने किसी भी एक एप्लीकेशन को आगे फोर्वर्ड नहीं किया। आप जो चुनावों के पहले जनता को अपना नारा देते थे, अपने आपको गरीबों का मददगार बताते थे और यह कहते थे कि मैं भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा, भ्रष्टाचारियों की लिस्ट के धमाके होंगे वह केवल आपकी बातें हीं थीं। आपने, मुख्य मंत्रीजी, कोई भी अपने प्रशासन में परिवर्तन नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के सभी मंत्री महोदयों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम विधायक जो भी अर्जी आपके पास शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की भेजें, जो भी अर्जियां आयें डिपार्टमेंट कन्सर्न तक तो उन्हें भिजवा दिया करें। उसके ऊपर आदेश करके कोई एक्शन तो लें।

दूसरी बात जो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा वह है चिकित्सा के एवं स्वास्थ्य के बारे में। इसके लिये भी मेरे कटौती प्रस्ताव दिये हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पांच-सात कटौती प्रस्ताव दिये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र का कस्बा भीनमाल है उसकी 20-25 हजार की आबादी है वहां पर चिकित्सा की पूर्ण सुविधायें नहीं हैं। मेरा आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी से यह निवेदन है कि भीनमाल में एक रेफरल अस्पताल खोला जाय। इसके अलावा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ही एक दासपा का कस्बा है उसकी पांच हजार की आबादी है वहां एक हाई स्कूल भी है। टेलीफोन सुविधा भी है। इस दृष्टिकोण से देखते हुए भी अभी तक वहां पर केवल एक सब-सैन्टर ही है चिकित्सा का। मेरा निवेदन है कि वहां पर प्राइमरी हैल्थ सैन्टर खोला जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वहां के लोग जन सहयोग से प्राइमरी हैल्थ सैन्टर के लिये बिल्डिंग भी बनाने को तैयार हैं। अगर आप वहां पर प्राइमरी हैल्थ सैन्टर खोल देंगे तो आसपास के गांवों के लोगों को भी उसका लाभ होगा और लोगों को चिकित्सा की सुविधा मिल सकेगी। इसलिये मेरा चिकित्सा मंत्री महोदय को यह निवेदन है आपके माध्यम से कि दासपा में प्राइमरी हैल्थ सैन्टर खोला जाय। इसी तरह, उपाध्यक्ष महोदय, कई सैन्टर्स मेरे क्षेत्र में हैं उनके द्वारा लोगों को, जो आस-पास के गांवों में रहते हैं, पूर्ण मेडिकल सुविधा नहीं मिल पा रही है जैसे तिलोड़ा में कोई चिकित्सा सुविधा का साधन नहीं है। वहां उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाय। बाली, भुञावी के आयुर्वेद अस्पताल, भूतपूर्व सरकार ने खोलने का निर्णय लिया था। इस क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जहां कि डिस्पेन्सरीज नहीं हैं वहां आप आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने की व्यवस्था करावें। हालांकि पहले की सरकार ने इस बारे में निर्णय लिया था लेकिन चूंकि वह सभी निर्णय कांग्रेस की सरकार ने लिये थे और अब वहां से जनता पार्टी का केन्डीडेट जीत कर नहीं आया है इसलिये वहां पर आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने का जो प्रावधान था उसे आपने

(श्री सूरजपालसिंह)
समाप्त कर दिया। मेरा निवेदन यही है कि अगर आप इस प्रकार द्वेष भावना से काम करोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको तो जनता का भला करना है। नहीं तो हमारा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है आपकी ही इमेज बिगड़ेगी। आपका ही नुकसान होगा, जनता आपको ही कोसेगी। हम कोई हमारा व्यक्तिगत काम लेकर आते नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि आप जरा राजनीति से ऊपर उठ कर काम करें तो आपकी इमेज गिरेगी नहीं। नहीं तो आपकी इमेज गिरेगी। जब तक राजनैतिक आचरण में सुधार नहीं होगा तब तक आपकी इमेज बिगड़ती ही रहेगी।

इसके अलावा एक बात जो मैं आपको और निवेदन करना चाहूंगा वह है मलेरिया के बारे में। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के पास सांचोर का नहीड क्षेत्र लगा हुआ है उस एरिया में मलेरिया का प्रकोप प्रचुर मात्रा में रहता है। उसकी वजह से हमारे यहां भी मलेरिया का बहुत भारी प्रकोप है। हालांकि राज्य सरकार ने मलेरिया का स्टॉफ वहां लगाया है पर वह पूरा नहीं है। मलेरिया विभाग के एम.एस.डब्ल्यू. का वेतनमान बहुत ही कम है। उनको किसी तरह की सुविधा नहीं है। इसलिये मेरा राज्य सरकार से, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन है कि इन मलेरिया के कर्मचारियों के वेतनमानों में सुधार किया जाय। आप जो 200-250 रुपये देते हैं इससे तो कोई उनकी हालत में सुधार नहीं होने वाला है। इसके अलावा आपने उनको लम्बा चौड़ा क्षेत्र दे रखा है, हर मलेरिया कर्मचारी को आपने 12-13 गांव दे रखे हैं। अब बिना साधनों के वह बेचारे 12-13 गांवों से कैसे काम कर सकते हैं। इसके अलावा जनरली यह भी देखा गया है कि जो मलेरिया के कर्मचारियों द्वारा डी.डी.टी. और बी.एच.सी. के स्प्रे किये जाते हैं, पता नहीं आज कल क्या बात है, कोई मिक्सचर में खराबी कर देते हैं या अडल्ट्रेशन कर देते हैं जिससे डी.डी.टी. के स्प्रे करने पर भी मच्छरों पर कोई असर नहीं होता है। मैं समझता हूं कि डी.डी.टी. से तो एक भी मच्छर नहीं मरता है। इसके लिये आप कोई नया शोध करें। इसके साथ-साथ, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में सब-सेंटर बहुत ही कम हैं। मेरे क्षेत्र में कई गांव ऐसे हैं जहां 15-20 मील के क्षेत्र के आस-पास कोई मेडिकल की सुविधा नहीं है और कोई दवाई का साधन नहीं है। इधर यह मच्छर मरते नहीं हैं।

श्री मदनसिंह दांता : आप यह सही कह रहे हैं। मैंने भी डॉक्टरों से पूछा था इसके बारे में ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बातचीत नहीं करें। आपको जो भी बात करनी है उसके लिये मेरे से इजाजत लें।

(व्यवधान)

आप बिराजिये, माननीय सदस्य मदनसिंहजी।

श्री सूरजपालसिंह : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज मच्छर तो मलेरिया के डी.डी.टी. से मरते नहीं हैं। यह तो मैं मान ही नहीं सकता कि सभी जगह गड़बड़ियां होती हों। कहीं-कहीं पर हो सकती हैं। गड़बड़ी के साथ-साथ मैं यह मानता हूं कि डी.डी.टी. स्प्रे से मच्छर रिज्यूडल हो गये हैं। इसलिये मेरा

(श्री सूरजपालसिंह)

निवेदन है कि मच्छरों की रोकथाम के लिए वैज्ञानिकों से शोध करवाकर कुछ नया उपाय ढूंढने का प्रयास किया जाय ताकि मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों का अन्त हो सके।

बस इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतना राम।

श्री रतना राम चौधरी (रानीवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र रानीवाड़ा है। रानीवाड़ा एक पंचायत समिति हैडक्वार्टर है वहां पर डेयरी का उद्योग है। उसकी करीब पांच हजार की आबादी है। मैंने सुना है कि राज्य सरकार ने रानीवाड़ा में डिस्पेन्सरी खोल दी है, उसके लिये धन्यवाद, परन्तु अभी तक, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि वहां डिस्पेन्सरी ने काम चालू नहीं किया है। वहां पर अभी तक कोई भी स्टॉफ नहीं पहुंचा है। इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से और डाइरेक्टर साहब से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप जल्दी स्टॉफ भेजें ताकि जनता को राहत मिले।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : डाइरेक्टर साहब को यहां से नहीं कह सकते।

श्री रतना राम चौधरी : अगर मैंने डाइरेक्टर साहब को कह भी दिया तो क्या हुआ। वह भी नोट कर सकते हैं और काम चालू करा सकते हैं। और गांग में एड-पोस्ट खोली है और पावसी में भी एड-पोस्ट खोली गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तक स्टॉफ नहीं पहुंचा है। आप जल्दी से जल्दी स्टॉफ भेजने की व्यवस्था करावें। इसके अलावा जैसा कि माननीय सदस्य श्री सूरजपालसिंह जी ने कहा, जो डी.डी.टी. का स्प्रे किया गया है उसका गांवों के मच्छरों पर कुछ असर नहीं हो रहा है। इसका पहली बार जब प्रयोग किया गया था उस वक्त डी.डी.टी. से मच्छर तो क्या छूछन्दर तक मर जाते थे जो कि बहुत ही जहरीले होते हैं। पर अब तो कुछ भी असर नहीं होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में मलेरिया की आम शिकायत है उसको दूर करने के लिये कोई और दवा शोध करके सभी जगह छिड़कावें तो जनता को राहत मिल सकती है।

इसके अलावा मैं एक बात मंत्रीजी को और निवेदन करना चाहूंगा। आप जिस तरह गलत सलत आश्वासन जनता को देते हैं वैसे आश्वासन कम से कम विधायकों को तो न दिया करें। आखिर मंत्री भी तो विधायकों में से ही बनते हैं। विधायक आपके साथी होते हैं। अगर आपको कोई काम नहीं करना हो तो आप उसके लिये भले ही स्पष्ट मना कर दें। मना आप करेंगे तो हमें दुःख भी नहीं होगा क्योंकि हम तो जो काम लेकर आते हैं वह व्यक्तिगत काम नहीं, अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को लेकर आते हैं। इसलिये आपको इस ओर विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप विधायक की बात को सुनेंगे तो वह जनता की बात होगी। उस समस्या को आप सुलझा देंगे तो उससे जनता को ही लाभ होने वाला है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन है कि वह इस ओर ध्यान दें।

बस इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री खेतसिंह राठौड़ ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने चार कटौती प्रस्ताव दिये हैं । चूंकि समय कम है इसलिये मैं मेरे क्षेत्र की समस्यायें माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा ।

ग्रामतौर पर , उपाध्यक्ष महोदय, विधायक के पास में तीन तरीके होते हैं । एक मंत्री को पत्र लिखना, दूसरा विधान सभा में प्रश्न पूछना ग्रौर तीसरा कटौती प्रस्ताव पेश करना । इन माध्यमों के द्वारा ध्यान ग्राकर्षित करना । मैंने तीनों माध्यम ग्रपनाये लेकिन मुझे ग्रफसोस होता है यह कहते हुए कि इनमें से एक का भी जवाब नहीं दिया ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न भी पूछा है । जब से ग्रापकी सरकार ग्रायी है लगातार हमारे गांव की डिस्पेन्सरी में कोई डॉक्टर नहीं है । डिस्पेन्सरी के लिये बिल्डिंग बनी हुई है । दवाइयां भी वहां उपलब्ध हैं । हमने मालूम किया कि डॉक्टर कहां चला गया तो पता चला कि डॉक्टर रेलवे में चला गया । मैंने डाइरेक्टर साहब से कहा तो कहा कि जल्दी ही दूसरे डॉक्टर की व्यवस्था कर रहे हैं । मैं निवेदन करूंगा कि डिस्पेन्सरीज में जल्दी से जल्दी डॉक्टर लगाइये ग्रौर वहां पर स्टॉफ भी भेजिये ।

शेरगढ़ में 12 सब-सेन्टर्स हैं । दो में स्टॉफ लगा हुग्रा है ग्रौर 10 में नहीं है । वे बन्द पड़े हैं । 12 में से 10 में स्टॉफ न हो तो ग्राप ही सोच सकते हैं कि कितने लोग परेशान होंगे ग्रौर कितनी चिन्ता लोगों को हो सकती है ।

साथ ही साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापको एक सूचना भी दूंगा कि 3 गांव ऐसे हैं जहां पर एलोपैथिक का सब-सैन्टर भी है ग्रौर ग्रायुर्वेद ग्रौषधालय भी है । मैंने लिख कर भी भेजा कि एक को वहां से शिफ्ट कर दीजिये । जहां पर लेने के लिये गांव वाले तैयार हों, ग्रायुर्वेद शफाखाना के लिये कमरा देने के लिये तैयार हों , वैद्य के लिये तैयार हों तो ग्राप उसको उस जगह पर शिफ्ट कर दीजिये । यह एक पॉलिसी डिसिजन है यह ग्राप ले लीजिये । यदि एक-एक गांव को ही सुविधा मिल जाय तो काफी लाभ मिलेगा ।

एक खास डिफिकल्टी यह है कि डिस्पेन्सरीज तो हैं लेकिन दवाइयां नहीं मिलती हैं । दवाइयों के लिये दुकान खोलने वाले लोग भी हैं लेकिन उसके लिये लाइसेन्स लेना पड़ता है ग्रौर उसके लिये कोई ट्रेनिंग होती है । मैंने रूपराजजी से बात की थी । उन्होंने कहा कि यह तो एक लम्बा तरीका है ट्रेनिंग के लिये उनको भेजना पड़ेगा । यह दवा देने का प्रश्न है, यदि किसी ग्रनट्रेन्ड को दवाई देने का लाइसेंस मिल गया तो उससे लाभ के बजाय हानि ग्रधिक हो सकती है । यह ग्राम लोगों के हित में नहीं होगा । उसके लिये मेरा यह निवेदन है कि हो सके तो इस प्रकार की ट्रेनिंग का कोर्स भी शुरू करना चाहिये । जब डिस्पेन्सरियां खोल रहे हैं तो उसके साथ में दवाइयों की भी व्यवस्था होनी चाहिये । डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन तो लिख देते हैं लेकिन बहुत दूर जाकर लोगों को दवाइयां लानी पड़ती हैं । इससे बड़ी परेशानी होती है । यदि उनसे खुद से ही लें तो चार्जेज ज्यादा होते हैं ।

बालेसर में एक डॉक्टर लगा हुग्रा है । उसको 3।। साल हो गये वहां लगे हुए ।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

उसका इन्ट्रेस्ट यही है कि वह किसी प्रकार से वहां से चला जाय। उसने 30 रु० फीस लेना शुरू कर दिया है। आप सोचिये गांव वालों से 30 रुपया ले तो कैसे चल सकता है। इसके बारे में शिकायतें भी आयी हैं, लेटर भी आपके पास आये हैं। या तो जांच करके उसके विरुद्ध एक्शन लें या उसको वहां से आप हटा दीजिये। मेहरबानी करके कोई न कोई उस पर कार्यवाही कीजिये।

सोमेश्वर में सब-सेन्टर बना हुआ है। डॉक्टर और स्टॉफ के रहने के लिये कोई क्वार्टर नहीं बने हुए हैं इस कारण डॉक्टर और स्टॉफ होस्पिटल में ही रहते हैं। मरीज आयें तो कहां रहें। मेरा निवेदन है कि जब पी. एच. सी बनायी है तो आप क्वार्टर्स के लिये भी तो मंजूरी दें। जिससे इस प्रकार की लोगों को डिफिकल्टीज न हों।

एक मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि परिवार कल्याण का डिपार्टमेन्ट है। परिवार नियोजन को ही नया नाम दिया गया है परिवार कल्याण वरना काम वह का वही है। परिवार नियोजन के अन्तर्गत हमने 3 लाख ऑपरेशन्स करवाये थे उसके परिणामस्वरूप हम इधर आकर बैठ गये और आप उधर आ गये। इतना इसका बजट था, न तो आपने उसको कम किया है और न ही बजट के अनुसार आपने ऑपरेशन्स वगैरह किये। ऑपरेशन भी नहीं किये और आपने बजट भी कम नहीं किया। हमने 3 लाख ऑपरेशन किये थे और आपने दस हजार ही किये हैं। इसलिये सारा का सारा पैसा डाइवर्ट करके गांवों के लोगों की सुविधा के लिये ज्यादा खर्च कर दें। लोगों को उससे लाभ मिलेगा। इतने पैसे की और इतने स्टॉफ की इस स्थिति में तो आवश्यकता नहीं है। स्वेच्छा से ऑपरेशन कराने वाले पी. एच. सी. में भी जाकर करवा सकते हैं। इसलिये इस खर्च को आप कम कर दीजिये इस स्टॉफ को भी कम कर दीजिये जिससे इससे जो बचने वाला पैसा है वह लोगों की अन्य भलाई के कार्यों में लग सके। उसके द्वारा लोगों को अधिक सुविधा मिल सके।

श्री रतनलाल वर्मा : आपने तो ऑपरेशन नहीं करवाया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने तो करवाया है। आपमें से बहुतों ने नहीं करवाया है।

श्री श्रवणलाल : घर का आपस का झगड़ा है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यदि इस प्रकार आबादी बढ़ती गयी तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं, स्वास्थ्य मंत्रीजी, यह देश के लिये बहुत ही नुकसानप्रद होगा। आप के लिये तो होगा ही लेकिन यह देश के लिये बहुत ही विकट समस्या पैदा कर देगा। यदि इस प्रकार से 1 करोड़ 15 लाख आदमी हर साल बढ़ते गये तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति बनेगी क्योंकि वे खाने के लिये अन्न मांगेंगे, वे कपड़ा भी पहिनने के लिए मांगेंगे और मकान भी रहने के लिये मांगेंगे। आपको इसके जरिये से जो फायदा मिलना था वह तो मिल गया। जो फायदा आप उठा सकते थे वह तो उठा लिया। अब बार बार इसका फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। आप यह निश्चित मान लीजिये कि यह स्थिति जारी रही तो आप कितनी ही योजना बना लें, कभी हमारा मुल्क खुशहाल

(श्री खेतसिंह राठौड़)

नहीं हो सकेगा और गरीबी की रेखा को पार करने वाली जो एक योजना भैरोंसिंह जी ने बनायी है अन्त्योदय की उससे भी काम नहीं चलने वाला है।

श्री त्रिलोकचन्द जैन (स्वास्थ्य मंत्री) : इतना कन्सन्ट्रेट किया है आपने इसको प्रेस करने में।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ने प्रश्न पूछा है और मैं कहना चाहता हूं कि हमने दो-तीन साल के लिये यह प्रोग्राम रखा था। इसको तो आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं कि जनसंख्या अधिक नहीं बढ़नी चाहिये। चाहे आप इसको परिवार कल्याण का नाम दें और हमने इसको परिवार नियोजन का नाम दिया। काम तो एक ही है। लेकिन यह नहीं कह सकता है कि यह गलत प्रोग्राम है। 3। लाख 3। लाख ऑपरेशन्स हुए थे। यह हम मानते हैं कि जल्दबाजी में कुंवारे और बूढ़े भी इसके अन्तर्गत आ गये होंगे लेकिन इससे कितनी पापूलेशन गिर गयी थी यह तो आप मानेंगे ही, और अब फिर बढ़नी शुरू हो गयी है और निश्चतरूप से मौजूदा हालत रही तो, आप चाहे अभी तो खुश हो लीजिये, आपको अभी तो खुशी हो सकती है, लेकिन अगले सालों में आपको इसको बहुत ही सीरियसली लेना पड़ेगा और यदि आपने आने वाले तीन वर्षों में नहीं लिया तो आपकी सारी योजना है वह फैल हो जायेगी। कोई भी आप योजना ले लें। परिवार नियोजन की योजना आपने नहीं ली और आपने इसके लिये मानस नहीं बनाया, आपने इसके लिये प्रचार नहीं किया, तो आप कितनी ही योजना बना लीजिये एक भी योजना सफल होने वाली नहीं है। यदि दस का खाना है और 20 खाने के लिये आ जाय तो सब खाना नहीं खा सकते हैं।

मंत्री महोदयों के बारे में कहना चाहता हूं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपने चूंकि घंटी बजा दी है इसलिये बहुत जल्दी समाप्त करूंगा। मैं यह कह रहा था कि आपके भी वे ही तौर तरीके हैं जो हमारे थे। वे ही मोटरें, वे ही पी.ए., पी.-एस.। हमारे सेक्रेटेरियट के पी.ए. थे और आपने आर.ए.एस. ऑफिसर्स लिये हैं। आपको नोलेज नहीं थी इसलिये आपने उनको लिया। किसीकी बपौती नहीं है। हम पहले प्रधान बने, डिप्टी मिनिस्टर बने और फिर मिनिस्टर बने और हम आप जिस प्रकार आये हैं सीधे उस प्रकार से नहीं आये। आप तो सीधे उतर कर आये हैं। कई माननीय सदस्य तो कहीं के भी कोई सदस्य नहीं थे और सीधे ही उतर कर आ गये। यह आप भी मानेंगे कि आपको सीधा ही चान्स मिल गया।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : कोई गलती नहीं की। डेमोक्रेसी में ऐसा होता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : गलती यह है कि लोगों ने वोट नहीं दिये इसलिये कि वे हम से नाराज हो गये और आपका काम चल गया। आपके भी वे ही तौर-तरीके हैं। कोई भी जायगा वह ही तरीका रखेगा इसलिए वह चाटन भी होगा, भाषण भी होगा और वही मालायें होंगी और तौर-तरीके वही होंगे लेकिन अभी तक आपके अन्दर राज्य करने की जो कैपेसिटी, जो गट्स और ग्रिप आनी चाहिए वह नहीं आई है। मेहरबानी करके

(श्री खेतसिंह राठौड़)

उसको आप सीरियसली लें और इन बातों को ध्यान में रखकर चलें। हम मानते हैं कि तीस साल तक उधर रहने के कारण उस समय जो तरीके श्री सतीशचन्द्रजी के और श्री भैरोंसिहजी के थे वह तरीके हमको नहीं आये हैं। इसलिये हमें विपक्ष सीखना है और आपका राज्य सीखना है, इसमें शक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयनारायण साला-दिया।

(अनुपस्थित)

श्री हरीश शर्मा !

श्री हरीश कुमार शर्मा (रामगंजमंडी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय 14 दिसम्बर को कोटा में मंत्रिमण्डल की बैठक हुई थी। सम्पूर्ण हाड़ोती प्रदेश को इससे बड़ी आशायें और विश्वास मंत्रिमण्डल के प्रति रहा है। जिस समय मंत्रिमण्डल की बैठक हुई तो उसमें कई घोषणायें कीं लेकिन मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, वह वादे करके भूल गए और आस लगाये बैठे हैं। एक भी घोषणा उसमें से क्रियान्वित नहीं हुई। उन्होंने कहा था कि जलप्रदाय विभाग का ए.ई.एन. का ऑफिस रामगंजमण्डी में खोल दिया जायेगा। जहां रामगंजमण्डी में एक कार्यालय खोलने का था वहां तो खुला नहीं और यह हुआ कि कोटा में एक और कार्यालय खुल गया। मेरी समझ में नहीं आता कि जब हम घोषणायें पूरी नहीं कर सकते तो फिर घोषणायें क्यों करते हैं ? वादे क्यों करते हैं। जब घोषणा की थी तो उसको पूरा करना चाहिए और जब ऐसा होता है तो क्षेत्र में हमारी सारी इज्जत खतम हो जाती है और क्षेत्र वाले कहते हैं कि तुम झूठ बोलते हो। मेरा निवेदन यह है कि जब घोषणायें की थीं तो उस पर आप विचार करें, उसके पूरा होने में देरी क्यों हुई और वह पूरी क्यों नहीं हुई ?

इसके अलावा हमारे यहां जलप्रदाय योजना जो बाराबास, रथकांकरा और नया गांव की थी उनका क्या हुआ। इनके लिए स्वीकृति तो दी थी लेकिन पानी का पाइप एक भी नहीं है। मोडक, उदपुरा पानी की टंकियों के लिए कह दिया गया था और लोगों ने पैसा भी जमा करा रखा था। मैं इसके बारे में मिला भी तो मुझे कहा गया था कि तीन-चार दिन में काम शुरू हो जायेगा लेकिन आज दिन तक वह दिन नहीं आया और घोषणा केवलमात्र घोषणा ही रह गयी। आपने रामगंजमण्डी के लिये 2 लाख गैलन देने के लिए घोषणा की थी लेकिन हुआ यह कि पहले आप दो समय पानी देते थे और अब आपने तीन बार कर दिया। रात को पानी देते हैं जब लोग सोये हुए होते हैं। आपने 1॥ लाख की जगह 2 लाख गैलन कर दिया लेकिन फिर भी लोगों को पानी नहीं मिलता है।

आपने ओरेन्ज प्लान्टेशन प्रोग्राम के लिए भी घोषणा की थी लेकिन यह काम भी अभी तक नहीं हुआ और लोग इसके लिए आख लगाये बैठे हैं। हमारे यहां उप-जिले म एक रेस्ट हाउस 1॥ लाख रुपये की लागत से बनाने की भी घोषणा की गयी थी लेकिन यह योजना अभी तक यों ही पड़ी हुई है। इसके अलावा आम रास्तों पर मलवा नहीं डालने और चरागाह की खानों की लीज को निरस्त करने की बात भी कही गयी थी लेकिन उसका भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री परिषद के माननीय सदस्यों से निवेदन

(श्री हरीश कुमार शर्मा)

करूंगा कि यदि आप घोषणा करके भी काम को नहीं करेंगे तो परिणाम यह होगा कि लोगों में क्लेष बढ़ेगा और उसके नतीजे गम्भीर होंगे ।

पंचायत समितियों के लिए इस सदन में घोषणा की थी कि सब पंचायत समितियों में अध्यापक पहुंच जायेंगे । मेरी पंचायत समिति लाडपुरा में 30 अध्यापकों की जरूरत है और आपने वहां एक भी अध्यापक नहीं दिया । यह मंत्रीमण्डल को भी निर्णय था । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से काम नहीं चलता ।शासन की पद्धति व्यवहारिक रूप से वही होनी चाहिए जिसको जनता स्वीकार करे । इसके अनुसार ही आपको कार्य करने पड़ेंगे ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मंत्रिमण्डल ने अच्छे-अच्छे काम भी किये लेकिन आम लोगों की राय अच्छी नहीं है क्योंकि आपने घोषणायें तो कर दी और काम नहीं किये । मडाना, सुकेत और खेड़ाअलदा यह तीन स्थान मेरे यहां ऐसे हैं जिनकी संख्या पांच हजार की है लेकिन वहां पर डाक्टर नहीं है । मेरा निवेदन है कि तीनों चिकित्सालयों को डाक्टर दिये जायें और रामगंजमण्डी में चिकित्सालय है जिसके लिए केन्द्रीय सरकार ने 86 हजार रुपया स्वीकृत करके भेजा, भवन तैयार हो रहा है और वहां पर काला कक्ष भी है लेकिन एक्सरे मशीन नहीं है । मेरे क्षेत्र में औषधालय भी मरीजों के अनुपात में नहीं हैं, औषधियां नहीं हैं, दवाइयां नहीं है, पट्टियां नहीं हैं और छोटी-छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए नहीं है । न वहां पर रोगीवाहन है, न ई. सी. जी की मशीन है, माईक्रोस्कोप, टी. टी. सी., डी. एल. सी., ई. एस. आई. की भी कोई व्यवस्था नहीं है । आयुर्वेदिक औषधालय जहां-जहां खुले हुए हैं और जहां-जहां चिकित्सालय हैं वहां नर्स और डॉक्टर दे दिये जायें । कम से कम नर्स तो बहुत आवश्यक है क्योंकि महिलाओं के डिलिवरी केसेज में उनकी बहुत आवश्यकता है । इसके लिए भी घोषणा कर दी गई थी गांव के हर औषधालय को नर्स दे दी जायेगी लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ ।

इसके साथ ही इस विभाग की दो तीन घटनायें मैं प्रस्तुत करूंगा । झालावाड़ के के डॉक्टर श्री जी. डी. शर्मा जो कि मेडिकल जूरिस्ट हैं उनकी जांच डा. दर्शन सिंह सरोया, डिप्टी डाइरेक्टर ने की 10-1-78 को और उसकी जांच रिपोर्ट आई लेकिन वह रिपोर्ट आज तक नहीं गयी । उस डॉक्टर का कुछ नहीं हुआ । क्या परिणाम आये उस रिपोर्ट के और इसमें क्यों देरी हुई इसका कारण समझ में नहीं आया । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही स्थिति आयुर्वेद विभाग की भी है । श्यामलाल शर्मा एक आर. ए. एस. ऑफिसर है । वह अपने आपको बहुत ऊंचा अधिकारी मानते हैं और मंत्री के आदेशों को रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं । जब कभी वह दौरे पर जाते हैं तो लोग घबराते रहते हैं और जब तक वह वापिस लौट नहीं जाते लोगों में डर बना रहता है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरे क्षेत्र में जो आयुर्वेदिक औषधालय हैं वह खाली पड़े हैं । वहां औषधियां ही नहीं हैं। मैं राज्य सरकार से और मंत्रिमण्डल से निवेदन करूंगा कि इस दृष्टि से हम विचार करें कि जो घोषणायें करें उनको हम गम्भीरतापूर्वक पूरा करें । जैसा जयपुर के माननीय सदस्य बोल रहे थे मैं कहता हूं कि

(हरीश कुमार शर्मा)

जयपुर को नहीं मिले और इसको छोड़ दिया जाय, यहां तो बहुत पैसा लगता है, गांव में बिल्डिंग बनाने के लिए भी जन सहयोग चाहिए और यहां मुफ्त में सरकार बनाती है। अपने पैसे से गांव में जनता औषधालय बनायें और आप नर्स, कम्पाउण्डर और डॉक्टर भी नहीं दे सकते। मैंने मेरे क्षेत्र के गांवों की लिस्ट मंत्री महोदय को दी थी जिनकी कि आबादी दो-हजार की है वहां सड़कें नहीं हैं, वह गांव जंगलों में बसे हुए हैं, एकान्त है और वहां साधन नहीं हैं। बरसात में वहां लोग परेशान होते हैं। तो सबसे पहले ऐसे स्थानों पर चिकित्सालय खुलने चाहिएं, यह मेरा निवेदन है। मैं धन्यवाद देता हूं मंत्रिमंडल को कि उन्होंने जन भावनाओं को ध्यान में रखकर ऐसे काम किये हैं जिनके लिए हमें नाज है, गर्व है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोपाल पचेरवाल!

(अनुपस्थित)

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा!

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहरथाना): उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान से जिस दिन अंग्रेज गये और हिन्दुस्तान की सत्ता कांग्रेस ने संभाली तो उन्होंने महात्मा गांधी का आदर्श अपने सामने रखा था। महात्मा गांधी के नाम पर वे राम राज्य लाना चाहते थे। उन्होंने तीस साल तक प्रयास किया लेकिन रामराज्य ला नहीं सके और स्वयं सत्ता से हट गये। सत्ता का परिवर्तन हुआ, केन्द्र में और प्रांतों में जनता पार्टी की सरकार बनी और जनता पार्टी की सरकार ने लोकनायक जयप्रकाशनारायण को अपना आदर्श मानकर, राजघाट पर, महात्मा गांधी की समाधि पर इस बात का संकल्प लिया कि हम सादा जीवन व्यतीत करेंगे, खर्चे में कमी करेंगे और हमारा जीवन हिन्दुस्तान के गरीब आदमी की तरह होगा। आशा और विश्वास था, यह कल्पना थी, हमारा अपना मानस था कि जो हमने संकल्प लिया है उसको हम जीवन में ढालेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का पिछले दिनों बजट पेश हुआ, उसको मैंने देखा। मुझे बड़ा दुःख हुआ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस बजट के अन्दर आज भी मंत्रियों के बंगलों पर इतना खर्चा है। मोटर का खर्चा 7 हजार रुपये माहवार है यात्रा भत्ता 1500 रुपये माहवार है। इसके अलावा आलीशान बंगले हैं। 3 हजार का टेलीफोन का बिल आता है। इस लोकतंत्र में, गरीब हिन्दुस्तान में और खास कर राजस्थान में क्या इस प्रकार चल सकता है? कांग्रेस सरकार तो चला सकती थी लेकिन जनता पार्टी के राज्य में इस प्रकार अनावश्यक खर्चा हो यह हमारे देश के लिये अच्छा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आप सुन कर ताज्जुब करेंगे हमारे सर्वोदय मंत्री की कार पर 10 हजार और 50 हजार रुपया मेन्टीनेंस पर खर्चा आता है। राजस्थान मंत्री परिषद् को इस बारे में सोचना चाहिए और राज्य के मंत्री परिषद् को इस रे में निर्णय लेना चाहिये कि जयप्रकाशनारायण का जो आदर्श है उसके ऊपर चलेंगे......

श्री मूलचन्द डागा: आपके होते हुए सुधार आयेगा?

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा: उपाध्यक्ष

(श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा)

महोदय, यहां जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता उनको भेजती है। जनता की कोई समस्यायें हैं वह समाधान के लिये हमारे पास आती हैं तो हम जनता के प्रतिनिधि होने के नाते उन समस्याओं को ओर मंत्रिमण्डल का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। मुझे अफसोस है कि राजस्थान का मंत्रिमण्डल हमारे पत्रों का कोई उत्तर नहीं देता है। स्वतंत्र राज्य के मंत्रियों को सोचना चाहिये कि उनके पास स्टैनो है, टाईपिस्ट है, उनके पास पी० ए० हैं, सरकारी डाक और लिफाफे हैं, टिकटें हैं, आखिर कारण क्या है कि जवाब नहीं दें? एक शिष्टाचार है। आप काम कीजिये, मत कीजिये लेकिन आपको कोई विधायक पत्र लिखता है तो शिष्टाचार के नाते आप पत्रों का उत्तर नहीं देते तो आपको कोई राईट नहीं हैं मंत्रिमंडल में बैठने का।

मेजर श्री फतह सिंह : इस बात से मैं भी सहमत हूं।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, लोग यहां कहते हैं, राजनीति में मत पड़िये लेकिन मुझे अफसोस है मंत्रिमण्डल से निवेदन करना चाहता हूं कि सारी सत्ता का केन्द्रीकरण क्यों कर रखा है? मेरे क्षेत्र में जैसे पटवारी है वह लूट नहीं करता है या जनता की कोई समस्या है तो उसके लिये आपके पास भागना पड़ता है। सारी पावर आपने अपने हाथ में ले रखी है। इस प्रकार का प्रयोग मध्य प्रदेश की जनता गवर्नमेंट ने शुरू किया है कि वहां के जिला के विधायक जिसको भी चाहें, अपने आप ले सकते हैं..

एक माननीय सदस्य : सत्ता का विकेन्द्रीकरण।

श्री मूलचन्द डागा : यह हरगिज नहीं करेंगे।

श्री मदनसिंह दांता : सुझाव दो, हर डिस्ट्रिक्ट में विधान सभा बना लो।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : मैं तो आपके सामने कह रहा हूं, इससे परेशानी दूर हो जायेगी।

मेरे साथी विधायक श्री हरीश शर्मा ने आपका आयुर्वेद विभाग के बारे में ध्यान आकर्षित किया। मेरे पास भी इस किस्म की शिकायतें हुई। निदेशक महोदय का व्यवहार सही नहीं है। लोगों को परेशान कर रहे हैं। हमारे जो पिछले आयुर्वेद मंत्री हैं वे तो उनको कन्ट्रोल नहीं कर पाये। लोगों की शिकायत है वह मैं आपके सामने पेश करता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जल्दी समाप्त कर रहा हूं।

कुछ चिकित्सा के डॉक्टर हैं, वे ऐसे डॉक्टर हैं जिनके खिलाफ 5-5 साल से जांच चल रही है। अवधनारायण सक्सेना सन् 72 से सस्पेन्ड हैं किन्तु उनको निर्वाह भत्ता नहीं मिल रहा है। उनके बच्चे क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे। मंत्री महोदय, आपको जो कुछ भी निर्णय लेना हो वह लें लेकिन आपके अपने नियम हैं उनके अनुसार निर्वाह भत्ता तो कम से कम देना ही चाहिये। 5 साल से निर्वाह भत्ता नहीं दिया। आपके सचिवालय के कर्मचारियों को जब तक पैसा नहीं दें यह सारा काम निपटाया नहीं जा सकता। आप सर्वोदयी विचारधारा के नेता

(श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा)

हैं, और सर्वोदय में आपका दृढ विश्वास है तो आप इन बुराइयों को मिटाइये। जनता से आपने वायदे किये हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की बात कह कर समाप्त करता हूं।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के अन्दर पिछले साल से कोई लेडी डॉक्टर नहीं है। मनोहरथाना पंचायत समिति हेडक्वार्टर हैं वहां हैल्थ सेन्टर है। पांच साल से कोई लेडी डॉक्टर नहीं है। एक बंगाली डॉक्टर हैं उनको आपने लगा रखा है, जो भाषा ही नहीं समझते ....

एक माननीय सदस्य : मज तो समझते हैं।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सारा हमारा झालावाड़ जिला है पूरा उपेक्षित रहा है . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कांग्रेस के जमाने में कुछ सुनवाई नहीं हुई। आज कम से कम विकास के सन्तुलन की दृष्टि से झालावाड़ जिले को ध्यान में रखा जाये चाहे सड़कों की बात हो, चाहे बिजली की और चाहे कोई और।

यही बात कह कर समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह !

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनू): माननीय उपाध्यक्षजी, बापू की पुण्य समाधि पर सामूहिक तौर से जननायक श्री जयप्रकाश नारायण की साक्षी में शपथ लेकर जब केन्द्रीय सरकार ने सत्ता को ग्रहण किया था उस समय हिन्दुस्तान की सारी जनता को ही नहीं बल्कि मुझे भी अहसास हुआ था, शायद नया प्रशासन जनता में नैतिक और राजनैतिक नये मापदण्ड स्थापित करेगा और आर्थिक और सामाजिक क्रांति के पथ पर तेजी के साथ अग्रसर होगा। लेकिन एक साल के बाद, केन्द्र को एक साल बीत गया, राज्य सरकार के 9-10 महीने बीत गये सादगी की बात करने वाले, उच्च विचार रखने वाले, आराम और मौज से दूर रह कर समग्र क्रान्ति के आह्वान करने वाले, सेवा का अपने जीवन में ध्येय लेकर चलने वाले लोगों की हकीकत क्या है, वह मैं आपको आंकड़ों के माध्यम से बताना चाहूंगी। सन् 1976-77 में मंत्रियों के वेतन पर 14 लाख 9 हजार रुपये खर्च होते थे, सन् 1977-78 में 19 लाख 96 हजार और वर्ष 1978-79 में 38 लाख 20 हजार रुपये खर्च होंगे। एक मंत्री पर प्रति वर्ष 1 लाख 92 हजार खर्च होंगे और प्रति माह 16 हजार खर्च होंगे..

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : White elephants.

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आर्थिक और सामाजिक क्रान्ति की उद्घोषणा करते हैं लेकिन आज इससे परे एक दूसरा पक्ष है। मंत्रियों में ताल मेल नहीं, जोइन्ट रेस्पान्सिबिलिटी अथवा सामूहिक उत्तरदायित्व की कमी है और कब किससे कौनसा विभाग ले लिया जायेगा, इसका किसी मंत्री को पता नहीं ..

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : इसकी चिन्ता नहीं होनी चाहिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इन्हें होगी, हमें तो चिन्ता नहीं है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आपको क्या काम है इनके विभागों से ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं तो केवल याद दिलाना चाहती हूं, सत्ता के परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में जो बापू की समाधि पर शपथ ली गई थी कि सादगी से जीवन बितायेंगे इस परिप्रेक्ष्य में मैं निवेदन करती हूं कि आपस में ताल-मेल ही नहीं। जिस तरह खींचा-तानी हो रही है, एक मंत्री का हुक्म दूसरा मंत्री नहीं मानता। मैं यह कहूंगी मुझे तो अच्छा नहीं लगा। मुझे अच्छा न लगे, लेकिन यह बात कोई न्यायसंगत नहीं होगी, क्योंकि जनता को तो पता लगाना आवश्यक है कि मौजूदा सरकार, जो जनता पार्टी की सरकार है, में कैसे काम होते है, कितनी एक दूसरे की इज्जत करते हैं। एक दरख्वास्त पर माननीय राज्य मंत्रीजी, जो मेरे सामने बैठे हुये हैं डूंडी साहब ने आदेश दिया। दरख्वास्त देने वाले ने कहा, आदेश करवा लिये हैं, यह लीजिये आदेश। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, तीन दिन पीछे मंत्रीजी के आदेश का क्या हुआ ? मैं यह मानती हूं कि वह विभाग उनसे सम्बन्धित नहीं था। वह आदेश फाड़कर फेंक दिये गये। सम्बन्धित मंत्री ने फाड़कर फेंक दिये . . .

श्री शंकरलाल : वह कौन था ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं नहीं बताऊंगी ये लाल चन्दजी जाने और वे जाने।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह तो बोलना पड़ेगा। नाम नहीं लेना चाहिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कोलायत और जैतारण से आने वाले दोनों माननीय सदस्यों को मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि प्रशासन के हित में न जाने कितने काम होते हैं लेकिन सार्वजनिक तौर से बताये नहीं जाते हैं। मैं भी प्रशासन के हित में बताना उचित नहीं समझती हूं।

तो मैं निवेदन कर रही थी आपस में ताल-मेल नहीं हो, एक मंत्री दूसरे मंत्री के आदेश को नहीं माने, एक दूसरे की इज्जत नहीं करें तो जनता किस प्रकार अपनी प्रिवेलेज को वेंटीलेट करे। आज जनता सरकार की छबि धूमिल पड़ चुकी है।

(व्यवधान)

विपक्ष के नाते मुझे कहना पड़ता है। जो जनता सरकार की तस्वीर आज के दिन जनता में है उसको पेश करने का मैंने प्रयास किया है। मेरी लड़ाने की कोई मंशा नहीं है...

श्री खेतसिह राठौड़ : राहु की दशा से अपने आप मरेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : .....इनको अपने विभागों के बारे में इस बात की हमेशा चिन्ता रहती है कि हमारी कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई विभाग कब तक रहे, यह आज इनको पता नहीं, जनता पार्टी के बोलने वाले सदस्य यह कहते हैं। सत्तारूढ़ दल के सदस्य कहते हैं तो एक चिन्तन की बात हो जाती है। अभी कल ही सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य कह रहे थे, एक छोटा मुख्य मंत्री भी है। जिस सरकार के मुख्य मंत्री कोई और हों, छोटा मुख्य मंत्री कोई और हो, बड़ा मुख्य मंत्री कोई और हो, आपस में मंत्री लोग एक दूसरे के आदेशों की उपेक्षा करें, अपमान करें, वहां क्या उम्मीद हो सकती है ? मैं तो, माननीय उपाध्यक्ष

# Page No 126

(126)



(श्रीमती सुमित्रा सिंह)
महोदय, यही निवेदन करूंगी साल भर से इस जनता सरकार ने अपनी छवि को धूमिल कर दिया।

अब मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने चिकित्सा के कटौती प्रस्तावों को लेना चाहती हूं। मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, मलेरिया इस प्रदेश में फैला। इस बार बरसात के मौसम में गांवों में बड़े पैमाने पर लोग इस बीमारी से ग्रस्त हो गये किन्तु डी.डी.टी. का स्प्रे समय पर नहीं किया जा सका। जब मैं अपने इलाके में गई और लिखित रूप में दिया कि गांवों में भयंकर रूप से मलेरिया फैला हुआ है। बीमारी के उपचार की व्यवस्था की जावे, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि मलेरिया बीमारी के प्रिवेन्टिव मेजर्स ये ले नहीं सके। डी.डी.टी. का स्प्रे समय पर नहीं हो सका। जिस वक्त डी. डी टी. का स्प्रे होना चाहिये था, उस समय स्प्रे नहीं हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकर ताज्जुब होगा जिस डी. डी. टी का स्प्रे अगस्त में शुरू किया गया था वह आज फरवरी और मार्च में भी पूरा नहीं हुआ है। इस जनता सरकार में जो डी. डी.टी. आ रही है वह भी पुरानी है या मिलावट की हुई है, सब स्टेण्डर्ड है, मच्छर इम्यून हो गये हैं जो मरते ही नहीं हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्षजी, आपने घंटी बजा दी।

पिछली बार कांग्रेस सरकार ने झुन्झुनू निर्वाचन क्षेत्र बीजूसर गांव में एक डिस्पेन्सरी खोलने का आदेश दिया था। आज से तीन वर्ष पूर्व एक दानदाता ने तीन लाख रुपये लगा करके इमारत बनाई। सरकार ने एग्रीमेन्ट किया था, उस एग्रीमेंट के मुताबिक यह आश्वासन दिया था कि यदि पेटर्न के मुताबिक, पी. डब्लू. डी. के अप्रूव्ड नक्शे के मुताबिक यदि आप हमको इमारत देंगे, और साथ में इक्विपमेंट पूरा देंगे तो हम डिस्पेन्सरी खोल देंगे। उसी के मुताबिक एक दानदाता महोदय ने तीन लाख रुपये खर्च किये। पिछली बार कांग्रेस प्रशासन ने डिस्पेन्सरी खोलने का न केवल आश्वासन दिया था बल्कि खोले जाने के आदेश भी दिये थे लेकिन, माननीय उपाध्यक्षजी, सत्ता का परिवर्तन हो गया। अब वैमनस्यपूर्ण तरीके से उसको बंद किया जाना नीति के एवं जनहित के विपरीत है, सिद्धान्तों के विपरीत है। एक कहावत है, हाकिम चला जाता था, लेकिन हुकुम नहीं जाता, यानि हाकिम जाता है, हुक्म कभी नहीं जाता है, लेकिन इस जनता पार्टी के प्रशासन में हाकिम के साथ हुक्म भी चला गया....

श्री बालकृष्ण थानवी : शराबबन्दी का आपका हुक्म था, वह कैसे चला गया ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन कर रही थी कि राजनीति का सिद्धान्त है, यह नीति का सिद्धान्त है कि हाकिम चला जाता है, लेकिन हुक्म नहीं जाता है। वह हुक्म क्यों जाये ? जो जनता के हित में दिया में जाता है, सर्व जन हिताय, सर्वजन सुखाय में जो हुक्म दिया जाता है वह कभी नहीं जाता है। लेकिन जनता सरकार को, क्योंकि उसका समग्र क्रान्ति का ध्येय है, मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहूंगी और तीखे शब्दों में आरोप गाना चाहती हूं चूंकि वह मेरे निर्वाचन

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

क्षेत्र में है और मैं विपक्ष की सदस्या हूं इस लिये सरकार उस एग्रीमेंट से मुकर गई। और साथ में तीन लाख रुपया सरकार के कहने से चिकित्सा विभाग के कहने से खर्च किया, उस पूर्व के आदेश को कांग्रेस सरकार के पूर्व के आदेश को, इस जनता सरकार ने निरस्त कर दिया। और आज हालत यह है कि उस तीन लाख रुपये की इमारत में गधे जाते हैं, जानवर जाते हैं और मवेशी जाते हैं। उस डिस्पेन्सरी में स्टाफ नियुक्त किया जा चुका था। उन्होंने जाकर चार्ज सम्भाल लिया था परन्तु पता नहीं, क्यों और कैसे स्टाफ को वापस बुला लिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय उपाध्यक्षजी, इन्हीं शब्दों के साथ में मेरे कटौती के प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रतनराम आर्य।

(अनुपस्थित)

श्री बाजकृष्ण यादव : क्या खेतसिंहजी इस तरह से करके ईसा मसीह बनने जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह मकासर !

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़): माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके मार्फत अपने कटौती प्रस्ताव पेश कर रहा हूं। सबसे पहले मैं चिकित्सा पर बोलूंगा चिकित्सा का दरअसल आधार क्या है ? मौजूदा चिकित्सा का आधार है, जिसके पास पैसा है वह जिन्दा रहे, जिसके पास पैसा नहीं है वह मरे। और जब यह सिद्धान्त कोई भी सरकार लागू करती है तो हमारी नजर उन अस्सी फीसदी लोगों की तरफ जाती है जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, जिनके पास रहने को घर नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है। तो ऐसे लोग कहां से दवाई लेंगे ? माना कि आपने इन्तजाम कर दिया बड़े-बड़े शहरों में, बड़े-बड़े हॉस्पिटल खोल दिए, आपके डाक्टर क्या काम करते हैं ? माननीय मंत्री महोदय, आप तो सर्वोदयी हैं और मेरे खयाल में सर्वोदयी होने के नाते कम से कम मेरे खयाल से सहमत तो नहीं होंगे मगर मेरी राय में हमदर्द तो जरूर होंगे, आज इस सिस्टम को खत्म कर दिया जाय। मेहरबानी करके आप बताइये, आपके डॉक्टर क्या काम करते हैं ? अगर कोई बड़े घर का आदमी कार लेकर आता है तो सलाम ठोकते हैं, और अगर कोई गरीब चला जाएगा तो पर्ची लिख कर दे दी जाती है। वह पर्ची लेकर जायेगा कहां ? आज दवाई की क्या हालत है। कितनी कीमत बढ़ गई है दवाई की। वह पर्ची लेकर कहां जाएगा ? शमशान भूमि की तरफ जाएगा, क्योंकि पैसा नहीं है उसकी जेब में। आपने कोई व्यवस्था की है ? राजस्थान जैसे प्रदेश में और देश के अन्दर आपने बहुत बड़ा वायदा किया है जनता को। ठीक आठ महीने बाद अभी मेरे से पहले बोलने वाली माननीय सदस्या, झुन्झुनू से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि आपका आपस में मेल नहीं है नीतियों का। तो कहा आपको चिन्ता करने की जरूरत नहीं। यह चिन्ता आपकी तो मिट गई। गद्दियां मिल गईं। जिनको सरपंची नहीं मिलती थी उनको एम. एल. ए. के पद मिल गये। जिनको वार्ड मेम्बरी नहीं मिल सकती थी उनको एम. एल.

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

ए. के पद मिल गये। आपको चिन्ता तो खतम हो गई। मगर यह चिन्ता इस देश के तमाम लोगों की चिन्ता है। आपकी कार्यवाहियों को, आपकी नीतियों को लोग देखते हैं बाहर। यह कोई अकेली आपकी जिम्मेदारी नहीं। ठेका नहीं लिया। देश के लोग बहुत ही संजीदगी से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है? वही बाबू जयप्रकाश हैं सम्पूर्ण क्रांति का मसीहा, क्या हो रहा है उनके साथ? कुछ वर्ग संघर्ष की बात कही थी और सम्पूर्ण क्रांति की बात कही थी जिसका आज अन्त हो रहा है? वही विद्यार्थी, वही नौजवान बिहार का, जिसने उसके आदेश पर देश के अन्दर एक तब्दीली पैदा की, आज वही भटका हुआ है। और मायूस विद्यार्थी क्या करता है? किस पर पत्थर मारे जाते हैं, किस पर जूते फेंके जाते हैं? जयप्रकाश बाबू की सभाओं पर? इससे ज्यादा चिन्ता और शर्म की बात हो नहीं सकती। बात करते हैं वर्ग संघर्ष की। यह सारा का सारा पैसा आप बड़े-बड़े शहरों में लगायें, जहां दुर्लभजी जैसे हॉस्पिटल मौजूद हैं, तथा अन्य हॉस्पिटल मौजूद हैं। बड़े लोगों को बड़ी जगह मरने दीजिए और छोटे लोगों की तरफ जाइये। यह सब अपनी दुकानें बन्द कर दो, कोई दवा बिकेगी नहीं। दवाई इंसान को जिन्दा रखने के लिए होती है। यह कोई खाने की चीज है, या पेट भरने की चीज है? नहीं।

श्री मदनसिंह दांता : और जयप्रकाश के इलाज पर जितना खर्चा किया, उतने से तो एक हॉस्पिटल खुल जाता।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह बात अलग है। किसी भी देश के नेता के लिए, देश के किसी भी आदमी के लिये जितना पैसा खर्च किया जाय उतना कम है, फिर चाहे वह जयप्रकाश हों, चाहे कोई भी हों। हम कहते हैं कि उनके लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा जुटाया जाना चाहिए, यह कोई बुराई की बात नहीं है। उनके लिए खून की भी जरूरत हो तो वह भी दिया जाय। खैर यह अलग बात है ......

(व्यवधान)

श्री मनोहरसिंह मेहता : जयप्रकाश बाबू के लिए कहना आपके मुंह से शोभा नहीं देता।

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : आपसे इस तरह की आशा नहीं थी।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : क्या राजा महाराजाओं की तरह बात करते हो।

श्री मदनसिंह दांता : मैंने इसमें क्या गलत बात कही है? मैं तो यह चाहता हूं कि जैसे जयप्रकाश बाबू के इलाज के लिए व्यवस्था की, ठीक उसी तरह से गरीब की झोंपड़ी में बसने वाली औरत के लिये भी व्यवस्था होनी चाहिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप जयप्रकाश की तुलना राजा-महाराजाओं से नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : आप कैसे कहते हैं कि यह खर्चा सरकार ने किया था? जनता ने पैसा इकट्ठा किया है। आपके पास पैसा हो तो आप भी किसी गरीब आदमी को भेज सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांति रखिये ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : पोइन्ट ऑफ आर्डर, सर...

(व्यवधान)

श्री त्रिलोकचन्द जैन : आप यह गलत-फहमी में नहीं रहें, सारा पैसा जनता ने खर्च किया है । जो नब्बे लाख की थैली दी है वह भी जनता ने ही इकट्ठी की है ....

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : जब भारत के राष्ट्रपति अपना इलाज कराने अमेरिका जाते हैं और उन पर जो खर्चा किया जाता है उसी तरह से गरीब पर क्यों नहीं किया जाता ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये ।

श्री रतनलाल वर्मा : यह रुपया जनता ने खर्च किया है सरकार ने नहीं किया है ।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : क्या इस हाउस के लिए उचित होगा कि आज देश के नेता जयप्रकाश नारायण के इलाज के बारे में ऐसी ऐसी बातें की जायं ? इस तरह की बातें की जायं ? जिस व्यक्ति ने देश को सर्वस्व दे दिया, मरते दम तक अपने खून की एक-एक बूंद देने को तैयार है, उस नेता के लिए ऐसी बातों का उपयोग करना क्या हाउस के लिए उचित है ?

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : यह देश के किसी नेता का सम्बन्ध नहीं है, यह इक्वलिटी का प्रश्न है । उनके लिए हुआ है तो गरीब के लिए भी होना चाहिए ।

श्री किशनसिंह भाटी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जे. पी. राष्ट्र के नेता हैं, उनके लिए ऐसे शब्दों का इनको प्रयोग नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिये ।

(व्यवधान)

यह आक्रोश की बात नहीं है, भावनाओं का सवाल है ।

श्री मदनसिंह दांता : मैं तो चाहता हूं कि उनका इलाज जरूर हो, लेकिन इसके साथ ही गरीब की झोंपड़ी में रहने वाले का भी इलाज हो ।

श्री किशनसिंह भाटी : राष्ट्रपति के लिए कहें, किसी और पदाधिकारी के लिए कहें, लेकिन जे. पी. के लिए कहना शोभा नहीं देता। वे सम्पूर्ण राष्ट्र के सम्माननीय नेता हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको कहना चाहूंगा कि अब इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ायें। जब हम कोई भी शब्द, राष्ट्रपति के बारे में हों या राष्ट्र नेता के बारे में हों, उनका उपयोग करें तो उनके प्रति पूरा आदर रखना चाहिए ।

श्री मदनसिंह दांता : मैंने अनादर की कौनसी बात कही है। मैंने तो यही कहा कि जहां उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था करें, वहां गरीब की झोंपड़ी में रहने वाले के लिए भी होनी चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : ये शब्द व्यंग्य में कहे गये हैं और ये व्यंग्य के शब्द वापस लिए जाने चाहिएं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजिये । माननीय सदस्य श्योपतसिंहजी, अपना भाषण जारी रखें ।

श्री टीकमचन्द कान्त : माननीय जे. पी. के बारे में कहे गए शब्द वापस लिये जावें ।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : वह देश के नेता हैं, तो वैसे देश के नेता न मालूम कौन-कौन हो गए हैं।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, उनके इलाज में जो व्यय किया गया है वह जनता ने किया है । मैं बता देना चाहता हूं कि जनता ने लोकनायक जयप्रकाश नारायणजी पर अपना विश्वास और श्रद्धा प्रकट करके इलाज करवाया है। इस प्रकार के शब्द जो ठाकुर साहब ने कहे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि इन शब्दों को वापस लें ।

श्री किशनसिंह भाटी : ठाकुर साहब की भावना तो इसी से प्रकट हो गई कि उन्होंने कहा कि देश में कौन-कौन नेता हैं , पंच और सरपंच भी नेता हैं । पंच और सरपंच से जे. पी. को कम्पेयर कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ठाकुर साहब से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि वे अपने शब्द वापस लें । जे. पी. का इलाज देश ने कराया है । उनका इलाज सरकार ने नहीं कराया है, राजस्थान सरकार ने नहीं कराया है , भारत सरकार ने नहीं कराया है । जनता के गरीब तबके ने करवाया है । आप अपने शब्द वापस लें ।

श्री मदनसिंह दांता: अगर सारे सदन की मन्शा यह है कि मैं अपने शब्द वापस लूं तो मुझे एतराज नहीं है लेकिन मेरी भावना को समझें । उन पर जितना खर्च हुआ है, उतना हो गांव के गरीब से गरीब आदमी पर हो ।

(व्यवधान)

आपसे ज्यादा मेरी जे. पी. पर श्रद्धा है । मैंने उन्हीं के सिद्धान्तों पर कहा था कि वैसा ही इलाज गांव की गरीब से गरीब स्त्री का झोंपडी में रहने वाली औरत का हो, तो इसमें क्या अन्याय हो गया ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं मंत्री महोदय से एक दरख्वास्त करूंगा कि आप पांच साल तक शहरों में जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं उन पर कोई खर्चा न करें और उस पैसे को गांवों में खर्च करें और शुरू करें मेडिकल स्टोर्स जहां से दवायें गरीबों को फ्री मिलें। आप एक एक्सपेरीमेंट करें। पैसे वाला वहां कभी नहीं जायेगा, जहां से दवाइयां फ्री मिलेंगी गरीब को । जहां पर झोंपड़ी वाले को 10 पैसे की टिकिया फ्री मिलेगी, वहां पर बड़ी-बड़ी कार वाले लोग नहीं जायेंगे । उनकी दवाई दूसरी है, उनका इलाज दूसरा है । इसलिए आप हर गांव के अन्दर मेडिकल स्टोर

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

खोलें सरकार की तरफ से जहां कि गरीबों को दवाइयां उपलब्ध हों, जो भी डॉक्टर लिख कर देगा ...

श्री मदनसिंह दांता : नहीं मिलेगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : और सारी बातों को तो आप छोड़ दीजिये सबसे पहले दस पैसे की टिकिया की व्यवस्था कीजिये गरीब के लिए, जिसके पास एक पैसा नहीं है और जो मौत से जूझ रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं अर्ज करना चाहूंगा मेरे क्षेत्र के बारे में, मैं अपने क्षेत्र की बात नहीं करता हूं, मेरे गांव मकासर के 20-20 मील के एरिया में कोई हॉस्पिटल नहीं है। वहां पर एक गांव पक्का सारणांव हॉस्पिटल खोला गया। जब हॉस्पिटल खोलने की बात आई तो पहले एक कन्डीशन रखी कि पहले भवन बनाकर दो। गांव वालों ने 60 हजार रुपये इकट्ठे किये, 2-2 रुपये का चन्दा करके और हॉस्पिटल बना दिया। डॉक्टर पहुंच गया, कम्पाउण्डर पहुंच गया, नर्स पहुंच गई। अभी 5-7 दिन पहले हुक्म हुआ है कि डॉक्टर साहब को गंगानगर भेज दिया जाय। वह हॉस्पिटल तोड़ दिया गया है। यह क्यों हुआ? क्या हॉस्पिटल शहरों में ही खोले जायं, गांवों में नहीं खोले जायं? अगर वह हॉस्पिटल बदलकर किसी गांव में ले जाते तो मुझे खुशी होती। एक नीति का सवाल कायम कर देना चाहिए, मंत्रीजी। आप मंत्री रहें या नहीं रहें, लेकिन आप नीति तय कर दें कि आपको दवा किसको देनी है, हॉस्पिटल कहां पर खोलना है, डॉक्टर कहां आयगा। इसी सझाव के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि आज आप घोषणा करेंगे इस सदन में कि मेडिकल स्टोर्स गांव में गरीबों के लिए भी खोले जायेंगे।

इसके साथ-साथ मैं दूसरा सुझाव मंत्री परिषद् के लिए दे रहा हूं। मंत्री परिषद् से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अधिकारियों पर दरअसल काबू नहीं कर पा रहे हैं। आप यहां पर कुछ तजुर्बेकार या जानकार लोगों को टिकट देते और एम. एल. ए. बनाते।

श्री कौशल किशोर जैन: आपको रखेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं भी टिकट ले लेता आपकी तरह, अगर मुझे जाना होता तो। आप जैसे ही आ गये तो मैं भी आ जाता।

मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके अधिकारी इतने मगरूर हो रहे हैं कि कुछ हद नहीं। मैं ठीक कहता हूं कि आपने पूनियाजी को पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर बना दिया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर से कि क्या आपके सेक्रेटरी, पी. डब्ल्यू. डी. इतने दिनों में कर्टसी के तौर पर कभी मिलने आये हैं? मिलने नहीं आये हैं, यह मैं जानता हूं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि मंत्रीजी से नहीं मिले हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आपको कैसे मालूम है?

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं जो बात कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। इस तरह के अधिकारी हैं और मैंने ऐसे अधिकारियों को देखा है। अभी एक आदेश हमारे उपनिवेशन राजस्थान कैनाल के

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

मंत्रीजी प्रोफेसर केद रजी ने एक डी. ओ. लेटर लिखा सेक्रेटरी के नाम, इरिगेशन सेक्रेटरी के नाम लिखा, उसका क्या रिजल्ट हुआ ? उस अधिकारी का तबादला हुआ। वह सेक्रेटेरियट में मंत्रीजी से मिला। क्यों मिला ? उस बख्तावरसिंह की मंत्रीजी से क्या बात हुई ? मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आपने मिड ऑफ दी सेशन में उसका तबादला कर दिया। कॉलिज में उसके बच्चे पढ़ते थे, दूरदराज चण्डीगढ़ के अन्दर तबादला कर दिया है। तो उसकी परेशानी लेजिटिमेट थी। मैं नहीं कहता कि तबादला न करें . . .

(4.27 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पीठासीन)

बख्तावर सिंह मुझे इस सड़क पर मिला, जयपुर में पहली दफा मिला, उसने अपनी सारी गाथा मुझे सुनाई। मैं उसको इरिगेशन मिनिस्टर के पास ले गया तो उन्होंने एक डी. ओ. लिखा लेकिन उनके हुक्म को माना नहीं गया।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आप करप्ट व्यक्ति को ले गये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय सदस्य, कोलायत से आने वाले, मैं नहीं कहता कि वह करप्ट नहीं है। अगर करप्ट है तो उसको फांसी लगा दो। मैंने किसको रोका है कि उसके खिलाफ जांच न हो। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि उसका तबादला क्यों किया गया ? मैं कहता हूं कि आपके मिनिस्टर के हुक्म की तामील नहीं की गई। अगर वह करप्ट था तो सजा देते। मैंने नहीं रोका। मैंने नहीं कहा कि सजा मत दो। मैं एक बात कहता हूं कि जो अधिकारी आपके मंत्री महोदय के हुक्म की परवाह नहीं करते उनके डी. ओ. लैटर की परवाह नहीं करते हैं तो कलेक्टर आपके दूसरे हुक्म की मखौल उड़ायेंगे। मैं पूछता हूं कि यह क्या बात है ? इरिगेशन सेक्रेटरी के बारे में, मैंने माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाया है, माननीय सभापति महोदय, जिस अधिकारी की बात मैंने कही है वह अधिकारी इतना मगरूर हो गया है कि उसके खिलाफ इस सदन के अन्दर हमारे जयपुर से आने वाले सदस्य ने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। मैं किसी अधिकारी को प्रोटेक्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं। आपके अधिकारी बहुत मगरूर हैं उनको ठीक करें। मैं यह नहीं कहता कि सारे अधिकारी ऐसे हैं। जो ईमानदार हैं, जो व्यवहार कुशल हैं जो ठीक लोग हैं उनकी तारीफ करें, उनको, तरक्की दें और अपने डिपार्टमेंट में ऐसे अधिकारियों को रखें।

इसके साथ-साथ, माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री परिषद् से एक और बात कहूंगा। मंत्री परिषद् पर मैंने कट-मोशन दिया है। मेहरबानी करके यह सेक्रेटेरियट छोड़ दीजिये वरना यह खा जायगा आपको। जहां पचास लाख रुपया लगाकर आप बैठेंगे, आपकी आत्मा आपको कचोटेगी। यह जो हुक्म है, कांग्रेस का है और बजा आप रहे हैं। यह ठंडा करने का कूलर आप लगा रहे हैं और आप इसमें बैठेंगे तो बीमार हो जाएंगे। क्योंकि राजस्थान की यह धरती ऐसी है कि ठंडे कमरे से बाहर निकलते ही आपको जुकाम पकड़ लेगा।

माननीय सभापति, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, आज जनता पार्टी की मंत्री

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

परिषद् ठंडे और गर्म होने वाले सचिवालय में बैठे जिस पर पचास लाख रुपये खर्च होंगे तो आपकी बदनामी होगी। यह आपके पक्ष की बात नहीं है। इसका होस्टल बना दीजिये। लड़कों का होस्टल बना दीजिये। बहुत विद्यार्थी हैं। या अगर होस्टल नहीं बनाना चाहते हैं तो कम से कम कोई अस्पताल या मरीजों का वार्ड बना दें। इस पैसे को आपने व्यर्थ ही बरबाद किया है। आप दफ्तर अपने घर पर ले जाएं। कोठियों में ले जाएं। कोई जरूरत नहीं है इतने बड़े दफ्तर की। मिनिस्टरों की कोठियां बहुत बड़ी हैं। इसलिए इनके लिए सचिवालय की जरूरत नहीं है। यह दो टायर, थ्री टायर एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। आप इसमें तब्दीली कीजिए। कोई सेक्रेटेरियेट की आवश्यकता नहीं है। गृह मंत्री महोदय के पास आई० जी० पी०, डी० आई० जी० है एक दर्जन से ज्यादा डी०आई०जी० है। फिर क्या जरूरत है गृह मंत्री महोदय को गृह सचिव और दूसरे अधिकारियों की। मेहरबानी करके आप इस सचिवालय को हटा दें। आप इस सचिवालय में न बैठें, यह मेरी राय है। मैं यह नेक सलाह आपको देना चाहता हूं एक दोस्त के तौर पर। इस गर्म-ठंडे होने वाले सचिवालय में आप बैठेंगे तो आपकी बदनामी होगी। मेहरबानी करके आप न बैठें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : दोस्त ये आपको मानते नहीं ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ अपने कट मोशन मूव कर रहा हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री नवरंगसिंह !

श्री किशनसिंह भाटी : सभापति महोदय, हाउस के अन्दर माननीय सदस्य टेम्पटेशन दे रहे हैं। यहां यह जरूरत नहीं है।

श्री सभापति : श्री नवरंगसिंह !

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़): सभापति महोदय, जिन आकांक्षाओं और इच्छाओं को लेकर सत्ता में यह परिवर्तन आया, ऐसे परिवर्तन के जरिये हिन्दुस्तान में एक नई क्रान्ति करने की बात जयप्रकाशजी ने की। नये मंत्रिमण्डल ने इस राजस्थान में शपथ ली तो राजस्थान की जनता की यह इच्छा,यह आकांक्षा थी कि जयप्रकाशजी की इच्छा के अनुसार, गांधीवादी विचारधारा के अनुसार सादगीपूर्ण जीवन हमारा मंत्रिमण्डल अपनाये। परन्तु मुझे इस बात का दुःख जरूर है कि हमारा मंत्रिमण्डल उसी लाइन पर कदम बढ़ा रहा है जिस लाइन पर 30 साल तक पिछली कांग्रेस सरकार ने बढ़ाया। सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्रिमण्डल के सदस्यों को यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह समय न ज्यादा बातों का है, न अभी ज्यादा समय बीता है, समय है और समय रहते ही इन्होंने हमारी जनता की इच्छा, आकांक्षाओं को नहीं समझा तो परिणाम कठोर होगा। इसके लिए मंत्रिमण्डल के सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे एक विधायक के रूप में अपनी तनख्वाह लें और मंत्री की तनख्वाह न उठावें और जो दो-दो हजार रुपये की तनख्वाह उठा रहे है, वह छोड़ें। दूसरी बात उनको मैं यह कहना चाहता हूं कि वे कार में न चलें। अगर उनको ज्यादा काम है तो स्कूटर पर आवें। कार का खर्चा हमारा राजस्थान बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक वक्त था जब जनता नारेबाजी से बहक जाती थी। अब वह

(श्री नवरंग सिंह)

वक्त चला गया। नारेबाजी से अब जनता को बहकाया नहीं जा सकता है।

सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा मंत्रि-मण्डल जो निर्णय लेता है, उस निर्णय की पालना बहुत कम होती है। हमारे मंत्रि-मण्डल के निर्णय केवल फाइलों की शोभा बढ़ाते हैं। मैं आपको अर्ज करूं कि जब यहां पर गृह विभाग पर मंत्री महोदय रिप्लाई दे रहे थे मैंने गृह मंत्री महोदय से पूछा कि अगर आपके आदेश को राजस्थान का आई० जी० पी० पालन नहीं करे तो आपको क्या महसूस होगा? मुझे इस बात का दुःख है, हमारे मन्त्री ने यहां पर कहा कि मैं वह आदेश वापस ले लूंगा। मान्यवर, यह शर्मनाक स्थिति है। इसलिए आदेश ऐसा दो जिसकी पालना हो। अगर अधिकारी पालन नहीं कर सकता तो जनता सरकार को ऐसे ऑफिस को बख्सने की जरुरत नहीं है।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि हमारे मुख्य मंत्री यह कहते है कि हमने परम्परा को तोड़ा है। कुछ हद तक परम्पराएं टूटीं हैं लेकिन जिस रोज जयपुर जिले के किसान यहां आए मुख्य मंत्री महोदय यह परम्परा कहां चली गई? कहने लगे, यह विधान सभा की परम्परा का सवाल है। इसलिए मंत्री साहबान को यह निवेदन करना चाहूंगा आपकी मार्फत सभापति महोदय, जयप्रकाशजी ने जो नारा दिया था, परम्पराओं को तोड़ना है, उस नारे को केवल नारे के रूप में नहीं बल्कि जनता इसे कार्य रूप में परिणित होते हुए देखना चाहती है। परन्तु, सभापति महोदय मैं निवेदन करूंगा, आज हमारे मंत्रियों का काम बचा है केवल तबादले करना। मैं यह अर्ज करूंगा, राजस्थान के शिक्षा विभाग में 20 हजार अध्यापकों के तबादले हमारे मंत्री ने किए। 15 हजार पंचायत समिति के कर्मचारियों के तबादले किए गये। इससे हमारे खजाने पर बहुत बड़ा भार पड़ा। यह इस बात को साबित करता है कि हमारी सरकार के मंत्री भी उन्हीं पदचिन्हों पर चल रहे हैं जिन पर कि पहले की सरकार चल रही थी। इसलिये, सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करूंगा कि मंत्रियों का काम तबादला करना नहीं है। मंत्रियों का काम नीति निर्धारित करना है और उसकी पालना कराना है। इन्हीं शब्दों के साथ जो मैंने दूसरे कट मोशन दिए हैं, डिस्पेन्सरी के बारे में, उस बारे में अर्ज करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, आज भ्रष्टाचार इस स्वास्थ्य विभाग में ताण्डव नृत्य कर रहा है। सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि झुन्झनूं के डॉक्टर, सी०एम०ओ०, के० एल० गुप्ता खुलेआम पैसा लेते हैं। किसी भी तरह का पेशन्ट हो, उसको तब तक भर्ती नहीं किया जाता है जब तक वह घर जाकर उनको फीस नहीं देता है। यह दर्दनाक स्थिति झुन्झनूं के अस्पताल की है। मेरे सामने इसी प्रकार की एक शिकायत आई। मैं झुन्झनूं गया हुआ था विजिलेन्स कमेटी की मीटिंग में भाग लेने। बुरी तरह से एक लड़के को मारा गया। उसको भर्ती कराया गया। अगले दिन डॉक्टर ने दूसरी पार्टी से पैसा लेकर छुट्टी कर दी। मैंने फिर उस लड़के को भर्ती कराया दूसरे दिन। तो, सभापति महोदय, यह स्थिति है हमारे स्वास्थ्य विभाग की। हमारे स्वास्थ्य मंत्री सर्वोदयी हैं इसलिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस विभाग की स्थिति को संभाले

(श्री नवरंगसिंह)

और इस स्थिति को देखें। इसी तरह से निवेदन करना चाहूंगा परसुरामपुरा में डिस्पेन्सरी खोलने का आदेश था। यह आदेश राज्य सरकार ने सेठ के साथ हुए एक कान्ट्रेक्ट के अनुसार दिया एक लाख रुपया नवयुवक मण्डल को देने की बात लिख दी। सेक्रेटेरियट के अधिकारियों से डेपुटेशन मिला। सभापति महोदय, आज तक वह हॉस्पिटल नहीं खुल सका। मैं निवेदन करूंगा, ज्यादा से ज्यादा औषधालय और हॉस्पिटल खोले जायें। राजस्थान में दो ही रोग हैं, जिनसे लोग ज्यादा पीड़ित होते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैंने जो कटौती प्रस्ताव के द्वारा सुझाव रखे हैं, आशा है कि मेरे सुझावों पर ध्यान देंगे।

श्री सभापति : श्री बत्तीलाल !

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) : आदरणीय सभापति महोदय, मन्त्री महोदय को मैं महात्मा गांधी . . .

श्री मदनसिंह दांता : यह क्या कह रहे हैं ?

श्री बत्तीलाल : माननीय मन्त्री महोदय, प्रो. केदार जैसे महानुभाव मंत्री हैं, जिनकी कोठी में जनता जनार्दन का मेला लगा हुआ रहता है। उनका खर्चा होता है। वह हनुमानजी की तरह हैं तभी उनकी याद आती है। कांग्रेस के समय में चार-चार एम. एल. ए. खड़े रहते थे, हिम्मत नहीं होती थी कि आई. जी. से बात कर लें। आज हम जनता के प्रतिनिधि जाते हैं तो वह हमसे बात करते हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : यह एम. एल. एज. के लिए क्या कहा जा रहा है ?

(व्यवधान)

श्री बत्तीलाल : इसी प्रकार से जैसे एक कम्पनी से दूसरी कम्पनी में कर्मचारियों में जाते हैं, उसी प्रकार से हमारे प्रतिनिधि यह सोचते हैं . . .

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, एम. एल. एज. के लिए इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए। आई. जी. के पास एम. एल. ए. जायें. . . .

(व्यवधान)

यह अपमानकारक है।

एक माननीय सदस्य : कौन-कौन से आई० जी० के पास गये हैं।

एक माननीय सदस्य : आप ही बताइये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज।

गणेशसिंहजी, पुलिस के इन्सपेक्टर जनरल हैं। अगर कोई माननीय सदस्य उनसे मिलने के लिए जायें तो यह अपमान की कोई बात नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जाना कोई गुनाह नहीं है। हमें किसी को भी जाने की आवश्यकता हो तो आई. जी. के पास जा सकते हैं परन्तु...

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा था, आज हमारी सरकार में सब की सब सुन लेते हैं। पहले नहीं सुनते थे।

श्री सभापति : इस सदन के सभी माननीय सदस्य हैं। माननीय सदस्य एक दूसरे पर इस प्रकार के आक्षेप नही करें। जिससे किसी माननीय सदस्य को ठेस पहुंचे। स्पीच संयमित होनी चाहिए। कोई माननीय सदस्य मतभेद रखें तो भी नाम लेकर नही कहें। उसको जनरल ढंग से कहना चाहिए। मेरे विचार में माननीय सदस्य के कहने में कोई दुर्भावना नहीं रही है। केवल रेफरेंस था।

श्री बत्तीलाल : मेरा कहने का मतलब था, सवार बदल गया है, घोड़ा वही है।

श्री सभापति : आप धीरे-धीरे बोलिए। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। आप ऐसा मानकर बोलिए, जैसे और कोई है ही नहीं। हम भी अकेले हैं।

श्री बत्तीलाल : मैं यह कहूंगा कि जिस प्रकार से जनता सरकार ने आचरण किया है, मैं आशा करता हूं, वह आगे भी निभायेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी जनता सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एकदम क्रान्ति कर दी है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि शिक्षा के लिए और भी स्थानों पर स्कूलों की आवश्यकता है। वहां भी स्कूल खोलने चाहिएं। नहीं तो, यह वैसा ही होगा कि जैसे अंधा बांटे रेवड़ी, अपनों-अपनों को दे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह जनता के साथ अन्याय है।

श्री बत्तीलाल : कोई गुण गाने वाली बात होगी तो गुणगान करूंगा। आलोचना करने वाली बात होगी तो आलोचना करूंगा।

सभापति महोदय, स्वर्गीय ढाबरिया साहब के समय में जनता सरकार ने यह स्वीकार किया था कि नादौती डिस्पेंसरी में डॉक्टर भेज दिया जाएगा, लेकिन वहां आज भी डॉक्टर नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर तहसील हेडक्वार्टर पर डॉक्टर नहीं है। ऐसे पिछड़े हुए कस्बे में, मैं सरकार से मांग करूंगा 50 हजार जनता की तरफ से, नादौती तहसील में एक डिस्पेंसरी जरूर खोलें। मैं इस ओर सरकार का ध्यान दिलाते हुए, अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भारत।

श्री सभापति : माननीय सदस्यों से एक निवेदन करना है। किन्हीं माननीय सदस्य की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोई बात नहीं है, लेकिन सदन की परम्परा के बारे में यह कहना चाहता हूं। इस सदन की परम्परा रही है कि जो भी भाषण माननीय सदस्य देते हैं तो अन्त में कोई भी माननीय सदस्य 'जय हिन्द' या 'जय भारत' नहीं कहते हैं। मैं कोई आपत्ति नहीं करता हूं। सभी माननीय सदस्य अनुभवी हैं। कोई 'जय हिन्द' कहेगा। कोई 'जय भारत' कहेगा। 27 साल से यह डेकोरम रहा है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान परम्परा की ओर आकर्षित कर रहा हूं। संसद में, पार्लियामेन्ट में भी यही है। भाषण के अन्त में इस प्रकार का कोई शब्द नहीं कहा जाता है।

श्री सभापति : श्री बंशीलाल सारस्वत !

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) :

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

सभापति महोदय, इस बारे में तो मुझे शक और सन्देह नहीं है कि जनता पार्टी के जो मंत्रीगण हैं उन्होंने, सत्ता और प्रभुता शासन में जो समझी जाती है, इस बात का परिचय दिया है कि उनके काम करने में सत्ता या प्रभुता की कोई निशानी नहीं है। शासन सत्ता कांटों का ताज, सूली की सेज और न्याय की दुधारी तलवार है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप कटौती प्रस्तावों पर आ जाइये, वरना भूमिका में ही रह जाओगे।

श्री बंशीलाल सारस्वत : इसके बावजूद भी ऐसी चीजें हैं और इस प्रकार के लोगों की.....

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, आसन काफी बोल रहा है।

श्री किशनसिंह भाटी : सभापति महोदय, झुन्झुनूं से आने वाली माननीय सदस्या का यह कह देना कि आसन काफी बोल रहा है, ठीक नहीं है, आसन के प्रति निरादर है।

(व्यवधान)

अभी तो आपकी, न्यायाधीश की पोजीशन है।

श्री सभापति : माननीय सदस्या की भावनाएं सम्मानजनक हैं।

श्री बंशीलाल सारस्वत : जनता यह समझ रही है कि अब भी उनको इस बात का अहसास है कि उनके पास प्रभुता की चूड़ियां हैं तो इनको भी फोड़ देना चाहिए और चूड़ियां फोड़ कर मैदान में आ जाना चाहिए। यह आपसे जनता अपेक्षा करती है। मैं केवल इतना ही कहना उचित समझता हूं कि महादेव को नाग ही शोभा है और जहर पीना उन्हीं के लिए संभव है। जो कुछ वर्षों पहले समझते थे, जो कल तक शासन में थे उन्हें जहर निगलना संभव है। मगर अब सांप और जहर जनता के मन्त्रियों के काम के नहीं हैं। उनके लिए वरदान नहीं, अभिशाप है। इनका परित्याग कर देना चाहिए।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव चिकित्सा के सम्बन्ध में है। शहरों में जो प्रणाली है और केन्द्रीय चिकित्सा के जो केन्द्र हैं उस बारे में बहुत से आदर्श हॉस्पिटल्स और चिकित्सालय बनाये हैं लेकिन इस समय लगेगा। कम से कम दो तीन साल की अवधि निर्धारित होनी चाहिए। अस्पतालों के विकेन्द्रीकरण और ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। शहरी अस्पतालों की शोभा और सजावट में ही ज्यादा समय न लगाया जाय और गांवों की ओर और विशेषतया उन व्यक्तियों और समाज की ओर ध्यान दिया जाय जो आशा लगाये बैठे हैं उनकी ओर भी ध्यान दें, उनके लिए भी प्रयास किया जाय। इस ओर जो असन्तुलन को मिटाने की कोशिश की है वह तो सराहनीय है। सभापति महोदय मेरे क्षेत्र में जहां एक भी अस्पताल नहीं था, डिस्पेन्सरी नहीं थी, नागौर के अन्दर ही जो हॉस्पिटल है वहां पर तीस-चालीस और पचास मील से लोगों को आना पड़ता है। वहां पर आज आशा बंधी है वो तीन डिस्पेन्सिरियां खोली गई हैं। इसी तरह से हर क्षेत्र में भी पंचायत समिति स्तर पर दो

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

डिस्पेन्सरियां खोलने का निर्णय लिया गया है।

## सदन की कार्यवाही

### विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की बैठक का समय आज की विचाराधीन मांगें पारित होने तक बढाया जाय।

श्री दुलाराम : माननीय सभापति महोदय, मुख्य सचेतकजी ने कल भी समय बढाया था इसी तरह और जब कुछ सदस्य रह गये बोलने से तो आसन की तरफ से मुनादी कर दी गई थी।

श्री नवनीत पालीवाल: सबको बुलवाया था।

श्री दुलाराम : एक मिनट सुन लीजिये। आप निश्चिन्त रहें। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि ...

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमूं) : सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति: माननीय दुलारामजी, रामेश्वरजी का व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया बिराजिये।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : सभापति महोदय, निवेदन यह है कि माननीय सदस्य इधर से बोलना चाहें या उधर से, जो भी निवेदन किया जाय, आसन को किया जाना चाहिये। चाहे इधर के सदस्य हों या उधर के, व्यक्तिगत बात करने से सदन की गरिमा नहीं बढ़ती है।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं।

प्रश्न यह है कि सदन का समय विचाराधीन मांगे पारित होने तक बढ़ाया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांगें पारित होने तक बढ़ाया गया।

### मांग संख्या 26 व 2 पर विचार

श्री बंशीलाल सारस्वत : मैं यह निवेदन कर रहा था, ग्रामों की ओर जो प्रयास किया गया है उस प्रयास को बढाया जाना चाहिए। दो अस्पताल का जो प्रावधान रखा है यदि सीमित साधनों के होते हुए आप और बढ़ा सकें तो अति उत्तम होगा। मगर इनके साथ ही गांवों में जो चिकित्सक जाते हैं और अन्य जो स्टाफ जाता है उनको इस सेवा में दीक्षित करने की जरूरत है। वहां पर कम अनुभव रखने वाले डाक्टर और विशेषतया जो कुछ कम जानकार होते हैं जो दक्ष नहीं होते, उनको भेज दिया जाता है। कई जगहों पर तो जूनियर स्पेशलिस्ट की जगह ही अनेक वर्ष से खाली है। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार से शहरों सिटी अलाउन्स दिया जाता है, उसी तरह से जो गांवों में जाते हैं उनको ग्राम अलाउन्स दिया जाना चाहिए ताकि वे लोग गांवों में जाने के लिए आकर्षित हों। अच्छे डॉक्टरों को वहां पर भेजा जाना चाहिए। नागौर का मैं निवेदन करूं कि तीन-तीन साल से चार जूनियर स्पेशलिस्ट की जगह खाली पड़ी है। जो जिला हैडक्वाटर हैं वहां पर कोई स्त्री विशेषज्ञ नहीं है। मुझे अभी मालूम हुआ है कि एक डॉक्टर को

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

लगाया गया है मगर उसने भी कहा है कि मेरे पति का ट्रान्सफर नहीं किया तो मैं नहीं जाऊंगी । इसलिए जो आदेश दिये जायें उनकी पालना भी होनी चाहिए । इस तरह का एटमोसफियर क्रियेट किया जाय ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा गांवों की ओर और जिला मुख्यालयों की ओर आकर्षित हों ।

दूसरा निवेदन मैं यह कर रहा था कि हम विधान सभा के सदस्यों के लिए मेडिकल एड फ्री है, मिनिस्टरों के लिए फ्री है, अधिकारियों के लिये और कर्मचारियों के लिए फ्री है । मगर गरीब आदमी जो गांव से आता है, जो सामान्य जन है, नागरिक है उसके लिये क्यों नहीं है ? यह तो सभी को अवेलेबल होनी चाहिए कल्याणकारी राज्य में ज्यादा से ज्यादा पैसा इस बारे में खर्च किया जाना चाहिए । जो भी बीमार हों, उनको दवा मिलनी चाहिए, उनका इलाज होना चाहिए। यह आपकी पद्धति गलत है। जो भी व्यक्ति राजकीय अस्पताल में जावे जहां भी हो वहां पर उसको फ्री मेडिकल एड मिलनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह सुविधा मिल सके । मैं यह भी निवेदन कर रहा था कि यह जो चिकित्सा की शिक्षा है इसमें आमूलचूल परिवर्तन किया जाना चाहिये और उसका और आयुर्वेद दोनों का समन्वय होना चाहिए ताकि उस पद्धति से लोग परिचित हो सकें। उसमें एक विषय यह भी होना चाहिए । अभी जो...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

शिक्षा पद्धति है उसमें एक विषय आयुर्वेद का भी रखा जाना चाहिए ताकि लोगों को इसका ज्ञान हो सके और वे उससे लाभ उठा सकें ।

तीसरा मैं निवेदन कर रहा था कि जो चिकित्सालय क्रमोन्नत किये गए हैं वहां माकूल रूप से आर्थिक सहायता नहीं मिली है और जो केन्द्रों पर अस्पताल है वहां पर्याप्त मात्रा में सरकार की तरफ से सहायता मिल जाती है । उसके लिए जन सहयोग भी प्राप्त हो सकता है, लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं लेकिन साथ-साथ अंशदान सरकार की तरफ से पर्याप्त मात्रा में और आवश्यकतानुसार सभी अस्पतालों को दिया जाना चाहिए । जैसे नागौर में 150 बैड्स रेज किए गए हैं हम ढाई लाख रुपए देने को तैयार हैं । दूसरे भी आ सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से स्वीकृति नहीं मिली । 1971 से 1974 तक बराबर स्वीकृत रकम पड़ी रही उसका उपयोग नहीं हो सका । रेफरल अस्पताल जो भी हो, उसको योजनाबद्ध तरीके से आर्थिक अंशदान देना चाहिए ।

श्री सभापति : माननीय श्री निर्मल कुमार ।

श्री निर्मल कुमार (झालरापाटन) : सभापतिजी, हमारे देश में और राजस्थान में मंत्री परिषद् का जिस प्रकार निर्माण किया जाता है, मैं समझता हूं, यह प्रथा गलत है । सारे विधायक मिलकर मुख्य मंत्री का चुनाव कर सकते हैं तो क्या वे विधायक अन्य मंत्रियों का चुनाव करने में असक्षम हो जाते हैं ? तो वर्तमान प्रथा को समाप्त किया जाये, संविधान में परिवर्तन हो सकता है । एक तरफ हम सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं, जनता द्वारा विधायक को वापस बुलाने के अधिकार की बात करते हैं, तो जो मंत्री अयोग्य हों, विधायक उसको वापस बुला सकें, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए । जब मंत्री परिषद का

(श्री निर्मल कुमार)

निर्माण हो जाए, विधायक जनता की समस्याओं को लेकर मंत्री के पास जावे, आवेदन करें तो मंत्री परिषद को चाहिए कि वह समस्याओं के समाधान में सहायक बने। कम से कम जवाब देना मंत्रियों की जिम्मेवारी होनी चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रत्येक मंत्री को एक वर्ष में हर जिला केंद्र पर जाकर समस्याओं की प्रत्यक्ष रूप में जानकारी लेनी चाहिए और उनका किस प्रकार से समाधान हो, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए।

दूसरी बात, मंत्री परिषद का स्थानान्तरण का काम समाप्त होना चाहिए। हर जिले में इस प्रकार की कमेटी का निर्माण किया जाए जो जिले में स्थानान्तरण होते हैं, विधायक व जिला अधिकारी मिलकर तय करें, ताकि कर्मचारी व अधिकारी मंत्रियों के पीछे चक्कर नहीं काटें। पिछले मंत्रिमंडल में और आज के मंत्रिमंडल की तुलना किए बिना मैं नहीं रह सकता। जो पिछले मंत्री थे उनका दर्शन भी दुर्लभ होता था, लेकिन आज दावे के साथ कहा जा सकता है कि जनता का प्रत्येक आदमी मंत्री से मिल सकता है। इसके लिए मैं मंत्री परिषद् को बधाई देना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : लेकिन काम नहीं होता है।

श्री निर्मल कुमार : स्वास्थ्य व चिकित्सा के संबंध में भी मेरे कटौती प्रस्ताव हैं। स्वास्थ्य व चिकित्सा की नीति पर हमें पुर्नविचार करना आवश्यक है। आज दवाइयों का जो निर्माण होता है, विदेशी कम्पनियां करोड़ों रुपये कमाकर विदेशों में ले जाती हैं लेकिन जो मंत्रीगण राज्य और केंद्र मे बैठे हैं कुछ नहीं कर सकते। क्या ऐसा कानून में परिवर्तन नहीं हो सकता कि विदेशी लोग इस देश में दवाइयों का निर्माण नहीं करें और यदि करें तो बिना लाभ-हानि के आम जनता को सुलभ कराये। हमारे मंत्री हिम्मत दिखाये और प्रधान मंत्री से कहें कि दवाइयों का दाम बिना लाभ-हानि के तय करें और सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने की कोशिश करें। इस समय दस पैसे की दवाई पांच रुपए मे बिकती है, इसमें सुधार लाना होगा, नहीं तो जनता के साथ जो वायदा किया है उस पर जनता कम भरोसा करेगी।

मैं झालावाड़ जिले की बात कहता हूं। वहां अस्पताल बहुत कम हैं। झालावाड़ जिले का अस्पताल शायद 150 शैय्याओं वाला है और वहां 100 शैय्याएं आ सकती हैं। वहां पर कुछ बजट दिया जाए क्योंकि जिला केंद्र है। झालावाड़ में ही नहीं प्रत्येक जिला केंद्र पर व्यवस्था हो, हर प्रकार के साधन सुलभ हों। ऐसा न हो कि सारी सुविधायें जयपुर में हो और बाकी जिला केंद्र वंचित रहें। मैं झालरापाटन से आया हूं। वहां 15 शैय्याओं का अस्पताल है, लेकिन हमेशा 40-50 मरीज रहते हैं। मैंनें अपनें प्रयास से 40 हजार रुपए के दो भवन निर्माण कराए हैं। वहां पर आप 15 बेड्स एक्स्ट्रा देनें की व्यवस्था करें ताकी लोगों को अधिक से अधिक सुविधा दी जा सके।

आयुर्वेद के मामले में मुझे निवेदन करना है कि इस विभाग के निदेशक का पद 9 महीने से खाली पड़ा हुआ है और एक वैद्य प्रमोशन लेकर बैठा हुआ है। भारी घोटाले हो रहे है खरीद में। तिल्ली का तेल 16.65) में खरीदा है, जबकि यह तेल 10 रुपए प्रति किलो से ज्यादा कभी नहीं बिकता। दूसरा कपूर 96) रु० प्रति किलो

(श्री निर्मल कुमार)
में खरीदा है, जबकि दूसरा टेन्डर 50)रु० प्रति किलो का था। उसको निरस्त किया पैसा खाकर 96)रु. प्रति किलो के हिसाब से खरीदा है जबकि सीधा-सीधा कपूर मंगाते तो कंपनी से 35) रु० प्रति किलो में ले सकते थे। इस प्रकार आयर्वेद विभाग में करोड़ों रुपये के घोटाले हुए हैं। जयपुर के व्यापारियों से मिलकर ये घोटाले किए जा रहे हैं। इसके लिए कमेटी बिठाई जाए विधायकों की, हमारे सदन में डॉक्टर व वैद्य हैं जो देखें कि कौनसी दवाइयां असली हैं। कौनसी नकली हैं, इसकी जांच करवाइए, नहीं तो दवाइयों के नाम पर हल्की चीज लेने से जनता के स्वास्थ्य के साथ अन्याय होगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इस कमेटी का एलान तो अभी कर दीजिए।

श्री निर्मल कुमार : जिन डॉक्टरों को हम अयोग्य कर देते उनका रड क्रास पर कब्जा जमा हुआ है। मनमानें ढंग से जिसको चाहें रख देते हैं। आज तक मनमाने ढंग से 21 डॉक्टर और कर्मचारी तंग आकर इस्तीफा दे चुके हैं और मैनेंजमेंट अपनें चहेतों को भर्ती कर रहा है, इस प्रकार का नाटक चल रहा है।

श्री सभापति : श्री अयूब खां !

श्री अयूब खां : सभापति महोदय, आजकल हमारे यहां राजस्थान में जो चिकित्सा की प्रणाली है वह काफी हद तक दोषपूर्ण है। अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलतीं और होती भी हैं तो चंद आदमियों को दी जाती है, बड़े आदमियों को दी जाती हैं और उन व्यक्तियों को दी जाती है जिनके पास पैसा होता है। और जिनके पास पैसा नहीं होता है उनको दवाइयां नहीं दी जाती हैं। यह कह दिया जाता है कि अस्पताल में दवाइयां ही नहीं हैं। इसलिये, सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन है कि गांवों के अस्पतालों में अधिक से अधिक दवाइयां उपलब्ध करायी जाएं।

श्री श्योपतसिंह मकासर सभापति महोदय, निर्मल कुमारजी ने जो बातें सदन में कहीं हैं उनके लिये मन्त्री महोदय उनको धमका रहे हैं।

श्री सभापति: ऑर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य श्री अयूब खां अपना भाषण जारी रखे।

श्री अयूब खां : तो, सभापति महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध है कि गरीबों को दवाई मुफ्त दी जाय। सभापति महोदय, आज लोग शहरों में रहते हैं उन्हें तो चिकित्सा की सुविधायें उपलब्ध होती हैं लेकिन जो लोग गांवों में रहते हैं उन्हें यह सुविधायें शहरों में रहने वालों की अपेक्षा कम उपलब्ध होती हैं। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि शहरी क्षेत्रों में कई सरकारी अधिकारी और कर्मचारी दवाइयों के फर्जी बिल उठाते हैं। इसके विपरीत गांवों में स्थिति ऐसी है कि बेचारे गांवों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को अस्पताल में दवाइयां नहीं मिलने से बहुत दिक्कत होती है। मेरा, सभापति महोदय, राज्य सरकार से आपके माध्यम से यह अनुरोध है, चिकित्सा व्यय के लिये राज्य सरकार को चाहिये कि उनकी तनख्वाहों के आधार पर फिक्स भत्ता कर दिया जाय ताकि इसमें गड़बड़ियां कम हों।

(श्री अयूब खां)

दूसरी बात जो मैं, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है कि आपने आज गांवों में अस्पताल खोलने की घोषणायें तो कर दी हैं लेकिन वहां पर न तो पूरी दवाइयां हैं न हीं वहां पर अभी तक पूरा स्टाफ है इस लिये उसकी व्यवस्था की जाय। इसके साथ-साथ गांवों में आपने अस्पताल खोल दिये हैं लेकिन लोग वहां जाते नहीं हैं या दवाइयां प्राप्त नहीं होती हैं। मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि आपको मोबाइल अस्पताल को व्यवस्था करनी चाहिये। ताकि उनसे गांवों की जनता के लिये दवाइयों की पूर्ण व्यवस्था होती रहें और दवाइयों की सुविधा गांवों की जनता को भी मिले।

बस मुझे इतना ही निवेदन करना है। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री जगदीश सिंह

(अनुपस्थित)

श्री गोपालसिंह !

श्री गोपालसिंह (खण्डेला): सभापति महोदय, हमारे देश के आजाद होने के बाद हमारे यहां पर उत्तरदायी सरकार बनने के बाद चिकित्सा के क्षेत्र में हमने काफी प्रगति की है निश्चित रूप से चिकित्सा क्षेत्र में परिवर्तन की ओर हम चले हैं उसके बाद हम दिनोदन चिकित्सा के क्षेत्र में खर्च भी अधिक से अधिक करते जा रहे हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय.....

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, नहीं। सभापति बैठे हैं।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : सभापति महोदय, हमारे प्रान्त की आबादी को देखते हुए हमारे गांवों की आबादी को देखते हुए अभी निश्चित रूप से हम उतने साधन नहीं जुटा पाये जितने कि हम साधन गांवों की जनता के लिये जुटाने चाहिये। इसलिये, सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध है कि चिकित्सा के क्षेत्र का जो खर्चा है वह आप कृपा करके ग्रामोन्मुख करें तो अधिक अच्छा होगा। यह अत्यन्त आवश्यक भी है। आज शहरों में ज्यादा चिकित्सा फैसिलिटीज हैं उसका मैं विरोध नहीं करता लेकिन जहां पर बिलकुल दवाइयों की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं वहां दवाइयां उपलब्ध कराने की आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। आज गांव के गरीब लोगों के लिये, गरीब काश्तकारों के लिये हम पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का हमारा जिम्मा है। आज हालत यह है कि किसी गांव के अस्पताल की हालत ऐसी है जैसे कि कोई छोटा सा दीपक जल रहा है और एक शहर का अस्पताल ऐसे दिखाई देगा जैसे कि कोई एक हजार वोल्ट का लेम्प जल रहा हो। मैं शहर के इस तरह के जो बड़े अस्पताल हैं उनका विरोध नहीं करता। लेकिन आखिर जिन लोगों को सुविधा देने का आपने जिम्मा लिया है उनको आप कब तक सुविधायें नहीं देंगे? इसके लिये मेरा राज्य सरकार से आपके माध्यम से सभापति महोदय, यह अनुरोध है कि आप अपने नजरिये को बदले और जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा चिकित्सा सुविधायें गांवों में पहुंचावे ताकि गांवों की जनता को राहत मिले। यह नजरिया आपको बदलना अत्यन्त आवश्यक है। आपको अपने नजरिये में परिवर्तन करना ही होगा। सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हर जिले के अस्पताल में सभी

(श्री गोपालसिंह )

तरह की सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिये ताकि लोगों को शहरों में नहीं आना पड़े, उनको जिला हैडक्वार्टर के अस्पताल में ही सभी तरह की चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हो जावें। वह बात दूसरी है जहां कोई स्पेशल रोग हो उसके लिये अगर कोई जोधपुर, जयपुर, उदयपुर अस्पतालों में जावे तो कोई हमारा विरोध भी नहीं है। अगर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट जयपुर में ही होता हो तो हमें एतराज नहीं हैं। लेकिन गांवों के अरजन्ट केसेज को मीट आउट करने के लिये कम से कम जिला अस्पताल ऐसे सक्षम तो जरूर होने चाहिये कि गांव के लोगों को जयपुर की तरफ नहीं आना पड़े। आप ऐसा करेंगे तभी हम आगे बढ़ पायेंगे।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, वह है गांवों में मैटरनिटी सुविधाओं के बारे में। यह बात सही है कि राज्य सरकार ने कई जगह रोड साइड पर मैटरनिटी होम्स भी कायम किये हैं लेकिन हमारे प्रान्त में उनकी संख्या नगण्य है। आज हमारे गांवों की अधिकांश जनता को मैटरनिटी की सुविधा नहीं मिलती है। हमारे गांव के गरीब लोग गांव का पिछड़ा वर्ग और गांव के किसान लोगों की औरतों को पूरी मैटरनिटी फैसिलीटिज नहीं मिलने के कारण मौते बहुत होती है। गांवों में कोई दवाइयों की फैसिलिटीज नहीं होने से, कोई दूसरी व्यवस्था नहीं होने से बहुत-सी मौतें होती हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी राज्य सरकार को इस ओर विशेषतौर से ध्यान देने की जरूरत है ताकि अधिक से अधिक औरतों को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाया जा सके।

वैसे तो माननीय सदस्यों ने यहां पर बहुत कुछ कह दिया है, दवाइयों के बारे में और अस्पताल खोलने के बारे में। सभापति महोदय, आज गांवों में हालत यह है कि जितने भी गांवों के अस्पताल हैं उनमें दवाइयां उपलब्ध नहीं होती है। लोग डॉक्टर के पास जाते और मन में समझते हैं कि हम दवाइयां बाजार से खरीदनी है। वह तो एक तरह से अस्पताल ऐसे हैं जो कि प्रेस्क्रिप्शन सेन्टर की तरह हैं। जहां मरीज जाते हैं और प्रेस्क्रिप्शन लिखा कर आते हैं। दवाइयां तो वहां पर उपलब्ध नहीं होती हैं। लोगों का मानस ऐसा बन गया है कि दवा तो मिलेगी नहीं। लोगों को दवा बाजार से खरीदनी पड़ती है। अब बेचारे पहले ही गरीब हैं दवा कहां से लावें। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, छोटे-छोटे इन्जेक्शन्स, छोटी-छोटी दवा बाजार से खरीद कर लानी पड़ती है। तो मेरा निवेदन है, राज्य सरकार से मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि आखिर वह दवाइयां जो राज्य सरकार खरीदती है वह कहां चली जाती हैं? इसकी जांच करने की आवश्यकता है। आपको इसको चैक करना चाहिये। आखिर दवाइयां कहां गयी? कहीं बाजार में तो नहीं बिक गयीं? मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अस्पतालों की दवाइयां बाजार में बिकती हैं। राज्य सरकार जिन लोगों के लिये दवाइयां करोड़ों रुपये की खरीदती हैं उन लोगों को अस्पतालों में दवा तो मिलती नहीं है बल्कि उनको तो प्रेस्क्रिप्शन मिलता है। मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से, सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस पर कन्ट्रोल रखें और देखें कि आया सही व्यवस्था, सही उपयोग राजकीय दवाइयों का हो रहा है या नहीं। आज आप बजट रखते हैं पर वह बजट उन गरीब लोगों के, जो गांव में रहते है जो पिछड़े

(श्री गोपालसिंह)
हैं, जो किसान हैं, काम में नहीं आता है। दवाइयां बाजार में बिकती हैं और उन गरीब लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है।

इसके साथ-साथ मैं एक बात और सभापति महोदय निवेदन करना चाहूंगा वह है पागल कुत्ते के काटने के बारे में। गांवों में इसके इलाज के लिये कोई व्यवस्था नहीं। गांव के गरीब लोगों को पागल कुत्ते के काटने के बाद शहरों में जयपुर में आना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि उसके लिये ज्यादा कोई खर्च नहीं होता है, बहुत खर्चीली योजना नहीं है, कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिल सकती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अस्पतालों में सिर्फ दवाइयां रेफ्रीजेटर्स में ही रखनी हैं। कुछ इन्जेक्शन उसमें रखने पड़ते हैं। सरकार चाहे तो यह व्यवस्था जिला हैडक्वार्टर्स पर कर सकती है। अगर आप यह व्यवस्था कर देते हैं तो गांवों में एक क्रान्ति आ जायेगी। इससे बहुत से लोगों को आप मरने से बचा सकते हैं। बस इतनी ही बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री हरिसिंह (फुलेरा)!

(अनुपस्थित)

श्री श्योपतसिंह मकासर !

(अनुपस्थित)

श्री बालकृष्ण थानवी !

श्री बालकृष्ण थानवी (फलोदी) : माननीय सभापतिजी, मैं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के बारे में कुछ अर्ज करूंगा। कांग्रेसी राज में भ्रष्टाचार ने शिष्टाचार का रूप ले लिया था। अतः उसकी वजह से आज की तारीख में भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। आज कोई भी गरीब अस्पताल में पहुंचता है तो उससे कुछ न कुछ लेने की कोशिश नर्स से लेकर कम्पाउन्डर्स व डॉक्टर्स तक करते हैं। चाहे किसी व्यक्ति को किसी चीज के लिये सर्टिफिकेट लेने का प्रश्न हो, चाहे अन्य प्रकार का डाक्टर से कोई काम हो तो उससे कुछ न कुछ लिया ही जायेगा तब ही जाकर उसको सर्टिफिकेट दिया जायगा वरना नहीं। इसलिये इस शिष्टाचार को, जो कि भ्रष्टाचार ही है, रोकथाम होनी चाहिये। यह केवल चिकित्सा विभाग में ही हो ऐसी बात नहीं है। यह तो सारे ही विभागों में व्याप्त है। चूंकि आज स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग से संबंध है इसलिये इस विषय में ही मैं कुछ कहना चाहूंगा।

आज हम देखते हैं कि गरीबों के पास सही माने में दवाई पहुंचाने का प्रयत्न नहीं होता है और न ही दवा खरीदने की शक्ति स्वयं गरीब में हो है। इसलिये अस्पतालों में, खासकर तहसील क्षेत्र के जो अस्पताल हैं, उनमें गरीबों को निःशुल्क देने के लिए कई दवाई, इंजेक्शन आदि रखे जाने चाहिये जिससे आज जो बाजार से खरीद लाने की बात कही जाती है उससे वे बच जायें। बाजार से खरीदने के लिये मरीजों को डॉक्टर जो चिट दिया करते हैं उसमें भी डॉक्टरों की दवाफरोशों से मिलीभगत होती है। जिस डॉक्टर के दवाफरोश से आपसी संबंध होते हैं उन्हीं के यहां बिकने वाली उन दवाओं को वे लिखते हैं ताकि व्यापारी को जो कुछ मुनाफा मिलता है उसमें से कुछ हिस्सा डॉक्टर को भी मिल

(145)



(श्री बालकृष्ण थानवी)

जाता है। इस तरह की जो स्थिति है उसकी रोकथाम की व्यवस्था होनी चाहिये।

प्रसूति के संबंध में भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, कारण कि इस बारे में गंभीर शिकायतें आती रहती हैं। ग्रामीण दाइयों में प्रशिक्षण की तो कमी है ही और इसके साथ-साथ तालीम का अभाव होने से उनके सामने बहुत ही दिक्कतें आती हैं। इसलिये हर तहसील हैडक्वार्टर पर एक लेडी डॉक्टर को जो कि जच्चा के बारे में पूर्ण जानकारी हो उपलब्ध कराना चाहिये जिससे प्रसूति के अवसर पर जच्चा के मरने की स्थिति पैदा न हो और कठिनाई न हो जच्चा को चिकित्सा लेने में। प्रसूति के समय कभी-कभी विषाक्त स्थिति पैदा हो जाती है जिसके कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती है और बच्चे की मां भी चली जाती है। इसलिये ऐसी स्थिति न बने और किसी भी जच्चा को यह दिन न देखना पड़े इसके लिये हर अस्पताल में जच्चा की अनुभवी एक लेडी डॉक्टर का होना भी बहुत ही आवश्यक है। आज हम किसी भी गांव में चले जायं तो प्रसूति के समय जच्चा के मरने की बातें बहुत सुनने में आती हैं। ये इसलिये हैं कि वहां पर लेडी डॉक्टर नहीं होती हैं। इसलिये मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी का इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा कि जहां-जहां लेडी डॉक्टर न हों वहां-वहां पर आप लेडी डाक्टर तत्काल भेजने की व्यवस्था करें।

सरकार ने 11 साल पहले सन् 1967 में स्वास्थ्य विभाग के ग्रामीण अंचलों में कार्यरत खण्ड शिक्षा प्रसारक (परिवार कल्याण) कर्मचारियों के वेतन स्केल को बढ़ाने की बात कही थी। उस फैसले के मुताबिक दिनांक 13-3-67 से परिवर्तित वेतन शृंखला 90-225 के मुकाबले 130-320 की क्रियेट की गई। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि 11 साल के बाद भी उनको इसका लाभ नहीं मिला है। परिवार नियोजन विभाग में जो नयी भर्ती की गयी वे उपरोक्त कर्मचारियों की तरह प्रशिक्षित भी नहीं हैं। फिर भी उन्हें प्रशिक्षित कर्मचारियों से अधिक वेतन शृंखला का लाभ प्राप्त है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि जिन कर्मचारियों के साथ में अन्याय हुआ है उनके साथ न्याय किया जाय।

मैं आपकी मार्फत, सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी को यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां-जहां पर भी डिस्पेन्सरीज नहीं है वहां-वहां आप डिस्पेन्सरीज खोले और यदि डिस्पेन्सरीज खोलना संभव नहीं है तो आप प्राइमरी हैल्थ सेन्टर ही खोलने की व्यवस्था कीजिये। और जहां आयुर्वेद औषधालय खोलना संभव हो सके तो वहां वे जरूर खोलिये। हमारे फलोदी क्षेत्र में बहुत लम्बी-लम्बी दूरी पर अस्पताल हैं। जहां जाने में ग्रामीणों का बहुत खर्चा होता है और यातायात की कमी के कारण वे समय पर वहां पहुंच भी नहीं पाते हैं और इस तरह मरीज दम तोड़ देता है। इसलिये अस्पताल के साथ-साथ आप महरबानी करके दवाई की भी व्यवस्था कराने की कृपा करें। यह निःशुल्क व्यवस्था होनी बहुत जरूरी है और गरीबों के हित यह में आवश्यक है।

मैं फलोदी के नमक क्षेत्र की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वहां पर करीब दस हजार मजदूर हैं। दस हजार मजदूरों के होते हुए भी वहां पर अस्पताल की कोई व्यवस्था नहीं है। डिस्पेन्सरी तो क्या वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी नहीं है। इसलिये वहां डिस्पेन्सरी नहीं तो कम से कम प्राइमरी हैल्थ सेन्टर अवश्य हों, यह

(श्री बालकृष्ण थानवी)
मेरी आपसे प्रार्थना है।

मैं मंत्री परिषद् के गठन के संबंध में भी दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। आज हम देखते हैं कि मंत्री परिषद अभी तक पूर्ण नहीं है। माननीय मुख्य मंत्रीजी की यह हिम्मत होनी चाहिये थी कि मंत्रिमंडल के आकार को वे प्रारम्भ में ही पूरा कर देते लेकिन दो किस्तों में भी इसको पूरा नहीं कर पाये। अभी तक तीसरी किस्त लटकी हुई पड़ी है। आप जिस किसी को भी लेना चाहें लेकर इसको पूरा कर दें। हां, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो क्षेत्र उपेक्षित हैं, खास कर मरुक्षेत्र यदि मंत्रिपरिषद् में उसका प्रतिनिधित्व होगा, जो कि अब तक नहीं के बराबर है तो इस क्षेत्र के साथ न्याय हो सकेगा ऐसी मेरी मान्यता है। मेरा यह भी स्पष्ट मानना है कि जब तक मंत्रिमंडल में अपूर्णता रहेगी तब तक उस अनुपात से जन कार्य भी अपूर्ण रहेगा। अतः मुख्य मंत्रीजी को अब इसमें बिल्कुल ही विलम्ब नहीं करना चाहिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : तीसरी किस्त में कहां से किन-किन को ले रहे हैं यह भी पूछ लें।

श्री बालकृष्ण थानवी : मंत्रिमण्डल के ऊपर जो खर्चा हो रहा है उसमें भी कमी होना बहुत आवश्यक है। यह उचित नहीं मालूम होता कि मंत्रिपरिषद् का खर्चा बढ़ता जाय और बातें सर्वोदय और ग्रामोदय की की जायं। इसलिये तत्संबंधी हर प्रकार से खर्चे में कमी की आवश्यकता है। अतः इसके खर्चे में कटौती की जानी चाहिये। यह कटौती सर्वोदय एवं अन्त्योदय के आदर्श के अनुरूप होगी उसके विरुद्ध नहीं होगी। इसलिये मेरा सुझाव है कि यदि मौजूदा खर्चे में 50 प्रतिशत की कमी कर दी जाय तो वह निःसन्देह सर्वोदय और ग्रामोदय के अनुरूप होगी तथा उसका स्वरूप भी निखरेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि सरकारी कार्य में कोई शिथिलता आने दी जाय।

इसके साथ-साथ, सभापति महोदय, मैं एक बात विशेष तौर से कहना चाहूंगा और वह यह कि मंत्रियों के नीचे जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ इस सदन में बराबर आरोप सुनाई देते हैं। जिन माननीय सदस्यों ने यहां सदन में आरोप लगाये हैं, अधिकारियों के संबंध में, मंत्रियों को उस ओर ध्यान देना चाहिये। मंत्रियों को जो आदेश देने हों वे सोच समझ कर दें पर यदि बाद में उन आदेशों की क्रियान्विति नहीं होती है तो फिर उनको अर्थात् मंत्रियों को उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करनी चाहिये फिर वे चाहे कोई आई.ए.एस. ऑफिसर ही क्यों न हों। जब अनुशासनहीनता के नाम पर छोटे-छोटे कर्मचारियों व चपरासियों को सस्पेण्ड किया जाता है तो फिर उच्च अधिकारियों को सस्पेण्ड करने में कोताही क्यों की जाती है? यह सही है कि जिन्हें भी सस्पेण्ड किया जाय उनकी पूरी जांच भी की जानी चाहिये ताकि महीनों और वर्षों तक केसेज न पड़े रहें और किसी के साथ ख्वाहमख्वाह का अन्याय भी न हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट में ही समाप्त करूंगा।

आज हम देखते हैं कि हर एक विभाग में अटके हुए मामले पड़े रहते हैं। कोई भी विभाग आज ऐसा नहीं है कि वहां पर पुराने अटके हुए मामले न पड़े हों। इसलिये उन सारे मामलों का पूरा चार्ट बनाया जाय और

(श्री बालकृष्ण थानवी)

उनके डिस्पोजल की पूरी व्यवस्था की जाय। साथ ही हर तीसरे महीने में उनका लेखा-जोखा लिया जाय और शेष रहे ऐसे सारे मामलों को जल्दी से जल्दी निपटा दिया जाय। मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकार इस ओर अवश्य ही ध्यान देगी।

चूंकि नये जिलों के निर्माण बाबत भी यहां दलीलें दी गई है और यह बताया गया है कि नये जिलों के निर्माण को महत्व दिया जाय। नये जिलों के निर्माण की आज यहां काफी लोगों ने मांग की है अतः मैं भी यहां यह कहना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि नये जिलों के निर्माण के समय फलौदी को भी जिले का दर्जा दिया जायगा। प्रदेश में अभी जिस तरीके से प्रशासनिक काम चल रहा है वह काफी बिगड़ा हुआ है। कारण कि हर विभाग में ढेर सारा काम बाकी पड़ा है। अतः इस सारे कार्य को भी भू-राजस्व अभियान की तरह अभियान चला कर तत्काल पूरा किया जाय, यही मेरा निवेदन है। आशा है राज्य सरकार मेरे इस सुझाव पर गंभीरता-पूर्वक विचार करके उसको अमली जामा पहिनायेगी ताकि सरकारी दफ्तरों में कांग्रेसी शासन के समय का जमा सारा कूड़ा करकट एकबारगी में ही साफ हो जाय और फिर नई रोशनी में नये काम को अन्जाम दे सकें।

श्री सभापति : श्री बालचन्द आर्य !

(अनुपस्थित)

श्री कौशलकिशोर जैन !

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय,

'खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है,

संभलकर पैर रखने पर भी कमर बल खा ही जाती है।'

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर। इस सदन में शेरो-शायरी किसी कन्टेक्स्ट में ही कही जा सकती है और बिना कन्टेक्स्ट के बातें करना इस सदन की गरिमा को भंग करना है। मैं चाहूंगा कि यह वर्ड्स आज की कार्यवाही से निकाले जायें। जनता ने हमें यहां पर अपनी जन समस्याओं के लिए भेजा है......

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा : यह शेरो-शायरी आपके लिए नहीं कही गयी है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : सभापति महोदय, इस सदन की गरिमा है, प्रतिष्ठा है। यहां ऐसी बातों का उपयोग करना निश्चित रूप से गरिमा को भंग करना है। और इस पर रोक नहीं लगाई गई तो इसकी कोई सीमा नहीं होगी। यह सदन अखाड़ा बन जायेगा।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं। शेरो-शायरी सदन में वर्जित है और नियमों के अनुकूल नहीं है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : इसको कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री मदनसिंह दांता : यह माननीय सदस्य हमेशा खड़े होते हैं और शेर कहते हैं। मैं समझता हूं इन्होंने इस कन्टेक्स्ट में यह बात कही है कि नजाकत के माफिक उनको बंगले मिले, गाड़ियां मिलीं ......

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : सभापति

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

महोदय, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इन शब्दों को कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं, मैंने कह दिया कि सदन में शेरो-शायरी वर्जित है।

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने आपत्ति की, लेकिन जिस कन्टेक्स्ट में मैंने यह शब्द कहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि छः महीने पहले जनता मंत्रिमण्डल बना। यह तो मैं नहीं कहना चाहता कि मंत्रिमण्डल ने जनता की आशाओं को पूरा नहीं किया किन्तु यह जरूर निवेदन करना चाहूंगा और इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा जनता मन्त्रिमण्डल को कि इन्होंने अपने द्वार जन-साधारण के लिए खोल दिये। जनसाधारण उनको मिल सकते हैं। यह बात सत्य है कि कुछ उत्तरदायित्व उनके ऊपर आये, कुछ जिम्मेदारियां उनके ऊपर आई हैं और यह जिम्मेदारी उनके अन्दर नज़ाकत लाई है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली साल 27 लाख 77 हजार रुपये का खर्चा मंत्रिमण्डल पर हुआ था। इस साल 38 लाख 30 हजार का खर्चा होने जा रहा है। 10 लाख का अन्तर है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर एक साल का यह खर्चा है, 17 हजार रुपया मासिक एक मंत्री पर खर्चा होता है....

श्री अब्दुल अजीज : आप मंत्री होते तो क्या होता ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री कौशलकिशोर जैन : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि द्वार सब के लिए खोल दिए अच्छी बात है। आपने सज्जनता की छाप डाली, अच्छी बात है, लेकिन इतने भी सज्जन मत बन जाइये कि नौकरशाही आप पर हावी हो जाये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे एक मंत्रिमण्डल के सदस्य भीलवाड़ा पधारे और वहां के जिलाधीश महोदय उनसे मिलने नहीं आये। उनको फोन कराना पड़ा। उस पर जिलाधीश महोदय मिलने आये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे खुशी होती इस बात की कि दूसरे दिन मैं यह सुनता कि भीलवाड़ा का जिलाधीश बदल दिया गया है। एक आई. ए. एस. ऑफिसर और एक जिले का जिलाधीश यह हिम्मत करे कि जनता पार्टी के मंत्रिमण्डल के एक वरिष्ठ सदस्य और केबिनेट-स्तर के मंत्री को वह मिलने नहीं आये। यह हिम्मत एक जिलाधीश की या सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर की या एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर की या चीफ इन्जीनियर की कैसे होती है? मेरा यह निवेदन है...

श्री राम रघुनाथ : मंत्री लोगों ने कह रखा है कि आप अपना काम कीजिए।

श्री कौशल किशोर जैन :....माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं और एक बात मंत्रिमण्डल के विषय में कहना चाहता हूं कि मंत्री किसी विषय के एक्सपर्ट होने चाहिएं। 8 महीने के अन्दर उन्होंने किसी क्षेत्र के अन्दर विशेषता प्राप्त की और उस डिपार्टमेन्ट को समझा और फिर उनको उस विभाग से बदल दिया गया...

श्री ग्योपतसिंह मकासर : आप किस-के माहिर हैं ?

श्री कौशलकिशोर जैन : मैं मंत्री नहीं हूं। मैं तो केवल सदस्य हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अगर सोचा जाये तो आप किस चीज में माहिर हैं ?

श्री मदनसिंह दांता : डिसिप्लिन में।

श्री कौशलकिशोर जैन : कल के उद्योग मंत्री आज चिकित्सा मंत्री हो गए। उन्होंने उद्योग को समझा था और आज उनका विभाग बदल दिया गया है। कल तक वह अपने प्राइवेट सेक्रेटरी पर आधारित थे, डिपार्टमेन्ट को कुछ समझा, कुछ करने को उद्यत हुए और उनका डिपार्टमेन्ट बदल दिया गया .....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मंत्री महोदय प्राइवेट सेक्रेटरी पर आधारित थे। यह एक ही मंत्री के लिए है या मुख्य मंत्री-जी के लिए है ?

श्री सभापति : यह आप अपने आप समझ लीजिए।

श्री कौशलकिशोर जैन : हमारे चिकित्सा मंत्री सर्वोदयी विचारधारा के हैं, बहुत सज्जन आदमी हैं। वह भीलवाड़ा आये थे। मैंने सुना कि रात्रि में कम्बल ओढ़कर भीलवाड़ा के अस्पताल को देखने गये। यह भीलवाड़ा की जनता का अहोभाग्य था, लेकिन मुझे कहते हुए दुःख है कि शायद एक महीना या दो महीना हो गया भीलवाड़ा की अस्पताल की दुर्दशा दूर नहीं हुई। मैंने पिछली बार सदन में भी कहा था कि प्रातःकाल के समय आप भीलवाड़ा जिले के उस अस्पताल में चले जायें तो कम से कम पचास लोग टट्टी जाते हुए वहां दिखाई देंगे, उस अस्पताल के मैदान के अन्दर। वह अस्पताल है या गन्दगी का साम्राज्य है ? माननीय मंत्री महोदय ने यह देखा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री महोदय ने दुर्दशा देखी। अगर वह दुर्दशा थोड़ी भी दूर हो जाती या कम हो जाती तो अच्छी बात थी। इसलिए चिकित्सा मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि अस्पताल की दुर्दशा की ओर वह ध्यान दें।

एक और शिकायत है। इसी विभाग में एक डॉक्टर का प्रतापगढ़ से भीलवाड़ा ट्रांसफर किया गया। हमने पूछा कि किस बात पर ट्रांसफर किया गया, तो उत्तर मिला कि शिकायतें आई थीं। शिकायत किस की आई थी ? शिकायत आई थी प्रतापगढ़ के डॉक्टर की। उसका ट्रांसफर भीलवाड़ा कर दिया गया और भीलवाड़ा के डॉक्टर का प्रतापगढ़ कर दिया गया। प्रतापगढ़ छोटा-सा स्थान है और भीलवाड़ा एक लाख की नगरी है। शिकायत आई थी प्रतापगढ़ के डॉक्टर की। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस बात की ओर ध्यान दें।

अब मैं थोड़ा आयुर्वेद के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान के अन्दर आयुर्वेद को पिछले तीस साल में वह स्थान नहीं मिला जो कि एलोपैथी को मिला है। क्या कारण है ? क्या आशा मैं करूं ? मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आयुर्वेद में भी वही वेतनमान दिये जायें जो कि एलोपैथी में दिये जाते हैं। गुजरात के अन्दर आयुर्वेद और एलोपैथी के एक ही वेतनमान हैं। मुझे जानकारी है कि आज जूनागढ़ में आयुर्वेद का शोध संस्थान काम कर रहा है और वहां के लोग आयुर्वेद औषधियों का आविष्कार कर और शोध

(श्री कौशलकिशोर जैन)
कर जनता को लाभ पहुंचा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि राजस्थान के अन्दर भी एक आयुर्वेद शोध संस्थान डाला जाये और उनके वेतनमान बराबर किये जायें।

माननीय सभापति महोदय, मैं केवल एक बात और निवेदन करूंगा कि आयुर्वेद कॉलिज के अन्दर 1956 में प्रधान चिकित्सक का ग्रेड 150–300 था, जिला आयुर्वेद अधिकारी का भी 150–300 था और लेक्चरार का भी यही ग्रेड था और रिसर्च असिस्टेन्ट का भी यही ग्रेड था, 1968 के अन्दर। फिर 1-4-73 को प्रधान चिकित्सक 'ए' श्रेणी का ग्रेड 275–680 कर दिया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसी स्तर में अन्य पद जिला आयुर्वेद अधिकारी, लेक्चरार और असिस्टेन्ट डॉइरेक्टर और रिसर्च असिस्टेन्ट के वेतनमान वही रखे गये। इन जिला चिकित्सकों ने क्या बिगाड़ा है ? मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसकी ओर ध्यान दें।

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

केवल एक बात और कह कर मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। भीलवाड़ा अस्पताल के अन्दर 2 ई. सी. जी. की मशीनें हैं और दोनों ही दो साल से बेकार पड़ी हैं। काम नहीं करतीं और कई बार गलत बता देती हैं। किसी के बीमारी हो, नहीं हो, लेकिन उन मशीनों का अपना काम है। मेरा निवेदन है कि जिस तरह की बातें हैं, इन बातों की ओर ध्यान देना होगा।

मैं एक बात की ओर जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगा। हमारे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री, राजनारायण ने जो योजना रखी है, छोटे-छोटे स्थानों पर हम डॉक्टर नहीं भेज सकते। चीन के अन्दर इस प्रकार के डाक्टर होते हैं जो पैदल घूमते हैं और छोटी-छोटी दवाइयां देते हैं। इस योजना के लिये सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्थान के मंत्रिमण्डल ने इस योजना के अन्तर्गत 27 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तीन माह का प्रशिक्षण देकर एक हजार कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित कर दिया है। दो सौ रुपया प्रति माह मिलेगा, दो सौ रुपये दवाओं के लिये मिलेंगे, 50 रुपये महीना भत्ता मिलेगा और 50 रुपया दवाओं के अतिरिक्त। तो हम लोगों की यह योजना है। गांव-गांव में, एक-एक व्यक्ति को कैसे रहना चाहिये, इस छोटी-सी योजना से गांव-गांव के अन्दर एक-एक गरीब आदमी को इस बारे में ज्ञान मिल सकेगा। धन्यवाद

श्री सभापति : माननीय श्री नरेन्द्रपाल सिंह !

(अनुपस्थित )

माननीय श्री आर. डी. यादव !

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमूं) : सभापति महोदय, मांग संख्या 2 और 26 के संबंध में दिये गये कटौती प्रस्ताव के बारे में विचार व्यक्त करना चाहूंगा।

जहां तक मंत्रिपरिषद् के बारे में सवाल है, मैं इतना ही, आपके माध्यम से मंत्रिपरिषद् के सदस्यों से निवेदन चाहूंगा कि सचिवालय में वातानुकूलित संयंत्र लगाया जा रहा है जबकि राजस्थान में गरीबी की रेखा से 56 प्रतिशत नीचे लोग निवास करते हैं। यह चीज राजस्थान जैसे प्रांत में उचित नहीं है। भूतपूर्व सरकार

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)
ने इसकी योजना बनाई थी, कुछ पैसा खर्च किया था, लेकिन अगर एक साधारण नागरिक और एक मंत्रिपरिषद् के सदस्य के बीच इतना अन्तर डालने वाला कोई भी खर्चा हो, तो मेरे खयाल से उसको निकाल देना चाहिये।

जहां तक चिकित्सा का सवाल है, मैं ग्रामीण क्षेत्र से चुना हुआ विधायक हूं। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में चिकित्सा के बारे में जो अन्तर पिछले काफी टाइम से चला आ रहा है उसमें कुछ सुधार वाली बात नहीं आई है। प्रथम तो मैं बताना चाहूंगा कि गये सैशन के अन्दर मैंने इसी सदन में ग्रामों और शहरों के बीच जो अन्तर है वह बताने की चेष्टा की थी। जनाना हॉस्पिटल और एस. एम. एस. हॉस्पिटल के अन्दर जो देहाती क्षेत्र के लोग अपने रोगियों के साथ आते हैं उनके लिये ठहरने की या टिन शैड की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन एस. एम. एस. हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की गाड़ियों के लिये गैराज जरूर हैं। जब मैं सदन में बोला और अखबारों में चर्चा हुई तो देहात के लोगों ने कहा कि विधायक महोदय, शायद अब कोई व्यवस्था हो, लेकिन तीन-चार महीने बाद गया, तो मैंने यह पाया कि खाली जमीन के ऊपर, खुले आकाश के नीचे, सर्दी के मौसम में जहां लोग सोते थे, वहां से उन्हें भगाने की कोशिश की गई। वहां साइकिल स्टेण्ड लगा दिया गया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री महोदय से पुरजोर शब्दों में मांग करना चाहता हूं, मैं व्यक्तिगत मांग नहीं करना चाहता हूं, यह ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के अन्तरात्मा की आवाज है। इस तरह के जो गैराज हैं, तुरन्त प्रभाव से उन्हें हटा देना चाहिये, साईकिल स्टैण्ड हटा देना चाहिये और जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से रोगियों के के साथ आना चाहते हैं उनके ठहरने के लिये कम से कम टिन शैड या कोई छपरा डालने की व्यवस्था करनी चाहिये।

दूसरा आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक होम्योपैथ विद्यार्थियों का सवाल है स्वास्थ्य मंत्रीजी ने बता दिया है कि पिछले एक महीने से छात्रों के प्रयास से उन्होंने परीक्षा की तिथि निश्चित कर दी है। इसके साथ ही मैं खेद व्यक्त करना चाहता हूं कि राजस्थान के होम्योपैथिक छात्र लम्बे अर्से से उत्तर प्रदेश के बोर्ड से परीक्षा देते रहे हैं। राजस्थान की सरकार ने इस बात को महसूस किया कि तीन-चार सौ छात्र होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के हैं उनकी परीक्षा की व्यवस्था राजस्थान में कराई जाये, लेकिन जो बोर्ड बना उसने कोई कार्यवाही नहीं की। सही बात यह है कि उस बोर्ड के जो सदस्य हैं, उनको मेन्डेट देते हैं, वह महाशय जो प्राइवेट कॉलेज चलाते हैं, उनसे मिलीभगत है। सेन्टर का लाखों रुपया इन प्राइवेट कॉलेज में आता है उनके प्रिन्सीपल्स से, उनके व्यवस्थापकों से और उस बोर्ड के सदस्यों से उनका मेलजोल है। वे नहीं चाहते राजस्थान बोर्ड के द्वारा उन छात्रों की परीक्षा लीजाये। अभी हाल ही में छात्रों ने अपनी परीक्षा का बहिष्कार किया। गत 1½ महीने से हड़ताल पर हैं। ऐसा मैंने सुना है कि कल परीक्षा निर्धारित की गई है। चिकित्सा मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर जानबूझकर किसी अधिकारी ने दिक्कतबाजी पैदा की है, तो निश्चितरूप से ऐसे अधिकारी के

# Page No 152

(152)



(श्री रामेश्वरदयाल यादव)

खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिये।

जहां तक ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा का सवाल है माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा इण्डस्ट्रीज के मामले में हमारी जनता सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को आगे लाने के लिये यह व्यवस्था की है कि एक लाख की आबादी से कम कस्बे और गांवों में जो इण्डस्ट्रीज स्थापित करेंगे उनको अनुदान की राशि दी जायेगी, वैसे ही मैं माननीय चिकित्सा मंत्री से कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में या एक लाख से कम की आबादी के शहरों में चिकित्सा सुविधा फ्री ऑफ चार्ज दिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। मैं यह इसलिये कहना चाहता हूं, जैसे खण्डेला से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बजट में प्रावधान होता है कि दवाइयां हर हॉस्पिटल में दी जाती हैं, लेकिन देखने को यह मिलता है कि वे दवाइयां मिलती नहीं हैं। वह दवाइयां डॉक्टर्स और कम्पाउण्डर्स के द्वारा ब्लैक मार्केटिंग की जा रही हैं, इकट्ठी ले जाकर बाजार में बेच आते हैं। इसलिये कहना चाहता हूं, ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को और एक लाख की कम की आबादी वाले शहरों में फ्री ऑफ चार्ज मेडिकल फैसीलिटीज मिलनी चाहियें। जहां तक मेरे चौमू विधान सभा क्षेत्र का सवाल है, भूतपूर्व चिकित्सा मंत्री जब सीकर से आ रहे थे, चौमू अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया था। वहां के रोगियों की हालत देखकर, उनकी संख्या देखकर, चौमू की 35 हजार की आबादी को देखकर, उन्होंने आश्वासन दिया था कि चौमू में अस्पताल को क्रमोन्नत किया जायेगा। जयपुर जिले में महामहिम राष्ट्रपति महोदय....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पंचों और सरपंचों के सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे, तब मुझे भी स्वास्थ्य विभाग का एक पर्चा मिला था। उसे जब मैंने पढ़ा तो मालूम हुआ कि चौमू अस्पताल को क्रमोन्नत किया जा रहा है। लोगों ने पढ़ा, सारे सरपंचों ने पढ़ा, उनके दिलों के अंदर खुशी हुई, लेकिन आज इस विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है इसमें चौमू का नाम हजम कर दिया गया है। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है या तो स्वास्थ्य मंत्री ने दोनों रिपोर्ट्स को वितरण करने से पहले चैक नहीं किया या यह हो सकता है कि जो अधिकारी जो कुछ सामने पेश करते हैं, मंत्रिमण्डल के सामने पेश करते हैं, उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। यह मेरा गम्भीर आरोप है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की, किसी अधिकारी ने गलती की हो, चाहे हैल्थ कमिश्नर हो, चाहे डाइरेक्टर ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ हो, उसके खिलाफ निश्चितरूप से कार्यवाही करें। राष्ट्रपति महोदय द्वारा पंचों के सम्मेलन को सम्बोधित करते समय, जयपुर जिले के आम आदमी को जो पर्चे वितरित किये गये, उसमें चौमू का नाम था। मुझे उम्मीद है कि स्वास्थ्य मंत्री जैसे सर्वोदयी नेता इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे।

इसके अलावा दूसरा निवेदन करूं कि एक पंचायत समिति में एक प्राइमरी हैल्थ सैन्टर होगा, दो डिस्पेंसरियां होंगी और एक

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

एड-पोस्ट होगी । ग्राम सेक्रेटरिया में एक सेठ नाटानी ने 25 हजार की बिल्डिंग बनाकर सरकार को देनी चाही। मैंने निवेदन किया कि यहां डिस्पेन्सरी है केवल एड पोस्ट हो सकती है, लेकिन वह एड-पोस्ट की सुविधा नहीं दी गई । आज शहरों और ग्रामों में अन्तर है । शहरों में जो भवन बनाये जाते हैं उनका पैसा राज्य कोष से खर्च किया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो भवन बनाये जाते हैं वे दानदाताओं के सहयोग से या चन्दा इकट्ठा करके बनाये जाते हैं...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो, सभापति महोदय, इस तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये । सभापति महोदय, जहां दानदाताओं द्वारा भवन दिये जाते हैं वहां लेडी डॉक्टर की पोस्ट खतम कर दी जाती है । मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री-जी से निवेदन करूंगा कि मेरे चौमू क्षेत्र में कालाडेरा गांव है वहां रामेश्वरप्रसाद सहरिया ने एन.सी.डब्ल्यू. सेन्टर और पी. एच. सी. के लिये बिल्डिंग उपलब्ध करा लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि भूतपूर्व सरकार की मंत्री श्रीमती कमला बेनीवाल ने उन पोस्टों को अपने क्षेत्र में ले जाने के लिहाज से एक को वैराठ में और दूसरी को फुलेरा में लगा दिया । आज वहां डेढ़ लाख की बिल्डिंग है, जो दानदाता ने दी है, लेकिन उसमें लेडी डॉक्टर नहीं है मेरा निवेदन है कि स्व. सेठों ने जहां बिल्डिंगें बनाकर दी हैं वहां से लेडी डॉक्टर की पोस्ट नहीं हटानी चाहिये । यह ख्याल सभी जगह रखना चाहिये । ऐसे स्थानों से लेडी डॉक्टर की पोस्ट नहीं हटानी चाहिये ।

मैं इतना ही कह कर समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री श्रवणलाल ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : सभापति महोदय, मंत्रिपरिषद् के संबंध में मेरे भी कटौती प्रस्ताव हैं । सभापति महोदय, ज्योंही हमारे मंत्रिपरिषद् ने शपथ ली, ग्रामीण जनता में बहुत उत्साह उत्पन्न हुआ । जनता ने सोचा कि नया मंत्रिमण्डल आया है । वर्षों से, जिस बात के लिये हम तरस रहे थे, उसकी यह पूर्ति करेंगे । सभापति महोदय, जिस प्रकार से मंत्रिमंडल छोटा बना और हर मंत्री के पास ज्यादा विभाग रहे । जनता की आकांक्षा ज्यादा होने के कारण यहां राजधानी में ग्रामीण एवं शहरी जनता अपने अमुक-अमुक कामों को लेकर पधारी । हमारे मंत्री महोदय ने अपने द्वार आम जनता के लिये खोल दिये । जिस प्रकार से एक मंदिर के अन्दर भगवान के दर्शन के लिये जनता जाती है उसी प्रकार उनके यहां किसी प्रकार की रोक-टोक नहीं हुई । लेकिन, सभापति महोदय, मैं इस बात को उचित नहीं समझता हूं । इसका नतीजा यह हुआ कि न भीड़ ने उनको काम करने दिया और न उन्होंने किया । यहां तक हालत हुई कि हमारे मंत्री महोदय को सुबह पांच बजे अपने घर को छोड़कर राज-काज की दृष्टि से एकान्त में छिपना पड़ा । तो, सभापति महोदय, मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री महोदयों से यह आशा करूंगा कि उनका जो कार्य है, उस कार्य को निष्ठापूर्वक करें, यह सदन आपके साथ है । मैं यह भी प्रार्थना करूंगा कि वे किसी भी उद्घाटन में जायं, लेकिन उद्घाटन के लिये जाने से पहले इस बात को देख लें कि जिसका

# Page No 154

(154)



(श्री श्रवणलाल)
में उद्घाटन करने जा रहा हूं, वह सार्वजनिक है या व्यक्ति विशेष का ।

सभापति महोदय, मुझे आपके द्वारा एक निवेदन करना है, मेरे क्षेत्र में वित्त मंत्री महोदय पधारे थे । मुझे इत्तला नहीं दी कि मेरे क्षेत्र में वित्त मंत्रीजी जा रहे हैं, लेकिन जिनके यहां जाने वाले थे उनका एक कार्ड मेरे पास आ गया था । मुझे मालूम पड़ा, राजस्थान के वित्त मंत्री एक खाद की दुकान का उद्घाटन करने जा रहे थे । तो मेरा निवेदन है कि व्यक्ति विशेष की दुकान आदि के उद्घाटन के लिये राजस्थान के वित्त मन्त्री पधारें, यह शोभा नहीं देता....

श्री मानसिंह दांगा : आपके जरिये जाना चाहिये था। बिड़लाजी के यहां जाना चाहिये था ?

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक कार्यों के लिये वे कहीं भी पधारें हमें बड़ी खुशी होगी, लेकिन चाहे वह छोटी दुकान हो या बड़ी दुकान हो....

श्री शीशराम ओला : सभापति महोदय, यह तो घर में बैठकर भी कहा जा सकता है।

श्री टीकमचन्द कान्त : कहने दो ।

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदय, माननीय सदस्य को बड़ा दुःख हो रहा है, क्योंकि इस प्रकार की बातें वे घर ही घर में कर लिया करते थे ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, जिस प्रकार से अभी कुछ समय पहले हमारे मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि हम 38 लाख रुपया एयर कंडीशन में खर्च करने जा रहे हैं......

श्री शीशराम ओला : 50 लाख ।

श्री श्रवणलाल : आगे जाकर 50 लाख होगा । तो मैं, श्रीमन्, आपके द्वारा हमारे मुख्य मंत्रीजी को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय वे विरोध पक्ष में बैठते थे उस समय वहां खस की टट्टियां लगती थीं, उन पर पानी छिड़का जाता था तो उसके लिये भी वे बार-बार पिछली सरकार को कोसा करते थे लेकिन, सभापति महोदय, अब केवल एक बहाना लेकर एयर कन्डीशन लगा रहे हैं कि पिछली सरकार इस काम को कर गई इस वजह से हमें लगाना पड़ रहा है । मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय निवेदन करूंगा, यही पैसा जनता के लिये खर्च किया जा सकता है । यह पैसा चाहे हवाई के लिये देते, चाहे ग्रामीण जनता के लिये देते यही पैसा बान्ध पर खर्च किया जा सकता था । यही पैसा किसानों को उनके खेतों की पिलाई के लिये देते तो आज जो इस पैसे को यहां लगाया जा रहा है वह किसान की भलाई में लगता, देश के उत्पादन में लगता । सभापति महोदय, किसान का उत्पादन बढ़ता, उत्पादन के साथ देश का विकास होता, समृद्धि बढ़ती और साथ में अपने बाल-बच्चों का भरण-पोषण करता । हमेशा हमेशा उनके बच्चे दुहाई देते कि यह बान्ध उनके समय में बना था ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन कर रहा हूं कि हमारे मंत्रिपरिषद के खर्च में अनेक प्रकार की कटौतियां हो

155



(श्री भवनलाल)

सकती हैं। गाड़ियां जैसे पहले कांग्रेस के राज्य में घूमा करती थीं वह आज भी घूमने लगी हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, अब दूसरी मांग चिकित्सा सम्बन्धी है, उसमें भी मेरे कटौती के प्रस्ताव हैं। चिकित्सा सम्बन्धी व्यवस्था शहरों को छोड़कर या जो मुख्य मुख्य कस्बे हैं उनको छोड़कर बाकी सब जगह नगण्य है। सभापति महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि किसी भी छोटे गांव के चिकित्सालय में जाएं तो जो पट्टियां उपलब्ध होती हैं, उनका कहीं पता नहीं है। मरीजों से पट्टियां मंगाते हैं। अगर किसी के फ्रेक्चर हो गया और वहीं पर पहुंच गए तो फ्रेक्चर के ऊपर जो पाउडर पट्टियां मिला कर प्लास्टर किया जाता है वह पट्टियां भी उसी से बाजार से मंगाई जाती हैं। वह पट्टी ले आता है तभी आकर प्लास्टर होता है। तो, सभापति महोदय, इस प्रकार से शहरों की तुलना में गांवों की उपेक्षा की जाती है, वह नहीं होनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा हिण्डौन की तरफ ध्यान दिलाऊं। वहां पर स्टेट टाइम का प्राथमिक चिकित्सालय है वह किस प्रकार का है? उसके अन्दर पांच या छः बेड हैं। सभापति महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि स्टेट टाइम का वह अस्पताल आज तक वहीं का वहीं है जबकि वहां की आबादी उस समय से लेकर के चौगुनी या छः गुनी पहुंच गई है। इसी के साथ-साथ पूरी तहसील का वर्क उसी डिस्पेंसरी के पास आता है। वहां पर ठीक प्रकार की व्यवस्था नहीं होने के कारण वहां के मरीज, सभापति महोदय, या तो भरतपुर जाते हैं या करौली जाते हैं। असुविधा के होने के कारण और भरतपुर की इतनी दूरी होने के कारण जो केसेज वहां पर होते हैं वह रास्ते में, यहां तक कि गांव के रास्ते में ही मर जाते हैं। इसलिए मैं आपके द्वारा, सभापति महोदय, वहां की व्यवस्था को सुधारने के लिए निवेदन करूंगा। पिछली सरकार ने एक बार घोषणा की थी कि वहां पर चालीस बेड का अस्पताल खोल दिया जाएगा, लेकिन पता नहीं कागजों में कहां गायब हो गया।

इसी के साथ साथ मेरा निवेदन है सभापति महोदय, महावीरजी के अन्दर एक डिस्पेंसरी है। महावीरजी एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। दूर-दूर के यात्री वहां पर आते हैं लेकिन वहां पर डिस्पेंसरी के अन्दर जो व्यवस्था है वह बिलकुल नगण्य है। आपको अभी का ताजा उदाहरण दूं, सभापति महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि वहां डाक्टर करीब

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पांच साल से उसी जगह मौजूद है। पांच साल से वह काम करता चला आ रहा है। कई बार उसका स्थानान्तरण हो गया लेकिन वह वहां से नहीं हटा। कांग्रेस सरकार चली गई लेकिन वह डॉक्टर वहां से नहीं गया। आप ताज्जुब करेंगे, सभापति महोदय, अभी-अभी एक केस पन्द्रह बीस रोज पहले हुआ, एक डिलिवरी का केस था जिसको लेकर गांव चले आए। उनके पास पैसा नहीं था। डाक्टर ने सौ रुपये मांगे। पहले रुपये दीजिए तब इस केस के हाथ लगाऊंगा। गांव वाले बेचारे भागे। उसके लिए सौ रुपये लाए। सौ रुपये लेने के बाद में उसने उस केस को सम्भाला। सभापति

# Page No 156

(156)



(श्री श्रवणलाल)

महोदय, इस चक्कर में वह डिलिवरी केस बिगड़ गया, वह बच्चा मर चुका था। बच्चे के मरने के बाद उस स्त्री की भी मौत हो गई, यह हालत हो रही है, सभापति महोदय। उसके लिए लिखा पढ़ी की, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई।

सभापति महोदय, इसी के साथ-साथ उस समय मिनिस्टर थे हमारे ललित किशोरजी चतुर्वेदी .....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : नाम मत लो, मंत्री-मंत्री कायम रहता है।

श्री श्रवणलाल : हमारे यहां कुछ वर्षा अधिक होने के कारण और कुछ छोटे-छोटे तालाब होने के कारण मच्छरों का ज्यादा जोर रहता है..

श्री सभापति : भाषण समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री श्रवणलाल : मच्छरों के पैदा होने का ज्यादा स्कोप है, इसलिए मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि मलेरिया का स्कोप बढा हुआ है, मलेरिया फैला हुआ है, इसको तुरन्त रोका जावे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री श्रवणलाल : एक मिनट में समाप्त करता हूं।

तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि वहां पर भ कर रोग फैल रहे है, उनकी रोकथाम की जाय। वहां पर डॉक्टरों की जो व्यवस्था है उसको ठीक किया जावे।

सभापति महोदय, करौली जिले का हास्पिटल है, वहां पर जो एक्स-रे मशीन है वह आए दिन खराब रहती है। वह आए दिन खराब रहने के कारण वहां के मरीजों को हमेशा तकलीफ उठानी पड़ती है। उन्हें या तो भरतपुर जाना पड़ता है या जयपुर भागना पड़ता है। इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान दिलाता हूं कि उस मशीन को जल्दी से जल्दी ठीक कराया जावे।

सभापति महोदय, इससे पहले कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं एक बात और कहना चाहूंगा। सभापति महोदय, जिला सवाई माधोपुर एक बेकवर्ड एरिया है, जहां पर काश्तकार ज्यादा हैं। आपने इस प्रकार की टाल लगा रखी है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में डिस्पेंसरी खोली जाएगी, एड-पोस्ट खोला जाएगा या प्राथमिक चिकित्सालय खोला जाएगा तो जनता से श्रमदान के रूप में पहले बिल्डिंग मांगते हैं.....

श्री सभापति : भाषण समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री श्रवणलाल : वह बिल्डिंग जब तक वह बना कर नहीं दें, हालांकि डिस्पेंसरी मंजूर हो गई, मंजूर हुई पड़ी है तब तक डिस्पेंसरी नहीं खोली जायगी। माननीय सभापति महोदय, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। किसान बिल्डिंग नहीं बना पाता है इसलिए जिस प्रकार से सरकार शहरों में व्यवस्था करती है, हॉस्पिटल बनाती है, बिल्डिंग बनाती है उसी प्रकार से गावों में व्यवस्था करे जिससे कि मंजूरशुदा जो डिस्पेंसरी है वह चालू हो सके। गांवों में डॉक्टर नहीं

(श्री अग्रवाल)

पहुंचते है, नर्स नही पहुंचती है, इसलिए डिस्पेंसरी की व्यवस्था गांवों में अधूरी रह जाती है। लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती है। यही मैं आपको निवेदन करूंगा।

श्री सभापति : माननीय श्री रतनलाल वर्मा।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : सभापति महोदय, आज से तीस साल पहले भी यही बात कहते थे कि गांव वाले अस्सी पर्सेंट हैं और आज भी सदन में यही बात कही जाती है कि अस्सी पर्सेंट गांव वाले हैं और हकीकत में भी अस्सी पर्सेंट ही है। किन्तु दुःख की बात तो यह है कि तीस साल से कभी भी अस्सी प्रतिशत पैसा गांवों में नहीं लगा, अस्सी प्रतिशत डॉक्टर और डाक्टरनियां गांवों में नहीं गईं और आज भी नहीं जा रही हैं।

मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से...

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अस्सी पर्सेंट गांव में रोगी ही हैं क्या ?

श्री रतनलाल वर्मा : आप मेहरबानी करके सुन लीजिए, यह अच्छी बात नहीं है।

तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूं आपके माध्यम से कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर सांप किसी को डस जाता है तो उसका इलाज नहीं होता, उसको मरना पड़ता है। अगर किसी औरत का बच्चा अटक जाय तो उसको मरना पड़ता है। मोटर का साधन नहीं, सड़कें नहीं, बैलगाड़ी से अगर ले जायें तो रास्ते में मौत हो जाती है। यह बात तीस साल पहले भी होती थी और आज भी होती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि दिग्विजयसिंह, हमारे कृषि और पशुपालन मंत्री अराई आए थे। हम तीन चार एम. एल. एज. भी उनके साथ गए थे। आप इनसे पूछिए, सड़कों का क्या हाल है ? अगर कोई गर्भवती महिला साथ हो जाय और उसको मोटर में बिठा कर...

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : सड़कें तो कल ही चली गईं।

श्री रतनलाल वर्मा : अगर किशनगढ़ लाया जाय तो, सभापति महोदय, मैं गारन्टी के साथ कह सकता हूं कि महिला जिन्दा हास्पिटल तक नहीं पहुंच सकेगी। सड़क पर चार-चार, पांच-पांच इंच के खड्डे हैं। इनकी एम्बेसडर मोटर थी, उसके नीचे से पत्थर अड़ रहे थे। बड़ी मुश्किल से आए और बड़ी मुश्किल से गए। आज भी, तीस साल गुजर जाने के बावजूद बड़े गांवों की यह हालत है। पंचायत समिति हैडक्वार्टर अराई की यह हालत है। एक पंचायत समिति हैडक्वार्टर ही नहीं अनेकों पंचायत समिति हैडक्वार्टर्स की यही हालत है। अभी भी यह कहा गया कि पांच हजार की जन० संख्या वाले गांवों को सड़क से मिलायेंगे। यह क्या तमाशा है, क्या मखौल है ? फिर यह समानता की बात करते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से जिस तरह से 80 प्रतिशत की बात कही जाती है या तो 80 प्रतिशत की बात करना बंद कर दें और यदि 80 प्रतिशत की कोई बात कही जाती है तो इस में कोई सन्देह नहीं है 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है, तो 80 प्रतिशत पैसा गांवों में ही लगना

(श्री रतनलाल वर्मा)

चाहिये, हर योजना, हर काम 80 का प्रतिशत पैसा गांव में लगना चाहिए।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, जहां पर अस्पताल है, वहां पर दो-तीन साल से डॉक्टर नहीं हैं। जहां पर लेडी डॉक्टर की पोस्ट है वहां पर 12 महीनों से लेडी डॉक्टर नहीं है। यह क्या व्यवस्था है? कांग्रेस के राज में ये लोग गुलछर्रे उड़ाते थे, रंगरेलियां करते थे। मैं यह कह देना चाहता हूं कि यह स्वास्थ्य का सवाल है, यह तन्दरुस्ती का सवाल है बीमार का इलाज करने का सवाल है। इसमें किसी प्रकार का, कोई तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए और समान रूप से इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तब जाकर यह न्यायोचित बात होगी। गांव वालों को तब जाकर आत्म संतुष्ट होगी। यदि वह बीमार होते ही दवा पी जाते हैं, उन्हें दवा मिल गई तो वह संतुष्ट हो जाएंगे। काश्तकार कुए से सिंचाई कर रहा हो, उसकी कोठार टूट जाय तो वह सीधा कुए में जाता है, और वहां पर मर जाता है। वह मर जाता है तो उसकी लाश सफाखाने लाई जाती है। वहां पर डॉक्टर नहीं मिलता। उसकी लाश को बैलगाड़ी में डालकर किसान दो-दो रोज तक घूमते रहते हैं लेकिन उसकी लाश का पोस्टमार्टम नहीं होता है। पोस्टमार्टम के बिना लाश नहीं जल सकती है। सांप खा जाए तो बिना पोस्टमार्टम के लाश नहीं जल सकती। यह सारे कानून कांग्रेस राज्य के बनाये हुए हैं। यहां पर स्वास्थ्य मंत्रीजो और अन्य मंत्रीजो बैठे हैं उनको मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि शंकाप्रद बातें हों, जहर खाकर मरने की बात हो, या किसी तरह की शंका की बात हो, पोस्टमार्टम की बात ठीक है लेकिन जहां पर शंका का सवाल नहीं है, किसी तरह का झगड़े का सवाल नहीं है, कुएं में गिर कर मर गया हो, औरत पानी भरते हुए कुए में गिर गई और मर गई हो, उसका पोस्टमार्टम दो-दो दिन न हो, यह गलत है। इसलिए इस कानून को बदलना चाहिए। यह कानून शहर के लिए हो सकता है परन्तु गांवों के लिए नहीं हो सकता है। गांवों के लिए यह कानून बड़ा परेशानी पैदा करने वाला है। यह हमको मालूम है क्योंकि हम गांवों में रहते हैं।....

श्री शंकरलाल : यह पुलिस डिमाण्ड पर कहें। बात आपकी सही है।

श्री रतनलाल वर्मा : यह चिकित्सा से भी संबंध रखता है। पोस्टमार्टम कौन करता है? आप करते हैं?

श्री सभापति : आप बोलिए।

श्री रतनलाल वर्मा : या तो गांव-गांव में पोस्टमार्टम की व्यवस्था करें और यदि गांव-गांव में यह व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो इस कानून को बदलिए। इन दो बातों में से एक आपको करनी होगी।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : 80 प्रतिशत मेंटल अस्पताल गांवों में भी खोल देने चाहिए।

श्री रतनलाल वर्मा : ये खुद पागल हैं। जनता पार्टी छोड़कर उधर चले गये हैं। यह पागलपन नहीं तो क्या है? पागल हो गये तो पागलखाने में रतनलाल ही ले जाएगा।

सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है....

श्री शंकरलाल : एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य के लिए पागलखाने से

(श्री शंकरलाल)

आने के शब्द जो कहे गये हैं, यह उचित नहीं हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : जो जैसा करेगा वैसा सुनेगा।

श्री शंकरलाल : हाउस के अन्दर यहां कहना गलत है।

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा, स्वास्थ्य विभाग और आयुर्वेद विभाग ये दोनों विभाग अब एक मंत्री महोदय के पास हैं, इसलिए जिन पंचायत समिति में औषधालय की व्यवस्था नहीं है, वहां कम से कम दो पंचायत समिति में एक औषधालय नहीं तो दस गांवों में एक औषधालय खोलिए और 50 गांवों के बीच में एक अस्पताल खोलिये। यह मेरा आपसे नम्र निवेदन है। इस मामले में अधिक न कहते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो किसान भारत का अन्नदाता है, अरे मंत्री महोदय····

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। माननीय सदस्य 'अरे-अरे' कह रहे हैं। यह संसदीय नहीं। यह शब्द निकाल दिया जाए।

श्री रतनलाल वर्मा : किसी के प्रति कोई ओछा शब्द नहीं कहा है। यह मेरा निवेदन है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : 'अरे' शब्द ओच्छा होता है ?

श्री रतनलाल वर्मा : मुझे सभी सदस्य शिरोधार्य हैं। मेरी निगाह में सदस्यों में कोई फर्क नहीं है। सभापति महोदय, गांवों के अन्दर किसानों के इलाज के लिए कोई साधन नहीं हैं। किसी तरह की सुविधा वहां नहीं है। किसान को कोई दवाई नहीं मिलती। फ्री इलाज नहीं होता। अगर वह बीमार हो जाता है तो अजमेर, जयपुर आना पड़ता है इलाज के लिए। सभापति महोदय, यहां डॉक्टर उससे फीस लेकर भर्ती करेगा। इसके बिना इलाज नहीं होगा। यह मैंने आंखों से देखा है। मैंने इसके लिए झगड़ा किया। हाथापाई की है अब भी नौबत आ जाएगी तो चूकने वाला नहीं हूं। हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज भी यह हो रहा है। कांग्रेस के जमाने में भी मैंने झगड़ा किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर, डॉक्टरनी के ऑर्डर दे देते हैं तो ये लोग जयपुर के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। विधायक के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, स्वास्थ्य मंत्री पर दबाव डाल कर ऑर्डर कैंसिल करवाते हैं। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक दफा आप आदेश दें, तो थूक कर चाटना मत सीखो। एक दफा आदेश कर दें····

श्री मदनसिंह दांता : क्या पालियामेन्ट्री लैंग्वेज है ?

श्री रतनलाल वर्मा : मैं यह निवेदन करूंगा, मैं गांव का रहने वाला हूं, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। आप कैसे भी समझ लीजिए।

श्री मूलचन्द डागा : आपके भाव अच्छे हैं।

श्री शंकरलाल : नीयत साफ है।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। आप पूरे जोश के साथ कहिए। . . . .

श्री रतनलाल वर्मा : दो मिनट में ही समाप्त कर रहा हूं। हाथ जोड़कर कहता हूं, मुझे बोलने दीजिए। फिर मैं कड़वी बात कह दूंगा तो आपको बुरा लगेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्रिमण्डल के कोई भी सदस्य उद्घाटन में जाएं तो कम से कम वे एक संकल्प कर लें। कहीं पर मुलम्मेबाज और दूसरे मे जैसे चंदजी हैं, जो उनके आगे लड़कियों का नाच करवाते हैं तो मिनिस्टर साहब वहां पर न जावें। वे लड़कियों का नाच अपने सामने नहीं होने देवें। यह मैंने पहले भी निवेदन किया था. ......

श्री मदनसिंह दांता : जब नाथूरामजी मिर्धा कहीं गये थे और लड़कियों का नाच हुआ था तो भैरोंसिंह शेखावत ने दो घंटे तक हल्ला किया था। आज उन्हीं के राज्य में लड़कियां नाचें यह उचित नहीं है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : सभापति महोदय, कला और संस्कृति पर राज्य सरकार की ओर से करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। कला संस्कृति के अनुसार कोई नृत्य होता है तो वह उचित है....

श्री रतनलाल वर्मा : अगर गुप्ताजी का राज्य आ जावे और वे अपनी औरत को नचावें तो मुझे कोई गम नहीं है लेकिन जनता राज्य में यह नहीं होगा।

श्री मदनसिंह दांता : ऑन ए-पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जहां तक मेरा संबंध है ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, श्री मदनसिंह दांता। मैंने आपका पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सुन लिया था।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय सभापति महोदय, इन्होंने महिलाओं के बारे में कहा है। हम कला और संस्कृति की बात कर रहे हैं। अगर संयमित ढंग से कोई कार्यक्रम होता है तो यह कहना गलत है कि लड़कियों को नचवाया जाता है। अगर उस फेस्टिवल में जायेंगे....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : इनका यह कहना किसी प्रकार से उचित नहीं है। मैं चाहूंगा, स्वास्थ्य मंत्रीजी इस पर कोई ध्यान नहीं दें।

श्री सभापति : यह उनके व्यक्तिगत विचार हैं।

माननीय श्री मदनसिंह दांता!

श्री मदनसिंह दांता : मैं यह निवेदन करूंगा, यह उचित नहीं होगा कि कोई माननीय सदस्य किन्हीं माननीय सदस्य की धर्मपत्नी के बारे में इस प्रकार से कहें।

कई माननीय सदस्य : हैं ही नहीं। अभी शादी ही नहीं हुई है।

श्री सभापति : श्री रतनलाल वर्मा!

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय सभापति महोदय, मैं नम्र शब्दों में कहता हूं। चाहे वह जनता पार्टी के माननीय सदस्य का क्षेत्र

(श्री रतनलाल वर्मा)

हो या कांग्रेस पार्टी के सदस्य का क्षेत्र हो, अगर कोई मंत्री महोदय किसी क्षेत्र में जाते हैं तो उस स्थान के विधायक को इसकी सूचना मिलनी चाहिए कि फलां तारीख को फलां मंत्री महोदय आ रहे हैं ताकि वहां की समस्याओं को प्रस्तुत कर सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरा यह नम्र निवेदन है। दूसरे जो लोग भ्रष्ट हैं, गलत हैं ऐसे आदमियों के यहां जाकर मंत्री महोदय खाना नहीं खायें। यह भी नम्र निवेदन है। इन सब बातों का पालन करना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य 'आप हाथ जोड़ कर प्रार्थना करने' शब्दों का प्रयोग नहीं किया करें।

श्री शंकरलाल : आदत है।

श्री रतनलाल वर्मा : हमारे जो जनता राज के मंत्री हैं, उनसे बहुत उम्मीद है। वह अपने रहन-सहन के तरीके को सम्भाले रखें, यही मेरा नम्र निवेदन है। जय भारत।

श्री सभापति : माननीय श्री सुभाषचन्द्र!

(अनुपस्थित)

माननीय श्री गुरुशरण छाबड़ा!

(अनुपस्थित)

माननीय श्री हरिकृष्ण!

श्री हरिकृष्ण (नदबई) : आदरणीय सभापतिजी, प्रशासन में अपव्यय की सदन में बड़ी चर्चा रही है। मैं इस बात को मानता हूं हूं, नयी-नयी सरकार बनी है। नयी-नयी समस्याएं रही हैं और जनता का अभाव मंत्रियों के यहां रहा है। इन बातों के होने का अर्थ यही है कि खर्चा बढ़े। किन्तु ऐसा लगता है कि खर्चे में कटौती होगी। मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हम गांवों की सही समस्या रख रहे हैं। इन बातों को जानने के लिए मंत्री महोदय को गांवों का दौरा करना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : गांवों का दौरा करने से खर्चा बढ़ेगा।

श्री हरिकृष्ण : गांवों की समस्याएं दूर करने के लिए यदि खर्च बढ़ता है तो बढ़ने दो। मैं तो यह भी निवेदन करता हूं कि गांवों के साथ-साथ सरकारी दफ्तरों में भी संबंधित माननीय मंत्री अचानक जायें। वहां जाकर देखें क्या हाल है? विद्यालय हैं, चिकित्सालय हैं, अचानक वहां पहुंच जायें। ऐसा करेंगे तो हमारी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होंगी। हमारी इच्छा थी कि राजस्थान में ऐसी सरकार आयेगी जो गरीबों की देख-रेख रखेगी।

चिकित्सा विभाग पर काफी चर्चा की है। मैं इस बात को पूर्ण दावे से कह सकता हूं कि चिकित्सालयों और औषधालयों में भ्रष्टाचार है। मैं निवेदन करूंगा कि किसी मरीज को लेकर पहुंचते हैं तो डॉक्टर महानुभाव को अगर पहले घर पर दिखायें तो ही भर्ती करते हैं और उसकी परवाह करते हैं। नहीं तो अस्पताल में बैड भी नहीं मिलता है। इसके अलावा दवा का प्रबन्ध सरकार की तरफ से है किन्तु वहां केवल नाम मात्र की दवा दी जाती है। जितनी भी दवा मिलती है, उसको रिकार्ड में दिखा देते हैं। गरीबों को पर्ची के सिवाय दवा नहीं मिलती है।

(श्री हरिकृष्ण)

(6.28 सायं)

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

दवा थोड़े आदमियों के काम आती है। इसकी सावधानी रखना हमारे मंत्री महोदय का काम है।

हमारे देश के चिकित्सालयों में पश्चिमी देशों की नकल हो रही है। इससे गरीब और साधारण आदमी के स्वास्थ्य का सुधार नहीं हो सकता है। हमारे चिकित्सालयों को इस प्रकार का बनाना चाहिए कि गरीबों का भला हो सके। मुझे बुखार आया। मेरा बुखार दूर करने में 100 रुपये का खर्चा होता है। गांव का गरीब किसान आदमी किस तरह से इतना खर्च कर पायेगा। गांव के लोगों की हालत बहुत खराब है। मैं तो यह कहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग पर मच्छरों ने विजय पा ली है। मच्छरों को मारने के लिए उन्हें शक्ति बढ़ानी चाहिए। मान्यवर, डिस्पेन्सरियां खुली हुई हैं, प्राथमिक चिकित्सालय भी हैं, किन्तु जहां प्राथमिक चिकित्सालय हैं वहां बेड्स का इन्तजाम नहीं, बिस्तर और चद्दर न मिले, अस्पताल की सफाई ठीक तरह से न हो, लेट्रिन का इन्तजाम नहीं हो, तो बीमार कैसे ठीक हो सकते हैं। मान्यवर, नदबई का अस्पताल प्राइमरी हैल्थ सेंटर है, वहां पर दस-बारह बेड्स की व्यवस्था है। उसको यदि 50 बेड्स का अस्पताल बना दिया जाय और प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के नाते एक लेडी डॉक्टर का भी प्रबन्ध करें तो वहां की जनता को अत्यधिक लाभ मिलेगा। उस प्राइमरी हैल्थ सेंटर के तहत पांच मेडिकल सब-डिविजन हैं, पांच सेन्टर परिवार नियोजन के हैं किन्तु नाममात्र के सेन्टर्स हैं, कहीं भी पूरी तरह से व्यवस्था नहीं है, कहीं नर्सें नहीं हैं, मेडिकल सेन्टर पर कोई इंतजाम नहीं है। बाज-बाज फेमिली प्लानिंग के सेन्टर बिना कर्मचारियों के खाली पड़े हुए हैं तो गिनती बढ़ाने से कि वहां के प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के तहत दस सब-सेन्टर हैं, कोई लाभ नहीं है। मेरा क्षेत्र पूरी तहसील नदबई है, उसमें दस पंचायतें बयाना की आती हैं। उनमें जनता के इलाज के लिए बहुत कम व्यवस्था है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वहां औषधालय, डिस्पेन्सरीज खोलने की व्यवस्था करें। उन गांवों की जनता सरकार को औषधालय, डिस्पेन्सरी खोलने के लिए अपनी ओर से मकान देने के लिए भी तैयार है। बरोली द्वारा दयावली, मिलकपुर व गेरा ये गांव ऐसे हैं जहां पर लोग मकान देने के लिए तैयार हैं। औषधालय और डिस्पेन्सरी के लिए वे मकान दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जहां प्राइमरी हैल्थ सेन्टर हैं वहां पर आधुनिक मशीनरी की व्यवस्था न हो तो इलाज की व्यवस्था अधूरी है। एक छोटी-सी मशीन, आक्सीजन की मशीन, जिसकी कीमत भी शायद कम होगी, के न होने से प्राइमरी हैल्थ सेन्टर से मरीजों को जिला अस्पताल में जाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जहां प्राइमरी हैल्थ सेन्टर है, वहां यदि डिस्पेन्सरी का इन्तजाम न कर सकें तो प्राइमरी हैल्थ सेन्टर की व्यवस्था बिठाने की अब आप कृपा करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मान्यवर, सदन में चर्चा नसबन्दी के संबंध में भी हुई है। यह वास्तव में बहुत जरूरी भी है। यदि बढ़ती हुई जनसंख्या पर सरकार ने काबू नहीं

(श्री हरिकृष्ण)

पाया तो यह आगे चलकर बहुत घातक होगी। इसका इलाज केवल एलोपैथी ही नहीं है नसबन्दी ही नहीं है। मान्यवर, हमारे देश की आयुर्वेदिक चिकित्सा में ऐसी-ऐसी जड़ी बूटियां हैं कि बच्चे पैदा होना तुरन्त बन्द हो जायं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि एलोपैथी चिकित्सा पद्धति ही नहीं है लेकिन उसके साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा, जो हमारे देश की चिकित्सा पद्धति है, की तरफ अधिक ध्यान देने की कोशिश करें। आयुर्वेदिक औषधियों से जब हमारे देश के बिना पढ़े-लिखे आदमियों के बच्चे होना बन्द हो सकता है तो क्यों नहीं जड़ी बूटियों की तलाश करके औषधियों का निर्माण कराया जाय।

मैं इतना ही कह कर बैठने की आज्ञा चाहूंगा। जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री आलम अली।

श्री आलमअली खां (फतहपुर) : सम्माननीय अध्यक्षजी मैंने सभी माननीय सदस्यों की मंत्रिमण्डल के बारे में सुबह से बात सुनी। आज एक नई चीज सुनने में आई। मन्त्रिमण्डल के खर्चों के लेखा-जोखा के बारे में कभी भी हाउस के अन्दर चर्चा नहीं की गई। पिछली सरकार अपनी सारी बातों को गुप्त रखा करती थी। लेकिन इस सरकार के समय में यह नई बात हुई है कि मंत्रिमण्डल के खर्चों का लेखा-जोखा सामने है, उस पर विचार-विमर्श हो रहा है और सबको बोलने का मौका मिल रहा है। इस बात के वास्ते मैं जनता सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

सम्माननीय अध्यक्षजी, खर्चा ज्यादा हो सकता है अच्छे कामों के लिए। पुराने जो सदस्य हैं इस साइड में बैठने वाले, वे जानते हैं कि उनकी सरकार हर काम ओले में करती थी।

श्री मदनसिंह दांता : Secret is success.

श्री आलमअली खां : सम्माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। सभी माननीय सदस्यों को पुराना अनुभव है, आप देखते थे कि विरोधी दल को आपकी सरकार बुरी नजर से देखती थी। मैं जनता सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारे विरोधी दल की इज्जत हमारे से ज्यादा की जावे। यह राज का कर्त्तव्य है।

सम्माननीय अध्यक्षजी, कोई भी सरकार हो, नाजायज खर्च नहीं होना चाहिए। ज्यादा खर्चा होना कोई अन्याय की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि अच्छे कामों में खर्च नहीं किया जाय लेकिन बुरे कामों में खर्चा नहीं किया जाना चाहिए। आज मैं चाहे जो कुछ कह सकता हूं और दूसरे भी कह सकते हैं, बोलने पर कोई पाबन्दी नहीं है, यह प्रजातन्त्र है। लेकिन नजर देखनी है कि खराब नीयत से तो नहीं देख रहा है। माननीय अध्यक्षजी, मैं मान कर चलता हूं कि आज की तारीख तक जनता सरकार की बुरी नजर नहीं है। आगे चाहे कुछ भी हो, इसके लिए मैं नहीं कह सकता।

मैं दूसरी बात अब कहूंगा शफाखानों व अस्पताल के वास्ते। कहते हैं कि अस्पतालों में भ्रष्टाचार है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहूंगा कि भ्रष्टाचार है या क्या है। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। सम्वत् 1975 में महामारी की तपकाली की

(श्री आलमअली खां)

बीमारी पड़ी, काफी संख्या में लोग मर गए। इस वैज्ञानिक युग में चेचक की बीमारी या दूसरी कैसी भी बीमारी हो उससे लोगों को मरने नहीं दिया जाता। चाहे कोई चोर हो, कोई डकैत हो, मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है। कोई कुछ भी कहे। मैं खुद साफ हूं तो दुनिया साहूकार है। मैं नहीं कहूंगा कि किसने क्या किया है, क्यों किया है? करने वाला जाने।

माननीय अध्यक्षजी, देश का जो भी नागरिक हैं चाहे ऑफिसर है, सिपाही है, या चपरासी है, चाहे किसी भी रूप में है वह सम्माननीय नागरिक है। हमारे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, ऑपरेशन सफलतापूर्वक करते हैं। बाकी जिसने चोरी की है वह उसकी सजा भुगतेगा। मैं चोरी करूंगा या डाका डालूंगा तो मैं सजा भुगतूंगा। हिन्दुस्तान धार्मिक मुल्क है यहां सब बातें धर्म की होनी चाहिएं। दुनिया में न कोई चोर रहेगा न डाकू, केवल धर्म ही रहेगा।

अस्पताल तो बड़े-बड़े शहरों में हैं मेरा निवेदन है, जहां साधन हैं वहां अस्पताल खोले जायें। साथ ही आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाइयों को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए। यूनानी व आयुर्वेदिक औषधालय ज्यादा खुलवायें जिससे खर्चा भी कम हो और गांव वालों को जो तकलीफ होती है वह दूर हो जाए। राज और राम में कोई फर्क नहीं है। हिन्दुस्तान में बड़े-बड़े बादशाह व राजा हुए हैं जिनका नामोनिशान नहीं रहा। साधु, सन्त व फकीरों की हर जगह पूजा हो रही है, वे धर्म के पक्के हैं। हमें हृदय-परिवर्तन करना पड़ेगा। बाकी राम-राम जपना और पराया माल तकना में कोई सार नहीं है। जो पुरानी सरकार के सदस्य हैं वे पहले अपने को देख लें। आप चाहे आए में जाओ, चाहे गए में जाओ. हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, हम तो कांग्रेस वालों को अपनी जनता के अन्दर ही मानते हैं। भेद-भाव करना आपका काम है हमारा नहीं है। पूरी दुनिया जनता में शामिल है। जो शैतानी करेगा वह सजा भोगेगा। धर्म आग में जलता नहीं, नाम कभी मरता नहीं, एक बच्चा जिस औरत का हो जाता है वह बांझ नहीं कहलाती। आज जो सरकार ने नया नमूना पेश किया है कि मंत्रिपरिषद् की मांग पर बहस होने दी है, यह देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देता हुआ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थी सिंह !

(अनुपस्थित)

श्री हनवन्त सिंह !

(अनुपस्थित)

श्री उगमराज मेहता !

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, जनता सरकार ने जो चिकित्सा के क्षेत्र में गांवों में प्रशिक्षण केन्द्र खोले हैं वहां पर तीसरे माह 20-20 कैंडीडेट्स तैयार होते हैं वे गांवों में जाते हैं और प्रारंभिक उपचार करते हैं और दवाइयां देते हैं। अजमेर जिले में जवाजा कैम्प है। वहां भी यह कार्य चालू है। मैं मंत्री महोदय के सामने कुछ मांगें रखना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में एक सब-सेंटर खोलने के आदेश दिये हैं इसके लिये धन्यवाद।

ब्यावर में प्रसूति गृह के ऑपरेशन थियेटर के लिये आवेदन किया गया था। बलॉक

(श्री उगमराज मेहता)

मर्चेन्ट्स एसोसिएशन की तरफ से आवेदन-पत्र दिया गया था। कम से कम 6 महीने उसको दिये हो गये, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। कृपया इसके आदेश दें ताकि यह कार्य चालू हो जाए। इसके कारण राज्य सरकार पर वित्तीय भार नहीं पड़ने वाला है, हम भवन बनाकर देंगे।

ब्यावर बड़ा शहर है आस-पास के क्षेत्रों से 20-20 मील से मरीज आते हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था नही है, बेड्स की कमी है इसलिये कम से कम 50 शैय्याओं के वार्ड के निर्माण हेतु आज्ञा प्रदान करें जनता वार्ड बनाकर देगी आप केवल आदेश दें। सिटी डिस्पेन्सरी भी खोलने के आदेश दें।

हमारे यहां कुछ पद खाली हैं, बच्चे रोग विशेषज्ञ, जूनियर स्पेशलिस्ट्स, ई.एन.टी. विशेषज्ञ आदि के। गाइनोकोलोजी विभाग में सोनियर सिविल असिस्टेन्ट की पोस्ट क्रियेट की जाए। पाली जिले में बगरी गांव में एक अस्पताल बना कर सरकार को दिया और दो साल का मेन्टीनेन्स खर्चा जमा कराया है, परंतु अभी तक न लेडी डॉक्टर की व्यवस्था है और न स्टॉफ की। इसलिए शीघ्र स्टाफ की नियुक्ति की जाए।

जयपुर फार्मास्यूटीकल वर्क्स के द्वारा सब-स्टेंडर्ड दवाइयां सप्लाई हुई हैं। इसकी लेबोरेट्री रिपोर्ट्स भी हैं फिर भी विभाग ने भुगतान भी कर दिया। मेरी समझ में नहीं आता, यह भुगतान कैसे हुआ? इसकी जांच करायें, विटामिन टेबलेट्स सप्लाई की गई थीं। इसी प्रकार ए. पी. सी. व एसप्रिन टेबलेट्स सप्लाई न करके पाउडर सप्लाई किया इसकी भी जांच करें।

इस साल जो टेन्डर से कान्ट्रेक्ट हुआ है उसे बुखार की गोलियां 4.41 रु. प्रति हजार के हिसाब से सप्लाई करने का ठेका दिया है। वह सप्लाई करने वाला नहीं है। अगर सप्लाई नहीं करें तो उस कंपनी को ब्लेक लिस्ट किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, आलोक इन्डस्ट्रीज रतलाम ने गत वर्ष 25 हजार ग्लूकोज GNS बोतलें सप्लाई की थीं उसने 12 हजार बोतल की सप्लाई करने का पेमेन्ट ही पहले उठा लिया। अध्यक्ष महोदय, उस व्यक्ति ने सप्लाई तो की नहीं और पेमेन्ट हमारे ब्यावर से उठा लिया। अध्यक्ष महोदय, उसने ग्लूकोज का सब-स्टेण्डर्ड माल सप्लाई किया। बाद में बोतलों में जाले पाये गये और उसमें मकड़ी भी पाई गयी। अध्यक्ष महोदय, 25 हजार ग्लूकोज की बोतल का रेट कान्ट्रेक्ट था। उस व्यक्ति ने सप्लाई 2 लाख बोतल की। इस प्रकार लाखों रुपये का फायदा उठाया। जो बिलकुल नाजायज था। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस सारे घोटाले की जांच करावें और दोषी व्यक्ति के खिलाफ में कार्यवाही करें। अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति पैसा ले गया उसका नाम है बन्शीलाल गांधी। वह रतलाम में यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था। मैं यह सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि ग्लूकोज की इस प्रकार की बोतलें उसने सप्लाई की जिनमें जाले थे और मकड़ी जैसे खतरनाक जीव भी थे। इसके अलावा मैं आपको, अध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वह व्यक्ति अब और इस

(श्री उगमराज मेहता)

प्रकार के बड़े आर्डर मेडिकल डिपार्टमेंट से लेने के लिये दौड़ रहा है। कहीं ऐसा नहीं हो कि वही व्यक्ति और कोई आदेश ले जावे और खराब दवाइयां दे दे जिससे कि जनता को नुकसान हो।

श्री मदनसिंह दांता : अरे आप तो जाले की कह रहे हो, आपके यहां तो दूध के ड्रम में मरे हुए चूहे मिले हैं।

श्री उगमराज मेहता : इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर बड़ाखेड़ा एक जगह है, उसकी अच्छी आबादी है। डॉक्टर के लिये आदेश भी दे दिये गये हैं, राज्य सरकार द्वारा, अध्यक्ष महोदय, लेकिन अभी तक वहां पर डॉक्टर पहुंचा नहीं है जिससे वहां की जनता को भारी नुकसान हो रहा है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी मंत्री महोदय, वहां डॉक्टर भेजें।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर टाड़गढ़ क्षेत्र है। अस्पताल के लिये वहां की जनता अपने पैसों से भवन बनाने को तैयार है। वहां के अस्पताल में आपने डॉक्टर की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की है। अगर आप वहां पर डॉक्टर भेज दें तो गांवों की जनता को राहत मिल सकती है। इसके अलावा वहां पर एक लेडी डॉक्टर की पोस्ट है लेकिन अभी तक कोई लेडी डॉक्टर आपने नहीं भेजी। अगर आप वहां पर लेडी डाक्टर भेज दें तो उसके आस-पास के गांवों की जनता को काफी राहत मिल सकती है। इस ओर भी राज्य सरकार ध्यान दे। इसके अलावा हमारे यहां पर जवाजा में गत साल पी. एच. सी. सेन्टर आपने खोला है उसके लिये तो मेरा आपको धन्यवाद है लेकिन मेरा निवेदन है कि आप उसे रेफरल अस्पताल बना दें तो जनता को ज्यादा राहत मिलेगी।

बस इतना ही मुझे निवेदन करना है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशचन्द्र शर्मा।

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रतनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आज भी आप पधारे और मुझे बोलने का आपने जो अवसर दिया है उसके लिये तो मैं आपका स्वागत करता हूं।

श्री मदनसिंह दांता : यह आपको कौनसे नम्बर काट कर दिये हैं।

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा : मैं तो यही मानता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सदन में मंत्रिपरिषद् के खर्चों के सम्बन्ध में काफी वाद-विवाद हुआ है। जहां तक सवाल सादगी का है अगर हमारे मंत्री लोग सादगी के साथ रहें तो यह एक बहुत ही अच्छी बात होगी। मंत्रिपरिषद् पर कम खर्चा हो और मंत्री सादगी से रहें तो यह अच्छी प्रवृत्ति होगी। अगर अभी से हमारे मंत्रिपरिषद ने कम खर्चे की प्रवृत्ति अपनाने की शुरुआत नहीं की तो, अध्यक्ष महोदय, आने वाला युग ऐसा आ रहा है कि हमें जनता जबरदस्ती ही कम खर्चे के लिये बाध्य करेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि आज से ही हमारे मंत्रिपरिषद् के सदस्यों को चाहिये कि सादगी की ओर बढ़े।

(श्री जगदीशचन्द्र शर्मा)

आज, अध्यक्ष महोदय, सदन में कई सदस्यों ने हमारे मंत्रियों के रहने-सहने के बारे में कहा । मैं भी निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आज जो सचिवालय में एअरकण्डीशन की व्यवस्था हो रही है उसे गर्म-ठण्डा करने के लिये, वह बात बिलकुल ही गलत है। अगर आप यह कहते हैं कि उसमें 17-18 लाख रुपये खर्च हो गये हैं तो कोई बात नहीं। आप उसे बन्द कर दें। नहीं तो यह जनता में एक चर्चा का विषय बन जायेगा और जनता हमें टोकेगी ।

दूसरा मेरा सुझाव है कि जनता पार्टी के मंत्रिपरिषद् को सादगी के साथ रहने के लिये गलीचे दफ्तरों एवं घरों में न बिछावें। यह जो सामन्ती रहन-सहन का ढंग है इसे समाप्त किया जाना चाहिये । अगर आप यह नहीं करेंगे तो आप जनता से बहुत दूर हो जायेंगे । यह रईसों की तरह रहने वाली आपकी जिन्दगी एक छूत की बीमारी की तरह होगी । आप जनता की समस्याओं से दूर हो जायेंगे और आपको जनता आदर की दृष्टि से नहीं देखेगी । इसलिये मेरा यह निवेदन है कि आप इस अनावश्यक खर्च को समाप्त करें । मैं इसका हामी नहीं हूं कि हमारे मन्त्री लोग एशो आराम से रहें। आप चाहे टेलीफोन का प्रयोग करें अधिक से अधिक चाहे कारों को प्रयोग में लें पर काम के लिये लें। आप कहीं दूरदराज बैठे हैं या आपको कहीं दूरदराज जनता के काम से जाना हो तो आप कार अधिक से अधिक काम में लें तो उचित होगा, जनता के काम के लिये अधिक व्यय होता है तो कोई बात नहीं। इसके लिये चाहे जनता आपकी आलोचना भी करे तो भी आप फिक्र नहीं करें। अगर आप बेकार ही उनका प्रयोग कर रहे हैं तो वह अनुचित है ।

इसके साथ-साथ में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी नागरिक अपनी समस्या के लिये अर्जी देता है तो आप वाजिब मांग का उसको जवाब जरूर दें। हमारी सरकार कांग्रेस सरकार की तरह नहीं है, वह जनता की सरकार है । अगर आप जनता की वाजिब बात को सुनते हैं तो इससे आपका मान बढ़ता है । आपको उनकी फरियाद का निराकरण करना चाहिये । आज चाहे हम लोग आपस में बैठ कर लड़ लें, हम आपस में बैठ कर तय कर लेवें, लेकिन नागरिक ने अगर आपको कोई अपनी वाजिब मांग के लिये एप्रोच किया है तो आप उसको अपने हस्ताक्षर से जवाब जरूर दें । इसका मैं आपको अभी एक उदाहरण देता हूं। मैंने हमारे केन्द्र के रेल मन्त्रीजी को पत्र लिखा तो उन्होंने मेरे एक पत्र का दो बार जवाब दिया। एक तो मुझे दिया। दूसरा उस व्यक्ति को भी जवाब दिया, जिसके बारे में मैंने निवेदन किया था। अपने हस्ताक्षर से जवाब दिये, उस ग्रामीण के पास भी उनका पत्र पहुंचा । तो मेरा निवेदन है कि यह बात बिलकुल गलत है कि आप किसी भी पत्र का जवाब नहीं दें। आप मन्त्री हैं, आपके पास लोग अपनी मांग लेकर आते हैं, अपनी फरियाद रखते हैं । आप उनकी वाजिब मांगों का जवाब तक नहीं दें, यह कहां तक उचित है । इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस ओर भविष्य में जरूर ध्यान दें ।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा वह है मेडिकल के बारे में जो मैंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनके बारे में। मैं, अध्यक्ष

(श्री जगदीशचन्द्र शर्मा)

महोदय, आपको बहुत ही विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि आज जितना भ्रष्टाचार मेडिकल विभाग में है उतना भ्रष्टाचार आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा पर मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि आप इस भ्रष्टाचार को समाप्त कर दें। जो आपके मेडिकल डिपार्टमेंट में, डाइरेक्टोरेट का स्वरूप बन गया है उस स्वरूप को आपको बदलना पड़ेगा। मैं आपको यहां जो गड़बड़ियां हैं उसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। सन् 1972 में केन्द्रीय परिवार नियोजन से हमारे परिवार नियोजन केन्द्र राजस्थान में 25 एम्बेसेडर कारें आयीं। वहां से 25 कारों में से 21 कारें हमारे स्टेट के लिये आ गईं। वह एम्बेसेडर कारें सन् 71 में इन्दिरा गान्धी के इलेक्शन में काम में ली गयी थीं। जब यहां पर आयीं, तो यहां के यातायात अधिकारी ने लिखा कि ये गाड़िया डिफेक्टिव हैं। बाद में यहां तो उनका उपयोग नहीं हुआ लेकिन उन 25 कारों में से 21 कारें यहां से भेज दी गयीं। यहां पर जो यातायात अधिकारी था उसको यह लिखने के लिये, कि गाड़ियां खराब हैं, पद से हटा दिया गया। उस समय केन्द्र में स्वास्थ्य, यातायात का जो डिप्टी कन्ट्रोलर था उसे सारी फोर्मेलिटी त्याग कर केवल एक प्रार्थना-पत्र ही राजस्थान का स्वास्थ्य यातायात अधिकारी बना दिया गया। सारे मामले की जांच की जानी चाहिये। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। अध्यक्ष महोदय, 25 एम्बेसेडर कारें हमारे यहां रहनी चाहिये थीं वह भी यहां नहीं रख कर सिर्फ चार एम्बेसेडर ही रखी गयीं। 25 में से 21 वापस भेज दी गयीं। आज तक उन 21 एम्बेसेडर कारों को यहां वापस नहीं भेजा गया है। मेरा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार से 21 एम्बेसेडर कारें तुरन्त वापस मंगवायी जायें ताकि वह कारें हमारे यहां परिवार कल्याण केन्द्रों में काम आवें। इस बड़े घोटाले की पूरी जांच करें।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर कितनी एक्स-रे मशीनें राजस्थान में हैं, इसका हमारे मेडिकल डाइरेक्टोरेट में कोई हिसाब-किताब नहीं है। अगर आप आज एक प्रश्न इसके बारे में पूछ लें तो, अध्यक्ष महोदय, मेडिकल डाइरेक्टर इसकी कोई जानकारी नहीं दे सकता है। प्रति वर्ष एक्सरे मशीनें खरीदी जाती हैं। पता नहीं उनका क्या होता है। मेडिकल डिपार्टमेंट को कोई जानकारी नहीं है कि वह कहां-कहां हैं कितनी हैं, कहां-कहां खराब हैं, कहां-कहां काम आ रही हैं या नहीं। हर साल लाखों रुपये की मशीनरी जनता के पैसों की खरीदी जाती है पर इसमें, अध्यक्ष महोदय, लाखों रुपयों की गड़बड़ी है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा पर इतना कह सकता हूं कि लाखों का भ्रष्टाचार हर साल दवाइयों और मशीनों की खरीद में होता है पर कोई जांच नहीं होती है।

इसी तरह ड्रग्स मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेन्स के अन्तर्गत पर्चेजेज होते हैं उसमें घटिया किस्म की दवाइयां सब-स्टेण्डर्ड की खरीद ली जाती हैं। ऐसी दवाइयां खरीदी जाती हैं जो कि सब-स्टेण्डर्ड हैं। पता नहीं किसकी साजिश से यह दवाइयां सब-स्टेण्डर्ड की खरीदी जा रही हैं? इससे जनता को बहुत भारी खतरा होता है पर कोई भी चेक नहीं किया जाता है। आज आप एलोपैथी की दवाइयों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेज रहे हैं और लोगों को वह दवाइयां दी जा रही हैं जो गरीबों

( श्री जगदीशचन्द्र शर्मा )

को देने को दवाइयां बांट रहे हैं वे बाजार में बिक रही हैं पर इस पर कोई रोक नहीं हो रही है राजस्थान दवा निर्माताओं द्वारा आई. पी., बी.पी., यू.एस.पी. स्टेण्डर्ड के अनुसार दवा नहीं बन रही है। नव शल्य चिकित्सा उद्योग से लाखों रुपयों की गाज, पट्टियां खरीदी गई हैं जबकि स्टोर पर्चेज रूल्स के अनुसार फर्म को ड्रग मेन्युफेक्चरिंग लाइसेन्स के अन्तर्गत दर्ज होना आवश्यक होता है। घोटाले की जांच करें। मेरा निवदन है कि सब-स्टेण्डर्ड दवाइयों की जो खरीद की गयी है उसके लिये दोषी अधिकारियों को दण्ड दिया जाय और भविष्य में सब-स्टेण्डर्ड की दवाइयां नहीं खरीदने के लिये आदेश दिये जायं।

इसके अलावा मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक खास और मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। आज भी मेडिकल डिपार्टमेंट में ऐसे-ऐसे शूरवीर बैठे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा पर एक व्यक्ति ने मेडिकल डाइरेक्टोरेट से फर्जी बिल का भुगतान ले लिया। बाद में डिप्टी डाइरेक्टर ने उसकी जांच की पर उस जांच के बाद भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। जो जांच की फाइल थी वह फाइल ही आफिस से गायब हो गयी। किसी फाइल में किसी ने कोई चेन्ज कर दी तो उसको सस्पेन्ड कर दिया गया था। 1967-68 के ऐसे मामले असेम्बली में भी आये हैं। लेकिन वह व्यक्ति आज भी डाइरेक्टोरेट में बैठा हुआ है। उसके ऊपर अंकुश मेडिकल डिपार्टमेंट के डाइरेक्टर और उच्चाधिकारियों का भी नहीं है। मैं बहुत नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं जैसी कि मुझे सूचना दी गई है, राजस्थान के मेडिकल एण्ड हैल्थ सेक्रेटरी और वर्तमान निदेशक ईमानदार व्यक्ति हैं। आश्चर्य है, फिर भी ये गड़बड़ियां दूर क्यों नहीं हो रही हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

घंटी मत बजाइये आप। मैं तो हुकम मानने वाले व्यक्तियों में से हूं।

चूरू जिले में डूंगरगढ़ में डॉक्टर नहीं है, छापर में डॉक्टर नहीं है। चूरू जिले का मुख्यालय है डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर, वहां पर एक भी लेडी डाक्टर नहीं है। इतनी धीमी व्यवस्था चली आ रही है फिर भी राजस्थान सरकार में भी कोई इस ओर ध्यान देने वाला मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। रतनगढ़ में हरियाणा और दूर-दूर के लोग आकर आपरेशन कराना चाहते हैं लेकिन आज तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस मायने में इस जिले को हमेशा मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा नेगलेक्ट किया जाता रहा है। रतनगढ़ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में 100 बेड्स भी नहीं हैं। इसलिये सीनियर स्पेशलिस्ट की पोस्ट बढ़ायी जाय और जिन जगहों पर डाक्टर्स और कम्पाउन्डर्स नहीं हैं वहां उनको भेजने की व्यवस्था फौरन कराई जाय। बादासर एक कस्बा है। 1½–2 लाख रुपये का हॉस्पिटल बनाया हुआ है वहां भी व्यवस्था कराने की कृपा करें।

इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं। आपने मुझे समय दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनसिंह भाटी।

( अनुपस्थित )

(श्री अध्यक्ष)

श्री रामकिशोर मीणा !

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) !

(अनुपस्थित)

श्री हजारीमल सारण !

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल !

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान मंत्रिपरिषद् का गठन इतने महीने के बाद भी अभी तक पूरा नहीं हो सका है। मंत्रिमंडल का गठन पूरा हो यह जरूरी बात है। मुख्य मंत्रीजी बार-बार कहते रहे हैं, पिछले दिनों कहा कि 20 तारीख के बाद और मंत्री बढ़ा दिये जावेंगे लेकिन अभी तक भी अनिश्चितता है। जब तक अनिश्चितता बनी रहती है तब तक इसको मंत्रिपरिषद् का गठन नहीं कह सकते। मंत्रिपरिषद् में अलग-अलग जिलों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये वह नहीं हुआ है। इससे लोगों में बड़ी आशंका है। जोधपुर डिविजन और उससे मिले हुए दूसरे डिविजन हैं, जिसे मरुप्रदेश कहा जाता है, उस ओर का कोई भी प्रतिनिधि मंत्रिपरिषद् में नहीं है। मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि 20 तारीख के बाद मंत्री लूंगा लेकिन आज तक किसी को लिया नहीं। लोगों में यह भावना बढ़ती जा रही है कि उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। जहां कहीं का प्रतिनिधित्व नहीं होता है उस इलाके की बात को मंत्रिपरिषद् में कोई कहने वाला होना चाहिये। जब तक नहीं होगा तब तक उस इलाके को रिप्रजेन्ट नहीं किया जा सकेगा। आप किसको लें यह आपके अधिकार क्षेत्र की बात है। लेकिन मंत्रिमंडल में हर इलाके का प्रतिनिधित्व होना अवश्य चाहिये जिससे मंत्रिपरिषद् के गठन का कार्य पूरा हो सके। एक का विभाग दूसरे को दे दिया, यह बात भी समाप्त होनी चाहिये ताकि मंत्रिपरिषद् ठीक प्रकार से काम कर सके।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक खर्चे का प्रश्न है मंत्रिमंडल में काम करने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ा उसका एक उत्तरदायित्व होता है जिसको उसको निभाना पड़ता है। आज उत्तरदायित्व उनका बढ़ भी रहा है। प्रश्न यह है कि सरकारी चीजों का उपयोग, जैसे वाहन का उपयोग सरकारी काम करते हुए हो, सरकारी काम के लिये ही उपयोग हो और व्यक्तिगत काम के लिये उसका उपयोग न हो। व्यक्तिगत काम के लिये उसको काम में न लें। यह वाजिब बात है कि सरकारी काम के लिये काम में लिया जाना चाहिये। जल्दी का काम हो तो उसका उपयोग होना भी चाहिये। लेकिन यदि वाहन व्यक्तिगत काम में आ रहा है और परिवार वाले बैठे फिर रहे हैं तो यह कहा जायेगा की सरकारी वाहन का दुरुपयोग हो रहा है। इसका अनुसरण फिर सरकारी अधिकारी भी करेंगे। आज कर भी रहे हैं। किसी भी सिनेमा हाल के बाहर देख लीजिये, कहीं और देख लीजिये, जगह-जगह डिपार्टमेंट की गाड़ियां मिलेंगी। इनमें परिवार के लोग बैठकर इधर–उधर फालतू फिरते हैं और इस प्रकार पेट्रोल खर्च करते हैं और वाहन का दुरुपयोग करते हैं। सरकारी काम के अलावा इस प्रकार से वाहन काम में लिया जाना फालतू खर्चा है और दुरुपयोग तो है ही। यदि टेलीफोन

(श्री शंकरलाल)

करते हैं सरकारी काम से तो उसके लिये सरकार से पैसा लें और व्यक्तिगत काम से टेलीफोन करते हैं तो सरकार से पैसा न लें। इस प्रकार की यदि व्यवस्था की गयी तो उपयुक्त होगी। खर्चे में कटौती कर दी जाय और सरकारी काम पूरा न हो और शिथिलता से काम हो, इसको मैं पसन्द नहीं करता। इसलिये निवेदन करूंगा कि आप इस तरह की सादगी का व्यवहार रखें जिससे फालतू खर्चे में कमी हो और सरकारी कार्य समय पर पूरा हो।

तीसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्रिमंडल के गठन के बाद केन्द्रीय सरकार और दूसरी जगह हरएक मंत्री से संबंधित कन्सल्टेटिव कमेटी बनायी जाती है। यह लोकतान्त्रिक चीज है। आपने वह भी नहीं बनायी। इसलिये आप हर विभाग की एक कन्सल्टेटिव कमेटी बनायें। दो एम. एल. एज. हों उसमें। पहले भी यह परम्परा थी। उसके बन जाने से मंत्रिमंडल का काम हलका हो जायगा। यह सुझाव देना चाहता हूं।

इसके अलावा आप जब भी दौरे पर जायं तो हरएक विधायक को सूचना दें। उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने भी यह बात कही है। उनका उदाहरण नहीं दूंगा। ऐसा महसूस होने लगा है कि जनता पार्टी का शासन आने के बाद जहां कांग्रेस के विधायक की कान्स्टीट्यूएन्सी है उसमें जितने मंत्री आते हैं उसकी सूचना नहीं मिलती। मुझे नहीं मिली है जब कि दूसरे विधायकों को उसकी सूचना मिली है। इस प्रकार से आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के साथ खिलवाड़ करते हैं।

मेजर श्री फतह सिंह : कांग्रेस के शासन काल में भी मुझे विधायक रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं यह कह सकता हूं कि मुझे किसी मंत्री ने कभी इत्तला नहीं दी।

श्री शंकरलाल : कोई भी हो। किसी ने भी गलती की हो। कांग्रेस के शासन में भी गलती हुई होगी लेकिन आज जहां का कोई भी प्रतिनिधि है, जिसको जनता ने चुना है, जो समस्या रख सकता है उसको जरूर इत्तला मिलनी चाहिये। उसको इत्तला दें। मुझे इस बात की खुशी है, और मैं इससे इन्कार नहीं करता हूं कि मुख्य मंत्रीजी को जितने भी मैंने पत्र लिखे बराबर उन्होंने मुझे जवाब दिया है और अपने हस्ताक्षर से दिया है। लेकिन राज्य मंत्री जवाब नहीं देते हैं। उनके पी.ए. से जवाब आता है। यह परम्परा अच्छी नहीं है। आपको पत्र लिखा मुख्यमंत्री जी, तो आप हस्ताक्षर से जवाब दें और आपके मंत्री लोग जवाब न दें, यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है। एम.एल.ए. को शिकायत हो या और कहीं से किसी की शिकायत आवे तो आपको उसको जवाब तो देना चाहिये जिससे उसे अहसास हो कि मंत्रिपरिषद् काम करती है।

मेरा निवेदन यह भी है कि मंत्रिपरिषद् की बैठक डिविजनल लेवल पर होगी, यह घोषणा की गयी थी लेकिन कोटा में ही एक बैठक होकर रह गयी। इसका क्या कारण है? क्या राजस्थान में और डिविजन नहीं हैं? केवल कोटा ही....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक डिविजन है? दूसरे डिविजन में भी मंत्रिपरिषद् की बैठकें करते तो ज्यादा अच्छा था। यह मैं निवेदन कर रहा हूं कि मंत्रिमण्डल

(श्री शंकरलाल)

में एक तो अलग-अलग नीतियों की बातें हैं। यह घटकवाद जब तक कायम रहेगा तब तक आपकी मंत्रिपरिषद् अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता। एक मंत्री कुछ कह दे और दूसरा कुछ कह दे, आप इसका कुछ उपाय करें। राजस्थान के हर डिविजन के लिए एक प्रकार की नीति अपनायेंगे तो आपकी मंत्रिपरिषद ठीक तरह से काम कर सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा के संबंध में क्योंकि आपकी घंटी हुई है केवल सुझाव दूंगा, भाषण के रूप में नहीं कहूंगा। एक तो निवेदन यह है कि चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए जो बातें कही गयी हैं उनमें जो मोबाइल सर्जिकल यूनिट्स हैं वह बहुत अच्छे साबित हुए हैं। राजस्थान के अन्दर मोबाइल सर्जिकल यूनिट्स की संख्या को बढ़ाया जाये जिससे कि गांवों के अन्दर जाकर ऑपरेशन, देख-रेख और पूरी चिकित्सा करें। उनकी संख्या बढ़ायें। वह गांवों में जायेंगे तो उससे काफी लोगों को फायदा हो सकता है।

दूसरे परिवार नियोजन को आप भी मानते हैं कि जरूरी है। यह बात दूसरी है कि ज्यादतियां हुईं लेकिन मेरे एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि जहां पहले एक साल में 3।। लाख ऑपरेशन हुए थे वहां लोगों ने इस साल सिर्फ 10 हजार ऑपरेशन ही कराये। हमारे राष्ट्रपति महामहिम नीलम संजीव रेड्डी कहते हैं कि इसके बारे में कानून बनाना चाहिए। राज्य सरकार इसके ऊपर विचार करें। जब तक आप इसका कानून नहीं बनायेंगे तब तक आपके परिवार नियोजन का कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। यह आबादी बढ़कर आपके लिए सिर-दर्द हो ही जायेगी। आगे जाकर हमें दिक्कत उठानी पड़ेगी। जबरदस्ती नहीं है, लेकिन कानून आप बनायें।

इसके अलावा निवेदन करना चाहता था कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अस्पताल हैं उनमें कमियां हैं। मैं चिकित्सा मंत्रीजी से खास करके निवेदन करना चाहूंगा कि आप हर हॉस्पिटल से संबंधित एक एडवाइजरी कमेटी बना दें। पहले भी डिस्ट्रिक्ट कमेटीज होती थीं। पाली जिले में जैसे अस्पताल हैं उसके लिये वहां के नागरिकों की एक समिति हो। उसमें वहां की नगरपालिका के चुने हुए आदमी और दूसरे लोग हों तो थोड़ा-सा अंकुश रह सकता है। वहां के डाक्टर रिश्वत नहीं लें, भ्रष्टाचार नहीं हो और गरीब को किसी प्रकार की यातनायें न हों। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हॉस्पिटल की एक एडवाइजरी कमेटी हो जिसमें चुने हुए आदमी हों। एड-पोस्ट हो, गांवों के सरपंच हों। पंचायत समिति लेवल पर प्रधान हो। जब तक यह कमेटी नहीं होगी तब तक भ्रष्टाचार केवल एक डिपार्टमेंट मिटाने में असमर्थ रहेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। हमारे राष्ट्रपतिजी जब स्वयं पाली पधारे और सुमेरपुर में प्रोग्राम हुआ तो उन्होंने कहा कि जो स्वास्थ्य रक्षक की योजना है, अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि यह योजना सफल होने वाली नहीं है। श्री राजनारायणजी के दिमाग की उपज कभी सफल होने वाली नहीं है। यह खिलवाड़ है। एक आदमी दो-तीन महीने ट्रेनिंग पाकर लोगों का उपचार करने

(श्री शंकरलाल)

का पार्ट-टाइम काम करे, तो यह कोई पार्ट-टाइम का काम थोड़े ही है। यह तो नीम हकीम वाली बात हो गयी। इससे तो आप लोगों को मारेंगे। गांव वालों को इससे नुकसान होगा। इसलिए आप इसको एग्जामिन कीजिए। केन्द्रीय सरकार के सामने स्पष्ट बात रखें कि जो स्वास्थ्य रक्षक की योजना है यह बिलकुल गलत योजना है। इससे तो अच्छा यह होगा कि आयुर्वेद को आप प्रोत्साहन दें। स्वास्थ्य रक्षक की योजना बिलकुल गलत है। इससे आपका कोई भला होने वाला नहीं है। यह हमारे लिए बहुत ही नुकसान-दायक है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक शिकायत के रूप में मंत्रीजी को कहना चाहूंगा, वह हैं नहीं, मैंने डाक्टरों के भ्रष्टाचार की शिकायत बड़ी स्पेसिफिक की थी। अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव भी था एक बलात्कार के मामले में। 12-11-77 को वह मामला पाली जिले के तखतगढ़ हॉस्पिटल में गया तो बिना पैसे उसका मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ। दूसरी पार्टी वाले पहुंच गये और डॉक्टर को मना कर दिया। उसके बाद दूसरी जगह के डॉक्टर ने मना कर दिया क्योंकि फैक्ट्री वाले आदमी स्वयं वहां पहुंच गये और तीसरी जगह भी पहुंच गये वहां भी मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ। तीन जगह जाने के बाद चौथे दिन पाली में मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। 12 तारीख का मामला था और 14 तारीख को मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ इस मामले में तीनों डॉक्टरों की आप इन्क्वायरी करायें। मैं चार्ज लगाता हूं कि डॉक्टर लोग पैसा लेकर झूठा सर्टीफिकेट दे देते हैं और पैसा नहीं देते हैं तो सर्टीफिकेट भी नहीं देते हैं। इसलिए तीनों डॉक्टरों की आप जांच करायें।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक निवेदन नहीं करना चाहता हूं। आपकी जो योजना पंचायत समितियों में एड-पोस्ट खोलने की है और एक डिस्पेन्सरी खोलने की है उसकी संख्या और बढ़ायें। मेरे जैतारण क्षेत्र में एक एड-पोस्ट है उसकी जगह मैंने दो नाम दिये हैं मोहराई और निम्बोला वहां एड-पोस्ट और खोलें।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

(अनुपस्थित)

श्री रामरघुनाथ!

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अभी सुना होगा कि मंत्रिमण्डल के लिए, और मंत्रि-मण्डल के सदस्यों की सुख-सुविधा के लिए कुछ अधिक धनराशि इस वर्ष उपलब्ध कराई गई है। माननीय सदस्य श्री कौशल किशोरजी यह बता रहे थे कम्पेरेटिव स्टेटमेंट के साथ में कि किस तरह से खर्च के लिए इस बार धन की वृद्धि की गयी है और अधिक मांग की गयी है। तो मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्रि-मण्डल के सदस्यों की सुख सुविधाओं का भी ध्यान होना चाहिए, जनता पार्टी नयी-नयी आई है और नये-नये मंत्री बने हैं इसलिए उनकी आवश्यकतायें भी अधिक होंगी, वह आराम से रहें लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस सुख-सुविधा के साथ में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की चिन्ता भी करें और जब उनकी सुख सुविधाओं

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

की चिन्ता न करें तो चिकित्सा की चिन्ता मुख्य तौर से करने की है ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। हमारी राजस्थानी में व हिन्दी में भी एक कहावत है कि "पहलो सुख निरोगी काया"। इसलिए अगर आदमी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। बाकी सुख-सुविधायें तो आप रखिये और चिकित्सा के लिए आप उपाय करें और चिन्ता करके उन ग्रामीण लोगों के लिए दवाइयां उपलब्ध करायें।

अभी माननीय सदस्य श्री शंकरलालजी भी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बात रहे थे कि आपने स्वास्थ्य रक्षक के नाम से एक नयी योजना लागू की है और उसके अन्तर्गत 500 रुपये की दवायें उपलब्ध करायेंगे और 600 रुपये सालाना यानि 50 रुपये प्रति माह के हिसाब से किसी एक व्यक्ति को पार्ट-टाइम जॉब देंगे। मैं यह निवेदन करूंगा कि उस आदमी को आप कैसे बाध्य कर सकते हैं पार्ट-टाइम जॉब देकर कि उसको कहीं जाना हो तो नहीं जाये? घर के काम के लिए या काश्त के काम के लिए कहीं खेत में जाना है तो नहीं जायें। जब वह आदमी अपने दूसरे कामों के लिए बाहर जा सकता है, अपनी काश्त के लिए जा सकता है, अपने व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए जा सकता है तो वह आपको गांव में उपलब्ध ही नहीं होगा। उसके आने-जाने के समय को देखकर और काम को देखकर तो बीमारी आयेगी नहीं, बीमारी किसी समय भी आ सकती है, वह आदमी उपलब्ध नहीं है तो फिर लोगों को चिकित्सा सहायता कैसे मिलेगी? मैं निवेदन करना चाहूंगा आपको कि इस चिकित्सा के तहत इस डिपार्टमेंट के तहत गांवों में मलेरिया और चेचक के लिए इन्सपेक्टर व जो अन्य कर्मचारी लगे हुए हैं, आपने यह क्यों नहीं सोचा कि यह जॉब उनको दे दिया जाये। उनकी संख्या बढ़ा दी जाये। उनकी ट्रेनिंग ज्यादा लम्बे समय की होती है। इस बारे में वह अधिक जानते हैं और वह ज्यादा जिम्मेदारी से इस काम को चला सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो आपने स्वास्थ्य रक्षक के नाम से योजना बनाई है इस पर आप पुनर्विचार करें और अधिक से अधिक ग्रामीण लोगों को लाभ हो ऐसा रूप इसको दें।

मैं इसके साथ ही निवेदन करना चाहूंगा, स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने यह घोषणा की कि हर पंचायत समिति क्षेत्र में यहा कान्स्टीट्युएन्सी में एक हॉस्पिटल और एक डिस्पेन्सरी हो और दो एड-पोस्ट हों। चिकित्सा हेतु जितने भी चिकित्सालय खोलें, ठीक है। लेकिन इसके साथ उन लोगों को, डॉक्टरों को इस तरह के आदेश दिये जायें या ऐसी व्यवस्था की जाये कि डॉक्टर लोग, महीने में कम से कम एक बार गांवों में जा कर कुछ घण्टे वहां ठहर कर गांव वाले लोगों का इलाज करें। शहर में रहने वाले आदमी और शहर के आस-पास रहने वाले आदमी को स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिये मील, दो मील पर चिकित्सा उपलब्ध हो और गांव में रहने वाले आदमी को 12-12 मील तक दवाई मिलने की सुविधा नहीं, यह सौतेला व्यवहार क्यों? इस योजना को इस तरह का स्वरूप दिया जाये, उनको इस तरह के आदेश दिये जायें, वैसे तो मैं कहूंगा कि सप्ताह में एक बार, मगर कम से कम माह में एक बार हर गांव को जाया करें, सारे गांव वालों को देखें व इलाज करें ताकि उन ग्राम वालों को 10-10 और 12-12 मील तक भागते न रहना पड़े। एक डॉक्टर होता है

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

और वह भी अपनी प्राइवेट प्रेक्टिस के चक्कर में या किसी और चक्कर में होता है, समय पर मिलता नहीं है। गांव से आये हुए एक बीमार को दिन भर लग जाता है। उसको अपनी एक दिन की मजदूरी खोनी पड़ती है। एक बीमार आया, उसके साथ देखभाल हेतु एक अन्य आदमी आया, वह कैसे इलाज कराये। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। उसको पांच रुपये मजदूरी मिलती है तो उस दिन की मजदूरी गई। उसके साथ आया एक आदमी उसकी मजदूरी गई। 10) रुपये रोज के और दो दिन लगाये तो 20) रुपये हो गये। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस तरह की योजना बनाई जाये जिससे अधिक से अधिक चिकित्सा की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र के लिये की जाये। मैं साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि नागौर जिले में इतना बड़ा अस्पताल है, वहां 200 मरीजों की शैया हैं। वहां पर लेडी डॉक्टर नहीं है। इतना बड़ा जिला, चार सब-डिविजन्स और जिले के एक हॉस्पटल में लेडी डॉक्टर नहीं। सुना है नागौर से उसकी पोस्ट हटा कर दूसरी जगह लगा दी। अगर लेडी डॉक्टर नहीं हो, तो जिन महिलाओं को विशेष बीमारी है, वह किसे कन्सल्ट करें, किसके पास जायें। जिले में एक भी लेडी डॉक्टर नहीं, यह बड़ी शोचनीय स्थिति है। इस पर विचार करके इस कमी को पूरा किया जाये। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा दांतों के संबंध में। यहां आगे भी यह बात कही गई। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एस. एम. एस. पुराना अस्पताल है। दांतों के लिये दो-तीन चिकित्सक हैं। उन लोगों को दांत बनाने तक की सुविधा नहीं। इसका मतलब कोई आदमी डॉक्टर के पास जाये, दांत को निकलवा सकता है, ईलाज हो सकता है, परन्तु दांत निकलने के बाद क्या करे। खाना खा नहीं सकता। दांत कहां बनवाये? प्राइवेट डॉक्टर से दांत बनवाओ या सड़क छाप क्वेक्स लोग होते हैं उनके पास जाओ। पैसे वाले कहीं भी जायें गरीब आदमी कहां जायेगा। मेरी एक दांतों के डॉक्टर से बात हुई थी, कहते हैं हमारे पास दांत बनाने का मैटिरियल नहीं है। हमने जो ट्रेनिंग ली है, पढ़ाई की है, कुछ भी कर नहीं सकते, हमारे पास साधन उपलब्ध नहीं हैं। कुछ दिनों बाद इस विद्या में अभ्यस्थ नहीं रहेंगे। अतः जहां-जहां आपकी डेन्टल सुविधायें हैं उनको मैटिरियल उपलब्ध कराइये। ताकि दांत उखड़ाने के बाद दांत बना कर दे सकें।

एक-दो मिनट और लूंगा। पागल कुत्ते के काटने की समस्या एक अलग समस्या है। पागल कुत्ते के काटने के बाद 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। शहर में कुत्ते कम मिलेंगे। म्युनिसिपेलिटी वाले पकड़ कर ले जाते हैं। देहात में कुत्ते बहुत हैं। किसी को काट ले तो वहां इलाज हो नहीं सकता। लाजमी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर अगर उपलब्ध हो तो वरना किसी बड़े शहर में जाकर 14 दिन ठहर कर इन्जेक्शन लगवाने पड़ेंगे। वहां रहना बहुत मुश्किल होता है, विशेष कर जिनकी आर्थिक हालत खराब है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, जहां प्राइमरी हेल्थ सेन्टर हैं वहां इन्जेक्शन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करिये। मैं सिर्फ दो चीजें और निवेदन करना चाहूंगा। मोबाइल सर्जिकल यूनिट्स को ग्रामीण क्षेत्रों तक और अधिक मात्रा में बढ़ायें ताकि इसका

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

उपयोग ग्रामीणों को अधिक से अधिक मिल सके।

इसके अलावा आयुर्वेद के लिये निवेदन करना चाहता हूं। जाखेड़ा में बहुत बड़ा विशाल भवन बना हुआ है, पर वहां 'बी' ग्रेड का औषधालय है। आस-पास कहीं चिकित्सा की सुविधा नहीं है। अतः उसको क्रमोन्नत कर 'ए' ग्रेड किया जाये।

एक घटना की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां पर जालसू नामक गांव में फरवरी, मार्च, 1977 से औषधालय चल रहा था। उसके बाद राज्य सरकार से इस वर्ष फरवरी, 1978 में एक आदेश मिला, मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक और औषधालय खोल दिया गया है। बाद में मालूम पड़ा कि जहां पहले औषधालय खोला था उसी को वहां से हटाकर नई जगह खोल दिया है और उसी औषधालय को जालसू रेलवे स्टेशन कर दिया जो स्टेशन मात्र है तथा मुश्किल से 100 जनसंख्या है और जहां पहले किया था उसकी जनसंख्या 2 हजार के करीब है। मुझे यह मामला समझ में नहीं आया। माननीय अध्यक्ष महोदय, पता नहीं यह कौनसी ईमानदारी या फिर भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है या क्या कहा जाये इस मनमानी को।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपकी मार्फत मंत्री महोदय से, क्योंकि मंत्री महोदय उपस्थित नहीं हैं, कोई न कोई मंत्री महोदय नोट कर रहे होंगे, निवेदन करूंगा कि इस औषधालय को बदल कर वापस वहीं करिये जहां बड़ा गांव है व अधिक लाभ मिल सकता है इस तरह के आदेश न हों तो ज्यादा उचित होगा सरकार के लिये। इस बार सत्ता में आये हैं पर अगर जनता के लिये और साधन उपलब्ध नहीं किए और पानी-बिजली के साधन नहीं जुटाए तो 5 साल बाद आप उधर नहीं बैठोगे, इधर बैठोगे।

मैं इतना ही कह सकता हूं।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई !

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : मैंने मंत्रिपरिषद् और चिकित्सा के संबंध में कटौती प्रस्ताव दिये हैं। मैं चाहूंगा कि पहले मंत्रिपरिषद् के संबंध में कुछ विचार रखूं।

अध्यक्षजी, मंत्री का पद सबसे ऐश का पद है। मंत्री या तो ऐश कर लें, पद का दुरुपयोग करें या एक समाज के सामने, पार्टी के सामने बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 30 सालों के अन्दर कांग्रेस के पीरियड में अच्छे नेता पैदा हुए, कुछ खराब भी थे लेकिन जिन आदमियों ने अच्छा काम किया जनता के अन्दर उनकी इमेज बढ़ी। मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने ज्यादा खराब काम किया। मैं चाहूंगा कि जनता पार्टी, जो कई वर्षों की मेहनत के बाद, बड़े प्रयत्न के बाद सत्ता में आई है और काफी दौड़-धूप के बाद जनता ने जनता पार्टी को शासन सौंपा है तो जो मंत्रिमण्डल में हैं इनको आदर्श रखना चाहिये। हम आदर्श नहीं रखें और दूसरों को ही कहें, यह नहीं हो सकता है। मंत्री पद अस्थायी पद है लेकिन एक गौरव का पद है, पार्टी की इमेज का प्रश्न

(श्री रामसिंह विश्नोई)

है। इसलिये मंत्री को सही रूप में जनता के सामने उच्च आदर्श रखना चाहिये। मंत्रिमण्डल में आदमियों को उचित स्थान दें, मंत्रियों का अधिकारियों के साथ अच्छा व्यवहार हो, यह सब बातें बहुत महत्व रखती है। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जो मेरे बूते के बाहर हो। आपका एक मंत्री के नाते उत्तरदायित्व है, क्योंकि नई पार्टी शासन में है इसलिये नया आदर्श आपको इस प्रदेश के अन्दर रखना चाहिये। यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं।

दूसरे चिकित्सा के सम्बन्ध में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि पहले बीमारी को गांव की जनता ही नहीं बल्कि शहरी जनता भी देवी प्रकोप या अपने पूर्व कर्मों का फल मानती थी लेकिन आधुनिक जमाने में यह बात साबित हो चुकी है कि जिस हालत में आदमी रहता है, आदमी की जैसी परिस्थिति है खाने-पीने की, रहन-सहन की उसके हिसाब से बीमारी होती है। उसको दूर करने के हजारों तरह के उपाय आज विद्यमान हैं।

अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से जनता को अनेक सुविधायें प्राप्त हैं लेकिन जो शहरों के अन्दर ऊंचे घराने के लोग है या जो समझदार हैं या अपना दिमाग रखने वाले हैं उन्होंने ही राज्य सरकार की सुविधायें प्राप्त की हैं। गांव की ओर राज्य सरकार ने कभी भी ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं देने की वजह सरकार के कोष की कमी थी। गांवों में अनपढ़ लोग हैं। वहां सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्थाएं नहीं हो सकीं और बड़े-बड़े शहर हैं वहां व्यवस्था हो सकी। शहर के लोगों के लिए ही व्यवस्था की गई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता आप कोई बड़ी मशीन एक्स-रे की गांवों में लगायें लेकिन एक छोटी बात है और महत्व का मामला है, जिस प्रकार अपने चिकित्सा विभाग ने चेचक का उन्मूलन किया और हिन्दुस्तान की जनता के सामने एक आदर्श रखा उसी प्रकार मच्छरों को मारने का कोई उपाय कर देते हैं तो जो सबसे भंयकर रोग है मलेरिया का वह दूर हो सकता है। आज हर गरीब के पास रहने को मकान नहीं है, सोने के लिये मच्छरदानी नहीं है। उनको मच्छर तंग करते हैं। दो-तीन महीने हो तंग करते हों तो कोई बात नहीं लेकिन 12 महीने तंग करते हैं और बीमारी फैलाते हैं। मच्छरों को मारने के लिये लाखों-करोड़ों रुपया खर्च करते हैं लेकिन एक भी मच्छर आपकी दवाओं से, डी.डी.टी. से मरता नहीं दिख रहा है, न आपका कोई इस प्रकार का प्रोग्राम है जिससे साबित हो सके कि आप मलेरिया का उन्मूलन करने जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, मच्छर छोटा अवश्य है लेकिन इसको मारने में भी आप नाकामयाब रहे हैं और मलेरिया की रोकथाम नहीं कर सके हैं। आप मलेरिया उन्मूलन पर लाखों-करोड़ों रुपया खर्च करें लेकिन जब तक इस जीव को मारने का उपाय नहीं करेंगे, तब तक बीमारी नहीं हटेगी। मैं समझता हूं जितने डॉक्टर लोग हैं ये भी दवा निर्माताओं से मिले हुये हैं जो यह चाहते हैं कि हमारी दवा बिके, जो दवा डॉक्टर लिखें उसको लोग लेते रहें और लाखों की आमदनी हमारे पास आ जाय। इतना इन्वेन्शन करने के बाद भी इस जीव को नहीं मार सके, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है।

इसके अलावा मैं निवेदन करना

(श्री रामसिंह विश्नोई)

चाहता हूं कि 2-3 दिन पहले मंत्री महोदय ने यह कहा था जहां बड़ी डिस्पेन्सरीज हैं वहाँ लेडी डॉक्टर की व्यवस्था होगी। बिलाड़ा शहर है वहां 30 हजार की आबादी है लेकिन लेडी डॉक्टर की व्यवस्था नहीं की। आपका बजट है या नहीं यह मुझे नहीं मालूम लेकिन वहां लेडी डॉक्टर का अपाइन्टमेंट नहीं किया गया है, वह करें।

मैं यह चाहता हूं जिन गांवों की दूरी 10-15 मील पड़ती है उनमें या तो डिस्पेन्सरी खोलें, एड-पोस्ट खोलें, कोई औषधालय खोलें या फिर कोई होमियोपैथी चिकित्सालय ही खोलें। किसी न किसी तरह की वहां व्यवस्था करें ताकि गांव का आदमी इमीजियेट अपनी आवश्यकता को पूरा कर सके।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा जो करप्शन है हमारे देश में वह राजस्थान में भी है। हर डॉक्टर के लिये नहीं कहता लेकिन जो मेडिकल जूरिस्ट होते हैं वह चोट लगने का सर्टिफिकेट देते हैं। जोधपुर के अन्दर और सारे राजस्थान में जहां-जहां मेडिकल जूरिस्ट की पावर्स हैं वहां मेडिकल जूरिस्ट लाखों की इन्कम करते हैं। इनकी इन्कम का मुकाबला नहीं है। एक-एक आदमी से हजार-हजार पांच-पांच सौ लेते हैं। जिसके लगी होती है उससे लेते हैं और जिसके नहीं लगी होती है, उससे भी पैसे लेते हैं। जो लोग इसमें लगे हुये हैं उनकी सम्पत्ति की जांच करें तो मैं कहता हूं लाखों की सम्पत्ति उनके पास मिलेगी। उनके घर पर आप छापा मारें तो काफी सम्पत्ति आपको मिलेगी और सैकड़ों गरीब आदमियों को मदद मिलेगी, जिन गरीबों की जेब काटते हैं, उन गरीबों को राहत मिलेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा। आज के डॉक्टरों में जो खामी इलाज करने में है वह यह है कि डॉक्टर जो प्रेस्क्रिप्शन लिखता है वह वही दवा लिखता है जो ज्यादा मंहगी है और जिस पर ज्यादा कमीशन मिलता है। ज्यादा कमीशन वही कम्पनी देगी जिसकी दवाओं की कीमत अधिक होगी या दवायें बोगस होंगी या जिसको डॉक्टर को देने के बाद पैसा बचेगा। अच्छी कम्पनियां कभी भी दवा पर कमीशन नहीं देंगी और कमीशन नहीं देंगी तो डॉक्टर कभी भी उस दवा को नहीं लिखेगा। मैं चाहूंगा, राजस्थान में जो भी डॉक्टर हैं उनको गरीबों के लिये चार छः आने की दवा लिखनी चाहिये ताकि इलाज करा कर गरीब आदमी ठीक हो सके। गरीब आदमी दवा के लिये 10-15 रुपये खर्च कर सके यह उसके लिये ना-मुमकिन-सी बात है। मेरा निवेदन है कि आप डॉक्टरों को इस तरह की डांट-फटकार पिलावें और आप उनकी चैकिंग करें या किसी को भेजकर उनकी जांच कराते रहें। मैं समझता हूं इससे गरीब आदमी को काफी राहत मिलेगी और जो भ्रष्टाचार प्रेस्क्रिप्शन में करते हैं उस पर भी रोक लगेगी। दूसरे जो सस्ती दवायें हैं और अस्पताल में उपलब्ध हैं वे भी मुहैया हो सकेंगी।

श्री अध्यक्ष: श्री मदनसिंह जी !

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : माननीय सदस्य, सेक्रेटेरियट में आज 27 दिन से भूख हड़ताल चल रही है। वहां शिक्षा मंत्री-जी का इन्तजार कर रहे हैं। वे जाकर नीबू का पानी वगैरह पिलायें।

(श्री मदनसिंह दांता)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मंत्रिमण्डल का सवाल है, मैं सात बातें मंत्रिमण्डल को निवेदन करना चाहता हूं। भगवान करे ये इन्हें याद रखें तो कोई भी मंत्री हो वह काम आयेगा। वे बात मैं अंग्रेजी में कहूंगा और हिन्दी में भी कहूंगा हमारे बाप-दादा पुराने जागीरदार थे, वे कहा करते थे कि मंत्रिमण्डल कैसा होना चाहिये। पहली बात बताऊंगा मंत्रिमण्डल की....

Mantri-Mandal should have administration under their eyes. अच्छे प्रशासन के लिए, प्रशासन को अच्छा जमाने के लिए यह जरूरी है कि उसका इन्तजाम मंत्री की आंखों के अन्डर रखना चाहिए।

They should have light of love in their hearts. इनका दिल है उसके अन्दर अपने कर्त्तव्यों के लिये गर्व होना चाहिये, खुशी होनी चाहिए। जैसे दीप को देखकर पतंगा खुश होता है वैसे ही अपने सिद्धान्तों, अपने नियमों, अपने कार्यक्रमों के प्रति इतना लव होना चाहिए कि अपने कार्यक्रम के सिवाय दूसरा नहीं सूझना चाहिए। जैसे गीता में कहा है कि सब धर्मों को छोड़ कर एक कर्त्तव्य पर मिट जायं।

They should have truth on their lips. इनके होठों पर सच्चाई होनी चाहिए और उसी सच्चाई पर चलना चाहिए।

They should have firmness in their fist. यह हिटलर ने भी कहा था कि देश के अन्दर अगर कोई देश दखल करता है तो उस वक्त मुट्ठी में ताकत होनी चाहिए या कलम में ताकत होनी चाहिए।

They should have blood of heritage in their soul. यानि अपनी परम्पराओं का खून है वह अपनी आत्मा के अन्दर जमा हुआ रहना चाहिए।

They should be resolute in their belief. जहां खड़े हो गए, जहां पर डट गए सिद्धांत पर वहां पर वर्ग विशेष की राजनीति का नहीं बल्कि सिद्धांतों का आदर होना चाहिये।

They should have sacrifice all around for the nation अपने देश के लिए आलराउण्ड सेक्रीफाइस हो। जब देश का प्रश्न सामने आए तो न पार्टी सामने होनी चाहिए, न कोई नेता होना चाहिए। मातृभूमि ही नेता हो, देश ही सबसे सर्वोच्च हो।

तो ये सात सिद्धांत हैं जिनको याद रखें।

बाकी मैं मंत्री महोदय को कहूंगा कि मैंने अपनी कांस्टीट्यूएन्सी के पांच सात ग्रामों के नाम दिये हैं जिनमें एक बाय गांव है, जहां सब कुछ सुविधा होते हुए डिस्पेंसरी नहीं है। वहां पर रुपया खर्च हो गया डिस्पेंसरी के लिए, वहां लोग भेज दिए गए, डी. एम. एच. ओ. ने वायदा कर दिया, हमने मकान बना लिया मकान बनने पर स्टाफ रवाना हो गया परन्तु आपकी नीति में कुछ ऐसी बात हुई कि वहां के लोग डिस्पेंसरी से वंचित रह गए। जो कुछ भी डिस्पेंसरी को रूप देना हो, देकर कम से कम एक डॉक्टर भेजें जब आपके पास पैसा हो तब ज्यादा स्टाफ भेज दें। कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे ही सेलेरा मंडा, डांसरोली गांव के लिए आपने वायदा किया है। मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर ध्यान दें,

(श्री मदनसिंह दांता)

अध्यक्ष महोदय, एक बात पर कुछ आपस में टसल हो गई थी जे. पी. बाबू के नाम पर। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि जितनी आपकी श्रद्धा है उतनी ही मुझे है, मुझे उनके नेतृत्व में श्रद्धा है। इसलिए अभी जो गलतफहमी हो गई थी उसके बारे में मैं यही कहना चाहता था, जैसे गांधीजी कहते थे कि मुझे तब खुशी होगी जब एक गांव की छोटी से छोटी जात की लड़की जाकर राष्ट्रपति बने। जैसे आपने नेताओं के इलाज के लिए व्यवस्था की वैसे ही गांव के गरीब से गरीब आदमी के लिए भी यदि मौका पड़ जाय तो हवाई जहाज देने में आपको संकोच नहीं करना चाहिए।

यही कह कर मैं जा रहा हूं। थैंक्यू।

एक माननीय सदस्य : वाकआउट कर रहे हैं क्या ?

श्री मदनसिंह दांता : नहीं, नहीं। सेक्रेटेरियट भूख हड़ताल तुड़ाने जा रहा हूं।

श्री रणजीतसिंह राठौड़ (ओसियां) : अध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव इस मंत्रिमण्डल की मांग पर था और चिकित्सा की मांग के ऊपर भी था। आज मंत्रिमण्डल के प्रश्न को लेकर के जिस तरह का इस बजट में प्रावधान है, वैसा पहले भी था किन्तु इस बजट में ज्यादा बढ़ाया गया है। खर्चा कितना ही हो, मंत्रिमण्डल के मार्फत अगर आम जनता का भला हो सकता हो तो उस पर खर्चा किया जावे। यह इनकी सूझ-बूझ पर निर्भर है कि उस पैसे का सदुपयोग कैसे हो। यह इस गरीब प्रान्त के लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा है। इस प्रान्त के भू-भाग में ही ऐसे आदमी रहते हैं जिनको एक टाइम खाना नसीब होता है और जिनको दो दिन में पानी नसीब होता है। यानी अलग-अलग तरह की अपने राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। इस स्थिति में अपने राजस्थान के मंत्रिमण्डल के ऊपर टैक्स का जो पैसा लगे वह पैसा अगर उन लोगों के हित में उपयोग नहीं आ सके और फिजूलखर्च हो तो आपको ठेस लगे या न लगे पर उस गरीब को बहुत भारी धक्का लगेगा जिससे टैक्स के जरिये से इकट्ठा किया हुआ पैसा आप लोगों पर खर्च होगा। बाकी मंत्रिमण्डल के सदस्य किस तरह से रहें, उनका किस तरह का रहवास हो, इस सम्बन्ध में पहले भी टीका टिप्पणी होती रही है और मैं समझता हूं कि जो आज उस तरफ बैठे हैं वह तीस साल तक इस बेंच पर बैठते रहे और उन्होंने हमेशा इसका विरोध किया है। हमारा काम खाली विरोध करने का नहीं है। हमारा काम है अगर अच्छा काम कर सकें तो पैसा ज्यादा से ज्यादा खर्च किया जावे। पहले राजाओं को दोष देते थे, उसके बाद जागीरदारों को दोष देते थे, तीस साल तक जिस कांग्रेस ने शासन किया उसको भी दोष भी देते रहे। आज दोष देने वाले ही उधर बैठे हैं तो नई पद्धति अपना कर उन्हें जनता के सामने एक आदर्श पेश करना चाहिए। उस आदर्श से जनता पार्टी की और जनता सरकार की एक साख बनेगी। इसलिए मेरा तो यही निवदन है कि इसमें जितनी कटौती कर सकें उतनी करें और जिस तरह से आप कम से कम खर्चा करके सादगी से रह सके, ऐशो आराम छोड़ कर वैसे रहें वरना हालत दूसरी बन जावेगी। आप लोगों की आदत बिगड़ जायेगी। आपकी पंचमुखी पार्टी है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, अगर आपकी आदत बिगड़ गई तो आपकी उतनी

(श्री रणजीतसिंह राठौड़)
फिक्र नहीं है लेकिन आपके बच्चों का भविष्य जरूर बिगड़ जायेगा। इसलिए जितना हो सके खर्चा कम करें।

श्री रघुनन्दन व्यास : पंचमुखी तो हनुमान का मंदिर है जहां पूजा होती है।

श्री रणजीतसिंह राठौड़ : आप पूजा कीजिए लेकिन यह घटकवाद की पार्टी है इसलिए निवेदन किया है।

अब इसके बाद में मेरे कटौती प्रस्ताव हैं मेडिकल पर। माननीय मंत्री महोदय ने जो मांग रखी है, उसका जितने आपने पास पैसा है वह पैसा अगर राजस्थान की जनसंख्या को देखते हुए स्वास्थ्य पर खर्च होगा तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अगर आपने भेदभाव बरता तो उस भेदभाव से जनता में एक भ्रांति फैलेगी। तीस साल तक यह भ्रांति दबी रही, फैल नहीं सकी और वही हालात आज भी है। जो इलाका है राजस्थान का उसमें 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। उनको कितनी सुख-सुविधा आप उपलब्ध करा सकते हैं इन पैसों से इसके सम्बन्ध में मैं आपको कुछ सुझाव दूंगा। किस तरह धन की कटौती करें और किस तरह से उस धन का सदुपयोग करें, मैं आलोचना नहीं करके इस सम्बन्ध में आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हालांकि यह पैसा पूरे राजस्थान के ऊपर करीब ढ़ाई करोड़ की आबादी पर खर्च होता है परन्तु जिस तरह से इस पैसे का बंटवारा किया है इसको देखने से यह मालूम होता है कि आपने खाली विधायकों को ही धोखे में नहीं रखा, खाली जनता को ही धोखे में नहीं रखा बल्कि स्वयं आपने आपको धोखे में रखा है। हमसे कहा गया कि हम गांवों की तरफ जा रहे हैं, हम गांवों पर पैसा खर्च करेंगे, ग्रामीण जनता पर पैसा खर्च करेंगे लेकिन इस प्रगतिशील बजट को देखने से पता लगता है कि यह केवल ढकोसला ही ढकोसला है। मैं आपको बता दूं कि आपके करीब छः करोड़ रुपयों में से दो करोड़ बीस लाख रुपया खाली एस. एम. एस. पर खर्च हो रहा है। अब आप समझिये, राजस्थान कितना बड़ा है इस पर तीन करोड़ रुपया खर्चा करेंगे। यहां पर आप कितना ही खर्चा करें हमें एतराज नहीं है, हम मानते हैं कि यहां पर हॉस्पिटल बड़ा है, यह केपिटल है, सब प्रकार के धनी लोग यहां पर आकर इलाज कराना चाहते हैं, वे यहां इलाज करवायें। परन्तु इसके बाद 26 जिले हैं। 26 जिलों में सिर्फ जयपुर शहर को छोड़ दें तो उसके बाद 25 जिले और जयपुर के देहाती क्षेत्र, पर आप कितना पैसा खर्च कर सकेंगे। उन पर करीब 3 करोड़ 13 लाख रुपया खर्च होगा। तो यह ढकोसला नहीं तो क्या चीज है? इसलिए मैं कहता हूं कि इस बजट की पोल खुल जाएगी और खुलने के बाद में जब गांव वालों को पता लगेगा कि जनता पार्टी कहती कुछ है और करेगी कुछ और, तो आपकी साख कमजोर पड़ जाएगी। हम 30 साल तक रहे और 30 साल में अच्छे ही काम किये हैं। कुछ खराब काम हुए तो उन खराब कामों को जनता ने पसन्द नहीं किया, मगर आपकी पोल खुलेगी तो आपको 30 महीने निकालना मुश्किल पड़ जायेगा। आप जनता के सामने आये हैं और जनता ने भारी वोटों से आपको जिताया है इसलिये मैं चाहता हूं कि आप आदर्श पेश करें और गांव वालों को स्वास्थ्य के मामले में अति सुख-सुविधा दें। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था पहला सुख निरोगी काया। अगर काया ठीक रहेगी तो सब कुछ ठीक है। अगर

(श्री रणजीतसिंह राठोड)
निरोगी काया नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि जो बजट का एलोकेशन हो उसमें देहात के ऊपर ज्यादा खर्च करने की कोशिश की जाय।

दूसरा, आप 32 करोड़ में से 26 करोड़ खाली एलोपैथी पर खर्च कर रहे हैं और बाकी 6 करोड़ आयुर्वेद, यूनानी, होमियोपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा पर खर्च कर रहे हैं। आप एक तरफ तो इस बात का दावा करना चाहते हैं कि हम गांवों में स्वास्थ्य के मामले में ज्यादा से ज्यादा सुख-सुविधा देना चाहते हैं दूसरी तरफ दवायें महंगी हैं। महंगी दवा गांव वाला लम्बे समय तक कहां से लायेगा, कहां से दवा उपलब्ध करायेगा? इसलिए मेरा निवेदन है कि आयुर्वेदिक औषधियों पर ज्यादा पैसा खर्च करें। कुछ जगहों पर गांवों में आपने डिस्पेन्सरियां खोली हैं, लेकिन मेडिकल डिपार्टमेंट का डॉक्टर गांवों में रहता नहीं है। करें क्या? इसलिए डिस्पेन्सरियां खाली पड़ी हैं। मैं यह मानता हूं कि सबका यह दृष्टिकोण होता है कि जहां रहें वहां रहने की अच्छी सुख सुविधा हो। किसी-किसी गांव में लाइट नहीं होती है, पानी नहीं होता है तो थोड़ी बहुत उनको तकलीफ होती है। गांव वाले तकलीफ सहन कर रहे हैं तो डॉक्टर को भी तकलीफ सहन करनी चाहिए। यदि उनके पास दवा नहीं है तो रह कर क्या करे। दवा उपलब्ध नहीं है तो क्या गांव का गन्दा पानी पिलायें, मूत्र सेवन करायें? आपका विचार मेरे ख्याल से मूत्र-सेवन पद्धति अपनाने का लगता है इसीलिए गांवों पर पैसा कम खर्च करना चाहते हैं। यह रूप मंत्रिमण्डल ने अपना रखा हो तो मंत्रि-मण्डल कर सकता है, परन्तु उसको गांव में अपनाने की बात अगर आप करना चाहते हैं तो गांव वाले उसको अपनायेंगे नहीं। आज आप मूत्र-सेवन की बात कर सकते हैं लेकिन गांव वाले उसको करेंगे नहीं। मूत्र-सेवन से गांव का भला करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं वह होगा नहीं। आप उनको चिकित्सा सुविधा से महरूम रख देंगे। इसलिए गांव में चिकित्सा की सुख-सुविधा ज्यादा हो यह आपका नाममात्र का ढकोसला है। इसमें ज्यादा से ज्यादा काम करें।

अब दूसरा सवाल आता है आपके मेडिकल कॉलिजेज का। पांच डिस्ट्रिक्ट्स में मेडिकल कॉलेजेज हैं। उनके अलावा बाकी जगहों पर सुख-सुविधा क्या है? बाकी जगहों पर दवाओं का इन्तजाम क्या है? बाकी जगहों पर भी दवाओं का इन्तजाम करना है। मेडिकल कॉलिजेज दवायें खरीदते हैं और आपका डिपार्टमेंट खरीदता है। जब मार्च का महीना खतम होता है उस वक्त वह दवायें खरीदने की कोशिश करते हैं। सारा काम थोड़े से समय में करना चाहते हैं तो बड़े होच पोच तरीके से होता है। कैसी दवायें आयें, किस तरह की दवायें हों, दवायें कहां से आयें इस बात की चिन्ता नहीं करते। उनको तो पैसा खर्च करना है। जो बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं वह बड़े-बड़े आदमियों से मिली हुई होती हैं, उन कम्पनियों से खरीद करके राजस्थान का पैसा बरबाद करते हैं। मेरा सुझाव है कि समय से पहले ही एक सेल बन जाय और उस सेल का यह काम हो कि कितना पैसा कहां पर अलॉट होना चाहिए। उस अलाटमेंट के अनुसार पैसा सही रूप से खर्च करना चाहिये।

अगर आप दवाओं के मामले में कुछ करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि जहां

(श्री रणजीतसिंह राठौड)

जहां आपके मेडिकल कॉलेजेज हैं वहां पर आप दवाओं के छोटे लघु उद्योग खोल दें। दवायें मेडिकल कॉलेज बनायें ताकि बाहर से खरीदनी न पड़ें। आप एक्सपेरीमेंट करें, दवायें कैसी हैं, इसकी अलग-अलग तरीकों से जांच करायें पांच मेडिकल कालेजेज में तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा नतीजा पेश होगा।

आज गांवों के अन्दर अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि लोग मलेरिया से पीड़ित हैं। यह बात सही है कि दो साल से इतना हल्ला मचाया कि मलेरिया की बीमारी को हमनें खतम कर दिया। अब सब जगह से अफवाहें आ रही हैं कि गांवों में मलेरिया भयंकर रूप से चल रहा है। मलेरिया क्यों नहीं हुआ दो साल तक, उसका कारण यह है कि बरसात कम हुई और अकाल पड़ गया तो मच्छर ज्यादा हुए नहीं, लेकिन वह वास्तव में खतम नहीं हुआ। आज हालत यह है कि बरसात ज्यादा आई तो जगह-जगह मलेरिया का इतना प्रकोप है कि कह नहीं सकते। मलेरिया सर्विलेन्स में आपके कितने ही आदमी काम कर रहे हैं, लेकिन वह दवायें नहीं दे रहे हैं। मलेरिया वर्कर्स की यह हालत है कि जबसे वह काम कर रहे हैं तबसे उसी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। न उनका प्रमोशन हुआ है और न डिपार्टमेंट उनको दवाइयां दे रहा है। आज भी उनकी वही हालत है। उनका बड़ा लम्बा-चौड़ा क्षेत्र है लेकिन हर गांव में सही तारीख को पहुंचते हैं। सरकार का यही आदमी हर गांव में पहुंचता है और तारीख लगाता है कि इतनी तारीख को इस घर पर आया था। दवाइयां उसके पास नहीं होती हैं। वह घर घर पहुंचने की कोशिश जरूर करता है। उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन उसको कोई डी०ए० नहीं मिलता है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हालत मलेरिया वर्कर्स की यह है कि उनको प्रमोशन नहीं मिलता है। अगर मलेरिया उन्मूलन पर रुपया खर्च करना चाहते हैं तो अच्छी दवाइयां लानी चाहिएं और उनकी दिक्कतों को दूर करना चाहिए नहीं तो वह किस बूते पर जाकर दवाइयां डिस्ट्रिब्यूट करेंगे। वह काम नहीं करेंगे तो लोगों को राहत नहीं मिलेगी।

मैं निवेदन करूंगा कि मेडिकल डिपार्टमेंट की जो हालत मैंने बतायी है यही हालत जनाना हॉस्पिटल की है। सारे राजस्थान के जनाना हॉस्पिटल्स पर खर्च होता है 24,30,000 रु० और जयपुर के जनाना हॉस्पिटल पर 30 लाख रुपया खर्च होता है। पूरे राजस्थान में 24,30,000 रु० और जयपुर में 30 लाख। आप 50 लाख रुपया खर्च करें हमें एतराज नहीं है, परन्तु एक तरह की समानता तो रखें। देहातों में भी औरतें बीमार होती होंगी, देहातों की औरतों के भी डिलीवरी होती होगी। उनके लिये क्या व्यवस्था है? मेरा नम्र निवेदन है कि जिस तरह से बजट में प्रोवीजन रखा है, जिस तरह से गांवों और शहरों में उसको डिस्ट्रिब्यूट किया है वह ठीक नहीं है। यहां पर जनाना अस्पताल खोल कर आप कुछ दिखाना चाहते हैं। हम यहां पर हैं और विधायक शिकायत न करें इसलिए जयपुर शहर पर ज्यादा जोर दिया जाता है। जयपुर जिले में देहात भी है और बाकी के 25 जिले और हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि बजट में जो पैसा रखा गया है उसका सही ढंग से उपयोग करें। देहातों का पूरा ध्यान रखें। अगर देहात का

(श्री रणजीतसिंह राठौड़)
ध्यान आप नहीं रखेंगे तो हवा आपकी बिगड़ेगी और लाभ हमको मिलेगा जैसे कि देहात में नसबन्दी के कारण हवा हमारी बिगड़ी थी और लाभ आपको हुआ ।

(व्यवधान)

श्री बालकृष्ण थानवी : बोलने का लाभ भी आपको मिल रहा है ।

श्री रणजीतसिंह : इसलिए मेरा निवेदन है कि गांव के बजाय शहरों को न लें ।

श्री अध्यक्ष : श्री गुल मोहम्मद !

श्री गुल मोहम्मद (जोहरी बाजार): माननीय अध्यक्ष महोदय, जबसे असेम्बली का सेशन चला है तभी से मुझे यह बात सुनने को मिली हैं कि सभी काम शहरों में हो रहे हैं और दूसरी जगहों की उपेक्षा की जा रही है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय को कि 30 साल से कांग्रेस शासन के अन्दर जयपुर के हितों को उपेक्षा की गई है। अगर आप विचार करके देखेंगे तो पायेंगे कि जयपुर अभी का बसा हुआ नहीं है, पुराना बसा हुआ है । जितने भी काम काज हुए वह पहले ही हो चुके थे, बाकी कितना खर्चा जयपुर पर किया गया । अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो आपको अहसास होगा कि जयपुर के हित में, जयपुर की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया गया । यह बात बिल्कुल गलत है कि जयपुर में हॉस्पिटल पर इतना खर्चा हो गया । अगर हॉस्पिटल पर खर्चा हुआ है तो एस० एम० एस० हॉस्पिटल पर हुआ है । एस० एम० एस० हॉस्पिटल का खर्चा निकालकर देखें कि इस हॉस्पिटल पर जयपुर में कितना खर्चा हुआ है तो आपको मालूम होगा कि जयपुर में जितना खर्चा होना चाहिए था उतना खर्चा नहीं हुआ है ।

जयपुर का सवाई मानसिंह अस्पताल सारे राजस्थान का अस्पताल है । इस अस्पताल में बहुत अनियमिततायें बरती जा रही हैं, दवाइयां नहीं मिलतीं, पट्टियां नहीं मिलतीं, तमाम चीजें बाजार से लानी पड़ती हैं । इन अस्पतालों की जांच पड़ताल के लिए एक समिति का गठन किया जाए जो इसकी जांच पड़ताल करें कि किस तरह से इन में अनियमिततायें बरती जा रही हैं और धन का दुरुपयोग किया जाता है । वह समिति इसके कार्य की जांच पड़ताल करती रहेगी ।

इसके अलावा जयपुर में एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और बनाया जाए जो वर्तमान पागलखाना भवन में स्थित हो । इस समय पागलखाने के आसपास रहने वाले व्यक्तियों के लिए पागलखाना से सरदर्द न्यूसेन्स पैदा हो गया है, पागल आते हैं, उनको भर्ती नहीं किया जाता तो वे बाहर ही ठहर जाते हैं और रात में मकानों में घुस जाते हैं । इस तरह न्यूसेन्स पैदा करते हैं । इसलिए मौजूदा पागलखाने को शहर से दूर रखा जाए और उस भवन में जयपुर का जिला अस्पताल रखा जाए। इसके अलावा जयपुर का टी. बी. अस्पताल बस्ती के निकट हो गया है, इसे दूर किया जाए ।

मेरा यह भी निवेदन है कि आयुर्वेद अस्पतालों को तरक्की पर तरक्की दी जाती है, आयुर्वेद के अस्पताल पर अस्पताल खोले जाते हैं और यूनानी अस्पतालों के लिए कोई बजट नहीं रखा जाता है और न ही ये खोले जाते हैं । हर साल 200 आयुर्वेद

185



(श्री गुल मोहम्मद)

अस्पताल खोले जाते हैं लेकिन यूनानी अस्पताल एक भी नहीं। इनके आंकड़ों की जांच की जाए कि किस तरह से यूनानी अस्पतालों को नेगलेक्ट किया जाता है। जब हर साल 200 आयुर्वेद औषधालय खोले जाते हैं तो यूनानी क्यों नहीं खोले जाते ? इस समय यूनानी औषधालयों में 28 पद 3 वर्ष से हकीमों के खाली पड़े हैं कोई भर्ती नहीं की गई है। यूनानी हकीमों का कोई प्रमोशन नहीं होता, मैं आंकड़े पेश करता हूं। उप-निदेशक आयुर्वेद के 5, यूनानी के कोई नहीं। जिला आयुर्वेद अधिकारी 21, यूनानी कोई नहीं, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज 3, यूनानी कोई नहीं। आयुर्वेदिक दवाखाने 2320, यूनानी 52, आयुर्वेदिक दवाओं की फार्मेसी 1, यूनानी कोई नहीं। आयुर्वेदिक कम्पाउन्डर के ट्रेनिंग सेन्टर 2, यूनानी कोई नहीं। आयुर्वेदिक दवाखानों में रोगियों के भर्ती करने की व्यवस्था है जबकि यूनानी औषधालयों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आयुर्वेद पर बजट का 90 प्रतिशत रुपया खर्च किया जाता है, यूनानी पर केवल 10 प्रतिशत। यह असमानता यूनानी और आयुर्वेद में पिछले 30 साल में की गई है। यह गंभीर मसला है, इसको बहुत अच्छी तरह से देखें आप चिंतन करें कि किस तरह से यूनानी अस्पतालों की ज्यादा आवश्यकता है। कुछ समय पहले की बात है, 3-4 यूनानी अस्पतालों को आयुर्वेद में बदला गया। यह क्या परम्परा है ? इसको बदलें।

जयपुर में सफाई की स्थिति बहुत खराब है, यह गंभीर प्रश्न है। यहां पर पाड़े बहुत कटते हैं जिसके लिए कोई उनके पास लाइसेन्स नहीं होता। बिना लाइसेन्स के पाड़े कटते हैं। यहां के अधिकारियों के उनसे पैसे बंधे हुए होते हैं। सैकड़ों की संख्या में पाड़े कटते हैं। इसके कारण एक गम्भीर बात उत्पन्न यह होती है कि बकरे के मीट में पाड़े का मीट मिला कर बेचते हैं। कई बार इसके लिए कहा गया तो भी कोई चैकिंग नहीं होती है। इसके लिए कानून सख्त बनायें व सख्ती से पालन किया जाए, दोषी कसाइयों का चालान किया जाए, उन पर सजा व जुर्माना किया जाए ताकि वे पाड़ा नहीं काटें और बकरे का मीट ही बेचें।

राज्य कर्मचारियों के लिए, जो जयपुर में काम करते हैं, दवाइयां उपभोक्ता भंडार से खरीदना अनिवार्य है। यह व्यवस्था केवल जयपुर में ही है, राजस्थान के किसी भी शहर में या हिन्दुस्तान के दूसरे राज्य में भी नहीं है। जब उपभोक्त भंडार से दवाई नहीं मिलती है तो कर्मचारी परेशान होता है, उसको एन. ओ. सी. लेना पड़ता है और फिर दूसरी जगह से खरीदनी पड़ती है। इसमें बड़ा घपला होता है। इस बात को खत्म करें और छूट दें कि जयपुर में भी कर्मचारी किसी भी दुकान से दवाइयां खरीद सकता है। यह उपभोक्ता भंडार से ही दवा खरीदने का नियम सिर्फ जयपुर के लिए ही लगाया है, इसे हटाया जावे।

जयपुर में सफाई न होने से संक्रामक रोग पैदा होते हैं। माननीय सदस्य जयपुर का जिक्र करते हैं, भला बुरा कहते हैं, जयपुर जो पिंक सिटी है उसकी सफाई की व्यवस्था बड़ी दयनीय है। सफाई के लिए सिनेमा व टी० वी० पर न्यूज रील्स दिखानी चाहिए, जनता को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कूड़ा न फेंके। सफाई किस तरह से करनी चाहिए, वह ज्ञान देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री ओम प्रकाश शर्मा !

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, कोटा में मंत्रिमण्डल की बैठक हुई, कुछ निर्णय लिए गए। उनमें से एक भी निर्णय अभी तक क्रियान्वित नहीं हुआ। मंत्रिमण्डल निर्णय ले और जनता में बताये उसके बाद विधायक जब अपने क्षेत्र में जाता है तो जनता पूछती है क्या हुआ ? जनता उसको घेरेगी। मैं तो नौजवान हूं, सहन कर लूंगा परन्तु बहुत से माननीय सदस्य बुजुर्ग हैं वे सहन नहीं कर सकेंगे। मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया था कि बूंदी अस्पताल 'बी' क्लास इसी वर्ष होगा। इस समय वहां 'सी' क्लास अस्पताल है। 105 शैय्यायें वहां पर हैं जबकि 170–180 से ज्यादा मरीज रहते हैं। इसके लिए मैंने पहले भी निवेदन किया था।

इसके अलावा वहां बच्चों का वार्ड नहीं। इसके लिए भी पहले निवेदन किया जा चुका है और मंत्री महोदय ने यह बात स्वीकार की है। इसी प्रकार बूंदी में टी० बी० अस्पताल है वह भूतपूर्व जिला प्रमुख कांग्रेस के मकान के अंदर है। किराए पर विभाग ने वह मकान ले रखा है और उसका किराया 500)- मासिक देते हैं। इस प्रकार 500)- प्रति माह किराया विभाग 5–7 साल से दे रहा है। इतने पैसों में तो भवन खड़ा हो जाता। अफसोस से कहना पड़ता है कि मंत्री महोदय ने आज्ञा दी कि अस्पताल को बदल कर बूंदी अस्पताल में ले जायं लेकिन उस आदेश की पालना अभी तक नहीं हुई।

इसी प्रकार जयपुर में जो हमारे स्वास्थ्य कार्यालय हैं, उसकी धांधली के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे डाइरेक्टर साहब हैं, वे वास्तव में न्याय-प्रिय हैं परन्तु उनके जो सबोर्डिनेट हैं उनका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक जगदेवजी हैं उनका पी. ए. है। वहां पर हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी के आदेश की प्रतिलिपि जाती है। मुझे पी. ए. साहब ने क्या कहा, वह मैं बताना चाहता हूं। जो असिस्टेन्ट पी. ए. है उसका नाम स्वामी है। मुझसे उसने कहा, जितना फाइल पर वेट होगा उतनी ही जल्दी फाइल आगे सरकेगी। यह स्वास्थ्य मंत्रीजी के आदेश के बाद पी. ए. ने कहा।–पी. ए. की इतनी हिम्मत कि वह विधायक से कहे वेट चाहिए। तो, श्रीमान्, जन साधारण के साथ क्या होता होगा, यह आप सोच सकते हैं। इस सम्बन्ध में मैंने डाइरेक्टर साहब से कहा था। उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुरन्त देखूंगा। मैं स्वयं इसका साक्षी हूं। मुझसे उन्होंने वेट मांगा था। वेट में क्या होता है, वह मैंने उनको दिखाया। मैं नौजवान हूं। मैंने उनको दिखाया, वेट क्या होता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि पी. ए. पैसा मांगता है तो मेरे ख्याल से पी. ए. की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। ऊपर तक यह जाल फैला हुआ है ऐसा मुझे नजर आता है। मंत्री महोदय के आदेश रद्दी की टोकरी में पड़े रहें, यह मेरी समझ में नहीं आता है। मंत्री महोदय आदेश दें और उसकी पालना न हो...

श्री त्रिलोकचन्द जैन : यह कब की बात है ?

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अभी की बात है।

श्री तिलोकचन्द जैन : आपने जब डाइरेक्टर साहब से कहा तो हम लोगों के नोटिस में नहीं लाये ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : डाइरेक्टर साहब को कहा था ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : कृपा करके कोई सीमा तो रखिए ।

श्री अध्यक्ष : 10-12 मिनट से अधिक किसी को समय नहीं दिया है ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि परिवार कल्याण और सर्वेक्षण के लिए प्रत्येक स्थान पर एक उप-केन्द्र खोला जाता है। सर्वे की वहां के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाती है उसमें एक सहायक और एक ए. एन. एम. की जिम्मेदारी होती है। उनको सर्वे के लिए केवल पांच मील की इजाजत है । पांच मील तक वे ड्यूटी दे सकते हैं जबकि उनको 20 हजार की आबादी तक का सर्वे करना चाहिये । अतः बहुत सारा क्षेत्र छूट जाता है । मलेरिया के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं उनको भी यह जिम्मेदारी देनी चाहिए ।

इसी प्रकार से जो राजनारायणजी ने एक व्यवस्था चलाई है, उसके सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है, श्रीमान्, बहुत से नवयुवकों को, जिनको इन्जेक्शन नहीं लगाना आता है, प्रशिक्षण दिया गया । आज उन पर किसी का दबाव नहीं है । किसी व्यक्ति का उन पर नियन्त्रण नहीं है । अत: मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन व्यक्तियों पर भी अगर विभाग का नियन्त्रण हो तो वास्तव में गांव का लाभ होगा ।

एक निवेदन और करना चाहूंगा । पी. एच. सी. में दो डॉक्टर होते हैं । वे आपस में लड़ते हैं । कहते हैं तू बड़ा, मैं बड़ा। इस बड़प्पन के चक्कर में कर्मचारी भी पड़ जाते हैं । उनमें गुटबाजी होती है और गांव के अन्दर अच्छा कार्य नहीं होता है । गांव के लोगों को इससे परेशानी होती है ।

आयुर्वेद के लिए मेरा यह निवेदन है कि मंत्री महोदय के यहां से जो आदेश दिए जाते हैं उनको भी रद्दी की टोकरी में फेंका जाता है । उसमें एक श्यामलाल शर्मा हैं। उन्होंने कई प्रकार की धांधली की है । उदाहरण मौजूद है । मेरे यहां बूंदी में जो अस्पताल खोला गया है, मैंने निवेदन किया था कि उसको किसी गांव में खोल दिया जाए । यह मन्जूर किया गया था परन्तु वह नहीं खोला गया है । कई जगह अस्पताल खुल गया परन्तु वैद्य नहीं है ।

इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रमुख नगरों में जीवन रक्षक औषधियों की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस रोकने के लिये उचित कदम उठाये जाने चाहिएं। साथ ही साथ गैर सरकारी डाक्टर की फीस भी उचित, नियन्त्रित होनी चाहिए । इससे गरीब लोगों को लाभ मिलेगा । जो बेरोजगार डॉक्टर हैं, उनको भत्ता और काम करने का अवसर दिया जाए । गांव में डॉक्टर जायेंगे तो गरीब लोगों को लाभ होगा । गांवों में जो डॉक्टर जाए उनको भत्ता दिया जाए क्योंकि शहर और गांव में सुविधाओं में काफी अन्तर है ।

धन्यवाद !

श्री अध्यक्ष : श्री राम करण सिंह !

(अनुपस्थित)

श्री रामप्रसाद लढ्ढा ।

श्री राम प्रसाद लड्ढा (माण्डल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छे जीवन के लिए अच्छी शिक्षा और अच्छी चिकित्सा की आवश्यकता होती है। गांव आज इसीलिए उजड़े हुए हैं कि वहां पर न तो अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है और न चिकित्सा की व्यवस्था है । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह कहना चाहूंगा कि गांवों में अधिक से अधिक चिकित्सा की सुविधाएं मुहय्या की जाएं । जयपुर में बैठ कर गांवों का विकास नहीं हो सकता है। जब तक गांव में रहने वाले आदमी के साथ बैठ कर विचार नहीं करेंगे तब तक विकास नहीं होगा। गांव के पढ़े-लिखे लड़के, काश्तकारों के लड़के, जिनके पास सौ बीघा जमीन है, भी शहर में जाना चाहते हैं। वह गांव में नहीं रहना चाहते । वह इसलिए गांव में नहीं रहना चाहते है कि जो सुविधाएं, व्यवस्थाएं आज शहरों में उपलब्ध हैं, वह गांव में नहीं हैं। एक आदमी, जो काश्तकार है अपने लड़के को पढ़ाता है। वह यह विचार करता है कि जब यह पढ़-लिख कर काबिल हो जाएगा तो गांव में बैठ कर हमारी सेवा करेगा। हमारे गांव की उन्नति का कार्य करेगा। गांव के सुख-दुख में हाथ बटाएगा। परन्तु यह हमारे देश, प्रदेश का दुर्भाग्य है कि गत 30 साल से हमारे गांवों की उपेक्षा की गई । इन तीस सालों में गांव उजड़े हैं और शहर पनपे हैं। वे गांवों से शहरों की ओर दौड़ रहे हैं। इसका कारण यह है कि गांवों में सुविधा नहीं है। मैं इसलिए यह चाहूंगा कि अधिक से अधिक बजट गांव में खर्च हो। चिकित्सा और शिक्षा की आधारभूत व्यवस्था जो समाज के लिए आवश्यक है वह गांव में उपलब्ध हो । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज की जो व्यवस्था है उसके अन्दर इस प्रकार के सुधार किए जा सकते हैं। जो व्यवस्था उपलब्ध है उसका अधिक से अधिक उपयोग हो ताकि कम से कम साधनों के अन्दर किसी प्रकार गांव में मेडिकल राहत पहुंचाई जाए ।

सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज जितने चिकित्सालय प्राइवेट मकान में चल रहे हैं, वे खराब हैं, व्यवस्थित नहीं हैं और जिस प्रकार सरकारी नक्शे के अनुसार वे होने चाहिएं, नहीं हैं। इसके कारण जो चिकित्सा सुविधा वहां पर होनी चाहिए, वह नहीं हो पाती है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो अस्पताल ऐसे भवनों में हैं जिनमें व्यवस्था ठीक नहीं है, जो व्यवस्थित रूप से राहत नहीं दे सकते हैं, उनको उन भवनों से हटा कर सरकारी नक्शे के अनुसार जो भवन हो उनमें शिफ्ट किया जाए। इसके साथ ही ए. एन. एम. की पोस्ट होनी चाहिये । इसका एक उदाहरण दूंगा। मेरे खुद के गांव माण्डल के क्षेत्र के राजाजी का करेड़ा में ए. एन. एम. की पोस्ट नहीं है। वहां पर यह पोस्ट कायम हो। आपने इसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा है। मैं चाहूंगा कि वहां पोस्ट कायम हो। इससे वहां पर महिलाओं को सुविधा मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा में हॉस्पिटल है, उसके बारे में आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि उसमें काफ़ी अव्यवस्था है। उसकी व्यवस्था को सुधारा जाय और प्रत्येक स्थान पर हर प्रकार की सुविधाएं दी जायें। एड-पोस्ट पर सीनियर मेल नर्स को रखा जाय । सीनियर मेल नर्स को जो अनुभव होगा, उसका काश्तकारों को भी लाभ मिलेगा ।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

इसके अलावा जैसा पहले भी बताया, वहां पर आये दिन बीमारियां होती रहती हैं। भीलवाड़ा जिले में टिटेनस की बीमारी अधिक होती है। मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर जो पोस्ट खाली है, उसको भरने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा खास तौर से हॉस्पिटल के अन्दर डाक्टर कम हैं। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

माण्डल के मेरे क्षेत्र में बागोर डिस्पेंसरी में डॉक्टर और कम्पाउण्डर में झगड़ा चल रहा है। बागोर में सब डॉक्टर को चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि जो कम्पाउन्डर गलत आदमी है उसको वहां से हटाया जाये। राजस्थान में किसी भी प्रकार की शिकायत आपके पास आती है, तो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। ऐसी जगह पर अच्छे आदमी को रखना चहिए।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जहां डॉक्टर लापरवाह और निष्क्रिय हैं और जनता के साथ खिलवाड़ करते हैं उनके खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिये। महात्मा गांधी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में एक डॉक्टर है, डा. जगदीशचन्द्र वैष्णव। उस हॉस्पिटल में 8-3-1978 को एक बच्चे की हालत बिगड़ती गयी। डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर नहीं आया, बच्चे का पिता गया तो भी डॉक्टर नहीं आया। अन्त में उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे डॉक्टर जो निष्क्रिय हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय ताकि जो 30-40 डॉक्टर हैं उनको नसीहत मिले।

इसके अलावा मैं अपने क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। बेमाली एक ऐसा स्थान है जिसका उद्घाटन चिकित्सा मन्त्री ने किया था। पर अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है वह तुरन्त प्रारम्भ हो। माण्डल एक बड़ा गांव है, जहां गत 25 वर्षों से डिस्पेन्सरी चल रही है उसकी बिल्डिंग नहीं बनी हुई है। उस पर ध्यान दिया जाय। जहां मकान बनाये गये हैं वह मकान ठीक नहीं हैं। उनकी ओर तुरन्त ध्यान दिया जाये।

बागोर में दो डॉक्टर की जगह है किन्तु एक डॉक्टर है। वहां आसपास में और कोई जगह नही है जहां लेडी डॉक्टर उपलब्ध हो। वहां पर एक लेडी डॉक्टर को भेजा जाये। शिवपुर एक हजार की आबादी का गांव है, वहां पर एड-पोस्ट की व्यवस्था की जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जिन बातों की ओर मैंने ध्यान आकर्षित किया है सरकार उनकी ओर ध्यान दे। यही कहता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : अध्यक्षजी, किसी बात को बार बार कहा जाये तो आनन्द नहीं आता और लोगों का ध्यान भी आकर्षित नहीं होता। एक बात जरूर है कि डॉक्टरों की पढ़ाई का जो तरीका है, उसके कारण मानव सेवा की जो भावना है वह समाप्त हो गई है और वह एक व्यवसाय बन गया है। डॉक्टरों की बिना पैसे काम नहीं करने की आदतें बन गई है। इसका कारण यह भी है कि कालेज में एम. बी. बी. एस. में भर्ती होने पर उसको पैसा देना पड़ता है और वहां पर जो उसको सीखने को मिलता है,

(श्री रघुनन्दन व्यास)

उसमें सेवा का भाव नहीं मिलता। आयुर्वेद में तो यह है कि :

वैद्यराज नमोतुभ्यं
यमराज सहोदर :
यमस्तु हरते प्राणं
वैद्यो प्राणः धनंजय।

तुम्हारे हाथ में इन्सान के प्राण रहेंगे, तुमको उनकी रक्षा करनी है। ऐलोपैथी की पद्धति में भी ऐसा परिवर्तन लाना चाहिये। आज डॉक्टरों में सेवा का संस्कार समाप्त हो गया है और केवल पैसे का लालच ही रह गया है मरीज मर रहा है लेकिन पहले डॉक्टर को पैसा चाहिये। 'आज 'नंगे पैर डॉक्टर' की बात कही जाती है, इसके साथ ही हमारे डॉक्टरों में जो पैसे लेने की आदत पड़ गई है, उसमें सुधार लाने के लिये हम लोग अगर अभी विचार करें तो आने वाले पांच वर्षों में कुछ परिवर्तन हो सकता है।

दूसरी बात मैं जयपुर के अस्पताल के बारे में कहना चाहूंगा। यहां पर गरीब को तो कोई सुनता ही नहीं, एक कबाड़खाना बना हुआ है। जिला अस्पतालों की बात करें तो उनकी स्थिति भी दयनीय बनी हुई है। वहां पर जो भी डॉक्टर जाते हैं उनमें सेवा भाव नाममात्र भी नहीं होता है। इसको बदलने के लिये हमें सोचना चाहिये और प्रयास करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने जिले की बात कहूंगा। मेरा जन्म तो हुआ जालोर में और एम. एल. ए. का सर्टिफिकेट सिरोही जिले ने दिया है। इसलिये मैं दोनों की थोड़ी-थोड़ी बात करूंगा। सिरोही का जिला अस्पताल 150 बैड्स का बना हुआ है। राज्य सरकार के रिकार्ड में है या नहीं, यह मुझे नहीं मालूम, अगर नहीं है, तो बनाया जाये।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे मन्त्री महोदय सिरोही के अस्पताल को 'बी' श्रेणी का हॉस्पिटल बना दें। अगर भवन सम्बन्धी कठिनाई आई तो हम सरकार को विवश नहीं करेंगे। दानदाताओं के आधार पर यह समस्या हल हो जायेगी। इतना ही नहीं टी. बी. के वार्ड के लिए एक व्यक्ति पैसे देने को तैयार है लेकिन सरकार से स्वीकृति नहीं आई है, स्वीकृति अभी तक नहीं पहुंची। हम यह तो नहीं कहते कि आप पैसा दीजिये। हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, मरीज है किन्तु मरीजों के सोने की व्यवस्था नहीं है। उसके लिए भवन बनाकर दे रहे हैं लेकिन उसकी स्वीकृति नहीं आ रही है। मैं मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस बारे में सोचें और शीघ्र ही स्वीकृति भिजवाने की कृपा करें।

आबू रोड में मेटरनिटी होम बने तीन वर्ष हो गये किन्तु वह खाली पड़ा हुआ है। वहां डॉक्टर नहीं है। सरकार ने उसको अभी तक कब्जे में नहीं लिया। इस कारण जो पैसा लगाया गया उसका उपयोग नहीं हो रहा है। अब यह तय किया गया है कि नगरपालिका क्षेत्र में प्रसूति गृह होगा। प्रसूति गृह वहां पर बना हुआ है, राज्य सरकार उसको कब्जे में ले।

आबू रोड में सभी लोग गर्मियों में जाया करते हैं। दो डॉक्टर हैं, तीसरी लेडी डॉक्टर है। उन तीनों के आपसी झगड़े के कारण वह अस्पताल मच्छीघर बना हुआ है। मरीजों को कोई देखता नहीं, डॉक्टरों के खिलाफ साइक्लोस्टाइल पर्चे बांटे गये लेकिन वे बहुत होशियार हैं। वहां के नेता को पकड़ कर ले

(श्री रघुनन्दन व्यास)

आते हैं, कभी पक्ष में और कभी विपक्ष में। ऐसे समय में शासन की जिम्मेवारी होती है कि एक बार निर्णय लेने के बाद उसको बदले नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की तीस लाख जनता का सवाल है। वहां पर आदिवासी, भील और गिरासिया लोग हैं अगर उनको राहत देनी है तो वहां के डॉक्टरों को आप दूसरी जगह भेज दीजिये। इससे उनका कल्याण होगा और उनका हित होगा, नहीं तो अस्पताल में आज कोई जाना भी नहीं चाहता, रोजमर्रा के झगड़े के कारण अस्पताल अस्पताल नहीं रहा है।

सिरोही जिले में रिवाज बन गया है कि वहां के जिले के ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर हैं लेकिन उन्होंने गन्दी राजनीति के कारण सेवा का पेशा छोड़ दिया है। लोग नाराज होंगे लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिनको आठ-दस वर्ष हो गये हैं उनको आप बदल दीजिये। उनमें गुण होगा तो जहां भी जायेंगे वहां पैसा कमा लेंगे। यह जो कसाई की पद्धति है इसको समाप्त किया जाना चाहिये। करोड़ों रुपया हम खर्च कर रहे हैं,अगर उसका जनता को लाभ नहीं मिले तो उसका कोई उपयोग नहीं होगा। ये मेरे दो निवेदन हैं।

सिरोही के अस्पताल में गन्दगी है, सरकार से निवेदन करूंगा कि उसको मिटाया जाय। पिछली बार भी एक गेंग लगाकर सफाई करानी पड़ी।

एक बात अभी जगदीशसिंहजी ने भी कही थी, एक्स-रे मशीन राजस्थान में घोटाला बनी हुई है। 6-6 महीने खराब रहती है। यह पुरानी सरकार का घोटाला है। एक फर्म से इस मशीन को ठीक करने का समझौता किया था, दूसरा व्यक्ति ठीक भी नहीं कर सकता, उसको सुधार नहीं सकता। इसलिए मैं समझता हूं या तो सारी एक्स-रे मशीनों को निकाल कर किसी ऐसे कुए में डाल दिया जाय जिसमें पानी नहीं हो या उनको ठीक कराया जाय। यह क्या तरीका है मशीन पड़ी हुई है, पैसा दिया हुआ है, प्राइवेट डॉक्टर पैसा कमाते हैं और हमारे पैसे का दुरुपयोग होता है। राज्य सरकार ने किसी फर्म से समझौता कर रखा है कि उसका मिस्त्री ही ठीक करेगा। इतनी मशीनें बन्द पड़ी हुई हैं। राज्य सरकार को चाहिए कि इसका बजट में प्रोविजन करे और कम से कम पांच केन्द्रों पर मशीन ठीक करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति करे। एक्स-रे मशीन और बन्द पड़ी रहे इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। मेरा यह निवेदन है, इस पर विचार किया जाय।

तीसरा निवेदन है जालोर अस्पताल में नया काम कराया जा रहा है। आई वार्ड और बन रहा है लेकिन उसकी जमीन पर गैर कानूनी ढंग से मांस बेचने वाले कसाइयों की दस दुकानें बनी हुई हैं। बड़ी बुरी हालत है हॉस्पिटल के इलाके में। जिला कलेक्टर को भी लिख दिया, सबके मकान बने हुए हैं, लेकिन गैर कानूनी ढंग से कब्जा किये हुए हैं। दो लाख रुपये वहां के व्यक्ति देने को तैयार हैं और इन्तजार कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जालोर के कलेक्टर को बाध्य करें कि जो गैर कानूनी ढंग से बैठे हुए हैं मांस बेचने वाले, जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है, उनको हटावें ताकि पैसे का सदुपयोग हो सके और आंखों का वार्ड बनाया जा सके। इससे जालोर जिले के लोगों को लाभ मिल सकेगा।

(श्री रघुनन्दन व्यास)

दूसरा, भीनमाल तहसील में लोगों ने आठ-दस लाख रुपया इकट्ठा किया हुआ है, वहां पर अस्पताल नहीं है। भीनमाल से जालोर 60 किलोमीटर है, भीनमाल से सिरोही 120 किलोमीटर है और भीनमाल से जोधपुर 140 किलोमीटर है। कहीं पर भी अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। भीनमाल दो लाख की आबादी का केन्द्र है। हम चाहते हैं कि वहां एक रेफरल हॉस्पिटल बनाया जाय। भवन बना देंगे, मानवता की सेवा होगी। जैसा राज्य सरकार ने अपनी नीति में तय किया है कि हर पंचायत समिति में दो डिस्पेन्सरीज देंगे उस आधार पर सिरोही जिले में रेवदर, दांतराई में अस्पताल की आवश्यकता है। अस्पताल भवन बनाकर देने को तैयार हैं। शिवगंज, आबूरोड तहसीलों में एक-एक अस्पताल दे दीजिये। हमने, माननीय अध्यक्ष महोदय, गिरवर में मांग की है, अगर वहां हो जायेगा तो आदिवासियों की सेवा होगी।

आयुर्वेद की काफी आलोचना हुई है, लेकिन मैं बता दूं आयुर्वेद में लगे लोगों में अज्ञान है। आयुर्वेद के डाइरेक्टर महोदय जो हैं, वह हैं ही नहीं, ऐसा कहना चाहिए क्योंकि पद रिक्त है। 9 महीने से यह पद भरा नहीं गया। मैं समझता हूं कि किसी एस० डी० ओ० को ही सौंप दें और यह भी संभव नहीं हो तो डाइरेक्टर, मडिकल को सौंप दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट।

आयुर्वेद के डाइरेक्टर का पद नहीं भरा गया है। आयुर्वेद डाइरेक्टोरेट में इतना भ्रष्टाचार है कि जिले में ही नहीं राजस्थान में कितने ही औषधालय खाली पड़े हुए हैं। उनमें वैद्यों का कोई पता ही नहीं। मेरे क्षेत्र में शिवगंज पंचायत समिति में मांडानी में एक आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी और सिरोही में फूंगनी में एक डिस्पेन्सरी दे दें। हम बिल्डिंग बनाकर दे देंगे, आप आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी दे दीजिये।

मंत्रिपरिषद ने अपनी आलोचना खूब कराई। आलोचना सुनने के लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। जो अच्छी बातें आई उनको वे स्वीकार करें।

"निन्दक नियरे राखिये आंगन कुटी छवाय"

जो बातें सुनने को मिलीं, भलाई म त्रुटियां हुई उनको सावधानी से स्वीकार करना चाहिए। मैंने थोड़ा-सा अधिक समय लिया उसके लिए धन्यवाद देता हूं और यह निवेदन करता हूं कि सिरोही के अस्पताल को 150 बैड्स का, 'बी' श्रेणी का अस्पताल घोषित किया जाय। मैंने जो और बातें कहीं उनको पूरा करवाने की व्यवस्था की जाय ताकि आदिवासियों का कल्याण हो और सेवा हो।

दूसरा जो भ्रष्टाचार का विषय है उसके विषय में चर्चा करने की मेरी इच्छा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल अजीज।

(अनुपस्थित)

श्री रामदेव चौधरी!

श्री रामदेव चौधरी (मूंडवा) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में चिकित्सा विभाग की मांग पर बहस चल रही है। मैंने भी मेडिकल विभाग की मांग पर दो-तीन कट मोशन दिये हैं। वैसे तो यहां पर बैठे करीब-करीब सभी माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार

(श्री रामदेव चौधरी)

के बारे में कहा है लेकिन में इसके बारे में अधिक नहीं बोलना चाहता हूं। मैं तो, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार को भ्रष्टाचार के बारे में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार केवल पैसों के लेने-देने में ही नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के और भी कई रास्ते हैं। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मेडिकल विभाग में डॉक्टरों और शिक्षा विभाग में टीचर्स के ट्रान्सफर्स को बिना किसी भेदभाव से आप करें तो भ्रष्टाचार आधे से अधिक तो यों ही समाप्त हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे मूण्डवा, जिला नागौर में एक अच्छा डॉक्टर था उसको बिना किसी कारण के ही बदल दिया गया। एक अच्छा सर्जन था उसको बदल दिया गया। एक लेडी डॉक्टर थी उसकी जगह खाली है। एक लेडी डॉक्टर का ट्रान्सफर टी.बी. अस्पताल में कर दिया गया है। दूसरी लेडी डॉक्टर को हटा दिया गया। इसके अलावा वहां दूसरा सर्जन नहीं होने से और तीन चार डॉक्टरों की पोस्ट्स भरी नहीं जाने के कारण अस्पताल में बहुत ही हालत खराब है। अध्यक्ष महोदय, बारानी में पी.एच.सी. में अच्छा सर्जन था। लोग नागौर से अपना इलाज कराने के लिये आते थे लेकिन राज्य सरकार ने दो-तीन लड़कों के कहने से उस अच्छे सर्जन का ट्रान्सफर कर दिया। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उस डॉक्टर को ट्रान्सफर ऑर्डर जो दिये गये वह उसको हाथों हाथ दिये गये। वहां की ग्राम सभा की सील लिफाफे पर लगा कर उसे आर्डर दिया गया। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या मेडिकल डाइरेक्टोरेट में काम काज देखने वाला बिल्कुल ही कोई नहीं है। मैंने उस लिफाफे के ऑर्डर को पढ़ा था। उसमें लिखा था, डाक्टर साहब हमने आपका ट्रान्सफर करवा दिया है। मेरे पास उसकी फोटो कॉपी पड़ी है, अध्यक्ष महोदय। इसकी जांच भी, अध्यक्ष महोदय, नागौर के चीफ मेडिकल एण्ड हैल्थ ऑफिसर ने की है। पर जांच में सही पाये जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। तो मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से चिकित्सा विभाग के मंत्री महोदय से और जनता सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या आपकी सरकार में यही न्याय मिलता है? अगर इस तरह की कार्यवाहियां जनता सरकार के राज्य में होती रहीं तो फिर जनता इस सरकार से क्या न्याय की उम्मीद कर सकती है?

अध्यक्ष महोदय, आज हमारे यहां अस्पताल में ऐसी स्थिति है कि इतना बजट राज्य सरकार दवाओं पर खर्च करती है फिर भी अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब सरकार तीन किलोमीटर में पोलिंग बूथ डिक्लेअर कर सकती है तो क्या सरकार ऐसे आदेश नहीं कर सकती है कि गांव के अस्पताल के पांच-सात किलोमीटर पर दवा की दुकान जरूर मिलनी चाहिये। इन्जेक्शन जरूर मिलने चाहिये। इसके लिये तो आप साधन कर दें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि बहुत ही खतरनाक हैं उनके लिये तो कम से कम यह व्यवस्था होनी ही चाहिये। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे टिटेनस है। टिटेनस के मरीज के इलाज के लिये तो दवाइयां फ्री मिलनी चाहिये। आप सभी जानते

(श्री रामदेव चौधरी)

हैं कि टिटेनस की बीमारी में रोजाना एक व्यक्ति को 100-200 रुपये की दवाइयां लेनी पड़ती हैं। ऐसी हालत में जब कोई गांव का मरीज अस्पताल में जाता है तो डाक्टर साहब कहते हैं कि दवा नहीं है बाजार से ले आओ। अब गांव का गरीब व्यक्ति कहां से दो सौ रुपये रोज की दवा लावे। तो वह तो मरेगा ही। तो मेरा निवेदन है कि आखिर आपने यह अस्पताल क्यों खोले हैं जबकि आपके पास दवा नहीं है। आज स्थिति यह है कि अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवा नहीं है। कम्पाउडर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, और तो और ए.पी.सी. और कुनैन जैसी बहुत ही जरूरी दवाइयां तक अस्पताल में नहीं मिलती हैं, पट्टियां नहीं मिलती हैं। इन्जेक्शन नही मिलते हैं। तो यह हालत है, अध्यक्ष महोदय, आज जो करोड़ों रुपये की दवाओं की पर्चेज सरकार कर रही है वह सारी दवाइयां बाजार में बेच दी जाती हैं और जनता के धन का मिसयूज होता है। वहां पर, अध्यक्ष महोदय, दवा मिलेगी भी तो उसको मिलेगी जो कि मेडिकल रिम्बर्समेन्ट कराता है या उनको फ्री दवाइयां मिलेंगी जो कि आप हम जैसे विधायक या सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी हैं जो ही ऐसे भाग्यशाली लोग हैं उनको दवा फ्री मिलती है। इनमें से ऐसे लोग हैं सैकड़ों की तादाद में जो कि हर माह 500-700 रुपये के फर्जी बिल दवाओं के बनाते हैं। जो दवा होती है उनको बाजार में अस्पताल वाले बेच देते हैं और फर्जी बिल बनाते है। इस प्रकार दवाओं को गरीब जनता नहीं ले सकती है। इसलिये मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस पर अंकुश लगाइये। नहीं तो जनता का भला नहीं होने वाला है।

इसके अलावा मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर किसी के चोट लगती है तो उसको पट्टी तो चाहिये ही पर अस्पताल में पट्टी नहीं मिलती है। टिन्चर आयोडिन नहीं मिलती है। ए.पी.सी. नहीं मिलती है। दवा नहीं मिलती है किसी भी प्रकार की। डाक्टरों के पास जाते हैं दवाओं के लिये तो यह कहा जाता है कि अभी तक डाइरेक्टोरेट से दवाओं की सप्लाई नहीं आयी है। दूसरा कोई भी व्यक्ति जाता है तो यह कहा जाता है कि बाजार से खरीद कर ले आओ। डाइरेक्टोरेट से जब दवाइयां आती हैं तो ऐसी आती है जिनकी डेट निकल जाती हैं। मैं खुद दो तीन बार अस्पताल गया वहां पर मैंने देखा कि एक व्यक्ति के प्लास्टर चढ़ाने के लिये पट्टियों के लिये 20 रुपये दिये। आज स्थिति यह है, अध्यक्ष महोदय, नागौर अस्पताल में कोई सर्जन नहीं है। मेरे खुद के प्लास्टर हुआ। वहां पर डाक्टर था पर प्लास्टर खुला नहीं था तो एक हरिजन ने मुझे पकड़ा और फिर मेरा प्लास्टर खुला आज आपके यहां पर यह हाल है। आज एक्स-रे की मशीन है तो कोई उसे काम में लेने वाला नहीं है। आखिर उसका क्या फायदा। तो मेरा यही निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, कम से कम जिला हैडक्वार्टर के अस्पतालों में तो पूरी व्यवस्था होनी चाहिये। सरकार को ध्यान होना चाहिये कि कम से कम डाक्टर और कम्पाउन्डर तो हो, अस्पताल में दवा तो मिलनी चाहिये। कुनैन और इंजेक्शन तो मिलने चाहियें। मलेरिया की दवा तो मिलनी चाहिये। बस इतना ही कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो चार पांच सुझाव आपके माध्यम से राज्य

(195)



(श्री रामदेव चौधरी)

सरकार को दिये हैं उनकी ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जावे। जहां तक हो सके गांवों में दवाओं की व्यवस्था होनी चाहिये। और तो और आज से चार पांच साल पहले जो नागौर जिले के पांच सात अस्पताल को अपग्रेड करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया था उसे क्रियान्वित करने की कृपा करें।

बस धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री फतहसिंह।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : अध्यक्ष महोदय, हर भूतपूर्व सैनिक के जीवन का प्रत्येक क्षण अनुशासनबद्ध रहता है फिर भी यहां पर इस छोटे जीवन में...

(व्यवधान)

यदि मैं, अध्यक्ष महोदय, आज थोड़ा समय का उल्लंघन करूं तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं।

मान्यवर, हमारे यहां एक पुरानी कहावत है पहला सुख निरोगी काया। अतः प्रत्येक व्यक्ति को निरोग और स्वस्थ रखना जनता की प्रतिनिधि सरकार का प्रथम दायित्व है। श्रीमान, बजट से मालूम हुआ, इस वर्ष यानी 1978-79 में विकास के लिये 507 करोड़ और 84 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे। उसमें से चिकित्सा के लिये हमारी सरकार ने सिर्फ 32 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान इस साल में किया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि चिकित्सा के लिये 32 करोड़ रुपये की धनराशि बहुत ही अपर्याप्त है। श्रीमान, मैं निवेदन करूंगा कि इसको बढ़ाया जाय। श्रीमान, इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि 32 करोड़ रुपये में से 26 करोड़ रुपये तो एलोपैथी चिकित्सा के ऊपर राज्य सरकार खर्च करेगी और 6 करोड़ रुपये होम्योपैथी, यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा पर हमारी सरकार खर्च करेगी। श्रीमान्, हम सभी यह जानते हैं कि एलोपैथी की चिकित्सा बहुत ही महंगी चिकित्सा पड़ती है। यदि हम हमारे गांवों में देशी पद्धति की दवाओं से इलाज करावें तो ज्यादा फायदा हो सकता है। इसके लिये, श्रीमान्, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार को चाहिये कि होम्योपैथी, यूनानी और आयुर्वेदिक दवाओं के लिये अधिक प्रावधान करना होगा।

श्रीमान, आज राजस्थान में जो गांवों में अस्पताल हैं उनकी हालत बहुत ही खराब है। वहां पर कोई भी प्रकार की दवाइयां उपलब्ध नहीं होती हैं। डॉक्टर लोग मरीजों को चिकित्सा के प्रेस्क्रिप्शन लिख देते हैं और कह देते हैं कि दवा बाजार से खरीद कर ले आओ। अब गरीब आदमी कहां से दवा लावे जब कि बाजार में दवा उपलब्ध नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जख्मों के लिये पट्टी तक अवेलेबल नहीं होती है। मुझे, श्रीमान, विश्वस्त सूत्रों से यह भी ज्ञान हुआ है कि राजस्थान सरकार ने दो माह पहले पट्टियों के लिए ऑर्डर दिया था और वह ऑर्डर दिया था, हमारे राजस्थान के हैंडलूम बोर्ड को। पर ऐसा सुना है कि हैंडलूम बोर्ड 30 लाख की पट्टियों की सप्लाई नहीं कर पा रहा है या यों कहिये कि हैंडलूम बोर्ड ने पट्टियों की सप्लाई नहीं की है। तो मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर हमारे हैंडलूम बोर्ड के पास पट्टियां

(मेजर श्री फतहसिंह)

उपलब्ध नहीं हैं तो आप दूसरी तरफ से लाइये, आप दूसरे साधन की ओर जाकर पट्टियों की व्यवस्था करें। आप राजस्थान हैंडलूम बोर्ड के सहारे ही नहीं बैठे रहें।

श्रीमन् वर्ष 1977-78 में परिवार कल्याण पर 3,79,30,000 रुपया खर्च हुआ और उसमें नसबन्दी के ऑपरेशन दस हजार हुए। मैं समझता हूं कि यह टार्गेट बड़ा पूअर है, कमजोर है। वर्ष 1978-79 में 5,74,00,000 रुपया खर्च होने वाला है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस आने वाले वित्तीय वर्ष में आपका लक्ष्य नसबन्दी का कितना है ?

श्रीमन् यह, बात सही है कि नसबन्दी में ज्यादतियां हुई थीं इस वजह से हम लोगों को इस ओर अधिक संख्या में बैठने का अवसर मिला। इसको स्वीकार करना चाहिये। हम सब लोगों को यह महसूस करना चाहिये कि हमारे देश की, हमारे प्रदेश की जनसंख्या बढ़ रही है उसको हमें सीमित करना है। अगर हम सीमित नहीं करेंगे तो वह समय दूर नहीं है जब यह हमारा देश और यह प्रदेश भिखमंगों का देश प्रदेश बन जायगा। इसलिये इस ओर सरकार पूरा ध्यान दे। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि इस साल आपका लक्ष्य कितनी नसबन्दी करने का है ?

श्रीमन् मैं सरकार की एक नीति के चित्र की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मुझे विशेष रूप से यह ज्ञात हुआ है कि डा. एस. एल. माथुर, जो ई.एस.आई., जयपुर में कार्यरत हैं और डॉ. जाजू, जो सी.एम.एच.ओ. के पद पर काम कर रहे हैं, के खिलाफ तीन वर्ष से डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी चल रही है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं और वे ही पर्चेज कमेटी के मेम्बर हैं। जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं वे क्यों पर्चेज कमेटी के मेम्बर रहें ?

श्रीमन् मैं अपने कटौती प्रस्तावों की ओर आना चाहता हूं। श्रीमन् मैं संक्षेप में ही बताऊंगा। श्रीमन् भीम एक सबसे नेग्लेक्टेड उप-जिला हैडक्वार्टर है। वहां पर एक ही डॉक्टर है। श्रीमन्, वहां पर एक महिला चिकित्सक की नियुक्ति की जाय।

श्रीमन्, बरार और देवगढ़ पंचायत समितियां हैं। वहां पर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र हैं। महिला चिकित्सक वहां नहीं हैं इसलिये महिला चिकित्सक की नियुक्ति आवश्यक है। देवगढ़ में एक वर्ष से महिला चिकित्सक नहीं है इसलिये देवगढ़ की 12 हजार की जनता पीड़ित है। मैं इसके विवरण में अधिक नहीं जाना चाहता। ब्यावर में एक सफाखाना है। वहां पर एक फौज की फौज मेल और फीमेल डॉक्टर्स की है। पति-पत्नी एक साथ एक जगह पर नियुक्त हैं। ऐसे स्थानों पर जहां महिला चिकित्सकों की आवश्यकता है वहां इन पति-पत्नी डॉक्टर्स को भिजवाने की व्यवस्था करें।

श्रीमन्, देवगढ़ 12 हजार की आबादी का नगर है। यहां पर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र है। इस वर्ष 1978-79 में सरकार कुछ रेफरल अस्पताल खोलने का इरादा कर रही है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि देवगढ़ कस्बे में जो प्राइमरी हैल्थ सेन्टर है उसको क्रमोन्नत करके, बड़ा करके रेफरल हॉस्पिटल बनाने की कृपा करें। भीम में हाई स्कूल है, पुलिस स्टेशन है, उप-जिला केन्द्र है। बहुत बड़ा गांव है। एक ही डाक्टर का

(मेजर श्री फतहसिंह)

चिकित्सालय हैं अत: इसको क्रमोन्नत किया जाय।

हमारी सरकार ने इस नीति की घोषणा की है कि प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में एक प्राइमरी हैल्थ सेन्टर होगा, दो चिकित्सालय होंगे, डिस्पेन्सरीज होंगी और एक एड-पोस्ट होगी। भीम सब-डिविजन में दो पंचायत समितियां हैं। भीम में सिर्फ एक प्राइमरी हैल्थ सेन्टर है और एक डिस्पेन्सरी है। श्रीमन्, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि आपने बगड़ में एड-पोस्ट स्थापित करने की मंजूरी गवर्नर साहब से दिला दी। बार गांव में एक डिस्पेन्सरी खोलने के लिए कहा गया लेकिन एड-पोस्ट्स और डिस्पेन्सरीज की सूची जब मैंने देखी तो उसमें बार गांव नहीं है। बार गांव भीम डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से 35 मील दूर है। जंगल में पड़ा है। मीलों तक कोई सफाखाना नहीं है। वहां के लोगों को या तो बदनोर जाना पड़ता है या भीम आना पड़ता है। किसी को सांप काट खाने पर या किसी के कुए में पड़ जाने पर या तो उसे ब्यावर ले जाना पड़ता है या बदनोर, जसोर या भीम ले जाना पड़ता है। इसलिये बार गांव में भी एक डिस्पेन्सरी खोलने की व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक है।

मैं सरकार को और चिकित्सा मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि देवगढ़ पंचायत समिति में कुआंथल में डिस्पेन्सरी और मदारिया में एड-पोस्ट्स खोलने की सरकार से अनुमति दिलायी।

श्रीमन् मैं पांच मिनट और लेना चाहूंगा।

आज या पिछले कई दिनों से उस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य जनता सरकार और जनता पार्टी की आलोचना करते आ रहे हैं। जनता सरकार और जनता पार्टी के छिद्र ढूंढ कर आलोचना कर रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं और खास तौर से उनको कहना चाहता हूं जो सरकारी बैन्चेज पर बैठे हुए हैं, उनकी आलोचना ने मुझे फिर से प्रेरित किया है इतिहास के पन्नों को उलटने के लिये। मैंने इतिहास के पन्ने उलटे और मैंने देखा। श्रीमन्, बैटल ऑफ ट्रैफलगार सन् 1806 में हुआ और नैलसन उसके कमान्डर थे। उन्होंने उस वक्त जनता को कहा:

"Who lives if England dies, and who dies if England lives."

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जो इस ओर बैठे हुए हैं कि "Who lives if Janta Party dies, and who dies if Janta Party lives." इसलिये आप अपने व्यक्तिगत हित को सामने न रखते हुए जनता पार्टी और जनता के हित को सर्वोपरी रखने का संकल्प करें।

इतिहास के पृष्ठों को और आगे ले जाना चाहता हूं, श्रीमन्। जब अमेरिका में सिविल वार चल रही थी और देश बड़े संकट में से गुजर रहा था तब उस समय के अमेरिका के प्रेसिडेन्ट अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था।

(व्यवधान)

उन्होंने अमेरिकन राष्ट्र को एक संदेश दिया जिसका मेरे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैं चाहता हूं भारत का प्रत्येक नागरिक और जनता पार्टी का प्रत्येक माननीय सदस्य 150 वर्ष पहले कहे हुए अब्राहम लिंकन के शब्दों को याद करें। मैंने लिंकन का इतिहास पढ़ा तो मुझे

(मेजर श्री फतहसिंह)

बात याद आ गई। अब्राहम लिंकन ने यह कहा अपने संदेश में :

"At what point shall we expect the approach of danger ? At what point shall we fortify against it ? Shall we expect some trans-Atlantic military giant to step the ocean and crush us at a blow ?"

He says, "Never. All the armies of Europe, Asia and Africa combined together could not by force take a drink from Ohio or make a track on the Blue Ridge in the trial of strength of a thousand years."

"At what point then shall we expect the approach of danger ?" I answer,"

He says, "If the danger ever comes, it will not come from abroad; it will spring up from amongst ourselves. As a nation of free men, we should either live united or die by suicide".

इसलिये आप लोगों को सलाह देता हूं कि उस महान व्यक्ति के शब्दों को याद रखें। इस जनता सरकार को और जनता पार्टी को न तो कांग्रेस (ओ) से खतरा है, न कांग्रेस (आई) से खतरा है, न सी. पी. आई. से खतरा है, न. सी. पी. एम. से खतरा है। यदि खतरा है तो वह अपने अन्दर ही व्याप्त है। इसलिए हम अपने घटकवाद से ऊपर उठें तो हम जिन्दा रह सकेंगे नहीं तो कदापि नहीं।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री बिरदमल सिंघवी !

(अनुपस्थित)

श्री हरजीराम बुरडक !

(अनुपस्थित)

श्री भैंरवलाल कालाबादल !

एक माननीय सदस्य : आज भी बरसोगे ?

श्री भैंरवलाल कालाबादल (खानपुर) : आज तो मेरा ऐसा मूड नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, अभी एक माननीय सदस्य मेजर साहब ने कहा था कि पहला सुख निरोगी काया। हमारी गांव की जनता, गांव के परिवार यदि निरोग रहेंगे तो हमारे घर, परिवार सुखी हो जायेंगे। आज, अध्यक्ष महोदय, मैं हमारी जनता पार्टी के मंत्रिमण्डल के सदस्यों से यह कहना चाहूंगा कि एक समय हमारी यह भारतमाता मुसीबतों में पड़ी हुई थी। इस भारतमाता के कई पुत्र इसकी मुसीबतों को हल करने के लिए फांसियों पर चढ़ गये, कई बलिदान हुए और अपनी सन्तानों के लिये, भारतमाता के बचे हुए शेष पुत्रों के लिए वह एक खेत बोकर हरा-भरा करके खेत छोड़ गये। उस खेत की रखवाली करने की जिम्मेदारी हमारे महात्मा गांधी के अनुयायी ने यह समझ कर ली कि वह इस खेत की रखवाली करेंगे। उन्होंने खेत को सींचा नहीं और उस फसल को उजाड़ने में लग गये। जब फसल उजड़ रही थी महात्मा गांधी के बोये हुए खेत की तो मैं उस जमाने में कहता था हमारे साथि

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

को कि गांधी बाबा खेत बोकर गये हैं, तुम इस फसल को मत उजाड़ो। पर मेरी एक न सुनी। नतीजा यह हुआ कि बाढ़ ही खेत को खाने लगी। आगे और नतीजा यह हुआ कि हरा-भरा खेत गांधी जी का उजड़ गया।

(9.50 रात्रि)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तो उधर जाने वाले उजड़ा हुआ खेत हमारी पांती में छोड़ गये। अब इस उजड़े हुए खेत में हम नया पौधा लगा रहे हैं। इन्होंने तो उजाड़ दिया और उजड़ा हुआ खेत जनता पार्टी की सरकार के अधिकार में आया है। अब इस उजड़े हुए खेत को किस बुद्धिमत्ता के साथ हमको हरा भरा करना है, यह हमारी जनता पार्टी के जिम्मेदार मंत्रिमण्डल के सदस्यों को देखना है। हमारा उजड़ा हुआ खेत किस प्रकार से हरा-भरा हो जाये और गांधीजी का नाम अमर बना रहे, यह काम हमको करना है। इन्होंने भी गांधीजी की समाधि पर शपथ ली है और उधर विरोध में बैठने वालों ने भी पहले गांधीजी की साक्षी में शपथ ली थी। लेकिन उन्होंने अन्टी लगा कर शपथ ली थी क्योंकि अन्टी लगाने के बाद सौगन्ध नहीं लगती। जनत पार्टी के सदस्यों ने शुद्ध मन से शपथ ली है अन्टी लगा कर शपथ नहीं ली है। अगर अन्टी लगाकर शपथ ली होगी तो सच मानिये आपका यह खेत हरा-भरा नहीं रह सकेगा। उजड़ा हुआ खेत हमको मिला, उजड़ा हुआ खजाना हमको मिला है। आज सभी लोगों की एकदम से भूख जागी है। कांग्रेसियों ने तीस साल तक कुछ भी नहीं किया। अब जनता पार्टी से चुनकर हम आये हैं। यहां के नेताओं को लगातार हम देख रहे हैं, चाहे इधर से खड़े हों या उधर से खड़े हों, वह यही कहते हैं कि हमारे यहां दवाइयां नहीं हैं, डाक्टर नहीं हैं। इधर के भी यही कह रहे हैं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, 30 साल में आज इनको समझ में आया है। लाखों और करोड़ों रुपयों का बजट खर्च होता आया है और आज भी यही कह रहे हैं। अपनी गलती आज सरकारी अधिकारियों पर डाल देते हैं और उधर से भी उनके ऊपर ही दोषारोपण करते हैं। सरकारी अधिकारी भी किसी विलायत से नहीं आये हैं। वह भी हिन्दुस्तान में ही पैदा हुए हैं। हमारे परिवार के बीच पैदा हुए हैं। उनमें यह बुराई कहां से आई? हम राम के भक्त बनें और काम रावण का करें। हम कृष्ण के भक्त बनें और काम कंस का करें। 30 सालों में तो हम सब के सब कंस बनते चले गये। तो हमारे परिवार में जन्म लेने वाले कंस ही बनेंगे। देवता कैसे बनेंगे। इसलिए अब देवता बनने का मौका सरकारी अधिकारियों को भी आया है और हमारे मंत्रिमण्डल के सदस्यों को और जनता पार्टी के माननीय सदस्यों को भी देवता बनने का मौका आया है। यह इन्हीं के ही हाथ में है। नर से नारायण हो जाता है। यह नर है अब को अगर यह चाहें तो अपने कर्त्तव्य सही करें, ईमानदारी से सेवा करें तो नारायण बन सकते हैं। लोग कहते हैं कि बजट नहीं है। देश की आजादी के लिए जो लोग लड़ रहे थे, उनके पास पैसा नहीं था। घास और साग-सब्जी खाकर आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। सुभाष को देखिये, आजाद हिन्द फौज बना कर दिल्ली चलने का नारा लगा दिया और देश को स्वतंत्र करा दिया। बिना पैसे करा दिया। आज हमारे पास बजट नहीं है। और हमारे

(श्री भैरवलाल कालाबादल)
दिलों में सेवाभावना है, प्रेम है, मोहब्बत है विश्वास है तो बीमार व्यक्ति भी अच्छा हो जाता है। भले ही मरीज मरने वाला है, अगर उसके परिवार के लोग डॉक्टर से पूछें कि डॉक्टर साहब कह तो दो कि क्या होगा और डॉक्टर कह दे कि चिन्ता मत करो, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं मेरी ओर से तो पूरा इलाज कर रहा हूं आगे भगवान मालिक है, तो......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

विश्वास के ऊपर वह जिन्दा रहता है। हमारे मंत्रिमण्डल के सदस्य ईमानदारी से और सच्ची भावना से जनता की निःस्वार्थ सेवा करेंगे तो आधी बीमारी तो वैसे ही दूर हो जायेगी। माननीय मंत्रीगण सदस्यों को विश्वास देते रहेंगे तो जनता के काम भी होते रहेंगे और आधी बीमारी भी दूर हो जायगी। मगर ये मंत्री विश्वास नहीं बन्धाते हैं, अभी कह रहे थे मंत्री के दरवाजे ऐसे हैं जैसे भगवान के दरवाजे भगवान के दरवाजे पर तो कुछ मिलता है और कुछ भी नहीं मिलता है तो कम से कम चरणामृत तो मिलता है मगर मंत्रिमण्डल के इन सदस्यों के दरवाजे पर तो वह भी नहीं मिलता। हम तो मंत्रिमण्डल के दरवाजे पर गये लेकिन कुछ भी लेकर नहीं आये। इस तरह की निराशा लेकर आयेंगे तो हमारी निराशा बढ़ती जायगी। उसमें क्या डॉक्टर करेगा और क्या मंत्रिमण्डल करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं लम्बा नहीं जाऊंगा। मैं यही प्रार्थना करके बैठ जाऊंगा कि किस रोज मंत्री घोषणा करेंगे कि फलां फलां जगह डिस्पेन्सरी खोलेंगे। मैं तो यही समझ बैठा था कि फलां तारीख तक घोषणा होगी। मैं तो भ्रम में ही बैठा था लेकिन अब मुझे चिन्ता हो गई। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं मेरे क्षेत्र में शफाखाने में एक गाड़ी है, उपाध्यक्ष महोदय, मरीजों को लाने-ले जाने की। हरीगढ़ में अभी झगड़ा हो गया बन्दूकें चलीं, वह जीप टूट गई...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जीप मरीजों को लाने ले जाने वाली थी। वह झालावाड़ में पड़ी है। उसको मरम्मत करके शीघ्र भेजिये जिससे मरीजों को सुविधा हो जाय। दूसरी बात यह है कि हमारे गांव में बजट ठीक भेजें। तीसरी बात यह है कि दो बड़े गांव ऐसे हैं खण्डी और नूरजी गाडरवाड़ा जहां 10-15 हजार की आबादी के कई गांव हैं। तो नूरजी गाडरवाड़ा में एक डिस्पेन्सरी तो कायम कर ही दें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। अभी एक डॉक्टर गया है। पहले वहां एक डॉक्टर गुप्ता थे। बहुत अच्छे डॉक्टर थे। एक डॉक्टर पारीक हैं वह निवाई से गये हैं लेकिन उन दोनों में झगड़ा हो गया। वे दोनों आपस में कहते हैं मैं बड़ा डॉक्टर हूं। मैं तो उनको कहता हूं जो अच्छा इलाज करे वह बड़ा डॉक्टर है लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, नहीं मानते हैं। दोनों में आपस में लड़ाई हो गई इस बात पर मैं परेशान हूं। डॉक्टर दोनों अच्छे हैं लेकिन उनमें लड़ाई हो रही है, मैं अब क्या करूं। मैं तो यह समझता हूं बड़े-छोटे का भेदभाव है तो हमारे मंत्री महोदय एक को कहीं और जगह भेज दें। वहां पहले लेडी डॉक्टर थी और अब वहां लेडी डॉक्टर की ही आवश्यकता है। लेडी डॉक्टर की सीट पर आ गया तो वह समझता है बड़ा डाक्टर हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, डाक्टर दोनों अच्छे हैं लेकिन वहां एक लेडी

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

डॉक्टर भेज दें और उस डाक्टर को किसी और जगह भेज दें तो छोटे-बड़े का भेद भी खतम हो जायगा। डाक्टर दोनो अच्छे हैं। शिकायत नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अजीतसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री माधोसिंह !

श्री माधोसिंह (रेवदर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेजर साहब ने अब्राहम लिंकन को एग्जाम्पल दी। जनता पार्टी के अन्दर जो कसमकस है उस पर प्रकाश डाला और यह फर्माया कि जनता पार्टी के सदस्यों को घटकवाद से ऊपर उठ कर और संगठित होकर जनता के लिये कुछ करना चाहिये। मैं मेजर साहब को आपके द्वारा धन्यवाद दूंगा कि वे सही परिस्थिति को जानते हैं।

मेजर श्री फतह सिंह : I am grateful to you.

श्री माधोसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कांग्रेस एक पुरानी संस्था है। कांग्रेस ने इस देश के लिये बहुत किया है, देश का मार्गदर्शन किया है और इसीलिये वह 30 साल तक सत्ता में रही। कांग्रेस ने जनता का भी विश्वास प्राप्त किया।

दूसरी बात कांग्रेस ने और कांग्रेस के लोगों ने यह कभी नहीं चाहा कि..

श्री रतनलाल वर्मा : कांग्रेस के दो टुकड़े कर दिये।

श्री माधोसिंह : कि स्वस्थ जनतन्त्र की परम्पराओं में दूसरी पार्टी को शासन में आने से रोका जाय। मेरा निवेदन है, आप में संगठन नहीं, आप संगठित नहीं हो सके हैं। जो अलग-अलग उसूलों के आदमी थे वे एक नहीं हो सके इसीलिये 30 साल में आप सत्ता में नहीं आ सके। मेरा निवेदन इसलिये है, माननीय मेजर साहब ने कहा था उसके लिये मुझे कुछ कहना चाहिये था इसलिये समय लिया। अब मैं अपने कट मोशन पर आता हूं।

मेरा आपसे निवेदन है जैसे आपकी सरकार बनी उसने सबसे पहला यह प्रोग्राम पेश किया कि बजट ग्रामोन्मुख रहेगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यहां पर पहले सत्र के अन्दर यह घोषणा की थी कि अब से राजस्थान का जितना खजाना है वह ग्रामों की तरफ उन्मुख होगा। माननीय रणजीत सिंहजी ने आंकड़े बताये। मैं उन आंकड़ों को तो दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन जिस तरह शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में धन का बंटवारा किया है वह स्पष्ट है, घोषणा के अनुरूप नहीं है। धन के बंटवारे में आप 25 डिस्पेन्सरीज का तो ग्रामीण समाज के लिये प्रावधान रख रहे हैं और 25 ही शहरी क्षेत्र के लिये रख रहे हैं। 20 प्रतिशत जनता के लिये 25 डिस्पेंसरीज और 80 प्रतिशत जनता के लिये भी 25 डिस्पेन्सरी। क्या इस तरह से ही आप ग्रामों का विकास करना चाहते हैं ? आप शहर में खर्च कर रहे हैं जहां बहुत कुछ हो चुका है। इस तरह आप ग्रामीण समाज के लिये रुपया उण्डेलने की बात कह रहे हैं। क्या ग्रामीण समाज के विकास की आपकी यही व्यवस्था है ?

मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आप यह सोचते है कि कांग्रेस के शासन में कुछ

(श्री माधोसिंह)

गलतियां रही हैं और आप यह सोचते हैं कि कांग्रेस ने ग्रामों में धन पर्याप्त खर्च नहीं किया था तो मैं निवेदन करता हूं जिस तरह की आपने घोषणा की है, उसकी आप पालना भी करिये । आप कथनी और करनी में फर्क मत करिये । ग्रामीण समाज के स्वास्थ्य की समस्या का समाधान आज तक कोई नहीं हुआ है । ग्रामीण समाज में ऐसे-ऐसे गरीब लोग रहते हैं जो गरीबी के कारण अपना पूरा इलाज नहीं करा सकते हैं । आधे बच्चे जन्म से पहले ही मर जाते हैं । उनकी मातायें भी बच्चे के साथ ही मर जाती हैं । उसके बाद तरह-तरह का रोग गांवों में फैलता है, उसके कुप्रभाव से पेट के दर्द, आंखों की बीमारी, आंतों का रोग आदि अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं । इन बीमारियों से, मैं निवेदन करूंगा, ग्रामीणों की अकाल मृत्यु होती रहती है । एक व्यक्ति जो 5/- रु. कमाने वाला है, वह कभी नहीं सोच सकता है कि 15-20 मील जाकर अपना इलाज करवा सके । मेरा आपसे अनुरोध है कि क्षेत्र-वाइज डिस्पेन्सरी खोलनी चाहिये । कहीं से व्यक्ति को 2-3 मील से ज्यादा नहीं जाना पड़े । एड पोस्ट भी उसी हिसाब से देनी चाहिये ताकि पांच मील में या सात मील जाकर ग्रामीण अपनी दवा का इन्तजाम कर सकें । मेरा निवेदन है, मेरा क्षेत्र रेवदर एक पहाड़ी क्षेत्र है, नदी-नालों से घिरा हुआ है और 3-4 महीने तो ऐसा हाल रहता है कि एक-दूसरे गांवों से कट जाता है । वहां अतिवृष्टि होती है, माऊन्ट आबू की वजह से सबसे अधिक वर्षा होती है । सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में भी रेवदर में सबसे ज्यादा होती है । आवागमन के मार्ग कट जाते हैं । यह भी कोई खास बात नहीं है अगर एक आदमी स्वस्थ रह सके । स्वस्थ रह कर ही वह कोई उत्पादन के काम कर सकता है और देश की प्रगति में सहयोग दे सकता है । ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूं कि राजाओं के टाइम में एक डिस्पेन्सरी खुली थी, उसके बाद आज तक नहीं खुली । यह ऐसा क्षेत्र है जहां बरसात में गांव एक दूसरे से बिल्कुल कट जाते हैं । सब जगह पानी भर जाता है । उपाध्यक्ष महोदय, बरसात में ही ज्यादा बीमारियां होती हैं । मेरे क्षेत्र के अन्दर एक दांतराई गांव है, सिरोही से आने वाले विधायक ने भी अनुरोध किया है, दांतराई क्षेत्र मेन सड़कों से 15 मील दूर है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट और दीजियेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : ज्यादा समय नहीं लीजियेगा ।

श्री माधोसिंह : मेरा निवेदन है कि दांतराई क्षेत्र की 4।। हजार की पॉपुलेशन है । उसके चारों तरफ का एरिया है उसमें 20 गांव हैं । वहां कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है । इस बात का अनुरोध करूंगा कि वहां के सेठ धन देने के लिये तैयार हैं । आप चाहेंगे तो बिल्डिंग बनाने को तैयार हैं, जो कहेंगे, औजार देने को तैयार हैं और सुविधायें साल दो साल के लिए देने को तैयार हैं । यह ऐसा क्षेत्र है जो बिल्कुल कटा हुआ है, जहां कोई सुविधा नहीं है, जो 42 मील जिला मुख्यालय से पड़ता है । रेवदर पंचायत समिति हैडक्वार्टर भी है । पी. एच. सी. वहां से 15 मील दूर है,

(श्री माधोसिंह)
वह पहाड़ी क्षेत्र है, और स्वास्थ्य सेवाओं से उपेक्षित है। आप इसकी व्यवस्था करें।

दूसरा आपसे मेरा अनुरोध है, आबू पंचायत समिति आदिवासी क्षेत्र है। आदिवासी क्षेत्र होने की वजह से आदिवासी उत्थान योजना लागू हुई है। किन्तु आबू रोड के सिवाय पंचायत समिति में कोई डिस्पेन्सरी नहीं है। गिरवर के अन्दर आप डिस्पेन्सरी का इन्तजाम करने की व्यवस्था करें जिससे पंचायत समिति का पश्चिमी क्षेत्र उपेक्षित नहीं रहे।

इसके अलावा मेरा निवेदन है कि हमारे क्षेत्र के अन्दर गत वर्ष रायपुर, जैतवाड़, लूनोल, गुलाबगढ़ में आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने के आदेश हुए थे। वह कैन्सल कर दिये थे। लूनोल व जैतवाड़ ग्राम में जो अस्पताल कायम रखे थे उन अस्पतालों के लिये न कोई वैद्य आया और न इलाज शुरू हो रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है जिस जगह अस्पताल खोले हैं उस जगहों पर दवाइयों का और वैद्यों का इन्तजाम तो कर दीजिये।

पी. एच. सी. के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, कहीं पी. एच. सी. दस साल से रन कर रहे हैं, कहीं पांच साल से रन कर रहे हैं, कहीं थोड़ा ज्यादा पीरियड भी हो सकता है, आज वहां यह स्थिति बनी हुई है कि लम्बे अर्से से बजट में 6 हजार रुपये का प्रावधान है। पहले भी सत्र में निवेदन कर चुका हूं कि जब तक पंचायत समिति या पंचायत समिति के लेवल पर दवाइयों का इन्तजाम पर्याप्त नहीं होगा ..

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तब तक गरीब जनता किस तरह से फायदा उठायेगी। इसलिये 6 हजार की थोड़ी-सी राशि है उसको बढ़ाकर 15 हजार करें। दूसरा सुझाव यह भी है कि जो पैसा मिले वह पी. एच. सी. के अन्दर खर्च होना चाहिये। सी. एम. ओ. के द्वारा पास होने में चार छः महीने में फार्मेलिटी पूरी होकर दवाई पहुंचती हैं। इस तरीके की स्थिति है पहले की सरकार को आप दोष दे हम सकते हैं हम आपको दे सकते हैं। इस प्रकार आरोप-प्रत्यारोप को छोड़कर सदुपयोग कीजिये पैसे का........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और सब लोगों को समान सुविधायें दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नारायण सिंह !

(अनुपस्थित)

श्री सुरेशकुमार !

श्री सुरेशकुमार : उपाध्यक्ष महोदय, यदि एक साल से लेकर बारह साल तक के बच्चों को मताधिकार होता तो राजस्थान की सरकार ही नहीं बल्कि, श्रीमान्, देश की सारी सरकारें पलट गई होतीं। देश में एक साल से लेकर बारह साल तक के 40 प्रतिशत बच्चे हैं, 30 प्रतिशत के अन्दर पुरुष और 30 प्रतिशत के अन्दर महिलायें हैं। तो, श्रीमान्, 40 प्रतिशत आबादी की इस देश के अन्दर इस कदर उपेक्षा है जिसकी कोई सीमा नहीं। श्रीमान्, आपके ही विभाग ने यह आंकड़े दिये हैं कि रोगी शय्यायें 1977 में 16405 हैं और मातृ शिशु कल्याण के लिए केवल 2177 हैं। श्रीमान्, हाल ही में यू. एन. ओ. रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें यह कहा गया है कि बच्चों की उचित देख-भाल न होने और पौष्टिक आहार न मिलने

(श्री सुरेशकुमार)

के कारण मानसिक विक्षिप्तता के शिकार होते हैं। अधिक जो मानसिक रोग के शिकार होते हैं वह बचपन में अच्छी चिकित्सा और अच्छी तरह से देखभाल न होने की वजह से होते हैं। श्रीमान्, जब देश की 40 प्रतिशत जनता की घोर उपेक्षा हो, तो देश विकास की ओर नहीं जा सकता। श्रीमान, जयपुर बहुत बड़ा शहर है, बहुत खर्चा होता है इस पर, लेकिन फिर भी कुल 50 बेड हैं शिशु कल्याण के लिये और बीकानेर में 60 बताये जाते हैं तो फिर जिला और देहात के अन्दर क्या हाल होगा, यह आप समझ सकते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर वास्तव में सुधार करना चाहते हैं और जनता को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो 40 प्रतिशत जनता की तरफ ध्यान दें। सरकार को सुझाव दूंगा कि चिकित्सा का अधिकाधिक बजट शिशु कल्याण और मातृ सेवा की तरफ लगायें तो अधिक अच्छा होगा। हर जिले में एक बाल विशेषज्ञ अवश्य रखा जाय।

श्रीमान्, जहां मेडिकल कॉलेज हैं, जो बड़ा शहर है वहां तो आपने डॉक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस समाप्त कर दी। पे-क्लीनिक का सिस्टम आपने शुरू कर दिया। जिलों में हमको उनकी दया पर छोड़ रखा है। अस्पताल का काम कम देखते हैं, प्राइवेट प्रेक्टिस के अन्दर ज्यादा समय लगाते हैं। जो प्राइवेट प्रेक्टिस का पैसा देता है उसी मरीज को अस्पताल में भर्ती करने को प्राथमिकता मिलती है। मेरा यह निवेदन है कि सारे जिलों से प्राइवेट प्रेक्टिस समाप्त कर देनी चाहिये। जैसे पे-क्लीनिक शहरों में रखे हैं, वह जिलों में चालू कर दें तो वहां की जनता को लाभ होगा।

श्रीमान्, भाई बजरंगलालजी ने कहा है, केवल उन्हीं ने ही ध्यान आकर्षित किया है कि आप मेडिकल कॉलेजेज में उतने ही लोगों को प्रवेश दें, जितने लोगों को रोजगार देने की योजना आपके पास हो उनको कुछ प्रतिशत अधिक दे दें जो प्राइवेट प्रेक्टिस में चले जायें। तकनीकी बेरोजगारों की संख्या न बढ़ायें। मैंने सुना है कोटा में एक नया मेडिकल कॉलेज और खुलने जा रहा है। मैं चाहूंगा, श्रीमान्, सरकार धन बरबाद न करें। आवश्यक सेवाओं के लिये जयपुर के कॉलेज को पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स बना दें जिससे विशेषज्ञों की सेवायें अपने यहां प्राप्त हो जायें। विशेषज्ञों को जिलों में भी भेजें। श्रीमान्, विशेषज्ञ जिलों में भी होने चाहिये.........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जिले की जनता ने कोई अपराध नहीं किया है।

आखरी बात मैं अपने क्षेत्र के विषय पर कह दूं वरना मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग कहेंगे कि हमारे बारे में नहीं कहा, केवल जयपुर-अजमेर की बात कहते रहे।

श्रीमान्, भरतपुर में एक अस्पताल है जो बाबा आदम के जमाने का बना हुआ है। न तो कांग्रेस ने उसमें बढ़ोतरी की और न जनता सरकार ने उसमें कोई तरक्की की है। इस बजट को देखते हुए कोई विशेष तरक्की होने की संभावना भी नजर नहीं आती है। न ढंग का ऑपरेशन थियेटर है न वार्ड ढंग के हैं। सारा इलाका गंदगी में अटा पड़ा है। वहां का अस्पताल पूरा कबूतरखाना है। जनाना अस्पताल है वह पूरा चिड़ियाघर है श्रीमान्, बावजूद इसके कि यह कबूतरखाना, चिड़ियाखाना है आप कानून बनाते हैं, आप

(श्री सुरेशकुमार)

नियम बनाते हैं कि रेशनेलाइज्ड पैटर्न पर स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी । परन्तु भरतपुर का यह अस्पताल इन सब नियमों कानूनों से भी महरूम है । यह सारी लिस्ट पढ़ कर कि भरतपुर के अस्पताल में कितने डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड सर्वेन्ट की कमी है, मैं आपका और सदन का समय बरबाद नहीं करना चाहता हूं। मंत्रीमहोदय को अलग से दे दूंगा । मैं तो यह चाहता हूं, श्रीमान्, भरतपुर की ओर ध्यान दिया जाए । मैं सरकार को दोष नहीं देता क्योंकि वह जगह ही ऐसी है और विकास की गुंजाइश नहीं है। मेरा सुझाव है कि इस इलाके की जो बिल्डिंग्स हैं, इस इलाके की जो जमीन है, उसको सरकार बेच दें । वहां मार्केट काम्पलेक्स बना दें, मंडियां बना दें । इससे इतना रुपया आ जाएगा कि भरतपुर में उस रुपये से नया अस्पताल बन सकता है । अगर सरकार गंभीरता से मेरे सुझाव पर गौर करे, ध्यान दें तो भरतपुर को एक अच्छा नया अस्पताल मिल सकता है । धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष :श्री प्रद्युम्नसिंह

(अनुपस्थित)

श्री ईश्वरचन्द्र !

(अनुपस्थित)

श्रीमती नारंगीदेवी !

(अनुपस्थित)

श्री शिवचरणसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण चौधरी !

(अनुपस्थित)

श्री करतार सिंह !

श्री करतारसिंह (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष, आज सदन के माननीय सदस्यों ने अपनी नाराजगी जाहिर की कि गांवों की उपेक्षा की गई है । इसमें कोई दो राय नहीं है । पिछली कांग्रेस सरकार ने तीस साल के अन्दर जो कुछ भी मेडिकल का बजट था, वह सब या तो शहरों में खर्च किया या वहां पर खर्च किया जहां पर कि उनके चाटुकार थे । स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि किसी-किसी गांव में दो-दो, तीन-तीन अस्पताल हो गये और कहीं 30-40 मील पर कोई अस्पताल नहीं खोला गया । मैं भी इस बात से पूर्ण सहमत हूं कि पिछले तीस सालों में निश्चित् तौर पर गांवों की उपेक्षा की गई है । मैंने मेडिकल विभाग की रिपोर्ट देखी तो थोड़ी खुशी हुई कि जनता सरकार ने गांवों की ओर चिकित्सा के क्षेत्र में कारगर कदम उठाए हैं । हालांकि यह प्रयत्न कम है फिर भी पूर्ण विश्वास है कि यह निश्चित रूप से अपने समय में अपना बजट गांवों की ओर बढ़ायेगी ।

मान्यवर, कुछ मैंने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं । इस संबंध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि वे इन पर गौर फरमायें। सबसे पहले जो आज गांवों की उपेक्षा हुई है, उसके लिये निवेदन करूंगा जहां पर औषधालय है, आयुर्वेद के, एलोपैथी के, मेरा निवेदन है कि वहां उनकी सुविधा उपलब्ध कराएं और जिन गांवों में कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां पर दूसरी जगह से स्थानान्तरित करें ।

(श्री करतारसिंह)

ताकि वहां की जनता के साथ न्याय हो। मुझे आशा है कि इस नीति के साथ राज्य सरकार चलेगी तो अवश्य ही बहुत-सी समस्या हल होगी और जो गांव चिकित्सा सुविधा से महरूम हैं वहां चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।

दूसरा मैंने इस प्रगति विवरण का अध्ययन किया है और यह महसूस किया है कि गांवों के साथ उपेक्षा का कारण यह है, जितने भी डॉक्टर हैं, वे गांव में नहीं जाना चाहते हैं। मेडिकल कॉलेज में जितने भी एम.बी.बी.एस. में स्टूडेन्ट भर्ती किये जाते हैं उनमें गांव का कोटा भी आप निर्धारित करें। गांव के बैक ग्राउन्ड का लड़का है और उसका पर्सेन्टेज कम है शहरी विद्यार्थी के मुकाबले तो उसको अवश्य स्थान दीजिये। मैं निश्चित् रूप से यह कह सकता हूं जब गांव का लड़का डाक्टर बनेगा तो वह गांव में जाएगा। जितने शहरी विद्यार्थी हैं वे गांव में जाने से कतराते हैं।

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि गांवों में पी.एच.सी. है। पंचायत समिति में एक पी.एच.सी. है। इसके अन्दर एक्स-रे व ऑपरेशन की और दूसरी छोटी-छोटी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। अजमेर में जो जवाहरलाल नेहरू अस्पताल है, मुझे यह कहते हुए दुःख है कि गांव वालों को भर्ती कराने में वहां दिक्कत होती है। डॉक्टर भर्ती नहीं करते है। इनकी समस्या का समाधान किया जाए। उनको सुख सुविधा नहीं है। गांव के अन्दर आज बिजली है इसलिए उनको भी चिकित्सा के साधन उपलब्ध कराये जाएं। वहां पर ऐसे अस्पताल खोलें कि उनको शहर में नहीं आना पड़े।

गांवों में आप भ्रमणशील शल्य चिकित्सालय प्रारंभ कीजिए। मैं राज्य सरकार को आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि हालांकि बजट में कमी है, उसके बावजूद आप यू. एन. ओ., युनीसेफ से सम्पर्क कर के सहायता लेकर गांव की ओर ध्यान दें। इसके साथ ही गांवों के अन्दर डॉक्टरों की भ्रमणशील इकाइयां कायम करें तो गांव वालों का फायदा होगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, मैं बच्चा था तब हमारे मदार सेनिटोरियम से गाड़ी आया करती थी....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मदार सेनिटोरियम वाले गांवों में आया करते थे। उनका समय और दिन निश्चित् था, सोमवार, मंगलवार। इसी प्रकार से मेरा निवेदन है कि पी.एच.सी. में जो डॉक्टर हैं उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था करें। वे गांवों के लिए एक निश्चित तारीख तय करें ताकि गांव वाले उस तारीख और समय पर तैयार मिलें और उनको भी सुविधा रहे। मेरा निवेदन है कि इससे गांवों के साथ भेद भाव दूर होगा।

यह जो नई योजना चली है सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता की, यह कागज पर तो अच्छी नजर आती है परन्तु मुझे इसका वास्तविक अनुभव है। मेरे गांव में स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता है। वहां यह योजना चल रही है। इन वर्कर को 50/- रुपये की तनख्वाह देंगे। इस कारण जो दवाइयां दी गई हैं, वह बेच रहे है। इस प्रकार वह भली प्रकार सेवा नहीं कर पा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि यदि यह योजना लागू करनी है तो इन कार्यकर्त्ताओं को अच्छी तनख्वाह दें ताकि सही मायने में वह आपकी सेवा कर

( श्री करतारसिंह )

सकें। पचास रुपये में वह एक घंटा सेवा नहीं कर सकते। वह दवाइयां बेचेंगे इसलिए मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि इस योजना को सफल बनाना है तो कार्यकर्ताओं की तनख्वाह बढ़ायें ताकि वह निश्चित रूप से काम कर सकें।

एक निवेदन और करना चाहता हूं। प्रत्येक सब-सेन्टर के साथ मेटरनिटी होम कायम किया जाए तो अच्छा होगा। एक बात में प्रिवेन्टिव हैल्थ मेजर के बारे में कहना चाहूंगा। जिस प्रकार हम एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन की स्कीम्स को लागू कर रहे हैं, उसी प्रकार मेरा निवेदन है कि वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यू. एच. ओ., यूनिसेफ आर्गनाइजेशन की इस सम्बन्ध में कई योजनाएं हैं, आप निश्चित रूप से उनसे सम्पर्क करें। इन योजनाओं के साथ बेलेंस्ड डाइट के बारे में कुछ कार्यक्रम हों। इस काम के लिए थोड़ा बहुत फण्ड अलॉट किया जाय, उनको गाईडेन्स दी जाय ताकि उनकी बेलेंस्ड डाइट हो सके। साथ ही किचन गार्डन बना कर, किस तरह हरी सब्जियों से विटामिन मिलता है यह सब जानकारी उनको हो सकें। पोस्ट ट्रीटमेन्ट करने के बजाय उनके स्वास्थ्य के लिये प्रिवेंटिव मेजर लेना बहुत जरूरी है।

इसके साथ-साथ मैं आपको निवेदन करूं कि जो मंत्रीगण हैं उनका स्टाफ के प्रति कोई ध्यान नहीं है। उनके साथ जो जमादार गनमैन लगे हुए हैं उनको कोई सुविधा नहीं है। बेचारे जमादार सारे दिन रात उनके साथ-साथ घूमते रहते हैं। न तो उनको कोई हार्ड ड्युटी अलाउन्स मिलता है और न कोई ओवरटाइम मिलता है। इसके साथ ही जो मिनिस्टरों के साथ गनमैन लगे हुए हैं, गार्ड है चीफ मिनिस्टर साहब के यहां, इन सिपाहियों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस बारे में आपका कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री करतारसिंह : मैं सुझाव दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये अब।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : कुछ एम. एल. एज. मंत्री पद पाने से रह गए हैं इनका भी ध्यान रखा जाय।

श्री करतारसिंह : मैं सुझाव दे रहा हूं, आपको इस पर विचार करना चाहिए। आप लोगों को 51 रुपये मिलते हैं, मिनिस्टरों को हजार रुपये मिलते हैं लेकिन उनकी ओर कोई ध्यान नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। धन्यवाद।

श्री समरथलाल !

(अनुपस्थित)

श्री हरलालसिंह खर्रा।

श्री हरलालसिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान मेडिकल की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। मैंने कटौती प्रस्ताव दिए हैं उनके बारे में मैं खास तौर से निवेदन करूंगा मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा कि भूतपूर्व सरकार ने ग्राम महरोली में डिस्पेंसरी खोली थी। मैं निवेदन करूंगा कि ग्राम महरोली की छः हजार से ज्यादा की आबादी है। जब भूतपूर्व सरकार ने डिस्पेंसरी खोली तो

( श्री हरनालसिंह खर्रा )

आपके चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने गांव वालों को बताया कि यह भवन कम पड़ रहा है, आप डॉक्टर के लिए क्वार्टर बनाइये कम्पाउण्डर के लिए क्वार्टर बनाइये, और थोड़ा और एडीशन नई बिल्डिंग में करिये। तो गांव वालों ने, जो कि किसान हैं, चन्दा करके डॉक्टर के लिए क्वार्टर बनाया, कम्पाउन्डर के लिए क्वार्टर बनाया और बिल्डिंग के अन्दर एक-दो कमरे बनाए। इस प्रकार पचासों हजार रुपये का खर्चा किया। मुझे मालूम पड़ा, इस सरकार ने आते ही वह आश्वासन, वह ऑर्डर कैंसल कर दिया। आठ महीने में लगातार मंत्री महोदय से मिलता रहा लेकिन आज तक कोई कार्य-वाही नहीं हो सकी। जनता पार्टी की सरकार ने आते ही वह ऑर्डर कैंसल कर दिया। मैं निवेदन करूंगा मंत्री महोदय से कि उस गांव में डॉक्टर नहीं है। वहां अन्य कोई चिकित्सा की सुविधा भी नहीं है, न औषधालय है, और न किसी भी तरह की अन्य चिकित्सा सुविधा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय यदि डिस्पेन्सरी को नहीं खोल सकें तो एड पोस्ट अथवा अन्य कोई विशेष चिकित्सा की सुविधा देने का कष्ट करें। वरना आप ही सोचें क्षेत्र का विधायक उस ग्राम में किस मुंह से जायगा।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों में आप चिकित्सा की सुविधायें नहीं दे रहे हैं, शहरों के अन्दर ही सब कुछ कर रहे हैं। मेरा निवेदन है, सरकार का यह निर्णय है कि दो डिस्पेन्सरी और एक एड पोस्ट पंचायत समिति लेवल पर दी जायगी, तो मैं निवेदन करूंगा कि हमारा पंचायती क्षेत्र और खास तौर पर मेरा क्षेत्र हमारी भूतपूर्व सरकार की तरफ से उपेक्षा का क्षेत्र रहा है और इस क्षेत्र में चिकित्सा की दृष्टि से कोई काम नहीं किया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में दस हजार की आबादी का एक ग्राम भाली है उस ग्राम में वोटर्स 6,000 है। पंचायत समिति क्षेत्र में सबसे बड़ा ग्राम है लेकिन वहां पर 'सी' श्रेणी का औषधालय है। मैं आपको मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि दस हजार की आबादी के ग्राम में 'सी' श्रेणी का औषधालय हो तो वहां की जनता के स्वास्थ्य का क्या हाल होगा। वहां की जनता भवन बनाने को तैयार है। या तो इसे 'सी' श्रेणी से 'ए' क्लास में क्रमोन्नत करें या और कोई चिकित्सालय की सुविधा दें।

इसी तरह से मेरे क्षेत्र में दो गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी भी छः हजार से अधिक है। एक ग्राम है जयतुसर और दूसरा नागल नाथूसर। इन दोनों गांवों में छः हजार से अधिक आबादी होते हुए भी न औषधालय है, न चिकित्सालय है और न अन्य सुविधा है। अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे जानकारी प्राप्त करें कि छः हजार की आबादी वाले किन ग्रामों में जनता को न चिकित्सालय की सुविधा है, न औषधालय है, न कोई एड पोस्ट है, न डिस्पेन्सरी है। इस जनता सरकार ने भी इनके बारे में नहीं सोचा तो बहुत बड़ी हद तक अन्याय होगा।

(व्यवधान)

समय तो आपका भी है और मेरा भी है, आपका ही ठेका नहीं है।

इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि जो चल-चिकित्सालय हैं उसको आप हटायें। पंचायत समिति लेवल पर महीने में कोई दिन तय करें जब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हॉस्पिटल्स हैं उनके

(श्री हरलालसिंह खर्रा)
डॉक्टर हैं वे कम से कम एक बार पंचायत समिति में जहां हॉस्पिटल है वहां जावें। पहले से इत्तला हो, वहां पर आपरेशन वगैरह हों और जो भी स्पेशलिस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं वे वहां जाकर लोगों का इलाज करें, जिससे लोगों को बार-बार दूर नहीं जाना पड़े और इसमें जो उनका खर्चा होता है वह भी नहीं हो।

इसके साथ ही मैं डायरेक्टोरेट के बारे में भी निवेदन करूंगा। इसके कर्मचारियों के साथ ज्यादती हो रही है। सन् 1961 में राज्य सरकार ने समाज सेवक की पोस्ट क्रियेट की। उसके थोड़े दिनों बाद ही उसका नाम खण्ड शिक्षा प्रसारक कर दिया। उनको एक साल का प्रशिक्षण देकर ट्रेनिंग दी गई। सन् 1967 में राज्य सरकार ने इनके नए वेतनमान निर्धारित किए। 1967 से लेकर अब तक 11 साल हो गए लेकिन अभी तक इन कर्मचारियों का फिक्सेशन नहीं किया गया है। इनका वेतन निर्धारण आज तक नहीं हुआ। मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय अपने विभाग से इस बात की जानकारी लें कि इतने दिनों तक देर लगाने के लिए कौन दोषी हैं? 11 साल में भी फिक्सेशन नहीं हो सका तो उनका क्या हाल होगा?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके अलावा दूसरा मेरा निवेदन है प्रमोशन के बारे में, यह बात सही है कि प्रमोशन में मनमानी बर्ती गई है। मैं नाम भी बता देता हूं। उसका नाम मदनमोहन है। बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर उसका पोस्टिंग 26-2-62 को हुआ। उसके बाद उससे जूनियर कर्मचारियों का प्रमोशन हो गया। इस कर्मचारी ने कई बार उच्चाधिकारियों से निवेदन किया। मैंने भी एक-दो बार कहा लेकिन आज तक उसके साथ न्याय नहीं हुआ। अब मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस तरह से जिन्होंने अन्याय किया है उनको दण्डित किया जाय और इस व्यक्ति को न्याय दिलाया जाय। इसका प्रमोशन यदि वाजिब है तो निश्चित तौर पर मिलना चाहिए।

इसके बाद में मेरे क्षेत्र के बारे में पुनः निवेदन करूंगा कि भूतपूर्व सरकार ने मेरे क्षेत्र की उपेक्षा की, क्योंकि कांग्रेस का आदमी पांच चुनावों में एक बार चुनाव जीत कर आया बाकी विरोधी लोग आए इसलिए सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब भी सरकार ने इस क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दिया तो मैं कहूंगा कि इस क्षेत्र के साथ ज्यादती ही होगी।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलाल ऐरन।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले में नसीराबाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर है। बीस हजार की आबादी वाले इस सैनिक केन्द्र में सन् 1916 में एक चिकित्सालय का निर्माण हुआ। उसे 1974 तक कंटोनमेंट बोर्ड, जो वहां की नगरपालिका के समकक्ष है, चलाता रहा। किन्तु आर्थिक कठिनाइयों से वह चिकित्सालय सुचारू रूप से नहीं चल सका। इसलिए वहां की जनता ने मांग की और कंटोनमेंट बोर्ड के सदस्यों ने सैंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति से राज्य सरकार को सौंपने का निर्णय लिया। 1974 से राज्य सरकार ने उस चिकित्सालय को अपने अधिकार में लेकर राजकीय चिकित्सालय में परिणत किया। 1974 में राज्य सरकार द्वारा अपने

(श्री भंवरलाल ऐरन)

अधिकार में लेने के पश्चात् इस बात की घोषणा की कि वहां के जो कर्मचारी, कार्यकर्त्ता थे उन्हें वही सुविधा दी जाएगी जो राज्य कर्मचारियों को दी जाती है। किन्तु बड़े खेद की बात है कि आज तक उन्होंने उस चिकित्सालय को नॉन-प्लान में नहीं लिया है। वहां के कर्मचारियों को दो-दो, तीन-तीन महीने का वेतन देने की अनुमति प्राप्त होती है और फिर तीन महीने तक वेतन मिलता। फिर बार-बार लिखने पर, दो महीने के लिए, कभी तीन महीने के लिए, सैंक्शन दी जाती है। मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि शीघ्र से शीघ्र इसकी व्यवस्था करें। आखिर वह वक्त कब आएगा जब नॉन प्लान में लिया जाएगा। एक बात और कि पुराने जो कर्मचारी हैं, कैन्टोनमेंट बोर्ड के पुराने कर्मचारी थे उनका प्राविडेंट फण्ड बोर्ड में जमा है। कर्मचारियों द्वारा, कैन्टोनमेण्ट बोर्ड द्वारा कितने ही लैटर लिख दिए गये। मन्त्री महोदय को मैंने लिखा था कि प्रॉविडेण्ड फण्ड का रुपया उन कर्मचारियों को दिला दिया जाये। अन्त में कैन्टोनमेण्ट बोर्ड ने यहां तक लिख दिया कि अगर 15 दिन तक राज्य सरकार ने निर्णय नहीं लिया तो यह रुपया लेप्स हो जाएगा। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा, एक पत्र लिखने की आवश्यकता है। इतने से काम के लिए डेढ़ वर्ष से लगातार कैन्टोनमेण्ट बोर्ड लिख रहा है। आपके माध्यम से अन्तिम बार मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको प्राथमिकता दिलाकर शीघ्र से शीघ्र रकम दिलायी जाये।

अपने कटौती प्रस्ताव के द्वारा मैं निवेदन करूंगा कि कैन्टोनमेण्ट बोर्ड ने जब यह चिकित्सालय दिया तो इसके साथ एक और बड़ी बिल्डिंग भी थी जो आज खाली पड़ी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, 1974 के बाद वहां समुचित दवाई की व्यवस्था नहीं है। वहां के इन्स्ट्रूमेण्ट्स खराब हो गये हैं, Rust हो गए हैं। उनका प्रवन्ध नहीं किया गया है। अच्छे-अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन इन्स्ट्रूमेण्ट्स के अभाव में उनको रोगियों को इन्कार करना पड़ता है और अजमेर रेफर करना पड़ता है। मैं राज्य सरकर से निवेदन करूंगा, उस चिकित्सालय का शीघ्र से शीघ्र प्रबन्ध किया जाकर, समुचित उपकरणों का प्रबन्ध किया जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दवाइयों का प्रावधान किया जाये।

यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य की ओर से एक छोटी सी डिस्पेंसरी भी चलाई जा रही है। राज्य सरकार का उसको बन्द करने का विचार है। जो वर्तमान चिकित्सालय है, वह उसका प्रबन्ध करने को तैयार नहीं है। उस डिस्पेंसरी को इसी चिकित्सालय में शामिल करके इसको 'बी' क्लास का चिकित्सालय घोषित करें। मैं निवेदन करूंगा कि लामाना, गोला, नायू, थल्का, लीठी, मकरेड़ा, न्यारा, बाघसुरी, लोहरवाड़ा, झड़वासा इन गांवों में चिकित्सा का कोई प्रबन्ध नहीं है। यदि राज्य सरकार एक-एक डिस्पेंसरी की व्यवस्था करे तो लोगों को राहत मिलेगी ये बड़े-बड़े 5-7 हजार की आबादी के गांव हैं। अभी तक कांग्रेस सरकार रही है। इन गांवों से कांग्रेस को वोट नहीं मिलता था। आज जनता सरकार है। आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा, इन गांवों में डिस्पेंसरी का प्रबन्ध किया जाये। मैं समझता हूं कि सरकार उचित प्रबन्ध करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नवलराय बच्चाणी !

श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर पश्चिम): माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ समय पहले अजमेर में पोलियो रोग फैला था। वह अभी भी निर्मूल नहीं हुआ है। पोलियो और मलेरिया ये दोनों रोग वहां समय-समय पर फैलते हैं। मलेरिया का जहां तक सम्बन्ध है, वहां एक तालाब है। उसमें पूरे नगर की नालियों का पानी पड़ा सड़ता रहता है। वहां पाल बीचला नाम का तालाब है। वह शहर के बीच में है। उसको यदि पाट दिया जाये और गोभी व सब्जी आदि के लिए भी उस पानी का सेवन बन्द किया जाये।

दूसरा मैं यह सुझाव दूंगा कि आयुर्वेद के लिए एक अलग से मन्त्री रखा जाये। प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, यूनानी होम्योपैथी और योगासन आदि का तभी विकास हो सकता है जब इसके लिये अलग से मंत्री रखा जायेगा। आज योगासन और प्राकृतिक चिकित्सा बढ़ती जा रही है लेकिन प्राकृतिक एवं योगासन चिकित्सा की शिक्षा देने वाला यहां पर कोई कॉलेज नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा भी उपलब्ध नहीं है। मैं समझता हूं कि योगासन चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा का प्रबन्ध किया जाये।

उप-वैद्यों और नर्स की भी कमी है। उनके लिये भी अधिक से अधिक कॉलेज और प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायें। तीन चार आयुर्वेद के कालेज और खोले जायें। एक कॉलेज अजमेर में खोला जाये, क्योंकि वहां पर 'ए' श्रेणी का अस्पताल है। जैसी कि ग्रामों के लिये स्वास्थ्य योजना बनाई गई है, वैसे ही 26 जिलों में 26 जिला अधिकारी वैद्यों को रखा जाये। जो ग्रामों के केन्द्र हैं, उनको उनके द्वारा संचालित किया जाये। जो सरकारी वैद्य और डॉक्टर हैं, उनकी प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द करके, उनको नॉन-प्रेक्टिसिंग मासिक भत्ता देना चाहिए। वैद्यों का वेतनमान भी बढ़ाना चाहिए। उपवैद्यों की स्थिति यह है कि उनको मैट्रिक तक पढ़ाई करने के बाद बहुत कम वेतन मिलता है। 110/- रु. के वेतन से दो साल के बाद में 130/- रु. देते हैं। मेरा निवेदन है कि उपवैद्यों का वेतन बढ़ाया जाये।

अजमेर नगर में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल है। उसमें दिनोंदिन गांवों के अधिक लोग आते हैं। नगर की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए बाहर के क्षेत्रों में भी चिकित्सालय खोले जायें। रामगंज, शास्त्री नगर, नगरा, श्रीनगर रोड, वहां भी चिकित्सालय खोले जायें जिससे यहां के लोग और जो गरीब रेलवे कर्मचारी लोग रहते हैं वह भी लाभ उठा सकें। जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में जो भीड़-भाड़ है, वह भी इससे कम होगी। आयुर्वेद वैद्यों और डॉक्टरों के स्थान रिक्त पड़े हैं, मैं चाहूंगा कि जल्दी-जल्दी से उनको भरा जाये। आयुर्वेद निदेशक का रिक्त स्थान पड़ा है उसे जल्दी भर देना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसी प्रकार से बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिशन्स को कम अनुदान दिया जाता है। वह कम से कम एक लाख दिया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामेश्वर प्रसाद !

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, यह उचित होगा कि बहस का जवाब सुन लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं समझा नहीं आपके कहने का क्या मतलब है ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आज की बहस समाप्त करके मंत्री महोदय का जवाब सुन लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : अगर सदन की सहमति होगी, तो विचार कर लेंगे ।

श्री रामेश्वर प्रसाद !

(अनुपस्थित)

श्री एच. एन. शर्मा !

(अनुपस्थित)

श्री गुलाबचन्द कटारिया !

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह माना जाता है कि खाने को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता या जिस प्रकार के पौष्टिक तत्व भोजन में होने चाहिए, उसके अभाव के कारण लोग बीमारियों से ग्रसित होते हैं, लेकिन सरकारी सेवा में रहने वाले लोगों के द्वारा मेडिकल का बिल उठाया जाता है उसका अगर विश्लेषण किया जाय तो मेरी यह मान्यता है कि अधिक पैसा प्राप्त करने वाले ऑफिसर लोग हैं, वे बहुत अधिक पैसा प्राप्त करते हैं, इसका मतलब है कि उनको अच्छा भोजन मिलता है, अच्छे वातावरण में रहते हैं, स्वच्छ मकानों में रहते हैं, परन्तु पता नहीं ऐसे कौनसे कारण हैं कि उनके द्वारा मेडिकल बिल उठाये जाते हैं । मुझे ऐसा लगता है कि फर्जी बिल बनाये जाते हैं । मेडिकल वालों से उनकी सांठ-गांठ होती है । दवाओं के नाम पर अपनी बीबियों के लिए श्रृंगार का सामान खरीदते हैं और दवाओं को उनके स्थान पर एडजस्ट किया जाता है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह जो मेडिकल रिएम्बसमेंट किया जाता है उसको पे के साथ जोड़ दिया जाय और उसी के आधार पर उनको अलाउन्स दिया जाय । इससे जो वास्तव में बीमार होते हैं और दवाइयों से जो वंचित रह जाते हैं उनको दवा मिल सकेगी और जो लोग मेडिकल वालों से सांठ-गांठ करके मेडिकल रिएम्बर्समेंट का दुरुपयोग करते हैं वह बन्द हो जायगा ।

श्रीमन्, उदयपुर में वैसे तो एक बड़ा हॉस्पिटल है इसमें दो राय नहीं हो सकती, लेकिन उसके पीछे जैसे-जैसे शहर का विकास होता जा रहा है, शहर अपनी चारदीवारी से बाहर निकलता जा रहा है, नई कॉलोनियां बन रही है, जो हाउसिंग बोड ने भी बनाई हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, करीब बीस हजार लोग जो शहर से बाहर रहते हैं लेकिन कोई स्थानीय अस्पताल की व्यवस्था नहीं होने के कारण वे बहुत परेशान हैं । इसलिए, मान्यवर, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय को यह सुझाव देना चाहता हूं कि वहां पर एक कृषि उपज मण्डी ने योजना स्वीकृत की है, ढाई लाख रुपये की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है, उसके लिए कागज भी मूव किये गये थे । अगर स्वीकृति मिल जाय तो आउट ऑफ सिटी जो लोग रहते हैं, जो शहर का विकास हुआ है उसको देखते हुए उनके लिए अस्पताल की अच्छी व्यवस्था हो सकती है ।

इसी तरह से जो उदयपुर के अन्दर टी.बी. हॉस्पिटल है । वहां पर राजस्थान के ही नहीं, मध्य प्रदेश व अन्य प्रान्तों से भी मरीज आकर अपना इलाज कराते हैं । वह शहर से आठ दस मील की दूरी पर होने से जो बाहर के लोग आते हैं, मरीजों के प[illegible] वाले, उनको

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

धूप में खड़ा होना पड़ता है। वहां खड़े होने के लिए भी शेड नहीं है। जब अस्पताल प्रारम्भ हुआ था उस समय गोलछा ने एक सराय की नींव डाली थी लेकिन वह अधूरी पड़ी हुई है। मेरा अनुमान है कि इसमें तीन लाख रुपया खर्च हो चुका है, पता नहीं क्यों काम बन्द कर दिया गया। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस सराय के अधूरे काम को राज्य सरकार अपने हाथ में लेकर पूर्ण करवाये ताकि बाहर से आने वाले लोग उसमें ठहर सकें और मरीजों की देख-भाल और सेवा कर सकें।

यही नहीं, श्रीमन्, टी.बी. हॉस्पिटल के अन्दर एक एक्सपर्ट डॉक्टर 22 साल से कार्यरत था परन्तु पता नहीं, उसको क्यों हटा दिया गया और किसी दूसरे को रख दिया। इसके लिए कई बार अनुनय-विनय की। यह टी.बी. के मरीजों के साथ में घोर अन्याय हो रहा है, वहां पर दूसरा कोई एक्सपर्ट डॉक्टर भेजा जाये जिससे मरीजों के साथ न्याय हो सके। आज भी मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उदयपुर टी.बी. हॉस्पिटल में आउटडोर के अन्दर एक एक्सपर्ट डॉक्टर को भेजा जावे।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से नगरपालिकाएं नगर की सुन्दरता के लिए फव्वारे बना सकती हैं, सड़कें बना सकती हैं, बाग बगीचे लगा सकती हैं तो उनके पास ऐसा बजट भी होना चाहिए जिससे कि छोटी-मोटी डिस्पेन्सरियों का निर्माण करा सकें और लोगों को राहत दे सकें। श्रीमन्, जहां एक ओर हमने इस प्रकार के बड़े अस्पताल बनाये, वहां दूसरी ओर आयुर्वेद के साथ घोर अन्याय हुआ है। पता नहीं क्यों, या तो यह समझते हैं कि इस पर लोगों को विश्वास नहीं है या आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं, गोलियां और पुड़ियाओं का कोई उपयोग नहीं है। मूलभूत चिकित्सा पद्धति को मन से निकाल दिया है। लोग बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहां पर खांसी के इलाज के लिए बीस रुपये की दवा लिख दी जाती है। इस कारण एक गरीब व्यक्ति अपना इलाज भी नहीं करवा सकता। आयुर्वेद के माध्यम से कम से कम पैसों में अच्छा से अच्छा इलाज हो सकता है इसलिए मैं चाहूंगा कि आयुर्वेद की ओर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाय और इसको डवलप करने के लिए प्रयत्न किया जाये।

जहां तक वैद्यों की तनख्वाह का..

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सवाल है उनको निम्न श्रेणी में माना जाता है। इस कारण उनका जीवन स्तर नीचा रहता है। वे लोग वास्तव में सेवा करना चाहते हैं लेकिन सेवा नहीं कर सकते। पिछली बार उनकी हड़ताल भी चली थी, सरकार से उन्होंने विनय भी की थी, सरकार ने उनको आश्वासन भी दिया था कि उनकी मांगों पर सहानुभूति से विचार किया जायगा, लेकिन काफी लम्बा समय निकल जाने के बाद भी अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि यदि आयुर्वेद को जिन्दा रखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि गरीब लोगों का कम से कम पैसों में इलाज हो, तो आयुर्वेद के विकास पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा और वैद्यों की तनख्वाह को बढ़ाना पड़ेगा ताकि वे इसमें अधिक रुचि लेकर परीक्षण करें। उदयपुर में एक डॉक्टर पारीक है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भगंदर एक भयानक रोग है, उदयपुर के हॉस्पिटल में इसका इलाज नहीं हो सकता

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

लेकिन वह एक धागे के सहारे उसका इलाज करते हैं। उसका उन्होंने एक सफल प्रयोग किया है मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसमें पांच रुपये भी खर्च नहीं होते हैं। मैंने सरकार से निवेदन किया था कि एक चल चिकित्सालय प्रारम्भ किया जाय और उस डॉक्टर को उसमें रखा जाय तो लोगों का भगन्दर का इलाज कम से कम पैसों में किया जा सकता है और उनको राहत मिल सकती है। यह एक चमत्कारी प्रयोग है। मैं चाहता हूं इसका पूरा-पूरा-लाभ उठाया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कल्याणसिंह सांखला !

(अनुपस्थित)

श्री माणकलाल ठाकोर !

(अनुपस्थित)

श्री माधोसिंह कछवाह !

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर में दो बड़े अस्पताल हैं, पुरुषों के लिए महात्मा गांधी हॉस्पिटल और महिलाओं के लिए उम्मेद हॉस्पिटल। इन दोनों अस्पतालों की हालत बड़ी शोचनीय है। पिछले सत्र में, जो 6 माह पूर्व हुआ था, इन अस्पतालों के बारे में मैंने विचार प्रगट किये थे। मुझे आज बहुत बड़ा दुःख है, उन विचारों का कोई मूल्यांकन सुधार के रूप में जनता पार्टी की सरकार के जरिये नहीं हुआ। आज मैं और भी ज्यादा दुःखी हूं क्योंकि जोधपुर में दो दिन पहले एक ताजी घटना हुई है।

आज ही राजस्थान पत्रिका में बड़े अक्षरों के हैडिंग में उसका उल्लेख हुआ। पोस्ट मास्टर पर हमला, जोधपुर में डाक नहीं बंटी और गांधी अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने उसके जखमों का मुआयना करने से इन्कार कर दिया, एक पोस्ट मास्टर पर हमला हुआ। खून से लथपथ होते हुए अपनी जान की रक्षा तो की ही, लेकिन पोस्ट ऑफिस की रक्षा भी की। रात को जब अस्पताल में उसको ले गए तो उस अस्पताल का नाम तो गांधी अस्पताल है, हमारे मंत्रीजी सर्वोदयी हैं, गांधी के अनुयायी के नाम से जाने जाते है। लेकिन उस गांधी अस्पताल में एक जख्मी पोस्ट मास्टर, जो मौत से जूझ रहा था, के घावों को देखने से डॉक्टर ने इंकार कर दिया। नतीजा यह हुआ कि दूसरे दिन जोधपुर के सभी पोस्टमैनों ने हड़ताल की, डाक नहीं बांटी, धरना दिया और मांग की कि उस डॉक्टर को निलंबित किया जाए। मुझे मालूम नहीं, सर्वोदयी मंत्री को इस बात का पता है या नहीं। अगर है तो फिर उस पर क्या कार्यवाही की, क्या सूचना प्राप्त की और उसमें किसी कारण से असमर्थ हैं तो उनका इरादा क्या है ? मैं समझता हूं कि इस मांग पर अपने विचार प्रस्तुत करते समय इस विषय पर प्रकाश डालेंगे।

उपाध्यक्षजी, हमारे अस्पतालों में सामान्य तौर से पट्टी का होना जरूरी होता है, जो बांधने के काम आती है, वहां पट्टी तो नहीं है लेकिन टट्टी के ढेर जरूर हैं। दवाइयों का स्टाक नहीं है, पर गंदगी के ढेर चारों तरफ हैं। यह व्यवस्था तो अस्पतालों में है। हमारे डॉक्टरों का यह नोबल प्रोफेशन नेक्स्ट टू गोड है। अगर सर्वोदयी मंत्री इस बात को जानते हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए। आपको पीड़ा होनी चाहिए, दर्द

(श्री माधोसिंह कछवाह)

उठना चाहिए। जिंदगी में अगर मंत्री पद संभालना है तो इसके सुधार के लिए आपको जीना व मरना है। मंत्रीजी अगर दोनों अस्पतालों की हालत नहीं सुधरी तो मैं मंत्रीजी की कोठी पर 28 तारीख को भूख हड़ताल शुरू करूंगा। माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की 6–7 महीने से व्यवस्था देख रहा हूं। मैं कहना चाहूंगा :

दर्द मेरा रुकता नहीं, जीने को मन करता नहीं।
ओ जीने वाले देखना, सर्वोदयी बचा या नहीं।

उपाध्यक्षजी, सारे समाज को चिंता है। हमारे अस्पतालों में यह हालत है तो गरीब का कहां ठिकाना, कहां आदमी जाएगा, कहां इलाज होगा ? यह सोचने की बात है. किसी ने अस्पताल में एक मरीज से पूछा, तुम जीते क्यों हो, मरते क्यों नहीं ? उसने कहा, डॉक्टर के लिए जीता हूं। उसको पता है कि मैं मर जाऊंगा; लेकिन उस डॉक्टर को इतनी फीस देनी है कि कम से कम दूसरा मरीज आए उसको तो जल्दी न मार दे। तो 30 साल में यह करेक्टर जरूर बिल्ड हुआ है। When character is lost everything is lost. तो सब कुछ बरबाद होने के बाद एक दीपक भारतीय संस्कृति का था उसको बुझाने की बात सोची गई। मरने वालों को जिंदा करने के लिए, इलाज के लिए जितने अस्पताल हैं, वह ऐसे डॉक्टरों के हाथ में हैं। सर्वोदयी मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आपसे कम से कम आज उम्मीद करूंगा कि आप ऐसा भाषण नहीं देंगे कि शिकायत आएगी तो यह कर देंगे, वह कर देंगे। आपको आज कम से कम, कुछ न कुछ नये विचार देने पड़ेंगे। आप उस अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट पर निर्भर रहेंगे, आप किसी नीचे के अधिकारी पर निर्भर रहेंगे। आपके पास कौनसी मशीनरी है, आपके पास कौनसी ऐसी व्यवस्था है जिसके जरिए जान सकें कि राजस्थान में दवाइयां ब्लेक में बिकती हैं, फर्जी बिल बना कर स्टाक में पड़ी हुई दवाइयां मरीजों के नाम बता कर बाजार में बिकती हैं और मरीजों को नहीं मिलती ?

जोधपुर में डॉक्टर एस.के. पांडे को पता ही नहीं रहता कि उनके नीचे क्या होता है। नर्सेज व कम्पाउण्डर्स के छोटे मोटे बिल्स होते हैं या उनका कोई इन्क्रीमेंट का मामला होता है तो अकाउन्टेंट व दूसरे लोग, जो वहां बैठे हैं, उनसे रिश्वत लेते हैं। बहुत खराब स्थिति होती है वहां। हमारे मंत्रीजी इस सारी व्यवस्था को कैसे देख सकते हैं, मंत्री बनने के बाद उन्होंने जरूर सोचा होगा। मैं चाहूंगा कि इसका स्पष्टीकरण करें।

एक ग्लूकोज प्लांट प्रोजेक्ट जोधपुर में लगना था। इसकी स्वीकृति हो चुकी, मशीनें आ चुकीं। इसके जरिए एक डेढ़ रुपये में ग्लूकोज की बोतल मिलेगी, जबकि इस समय में 4–5 रुपये में मिलती है। मुझे पूरा ज्ञान नहीं है, वह प्लांट खटाई में पड़ा हुआ है। क्यों ? वहां के सुपरिन्टेन्डेंट की सुस्ती समझिए, उनकी नींद नहीं खुलती है या हमारी सरकार को किसी प्रकार चिंता नहीं है।

मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। मुझे मालूम है, समय अधिक हो गया है।

अब मैं थोड़ा मंत्रिपरिषद् के बारे में कहना

(श्री माधोसिंह कछवाह)

चाहता हूं। कुछ लोगों ने तथा माननीय सदस्यों ने मंत्रियों की मोटर, बंगले इत्यादि की चर्चा की। मैं समझता हूं वे ठीक तौर से इस मामले में अपने आप को संभाल नहीं पाते। मंत्रियों को 1400-1500 के आस-पास तनख्वाह मिलती है और कुछ नहीं। मोटर उनके खुद के लिए नहीं है। वह राजस्थान की जनता का भार लिए हुए हैं, उनके लिए यह व्यवस्था आवश्यक है। राजस्थान के अंदर किसी मंत्री का जो स्टेटस है, मैं समझता हूं, हमारे आई. ए. एस. व आई. पी. एस. अधिकारियों पर जितना खर्चा होता है उससे तो कम है। विधायक का स्तर भी कम है। क्या है यह 500 रु. तनख्वाह? सबसे बड़ा करप्शन का कारण बना हुआ है तो यही है। हमारे मंत्रियों को पूरी तनख्वाह मिलनी चाहिए, वे किसी जज से कम नहीं है। विधायक को पूरी तनख्वाह मिलनी चाहिए, उस पर जिम्मेदारियां है। जनता का हम में विश्वास है, उसको कायम रखने के लिए, और उसकी निष्ठा को कायम रखने के लिए, नए करेक्टर को बिल्ड करने के लिए आवश्यक है कि उनको जरूरी सुविधायें मिलें, जो आई. ए.एस.व आई.पी.एस. अधिकारी हैं, विभागाध्यक्ष हैं उनसे वे सुविधायें कम नहीं हों।

मैं पुनः एक बार, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिए मेरे मन व आत्मा से अपील करना चाहूंगा कि मेरी 28 तारीख को याद रखें। 28 तारीख को जोधपुर बंद हुआ था, इसके अलावा मैं उनको मौका देना चाहता हूं कि इस बीच शायद कुछ न कुछ व्यवस्था संभले। 28 तारीख को सुबह 5 बजे चिकित्सा मंत्री की कोठी के बाहर मैं बैठ जाऊंगा।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए !

श्री बहादुर सिंह !

श्री बहादुर सिंह (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा सुविधा में सुधार के लिये मैंने भी कटौती के प्रस्ताव दिये हैं। मेरे कटौती के प्रस्तावों के माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान मेरे क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था के बारे में दिलाना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय सदस्य, जो जयपुर से आते हैं, जयपुर की चिकित्सा व्यवस्था के बारे में अपने विचार व्यक्त किये। उन्होंने चिकित्सा सुविधा की कमी की ओर ध्यान दिलाया, साथ ही साथ अपना असन्तोष जाहिर किया। जब जयपुर शहर की हालत चिकित्सा के बारे में यह है तो, उपाध्यक्ष महोदय, सोचिये मेरे इलाके के बारे में। मैं यहां से 500 किलोमीटर दूर के क्षेत्र से आता हूं। हमारे यहां की यह हालत है कि जब हमारे यहां पर कोई आदमी ज्यादा बीमार हो जाता है यानी खुदा के घर जाने की उसकी बारी आती है तो हम उसको यहां पर खुदा का घर समझ कर लाते हैं पर जब यहां के माननीय सदस्यों की चिकित्सा व्यवस्था के बारे में इतनी शिकायत है तो हमारे जैसे लोगों के क्षेत्र की जनता के और हमारे मन में कितना दुःख होता है व कितना असन्तोष होता है। आज तीस साल से, जबसे हमारा राजस्थान बना है, चिकित्सा सुविधाओं पर राज्य सरकार ने खर्चा तो किया है लेकिन आपको यह स्पष्ट इंगित हो जायेगा कि जो आज से तीस साल पहले शहरों और गांवों में फर्क था उसी तरह का फर्क तीस साल कांग्रेस का राज्य रहने के बाद शहरों और गांवों में रहा।

(श्री बहादुर सिंह)

अब जो इस साल जनता पार्टी का बजट आया उसमें भी हमें देखने को यही मिलता है कि कितना शहर और गांवों में फर्क है, कितना भेदभाव आज भी है। एक साल जनता पार्टी की सरकार बने हो गये हैं पर यह भेदभाव स्पष्ट इंगित हो रहा है। आखिर इतना भेदभाव क्यों है। एक आई. ए. एस. अधिकारी का टोमी अगर बीमार हो जाये, एक आई. ए. एस. अधिकारी के टोमी का कान खराब हो जाये तो उसके केलसियम के इन्जेक्शन लगाने को शहरों में पूर्ण सुविधा रहती है। उसी आई. ए. एस. आफिसर की बहन या मां अगर प्रसव से पीड़ित हो तो उसको सभी सुविधायें मिल जाती हैं। किन्तु किसी गांव में किसी गरीब किसान की मां या बहन को प्रसव पीड़ा हो तो कोई पूछने वाला नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे प्रजातन्त्र के नाम पर कलंक है। यह फायदा है आज, उपाध्यक्ष महोदय, आई. ए. एस. आफिसर को और आई. ए. एस आफिसर को जो कि इन्डियन एग्रीकल्चर सर्विस का आफिसर है वह गांव में रहता है उसको, उसके परिवार को गांव में कोई पूछने वाला नहीं है, उसको कोई चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती है। इस तरह का भेदभाव क्यों है, उपाध्यक्ष महोदय? एक इन्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी में और इन्डियन एग्रीकल्चर सर्विस के अधिकारी में आज भी यह भेदभाव समाप्त नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार इस ओर ध्यान दे।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मेरे क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं की कमियों की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने 15–20 हजार की आबादी वाले कस्बों में तो चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था कर दी लेकिन जो दस-दस हजार की आबादी वाले गांव हैं और उसके आसपास के कई दो-दो हजार की आबादी के गांव हैं जो कि मील के घेरे में है उन सभी की 20 हजार तक की आबादी हो जाती है तो वहां पर चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जनता पार्टी की सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आज से तीस साल पहले तक कांग्रेस की राज्य सरकारों ने शहरों और गांवों के बीच में भेदभाव रखा। अब एक साल हो गया है जनता पार्टी की सरकार को भी पर अभी तक चिकित्सा व्यवस्था में सुधार गांवों में नहीं आया। आज भी लोग गांवों से बीमारों को लेकर शहर में आते हैं। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कई बार गांवों में जब लोग ज्यादा बीमार होते हैं तो पहले तो वह कस्बों में भाग कर आते हैं और वहां से जीप में डाक्टर को लेकर गांवों में जाते हैं। उनको फीस देते हैं। लेकिन कई ऐसे होते हैं जिनके पास यह व्यवस्था नहीं होती है। गांव वाले मरने की हिम्मत तो कर लेते हैं पर डाक्टर को जीप द्वारा लाने-ले जाने की हिम्मत नहीं करते। न उनके पास फीस ही होती है देने को। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारे प्रजातन्त्र के नाम पर कलंक जो है उसको तो आप पोंछिये।

उपाध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम है मैं अब ज्यादा निवेदन नहीं करते हुए ए

(श्रीबहादुर सिंह)

दो बात मन्त्रिपरिषद् के बारे में कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। यहां पर, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रिपरिषद् के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रिपरिषद् के सदस्यों को इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह कांग्रेस के मन्त्री लोग अपने व्यक्तियों को प्राथमिकता देते थे उस प्रणाली से काम नहीं करें। आज जिन लोगों की मन्त्री महोदय से प्रेक्टिकल जान पहचान है उनके काम को जनता पार्टी के मन्त्री लोग प्राथमिकता देते हैं और जिस आदमी से उनकी प्रेक्टिकल जान पहचान नहीं होती है उनका काम चाहे जितना ही सही क्यों नहीं हो उनके कामों की अवहेलना की जाती है। प्रेक्टिकल जान पहचान वाले मित्र का काम चाहे जितना गलत क्यों नहीं हो उसका काम कर दिया जाता है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की अवहेलना नहीं की जानी चाहिये और जनप्रतिनिधियों की बात को खास तौर पर ध्यान में रखना चाहिये, उनकी अवहेलना नहीं होनी चाहिये। नहीं तो फिर जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस की सरकार में कोई भेदभाव नहीं रहेगा। अतः इस ओर ध्यान दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री टीकम चन्द।

श्री टीकमचन्द कान्त (जालौर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जालौर के अस्पताल में जो आई स्पेशलिस्ट थे डाक्टर साहब वह ईरान चले गये। उपाध्यक्ष महोदय, अब वहां कोई आई स्पेशलिस्ट डाक्टर नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह कहना चाहूंगा कि क्या जरूरत है फिर हमारे यहां मेडिकल कालेज खोलने की और लोगों को मेडिकल शिक्षा देने की जब कि वे लोग यहां पर पढ़ लिख कर धन कमाने के लिये ईरान चले जाते हैं। क्या जरूरत है डाक्टरों इन्हें पढ़ाने की? हमारी सरकार इतना जनता पर कर भार लाद कर मेडिकल कालेज खोल कर इन्हें पढ़ाती है। उन मेडिकल कालेजेज का जो प्रोडक्ट है। वह अपने देश की गरीब जनता की सेवा नहीं करे, उनके दिल में अपने देश के लोगों के प्रति कोई भाव नहीं है, जो भावना एक चिकित्सक के मन में होनी चाहिए वह उनमें नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र जालौर में ही नहीं, बल्कि सारे राजस्थान के सभी गांवों में ये डाक्टर, उपाध्यक्ष महोदय, लहू का व्यापार करते हैं। यह लोग, उपाध्यक्ष महोदय, पैसों से ही चिकित्सा करते हैं। बिना पैसे इलाज करते नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, यह हालत रही तो कैसे पार पड़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जनता सरकार का ध्यान इस ओर विशेष तौर से दिलाना चाहूंगा। वह इस ओर ध्यान दें। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो एलोपैथी की पद्धति इलाज करने की है वह पद्धति, उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभी जानते हैं, बहुत ही महंगी पद्धति है। इसको सिर्फ सम्पन्न लोग ही काम में ला सकते हैं। गरीब लोगों की चिकित्सा पद्धति एलोपैथी पद्धति नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे गांवों में आज भी काफी प्रभावशाली नुस्खे आपको आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के मिलेंगे, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इतना होने पर भी हमारी आयुर्वेदिक पद्धति से लोगों को मोह नहीं है। हम आज

(श्री टीकमचन्द कान्त)

भी इस पद्धति से गांवों की जनता में विश्वास पैदा नहीं कर सके हैं। मैं धन्यवाद देता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, चीन के लोगों को जिन्होंने अपनी एक्यूपंचर पद्धति को, जो कि उनकी चिकित्सा को पुरानी पद्धति है, कायम रखा। हमारे यहां पर जो आयुर्वेदिक पद्धति है उसकी मौलिक खोज हम अभी तक नहीं कर सके हैं। हमने कोई शोध नहीं की है। आज तीस साल हो गये हैं हम कोई खोज नहीं कर सके हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति हमारी गरीब जनता के लिये आवश्यक है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर पहले अनुभवी लोगों को आर. एम. पी. की डिग्री दे दी जाती थी पर अब नहीं दी जाती है। हमारे यहां पर एम. बी., बी. एस. अधिक नहीं हैं। इसलिये गांवों के लिये उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। परन्तु काफी ऐसे लोग हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जिन लोगों को चिकित्सा का चाव है परन्तु कॉलेज में एलोपैथी की पढ़ाई नहीं कर सके। पर वे लोग अनुभव के आधार पर लोगों का इलाज करते हैं। उनके मन में गांवों की गरीब जनता के प्रति सहानुभूति है, जनता की सेवा करना अपना धर्म समझते हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार ऐसे अनुभवी लोगों को आर. एम. पी. डिग्री देने के प्रश्न पर पुनः विचार करे। तात्पर्य यह है कि जो लोग अनुभवी हैं और जो अनुभव के आधार पर गरीबों का गांवों में रह कर इलाज करना चाहते हैं उनका पंजीयन कर लिया जाय और उन्हें अवसर दिया जाय तो काफी समस्यायें हल हो जावेंगी। न सब जगह ऑपरेशन थियेटर कायम किये जा सकते हैं, न सब जगह हॉस्पिटल खोले जा सकते हैं और न ही सब जगह एम. बी., बी. एस. डाक्टर्स पहुंच सकते हैं। इसलिये इस पर पुनर्विचार करना चाहिये।

मेरा यह भी विचार है कि आर. एम. पी. के अनुभवी डाक्टर्स को गांवों में काम करने की छूट दे दी जाय और जिले से या पी. एच. सी. से कम से कम पांच दिन के बाद में या एक हफ्ते के बाद में डाक्टर वहां पहुंचें, दौरा करें, वह उनको गाइड करें और निर्देश दें। जो आर. एम. पी. हैं वे साल के अन्दर महीने भर के लिये जिलों के चिकित्सालयों में लाये जायं ताकि वहां उनको नये-नये अनुभव हो सकें और अनुभव प्राप्त कर वे लोगों की अधिक सेवा कर सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मेडिकल कालेज के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा। यह बात विचित्र लगेगी आज के विज्ञान के जमाने में, मेरे ख्याल से मेडिकल कॉलेज में उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाय जिन्हें भगवान का डर हो। भगवान के डर से गरीब की सेवा तो वे करेंगे। मेडिकल कॉलेज चलते रहे हैं सब कर दाता के पैसे ही से और उसी पर ही निर्भर हैं फिर भी उस कर दाता को कुछ भी बदले में नहीं मिलता।

जालौर की बात तो हमारे गुरु कह गये फिर भी जालौर चिकित्सालय में नये निर्माणों के विषय में कहूंगा। वर्षों पूर्व एक-दो निवास डाक्टरों के लिये थे वे ही अब भी हैं। उस ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। डाक्टर वहां नहीं रहते हैं, फलस्वरूप बहुत से लोग तकलीफ पा रहे हैं। भविष्य में निर्माण हो तो डाक्टरों के निवास के निर्माण का विशेष ध्यान रखा जाय।

(श्री टीकमचन्द कान्त)

केशवाना ग्राम के सम्बन्ध में कांग्रेस सरकार ने कहा था कि मकान बना कर दे दो तो डाक्टर वहां आ जावेगा। वहां अभी तक कुछ हुआ नहीं। केशवाना ऐसे स्थान पर है कि बरसात में चार महीने वहां के लोग अन्य स्थान पर नहीं जा सकते। ऐसे स्थान पर तो डिस्पेन्सरी दवाखाना खोलना आवश्यक है। हमने तो मांग की है डिस्पेन्सरी की, वह नहीं दे सकते तो कम से कम एड पोस्ट ही दे दें। कम से कम अब तो एड पोस्ट दे ही दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मेरा विचार है वह मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। वह यह है कि 55-60 वर्ष की उम्र में डाक्टर रिटायर होते हैं उन्हें गांव में जाने के लिये उत्साहित किया जाय ताकि वे गांव में जाकर बैठ जायं। उससे भी गांव के लोगों को फायदा होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात और महाराष्ट्र में पांच-सात वर्ष के लिये प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द रहती है। हॉस्पिटल्स में उनकी लिस्ट लगी हुई रहती है जिन्हें कि प्राइवेट प्रेक्टिस करने की इजाजत नहीं है। उससे जनता को काफी लाभ मिलता है। वे रुचि से कार्य करते हैं, पांच-दस वर्ष तक अच्छा काम करते हैं तो नाम होता है वे। यह जानते हैं कि स्वतः ही जनता हमको पूछती आवेगी उस समय हमारी प्राइवेट प्रेक्टिस बढ़ेगी। एक एक्सपेरीमेन्ट के तौर पर ही सही कम से से कम पांच-सात वर्ष के लिये नये डाक्टर्स की प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द कर दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कटौती प्रस्ताव बहुत हैं। आपने काफी समय ले लिया है।

श्री टीकमचन्द कान्त : अब मंत्रिपरिषद् के विषय में थोड़ा कहूंगा। सब को बीस-बीस मिनट मिल गये हैं। मुझे भी ले लेने दें।

सत्ता के परिवर्तन के साथ नये मंत्री आये, नया रहन-सहन और नया तरीका आया। पहले गाड़ियां जो इनके आगे-पीछे दौड़ती थीं वे अब कम हुई हैं। अब इनकी कोठियों में गरीब विश्राम ले सकता है। खर्च कम हुए हैं, जनता के ज्यादा नजदीक पहुंचे हैं। लेकिन अभी आशा पूरी नहीं हुई है। आफिसर्स उनकी नहीं मानते हैं। ये शिकायत है। श्रीमान्, मंत्री जनता के प्रतिनिधि हैं। जनतंत्र के प्रतिनिधि हैं। उनकी बात आफिसर्स नहीं मानते हैं तो यह जनतंत्र का अपमान है। जनता के प्रतिनिधि का अपमान है, यह जनता का स्वयं का अपमान है। उनसे कहिये, आफिसर्स को सिखायें कि इस हाउस के माध्यम से उनको तनख्वाह मिलती है, उनको सत्ता मिलती है। उन्हीं लोगों का अनादर करें, उनके ही प्रतिनिधियों का अनादर करें और आदेशों की अवहेलना करें यह नहीं चल सकता। श्रीमन्, यदि ये मंत्री जनतंत्र का आदर नहीं करवा सकते हैं, अगर जनता का आदर नहीं करवा सकते हैं तो, श्रीमन्, मेरे खयाल में इन्हें मंत्री रहना भी उचित नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेजर साहब ने कहा था कि इनके ही कार्यकलाप हमारा आदर्श प्रस्तुत करेंगे, सही दिशा का मार्गदर्शन करायेंगे, यह ध्यान में रहे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओंकारलाल चौहान।

(अनुपस्थित)

(221)



(श्री उपाध्यक्ष)

श्री रावतराम आर्य ।

(अनुपस्थित)

श्री नरपत राम ।

(अनुपस्थित)

श्री हरचन्द सिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री काशीनाथ गुप्त !

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मुख्य सचेतक मुख बन्द का प्रस्ताव ला रहे हैं। 10।।। बज रहे हैं, हालांकि मेरा नाम भी बोलने वालों में आवेगा, इसको यहीं समाप्त करें।

श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज आपके डाइरेक्टोरेट ने सी.एम.एच.ओ. एस. कितना अपंग बना रखा है। उसने अधिकार केन्द्रित कर रखे हैं। आप जिलों के अन्दर देखें, जितने हैड आफ डिपार्टमेंट हैं, कलेक्टर हैं, अन्य आफिसर्स हैं सब को पूरे अधिकार प्राप्त हैं लेकिन आपके यहां पावर्स आफ हैड आफ डिपार्टमेंट सी.एम.एच.ओ. एस. को नहीं दी हुई हैं जिससे वहां पर जिले के समस्त चिकित्सालयों में काम हो नहीं पाता है। कम से कम उनको पावर्स दे दी जाय ताकि जिलों के अस्पताल में सुव्यवस्था कर सकें।

यह भी देखने में आया है कि जिलों में या सब ही जगह पर डाक्टर्स प्राइवेट प्रेक्टिस में लगे रहते हैं। मरीज को बिना फीस देखते नहीं। जब तक कोई भी मरीज उनके घर पर फीस देकर नहीं आता है तब तक ठीक प्रकार से उसको देखते नहीं और उसका अच्छा इलाज नहीं करते हैं। घर पर फीस दिये बिना प्रवेश तक नहीं मिलता है। भरतपुर पिछड़ा हुआ है। 30 साल से तो नाराजगी थी कि हमेशा वहां से कांग्रेस के विरोध में उम्मीदवार आता रहा है लेकिन आज के समय में भी उस क्षेत्र को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। 1977-78 की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट में लिखा है कि क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिये हर पंचायत क्षेत्र में एक प्राथमिक चिकित्सालय, दो डिस्पेन्सरी और एक एडपोस्ट खोली जावेगी लेकिन मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि वहां 15 वर्ष में एक डिस्पेन्सरी नहीं खोली गयी जब कि एक डिस्पेन्सरी ही वहां है। आज भी डिस्पेन्सरी या एडपोस्ट नहीं खोली गयी है। मैं नहीं समझता कि यह अवहेलना किस प्रकार से है जब कि वह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। पिछले वर्ष बाढ़ आयी। लाखों रुपयों की गोलियां वहां पर बांटी गई। पांच-पांच डाक्टर कम्पाउन्डर लगाये गये इस क्षेत्र में बीमारियों को रोकने को। जब डिस्पेन्सरी खोलने का नम्बर आया तो भूल गये। भटावली गांव में तीन बार डाइरेक्टर के कहने के बाद भी वहां पर कोई डाक्टर नहीं पहुंच पाये और चिकित्सा का कोई इन्तजाम न कर पाये। मेरे यहां चार-चार, पांच-पांच हजार की आबादी के कई गांव हैं जो चिकित्सा से महरूम हैं। मैं चाहूंगा कि आप अगली बार इन क्षेत्रों का ध्यान रखें चाहे आयुर्वेदिक औषधालय खोलें या एडपोस्ट खोलें जिन क्षेत्रों में बाढ़ के कारण पांच-पांच और छः-छः महीने तक आने-जाने के साधन नहीं हैं और बड़ी-बड़ी आबादी है उन गांवों को चिकित्सा सुविधा देनी चाहिए।

(श्री काशीनाथ गुप्त)

साथ ही साथ में आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि आज जिन क्षेत्रों के अंदर प्रसूति गृह अभी तक नहीं खुले हुए हैं वहां ऐसी व्यवस्था की जाये कि अगले वर्ष प्रसूतिगृह खुल जायें। हमारे यहां दस-बारह मील तक कोई प्रसूति गृह नहीं है जब कि वहां के रहने वाले प्रसूति गृह के लिए भवन देने को तैयार हैं। मेरा निवेदन है कि उन्हें यह सुविधा दी जाये। आपके जिले के अधिकारी, जिनको तजुर्बा नहीं है और जानकारी नहीं है, मनमाने ढंग से डिस्पेन्सरी और एडपोस्ट के लिए चाहे जहां कह देते हैं। उन्हें स्वयं को पता नहीं, कौनसा गांव कितना बड़ा है और कहां जरूरत है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वहां के अधिकारियों को आदेश कर दें कि जनप्रतिनिधियों की राय लेकर ही चयन किया करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र कुम्हेर में चिकित्सालय 15 साल पहले खुला था। आज भी वह उसी हालत के अन्दर है। वहां लेडी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है। जब कि हरएक प्राथमिक चिकित्सालय में एक स्त्री चिकित्सक रहती है लेकिन आज उसका भी मेरे क्षेत्र में अभाव है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बात और कहना चाहूंगा। राज्य सरकार की ओर से दवाइयां मुफ्त दी जाती हैं लेकिन भरतपुर क्षेत्र के अन्दर मैं रोजाना देखता हूं कि दवाइयों के वितरण का कोई इन्तजाम नहीं है। डाक्टर कहते हैं कि हमारे यहां प्रावधान नहीं है।

एक बात और बताना चाहूंगा। जिन क्षेत्रों में वहां के निवासी अपनी ओर से एड-पोस्ट के लिए या डिस्पेन्सरी के लिए भवन निर्माण कराके देने के लिए तैयार हैं उन स्थानों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और डिस्पेन्सरी में कई जगह नियुक्तियां नहीं होने से वहां स्थान रिक्त हैं इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि जहां डाक्टरों की कमी है वहां उनकी नियुक्ति करके उनको भेजना चाहिये नहीं तो गरीब आदिवासी संकड़ों किलोमीटर की दूरी से आते हैं और उनका समय पर इलाज नहीं होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा हैडक्वार्टर पर जो महात्मा गांधी चिकित्सालय का भवन बनाया उसमें गांव के रहने वाले आदिवासियों ने बच्चे से बूढ़े तक सबने अपने पेट काट कर चन्दा दिया। लगभग 4 लाख का चन्दा दिया और भवन बनाया लेकिन गरीब लोग दूरी से अपने इलाज के लिए आते हैं तो उनके साथ डाक्टरों का व्यवहार अच्छा नहीं रहता है। डाक्टर लोगों ने गुटबंदी कर रखी है। जो उनको पैसे देते हैं उन्हीं को एडमिशन मिलता है। आखिर आदिवासी हरिजन, जो गरीब होते हैं, सरकारी अस्पताल से वापस लौट कर प्राइवेट डिस्पेन्सरी में अपनी चिकित्सा कराते हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि बांसवाड़ा जिला हैडक्वार्टर पर जो डाक्टर आपस में गुटबन्दी करते हैं उनको वहां से हटाकर दूर भेजना चाहिए।

(श्री नाथूराम)

इसी तरह से पंचायत समिति गढ़ी में भारत सरकार द्वारा एक बाल विकास परियोजना चल रही है। वहां पर शिशु विशेषज्ञ का स्थान रिक्त है इसलिए वहां बच्चों की सेवा नहीं होती है। भारत सरकार उसका खर्चा देती है। आपके द्वारा मैं चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वहां पर डाक्टरों को भेजने की जल्दी व्यवस्था करनी चाहिये।

इसके अलावा जो कुए वगैरह हैं वहां दवा वगैरह का उपयोग नहीं होता है इसलिए वहां कई तरह की बीमारियां होती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से गांवों में जहां डिस्पेंसरी भवन बनाने हैं या एडपोस्ट भवन बनाने हैं उनको बनाने का खर्चा सरकार की नीति के अनुसार गरीब आदिवासियों पर ही थोपा जाता है। तो मैं आपको निवेदन करता हूं कि शहरों में जिस तरह से कोई भी भवन बनाया जाता है उसका खर्चा सारा सरकार देती है। उसी प्रकार आदिवासी क्षेत्रों में भी नीति में परिवर्तन करके सरकार के फण्ड से पैसा देकर भवन बनवाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

बड़ोदिया में एक डिस्पेन्सरी है। मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि वहां बाड़मेर से डाक्टर को भेजा है .....

श्री नवरंग सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर। मंत्री महोदय को डिस्टर्ब किया जा रहा है।

श्री नाथूराम : बाड़मेर से जिस डाक्टर का ट्रान्सफर किया है उस डाक्टर को बार बार सरकारी पेशियों पर कोर्ट में जाना पड़ता है। 15-15 रोज वह अनुपस्थित रहता है। मैंने मंत्री महोदय से भी निवेदन किया कि आप बाड़मेर से बांसवाड़ा भेजते हैं उसके बजाय उसका बांसवाड़ा स्थानान्तरण कर दिया जाये ताकि लोगों को नुकसान नहीं हो। मैंने माननीय मंत्री जी को इसके लिए पत्र भी दिया लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि उदयपुर जिले का कोई डाक्टर हो तो उसको रखें। इस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, औषधालयों के लिए मैं आपके द्वारा निवेदन करता हूं कि औषधालयों में जबरदस्त भ्रष्टाचार है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के वैद्य हैं उनको डूंगरपुर और बांसवाड़ा पहाड़ी क्षेत्र में भेजा जा रहा है। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि 22 साल में कोई भी मंत्री आयुर्वेद विभाग को नहीं सुधार सका और न भविष्य में सुधार सकेगा। जिस तरह से माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं मेडिकल एण्ड हैल्थ से आयुर्वेद को बिलकुल अलग कर दूसरे मंत्री के जिम्मे करना चाहिए नहीं तो आयुर्वेद विभाग में जहां औषधालयों में वैद्य लोग हैं वह गन्दी पालिटिक्स में रहते हैं और एलोपैथी का इलाज करते हैं। 8 आने का इन्जेक्शन आता है और गरीब आदिवासियों से वह वैद्य लोग पांच-पांच और दस-दस रुपये ले लेते है। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आयुर्वेद विभाग के जो वैद्य हैं वह एलोपैथी का इलाज नहीं करें और आयुर्वेद औषधियों से ही इलाज करें तो ही ठीक रहेगा, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। वह पैसा कमाते हैं और गरीब लोगों को लूटते हैं। यह भ्रष्टाचार है इसको मिटाना चाहिए। आयुर्वेद विभाग में जो वैद्य पैसा खर्चते हैं वह तो अपने घरों के नजदीक रहते हैं और जो नाजायज फायदा नहीं पहुंचाते हैं उनको

(श्री माथुराम)
पहाड़ी क्षेत्र में भेजा जाता है इसलिए वैद्यों की जल्दी से जल्दी व्यवस्था करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, गांवों में आदिवासी लोग नालों का पानी पीते हैं उन नालों में कोई दवाई नहीं डाली जाती है। इस कारण हमेशा वहां मलेरिया फैला रहता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इसकी जल्दी से जल्दी व्यवस्था करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डा. गंगासहाय।

श्री गंगासहाय (कठूमर) : मैं चिकित्सक हूं, चिकित्सा पर बोलूंगा, आप घंटी न बजायें।

श्री उपाध्यक्ष : आप कितना समय लेंगे ?

श्री गंगासहाय : थोड़े समय में ही समाप्त करता हूं।

Healthy mind is a healthy body

स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग होता है और स्वस्थ दिमाग होता है तो स्वस्थ विचार होते हैं।

महोदय, हर सरकार का परम कर्त्तव्य होता है कि अपने नागरिकों को स्वस्थ रखे। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति ऐसी है जो बहुत ही सुलभ है और सस्ती है। इसलिये 1971 में इस पद्धति को मान्यता दी और सरकार ने बोर्ड बनाया। परन्तु दुःख है कि जो काम किये जाने चाहिये, वह पिछली सरकार ने नहीं किये। उसका यह उदाहरण है कि होम्योपैथी बोर्ड का गठन 1971 में हुआ यह एक्ट के अनुसार नहीं किया गया। बहुमत के निर्णय को कभी माना नहीं। बोर्ड की मीटिंग में बोलना चाहते थे लेकिन आज तक मीटिंग नहीं बुलाई। महोदय, बोर्ड के प्रथम रजिस्ट्रार की नियुक्ति सरकार कर सकती है उसके बाद बोर्ड के निर्णय के अनुसार नियुक्ति होनी चाहिये। इलेक्टेड मेम्बर्स की परवाह नहीं की गई। अब तक जितने रजिस्ट्रार नियुक्त किये गये हैं उनके सम्बन्ध में बोर्ड से कोई राय नहीं ली गई। उपाध्यक्ष महोदय, बोर्ड के कर्मचारियों के लिये कोई सलेक्शन कमेटी नहीं बनाई गई है। मर्जी चाहा उसको रख लिया है। मर्जी चाहा उसको हटा दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त बोर्ड ने कुछ निर्णय लिये हैं, जैसे एक अच्छे पुस्तकालय के निर्माण का लेकिन आज तक इसे कार्यान्वित नहीं किया गया। इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान बोर्ड का कार्यकाल 9-4-78 को समाप्त होने जा रहा है जिसकी सूचना रजिस्ट्रार को देनी चाहिये। मेरी जानकारी के अनुसार सरकार को अभी भी जानकारी नहीं दी गई। महोदय, साफ जाहिर होता है कि सरकार अपनी मनमानी करना चाहती है।

इसी प्रकार मुझे पता लगा है कि होम्योपैथी बोर्ड की कल ही बैठक हुई है। उसमें जो सदस्य विचार रखना चाहते थे उनके द्वारा पूर्व में लिखित सूचना देने के उपरांत एजेन्डा में नहीं लिया गया, न सूचना दी। बोर्ड में जो निर्णय लिये जाते हैं उनकी भी सूचना लिखित में सदस्यों को नहीं दी जाती।

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में चलने वाले होम्योपैथी कालेजेज को मान्यता देने का निर्णय लिया गया था। तीन कालेज चलते थे। राजस्थान होम्यो मेडिकल कालेज, जयपुर, हेनिमन होम्यो महाविद्यालय, जयपुर और भारतीया होम्यो मेडिकल कालेज, भरतपुर। इस सम्बन्ध में

# Page No 225

225



( श्री गंगासहाय )
सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया था, कमेटी ने निर्णय लिया किन्तु एक सदस्य के एतराज करने के कारण हेनिमन होम्यो महाविद्यालय, जयपुर को मान्यता नहीं दी गई। इस कालेज को श्री सूरज कुमार गौड़ चलाते हैं। इसलिये कि उनका आर. एस. एस. से संबंध है....

श्री तिलोकचन्द जैन : कालेज का नाम क्या है ?

श्री गंगासहाय : हेनिमन होम्यो कालेज, जयपुर। गत 20 वर्षों से यह शिक्षण संस्थान चला रहा है। पहले बोर्ड की मान्यता नहीं थी, सैकड़ों, हजारों लोगों को उपाधियां देता रहा है जो चिकित्सा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, इसी कालेज के छात्र निकले हैं जिन्हें कई मन्त्रियों ने और मुख्य मंत्री ने प्रमाण-पत्र दिये हैं। महोदय, 11-4-77 को बोर्ड की मीटिंग में तीनों कालेजेज में छात्रों की भर्ती के लिये निर्णय लिया गया था और यह तय किया गया था कि जून, 77 में निरीक्षण करेंगे। उसके अनुसार हेनिमन होम्यो कालेज, जयपुर में भर्ती की लेकिन उसको मान्यता नहीं दी। इस कारण जो छात्र पढ़ रहे थे उनका जीवन अंधकारमय हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय, जो छात्र भर्ती किये गये, उनका भविष्य अंधकारमय हो गया। कालेज के पास अपना भवन है, पुस्तकालय है, इन्डोर वार्ड भी है योग्य शिक्षक भी हैं।

इसी प्रकार होम्योपैथी बोर्ड के सदस्यों और अधिकारियों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार मेडिकल सेक्रेटरी को है किन्तु दुर्भाग्य से मेडिकल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जो हैं वही चेयरमैन बन गये। अब कौन किस की अपील सुनेगा ? आज तक जो अपीलें की गई हैं, उनकी सुनवाई नहीं हुई है। 1971 में फीस ली किन्तु न रजिस्ट्रेशन किया गया और न फीस वापस की गई......

एक माननीय सदस्य : फीस हड़प जाते हैं।

श्री गंगासहाय : उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ एक बात और कहना चाहूंगा। इन अनियमितताओं को देखते हुए निवेदन है किसी होम्योपैथ को अध्यक्ष बनाया जावे।

अभी बताया गया कि गांवों में लोग जाने को तैयार नहीं हैं। बहुत से होम्योपैथ चिकित्सक गांवों में जाने को तैयार हैं। होम्योपैथ चिकित्सकों को मान्यता देकर गांवों में भेजा जाय तो गांवों की समस्या हल हो सकती है।

इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रंग जी।

( अनुपस्थित )

श्री उमराव सिंह गूजर।

( अनुपस्थित )

श्री परसराम मोरदिया।

( अनुपस्थित )

श्री शिवराज सिंह।

( अनुपस्थित )

श्री कुन्जी लाल।

( अनुपस्थित )

श्री शीश राम ओला।

( अनुपस्थित )

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री जीतमल जैन ।

श्री जीतमल जैन ( अलवर ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वस्थ शरीर के अन्दर ही स्वस्थ मन निवास करता है। जब मन स्वस्थ रहता है तो विचार भी स्वस्थ रहते हैं। उस स्थिति के अन्दर नागरिक अपने परिवार, अपने समाज और राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है उसका ठीक तरह से निर्वाह कर सकता है। इस कारण राज्य का परम कर्तव्य है कि अपने नागरिकों को स्वस्थ रखे। राज्य की यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों को स्वस्थ रखे ताकि वह ठीक प्रकार से जीवन-निर्वाह कर सकें। भारत जैसे देश के अन्दर चिकित्सा की इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिय। Prevention is better than cure रोग आये ही नहीं इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये। गांवों में लोगों को इस तरह से शिक्षित करें कि वह रोगों से बच सकें। गन्दगीके कारण रोग नहीं पनप सकें। लेकिन इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर पिछले 30 सालों में हमारा चिकित्सा का स्तर बहुत गिरा है। मेरा निवेदन है जो खाद्य पदार्थों का व्यापार करते हैं वे खाद्य पदार्थों में मिलावट करके बहुत बड़ा अन्याय करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, व्यापारियों पर छापों की कार्यवाही को आप थोड़ा तेजी से चलायें और जो इस प्रकार के अपराधी हैं, जो समाज के लोगों के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनको दण्डित करें। मेरा निवेदन है, इस काम में तेजी लायें। इसके साथ-साथ मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। हमारा प्रान्त बहुत बड़ा है इसलिये सीमित साधनों में चिकित्सा की सुविधायें पहुंचाना कठिन है। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा प्रत्येक जिले में जो अस्पताल हैं उनमें सभी प्रकार की सुविधायें हों और आधुनिक उपकरणों से उन्हें सुसज्जित करें ताकि जो ऐसे लोग हैं, जिनके उपचार की गांवों में व्यवस्था नहीं है, उन्हें जिला केन्द्र पर उपचार उपलब्ध हो सके। आबादी के अनुसार और आवश्यकतानुसार जिला केन्द्रों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है।

भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में बातें कही गईं। अधिकारियों के लिये विशेष रूप से कहा गया कि बड़े-बड़े वेतन पाने वालों के रिएम्बर्समेंट बिल बहुत बड़े-बड़े होते हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा, इन्कम-टैक्स देने वाले जितने भी अधिकारी हैं, जिन्हें चिकित्सा की सुविधायें उपलब्ध हैं उनका रिएम्बर्समेंट तुरन्त बन्द कर देना चाहिये और जो छोटे कर्मचारी हैं जो इन्कम-टैक्स नहीं देते हैं, उनके वेतन के साथ ही एक फिक्स अमाउन्ट जोड़ दिया जाना चाहिये ताकि छोटे कर्मचारियों को लाभ हो सके। बड़े-बड़े लोगों के लिये यह सुविधा बन्द कर देनी चाहिये।

इसके साथ ही कुछ अनियमितताओं की ओर भी मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा जो मेडिकल विभाग में चल रही है। सदन को जानकर आश्चर्य होगा कि आज तक.....

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आपस में वार्तालाप न करें। जो चर्चा चल रही है, उसको सुनें।

श्री जीतमल जैन : उपाध्यक्ष महोदय, सर्जिकल इन्स्ट्रूमेंट खरीदने के लिये सितम्बर में लिस्ट आउट हो जानी चाहिये। आज मार्च चल रहा है। किन्तु मेडिकल डिपार्टमेंट ने वह लिस्ट अभी तक नहीं निकाली है। जिला अस्पतालों में सी. एम. एच. ओ. पावरफुल है। वह अपने तरीके से सामान की खरीद करते हैं और अपने चहेते लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। यह मेडिकल डिपार्टमेंट की लापरवाही का एक नमूना है।

अब एक चीज मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा। पर्चेज कमेटी के लिये मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि पर्चेज कमेटी में उन लोगों को लिया गया है जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उन लोगों को पर्चेज कमेटी से निकालना चाहिये......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दो मिनट निवेदन करना चाहूंगा।

मैं रिश्वत के लिये भी निवेदन करना चाहूंगा। थाईफार्मा कम्पनी ट्रेड सैन्टर के द्वारा खरीद की गई है। मैं आपको इस विभाग की अनियमितता का जिक्र कर रहा हूं। ट्रेड-सैन्टर द्वारा खरीद की गई है जब कि उसके पास लाइसेन्स नहीं है। उसके द्वारा औषधियां खरीदना अनियमितता में आता है, इसके साथ ट्रेड सैन्टर के द्वारा दवा खरीदने में 15 प्रतिशत उसको खर्च देना होता है। इस तरह राज्य सरकार के कोष पर 1 लाख 20 हजार का बोझ पड़ता है। इस मसले की जांच होनी चाहिये। ट्रेड सैन्टर उन औषधियों का निर्माण नहीं करता है। आज तक इसके पास ड्रग लाइसेन्स नहीं है। इन सारी अनियमितताओं की जांच की जाय, और जो दोषी हैं उनको उचित दण्ड दिया जाय....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक बात अपने क्षेत्र की कह कर समाप्त करूंगा।

अलवर के अस्पताल के सम्बन्ध में मैंने पहले भी निवेदन किया था कि 220 बैड्स का अस्पताल है, लेकिन 300 बैड्स नियमित रूप से चलते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अलवर का जो अस्पताल है, उसमें रेवाड़ी तक के लोग उपचार के लिये आते हैं। कई बार वार्ड में बैड न मिलने पर रोगियों को जमीन पर लिटाना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जितनी रोगियों की संख्या है उसके अनुसार बैड्स की संख्या बढ़ाई जाय। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि अलवर के अस्पताल को 'ए' ग्रेड का घोषित किया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ जो वहां का जनाना अस्पताल है उसकी भी दयनीय स्थिति है। उसके चारों तरफ बाउन्ड्री वाल नहीं है। उसके आस-पास के लोगों ने उस जगह को एक तरह से परमानेन्ट लेट्रीन बना रखा है। सारे एरिया में गन्दगी का वातावरण है। उपाध्यक्ष

# Page No 228

(228)



(श्री जीतमल जैन)

महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि उसकी बाउन्ड्री वाल ग्रति शीघ्र खिचवाने की व्यवस्था करें ।

धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन लाल ।

श्री मोहनलाल शर्मा ( डूंगरगढ़ ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मुझे ग्रापके विधान सभा के सचिवालय से ग्रापत्ति है कि हमेशा यह देखा जाता है कि पहले-पहल नाम 3-4 ग्रादमियों के स्पेसिफिकली लिये जाते हैं जैसे कि उनको कटौती प्रस्तावों का उद्घाटन करने का ठेका दे रखा है। यह ठेका दे रखा है, तब तो कोई बात नहीं है ग्रन्यथा इसकी व्यवस्था कीजिये ग्रौर......

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : ग्रान ए पॉइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय ने यह कहा कि ग्रापने ठेका दे रखा है । ग्रापने यह ठेका दे रखा है । यह लेंग्वेज मोस्ट ग्राब्जेक्शनेबल है। ग्रासन के लिये ये शब्द उचित नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य का तात्पर्य सचिवालय से होगा ।

श्री मोहनलाल शर्मा : कोई लॉटरी से व्यवस्था कीजिये। 11-11 बज जायं, तब भी हमारा नम्बर नहीं ग्राता है......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कटौती प्रस्ताव जितने प्रस्तुत किये जा सकते हैं ग्रौर जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होते हैं, उनके ग्राधार पर किन व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है उनके नियम बने हुये हैं। उन नियमों को भी देखने का कष्ट करिये ।

श्री मोहनलाल शर्मा : मैं एक बात निवेदन कर रहा हूं कि भ्रष्टाचार के बारे में नहीं कहना चाहता हूं । इतना ही कहूंगा कि सारे सदस्य इस पर बोल चुके हैं ग्रौर कोई भी इसके पक्ष में नहीं है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार नहीं है। ग्राप कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है लेकिन सारा सदन कहता है कि भ्रष्टाचार है। हमारे मंत्रिमण्डल का जो सचिवालय है यह नहीं कहेगा कि भ्रष्टाचार है। उनके यहां से उत्तर ग्राएगा कि सब बातें गलत हैं । मेरा निवेदन है ग्रापके माध्यम से कि मंत्रिमण्डल द्वारा प्रस्ताव करवा दीजिए, उसे राज्यपाल को भिजवा दीजिए ग्रौर कानून बना दीजिये कि भ्रष्टाचार कहना कानूनी जुर्म है ताकि हमेशा के लिए रगड़ा मिट जाय ।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि ग्राप कहते हैं, ग्रापके माध्यम से हमारे मंत्रिमण्डल के जितने भी लोग हैं वे कहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे ग्राई. ए. एस., ग्राई. पी. एस. ग्रफसर हैं, हमारा सचिवालय है वह हमारा कहना मानता है । मैं यह कहता हूं कि केदारजी ने कई हुक्म दिए होंगे, ग्रन्य मंत्रियों के पास कम जाने का मौका मिलता है, उन्होंने जो हुकुम दिए वह तीन-चार महीने से पेंडिंग पड़े हुए हैं। उनके पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि जांच करावेंगे कि उनका निर्णय ठीक है या क्या है? मन्त्रिमण्डल के सदस्य ग्रपने गरेबान में नजर डाल कर देख लें कि क्या यह बात सही है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य से मैं पूछना चाहूंगा कि चिकित्सा सम्बन्धी मांग पर बोल रहे हैं या मंत्रिमण्डल पर बोल रहे हैं ।

श्री मोहनलाल शर्मा : मैं माफी चाहूंगा, मेरा जो दर्द था वह मैंने कह दिया अब मैं कटौती प्रस्तावों पर आ रहा हूं।

हमारा चूरू जिला बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है........

(व्यवधान)

बहुत अच्छा है लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि.......

श्री नवरंगसिंह : बड़ी गहराई से बोल रहे हैं।

श्री मोहनलाल शर्मा : कोटा में मंत्रिमण्डल की बैठक हुई, कितने मामले उनके सामने आए ? मैं आपकी मार्फत निवेदन करूंगा कि चूरू में भी मंत्रिमण्डल की बैठक करके देखें कि चूरू जिले में कितने अभाव अभियोग हैं और क्या उसकी हालत है ? किसी भी विभाग द्वारा उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा आपकी मार्फत कि मंत्रिमण्डल की बैठक बुलाने के लिए बाध्य किया जावे....

(व्यवधान)

मैं तो मेरे जिले की बात कह रहा हूं। बारी बारी से सभी का नम्बर आए....

(व्यवधान)

आप डिस्टर्ब नहीं करें, तो मैं एक मिनट में खतम कर देता हूं।

अब एक निवेदन करूं, आपकी मार्फत मंत्रिमण्डल से कि अभी मालूम हुआ मेजर साहब के कहने से और दूसरे साथियों के कहने से कि हमारी राजस्थान सरकार ने एडपोस्ट व डिस्पेंसरीज की लिस्ट निकाल दी है। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि कैसे लिस्ट निकल गई ? जनप्रतिनिधियों की कोई सलाह नहीं ली गई, चूरू जिले की विकास समिति की कोई सिफारिश नहीं ली गई। हम तो उम्मीद करते थे कि हमारी सलाह ली जाएगी, लेकिन अफसोस है कि जन प्रतिनिधियों को विश्वास में नहीं लेकर लिस्ट निकाल दी। यह भी सचिवालय की एक देन है। इस प्रकार से नहीं होना चाहिये। आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि इसमें गड़बड़ है। इस गड़बड़ को दूर किया जावे।

चूरू जिले में 43 डाक्टर हैं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पांच-छः डाक्टर हैं और तीन जगह बड़ी म्युनिसिपैलिटीज हैं। पहले चतुर्वेदी साहब से आठ महीने तक रिक्वेस्ट करते-करते मैं थक गया, बिदासर में डॉक्टर आठ महीने से एक भी नहीं है, तो आप अन्दाज लगाइये....

श्री उगमराज मेहता : बजट पास कर दो, एक तारीख से काम चालू हो जाएगा।

श्री मोहनलाल शर्मा : नए मंत्री महोदय से भी निवेदन किया है कि डूंगरगढ़ और मौबासर में लेडी डाक्टर नहीं है। चूरू हैडक्वार्टर पर 13 डाक्टर की पोस्टें हैं लेकिन दो ही डाक्टर हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी प्रकार से मैं जनता पार्टी के मंत्रिमण्डल से निवेदन करूंगा कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, इससे जनता पार्टी की छवि बिगड़ती है। मैं कह देता हूं कि आप जानें और आपका धर्म जाने।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री रामरघुनाथ : धन्यवाद है ।

श्री मोहनलाल शर्मा : बस हो गया साहब ।

इसी प्रकार से मैं निवेदन करूं कि पहले भी हमारे यहां के मंत्री रहे हैं, स्टेट मंत्री भी रहे हैं । उस समय चूरू जिले में कांग्रेस ने जितने औषधालय खोले, अस्पताल और डिस्पेंसरीज खोली, उनकी चौथाई भी, पच्चीस पर्सेंट भी अभी नहीं खोली गई हैं । मेरी तो समझ में नहीं आता कि आपका क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से आप किस की सलाह लेते हैं ? मैं निवेदन करूंगा कि आप हमसे सलाह लीजिए, मानें न मानें यह आपकी मर्जी है । हमारा काम सुझाव देना है ताकि आपको असलियत का पता लग सके ।

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

धन्यवाद साहब ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अचलाराम ।

( अनुपस्थित )

श्री दाऊ दयाल जोशी ।

( अनुपस्थित )

श्री चुन्नीलाल ।

( अनुपस्थित )

श्री हरीसिंह यादव

श्री हरिसिंह यादव (बानसूर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रात्रि के सवा ग्यारह बजे स्वास्थ्य विभाग की मांगों के बारे में कटौती प्रस्ताव पेश करना पड़े यह शायद स्वास्थ्य के नियमों के अनुकूल बात नहीं होगी । फिर भी सदन के माननीय सदस्यों की भावना और जो सचिवालय बैठा है उसके स्वास्थ्य नियमों को ध्यान में रखते हुए मैं केवल सरकार को अपने कटौती प्रस्तावों के जरिये दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं ।

एक तो, मान्यवर, हमारी सरकार ने पिछले अधिवेशन में घोषणा की थी कि हमें जहां दो तरह की फैसेलिटीज हैं आयुर्वेद और एलोपैथिक, उन दोनों को एक जगह नहीं रखेंगे । यह बड़ा टैक्निकल इनका दिमाग चल रहा था । नौ महीने गुजार दिए आज तक इस योजना को कार्यान्वित नहीं कर सके । राजस्थान के गांवों में चिकित्सा की कमी है जो इस बजट से पूरी नहीं हो सकती । दूर दराज के बेचारे मरीजों को सुविधा दी जा सकती थी परन्तु अभी तक सरकार ने नहीं दी । मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि राजस्थान के अन्दर जहां भी गांवों के अन्दर दो सुविधायें प्रचलित हैं उनमें से एक को शीघ्र ऐसी जगह पर भेजें जहां पर कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है। इससे ग्रामीण जनता को सुविधा मिलेगी ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : Good suggestion.

श्री हरिसिंह यादव : इन्होंने जो प्रगति रिपोर्ट दी है यह बड़ी निराशाजनक है एक मायने में । इसमें परिवार कल्याण का जो चैप्टर है उसमें, मान्यवर, इन्होंने यह बताया है कि एक साल की अवधि में पुरुषों की नसबन्दी एक हजार से कम है और महिलाओं की जो है वह उससे कई गुना ज्यादा है । यह इस बात का द्योतक

(श्री हरिसिंह यादव)

है इनके शब्दों के अनुसार भी, मान्यवर, आज भी हमारे समाज के अन्दर महिलाओं का शोषण है जब कि महिलाओं का दर्जा समान है फिर भी उनको इस बात के लिए पुरुष प्रेरित ज्यादा कर पा रहे हैं कि वे अपना आपरेशन करवा दें। पुरुष को उसमें छोड़ दें। यह स्थिति अच्छी नहीं है। मैं यह मानता हूं कि आपातकाल के दौरान जिस तरह से अमानुषिक तरीके से नसबन्दी की गई वह ठीक नहीं थी, परन्तु सरकार को, माननीय मुख्य मंत्रीजी और हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी को इस पर ध्यान देना चाहिए। इनकी कोई योजना सालाना लक्ष्य की होनी चाहिये। अन्यथा सरकार किसी को भी स्वस्थ नहीं रख सकेगी यदि इसी रफ्तार से आबादी इस राजस्थान और हिन्दुस्तान में बढ़ती रही। बढ़ती आबादी के लिए पौष्टिक आहार, वस्त्र और दवाइयां चाहियें। खाने वालों की संख्या निरन्तर बढ़ती रही तो किसी को भी स्वस्थ्य नहीं रख सकेंगे। मेरी यह मान्यता है कि जब तक यह सरकार, यह राजस्थान की सरकार टार्गेट फिक्स नहीं करेगी कि हमको इस वर्ष के अन्दर इतने परिवारों का कल्याण करना है, उनको नियोजित करना है, उनको समझाना है तब तक राजस्थान का भला नहीं कर सकते।

श्रीमान् ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए हैं। पंचायतों से यह काम कराना चाहिए। तो उसको यह काम देने की व्यवस्था करनी चाहिए। बच्चों की बाढ़ को रोकने के लिए अगर सरकार पंचायतों के जरिये, पंच और सरपंचों के जरिये समाज को मोबिलाइज करे और अपनी तरफ से प्रोत्साहन दे तो मैं निश्चित रूप से यह सकता हूं कि परिवार कल्याण का काम आगे जा सकता है और प्रदेश में जन संख्या नियोजित हो सकती है।

श्रीमन्, एक बात मैं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं। यह जो हमारा पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट है इसमें मलेरिया की रोकथाम करने के लिए डी.डी.टी. दवा आती है। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि हिन्दुस्तान के मच्छर इस डी.डी.टी. की दवा को खाकर इतने मजबूत हो गये हैं कि उनकी गति हवाई जहाज के मुताबिक हो गई है। वे न गर्मी से मरते हैं, न सर्दी से मरते हैं और न इस दवा से मरते हैं। हिन्दुस्तान के अन्दर और राजस्थान के अन्दर स्वास्थ्य विभाग में यह सबसे बड़ा सुधार करना पड़ेगा कि यदि बीमारियों को इरेडिकेटेड करना है, यदि उनकी रोकथाम करनी है तो प्रमाणित औषधियां निर्मित होनी चाहिए और प्रमाणित औषधियों के निर्माण के लिए कदम उठाये जाने चाहिए। दवा खाने वालों को हम दवा मुफ्त में नहीं दे सकते हैं, ऐसी हमारी स्थिति है लेकिन कम से कम प्रमाणित आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवा तो हो, जो वाजिब रेट पर मरीजों को दी जाय। यह व्यवस्था तो सरकार अवश्य करें।

इसके साथ-साथ मैं केवल एक बात हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट को प्रशासनिक दक्षता को निवेदन करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में 6 बैड्स की डिस्पेन्सरी है नीमूचाना गांव में। जब से मैं विधायक बना हूं तब से वहां पर कोई डाक्टर नहीं गया है ..

एक माननीय सदस्य : और जब तक विधायक रहेगा, तब तक नहीं जायेगा।

श्री हरिसिंह यादव : वहां पर एक कम्पाउण्डर है। किसी डाक्टर साहब को

(श्री हरिसिंह यादव)

नहीं भेजा। मैंने निवेदन किया था कि किसी डॉक्टर को भेजो, लेकिन हमारे यहां डॉक्टरों की मन्शा यह रहती है वे गांवों में नहीं जायेंगे, इसलिये वह नहीं आये। अगर डॉक्टर देहात में नहीं जायेंगे तो हम देहात के गरीब तबके को रिलीफ नहीं दे सकेंगे। डाक्टरों की इस मंशा को, जनता सरकार को देहातों को मेडिकल रिलीफ देने के लिए समाप्त करना होगा। मान्यवर, ऐसे कई डाक्टर हैं जो शहरों में अधिकारियों की चापलूसी करके और नेताओं को पकड़कर कई वर्षों से जमे हुए हैं। उनको देहात की तरफ भेजना होगा। मेडिकल डिपार्टमेंट को नियम बनाना होगा कि डाक्टर साहबान को एक निश्चित समय तक देहातों में जाकर सेवा करनी पड़ेगी ताकि उनके अन्दर जो अच्छे सक्षम डाक्टर हैं उनका फायदा देहातों को को भी मिले। मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह मसला जो है हमारे यहां के डाक्टरों का गांवों में नहीं जाने का, डाक्टर तनख्वाह भी लेते रहते हैं और गांवों में हुकुम से जाते नहीं हैं, इस बारे में कड़ाई की जाय और डाक्टरों को बाध्य किया जाय कि डाक्टर गांवों में जाकर सेवा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती श्यामा कुमारी।

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द जैन।

(अनुपस्थित)

श्री रघुवीरसिंह कौशल।

(अनुपस्थित)

श्री शिव नारायण।

(अनुपस्थित)

श्री चिरंजीलाल।

श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ शब्दों में अपने सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि उनको मंत्री महोदय क्रियान्वित करने की कोशिश करें।

मेरा एक सुझाव है कि इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के अन्तर्गत जयपुर में दवाइयां बनाने का कारखाना खोला जाय, उसमें किसी प्रकार के और साधनों की आवश्यकता हो ऐसी बात नहीं है। जिन कारखानों में इस प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता न हो उन कारखानों को ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में खोलें जहां कि रेल और सड़क की सुविधा हो, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो। मेरे क्षेत्र के सराधना गांव का नाम इस संबंध में लूंगा। वहां पर जमीन मिल जायगी स्टेशन के नजदीक ही और वह मेन रोड पर है। इस प्रकार के गांवों का विकास होना चाहिए।

इसी प्रकार से हर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर पर एक सर्जन और उसके साथ ही एनेस्थेसिया में एक्सपर्ट डाक्टर निश्चित रूप से रखे जाने चाहियें, अन्यथा लोगों को लम्बी दूर चलकर बड़े-बड़े अस्पतालों में अपने आपरेशन कराने पड़ते हैं।

दूसरा मेरा सुझाव है कि जो प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स हैं उनमें जो डाक्टर्स रहते हैं उनके अन्तर्गत उप-केन्द्र चलते हैं तो 15 दिन के अन्दर एक निश्चित दिन, निश्चित समय मुकर्रर करना चाहिए जब कि डाक्टर वहां जायं। इससे लोग इकट्ठे होकर डाक्टर का लाभ उठा सकते हैं। प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में जीप गाड़ी रहती है उसके माध्यम से उसका

(श्री चिरंजीलाल गर्ग)

एप्रोच हो सकता है। इससे गांवों में एलोपैथिक चिकित्सा के बारे में श्रद्धा उत्पन्न कर सकते हैं।

एलोपैथिक विभाग में कई प्रकार की अनियमितताएं होती हैं, मैं उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। अजमेर मेडिकल कालेज में एक ट्यूटर पेड्रियाट्रिक्स में थे उनका केवल स्थानान्तरण इसलिए किया गया कि एक नई पोस्ट जयपुर में बढ़ाने से एक आई. ए.एस. के लड़के को पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन देना था दुर्भाग्य है, आई.ए.एस. आफिसर के लड़के के एडमिशन के विरुद्ध हाई कोर्ट में जाकर रिट के माध्यम से स्टे लेकर एडमिशन नहीं होने दिया। इस प्रकार की अनियमितताएं मेडिकल डिपार्टमेंट में होती हैं। इस प्रकार से अपवाद होता है, आई.ए.एस. के लड़के को एडमिशन देने के लिए ट्यूटर की नई पोस्ट बनाकर अजमेर के ट्यूटर को लाया गया। इस प्रकार की अनियमितताओं को रोका जाना चाहिए अदरवाइज हमें कहना पड़ेगा कि Health Commissioner is specialist in committing irregularities illegalities in his departme t इसलिए मैंने निवेदन किया कि इस प्रकार की अनियमितताएं नहीं होनी चाहिए।

इसके साथ-साथ आयुर्वेद विभाग के बारे में सुझाव देना चाहूंगा। आजकल जो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट करते हैं वह अधिकांश एलोपैथिक मेडिसिन्स को काम में लेते हैं। इसके लिए इनको प्रतिबन्धित करना चाहिए, अन्यथा वैद्यों को गांवों के अन्दर भेजने का लाभ नहीं है। पब्लिक हैल्थ सेंटर पर डॉक्टर रहते हैं। आयुर्वेद के वैद्यों को आयुर्वेदिक औषधियों को काम में लेना चाहिए। आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में औषधियां पर्याप्त मात्रा में रखी जानी चाहिए। अगर शासन ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकता है तो ऐसे औषधालय खोलने की आवश्यकता नहीं है जिनमें आयुर्वेदिक औषधियां उपलब्ध नहीं हो।

आयुर्वेदिक अनुसंधान पर सवा करोड़ रुपया बरबाद क्यों किया जाता है? वहां किसी प्रकार का अनुसंधान नहीं किया जाता है केवल 12 व्यक्ति अपनी जीविका उपार्जित करते हैं। अगर 12 लोगों को ही आजीविका देनी हो तो उसको अनुसंधान केन्द्र के नाम से नहीं चलाना चाहिए, उसको बन्द कर देना चाहिए, अन्यथा यह आयुर्वेद शोध के लिए कलंक है।

इसके साथ-साथ आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे एक मित्र ने कपूर की बात यहां पर कही थी। राज्य सरकार कपूर 56) रु. किलो से खरीदती है, दूसरी ओर अन्य कम्पनियां कपूर इम्पोर्ट करती हैं और वह 35) रुपये किलो में बेचती हैं। अगर राजस्थान सरकार स्वयं इम्पोर्ट करे तो वह 15 रुपये किलो में पड़ेगा। मैं नहीं समझता हूं कि राजस्थान सरकार 56 रुपये में क्यों कैम्फर खरीदती है जब कि 15 रुपये किलो में वह इम्पोर्ट कर सकती है? इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसी प्रकार से सार्वजनिक संस्थान रद्दी एक रुपये किलो में बेचते हैं और हमारा आयुर्वेदिक विभाग खरीदता है उसको ढाई रुपये किलो में, इस ओर विभाग को ध्यान देना चाहिये आप देखिये कि 50-60 रुपये किलो में हींग के टेन्डर इन्वाइट किये जाते हैं और उस में 6 रुपये किलो का हींग डाला जाता है। इस

(श्री चिरंजीलाल गर्ग)
प्रकार से दवाइयों के निर्माण में कितनी ज्यादती होती है। यहां तक घोटाला होता है कि जिस मात्रा में कच्चा माल खरीदा जाता है उस प्रपोर्शन से औषधियों का निर्माण नहीं किया जाता है। आयुर्वेद विभाग के मंत्री महोदय इस बात पर ध्यान नहीं दे सकते हैं कि कितना धन बरबाद हो रहा है। कच्चे माल की खरीद के अनुपात में औषधियों का निर्माण नहीं होता है। एक वैद्य रामनारायण निर्माणशाला में थे। वह लाखों रुपयों का घोटाला कर चुके हैं। उसकी इन्क्वायरी चल रही है, लेकिन आज फिर उसी बेईमान आदमी को अजमेर में ले जाकर बैठा दिया गया है। जिनके खिलाफ इस प्रकार की इन्क्वायरी चल रही है उन्हीं को उस स्थान पर ले जाकर रखा जाता है, यह दुखद बात है।

इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे निदेशक महोदय, आयुर्वेद के होने चाहिए, वे नहीं हैं। इसके कारण हमारे प्रदेश के अन्दर जो व्यवस्था होनी चाहिए, वह नहीं कर पा रहे हैं। जल्दी से जल्दी नियुक्ति कर इस के प्रशासन में सुधार लाया जाना चाहिए।

इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मेघराज पंवार।

(अनुपस्थित)

श्री मंजूर अली।

(अनुपस्थित)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री अमृतलाल पंवार।

(अनुपस्थित)

श्री मत्स्यसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री गोविन्दसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री सुखलाल सेणचा।

(अनुपस्थित)

श्री जगतार सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री बुलाराम।

(अनुपस्थित)

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता।

(अनुपस्थित)

श्री गणेश लाल बैरागी।

(अनुपस्थित)

श्री गोपाल सिंह (आहोर)।

श्री गोपालसिंह (आहोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दो-तीन आयुर्वेदिक औषधालय और एक प्राइमरी हैल्थ सब-सैंटर की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करूंगा। ग्राम बाला में छः साल से आयुर्वेदिक औषधालय के लिए बिल्डिंग बनी पड़ी है परन्तु अभी तक स्टॉफ वहां पर नहीं पहुंचा है। इसी तरह गांव ऊण, जो आहोर का एक बड़ा केन्द्र है, के लोग नदी होने से वर्षा के दिनों में चिकित्सा की सुविधा नहीं

(श्री गोपालसिंह)
ले सकते। इसलिए एक आयुर्वेदिक औषधालय वहां पर खोला जाना आवश्यक है। आहोर में लेडी डाक्टर नहीं है जब कि यह म्युनिसिपल कस्बा है। वहां पर लेडी डाक्टर की आवश्यकता है। इसी तरह ग्राम भाद्राजून में प्राइमरी हैल्थ सब-सैन्टर के लिए बिल्डिंग बनी हुई है। वहां पर एक प्राइमरी हैल्थ सब-सैन्टर जल्दी खोला जाए।

जनसंख्या के बारे में काफी कहा गया है। मेरा एक सुझाव है। जनता को एज्यूकेट करने की जगह अगर स्कूलों में जनसंख्या के नाम का एक विषय खोल दिया जाए और उसके अन्दर परिवार कल्याण की शिक्षा दी जाए जिसमें बढ़ती हुई जनसंख्या का डर और उसका अहसास कराया जाए तो मेरे ख्याल से यह काम आसान हो जाएगा। आज हम कहते हैं कि गांवों में गरीब लोगों को समझावें। परिवार कल्याण की ओर हम ध्यान दें। मेरे ख्याल से स्कूलों में हमने यह विषय यदि खोल दिया तो भविष्य में समाज कल्याण पर हमें इतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा और न ही लोगों को जंगलों में भागना पड़ेगा।

शहरों में या गांवों में नए अस्पताल खोलने के बजाए जो अस्पताल जिस तरीके के हैं, पहले उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए तो उससे ही आस-पास के लोगों को ज्यादा फायदा मिल सकता है।

एक और निवेदन है। जयपुर शहर में न्यूरो सर्जन डॉ. आर.एस.माथुर हैं। उनका अभी अभी स्थानान्तरण जोधपुर में आर्डिनरी सर्जन के रूप में कर दिया गया है। मेरे ख्याल से इस क्वालिफिकेशन का एक ही डाक्टर है। मैं समझता हूं, जयपुर राजधानी होने के नाते न्यूरो सर्जरी का कोई डाक्टर यहां रखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। आर.एस.माथुर, जोधपुर शहर के ही रहने वाले हैं फिर भी मैं चाहूंगा और अगर ठीक समझें तो उन्हें जयपुर के अस्पताल में ही रखा जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मणीराम।

श्री मणीराम (तारानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को आपने बोलने का मौका दिया है। अब की बार यह असेम्बली चलने के बाद यह मेरा पहला मौका आया है जब दो शब्द कहने के लिये आपने मौका दिया है।

इन्सान को, जब धरती पर जन्म लेता है, तो पांच चीजों की जरूरत होती है। चाहे वह गरीब हो, चाहे वह अमीर हो लेकिन ये पांच चीजें जीवन के लिए अनिवार्य हैं। लेकिन ये चीजें कुछ साधन सम्पन्न को मिलती हैं, गरीब आदमी को नहीं मिलती हैं। सबसे पहले उसको पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। उसके बाद उसको रहने के लिए मकान मिलना चाहिए। उसके बाद चिकित्सा की सुविधा मिलनी चाहिए। उसके बाद वस्त्र मिलने चाहिए। फिर शिक्षा मिलनी चाहिये। इन पांच चीजों के बगैर इन्सान नहीं रह सकता है। ये पांच चीजें समाज के अन्दर बड़ी जरूरी हैं। कोई पैसे वाला बीमार पड़ जाएगा तो बड़े डाक्टर, सर्जन दौड़े जाएंगे लेकिन एक गरीब बीमार हो जाएगा तो उसको चार पैसे की टिकिया नहीं मिल सकती। उसका बच्चा, बीबी बीमार हो जाए तो उसे दवा नहीं मिलती है। पैसे वाले का इलाज होगा लेकिन गरीबों का इलाज नहीं हो सकता है। गांव वाले शहर में आएंगे, डॉक्टर को फीस देंगे तो इलाज होगा। पैसे का साधन जिसके पास है, उसका इलाज होगा। वहां कोई उसका इलाज करने

(श्री मगीराम)

वाला नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जहां पैसे वाले का इलाज हो, वहां गरीबों का भी इलाज होना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि गांव में बसने वाले जो गरीब शहर में अपना इलाज कराने आते हैं उनके पास साधन नहीं है। इसलिये डाक्टर को चाहिये कि वह उनका इलाज करे।

खैर, आज मेरे क्षेत्र के अन्दर एक अस्पताल है और एक शिशु कल्याण केन्द्र भी है। इस शिशु कल्याण केन्द्र में और अस्पताल में 25 बैड हैं। जनसंख्या के हिसाब से हम देखते हैं तो दवाइयां ना के बराबर हैं। साल भर में दस-ग्यारह हजार रुपये की दवाइयां मिलती हैं। सारी तहसील में एक ही जगह ऐसा साधन है। सारे लोग वहां आते हैं। उनको दवाई नहीं मिलती है। जिसके पास पैसा है वह बाजार से मोल लेकर इलाज कराना चाहे तो करा सकता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि तारानगर तहसील में एक ही इलाज होने की जगह है, मरीज वहां पर आते हैं किन्तु वहां पर दवा दारू का प्रबन्ध नहीं है इसलिये कृपा करके थोड़ा सा बजट तारानगर तहसील के लिए बढ़ायें। वहां पर कोई रेलगाड़ी का भी साधन नहीं है ताकि दूसरी जगह जा सकें। ऊंट गाड़ी द्वारा वहां के मरीज आते हैं। वहां दवाइयों का कोई प्रबन्ध नहीं है। बहुत मामूली वहां का बजट है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो दवाई का बजट है, वह बढ़ायें।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत छोटी सी बात है। इसको पूरा करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा मंत्री का ध्यान उन लोगों की ओर दिलाना चाहूंगी, जो गरीब हैं, जिन्हें रोज तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जो बिना दवाई के ही बेमौत मर जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय का ध्यान मेरे क्षेत्र में स्थित सिरसी में प्राइमरी हैल्थ सन्टर की ओर दिलाना चाहूंगी।

( व्यवधान )

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : दो-दो अस्पताल हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : 23-2-78 को मैंने वहां सरप्राइज विजिट किया। वहां दोनों ही डाक्टर उपस्थित नहीं थे। उपस्थित कर्मचारियों ने सरपंच व जनता के समक्ष बताया कि डाक्टर शर्मा दौरे पर गये हुए हैं। दूसरी डाक्टर भदौरिया बिना किसी सूचना के दो दिन से नहीं आयी हैं। उनके बारे में मालूम हुआ कि इसी तरह से वह गैर हाजिर रहती हैं व यदा-कदा आकर सब दिनों की हाजरी भर जाती हैं। हाजरी रजिस्टर पेज 9 पर रिमार्क मैंने स्वयं लिखा। उस पर उपस्थित सरपंच व कर्मचारियों ने साइन किये। कहने का मतलब यह है कि यदि हम चिकित्सा सुविधाएं देते हैं, तो समय-समय पर उनको चैक भी किया जाना चाहिये कि वहां का

( सुश्री पुष्पा जैन )

स्टाफ काम कर रहा है या नहीं ? मेरा यह आग्रह है कि ऐसी चिकित्सा सुविधाओं को और अस्पतालों को बन्द कर दिया जाये जिन्हें हम सुचारु रूप से चला नहीं सकते क्योंकि हमें सरकारी पैसों को खराब करने का कोई हक नहीं है जिसको हम जनता से वसूल करते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा ही हाल जाहोता में स्थित प्राइमरी हैल्थ सेण्टर का है। सिरसी के डाक्टर की आवास समस्या का भी मैं जिक्र करना चाहूंगी। वहां के डाक्टर ने बताया कि जो आवास सुविधा है उसको डा. सक्सेना इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि कई वर्षों से सस्पेन्ड हैं। वह किसी प्रकार से उस मकान को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वह जनता से सरकारी डाक्टर की गैर मौजूदगी में मनमानी राशि वसूल करते हैं। मुझे ताज्जुब है, इतने सालों से वह डाक्टर सक्सेना अवैधानिक तरीके से वहां रहते हैं, और आज तक सरकारी जानकारी में यह तथ्य नहीं आया है ।

( व्यवधान )

उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मैं चिकित्सा मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहती हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो चिकित्सा सुविधा देते हैं, उसके साथ लेडी डाक्टर भी देनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में लेडी डाक्टर की सुविधा देने की अधिक आवश्यकता है। ग्रामीण महिलाएं अभी ऐसी शिक्षित नहीं हैं कि वह ठीक तरह से मेल डाक्टर को अपनी बात बयान कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगी कि किसी भी स्थान से किसी डाक्टर का स्थानान्तरण होता है तो जल्दी से जल्दी दूसरा डाक्टर भेज देना चाहिए ।

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय को नोट करना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : हृदयंगम कर रहे हैं ।

सुश्री पुष्पा जैन : जयपुर अस्पताल के अन्दर दवाएं मरीजों को दी नहीं जाती हैं। बहुत खराब व्यवस्था चल रही है। चर्मरोग विभाग के डाक्टर के खिलाफ शिकायतें होने के बावजूद भी उन्हें तीन साल से अस्थायी नियुक्ति दी जा रही है। 30 वर्षों से इसी प्रकार का चल रहा है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वहां पर कोई फिजीशियन नहीं है। यहां पर भी कई बार ये बातें आई हैं ...

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : क्या कह रही हैं, आप बीच में ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया जारी रखें।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है लेकिन जरा भी दर्द अनुभव नहीं करती है। मेरा निवेदन है कि सरकार खास तौर से इस पर ध्यान दें ।

( व्यवधान )

उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण एरिया में अच्छे प्राइवेट डाक्टर होते नहीं हैं। अगर होते हैं तो वह इतना पैसा वसूल करते हैं कि गरीब ग्रामीणों के पास देने के लिए नहीं होता है। इस लिए मेरा निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा सरकारी अस्पताल खोले जायें। उनके लिए खास तौर से व्यवस्था की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोविन्द सहाय ।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री माणकचन्द सुराणा ।

(अनुपस्थित)

श्री अब्दुल अजीज ।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ खास बातों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं । अगर हमारे राज्य की नीयत साफ है तो हम इस बात पर सोचें कि जो लोग हमारे लिए रास्ता साफ करते हैं, जो रात के वक्त कारखानों में, खेतों में, खानों में काम करते हैं, जो राज्य की पूंजी का बहुत बड़ा हिस्सा मिलता है, वह उनकी कमाई से मिलता है, उनके काम से मिलता है लेकिन जब वह बीमार पड़ जाते हैं तो उनको हम क्या देते हैं ? इस पर गौर करें । चाहे वह गली हो, चाहे वह कारखाना हो सबसे ज्यादा आमदनी पर किसी का हक है तो वह उन आदमियों का है । हमें देखना है कि हम उनके लिए अपना कितना फर्ज निभाते हैं ? जो आपको राजस्व देते हैं उन लोगों को आप क्या देते हैं ।

डवलपमेंट के काम के साथ-साथ जो इन्सान के जीने के लिए निहायत जरूरी चीज है वह है दवाईयां/दवाइयां हम कितनी सस्ती कर सकते हैं और किस प्रकार से बांट सकते हैं जिससे वे गरीबों तक पहुंच सकें, इस पर सरकार अपना मानस बनाये । आपकी राज्य सरकार, जो एक नई उम्मीद के साथ आई है, क्या नया रंग देगी और क्या सुविधाएं मुहैय्या करायेगी, इस पर ध्यान देना चाहिए तीस सालों की नीतियों के आधार पर ही डाक्टर, वैद्य लगाये हैं और यूनानी दवाखाने खोल दिये हैं । जो आपके लिये पैदा करते हैं, चाहे वह खेतों में काम करने वाले हों, चाहे कारखानों में काम करते हों, उनको क्या देते हैं? इसकी ओर ध्यान देंगे तो मैं समझता हूं आप अपना फर्ज पूरा कर सकेंगे । मैं आपको याद दिलाऊं, ज्यादातर पीड़ित वे लोग हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं । क्या आप फैसला कर रहे हैं उनको गोलियां देने का ? आप देखेंगे कि हमारे समाज में जो असमानता है, जो आर्थिक असन्तुलन हो चुका है, उसमें सबसे बड़ी चीज है कि सन्तुलित भोजन उनको नहीं मिलता, वे बीमारी के शिकार हो जाते हैं फिर भी दिन रात मेहनत करते हैं । उनकी तरफ भी आप ध्यान देवें तो मैं समझता हूं तमाम बातों की ओर ध्यान हो जायगा । सर्वोदय के रूप में सर्वोदय का नारा लगाने के साथ आप सोचें ।

मेरे इलाके में 25-30 हजार मजदूर काम करते हैं उनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । प्रोफेसर केदार जब मकराना तशरीफ लाये थे तो उन्होंने मेडिकल मंत्रीजी को लिखा था कि एक सर्जन की व्यवस्था कर दी जाय । माइन्स और कारखानों में एक्सीडेन्ट हो ही जाते हैं चाहे कितनी भी सावधानी हो, किन्तु वहां पर कोई सर्जन नहीं है । सर्जन के अभाव में मरीजों को किशनगढ़, अजमेर और जयपुर जाना पड़ता है । अक्सर मरीज रास्ते में ही कोलेप्स हो जाता है । अगर यह कहा जाय कि राज्य सरकार वहां पर क्या खर्च कर रही है, उपाध्यक्ष महोदयजी, तो मैं यह कहूंगा कि दो सौ सदस्यों को अगर एक लैटर में लिख दिया जाय कि चिकित्सा में क्या खर्च होगा, कान्स्टीट्यूएन्सी वाइज शिक्षा में आपके यहां क्या खर्च होगा, इस प्रकार का एक प्रोफार्मा बना दिया जाय तो मैं समझता हूं कि हर सदस्य को यह मालूम हो जायगा कि उसकी कान्स्टीट्यूएन्सी में कितना खर्च हो रहा है ।

(श्री अब्दुल अजीज)

ये बड़े-बड़े पोथे दे दिये जाते हैं, न पढ़ने की फुरसत और न देखने की। क्या लिखाइड लोग तो मालूम कर लेते हैं लेकिन बाकी 80 परसेन्ट लोगों को मालूम नहीं कि मेडिकल में कितना खर्चा होता है, शिक्षा में कितना खर्च होगा और इण्डस्ट्रियल पाइन्ट आफ व्यू से कितना होगा? मैं तो पढ़कर मालूम कर लेता हूं लेकिन 80 परसेन्ट लोगों को मालूम नहीं होता है। कम से कम सबस्य वाइज सरकार की रिपोर्ट आनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र में क्या विकास होने वाला है, क्या आमदनी होगी और क्या खर्च होगा। इन तीन बातों की अगर आप सूचना देंगे तो मैं समझता हूं कि हम सही लड़ाई लड़ सकेंगे। लेकिन लोगों को मालूम नहीं होता।

श्री नवरंग सिंह: लड़ाई लड़ने के लिए कौन मौका देगा?

श्री अब्दुल अजीज : मैं सदन का बहुत ज्यादा समय नहीं लेता हुआ इतना ही कहूंगा कि कुछ बातों को राजनीतिक आधार पर तय नहीं करना चाहिए। खास तौर से डाक्टर्स, कम्पाउण्डर्स और नर्सेज के ट्रान्सफर्स के मामले में ईमानदारी से काम लेना चाहिए। मरीजों को पहले दवाइयां मिलनी चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा कि महाराना में एक बड़ा हॉस्पिटल खोलेंगे तो मेहरबानी होगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुरुशरण छाबड़ा।

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान मेरे क्षेत्र की चिकित्सा सम्बन्धी समस्याओं के सम्बन्ध में दिलाऊंगा। मेरा विधान सभाई क्षेत्र सूरतगढ़ है जो सूरतगढ़ से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में छोटी मोटी सात मण्डियां आती हैं। मैं निवेदन करूंगा कि सूरतगढ़ में काफी अच्छा हॉस्पिटल बना हुआ है। वहां डाक्टर का अभाव रहने की स्थिति में जो मोबाइल डाक्टर हैं उनका उपयोग किया जाता है। इसलिए देहातों के ऊपर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कृपया एक सर्जन सूरतगढ़ में नियुक्त करने की कृपा करें ताकि मरीजों को अच्छा इलाज मिल सके। इसी प्रकार से दूसरी मण्डी सामसिहपुर है जो एक एडपोस्ट का स्थान है। वहां पर एक एम. बी., बी. एस. डाक्टर नियुक्त किया जाय तो लोगों को राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त तीसरी मण्डी जैतसर है, दस हजार की आबादी है उसके बावजूद भी न वहां पर कोई एडपोस्ट है और न डिस्पेन्सरी। वहां पर डिस्पेन्सरी या एडपोस्ट का भी शीघ्र से शीघ्र इन्तजाम किया जाय तो उचित होगा। इसके अतिरिक्त अनूपगढ़ तहसील हैडक्वार्टर है, उसकी आबादी 15 हजार है। वहां एक हॉस्पिटल खोलने के लिए राज्य सरकार पूर्व में घोषणा कर चुकी है। उसको खोलने की व्यवस्था करे और जितना जल्दी हो सके भवन का निर्माण कराया जाय ताकि पाकिस्तान की सीमा के ऊपर रहने वाले मेरे देहात के भाइयों को काफी राहत मिल सके।

इसके अतिरिक्त दो शब्द मैं मंत्रिपरिषद् के ऊपर भी कह दूं। निस्सन्देह जब से जनता राज्य आया है, हमारे मन्त्रियों का आचार, व्यवहार अत्यन्त ही सादगीपूर्ण रहा है। इस बात की सब लोगों ने तारीफ की है। यह बात अलग है कि आज भी हमारे मंत्री लोग कोठियों में रहते हैं, कारों में चलते हैं। वैसे जिम्मेदारी के साथ कुछ सुविधायें भी

(श्री गुरुशरण छाबड़ा)

अत्यावश्यक होती हैं, उन सुविधाओं के अभाव में कोई भी व्यक्ति इतने बड़े प्रदेश का शासन नहीं चला सकता। लेकिन प्रश्न यह है कि सुविधाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि मन्त्रिपरिषद् के अधिकांश लोग इस बात को मद्देनजर रखते हुए ऐसा प्रयत्न करें कि कम से कम खर्चा किया जाय और जन-साधारण के लिए उनके दरवाजे अधिक से अधिक खुले रहें, जनसाधारण को अधिक से अधिक सुविधायें दे सकें। लेकिन मुझे खेद है कि समय-समय पर विधान सभा के भीतर और बाहर हमारी मन्त्रिपरिषद् के ऊपर आरोप लगते हैं। एक सबसे बड़ा आरोप लगाया जाता है कि ब्यूरोक्रेसी हमारे मंत्रिपरिषद् पर हावी है, नौकरशाही मन्त्रिपरिषद् पर हावी है। इस मंत्रिपरिषद् के ऊपर, मन्त्रिमण्डल पर नौकरशाही हावी है। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार हूं कि नौकरशाही मन्त्रिपरिषद् पर हावी नहीं है लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि हमारा मन्त्रि-परिषद् भी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर हावी पूरी तरह से नहीं है, यह अलग बात है कि घोड़ा सवार पर नहीं लेकिन सवार घोड़े पर होते हुए भी चाबुक उसके हाथ में नहीं है।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : कौन से मन्त्रियों पर हावी है?

श्री गुरुशरण छाबड़ा : मैंने यह नहीं कहा। मैंने कहा है कि सवार घोड़े पर होते हुए भी चाबुक हाथ में नहीं है। मैं उनके बारे में कहूंगा...

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : घोड़े की तुलना की है, क्या मंत्री घोड़े हैं?

श्री गुरुशरण छाबड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि आज भी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जिस प्रकार से जनता द्वारा निर्वाचित सरकार हावी होनी चाहिए, उस तरह से अभी हमारी सरकार हावी नहीं है। यह आज ही नहीं आज से पहले भी जब ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हुआ था तब भी ब्यूरोक्रेसी थी...

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : व्यवस्था का प्रश्न है। मांग आज की तारीख में पास होनी चाहिए थी। अब चूंकि अर्द्धरात्रि के 12 बज चुके हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए। जब तक मांग पास नहीं हो जाती तब तक के लिए समय बढ़ा दिया गया है।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : ब्रिटिश साम्राज्य के जाने के बाद उनके जो अवशेष थे, जो आई० सी० एस० अधिकारी थे, उन्होंने भी जनता द्वारा निर्वाचित सरकार के मार्ग में कुछ रुकावटें पैदा करने की कोशिश की। उसके कारण जो उनके विशेषाधिकार थे, संसद को विवश होकर उनको खतम करना पड़ा। आज राजस्थान में एक परिवर्तन आया है। इस देश की जनता परिवर्तन लाई है। आम तौर पर लोगों ने व छोटे कर्मचारियों ने इस परिवर्तन का स्वागत किया है लेकिन ये जो आई. ए० एस० व आई० पी० एस० अधिकारी हैं वह इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि देश की जनता ने एक क्रांति की है, एक परिवर्तन किया है। उनके दिमाग में एक ही बात है, मंत्री बदलते हैं, संतरी नहीं रहते हैं, शासक बदलते हैं, प्रशासक नहीं रहते हैं। वे समझते हैं, हम लोग स्थाई अधिकारी हैं, मंत्रिपरिषद् अस्थाई है। जो आज मंत्री हैं कल साधारण विधायक बन सकते हैं। वे इस प्रकार सोचते हैं, जैसे कोई उनका जन्मसिद्ध अधिकार हो। जिस तरह

(श्री गुरु शरण छाबड़ा)

राजाओं का शासन जन्मजात शासन होता था, ये भी अपने को स्थाई मानते हैं। इसलिए मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि इन आई० ए० एस० अधिकारियों को जो विशेषाधिकार मिले हुए हैं उन्हें समाप्त करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। जब तक इनके विशिष्ट अधिकार समाप्त नहीं होते, जब तक राज्य सरकार को इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होगा, तब तक आप इनको अपने कन्ट्रोल में, अनुशासन में नहीं रख सकेंगे। इसके साथ साथ आप इनसे जो भी काम लेना चाहें, उसके लिये आप इनको अधिकारात्मक रूप से कहिये, रिक्वेस्ट मत कीजिए। एक छोटे से काम के लिए आप अधिकारियों को रिक्वेस्ट करते हैं। आप अपना अधिकार जमा सकेंगे, तभी आप इनके विरुद्ध प्रभावकारी तरीके से कदम उठा सकेंगे।

मैं आपको यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि राजस्थान में सचिवालय है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह सरकार शासकों की नहीं बल्कि प्रशासकों की है। मैं सुझाव देता हूं इसका नाम मंत्रालय किया जाए। जनता के दिमाग मे मनोवैज्ञानिक बात पैदा की जाए कि सचिव नहीं, मंत्री महत्वपूर्ण है। इसलिए इसका नाम सचिवालय की जगह मंत्रालय किया जाए। मेरे पूर्ववक्ता ने सुझाव दिया था कि सचिवालय को बन्द किया जाये। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि सचिवालय को बन्द करके मंत्रियों की कोठी पर दरबार लगाए जायें। यदि मंत्रियों के घर पर दुकानदारी चालू हुई तो वह दोषपूर्ण होगी। मंत्रियों की कोठियों पर उनके परिवार रहते हैं इसलिए मंत्रियों की कोठियों पर दफ्तर नहीं लगाने चाहिए।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : आप मंत्रियों के काम को दुकानदारी मानते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : इन्ट्रप्शन मत करें। आप 8 मिनट का समय ले चुके हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : यदि अलग-अलग मंत्रियों के यहां दफ्तर लगे तो जन-साधारण को कठिनाई होगी। आज एक स्थान पर सचिवालय चलता है। किसी व्यक्ति को छोटा सा काम होता है तो वह सचिवालय पहुंच जाय तभी उस काम को करवा सकता है। एक फाइल विभिन्न मंत्रालयों से होकर गुजरती है। एक व्यक्ति को वापस दूसरे विभाग में जाना हो तो विलंब नहीं होता। इसलिए अलग-अलग मंत्रियों के यहां दफ्तर लगाने के बजाय सचिवालय में ही दफ्तर रहने चाहिए। इस बात का प्रबल समर्थक होते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सचिवालय का नाम मंत्रालय रखा जाय, सरकार का इसमें कोई खर्चा नहीं आएगा और जनता का मनोबल ऊंचा होगा।

इसके अतिरिक्त एक सुझाव और है। हमारे माननीय मंत्री बहुत ही साधु स्वभाव के हैं। डेमोक्रेसी में शासक और शोषित, जनता और शासक के बीच में फर्क नहीं होना चाहिए, खाई नहीं होनी चाहिए। जनता यह समझे कि विधायक और हमारे बीच कोई फर्क नहीं। विधायक यह समझे कि मंत्री और हमारे बीच कोई फर्क नहीं है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जनता और मंत्रियों के बीच सीधा संबंध होना चाहिए। जनता सरकार के मंत्रियों के दरवाजे जनता के लिए खुले होने चाहिए। उनका साधुओं जैसा व्यवहार होना चाहिए लेकिन साधु बन कर आप भ्रष्ट व

(श्री गुरुशरण छाबड़ा)

बेईमान लोगों का स्वागत करेंगे, तो कभी भी देश का प्रशासन नहीं सुधर सकता, आप साधु नहीं, शासक बनिए ।

धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : राज्य मंत्री श्री महबूब अली ।

श्री महबूब अली (राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम तो मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही अमूल्य सुझाव दिए हैं और इतनी देर तक मांगों पर विचार विमर्श किया है । मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि वर्तमान मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों की, विशेष प्रकार से, रहन-सहन की सारी प्रक्रिया और दिनचर्या एक साधारण व्यक्ति के समान है । यदि आप कांग्रेस के जमाने के मंत्रियों की बात कहें और उनको देखें तो जो लोग उनके सम्पर्क में आए हैं वे इस बात को जानते हैं कि वे किस कदर अथोरिटी डंकन थे, आज की तारीख में किसी मंत्री को अहम् नहीं है, वे अपने को साधारण व्यक्ति की तरह मानते हैं और उसी प्रकार से जिंदगी बिताते हैं । उसके बाद भी यदि यह कहा जाए कि मंत्रिमंडल को अपने एशो-आराम के लिए बहुत कुछ चीजें मिल रही हैं और वे एशो आराम कर रहे हैं, तो बिलकुल गलत बात है । उनका जीवन करीब से देखें, जैसे बहुत से माननीय सदस्यों ने देखा होगा, तो मालूम पड़ेगा कि वे किस प्रकार से सादी जिंदगी बिताते हैं, सड़क पर चलते समय हमेशा अपने पैरों को सड़क पर यह अहसास करने के लिये रगड़ते हैं कि वास्तव में वे सड़क पर हैं । उपाध्यक्ष महोदय, पहले के मन्त्रियों के रहने के तौर-तरीके, उनका बोलने का ढंग सभी कुछ और ही था । मैं उस जमाने का एक उदाहरण देना चाहता हूं, कांग्रेस के एक मन्त्रीजी का मुझे बहुत ही कटु अनुभव है । मैं किसी काम से उनके पास चला गया । जनता का काम था । उन्होंने मेरे साथ इस प्रकार का व्यंग्य के साथ बर्ताव किया कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूं । अगर चाहते तो मुझे काम के लिये मना कर सकते थे लेकिन उन्होंने जिस अहम के साथ, जिस घमंड के साथ बर्ताव किया उसको मैं क्या बयान करूं ? उन्होंने मुझसे बड़े रूड तरीके से बात की । उपाध्यक्ष महोदय, उनके बात करने के तौर-तरीके कुछ और ही थे । वह साफ इन्कार कर सकते थे, लेकिन जिस घमण्ड और अहम् के साथ उन्होंने जिस भाषा को यूज करके मुझे इन्कार किया, उसके लिये मैं क्या बयान करूं ? अगर किसी भी व्यक्ति का काम नहीं करना हो, तो स्पष्ट मना कर सकते थे । लेकिन अगर आज आप जनता पार्टी के मन्त्रियों के पास जायेंगे तो आपको बहुत ही फर्क बातों में मिलेगा । आप किसी भी मन्त्री के पास चले जाइये, आपको मालूम होगा कि कांग्रेस और जनता पार्टी के मंत्रियों में एक मौलिक अन्तर है ।

मैं इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिन परिस्थितियों में यह जनता सरकार आई है, उस पर हमें विचार करना होगा । आपात-कालीन स्थिति के तुरन्त बाद ही यह जनता सरकार आई है । आते ही इस सरकार के सामने बहुत सी समस्यायें पैदा हो गयी थीं । उपाध्यक्ष महोदय, आपातकालीन समय, इमर्जेन्सी के दौरान किस प्रकार से हर वर्ग का दमन हुआ, वह तो शायद आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है । पिछली सरकार ने जो जो जुल्म ढाये थे इमर्जेन्सी में और जितना दमन किया था उसका ही रीएक्शन है कि

(श्री महबूब अली)

कांग्रेस का सफाया हो गया। उसके हटते ही इमर्जेन्सी समाप्त हो गयी थी। इमर्जेन्सी समाप्त होते ही, नेचुरल रीएक्शन हुआ, जो लोग घुट रहे थे अन्दर ही अन्दर उन्होंने, स्कूलों में, कालेजों में हड़तालें शुरू कर दीं और मिलों और सरकारी कर्मचारियों की यूनियन्स ने नोटिसेज देने शुरू किये। इसके अलावा हर वर्ग ने अपनी अपनी समस्याओं को जनता सरकार के सामने रखना शुरू किया। उपाध्यक्ष महोदय, जनता सरकार के मन्त्रियों ने उनकी समस्याओं को हल करना शुरू किया। उन्हें सुना। मैं यहां पर यह स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि इस वक्त जो जो भी मन्त्री हैं वह लोग अपनी जिम्मेदारी को भली-भांति निभा रहे हैं। मैं आज सारे चेलेन्जेज स्वीकार करने को तैयार हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी जनता सरकार ने अन्त्योदय योजना और राजस्व अभियान के द्वारा ग्रामीण जनता की समस्याओं का निराकरण करने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। यह बात सही है कि आपातकाल के दौरान लोगों का मनोबल गिरा था पर अब जनता पार्टी की सरकार ने आकर उनका मनोबल वापस ऊपर उठा दिया है, और भी उठाने का प्रयास कर रही है। मैं समझता हूं कि आप सभी लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि जनता पार्टी की मंत्रिपरिषद् इस बात की ओर सजग है।

इसके अलावा मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर कुछ माननीय सदस्य, खास तौर से विपक्ष के कांग्रेस के महानुभावों ने जनता पार्टी के मन्त्रियों के खर्चे के बारे में अपना काफी रोष दिखाया। कई सदस्यों ने बहुत तेजी के साथ बोल बोल कर, बड़े हौसले और बड़ी बुलन्दगी के साथ कहा कि जनता पार्टी की सरकार के मन्त्रियों के खर्च बहुत हैं। उनका जो खर्चा बजट में रखा गया है वह बजट प्रोविजन, कांग्रेस के जमाने में मन्त्रियों के खर्चे के जो प्रोविजन्स रखे जाते थे उससे कहीं अधिक है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज रुपये के मूल्य में, उस वक्त की कीमतों में और आज की कीमतों में फर्क पड़ा है, अधिक कीमतें हो गयी हैं, महंगाई बढ़ी है।

एक माननीय सदस्य : यह आप कह रहे हैं?

श्री महबूब अली : जी हां, यह मैं कह रहा हूं। कुछ सोच समझ कर ही कह रहा हूं।

आपको बजट प्रोविजन्स के आंकड़ों को देखने से पता लगेगा, मैं आपको वह आंकड़े भी दूंगा कि कांग्रेस के मन्त्रियों के टेलीफोन्स, कार के खर्चे, पानी व बिजली के खर्चे कितने थे और आज जनता पार्टी के मन्त्रिपरिषद् के मन्त्रियों के कितने खर्चे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह आंकड़े देखने से पता लग जायेगा कि कितना कम खर्चा जनता पार्टी की सरकार के मन्त्रिपरिषद् के लोगों पर हो रहा है। मैं यहां कोई डींग नहीं हांक रहा हूं। आप कांग्रेस के पिछले तीस सालों के कार्यकाल को देखें, उनके खर्चों को देखें। जब सदन में पिछले तीस सालों की बात करते हैं तो सदन के कई माननीय कांग्रेसी सदस्य यह कहते हैं कि आप तो पिछले तीस सालों की बात ही करते हैं। पर क्या करें, उपाध्यक्ष महोदय? हालांकि वह तो कहते हैं कि कब तक यह आवाज पिछले तीस सालों की लगाते रहेंगे, कांग्रेस में पिछले तीस सालों में यह हुआ, वह हुआ पर, उपाध्यक्ष महोदय, तब तक यह आवाज लगती रहेगी जब तक

(श्री महबूब अली)
उनके किये हुए कामों का अन्त नहीं आ जाय। जब कभी ऐसा प्रश्न आयेगा तो उसका रेफरेन्स देना ही पड़ेगा, तथ्यों को सामने रखना ही पड़ेगा, तथ्यों को इलूसिडेट करना ही पड़ेगा। हमको कम्पेअर करना है तो करना ही पड़ेगा। आप कहते हैं कि कब तक पिछले तीस साल की बातों की दुहाई देते रहेंगे तो यह तो परिस्थितियों के मुताबिक करना ही पड़ेगा।

श्री अब्दुल अजीज : कांग्रेस की अच्छाइयों का तो मुकाबला करो। उनकी अच्छाइयों के साथ कोई तालमेल नहीं है।

श्री महबूब अली : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि कांग्रेस के कुछ माननीय सदस्यों ने यह स्वीकार किया कि जनता पार्टी के मन्त्री लोगों और पहले के मन्त्रियों के बातचीत करने के ढंग में फर्क है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात का बहुत ही भारी आश्चर्य हुआ। यहां पर कई माननीय सदस्यों ने यह कहा कि जनता पार्टी के मन्त्रिपरिषद में आपस में भयंकर झगड़ा है। यह लोग आपस में लड़ते हैं। मैं सदन के माननीय सदस्यों को आपके मध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, यह सूचित करना चाहूंगा कि हमारे मन्त्रिपरिषद् में कोई आपस में झगड़ा नहीं है। न हमारे मन्त्रि-परिषद् में कोई घटकवाद ही है। हमारा आपस में कोई विरोध नहीं है। पता नहीं कांग्रेस के माननीय सदस्य ये बेबुनियाद बातें कहां से लाते हैं? इसके पीछे क्या औचित्य है, यह समझ में नहीं आता?

इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि मुख्य मन्त्री जी ने मंत्रिमण्डल का पूरा गठन नहीं किया। इसके सम्बन्ध में तरह तरह की बातें करते हैं। उनके कहने का मुझे कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। यह तो मुख्य मन्त्रीजी के मन की बात है कि वह कैसे मंत्रिमण्डल का गठन करें। जहां तक सवाल इसको लेकर झगड़ा होने का है, यह बात तो बिलकुल गलत है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे मंत्रिपरिषद में कोई मतभेद नहीं है, और फौलाद की तरह, चट्टान की तरह वह बिलकुल मजबूत है और हमारी जनता पार्टी के सदस्यों में फूट डालने के कांग्रेस के जो इरादे हैं वह नापाक इरादे हमेशा के लिये विध्वंश कर दिये जायेंगे। मुझे इतना ही कहना है कि हमारे यहां पर कोई मतभेद नहीं, कोई घटक का झगड़ा नहीं है। यह बिलकुल सत्य है। बल्कि कांग्रेस में आपस में मतभेद हो गये हैं, कांग्रेस (आई) और कांग्रेस (ओ) दो कांग्रेस हैं।

श्री नवरंग सिंह : यह कांग्रेस (ओ) तो आपके साथ है।

श्री महबूब अली : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान का यह जनता पार्टी का ही मंत्रि-मण्डल है जिसकी जब कभी बैठक होती है, तो उसके अन्दर न केवल कैबीनेट स्तर के मन्त्री ही बैठा करते हैं बल्कि उनके साथ साथ राज्य स्तर के मन्त्री भी बैठते हैं। उनकी राय भी बैठक में ली जाती है। यह पहले कांग्रेस राज्य में नहीं होता था। तो आपस में फूट और झगड़ा रहने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आपका मंत्रिमण्डल तो लाइफ ओरेन्ज है ।

श्री महबूब अली : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जनता पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के कई माननीय सदस्यों ने जनता पार्टी के मंत्रिपरिषद् पर यह आरोप लगाया कि कई माननीय सदस्यों के पत्रों का जवाब नहीं दिया जाता है । मेरी यह मान्यता है कि माननीय सदस्यों के जो पत्र आयें उनका जवाब जरूर जाना चाहिये । उनका एक्नोलेजमेंट तो कम से कम होना ही चाहिये । इस प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिये कि उनका एक्नोलेजमेंट न हो । अगर किसी माननीय सदस्य ने ऐसा अनुभव किया है तो इस प्रकार की भविष्य में कभी भी कोई भूल नहीं होगी ।

जहां तक सवाल आगन्तुकों से भेंट करने का है या आगन्तुकों को बैठाने की बात है, हमारे मन्त्रियों के यहां पर बैठने की पूर्ण सुविधा है । और भी बेन्चेज मन्त्रियों के कमरे के बाहर लगा दी जायेंगी ताकि लोग आराम से बैठ सकें । हमारी यह कोशिश रहती है कि जो भी मन्त्री लोगों से मिलने के लिये आवें उनसे बातचीत की जाय । जनता को उनकी उचित मांगों को मन्त्रियों को सुनाने का अवसर दिया जाये । मेरे ही मकान के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा मकान सवाई मानसिंह अस्पताल के पास है । कई बार बीकानेर से, जोधपुर से लोग आते हैं और रात को मेरे यहां पर आकर सो जाते हैं । मेरा मकान ईजीली अवेलबल है । हमारे दूसरे मन्त्री लोगों के यहां भी कोई भी जा सकता है । लेकिन कांग्रेस के मन्त्रियों के घर के अन्दर इस तरह अन्दर जाकर सोना तो दूर रहा, कोई ईजीली घुस नहीं सकते थे ।

(व्यवधान)

तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस के मन्त्रियों में और जनता पार्टी के मन्त्रियों को अगर आप तुलना करेंगे तो दोनों में बहुत भारी फर्क मिलेगा ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : तो क्या आप अपनी तुलना गान्धी से करेंगे, या कांग्रेस के पापियों से ।

श्री महबूब अली : अब, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको खर्चे के आंकड़े देना चाहूंगा कि कांग्रेस के मन्त्रियों के खर्चे और जनता परिषद् के मंत्रियों के खर्चे की क्या स्थिति है, आप तुलनात्मक आंकड़े देखें ।

खर्चा जुलाई से लेकर सितम्बर तक, श्री हरिदेव जोशी, मुख्य मन्त्री, कांग्रेस के और जुलाई से सितम्बर तक के ......

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : हम सुनना नहीं चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये, सुनिये ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : हम सुनना चाहते हैं, आप सुनाइये ।

श्री महबूब अली : जुलाई से सितम्बर तक ।

श्री अब्दुल अजीज : क्या आंकड़े दे रहे हैं ? आपको कोई तुलना ही करनी है तो अच्छी बात की कीजिये ।

श्री महबूब अली : आप सुनिये ।

(श्री महबूब अली)

कम्पेरिजन किया है। जुलाई से तीन महीने के फिगर दिये हैं।

विद्युत् : श्री भैरोंसिंह 1890 रुपये

पानी : श्री भैरोंसिंह 338 रुपये

विद्युत् : श्री हरिदेव जोशी 5252 रुपये

पानी : श्री हरिदेव जोशी 1162 रुपये

इसी कोरस्पोन्डिंग ईयर का बता रहा हूं।

मोटर गैराज का खर्चा :

श्री भैरोंसिंह 1604 रुपये

श्री हरिदेव जोशी 37,000 रुपये

टेलीफोन का खर्चा :

श्री भैरोंसिंह 9523 रुपये

श्री हरिदेव जोशी 28297 रुपये

कई माननीय सदस्य : शेम शेम।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : 5 साल में क्या होगा, देखियेगा।

इट शोज कि वे सरकारी कार्य के प्रति कितने चिन्तित थे। काम नहीं करेंगे तो क्या खर्चा होगा।

श्री महबूब अली : अभी आपने यह कहा था कि मंत्रिपरिषद् पर इतना खर्चा है। इसलिये यह तो मैंने आपके सामने एक छोटा सा नमूना पेश किया है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : इस विषय में कांग्रेस के सदस्यों ने तो कम कहा था, आप ही की पार्टी के माननीय सदस्य, जो भीलवाड़ा से आये हैं, श्री कौशलकिशोर जी ने ही बताया था। कम्पेरेटिव स्टेटमेन्ट उन्होंने बताया।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उसी का जवाब दिया है। आप सुनने की थोड़ी क्षमता रखिये। बैठ जाइये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : यही बात कांग्रेस के विपक्ष में जब आप थे तो बोलते थे।

श्री महबूब अली : इसी प्रकार मेरे पास बहुत बड़ी तालिका है, इसमें हर क्षेत्र के आंकड़े दिये हुए हैं। समय बहुत कम है वरना हरएक मंत्री की सूची मेरे पास है मैं आपको बताता। यह तो मैंने एक नमूना आपको बताया है। तीन महीने के आंकड़े कलेक्ट किये हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर कोई जानना चाहे तो मैं पूरी तालिका उनको बता सकता हूं। इस सम्बन्ध में जो फेक्ट्स हैं वे बहुत ही रिवीलिंग हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अर्ज करता हूं कि इस मांग को स्वीकार किया जाय।

श्री अब्दुल अजीज : एक ही का जवाब दिलवा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह निवेदन करूंगा कि बार बार बाधा न डालें। मैं अनुमति दूंगा तब ही सवाल रखेंगे आप।

श्री अब्दुल अजीज : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जब आपने यह कहा कि

(श्री ग्रब्दुल ग्रजीज)
सादगी से काम करेंगे तो फिर बजट बढ़ाने का क्या मतलब है ? ग्रापने खुद ने माना है कि महंगाई बढ़ी है । ग्रापने ग्रपने स्टेटमेंट को सही बताने के लिये कह दिया कि महंगाई बढ़ी है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी उत्तर दे दें ।

श्री त्रिलोक चन्द जैन (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का ग्रत्यन्त ग्राभारी हूं कि उन्होंने चिकित्सा व्यवस्था का बहुत विस्तारपूर्वक विवेचन किया ग्रौर चरित्र-चित्रण किया । उससे राजस्थान में चिकित्सा की जो स्थिति है उसका नक्शा सामने ग्रा जाता है ग्रौर यह ग्रहसास होता कि किस प्रकार की व्यवस्था सारे राजस्थान में है । जो चित्र है वह यह है कि ग्रौषधियों पर, दवाग्रों पर 1.20 पैसा प्रति व्यक्ति खर्च होता है ग्रौर चिकित्सा पर 8.03 पैसा प्रति व्यक्ति खर्च होता है । गांवों में 18 हजार लोगों पर एक डाक्टर है ग्रौर शहर में 2 हजार लोगों के पीछे एक डाक्टर है । यह जो चिकित्सा की व्यवस्था है, जो कुछ भी है, प्रगति या जो कुछ है, उसको हमें स्वीकार करना है ।

सब लोगों ने चिन्ता प्रकट की है वह एक वस्तु स्थिति है । उससे यह ग्रनुमान होता है कि ग्रब चिकित्सा व्यवस्था एक वैज्ञानिक तरीके से करनी होगी तब ही, जैसी कि चिन्ता प्रकट की गयी है, सारे राजस्थान में हम गरीबों तक चिकित्सा का लाभ पहुंचा सकेंगे । हर क्षेत्र में हम चिकित्सा का लाभ पहुंचा सकेंगे ।

ग्रापने देखा होगा, पिछले सत्र में इस बात की कोशिश की गयी कि जो भी साधन उपलब्ध हैं उनका उपयोग व्यवस्थित ढग से किया जाय ग्रौर खास कर उन क्षेत्रों की ग्रोर ध्यान दिया जाय जो इस सारी व्यवस्था से वंचित रहे हैं । इसलिये घोषणा की गयी थी कि हर पंचायत समिति के क्षेत्र में दो डिस्पेन्सरियां ग्रौर एक एडपोस्ट पहुंच जाय । ग्रब तक जितने भी चिकित्सालय खुल चुके थे ग्रौर जितने भी शेष थे, बजट में जो प्रावधान किया गया उसके ग्रनुसार ग्रापको यह जानकर खुशी होगी कि 153 डिस्पेन्सरीज खोली गयीं ग्रौर 110 एडपोस्ट्स खोले गये । जो घोषणा की गयी उसको पूरा करने के लिये डिस्पेन्सरीज का ग्रागामी बजट में ग्रौर प्रावधान किया गया है । जो घोषणा की गयी थी उस ग्रोर कदम बढ़ाया है ।

माननीय सदस्यों ने कहा कि कई जगहों के नाम सूची में नहीं हैं । घोषणा के ग्रनुसार जो रिग्रोरिएन्टेशन किया गया है उसी के ग्राधार पर सूची तैयार की गई है । उसमें स्पष्ट सूचना है । कहीं पर, किसी क्षेत्र में चिकित्सालय नहीं है एक एडपोस्ट नहीं है तो उसको प्राथमिकता देते हुए सूची तैयार की गई है । राज्य सरकार पूर्णरूप से कटिबद्ध है कि ग्रामीण क्षेत्रों को चिकित्सा सुविधा मिले ।

ग्रागामी वर्ष में, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे ग्रायुर्वेद का क्षेत्र हो, चाहे यूनानी चिकित्सा का क्षेत्र हो ग्रौर चाहे होम्योपैथी का क्षेत्र हो, जो चिन्ता प्रकट की गयी है उससे ग्रनुमान होता है कि केवल ग्रस्पताल खोल देने से ही काम नहीं चल सकेगा । वहां पर पट्टियां, ग्रौषधियां ग्रौर उपकरण होने चाहिये, जो उपकरण पड़े हुए हैं उनको उपयोगी बनाना चाहिये । मैं यह मानता हूं कि ग्रागामी वर्ष

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

जो भी सेवाएं उपलब्ध हैं उनको सक्षम बनाने का वर्ष होगा। उनको ठीक करने का वर्ष होगा। औषधालयों में, डिस्पेन्सरीज में स्टाफ पहुंचा देने का वर्ष होगा और जो भी साधन उपलब्ध हैं उनके द्वारा जो चिन्ता व्यक्त की गयी है उसको दूर करना होगा। जो भी साधन उपलब्ध हैं उनके द्वारा जनता की भली-भांति सेवा को जा सके, इस दृष्टि से जैसा निवेदन किया, राज्य सरकार चिकित्सा के सारे साधन और चिकित्सा की व्यवस्था को गांवों की ओर ले जाना चाहती है। इस दृष्टि से एक योजना, जिसका जिक्र आपने भी किया है, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, योजना प्रारम्भ हुई है। इस वर्ष 27 पंचायत समितियों में 1000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। एक हजार कार्यकर्त्ता एक हजार की जनसंख्या के क्षेत्रों में पहुंच जायेंगे।

दूसरी तरफ यह चिन्ता प्रकट की गयी है कि पंचायत समिति क्षेत्रों में लेडी डाक्टर्स नहीं पहुंच पाती हैं। जो लोकल दाइयां हैं उनको भी ट्रेण्ड करने का कार्यक्रम हाथ में लिया गया है ताकि उनको भी मोटीवेट किया जा सके वैज्ञानिक पद्धति की ओर और उनका भी उपयोग सहायक के रूप में लिया जा सके। उनको भी तैयार किया जा रहा है और जहां कोई साधन नहीं हैं वहां यह मददगार साबित हो सकेंगी।

इसी के साथ अगले वर्ष 200 नये उप-केन्द्र खोले जायेंगे, 5 रेफरल हास्पिटल्स को क्रमोन्नत किया जायेगा। 5 प्राथमिक केन्द्र को क्रमोन्नत किया जायेगा और खास करके जो पिछड़े क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर के कुछ क्षेत्र और अलवर के कुछ क्षेत्र उनको प्राथमिकता दी जायेगी। 5 रेफरल हास्पिटल्स को और 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत किया जायेगा और इस तरह से धीरे धीरे गांवों की ओर चिकित्सा सेवाओं को ले जाया जायेगा। लेकिन यही पर्याप्त नहीं है। बहुत कम साधन हैं इसलिए और भी योजनाएं सोची गयी हैं। आपको ध्यान है कि राजस्थान में एक विशेष आयोजन रहता है और वह है सर्जिकल केम्प का। 500 बेड्स के एक सर्जिकल कैम्प की योजना है उसको भी सक्षम बनाया जायेगा और साधन जुटाये जायेंगे ताकि बीमारों को उनके दरवाजे पर ही जाकर चिकित्सा संबंधी सुविधा दी जा सके और अधिक से अधिक लोगों की सेवा कर सकें। यह भी एक ऐसा आयोजन है जिसमें काफी रुपया खर्च होता है इसलिए यह भी सोचा गया है कि जहां जिला चिकित्सालय है वहां चिकित्सकों को इस प्रकार के आदेश दिये जा रहे हैं कि हर महीने वे हर पंचायत समिति क्षेत्र में जाकर, ग्रामीण क्षेत्र में जाकर जैसे मोबाइल कैम्प लगाते हैं उसी तरह से 8-10 दिन के कैम्प लगायें ताकि जहां साधनों के अभाव में अस्पताल नहीं खोले जा सकते और एडपोस्ट नहीं खोली जा सकती, वहां जाकर बीमारों की सेवा कर सकें। इस प्रकार के केन्द्र का एक्सपेरीमेन्ट किया गया है इस वर्ष और बहुत उपयोगी रहा है। एक एक कैम्प में 700-800 मरीज आये हैं और आपरेशन्स हुए हैं।

एक और योजना इस साल चालू की जायेगी। पंचायत समिति क्षेत्र में जहां प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र हैं और रेफरल हास्पिटल हैं, उनके आसपास के

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

क्षेत्र में डाक्टरों की टोली महीने में दो बार जाकर बीमारों को संभालेगी, उनका ध्यान रखेगी, और निदान करेगी। वहीं पर चिकित्सा करेगी, औषधियां बांटेगी और उनका उपचार करेगी। इस तरह से आप देखेंगे कि इस प्रकार की योजनायें बनाई जा रही हैं जिनके द्वारा जो चिकित्सा के साधन हैं उनको ग्रामीण क्षेत्र में तब तक उपलब्ध किया जाये जब तक ऐसी योजना नहीं बना लें कि ठेठ पंचायत क्षेत्र तक सब जगह अस्पताल खुल सकें।

आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि ग्रामीण चिकित्सा सेवाओं के लिए भारत सरकार की मदद से और विश्व बैंक की सहायता से भरतपुर, कोटा और सवाई माधोपुर इन तीन जिलों को भारत सरकार के निर्देशानुसार चुना गया है जहां नये प्रोजेक्ट्स लिये जायेंगे। इसके अन्तर्गत पोषाहार, जन्म निरोधक, उपचार आदि सेवाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में काम होगा। इसमें आपरेशन थियेटर होगा, 6 रोगी शैयाओं की भी व्यवस्था होगी और महिला रोग विशेज्ञ और बच्चों के रोग के विशेषज्ञ होंगे। इस तरह से इसके आधार पर तीन जिलों में यह सेवायें उपलब्ध कराई जायेंगी।

इसके साथ ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, नई दिल्ली से चूरू जिले के लिये अनुबंध हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं का विकास किया जायेगा और चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराई जायेंगी। राजगढ़ पंचायत से यह प्रारम्भ होगा। वहां भी 50 रोगी शैयाओं का अस्पताल क्रमोन्नत करने का प्रावधान किया गया है। इस तरह से जो भी साधन हैं उनको ग्रामीण क्षेत्र में ले जाया जायेगा और ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा की सेवा उपलब्ध कराई जायेगी। इसलिए जो चिन्ता आपने प्रकट की है, वही चिन्ता राज्य सरकार की है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों की ओर चिकित्सा सेवाओं को ले जाये। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की ओर चिकित्सा सेवाएं ले जाने का यह अर्थ नहीं है कि नगरीय क्षेत्र को कोई उपेक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं। अगले बजट में यह घोषणा की गयी है, जो वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में की है नगरपालिका क्षेत्र में जो 10 हजार या उससे ऊपर के क्षेत्र हैं वहां अस्पताल में लेडी डाक्टर की सेवायें दी जायेंगी। जो 100 रोगी शैयाओं के अस्पताल हैं वहां विशेष सेवाओं का विकास शनैः शनैः किया जायेगा। वहां भी लेडी डाक्टर की व्यवस्था की जायेगी।

यहां पर चिन्ता प्रकट की गई कि लेडी डाक्टरों की व्यवस्था बहुत सी जगह नहीं है और डाक्टरों की भी व्यवस्था नहीं हो रही है। मेरा अनुमान है कि माननीय सदस्य सत्र को समाप्त करके घर पहुंचेंगे तब तक सम्भवतः डाक्टर भी पहुंच जायेंगे। यह जरूर है कि कमी रही है और डाक्टरों को जुटाने में बहुत कमी रही है। लेकिन अब ऐसी व्यवस्था कर ली गयी है कि डाक्टर इस माह के अन्त तक अपने अपने क्षेत्रों में पहुंच जायेंगे। लेडी डाक्टर के बारे में जरूर असुविधा आज भी बनी हुई है। एक तो उपलब्ध नहीं है, कोशिश की जा रही है और आपने देखा होगा कि उनके लिए राज्य सरकार ने एक सुविधा दी है। जो अवकाश प्राप्त हैं और जो वापस काम कर सकती हैं उनको वापस एम्पलाय करने का भी निर्णय लिया है। इसके बावजूद भी उपलब्ध नहीं हो रही हैं। अब फिर विज्ञापन दिया जा रहा है और बहुत सम्भवतः

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)
अप्रेल के अन्त तक लेडी डाक्टर की भी व्यवस्था की जा सकेगी। जनता को चिन्ता है कि अस्पताल खुले हुए हैं और 7-8 महीने से डाक्टर नहीं पहुंच पाये हैं। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि डाक्टर को भेजते हैं और हम आशा करते हैं कि वहां पहुंच जायेंगे लेकिन उनका ट्रान्सफर करते हैं वह छुट्टी लेकर बैठ जाते हैं। वह पहुंच नहीं पाते हैं, जबतक यह मालूम नहीं होता है तब तक दूसरा डाक्टर नहीं भेज सकते हैं। इस तरह से यह अवधि निकल गयी है और अवश्य असुविधा रही हैं। जो माननीय सदस्यों ने अपनी चिन्ता बताई वह सही है, लेकिन इसको धीरे धीरे उनके ही सहयोग से समाप्त कर दिया जायगा, इसका निवारण कर दिया जायेगा और अप्रेल तक, मेरा ख्याल है, लेडी डाक्टर हर जगह पहुंच जायेंगी।

माननीय सदस्यों ने मलेरिया के बारे में चिन्ता प्रकट की है। मलेरिया एक बार समाप्त होकर वापस आया है। शायद मच्छरों ने नया जन्म लिया हो....

श्री माधोसिंह कछवाह: श्रीमान्, मच्छर यहां भी काट रहे हैं। माननीय सदस्या को दो चार ने यहां भी काटा हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा: देखिये, यहां भी मच्छर काट रहे हैं।

एक माननीय सदस्य: मीठे खून पर मच्छर आते हैं।

श्री त्रिलोकचंद जैन: लेकिन यह समस्या केवल राजस्थान की नहीं, यह तो प्राकृतिक समस्या है। इसके ऊपर भारत सरकार की सहायता से अनुसंधान हो रहा है। नये तरीके का मच्छर आया है वह रेसिस्टेन्स पावर लेकर आया है। इसकी खोजबीन की जा रही है। 17 इकाइयां सारे राजस्थान में खोली गई हैं। अगले वित्त वर्ष में 26 इकाइयां हो जायेंगी। मच्छरों से लड़ने के लिये नई स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है। बहुत संभव है मलेरिया के बारे में माननीय सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की है, उनके सहयोग से यह लड़ाई लड़ली जायेगी।

चिकित्सा शिक्षा की दृष्टि से जो हमारे पांच मेडिकल कालेजेज हैं उनके बारे में भी माननीय सदस्यों ने बातें कहीं हैं। श्री रघुनंदन व्यास ने भी एक बात कही है। चिकित्सा व्यवस्था की दृष्टि से कोई भी कार्यक्रम ऐसा होगा उस पर पुनर्विचार करने की बात होगी तो उस पर विचार किया जावेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि शिक्षण संस्थाओं को रूरल ओरियेन्टेड बनाया जाये, इसका अवश्य प्रयत्न किया जायेगा। यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कालेजेज में इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर एक नया कार्यक्रम इन्ट्रोड्यूस करने की बात की जायेगी ताकि डाक्टर गांवों में जा सकें।

एक माननीय सदस्य: मंत्री महोदय, 80 पर्सेन्ट कोटा विद्यार्थियों के लिये रखा जाये।

श्री त्रिलोकचंद जैन: राष्ट्रीय स्कूल स्वास्थ्य सेवायें प्रोग्राम के अन्तर्गत 10 जिलों के 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को चुना जायगा। उनके द्वारा प्राथमिक स्कूलों के छात्रों को स्वास्थ्य के बारे में विशेष शिक्षण दिया जायेगा। जो अस्पताल हैं, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र हैं, पंचायत समितियां हैं तो उनके जिम्मे कुछ एक काम सौंपे जायेंगे। स्वास्थ्य सेवा प्रोग्राम के अन्तर्गत स्कूलों को प्राथमिक

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

स्वास्थ्य केन्द्र से जोड़ा जायगा तो बच्चों को शुरू से ही जानकारी मिल सकेगी। इस प्रकार की योजना तैयार की जायेगी।

इसी के साथ-साथ एस.एम.एस.हास्पिटल के बारे में, माननीय सदस्यों ने खास कर गिरधारीलाल जी भार्गव और उजला बहनजी ने जो चिन्ता व्यक्त की है और जो बातें कहीं हैं, मेरा निवेदन है कि एस.एम.एस. ही नहीं सारे अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार किया जायेगा। सब लोगों ने अपने-अपने क्षेत्र की बात कही है उनको मेरा निवेदन है कि सब अस्पतालों की जो व्यवस्था है उसके अन्दर तेजी से सुधार किया जायेगा, माननीय सदस्यों का सहयोग चाहिये। माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक माननीय सदस्यों का इसमें सहयोग नहीं होगा तब तक यह संभव नहीं हो सकेगा। यहां पर भी समिति का गठन होगा। इसके साथ-साथ जो भी कठिनाइयां, दिक्कतें होती हैं, जिस प्रकार का कार्य वहां चलता है, उसकी जानकारी समय समय पर देते रहेंगे। इस प्रकार परम्परा बन जाये कि हर जिले के विधायक को समय-समय पर निमन्त्रित कर विचार-विमर्श करेंगे ताकि जानकारी मिल सके और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किये जा सकें। आपके और राजकीय सहयोग से इस मामलों को जल्दी निपटा लिया जायगा।

आज चिन्ता यहां प्रकट की गई है कि महिलाओं के लिये और बच्चों के लिये कोई अलग से अस्पताल होना चाहिये। यह बहुत वाजिब मांग है। इसके लिये प्रयत्न जारी हैं कि महिला चिकित्सालय खोल सकें। इसके साथ-साथ यह प्रयत्न किये जायेंगे कि बच्चों का भी अलग से अस्पताल बन सके ताकि जो कमियां राजस्थान में.....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : It should be for every city, not for Jaipur only.

श्री त्रिलोकचंद जैन : इसके साथ ही साथ अनुसंधान केन्द्र की भी यहां स्थापना होगी। हृदय रोग और दूसरे रोगों के अनुसंधान के लिये एस.एम.एस. मेडिकल कालेज के साथ अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की जायेगी। इसके लिये बांगड़ से सहयोग मिला है। इसकी स्थापना के बाद अनुसंधान का काम भी यहां पर चल सकेगा।

एक यह भी सोचा जा रहा है कि आगामी वर्ष में, जिस प्रकार से मोबाइल सर्जीकल यूनिट्स हैं, उसी तरह से सम्पर्क करके ऐसे साधन जुटाये जायेंगे जिनके द्वारा मोबाइल अस्पताल भी रहें ताकि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा नहीं पहुंच सके वहां पर डाक्टर चले जायें, सप्ताह में एक बार चिकित्सा की सुविधा कर आयें और अधिक से अधिक चिकित्सा सुविधा दे सकें।

एस.एम.एस. के साथ जो इमर्जेन्सी वार्ड है उसका भी एक्सटेन्शन किया जायगा ताकि ज्योंही इमर्जेन्सी में रोगी आये तत्काल उसकी वहीं पर व्यवस्था हो सके।

मेजर श्री फतेहसिंह : अजमेर और ब्यावर का नाम नहीं लिया।

एक माननीय सदस्य : नाम तो जालोर का भी नाम नहीं आया।

श्री त्रिलोकचंद जैन : गिरधारी लाल भार्गव ने प्रश्न उठाया था। इसके लिये एक कमेटी बनी हुई है। जब तक उसकी रिपोर्ट

# Page No 252

(252)



(श्री त्रिलोकचन्द जैन)
नहीं आ जाती है, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। रिपोर्ट आने पर उसके आधार पर राज्य सरकार उसके सुझावों पर सारी स्थिति को देखते हुए निर्णय लेगी। लेकिन आपको मालूम होगा, इन्डियन मेडिकल कौंसिल ने निर्णय लिया है प्राइवेट प्रेक्टिस को रोकने के लिये। राज्य सरकार के पास भी यह निर्णय आया है। कमेटी की रिपोर्ट आ जायेगी, तब इस पर विचार किया जायेगा।

आयुर्वेदिक औषधालयों के लिये भी आप लोगों ने चिन्ता व्यक्त की कि उनमें अच्छी व्यवस्था नहीं है। सभी प्रकार औषधालयों में अच्छी व्यवस्था की जायेगी। औषधालयों में जो कमियां हैं, उनकी पूर्ति की जायेगी। औषधियां पहुंच सकें, इसकी व्यवस्था की जायेगी। जो वहां पर भ्रष्टाचार की बात कही गई, उसका निराकरण किया जायेगा। जो विशेष बातें कही गईं, उनके बारे में और जो जानकारी देंगे उसकी जांच कराई जायेगी। कोई डॉक्टर हो या कोई वैद्य हो, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जायेगा। दोषी को हटाया जायेगा, यदि कोई बात हुई है, तो एक्जामिन करा ली जायेगी।

आयुर्वेद के क्षेत्र में यहां पर आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान है उसके साथ कॉलेज चलता है उसको भी सुसंगठित बनाया जायेगा। उसके बारे में भी कुछ शिकायतें हैं कि वहां चिकित्सा की व्यवस्था ठीक नहीं है। भारत सरकार से बात करके उस व्यवस्था को ठीक कर लिया जायेगा ताकि अनुसंधान ठीक से हो सके। होम्योपैथी बोर्ड के बारे में जो चिन्ता प्रकट की है वह सही है। उसका पुनर्गठन किया जायगा। होम्योपैथी के विकास के लिये पूरा प्रयत्न किया जायगा। इसके लिये ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जायगी। एग्जामिनेशन का भी प्रबन्ध करने की सोच रहे हैं। और भी जो कार्य करने होंगे उसको सक्षम बनाने के उन पर पूरी तरह से विचार किया जायेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : होम्योपैथी दवाओं का पुनर्भरण नहीं होता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे ?

एक माननीय सदस्य : गांवों में चलिये साहब।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : मैं गांवों से तो वापस जयपुर में आया हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो यूनानी पद्धति के बारे में कहा गया है उसके बारे में मेरा निवेदन यह है कि अच्छे हकीम मिलते नहीं हैं। काफी कोशिश करने पर भी हकीम नहीं मिले है।

श्री अब्दुल अजीज : मेरे पास लिस्ट है, 20 हकीमों की।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : आपकी तो आदत बन गई है बीच में बोलने की।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझसे भी कई हकीम मिले हैं। उन्होंने कहा है...

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय मंत्री महोदय का भाषण तो सुन लीजिये फिर क्वेश्चन पुट-अप कर लेना।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को इस बारे में चिन्ता है लेकिन हकीम उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। यदि आपके पास प्रमाणित लोग हैं और कोई लिस्ट है

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

तो राज्य सरकार अवश्य उनकी सेवायें लेना चाहेगी और जो यूनानी अस्पताल में पद खाली पड़े हैं उनको भरना चाहेगी। इस के बारे में एक निवेदन और कर दूं, जो भी पढ़ना चाहेगा उसके लिये स्टाइपेंड की भी व्यवस्था की जायगी। जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि इसको राज्य सरकार चलाना नहीं चाहती है, यह बात नहीं है। यूनानी अस्पताल हम चलाना चाहते हैं, राज्य सरकार इनको चलाने की मंशा रखती है। यदि आपके सहयोग से यह व्यवस्था हो जाती है तो मैं उसके लिये अवश्य विचार करूंगा।

श्री नवनीत पालीवाल : अगर उम्र उनकी राज्य सेवा से बाहर हो गई हो तो....

श्री अब्दुल अजीज : मेरे पास वास्तव में सूची है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या मंत्री महोदय समाप्त कर चुके हैं?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : इसके साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा के विकास पर भी जोर दिया जायगा। इसको भी मान्यता प्रदान की जायगी।

अभी तक कुष्ट रोग की चिकित्सा की भी व्यवस्था नहीं है। उसकी भी सारी व्यवस्था की जायगी।

इसके साथ ही योगिक केन्द्र का भी विकास किया जायगा। एक समन्वित पद्धति का विकास किया जायगा। यदि इसके लिये अनुसंधान केन्द्र भी खोलना होगा तो उसके लिये भी प्रयत्न किया जायगा।

माननीय सदस्य बहुत जल्दी में हैं अतः अन्त में एक बात कह कर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। जिन माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये हैं, उनके सभी के उत्तर दिये जा चुके हैं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : उसकी जांच करा ली है। जो वेतन नहीं मिला है उसकी भी जांच कर ली गई है। शीघ्र ही कार्यवाही कर दी जायगी।

माननीय माधो सिंह जी ने कहा उसके बारे में भी मैं बताना चाहता हूं। जो वहां घटना घटी है, मैं उसकी जानकारी देना चाहता हूं। 16-3-78 को यह घटना हुई है। अस्पताल में मां और बच्चा पहुंचा है। मां तो सीरियस थी उसको भर्ती कर लिया गया। वे मेडीकल लीगल सर्टिफिकेट चाहते थे इसके लिये अस्पताल वालों ने कहा, अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिये तो इसके जो टांके लगाने हैं, घाव के अनुसार वे सवेरे लग पायेंगे। लेकिन उन्होंने कहा अभी लगा दीजिये। उन्होंने इनसिस्ट किया। उसके बाद करीब 400-500 लोग इकट्ठे हो गये। यह जोर दिया कि टांके तुरन्त लगाये जायं और मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाय। इस घटना को सुनकर कलेक्टर महोदय भी पहुंच गये थे और पुलिस के आफिसर भी पहुंच गये थे उन्होंने तुरन्त सिचुएशन को संभाला। अब उसके लिये डॉ. हरनेजा जो प्रोफेसर हैं सर्जरी के, की इन्क्वायरी बिठा दी है। उस इन्क्वायरी की रिपोर्ट आने पर कार्यवाही कर ली जायगी। यह पूरी जानकारी मैंने आपके सामने रख दी है। मैं एक बार फिर आप सबसे यह कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार....

श्री माधोसिंह कछवाह : वहां दवाओं की चोरी को रोकने की क्या व्यवस्था की ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : मैं जोधपुर गया था। महात्मा गान्धी अस्पताल के बारे में आपने बताया है, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कई माननीय सदस्यों ने अव्यवस्थाओं के बारे में अपनी चिन्ताएं प्रकट की हैं। अतः इस प्रकार की समस्या सभी जगह है तो धीरे-धीरे इस सारी अव्यवस्था को भी सुधारा जायगा। भ्रष्टाचार है, दवाइयां उपलब्ध नहीं होतीं, मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं यह आम शिकायत है कि अस्पताल में पट्टियां नहीं मिलती हैं, दवाइयां नहीं मिलती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं काफी अस्पतालों में गया और ऑल ऑफ ए सडन गया लेकिन उन्होंने मुझे बताया दवाइयां काफी हैं, पट्टियां काफी हैं....

मेजर श्री फतह सिंह : बरार में नहीं है।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : दवाइयां मिल सकें, पट्टियां मिल सकें और अन्य जो सामान्य सुविधायें हैं, वे उपलब्ध हो सकें और गरीब से गरीब व्यक्ति को मिल सके इसमें भी समुचित सुधार कर लिया जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं जो चिन्ता प्रकट की है स्वास्थ सेवाओं के सुधार के बारे में, वह अवश्य की जायगी और आगामी सत्र में मिलेंगे तो ये असुविधायें नहीं रहेंगी।

ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में कहा गया, इसके लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो आगामी वर्ष की योजना तैयार की है वह अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्र में जायें और सब तरह की शक्ति को उधर लगाया जाय, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। नगर क्षेत्रों की भी कमियों की पूर्ति करेंगे। इस आशय के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मांग पारित की जाय।

सुश्री पुष्पा जैन : मंत्री महोदय, एक प्रश्न का उत्तर और दे दें। माननीय सदस्या को जो मच्छर काट रहे हैं, जब तक आपका अनुसंधान पूरा हो और उसकी रिपोर्ट पेश हो तब तक एक ओडोमास माननीय सदस्या को भेंट कर दिया जाय।

श्री अब्दुल अजीज : माननीय मंत्री महोदय, कई प्रश्न रह गए हैं जिन पर आपने कोई प्रकाश नहीं डाला है। परिवार कल्याण के बारे में आपने कुछ भी नहीं फर्माया। सरकार इस बारे में क्या करना चाहती है? बढ़ती हुई आबादी की समस्या की तरफ से क्या आपने ध्यान हटा दिया है और इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया है?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : माननीय सदस्य, कई बातें ऐसी हैं जो मैं नहीं कह सका हूं। फैमिली प्लानिंग, परिवार कल्याण योजना के बारे में मैं निवेदन कर दूं कि हमने उस कार्यक्रम को छोड़ नहीं दिया है, वह कार्यक्रम है लेकिन स्वेच्छा से किया जाएगा। हम यह नहीं समझते हैं कि यह कार्यक्रम केवल कृत्रिम साधनों से और प्रसाधनों से ही हो सकेगा। इसमें राष्ट्रीय संकल्प की आवश्यकता होगी। इन कृत्रिम साधनों से कुछ भी नहीं हो सकेगा। हमारा पर्सेन्टेज जनसंख्या का बढ़ता जा रहा है उसको रोकने के लिए राष्ट्रीय संकल्प की आवश्यकता है। यह भी एक तथ्य है कि हमारी अधिकांश जनसंख्या खेती पर निर्भर है। जब तक खेती से उद्योग की तरफ उनको नहीं लगा सकते इस समस्या का समाधान इतना आसान नहीं है। जब तक उद्योगों पर

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

नहीं चले जाते हैं तब तक हम राजस्थान के परिवारों पर यह लागू नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि स्वेच्छा से काम करें, स्वेच्छा से सब साधन उपलब्ध करायें, शिक्षण प्रशिक्षण दें और साधन उपलब्ध करायें। इसका अधिक से अधिक डायरेक्टली प्रचार किया जावेगा और ऐसा वातावरण बनाया जाएगा कि जिससे यह काम हो सके। इसमें आप और हम सभी में संकल्प पैदा हो तभी हम कर सकेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : रात को 1 बजे तो परिवार नियोजन की बात मत करो।

मांग संख्या 2 व 26 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 2— मंत्रिपरिषद् के संबंध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 38,20,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग बहुमत से स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 26- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 46,40,06,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

मांग सर्व सम्मति से स्वीकृत की गई।

सदन की बैठक आज दिनांक 18 मार्च, 1978 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 1.03 बजे, शनिवार, दिनांक 18 मार्च, 1978 के म.पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(258)



## परिशिष्ट 1

( तारांकित प्रश्न संख्या 318 की सूची )

चूरू में 20-8-77 के पश्चात् हुई वर्षा की सूची

| | |
|---|---|
| 20-8-77 से 23-8-77 तक | शून्य |
| 24-8-77 | 13 मि. मी. |
| 25-8-77 | 03 मि. मी. |
| 26-8-77 से 1-9-77 तक | शून्य |
| 2-9-77 | 14 मि. मी. |
| 3-9-77 से 5-9-77 तक | शून्य |
| 6-9-77 | 70 मि. मी. |
| 7-9-77 | शून्य |
| 8-9-77 | 23 मि. मी. |
| 9-9-77 से 14-9-77 तक | शून्य |

## परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 319 की सूची )

वकीलों को बोर्ड द्वारा किये गये भुगतान की राशि सम्बन्धी विवरण

| क्र. सं. | वकील का नाम | भुगतान की गई राशि |
|---|---|---|
| 1. | श्री महावीर चन्द भण्डारी, जोधपुर । | 12,000/- रुपये |
| 2. | श्री शशिकान्त गुप्ता, जयपुर । | 550/- रुपये |
| | योग .. | 12,550/- रुपये |

# परिशिष्ट 3

( तारांकित प्रश्न संख्या 15 की सूची )

| | |
|---|---|
| प्रचार प्रसार व्यय | 1,62,871—88 |
| मुशायरा व्यय | 8,651—82 |
| कार्यालय व्यय | 33,916—52 |
| आवास व्यवस्था | 14,852—00 |
| सांस्कृतिक कार्यक्रम | 38,800—00 |
| ललित कला प्रदर्शनी | 4,500—00 |
| उपहार | 3,029—20 |
| खेलकूद | 5,000—00 |
| कवि सम्मेलन | 10,000—00 |
| जुलूस व्यय | 28,786—00 |
| ध्वनि प्रकाश आयोजन | 4,155—15 |
| आतिशबाजी | 3,966—00 |
| कुल व्यय . . | 3,23,518—35 |

---

## परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

### मकराना क्षेत्र की सड़कें

320. श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मकराना क्षेत्र में इस वर्ष कहां-कहां कच्चो व पक्की सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि मकराना से नागौर-कुचामन-डीडवाना होकर सड़क सौ मील है जबकि मकराना-मनाना होकर केवल साठ मील है ? यदि हां, तो इस सड़क को पूर्ण कराने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

(3) क्या यह सही है कि मकराना-बिदियाद सड़क का मरम्मत कार्य विभाग द्वारा नहीं किया जाता ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक होगा ?

उत्तर

(1) इस वर्ष मकराना क्षेत्र में निम्नलिखित सड़कों के निर्माण का कार्य चालू है:—

(अ) मकराना-मंगलाना सड़क सुधार कार्य कि. मी. 0/0 से 7/0 तक चालू है।

(ब) मकराना-बूडसू सड़क का निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है।

(स) माइनिंग सड़कों का निर्माण के अन्तर्गत रेवतडूंगरी से भातामर माइन्स तक 2 कि. मी. डामर का कार्य चालू है। तथा पिक रेल से चकडूंगरी के बीच बोरावड़ तक एवं बोरावड़ से बोरावड़ माइनिंग एरिया की सड़कों के कार्य भी शीघ्र ही हाथ में लिये जा रहे हैं।

(2) मकराना से नागौर-डीडवाना होकर 170 कि. मी. है तथा मनाणा रानी गांव खाटू होकर नागौर 119 कि. मी. है। सड़क को पूर्ण कराने हेतु छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विचार किया जायेगा।

(3) मकराना बिदियाद सड़क माइन्स विभाग की सड़क होने से इस विभाग द्वारा इसकी मरम्मत नहीं कराई जाती है। ऐसी माइन्स विभाग की सड़कों की देख-रेख व मरम्मत इस विभाग द्वारा कराये जाने पर विचार किया जायगा।

### राज्य में चरागाह भूमि का आवंटन

321. श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि आपातकालीन स्थिति के दौरान राज्य सरकार द्वारा बहुत सी चरागाह भूमि का आवंटन अवैधानिक रूप से कर दिया गया था ? यदि हां, तो राज्य सरकार इसके लिये क्या कदम उठा रही है ?

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा पिछले विधान सभा सत्र में जनता को अवैध आवंटन को रद्द करने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो कब तक यह कार्यवाही पूरी कर दी जायगी ?

(राजस्व मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां, सन् 1975 में चलाये गये भू-आवंटन अभियान के दौरान चरागाह भूमि का परिवर्तन कर भूमिहीनों को आवंटन किया गया था। समस्त मामले पर पूर्ण विचार मंत्रि-मण्डलीय उप-समिति कर रही हैं।

(2) जी हां। यह मामला मंत्रिमण्डल की एक उप-समिति के विचाराधीन है। शीघ्र ही कार्यवाही किये जाने की आशा है।

गुड़ बनाने के लिए लाइसेंस

322. श्री रामप्रसाद लडढ़ा (मांडल): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि मांडल की मुख्य फसल गन्ना है? क्या यह सही है कि काश्तकार को कच्चे माल का पक्का माल बनाने के लिए अपने कृषि बिजली कनेक्शन का उपयोग करना होता है?

(2) क्या यह सही है कि ऐसे कृषि कनेक्शन के उपयोग के लिए उद्योग विभाग का गुड़ बनाने के लिए लाइसेन्स लेना पड़ता है?

(3) क्या यह भी सही है कि ऐसा लाइसेन्स जयपुर से ही मिलता है?

(4) क्या यह सही नहीं है कि काश्तकार बिना मतलब से इस व्यवस्था का शिकार होता है? लाइसेन्स की व्यवस्था को न समझने के कारण काश्तकार अपने कच्चे माल का पक्का माल ही नहीं बना पाता है व खंडसारियों के मन मुताबिक भावों पर उसे गन्ने को बेचना पड़ता है?

(5) काश्तकार के लिये लाइसेन्स पद्धति जो विगत सरकार की थोपी हुई व्यवस्था है उसके लिए वर्तमान राज्य सरकार क्या विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। गन्ना मांडल क्षेत्र की मुख्य फसल है। गन्ने से गुड़ एवं खण्डसारी शुगर बनाने के लिये कृषि बिजली कनेक्शन का उपयोग अनिवार्य नहीं है। गुड़ एवं खण्डसारी हस्तचलित क्रशर एवं अन्य पावर कनेक्शन से भी बनाये जा सकते हैं।

(2) जी हां। पावर से गुड़ बनाने वाले यंत्रों को लगाने से पूर्व उद्योग विभाग से लाइसेन्स लेना पड़ता है, परन्तु पावर के बगैर गुड़ बनाने के लिए किसी लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं है।

(3) दिनांक 9-2-78 से पूर्व लाइसेन्स उद्योग विभाग के जयपुर स्थित मुख्यालय से मिलता था लेकिन अब नियमों में संशोधन कर यह लाइसेन्स शुगर मिलों के लिये आरक्षित क्षेत्रों के अतिरिक्त, दिनांक 9-2-78 से, उद्योग विभाग के जिलास्तरीय अधिकारियों के द्वारा दिया जाता है।

(4) जिला स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से लाइसेन्स दिये जाने की प्रक्रिया के फलस्वरूप स्थानीय लोगों को कम समय में लाइसेन्स प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध हो गई है। लाइसेन्स प्राप्त करने की प्रणाली सरल है केवल निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन-पत्र भर कर प्रस्तुत करने पर लाइसेन्स प्रेषित कर दिया जाता है। काश्तकारों को वर्तमान लाइसेन्सिंग प्रणाली से परेशानी के संबंध में, विभाग में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई

Page No 260

(260)



( उद्योग मंत्री )

है फिर भी राज्य सरकार द्वारा आवेदन-पत्र प्राप्त होने की तिथि से अधिक से अधिक डेढ़ माह (1-1/2 माह) की अवधि में लाइसेंस देने के लिये लाइसेन्सिंग अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं। कृषक स्वयं हस्त-क्रशार से गुड़ बना कर गन्ने का उपयोग कर सकता है, इसके लिये लाइसेन्स अनिवार्य नहीं है। ऐसी स्थिति में खण्डसारी इकाइयों को मनमाने भावों पर गन्ना बेचने के लिये कृषक मजबूर नहीं है।

काश्तकार को हस्तचलित क्रशार से गुड़ बनाने के लिये लाइसेन्स से मुक्त करने का राजस्थान खन्डसारी शूगर मन्युफेक्चरर्स लाइसेन्सिंग ऑर्डर, 1974 में प्रावधान कर दिया गया है। यह प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार उपलब्ध कराने की नीति को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है।

पांच हजार एवं उससे अधिक जनसंख्या के गांवों को डामर सड़कों से जोड़ने का निर्णय

323. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने पांच हजार एवं उससे अधिक जनसंख्या के गांवों को डामर सड़कों से जोड़ने का निर्णय ले लिया है और उक्त निर्णय की क्रियान्विति की जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले जहां कि जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर पर औसत 4 और 27 क्रमशः बसी हुई है, में भी यही मापदण्ड अपनाना उन पिछड़े हुए जिलों को और भी पिछड़ा हुआ रखना नहीं है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त निर्णय उक्त पिछड़े हुए जिलों के लिए किसी भी न्याय के सिद्धान्त पर सही नहीं उतरता ? यदि हां, तो राज्य सरकार उक्त पिछड़े हुए जिलों के लिए 2000 की जनसंख्या का मापदंड अपनाने के निर्णय लेने के लिए तैयार है? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जनसंख्या का आधार एक मापदण्ड है जिसको समानता से अपनाना होगा। सड़क दूसरे मापदण्ड जैसे कृषि, उद्योग व अन्य महत्वों के अनुसार भी स्वीकृत की जाती है।

(3) जी नहीं। मापदण्ड 5000 की आबादी से 2500 की आबादी जोड़ने वाली सड़कें अगले वर्षों के लिए लेने का विचार किया जा रहा है।

कोटपूतली में सैटलमेंट का कार्य और कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

324. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटपूतली तहसील में हो रहे सैटलमेन्ट में कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों में से किस-किस के विरुद्ध कब कब शिकायतें की गईं और उन पर क्या क्या कार्यवाही हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

( श्री रामकरण सिंह )

(2) सैटलमेंट का कार्य पूर्ण हुए बिना ही बीच में किन-किन कर्मचारियों व अधिकारियों का उक्त क्षेत्र से किन कारणों से स्थानान्तरण किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि भूमि व भू-खण्डों की नापतोल करने वाले व्यक्ति उनसे पूर्ण परिचित होते हैं और उनसे ही पूर्ण कार्य सम्पन्न कराना सब तरह से वाजिब और न्याय संगत है ?

उत्तर

(1) कोटपूतली तहसील में हो रहे सैटलमेंट में कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों के विरुद्ध समय समय पर प्राप्त शिकायतें मय उन पर चल रही कार्यवाही परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(2) सैटलमेंट कार्य पूर्ण हुए बिना जिन-जिन कर्मचारियों एवं अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया उनकी सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है ।

(3) यह सही है । परन्तु जिस भू-मापक का कारणवश स्थानान्तरण किया जाता है उसके स्थान पर कार्य के अनुभवी भू-मापक को ही लगाया जाता है ।

( सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई )

ग्राम सेवा सहकारी समितियों का पुनर्गठन

325. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम सेवा सहकारी समितियों की बड़ी यूनिट बनाने एवं पुनर्गठन हेतु राज्य सरकार की क्या नीति है ?

(2) क्या यह सही है कि अधिक गांवों को एक समिति में मिलाने से व एक दूसरे गांव की दूरी अधिक होने से रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं, खाद, बीज, शक्कर आदि लाने ले जाने में जनता को कठिनाई नहीं होगी ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार इस पर पुनर्विचार करना उचित समझेगी ?

उत्तर

(1) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा गठित अध्ययन दल की सिफारिशों के अनुसार प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों को सक्षम इकाई बनाने की दृष्टि से राज्य में विभिन्न कमजोर कार्यरत सहकारी समितियों का एक दूसरे के साथ पुनर्गठन किया गया है । इस नीति के अनुसार साधारण क्षेत्र में प्रत्येक समिति के कार्य क्षेत्र में 2000 हैक्टेयर्स कृषि योग्य भूमि होना जरूरी है । अर्ध रेगिस्तानी व रेगिस्तानी क्षेत्रों को समितियों में प्रत्येक समिति के क्षेत्र में 5000 हैक्टेयर्स कृषि योग्य भूमि होना जरूरी समझा गया ताकि प्रत्येक समिति निकट भविष्य में 2.00 लाख का अल्पकालीन ऋण प्रत्येक वर्ष में वितरित कर सके । इस आधार पर समितियों को बड़ी यूनिट बनाने हेतु पुनर्गठन किया गया है ।

(2) जी नहीं । राज्य सरकार द्वारा जिलाधीशों को आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं कि जिन क्षेत्रों में पुनर्गठित समितियों के मुख्यालय की दूरी के कारण ग्रामीणों को उपभोक्ता वस्तुएं जैसे शक्कर, कपड़ा

(सहकारिता मंत्री)

आदि के प्राप्त करने में कठिनाई आती है तो ऐसे क्षेत्रों में पुनर्गठित समितियों के क्षेत्र में जहां पहले से चीनी, कपड़ा आदि वस्तुएं ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जाती हैं, वहां सब-सेन्टर्स पुनर्गठित समितियों के खोले जा सकते हैं और यदि पुनर्गठित समितियां सब-सेन्टर्स खोलने में सक्षम नहीं है, तो अन्य प्रबन्ध किया जावे ।

नोहर तहसील के ग्रामों में लघु उद्योग

326. श्री बहादुर सिंह (नोहर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य सरकार ग्रामों के लघु औद्योगीकरण के लिए क्या उपाय कर रही है ?

(2) क्या यह सही है कि नोहर तहसील के पल्लू तथा रावतसर क्षेत्र में डेयरी, ऊन उद्योग तथा ग्वार कारखाना लगाने की प्रबल सम्भावनाएं हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार उक्त उद्योग लगाने का कब तक इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा लघु उद्योग स्थापित कराने के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं एवं सहायता उपलब्ध कराई जाती है । लघु उद्योगों को दी जाने वाली सहायता एवं सुविधाओं की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी हां । राज्य सरकार (उद्योग विभाग) स्वयं द्वारा कोई उद्योग स्थापित नहीं किया जाता है किन्तु राज्य सरकार, उद्योग विभाग तथा अन्य सम्बन्धित मण्डलों/निगमों के माध्यम से विभिन्न सहायता एवं सुविधाएं उपलब्ध कराकर उत्साही उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु प्रेरित करती है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गांव टावलिया खुर्द के सरपंच के विरुद्ध गबन का मामला

327. श्री भूरालाल (गोगुन्दा) : क्या पंचायती राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गांव टावलिया खुर्द के सरपंच, श्री नन्दराम जोशी को श्री देवी सिंह राजपूत, नि. रावलीया खुर्द ने दिनांक 3-12-75 को 367 रु. रतनजोत के ठेके की आखिरी किश्त जमा करा दी थी, परन्तु श्री नन्द राम ने उक्त रकम दिनांक 13-1-78 तक जमा नहीं कराई ?

(2) क्या यह भी सही है कि जब कि सरपंच ने 30-12-77 को पंचायत का चार्ज ग्रुप सचिव को दे दिया, जिसमें उक्त रकम को जमा करना नहीं बताया ? परन्तु 12-1-78 को 455/- रु. जमा कराया गया ? यदि हाँ, तो क्या यह गबन पंचायत कोष का दुरुपयोग नहीं है ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा सरपंच के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

उत्तर

(1) जी हां । श्री नन्दराम जोशी, सरपंच ने दिनांक 13-1-78 को मनीआर्डर द्वारा 361) रुपये मूल व 94) रुपये ब्याज कुल 455) रुपये पंचायत में जमा कराये हैं ।

(2) जी हां । श्री नन्दराम जोशी, सरपंच द्वारा पंचायत की राशि को यथा समय

(पंचायती राज मंत्री)
पंचायत कोष में जमा नहीं कराने और प्रशासक को पंचायत का चार्ज देते समय भी उक्त राशि चार्ज में नहीं देने का कृत्य स्पष्ट रूप से पंचायत की राशि के गबन एवं दुरुपयोग की परिभाषा में आता है। श्री देवीसिंह द्वारा दिनांक 28-1-78 को शिकायत प्रस्तुत करने पर ही यह मामला प्रकाश में आया है और इस प्रकरण की जांच कार्यवाही चल रही है।

भूमि संबंधी कानूनों में संशोधन

328. श्री करतारसिंह (किशनगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में राजस्थान में जो भूमि संबंधी कानून (भू-राजस्व अधिनियम एवं राजस्थान टेनेन्सी अधिनियम आदि) लागू हैं ये काफी अर्से पहले बनाये गये थे?

(2) वर्तमान में क्या राज्य सरकार इन कानूनों को समयोचित मानती है?

(3) क्या यह सही है कि इन भूमि संबंधी कानूनों में इतने संशोधन किये जा चुके हैं कि इनका मूल रूप ही समाप्त हो चुका है?

(4) क्या वर्तमान में राज्य सरकार इन भूमि संबंधी कानूनों को वर्तमान समयानुसार पुनः अभिलेख (रि-ड्राफ्ट) करना उपयुक्त समझती है? यदि हां, तो इस संदर्भ में राज्य सरकार ने क्या कोई कार्यवाही की है? कब तक इन भूमि संबंधी कानूनों का री-ड्राफ्ट कर लिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वर्तमान में उक्त कानून समयोचित है।

(3) जी नहीं।

(4) वर्तमान में राज्य सरकार इन भूमि सम्बन्धी कानूनों को वर्तमान में समयानुसार पुनः अभिलेख करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है। राजस्थान टेनेन्सी अधिनियम नया प्रारूपेण हेतु विधि विभाग में कार्यवाही की जा रही है। राजस्व सम्बन्धी कानूनों में पुनः अभिलेख करने का प्रश्न नीति निर्धारण का है। इस पर राज्य सरकार विचार करेगी। इसमें कितना समय लगेगा वह इस समय बतलाना सम्भव नहीं है।

उत्तर राजस्थान दुग्ध उत्पादक संघ, बीकानेर के महा प्रबन्धक के विरुद्ध शिकायतें

329. श्री हजारीमल सारण (सरदार शहर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उत्तर राजस्थान दुग्ध उत्पादक संघ, बीकानेर के महा प्रबन्धक के कार्य-व्यवहार के प्रति दुग्ध उत्पादकों व समितियों में भारी असन्तोष है और अनेक शिकायतें महा प्रबन्धक के खिलाफ राज्य सरकार को की गई हैं? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त महा प्रबन्धक को संघ के हित में अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी या हटायेगी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार उक्त संघ का प्रबन्ध दुग्ध उत्पादकों के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में सौंपने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

पशुपालन मंत्री

उत्तर

(1) जी हां। कुछ शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई हैं एवं महा प्रबन्धक को स्थानान्तरण करने या हटाने का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) जी हां। वर्तमान में मनोनीत, संचालक मंडल, जिसमें दुग्ध उत्पादकों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं, की अवधि दिनांक 2-9-79 को समाप्त होने पर, चयनित संचालक मंडल के विषय पर विचार किया जावेगा।

अगोलाई-माडपुरा सड़क का कार्य

330. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले की अगोलाई (जिला जोधपुर) से माडपुरा की सड़क का निर्माण कब कराया गया था? क्या बाड़मेर जिले में इससे पुरानी कोई और सड़क है जो अब तक डामर की नहीं बनायी गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि इस सड़क पर चार ग्राम पंचायतों के मुख्यालय, एक पुलिस थाना और एक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र स्थित हैं?

(3) क्या यह सही है इस सड़क को अत्यन्त बिगड़ी हुई स्थिति के कारण उस मार्ग पर चलने वाली बस सेवा अनियमित है और इसी कारणवश जिले के इस क्षेत्र के नागरिकों और कर्मचारियों को सम्बन्धित तहसील, सब-डिवीजनल, पंचायत समिति और जिला मुख्यालय तक आने-जाने में कम से कम तीन दिन लगते हैं?

(4) इस सड़क को अब तक डामर की नहीं बनाने के क्या कारण रहे हैं? अब कब तक इसे डामर का बना दिया जायेगा?

उत्तर

(1) यह सड़क स्टेट के समय से एक ग्रेवल रोड बनी हुई है।

जी नहीं।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। ऐसी कोई जानकारी विभाग को नहीं है।

(4) इस सड़क को डामर करने का अभी तक कोई प्रस्ताव या स्वीकृति नहीं है।

छठी पंचवर्षीय योजना में विचार किया जा सकेगा।

राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा रोड रोलरों की खरीद

331. श्री हरजी राम बुरड़क (लाडनूं): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार को यह जानकारी है कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा खरीदे गये रोड रोलरों में घोटाला हुआ है? यदि हां, तो कब और क्या घोटाला हुआ है और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अब तक क्या-क्या कार्यवाही की है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) अब इस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही कब तक करनी है?

उत्तर

(1) बोर्ड में 18 रोड़ रोलर अब तक निम्न प्रकार के खरीदे गये हैं:—

1. स्पीड क्राफ्ट रोड रोलर- वित्त नियमों के अन्तर्गत ओपन टेण्डर मांगकर, यह रोड रोलर 'जी' शेड्यूल के आधार पर न्यूनतम दर पर खरीदे गये।

1. लायन
4. जेसप रोड रोलर — डी.जी.एस.डी. के माध्यम से राशि जमा कर यह रोड रोलर खरीदे गये। यह उल्लेखनीय है कि जेसप एण्ड को. भारत सरकार का एक राजकीय उपक्रम है।

3. जेसप रोड रोलर — यह रोड रोलर डी.जी.एस.डी. द्वारा स्वीकृत दर पर खरीदे गये। उपरोक्त अनुसार जेसप एण्ड को. एक राजकीय उपक्रम है।

4. जेसप रोड रोलर — ये रोड रोलर डी.जी.एस. डी. के रेट कान्ट्रेक्ट के आधार पर खरीदे गये।

(2) उक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त रोड रोलरों की खरीद में कोई अनीयमितत्ता नहीं बरती गई है।

## कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, जोधपुर

332. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : क्या भेड़ व ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र (भेड़) कब से कार्य कर रहा है?

(2) अब तक कितने मेमने पैदा हुए हैं? कितने मेमने आज तक जिन्दा हैं? कितने मेमने पैदा होने के 6 माह की अवधि में मर गये?

(3) इस केन्द्र पर वेतन एवं भत्ते व अन्य कार्यों पर कितना व्यय हुआ?

(4) व्यय और समय अवधि के संदर्भ से क्या प्रगति बहुत कम नहीं है?

उत्तर

(1) मण्डोर (जोधपुर) में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र (भेड़) माह नवम्बर, 1968 से कार्य कर रहा है।

(2) अब तक 1,788 मेमने उत्पन्न हुये। वर्ष 76-77 में 149 संकर मेमने भेड़ पालकों के पास जिन्दा थे। इसके अतिरिक्त वर्ष 77-78 में फरवरी, 78 तक उत्पन्न 215 संकर मेमने भेड़पालकों के पास जिन्दा थे। छः माह में मरने की सूचना एकत्र नहीं की जाती है।

(3) इस केन्द्र पर फरवरी, 78 तक रु. 2,97,928/- वेतन, भत्ते व अन्य कार्यों पर व्यय हुआ। नया कार्यक्रम होने के कारण प्रगति कम रही है।

राज्य में लघु उद्योगों के लिए सर्वे

333. श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार राज्य में गांधीवादी सिद्धान्त के आधार पर लघु उद्योगों को सुचारु रूप से चलाये जाने पर विचार कर रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार सिद्धान्ततः इस बात को स्वीकार करती है कि बड़े पैमाने पर चलने वाले उद्योग उसी क्षेत्र में कायम किये जाने चाहिए जहां कुटीर और लघु उद्योगों द्वारा संतोषजनक उत्पादन संभव न हो ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस बारे में सर्वे कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब से और उसके लिए क्या योजना बनाई गई है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। हाल ही में भारत सरकार ने इस विषय में निर्णय लिया है, जिसके अनुसार 504 वस्तुओं का उत्पादन लघु व कुटीर उद्योगों के लिए आरक्षित कर दिया है। पहले यह आरक्षण केवल 180 वस्तुओं के उत्पादन के लिए ही था, जिसको बढ़ाकर अब 504 वस्तुओं के लघु उद्योगों के लिए किया गया है। इन वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने वाले उद्योगों को नहीं करने दिया जायेगा। ऐसी और वस्तुओं के आरक्षण का प्रश्न भी भारत सरकार के विचाराधीन है। राज्य सरकार भी इसी नीति का अनुसरण कर रही है।

504 वस्तुओं की सूची सदन के पटल पर रख दी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

पशु चिकित्सालय भवन, सांचौर

334. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सांचौर नगर में पशु चिकित्सालय भवन के पूरे अहाते का निर्माण अभी तक नहीं करवाया गया है ? अगर हां, तो अहाते की मरम्मत एवं पूरे अहाते का निर्माण कार्य करवाने हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि अहाते का कार्य पूरा करवाने हेतु धनराशि की मांग विभाग से पहले भी की गई थी ? अगर हां, तो कब एवं वांछित धनराशि की मंजूरी अब तक क्यों नहीं की गई ? अब वांछित धन राशि मंजूर की जाकर अहाते का निर्माण कार्य कब तक पूरा करवा दिया जावेगा ?

(3) क्या यह भी सही है कि अगर अहाते का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण नहीं करवाया गया तो पड़ोसी लोगों द्वारा पशु चिकित्सालय भवन की जमीन का नाजायज कब्जा कर दबाने का खतरा है ? अगर हां, तो उक्त अहाते का निर्माण कार्य कब तक पूरा करवाकर उपरोक्त पशु चिकित्सालय भवन की भूमि की सुरक्षा की जा सकेगी ?

(4) क्या यह भी सही है कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा कुछ रकम मंजूर की जाकर पशु चिकित्सालय भवन की मरम्मत करवाई गई थी ? अगर हां, तो कब

( श्री रघुनाथ विश्नोई )
तक एवं कितनी धनराशि मंजूर की जाकर उक्त भवन की मरम्मत करवाई गई थी ?

(5) क्या यह भी सही है कि अब तक पूरे भवन की मरम्मत पर्याप्त धनराशि के अभाव में नहीं की जा सकी है ? अगर हां, तो पूरी मरम्मत कराने के लिए कितनी धनराशि की और आवश्यकता होगी एवं आवश्यक धनराशि मंजूर की जाकर मरम्मत पूरी कब तक करवा दी जावेगी, ताकि आने वाली वर्षा से शेष भवन गिरने से बचाया जा सके ।

उत्तर

(1) जी हां । कार्य पूर्ण करने हेतु रुपये 6,600/- की आवश्यकता होगी ।

(2) जी हां । धनराशि की मांग 1975 में की गई थी । वित्तीय प्रावधान की कमी के कारण मंजूरी नहीं दी जा सकी । वर्ष 1978-79 में कार्य पूरा करा दिया जावेगा ।

(3) जी नहीं । उत्तर खण्ड (2) में दिया जा चुका है ।

(4) जी हां । चल पशु चिकित्सा भवन की मरम्मत पर वर्ष 1976-77 में 4,600/- रुपया व्यय किया गया है ।

(5) पूर्ण भवन के मरम्मत कार्य हेतु तखमीना बनवाया जा रहा है । इसके बाद वांछित धनराशि उपलब्ध होने पर मरम्मत पूर्ण करने की कार्यवाही की जा सकेगी ।

ग्राम सेवा सहकारी समिति, तलाब की जांच

335. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति तलाब में गबन एवं घोटालों की जांच हेतु जांच बैठाई गई थी ? यदि हां, तो जांच अधिकारी ने जांच के दौरान जो बातें एवं कमियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद राज्य सरकार क्या एक्शन ले रही है तथा अब तक क्या हुआ ?

उत्तर

(1) जी हां । ग्राम सेवा सहकारी समिति, तलाब, जिला अलवर का रेकार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण जांच प्रारम्भ नहीं की जा सकी ।

(2) वर्तमान में समिति का रेकार्ड प्राप्त किये जाने की कार्यवाही जरिये पुलिस की गई है । रेकार्ड प्राप्त हो जाने पर जांच करवाई जाकर सहकारी संस्था अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी ।

पंचायत समिति, खेतड़ी क्षेत्र में पशु चिकित्सालय

337. श्री मालाराम (खेतड़ी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति, खेतड़ी में कुल कितने पशु हैं ? क्या राज्य सरकार ने इसका सर्वे करवाया है ?

(2) इस क्षेत्र में कितने पशु चिकित्सालय हैं तथा पशुओं की संख्या को देखते हुए क्या राज्य सरकार का चिकित्सालयों में वृद्धि करने का विचार है ?

(कृषि मंत्री)

उत्तर

(1) पंचायत समिति, खेतड़ी में 1,20, 440 पशु हैं। राज्य सरकार द्वारा हर 5 वर्ष के बाद तहसीलवार पशु गणना कराई जाती है।

(2) दो (एक पशु चिकित्सालय एवं एक पशु औषधालय कार्यरत हैं)।

अभी नहीं।

राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि. के प्रबन्ध संचालक

338. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अनेक अनियमितताओं के बावजूद भी राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि. के प्रबंध संचालक के पद पर अब तक श्री जी. भीमनाथवाला को रखा हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि श्री भीमनाथवाला को अनियमितता, धन के दुरुपयोग तथा गबन की जानकारी देने वाले अपेक्स बैंक के कर्मचारियों को भी श्री भीमनाथवाला धमकियां दे रहे हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि सहकारिता मंत्री को दी गई बैंक के दोषी व्यक्ति की रिपोर्ट उसी व्यक्ति के पास पहुंच गई?

उत्तर

(1) जी नहीं। श्री जी.ए. भीमनाथवाला की प्रतिनियुक्ति अवधि 31 मार्च, 1978 को समाप्त हो रही है और उसमें वृद्धि नहीं की जा रही है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

ग्राम सुखपुरा को लाल पत्थर की खान

339. श्री एच.एन. शर्मा (बेगूं) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, भैंसरोडगढ़, ग्राम सुखपुरा के पास मगरी पर लाल पत्थर की पट्टियों की खदान से पट्टियां निकाली जाती थीं? अगर हां, तो इस खदान को किन कारणों से बन्द किया गया?

(2) क्या निकट भविष्य में राज्य सरकार इस खदान पर पुनः कार्य शुरू करने का विचार रखती है? अगर हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। विभाग द्वारा ग्राम सुखपुरा पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ में किसी प्रकार की खान स्वीकृत नहीं है और न ही कोई खनन पट्टे चल रहे हैं।

(2) जी हां। फील्ड स्टाफ के द्वारा जांच कराई जा रही है यदि कोई लाल पत्थर की वेन वहां हुई तो शीघ्र सर्वेक्षण किया जाकर डेलिनेटेड प्लाट तैयार किये जाकर अनुदान नियमानुसार दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

सरपंचों एवं पंचों को पारिश्रमिक देने का विचार

340. श्री शंकरलाल (जैतारण)

(श्री शंकर लाल)

क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ग्राम पंचायतों के निर्वाचित सरपंचों और पंचों को मासिक पारिश्रमिक देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना कब तक ? और नहीं तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि अभी कोई मासिक पारिश्रमिक देने का प्रावधान नहीं होने से नेक, अच्छे, उत्साही परन्तु गरीब लोग पंचायत के कार्य में सरपंच अथवा पंच की हैसियत से अपना समय देने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं ?

उत्तर

(1) निर्वाचित सरपंचों एवं पचों को मासिक पारिश्रमिक देने सम्बन्धी मामला राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के सम्बन्ध में गठित अशोक मेहता कमेटी का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसकी सिफारिशों के आधार पर इस मामले में भी विचार किया जाना संभव है।

(2) जी नहीं।

कृषि उपज मण्डी समिति, बीकानेर

341. श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर कृषि उपज मण्डी समिति ने नई मण्डी के लिए बीकानेर-कोलायत रोड पर जस्सूसर गेट के पास जगह लेकर चारदीवारी बनाना चालू कर दिया था और चारदीवारी लगभग पूरी बन गई थी परन्तु आपातकाल के दौरान इस जगह को छोड़कर बीकानेर की बीचवाल रोड पर उरमूल डेयरी के पास जगह पसन्द कर भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री हरि देव जोशी से जगह पर मंडी का शिलान्यास करवाया गया ? यदि हां, तो बीकानेर-कोलायत रोड पर चारदीवारी बनाने में कितना खर्चा किया गया था तथा पुरानी जगह को किस के आदेश पर छोड़ा गया ?

(2) क्या यह भी सही है चीफ टाउन प्लानर नई जगह के विरुद्ध थे ? क्या कृषि उपज मंडी समिति ने मण्डी के लिए लगभग 132 एकड़ जमीन की मांग की थी और इसे लगभग 87 एकड़ जमीन नई जगह पर दी जा सकी ?

(3) क्या यह सही है कि नई जगह नगर विकास न्यास, बीकानेर ने लगभग 40 लाख रुपये में मंडी को दी है ? यदि हां, तो पुरानी जगह से यह जमीन कितनी गुना महंगी है ?

(4) क्या यह सही है कि नई जगह पर मंडी बनाई गई तो भविष्य में विस्तार के लिये और खाली जगह प्राप्त नहीं होगी क्योंकि चारों तरफ रिहायशी बस्तियां, वर्कशाप, डेयरी व आफिसेज हैं ? यदि हां, तो जगह बदलने में किनका निहित स्वार्थ है ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति, बीकानेर ने नई मण्डी के लिये कोलायत रोड पर चार दीवारी बनाना शुरु कर दिया था। केवल दो ओर की दीवारें बनी थीं। कोलायत रोड वाले भू-खण्ड पर चारदीवारी बनाने में 78,454.97 रु.

# Page No 270

(270)



( कृषि मंत्री )
खर्च किये गये। स्थान में परिवर्तन बीकानेर के व्यापारियों के अनुरोध पर तत्कालीन मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न एक बैठक के निर्णय के अनुसार किया गया।

(2) चीफ टाउन प्लानर उस बैठक में उपस्थित थे जिसमें स्थान बदलकर नये भू-खण्ड पर मंडी बनाने का निर्णय लिया गया था। मंडी समिति द्वारा 132 एकड़ भूमि की नहीं 125 एकड़ भूमि की मांग की गई थी जिसमें से उसे 94.49 एकड़ भूमि प्राप्त हुई है।

(3) जी नहीं। इस भूमि की अभी कोई कीमत निश्चित नहीं की गई है। यू.-आई.टी. द्वारा यह भूमि इस शर्त पर दी गई है कि जो कीमत राज्य सरकार तय करेगी उसका मंडी समिति द्वारा भुगतान कर दिया जायेगा। जमीन की अभी कोई कीमत तय नहीं होने से महंगी होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी नहीं। नये भू-खण्ड पर मंडी के भविष्य के विस्तार के लिये भी पूरा प्रावधान है तथा स्थान की कमी नहीं रहेगी। निहित स्वार्थ होने का प्रश्न ही नहीं होता।

### सवाई माधोपुर जिले में चरागाहों का गलत आवंटन

342. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा),

श्री कुंजीलाल (बामनवास),

श्री राम किशोर मीना (सिकराय) :

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले में चरागाहों के गलत आवंटन द्वारा ग्रामीणों में भयंकर रूप से कई प्रकार के झगड़े चल रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मामले की गम्भीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने जिले के जन-प्रतिनिधियों के साथ कई बार बातचीत की है ? यदि हां, तो कब-कब और कहां ?

(3) क्या राज्य सरकार ने उक्त मामलों के उचित हल के लिए कोई रास्ता निकाला है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) 1975 में चलाये गये राजस्व अभियान के दौरान चरागाह भूमि को परिवर्तित कर भूमिहीनों को आवंटन किया गया था जिसके संबंध में गांवों में आपसी विवाद उत्पन्न हुए हैं।

(2) जी हां। उक्त मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने जिले के प्रतिनिधियों के साथ सवाई माधोपुर जिलाधीश कार्यालय में दिनांक 31-8-77 को विचार किया था एवं एक बैठक सांसदों, विधायक एवं जन-प्रतिनिधियों की दिनांक 30-12-77 को जयपुर में हुई थी ?

(3) उक्त मामलों के उचित हल के लिये विचार करने हेतु राज्य सरकार ने मंत्री मंडल की एक उप-समिति नियुक्त की है। समिति की राय प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

## परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 60 की सूची)

22 गोदाम औद्योगिक बस्ती, जयपुर में बंद इकाइयों की सूची

| क्र.सं. | इकाइयों का नाम | प्लाट / शेड संख्या | उत्पादित वस्तु | बन्द होने का कारण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | मैसर्स इंडिया फेल्ट मे. कं. | शेड नं. ए-5 सी-24 | फेल्ट | उद्यमी की मृत्यु । |
| 2. | ,, जयहिन्द स्टील वर्क्स | ,, नं. बी-8 | स्टील फर्नीचर | शेड मे. नित्र प्लास्टिक इण्ड. को बेच दिया है । |
| 3. | ,, वेटर्न केबल्स प्रा. लि. | ,, सी-8, सी-6 | केबल्स | आर्थिक कठिनाई । |
| 4. | ,, भारत मेटल वर्क्स | ,, सी-24 | स्टील फर्नीचर, कब्जे. कुन्दे | उद्यमी का निधन । |
| 5. | ,, जय भारत इण्डस्ट्रीज कार्पो. | ,, सी-15 | औसगन | उद्यमी ने दूसरी इकाई फरीदाबाद में लगाली है, यहां रूचि नहीं लेते हैं । अतः शेड का आवंटन निरस्त किया जाता है । |
| 6. | ,, स्टील की. इण्डस्ट्रीज | प्लाट, बी-28 | कृषि यंत्र, हाथ के औजार | मर्केन्टाइल के. बैंक का ऋण था, बैंक के फेल होने से इकाई पर विपरीत असर पड़ा तथा आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा । |
| 7. | ,, राजस्थान रबड़ इण्डस्ट्रीज | सी-37, 38 | हवाई चप्पल | अनुभवहीनता से भारी हानि होने के कारण। |

औद्योगिक क्षेत्र विश्वकर्मा, जयपुर में बन्द इकाइयों की सूची

| क्र.सं. 1 | इकाई का नाम 2 | प्लाट नं. 3 | उत्पादित वस्तु का नाम 4 | बन्द होने का कारण 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | मैसर्स डेगटोस इण्डस्ट्रियल कार. | 193 | इन्जीनियरिंग | कार्यशील पूंजी की कमी एवं विपणन की कठिनाई। |
| 2. | ,, भगवती मिनरल इण्डस्ट्रीज | 214 | मिनरल | विपणन की कठिनाई व कार्यशील पूंजी की कमी। |
| 3. | ,, कालोकिट सोप वर्क्स | 216 | साबुन | ,, ,, |
| 4. | ,, मोहन जी. आई. पाइप इण्डस्ट्रीज | 221 | पाइप | ,, ,, |
| 5. | ,, अविरा केमिकल | 254 | रसायन | ,, ,, |
| 6. | ,, जे. प्लास्टिक | 255 | प्लास्टिक | विपणन की कठिनाई तथा कच्चे माल की कमी। |
| 7. | ,, जयपुर बोरियम प्रोडेक्ट | 257 | रसायन | ,, ,, |
| 8. | ,, गोपाल इण्डस्ट्रीज | 361 | बाल्टियां | विपणन की कठिनाई तथा कच्चेमाल की कमी। |
| 9. | ,, इलेक्ट्रोनिक स्विच गेयर्स | 385 | स्विच गेयर | कार्यशील पूंजी की कमी। |
| 10. | ,, विविक का स्टक | 389 | इन्जी. | ,, |
| 11. | ,, विजय सिंह | 403 | ग्राइस | ,, |
| 12. | ,, राजस्थान एल्यूमिनियम कार. | 15 | एल्यूमिनियम | हिस्सेदारी में मतभेद। |
| 13. | ,, जय श्री उद्योग | 13 | इन्जीनियरिंग | कार्यशील पूंजी की कमी। |
| 14. | ,, आर. के. इण्डस्ट्रीज | 28/29 | प्लास्टिक | ,, |
| 15. | ,, आर. एस. टिन प्रोडक्ट्स | 81 | टिन कन्टिनर्स | इकाई में कार्य न करके, साइट पर कार्य करते हैं। |
| 16. | ,, दिया टूट इण्डस्ट्रीज | 92 | टैक्स टाइल | कार्यशील पूंजी की कमी के कारण। |
| 17. | ,, जयपुर इलेक्ट्रोनिक्स | 113 | इलेक्ट्रोनिक्स | श्रमिकों द्वारा हड़ताल करने के कारण। |
| 18. | ,, पस्टनर्स एण्ड फोरेन्स | 156 | इन्जी. | कार्यशील पूंजी की कमी। |
| 19. | ,, सोनी ऑयल मिल | 274 | तेल मिल | तेल के व्यापार में अस्थिरता के कारण। |
| 20. | ,, भारत इण्डस्ट्रीज | 393 | तेल मिल | तेल के व्यापार में अस्थिरता के कारण। |
| 21. | ,, ओसवाल इण्डस्ट्रीज | 395 | केमीकल | उद्योग में कार्यशील पूंजी की कमी। |
| 22. | ,, राजस्थान उद्योग | 88 | प्लास्टिक | कार्यशील पूंजी की कमी के कारण। |
| 23. | ,, मोदी इण्डस्ट्रीज कार. | 164 | इन्जी. | विपणन की कठिनाई। |

Page No 273



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 24. | मैसर्स जैन इण्डस्ट्रीज | 2 | रसायन | आयकर विभाग द्वारा सील लगाने के कारण। |
| 25. ,, | राज. मारबल एण्ड मिनरल | 3 | मारबल/मिनरल | विपणन की कठिनाई । |
| 26. ,, | राजस्थान लाइट केमिकल इण्डस्ट्रीज | 62 | केमिकल | कार्यशील पूंजी की कमी के कारण । |
| 27. ,, | परफैक्ट एग्रो इण्डस्ट्रीज | 82 | इन्जीनियरिंग | कार्यशील पूंजी की कमी के कारण । |
| 28. ,, | अलोक इण्डस्ट्रीज | 85 | ,, | विपणन की कठिनाई एवं पूंजी की कमी । |
| 29. ,, | राज. इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज | 86 | ,, | कार्यशील पूंजी की कमी के कारण । |
| 30. ,, | आर. डी. प्लास्टर | 93 | मिनरल | विपणन की कठिनाई । |
| 31. ,, | जूपीटर कास्टर्नस | 97 | इन्जीनियरिंग | कार्यशील पूंजी की कमी व विपणन की कठिनाई। |
| 32. ,, | भारत उद्योग | 98 | ,, | कार्यशील पूंजी की कमी के कारण । |
| 33. ,, | अजन्ता एन्टरप्राइजेज लि. | 107 | ,, | कार्यशील पूंजी की कमी व विपणन की कमी के कारण |
| 34. ,, | राजस्थान कास्टिंग | 147,148 | ,, | कार्यशील पूंजी की कमी के कारण। |
| 35. ,, | जयपुर एग्रीकल्चरर्ल्स इम्पली. | 176 | ,, | मालिक बन्द करके चले गये । |
| 36. ,, | बिन्नी रोलर फ्लोर मिल्स | 177 | फ्लोर मिल्स | विपणन की कठिनाई। |
| 37. ,, | ओ. एस. रौलिंग मिल्स, | 178 | इन्जीनियरिंग | विपणन की कठिनाई एवं पूंजी की कमी । |
| 38. ,, | अलका इन्जीनियरिंग वर्क्स | 182 | ,, | कार्यशील पूंजी की कमी के कारण । |
| 39. ,, | शक्ति इण्डस्ट्री प्रोडक्टस | 224 | श्रमिक सुरक्षा एवं टेक्सटाइल सामग्री | बिक्री कर की दर अधिक होने के कारण कम्पीट नहीं कर पा रही है । |
| 40. ,, | महामाया मार्ट्निग इण्डस्ट्रीज | 69 | प्लास्टिक | कच्चा माल नहीं मिलने के कारण एवं कार्यशील पूंजी की कमी । |
| 41. ,, | फ्लड कंट्रोल प्रा. लि. | 72 | इन्जीनियरिंग | मालिक जयपुर से बाहर चले गये । |

274



## परिशिष्ट 6

( अतारांकित प्रश्न संख्या 67 की सूची )

पूर्ण एवं अपूर्ण सार्वजनिक पेयजल कूपों की सूची

| क्र. स. | नाम ग्राम | पेयजल कूप हेतु स्वीकृत धनराशि | पूर्ण अथवा अपूर्ण | कुल व्यय की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | देवखेड़ा .. .. .. | 900) | पूर्ण | 900) |
| 2. | पकरोडा .. .. .. | 1,600) | अपूर्ण | 1,600) |
| 3. | खारेड़ा .. .. .. | 1,100) | पूर्ण | 1,100) |
| 4. | बींजवाड .. .. .. | 310) | पूर्ण | 310) |
| 5. | बिलन्दी .. .. .. | 300) | अपूर्ण | 300) |
| 6. | शिकारों का बास .. .. | 1,000) | पूर्ण | 1,000) |
| 7. | बैलाका .. .. .. | 100) | पूर्ण | 100) |
| 8. | खेड़ली .. .. .. | 100) | पूर्ण | 100) |
| 9. | घाटला .. .. .. | 300) | पूर्ण | 300) |
| 10. | बालेटा .. .. .. | 500) | पूर्ण | 500) |
| 11. | लोली .. .. .. | 1,000) | पूर्ण | 1,000) |
| 12. | तूलेडा .. .. .. | 100) | अपूर्ण | 100) |
| 13. | हाजीपुर .. .. .. | 1,400) | अपूर्ण | 1,400) |
| 14. | हाजीपुर की ढाणी .. .. | 1,500) | अपूर्ण | 1,500) |
| 15. | करवावाल .. .. .. | 1,600) | पूर्ण | 1,600) |
| 16. | मेथला .. .. .. | 500) | अपूर्ण | 500) |
| 17. | करवाडी .. .. .. | 300) | अपूर्ण | 300) |
| 18. | मोरेडा .. .. .. | 300) | अपूर्ण | 300) |
| 19. | बींजवाड नरूका .. .. | 500) | पूर्ण | 500) |
| | | 13,410) | | 13,410) |

विशेष विवरण

ग्राम वासियों द्वारा किये गये श्रमदान की राशि उपरोक्त व्यय में शामिल नहीं है।

278



## परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 70 की सूची)

पंचायत समिति, बामनवास द्वारा दी गई वर्षवार अनुदान की सूची

| क्रमांक | नाम व्यक्ति जिसको पैसा दिया गया | वाउचर नम्बर व दिनांक | राशि | कार्य का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **वर्ष 1975–76** | | | |
| 1. | श्री ठण्डीराम, सरपंच, केमला | 10।2-6-75 | 500) | कूप मरम्मत |
| 2. | श्री बृजलाल, सरपंच, मीताकोलेता | 54।13-6-75 | 2,500) | स्कूल भवन |
| 3 | श्री रामविला गुप्ता, ग्र. भांवरा | 57।13-6-75 | 3,000) | स्कूल भवन |
| 4. | श्री रामस्वरूप, सद. बिजारी | 55।13-6-75 | 3,000) | स्कूल भवन |
| 5. | श्री रामधन, सरपंच, नादोती | 2।1-7-75 | 1,500) | तालाब मरम्मत |
| 6 | श्री श्रीराम, सरपंच, शफीपुरा | 26।2-7-75 | 1,500) | मरम्मत राधे की तालाब |
| 7. | श्री रामकिशोर शर्मा, कृ. प्र. अ. प्रशासक, ग्रा. पं. पट्टीकला बामनवास | 43।8-7-75 | 1,500) | इदावाला तालाब |
| 8 | श्री रामधन, सरपंच, नादोती | 44।10-7-75 | 300) | शाला भवन, नादोती |
| 9. | श्री प्रशासक, बामनवास पट्टीखुर्द | 45/10-7-75 | 500) | कूप कोलियान |
| 10. | श्री रामस्वरूप, ग्रा. से., नादोती | 59।8-8-75 | 600) | भीलापाड़ा स्कूल |
| 11. | श्री अनिरुद्ध प्रसाद सिंह, प्रशासक, ग्रा. पं. बामनवास पट्टीकलां | 23।1-3-76 | 1,200) | बूधावाला तालाब |
| 12. | सरपंच, नादोती | 149।10-6-75 | 1,000) | स्कूल भवन |
| 13. | श्री मिश्रीलाल, सरपंच, ककराला | .. 13।1-3-76 | 150) | रास्ता दुरुस्ती |
| | **वर्ष 1976–77** | | | |
| 1. | श्री रामधन, सरपंच, नादोती | 5/17-4-76 | 1000) | तालाब मरम्मत |
| | | 21-6-77 | 500) | तालाब मरम्मत |

(278)



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2. | श्री श्रीचन्द, सरपंच, बरदाला | 216।31-5-76 | 300) | शाला निर्माण |
| 3. | श्री अनिरुद्ध प्रसाद सिंह, प्रशासक, ग्रा. पं. बामनवास पट्टीकलां | 56।21-1-76 | 300) | दूधावाला तालाब |
| 4. | श्री मोहनलाल जैन, ग्राम सेवक, बिन्जारी | 8।1-9-76 | 300) | शाला निर्माण |
| 5. | श्री मोहनलाल जैन, ग्राम सेवक, बिन्जारी | 9।1-9-76 | 100) | कूप पारा भावड़ |
| 6. | श्री मोहनलाल जैन, ग्राम सेवक, बिन्जारी | 10।1-9-76 | 200) | स्कूल भवन निर्माण |
| 7. | श्री कृष्ण स्वरूप, सरपंच, गढ़मोरा | 185।17-5-76 | 1,200) | स्कूल भवन, गढ़मोरा |
| 8. | श्री बृजलाल, सरपंच, मीनाकोलेता | 5।1-9-76 | 100) | कूप निर्माण |
| 9. | श्री बृजलाल, सरपंच, मीनाकोलेता | 6।1-9-76 | 200) | पंचायत भवन निर्माण |
| 10. | श्री बृजलाल, सरपंच, मीनाकोलेता | 7।1-9-76 | 1,200) | शाला भवन, सीकरोली |
| 11. | श्री रामस्वरूप ग्राम सेवक, नादोती | 34।1-3-76 | 991) 20 | रेस्ट हाउस मरम्मत |
| 12. | श्री पन्नालाल, ठेकेदार, बामनवास | 47।21-10-76 | 2,524) 60 | भरना तालाब |
| 13. | श्री प्रशासक, बामनवास, पट्टीखुर्द | 95।25-2-77 | 500) | मोर निर्माण तालाब |
| 14. | श्री रेवड़मल, सरपंच, जाहुरा | 50।31-3-77 | 750) | शाला भवन, कुण्डोला |
| 15. | श्री भगवती प्रसाद शर्मा, प्रशासक, बामनवास पट्टीखुर्द | 97।31-3-77 | 1,500) | भगतावाला |
| 16. | श्री भगवती प्रसाद शर्मा, प्रशासक, बामनवास पट्टीखुर्द | 98।31-3-77 | 1000) | खेतलाई तालाब |
| 17. | श्री भगवती प्रसाद शर्मा, प्रशासक, बामनवास पट्टी खुर्द | 99।31-3-77 | 1,000) | सुन्दरलाव तालाब |
| 18. | श्री भगवती प्रसाद शर्मा प्रशासक, बामनवास पट्टीखुर्द | 100।31-3-77 | 1,000) | रतनावाला |
| 19. | श्री भगवती प्रसाद शर्मा प्रशासक, बामनवास पट्टी खुर्द | 101।31-3-77 | 1,000) | दांत्या वाला |
| 20. | श्री भगवती प्रसाद शर्मा, प्रशासक, बामनवास पट्टीखुर्द | 102।31-3-77 | 2,000) | कंकड़ा वाला |
| 21. | श्री सरपंच, रामधन, नादोती | 56।31-3-77 | 3,000) | बोमल्या वाला |
| 22. | श्री राधेश्याम, सरपंच, रौंसी | 48।31-3-77 | 50) | रास्ता दुरूस्ती |
| 23. | श्री राधेश्याम, सरपंच, रौंसी | 49।31-3-77 | 90) | हरिजन कूप |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | वर्ष 1977–78 की सूची | | | |
| 1. | श्री मिश्रीलाल, सरपंच, ककराला | 18-5-77 | 500) | कूप निर्माण |
| 2. | श्री राधेश्याम, सरपंच, गढ़मोरा | 1-6-77 | 450) | कूप निर्माण |
| 3. | श्री रामधन, सरपंच, ककराला | 21-6-77 | 500) | पूरण वाला तालाब |
| 4. | श्री मिश्रीलाल, सरपंच, ककराला | 81।18-5-77 | 150) | कूप मरम्मत उपरवाला |
| 5. | श्री मिश्रीलाल, सरपंच, ककराला | 79।18-5-77 | 200) | हरिजन कूप |
| 6. | श्री मिश्रीलाल, सरपंच, ककराला | 80।18-5-77 | 150) | कूप मरम्मत |

सूची उन कार्यों की जिनके लिये दी गई राशि का उपयोग नहीं होना बतलाया गया है।

| क.सं. | नाम कार्य | ग्राम का नाम | राशि जो दी गई थी |
|---|---|---|---|
| 1. | कूप मरम्मत | सरपंच, केमला | 500) |
| 2. | कूप कोलियान | पट्टी खुर्द | 500) |
| 3. | तालाब मरम्मत | सरपंच, नादोती | 1,500) |
| 4. | तालाब मरम्मत | सरपंच, नादोती | 1,500) |
| 5. | बन्ड भगतावाला | भगतावाला | 1,500) |
| 6. | स्कूल भवन | मिनाकोलेता | 1,200) |
| 7. | तालाब | गोल्यावाला | 3,000) |
| 8. | तालाब | भरना | 2,524) 60 |
| 9. | स्कूल भवन | गढ़मोरा | 1,200) |
| 10. | शाला भवन टूण्डीला | सरपंच, नाहरा | 750) |

## परिशिष्ट 8

( अतारांकित प्रश्न संख्या 72 की सूची )

सूरतगढ़ मण्डी के दुकानदारों की सूची जिन्हें पिड बनाने हेतु अनुदान (सब्सिडी) दी गई थी

| क्र. सं. | नाम दुकानदार | | | राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | मैसर्स मंगलचन्द कन्हैयालाल | .. | .. | 1,000.00 |
| 2. | ,, पृथ्वीराज द्वारकादास | .. | .. | 1,000.00 |
| 3. | ,, हेपमल शिवशंकर | .. | .. | 1,000.00 |
| 4. | ,, जगदीश एण्ड कम्पनी | .. | .. | 1,000.00 |
| 5. | ,, हरिकृष्ण एण्ड सन्स | .. | .. | 1,000.00 |
| 6. | ,, मनसुखदास अयोध्याराम | .. | .. | 1,000.00 |
| 7. | ,, किशोरचन्द श्यामसुन्दर | .. | .. | 1,000.00 |
| 8. | ,, सुखलाल रामलाल | .. | .. | 2,000.00 |
| 9. | ,, कालूराम तोलाराम | .. | .. | 2,000.00 |
| 10. | ,, बृजमोहन सालगराम | .. | .. | 3,000.00 |
| 11. | ,, चौधरी देवेन्द्रसिंह वेन्द्रसिंह | .. | .. | 2,000.00 |
| 12. | ,, सत्यपाल पुत्र श्री देवाराम | .. | .. | 1,000.00 |
| 13. | ,, मानकचन्द सुगेरचन्द | .. | .. | 1,000.00 |
| 14. | ,, चौथमल धनराज | .. | .. | 1,000.00 |
| 15. | ,, [illegible]लाल एण्ड कम्पनी | .. | .. | 1,000.00 |
| 16. | ,, नथमल अमरचन्द | .. | .. | 1,000.00 |
| 17. | ,, नारायणसिंह गरदिशमल | .. | .. | 1,000.00 |
| 18. | ,, मनफुलराम एण्ड सन्स | .. | .. | 1,000.00 |
| 19. | ,, सुलताना राम बोलाराम | .. | .. | 1,000.00 |
| 20. | ,, उदयराम एण्ड कम्पनी | .. | .. | 1,000.00 |
| 21. | ,, भेरेदान बनेदान | .. | .. | 1,000.00 |
| 22. | ,, लालचन्द एण्ड सन्स | .. | .. | 1,000.00 |

# परिशिष्ट 'ख'

मण्डी-समिति, पीलीबंगा द्वारा अपने सदस्यों को पुलिया बनाने हेतु दी गई अग्रिम राशि तथा अन्य सामग्री का विवरण

| क्र.सं. | सदस्य का नाम | राशि (1972-73) | राशि (1975-76) |
|---|---|---|---|
| 1. | कमरदीन जलमानी | 300।— | |
| 2. | मुखराम जलमानी | 300।— | |
| 3. | दलालसिंहजी शेखावत | 2,400।— | |
| 4 | रणजीत सिंह | 300।— | |
| 5. | जयनारायण गोठवाला | 1,200।— | |
| 6. | हनुमान, लिखरीसर | 3,300।— | |
| 7. | अंतराम गोठवाला | 3000।— | तथा 30 हजार ईंट, 100 थैले सीमेन्ट । |
| 8. | पेमाराम | 1,500।— | |
| 9. | वलूराम, मारवाड़वाला | 4,500।— | |
| 10. | बेगाराम | 1,200।— | |
| 11. | थोनारामण, गोठवाला | 900।— | |
| 12. | जसनराम | 900।— | |
| 13. | रामनारायण, घमंड़िया | 1,200।— | |
| 14. | बीरबल राम, सूरतगढ़ | 3,000।— | तथा 30 हजार ईंट, 100 थैले सीमेंट |
| 15. | बृजलाल गोमूवाला | 6,600।— | तथा 66 हजार ईंट, 220 थैले सीमेंट |
| 16. | मनपुदा खोत, खोतावाली | 1,500।— | तथा 15 हजार ईंट, 50 थैले सीमेंट |
| 17. | हनुमान विश्नोई, सादारपुरा | 3,000।— | तथा तीस हजार ईंट 100 थैले सीमेंट। |
| 18. | भागीरथ जांगिड़, पीलीबंगा | 6,000।— | तथा तीस हजार ईंट 200 थैले सीमेंट |
| 19. | तसपाल ताखर, रंगमहल | 600।— | तथा 21 हजार ईंट व 70 थैले सीमेंट |
| | | 70 पुलियों के लिए दी गई राशि 21 हजार रु. | 75-76 में पुलियों 84 के पेटे 25,200।—एवं 1,92,000 ईंट तथा 840 थैले सीमेंट दी गई । |

नोट :—वर्ष 1972-73 में सर्वश्री कमरुदीन, कल्याण सिंह एवं कालूराम व बेगाराम, जसराम व रामनारायण द्वारा अभी हिसाब पेश नहीं किया गया है । इस सम्बन्ध में उक्त व्यक्तियों को कई बार नोटिस भी दिये जा चुके हैं ।

(2) वर्ष 1975-76 में बृजलाल ठियाम व मनफूल खोरा पुलिया बनाकर जांच हेतु लिखा गया है । श्री हनुमान पुत्र रामनारायण द्वारा भी पुलिया बनाने का प्रार्थना-पत्र पेश किया है और पुलिया कापर जांच हेतु निवेदन किया है ।

# Page No 280

(280)



## परिशिष्ट 9

( अतारांकित प्रश्न संख्या 73 की सूची )

सूची "क"

( सूची व्यय)

| वर्ष | अधिकारियों एवं कर्म-चारियों का वेतन | अन्य भत्ते | योग |
|---|---|---|---|
| 1973-74 | 37,134 | 41,229 | 78,363 |
| 1974-75 | 97,646 | — | 97,646 |
| 1975-76 | 34,247 | 53,213 | 87,460 |
| 1976-77 | 47,336 | 51,340 | 98,676 |
| 1977-78 | 77,371 | 15,644 | 93,015 |

सूची "ख"

| वर्ष | जानवरों से प्राप्त आय | कृषि उपज से प्राप्त आय | अन्य साधनों से प्राप्त आय | कुल आय |
|---|---|---|---|---|
| 1973-74 | 27,680 | 24,194 | 5,508 | 57,382 |
| 1974-75 | 45,180 | 59,915 | 822 | 1,05,917 |
| 1975-76 | 1,13,385 | 96,594 | 3,524 | 2,13,501 |
| 1976-77 | 56,232 | 9,077 | 5,983 | 70,313 |
| 1977-78 | 21,000 | 29,630 | 932 | 51,562 |

———

(281)



# परिशिष्ट 10

( अतारांकित प्रश्न संख्या 76 की सूची )

| खसरा सं. | रकबा | | घोषणा की गई की तिथि | अधिकारी का नाम |
|---|---|---|---|---|
| | बीघा | बिस्वा | | |
| 210 | 23 | 14 | 28–9–59 | जिलाधीश, नागौर |
| 247 | 56 | 13 | ,, | ,, |
| 339 | 12 | 18 | ,, | ,, |
| 217 | 87 | 14 | ,, | ,, |
| 304 | 11 | 76 | ,, | ,, |
| 391 | 79 | 01 | ,, | ,, |
| 1061 | 40 | 19 | ,, | ,, |
| 229 | 21 | 18 | ,, | ,, |
| 310 | 138 | 06 | ,, | ,, |
| 548 | 35 | 01 | ,, | ,, |
| 236 | 368 | 12 | 27–4–69 | उप-खंड अधिकारी, मेड़ता |
| 282 | 122 | 11 | ,, | ,, |
| 953 | 6 | 17 | सेटलमेंट पूर्व घोषित है | |

खसरा नं. 247 रकबा 56–13 में से 22 बीघा पर अतिक्रमण है जिसका नियम बेदखली का मामला उप-खण्ड अधिकारी, मेड़ता के यहां विचाराधीन है।

इसी प्रकार खसरा नं. 953 में रकबा 6–17 में से 1 बीघा रकबे में 3 व्यक्तियों के बाड़े लगे हुए हैं। इस सम्बन्ध में धारा 91, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत तहसील में कार्यवाही जेर तजबीज है।

शेष समस्त रकबा चरागाह के काम में आ रहा है।